पंचदश माला, खंड 3, अंक 14

मंगलवार, 21 जुलाई, 2009
30 आषाढ़, 1931 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)



(खण्ड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. PL-06
Acc. No. 77 (2011) (2)
Dated 11/10/2011

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डॉ. रविन्द्र कुमार चड्ढ
संयुक्त सचिव

जे.पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

बलराम सूरी
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 3, दूसरा सत्र 2009/1931 (शक)]

अंक 14, मंगलवार, 21 जुलाई, 2009/30 आषाढ़, 1931 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	241 से 244	1-36
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	245 से 260	36-127
अतारांकित प्रश्न संख्या	2195 से 2389	127-565
सभा पटल पर रखे गए पत्र		565-578
'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' के बारे में दिनांक 7.7.2009 के तारांकित प्रश्न संख्या 48, के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण		578-579
सदस्यों द्वारा निवेदन		
अंतिम उपयोग निगरानी प्रबंध के बारे में		579-587
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	पश्चिम बंगाल में दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में दुग्ध यूनियनों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अधीर चौधरी	587
(दो)	उत्तर पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर सीवर और ड्रेनेज सिस्टम के लिए योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	588
(तीन)	आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी के जल का उचित हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	589
(चार)	पूर्वी उत्तर प्रदेश में गहरे बोरिंग के माध्यम से भूमिगत जल का उपयोग करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	590

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(पांच)	महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	590
(छह)	उत्तर प्रदेश के कानपुर में टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया के भूतपूर्व कर्मचारियों को उनके आवास से निकले जाने को रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजाराम पाल	590
(सात)	देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में श्वेत पत्र लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री दत्ता मेघे	591
(आठ)	छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित कोरबा फर्टिलाइजर्स फैक्टरी को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. चरण दास महन्त	592
(नौ)	गुजरात स्थित सरदार सरोवर परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने तथा इस योजना हेतु निधियों के लिए पर्याप्त उपबंध किए जाने और इसे समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिन पाठक	592
(दस)	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति के मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता	
	श्री वीरेन्द्र कुमार	593
(ग्यारह)	जबलपुर स्थित बारगी बांध मुख्य नहर परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने तथा इसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की परिधि में लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री राकेश सिंह	594
(बारह)	उत्तर प्रदेश के इटावा और मध्य प्रदेश में भिंड के बीच रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री अशोक अर्गल	594

विषय कॉलम

(तेरह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को एक राष्ट्रीय पर्यटक स्थल घोषित किए जाने तथा पर्यटकों के लिए आवश्यक बुनियादी संरचना उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 595

(चौदह) उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले के खुर्जा में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर 595

(पंद्रह) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 का मरम्मत कार्य किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव 596

(सोलह) वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारत लौटकर आने वाले बेरोजगार अनिवासी भारतीयों के लिए कल्याण निधि की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. सम्पत 596

(सत्रह) तमिलनाडु के चेन्नई में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

डॉ पी. वेणुगोपाल 597

(अट्ठारह) तीस्ता बैराज परियोजना के समापन कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री नृपेन्द्रनाथ राय 598

(उन्नीस) एस.एस.बी. के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के बच्चों को रोजगार प्रदान किए जाने तथा एस.एस.बी. के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को वित्तीय अनुग्रह राशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 598-99

अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2009-2010

विद्युत मंत्रालय

श्री उदय सिंह 601

श्री पन्ना लाल पुनिया 616

श्री शैलेन्द्र कुमार 621

विषय	कॉलम
श्री दारा सिंह चौहान	625
श्री जगदीश शर्मा	629
श्री मिथिलेश कुमार	634
श्री टी.के.एस. इलेंगोवन	634
श्री प्रेमदास	637
श्री तथागत सत्पथी	637
श्रीमती सुप्रिया सुले	645
श्री ए. सम्पत	646
श्री के. सुगुमार	649
श्री कौशलेन्द्र कुमार	652
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	653
श्री के. बापीराजू	657
श्री वीरेन्द्र कुमार	678
श्री अर्जुन राम मेघवाल	679
श्री एन. कृष्टप्प	682
श्री एन. चेलुवरया स्वामी	683
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	685
श्री राधा मोहन सिंह	687
डा. रतन सिंह अजनाला	690
श्री असादूद्दीन ओवेसी	693
श्री निनोंग ईरींग	696
श्री पी. लिंगम	698
श्री जगदानंद सिंह	700
श्री प्रेमचन्द गुड्डू	704
श्री नरहरि महतो	705
श्री के. सुधाकरण	707
श्री अनुराग सिंह ठाकुर	710

विषय		कॉलम
	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	712
	श्री विजय बहुगुणा	716
	श्री शरीफुद्दीन शारिक	718
	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	719
	श्री बृजभूषण शरण सिंह	721
	श्री सुशील कुमार सिंह	725
	श्री सज्जन वर्मा	731
	श्री सी.एल. रुआला	733
	श्री भूदेव चौधरी	734
	श्री थोल तिरूमावलावन	738
	श्री उदय प्रताप सिंह	741
	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	742
	श्री जे.एम. आरुन रशीद	744
	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	749
	श्री हंसराज गं. अहीर	754
	श्री तूफानी सरोज	755
	श्री सुशील कुमार शिंदे	757-779
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
	संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश मंत्री श्रीमती हिलेरी क्लिन्टन की हाल में भारत यात्रा	
	श्री एस.एम. कृष्णा	659-675
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	791-792
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	791-802
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	803-804
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	803-806

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 21 जुलाई, 2009/30 आषाढ़, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व राष्ट्रपति की इन्दिरा गांधी विमान पत्तन पर तलाशी ली गई थी। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। नागर विमानन मंत्री को सभा में वक्तव्य देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी क्वैश्चन ऑवर है, उसके बाद लेंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 241, श्री मनसुखभाई डी. वसावा।

[हिन्दी]

खानों का संरक्षण और विकास

+

*241. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :***
श्री घनश्याम अनुरागी :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामान्यत: खनिजों के विकास के मामले में तथा विशेषकर खानों को पट्टे पर देने/राज्य सरकारों को खनिज रियायतें देने की स्वीकृति प्रदान करने में केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है;

(ख) क्या भारतीय खान ब्यूरो खान और खनिज (विकास और विनियमन) कानून के अंतर्गत खानों के संरक्षण और विकास के मामले में विनियामक की भूमिका निभाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विद्यमान व्यवस्था से देश में अवैध खनन पर रोक लगाने में सहायता मिली है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या केंद्र सरकार का विचार मौजूदा कानूनी ढांचे में कोई परिवर्तन करने का है?

[अनुवाद]

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय संविधान में यथा उपबंधित, संसद कानून द्वारा, यदि वह इसे जनहित में उचित ठहराती हो, केंद्र सरकार को संसद द्वारा अनुमत सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में लेने की अनुमति दे सकती है। तदनुसार, संसद ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 (एमएमडीआर एक्ट) बनाया है जिसमें भारत में खनन क्षेत्र के विनियमन के लिए रूपरेखा दी गई है। एमएमडीआर अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारें गैर-ईंधन खनिजों के लिए खनिज रियायतें (टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टा) प्रदान करती हैं तथापि, एमएमडीआरएक्ट की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में खनिज रियायत प्रदान करने से पहले केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। केंद्र सरकार को खनिज रियायतें प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित की अनुमति देने की शक्तियां प्राप्त हैं:

(i) एमएमडीआर अधिनियम में विनिर्दिष्ट खनिज रियायत की मंजूरी की अधिकतम क्षेत्र की सीमा को शिथिल करने;

(ii) पूर्व में मंजूरी के अंतर्गत धारित करने के बाद अथवा विशिष्ट उपयोग के लिए आरक्षित किए गए क्षेत्र को अधिसूचित करने की जरूरत को शिथिल करने;

(iii) संरक्षण के प्रयोजनार्थ अथवा पीएसयू द्वारा विशिष्ट उपयोग के लिए खनिज धारी क्षेत्र का आरक्षण करने।

(ख) और (ग) केंद्र सरकार ने खनिजों के संरक्षण और विकास के लिए खनिज संरक्षण तथा विकास नियमावली 1988 (एमएमडीआर) तथा खनिज रियायत नियमावली 1960 (एमसीआर) बनाए हैं। खान मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय भारताय खान ब्यूरो (आईबीएम) खनन

कार्यकलाप विनियंत्रित करने और खनिजों के संरक्षण और विकास के हित में यह सुनिश्चित करने के लिए खनन कार्यकलाप क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक तरीके से, किए जाते हैं, एमसीडीआर तथा एमसीआर को लागू करता है। आई बी एम एमएमडीआर एक्ट तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्रमुख खनिजों (गैर-ईंधन) के संबंध में निम्नलिखित नियामक भूमिका अदा करता है:

(i) खनिजों के संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा को ध्यान में रखकर खनन प्लानों, स्कीमों तथा परिसमापन प्लानों को अनुमोदित करना।

(ii) गवेषण, पूर्वेक्षण, खानों और खनिजों पर डाटाबेस संग्रहण, मिलान तथा रख-रखाव करने और खनन उद्योग की समस्याओं और संभावनाओं को वर्णित करते हुए प्रकाशन/बुलेटिन जारी करना।

(iii) खानों का निरीक्षण।

(iv) क्षेत्र आधारित पर्यावरणीय आंकलन अध्ययन करके पर्यावरण पर खनन के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने को सुसाध्य बनाना।

(v) खनन, भूविज्ञान, खनिज प्रोसेसिंग तथा अयस्क और खनिजों के विश्लेषण सहित पर्यावरणीय पहलुओं का स्वत: तकनीकी-आर्थिक फील्ड अध्ययन करना तथा इन क्षेत्रों में आर एण्ड डी कार्यकलापों को बढ़ावा देना।

(vi) प्रदर्शिनियों तथा श्रव्य-दृश्य मीडिया के माध्यम से खनिज डिपाजिटों का संरक्षण, क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक विकास और खनित किए गए क्षेत्रों की बहाली तथा पुनर्वास सहित पर्यावरण की रक्षा के बारे में जागरुकता को बढ़ावा देना।

(vii) खनन क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देना और मानिटर करना।

(viii) देश के खनिज संसाधनों के क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देना।

(घ) और (ङ) जी, हां। खनिज अधिकार तथा राजस्व संग्रहण राज्य सरकार में निहित है जिन्हें एमएमडीआर एक्ट की धारा 23 (ग) के अंतर्गत अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्तियां भी प्राप्त हैं। खान मंत्रालय खनन प्रचालनों की स्थिति की समीक्षा करता है और उपयुक्त सलाह भी देता है। आईबीएम एमएमडीआर एक्ट तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियामक कार्य करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि खनन कार्यकलाप खनन प्लान की शर्तों के अनुसार हैं। तथापि, मौजूदा विधायी ढांचे की राष्ट्रीय खनिज, नीति, 2008 तथा होदा समिति की सिफारिशों की दृष्टिकोण से समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री मनसुखभाई डी. वसावा : उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का जवाब दिया है, वह वैसे तो जवाब देखने और पढ़ने से सही लगते हैं लेकिन जो जवाब आज दिया गया है, उसके पहले भी ऐसे कई प्रश्न आये तो सेम ही जवाब आये हैं। फिर भी लगातार खननों में गैर-कानूनी काम अवैध रूप से चलता रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि किसी किसी क्षेत्र में अवैध खनन कार्य हो रहा है, वहां 40एमएम से लेकर 100एम.एम. के होल बनाये जाते हैं लेकिन अवैध काम करने वाले लोग 200एमएम से 500एमएम के होल बनाकर ब्लास्टिंग करते रहते हैं। इस भारी ब्लास्टिंग के कारण जमीन का पानी नीचे चला जाता है और कहीं-कही धरती कम्पन का भय होता रहता है। इससे धरती का खोखलापन हो जाता है और इस क्रिया से भारी मात्रा में आस-पास के क्षेत्रों में इन्सानों का भी नुकसान करता है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न पूछें।

श्री मनसुखभाई डी. वसावा : मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी जानकारी है, यदि है तो ऐसे लोगों को अवैध काम करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

[अनुवाद]

श्री बी.के. हान्डिक : महोदय, अवैध खनन को नियंत्रित करने तथा इसे रोकने की शक्ति केन्द्र सरकार के पास नहीं है। यह शक्ति राज्य सरकारों के पास है। राज्य सरकारों को यह शक्ति दी गई है तथा इस परिस्थिति से वे ही मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि यह कानून एवं व्यवस्था की समस्या है तथा केवल वे इस पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। लेकिन अवैध खनन की समस्या को और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए 1999 में एमएमडीआर अधिनियम में अन्तर्निहित कानूनी उपबंधों को मजबूत बनाया गया है। माननीय सदस्य के लाभ

के लिए क्या मैं कुछ नियमों को उद्धृत करूं? केवल अभिग्रहण की तुलना में इसमें परिवहन एवं भंडारण तथा जब्ती हेतु उपबंध शामिल किए गए हैं। धारा 4(1क) शामिल किया गया तथा धारा 21(4) को अवैध रूप से रखे गए खनिज परिवहन तथा भंडार को कानून के दायरे में लाने के लिए अधिनियम की धारा 21(4) में संशोधन किया गया। धारा 21(4क) को खनिज, यंत्र, उपकरण, वाहन या अवैध खनन के लिए अभिग्रहण की गई अन्य किसी वस्तु की जब्ती हेतु शामिल किया गया। इसके लिए एक कानून है। मैं सभा का समय बेकार नहीं करना चाहता हूं। हमने कानून पारित किया है तथा कानून को और सख्त बनाया है। लेकिन ये कानून उन राज्यों में लागू किए जाने हैं जहा खान स्थित हैं। इसकी जांच करना राज्य सरकार का काम है। लेकिन हम राज्य सरकार से बराबर संपर्क में हैं तथा वे कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे विचार में माननीय सदस्य ने कोई विशिष्ट मामला नहीं दिया है। यदि वे कोई विशिष्ट मामला दें तो मैं निश्चित रूप से उस पर गौर करूंगा।

[हिन्दी]

श्री मनसुखभाई डी. वसावा : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हम टी.वी. के माध्यम से या कई अखबारों में पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक भी मामला बताऊं, मैं बता भी सकता हूं, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए कि कानून होते हुए भी गैर कानूनी कृत्य चलते रहते हैं। केवल मैं ही नहीं, सभी लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं, लेकिन ये कृत्य फिर भी नहीं रुकते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कानून होते हुए भी, हमारे पास बहुत स्ट्रांग कानून हैं, लेकिन फिर भी हम उन कानूनों को गैर कानूनी काम करने वालों पर लागू नहीं कर पाते हैं। कहीं-कहीं हम समझौता कर लेते हैं। जो ठेकेदार हैं या कंपनियां हैं, हम कंपनियों के साथ समझौता कर लेते हैं। अगर वे चोरी करने में पकड़ी जाती हैं तो उन्हें सजा दी जानी चाहिए। हम उनके साथ समझौता क्यों करते हैं? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि समझौता करने का कारण क्या है?

[अनुवाद]

श्री बी.के. हान्डिक : महोदय, मैं समझ नहीं पाया कि कौन समझौता करता है तथा किसके साथ करता है। केन्द्र सरकार कानून पारित करती है तथा राज्य सरकार इसका क्रियान्वयन करती है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा जहां इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स द्वारा कार्रवाई की गई जो एमएमडीआर अधिनियम, 1988 को लागू करती है। वर्ष 2008-09 के दौरान 2500 खानों का निरीक्षण किये जाने का लक्ष्य था लेकिन 2,645 खानों का निरीक्षण किया गया जो लक्ष्य ज्यादा था; उल्लंघन करने वाली खानों की संख्या 1,034 थी; उल्लंखन करने वाली खानों की संख्या 1,963 थी; उल्लंघनों के बारे में बताए जाने के बाद सुधार करने वाली खानों की संख्या 818 थी; जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों की संख्या 276 थीं; कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद 270 खानों में सुधार हुआ। इस प्रकार हमने कार्रवाई की है।

इस प्रकार, हमने कार्रवाई की है। माननीय सदस्य कोई विशिष्ट मामला नहीं बता रहे हैं। वह मात्र यही कह कर हैं कि चारो तरफ ऐसे मामले हो रहे हैं। कृपया किसी एक मामले का नाम लें ताकि मैं माननीय सदस्य की सहायता कर सकूं। मैं उत्तर देने की कोशिश भी कर सकता हूं। यदि माननीय सदस्य मुझे या इस सभा को विश्वास दिला पाते हैं, तो निश्चित रूप से हम उनके सुझाव को स्वीकार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री घनश्याम अनुरागी : महोदय, पूरे देश में पर्यावरण की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। रोजाना अखबारों के माध्यम से यह खबर पढ़ने को मिलती रहती है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मध्य प्रदेश व राजस्थान इससे लगे हुए हैं। यहां आये दिन नदियों और पहाड़ों का स्वरूप लगातार बदलता जा रहा है और पूरे देश में पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं। वहां पर नदियां और पहाड़ हैं। वहां पर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा अवैधानिक तरीके से खनन किया जा रहा है। वह इस तरह से खनन कर रही है, जिससे पर्यावरण का पूरा स्वरूप ही प्रदूषित हो रहा है और इससे जन-जीवन पूरी तरह से परेशान हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री घनश्याम अनुरागी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो खनन हो रहा है, उससे पर्यावरण खराब न हो, हमारे देश का स्वरूप न बदले, हमारे लोगों में तकलीफ बीमारियां न बढ़ें। क्या आप खनन कराने से पहले इसकी जांच करा सकते हैं, यह जांच किस स्थिति में कराई जा सकती है, या नहीं कराई जा सकती है, यह बताएं? हमारे स्टेट के लोग बहुत गरीब हैं। वहां पर बालू ली जाती है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न पूछें।

श्री घनश्याम अनुरागी : महोदय, मैं पहाड़ के बारे में बोल रहा हूं। लखनऊ में हजारों, करोड़ों पहाड़ों के पत्थर लगाये जा रहे हैं जिससे पर्यावरण खराब हो रहा है और यह खनन किया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न पूछें।

...(व्यवधान)

श्री घनश्याम अनुरागी : महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि बालू के लिए जो अवैध तरीके से खनन हो रहा है, उसे आप रोकने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे? मेरी विशेष प्रार्थना है कि पर्यावरण ठीक हो सके, इसके लिए आप कार्यवाही करें।

[अनुवाद]

श्री बी.के. हान्डिक : महोदय, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या पर्यावरण और संरक्षण संबंधी चिन्ताओं पर ध्यान दिया गया है अथवा नहीं। मैं यह कहना चाहूंगा क खनन करने से पहले हमें पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है। मैं आपको बताऊं कि यह सर्वाधिक कठिन कार्य है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राप्त करना सर्वाधिक दुष्कर कार्य है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति पाना अपने आप में कठिनतम परीक्षा है। इस प्रकार, ये सभी कार्य किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार समस्याओं से अवगत नहीं है। अनेक कदम उठाए गए हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सभी बातों का ध्यान रखा है ताकि वे हमें स्वीकृति देने से पहले इस बारे में स्वयं सुनिश्चित कर लें कि पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचेगी।

[हिन्दी]

श्री घनश्याम अनुरागी : उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में रोज जो खनन हो रहा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक ही सवाल पूछ सकते हैं। श्री सतपाल जी महाराज।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

व्यवधान)

श्री सतपाल महाराज : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उत्तराखंड में बहुत सी नदियां प्रभावित होती हैं। नदियां रेत लाती हैं पहाड़ों से और रेत से नदी का वाटरबैड बढ़ता जाता है। वहां पर माइनिंग रोक दी गई है। मंत्री जी क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि इनके पास कोई साइंटिफिक डायरैक्शंस हैं जो यह स्टेट गवर्नमैंट को दे सकें ताकि रेत निकाली जाएं और जिससे नदी का प्रभाव जो विनाशकारी हो जाता है, वह न हो?

[अनुवाद]

श्री बी.के. हान्डिक : महोदय, मेरा उत्तर वही है। पर्यावरण और वन मंत्रालय की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है और वह इसे ईमानदारीपूर्वक करता है। मैं इस सम्मानीय सभा को बता सकता हूं कि इस मंत्रालय से स्वीकृति पाना कठिनतम परीक्षा है और यहां तक कि हमें यह स्वीकृत शीघ्र नहीं मिल पाती हैं।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज : आप कुछ डायरेक्शन देते हैं या नहीं?

[अनुवाद]

श्री बी.के. हान्डिक : यदि ऐसी बात हो रही है तो हम निश्चित रूप से पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुरोध करेंगे। यह निर्देश देने का प्रश्न नहीं है।

श्री यशवंत सिन्हा : सरकार की यह नीति है कि खनन क्षेत्र में सभी गैर-परमाण्विक ईंधन भिन्न खनिजों हेतु शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी। *[हिन्दी]* मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस नीति के बनने के बाद कितनी पड़ी परियोजनाएं माइनिंग सेक्टर में 100 प्रतिशत फॉरेन इन्वेस्टमैंट के साथ शुरू हुई हैं और विशेषकर झारखंड राज्य में कितनी इस प्रकार की परियोजनाएं चल रही हैं?

[अनुवाद]

श्री बी.के. हान्डिक : कृपया आप अपना प्रश्न दोहराएंगे?

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, क्या मैं अपना प्रश्न दोहराऊं?

महोदय, मेरा प्रश्न यह है। खनन क्षेत्र में सभी गैर परमाण्विक और ईंधन-भिन्न खनिजों हेतु शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। यह सरकार की नीति हैं। अब मैं माननीय मंत्री

महोदय से यह जानना चाहता हूं। इस नीति और इस उदारीकरण के परिणामस्वरुप इस देश में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से कितनी बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई हैं तथा इनमें से कितनी झारखण्ड राज्य में हैं?

श्री बी.के. हान्डिक : जहां तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रश्न है, मुझे अलग से नोटिस चाहिए। सामग्री मेरे साथ है। वस्तुत: आप इस संबंध में एक अलग नोटिस दें और तब जाकर मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री अर्जुन चरण सेठी : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर निस्संदेह बड़ा है। परन्तु साथ ही साथ उत्तर के अंत में उन्होंने उद्धृत किया है और मैं अंतिम वाक्य को उद्धृत करना चाहूंगा:

> "तथापि वर्तमान विधायी खाका राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 तथा होडा समिति की सिफारिशों के आलोक में समीक्षाधीन है।"

महोदय, चूंकि उन्होंने होडा समिति का उल्लेख किया है और इसकी सिफारिशें केन्द्र सरकार के समीक्षाधीन है, क्या उन्हें पता है कि खनिज वाले राज्यों जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान और यहां तक कि पश्चिम बंगाल ने होडा समिति की कतिपय सिफारिशों पर आपत्ति दर्ज की है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सोचते हैं कि यदि होडा समिति की सिफारिशें लागू की जाती हैं तो खनिज उत्पादक राज्यों के हित प्रभावित होंगे और यह हमारे देश के संवैधानिक ढांचे के विरुद्ध जाएगा। सभी मुख्यमंत्रियों ने एक से अधिक बार बैठकें की और इस बात को भारत के प्रधानमंत्री के पास प्रस्तुत किया। यदि मुझे ठीक से याद है तो आज तक इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। क्या माननीय मंत्री स्थिति स्पष्ट करेंगे? अब क्या स्थिति है? इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई निर्णय लेने से पहले क्या सभी राज्यों के उस विवाद का अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा जिसका मैंने उल्लेख किया है? सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि संबंधित राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए हमारे संविधान में की गई संवैधानिक व्यवस्था को हानि न पहुंचे।

श्री बी.के. हान्डिक : महोदय, माननीय सदस्य यह बात याद रखें कि यह प्रश्न इस सभा में अनेक बार उठाया गया है। हमने उस समय भी आश्वासन दिया था, अनेक बैठकें हुई हैं। माननीय सदस्य को स्वयं पता है कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई थी। सभी से विचार विमर्श करने के बाद हमने राष्ट्रीय खनिज नीति बनाई। होडा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद नीति को अंतिम रूप दिया गया है – होडा समिति ने बहुत अच्छी सिफारिशें की हैं। स्वाभाविक है कि ये संसद के सामने आएंगी। आपके पास वाद-विवाद करने के लिए पर्याप्त समय है...*(व्यवधान)* लेकिन जहां तक विचार-विमर्श का संबंध है मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि विचार-विमर्श अनेक बार किया गया है। उन्हें स्वयं याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री भी उनसे मिले थे एवं उनसे मंत्रणा हो रही थी...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन चरण सेठी : इसके क्या परिणाम निकले? क्या सरकार ने संबंधित राज्यों के विवाद पर विचार किया है? होडा समिति की विशेष सिफारिशों का क्रियान्वयन करते समय क्या भारत सरकार ने संबंधित राज्यों के हितों को ध्यान में रखा है? क्या संबंधित राज्यों के हितों की रक्षा की जाएगी?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों की तरफ से कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री बी.के. हान्डिक : महोदय, हमारा उद्देश्य प्रत्येक राज्य के हितों की रक्षा करना है।

श्री बसुदेव आचार्य : हमारे देश से काफी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात होता है यद्यपि अनेक लौह एवं इस्पात संयंत्रों की स्थापना की जा रही है और समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया गया है एवं उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए है। वर्ष 2007-08 में 89 मिलियन टन लौह अयस्क का निर्यात किया गया। अगले वर्ष कुछ मंदी आई क्योंकि श्री चिदम्बरम ने लौह अयस्क के निर्यात पर 500 रुपये प्रति टन ड्यटी लगा दी। अत: कुछ मंदी आई लेकिन इसके बाद यह मंदी कम हुई एवं निर्यात में वृद्धि हुई। हमारे देश से लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग है क्योंकि उन देशों में प्रतिबंध है जो हमारे देश से लौह अयस्क का आयात कर रहे हैं। वे अपने लौह अयस्क का निर्यात नहीं कर रहे हैं। उनके पास अच्छी गुणवत्ता वाले लौह अयस्क का भण्डार है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि सरकार स्वदेशी उद्योगों की रक्षा करने के लिए अपने देश से लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी?

श्री बी.के. हान्डिक : हमने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है। अत:, निश्चय ही यह एक सुझाव है जिस पर हम विचार करेंगे। मेरा केवल यह कहना है कि "हम विचार करेंगे।" वर्ष 2008-09

में 204 मिलियन टन उत्पादन हुआ था एवं उपभोग 89 मिलियन टन हुआ था। अत:, वास्तव में इसकी कोई कमी नहीं थी। इसलिए, लौह अयस्क का निर्यात किया जा सकता था...*(व्यवधान)* लेकिन इस तथ्य के बावजूद, माननीय मंत्री कहते हैं कि वे चाहते हैं कि इस पर प्रतिबंध लगे। जब भी किसी माननीय सदस्य से सुझाव प्राप्त होता है हम इस पर विचार करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। हम इसका अध्ययन करेंगे। यदि यह स्वीकार्य होगा तो हम इसका चयन करेंगे तथा यदि यह स्वीकार्य नहीं होगा तो हम इसका चयन नहीं करेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मैं आपसे इस पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री बी.के. हान्डिक : मैं इस पर केवल विचार नहीं करूंगा बल्कि अत्यंत गंभीरता से विचार करूंगा।

[हिन्दी]

सर्विस लेन का निर्माण

*242. **श्री राकेश सिंह :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का विचार आगामी सड़क परियोजनाओं में सर्विस लेन तथा फ्लाई ओवरों को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का विचार चार लेन वाली सड़कों के बजाय दो लेन वाली सड़कों का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस कदम से यातायात के सुचारु संचालन में बाधा आने तथा भारी मोटर यातायात के आवागमन पर दबाव पड़ने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) से (च) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाने का कार्य उन खंडों में करता है जिनमें यातायात की मात्रा की दृष्टि से बीओटी आधार पर चार लेन बनाया जाना व्यावहारिक नहीं है। ऐसी सड़कों पर यातायात की कम मात्रा को देखते हुए, यातायात के निर्बाध आवागमन में बाधा आने की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत देश की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, उसके कार्य करने की गति अत्यंत धीमी है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना देश की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत छ: लेन रोड का निर्माण होना है। मध्य प्रदेश, जहां से मैं चुन कर आया हूं और मंत्री जी, आप भी आए हैं, जो केन्द्र में स्थित है और भेदभाव का शिकार है, एक किलोमीटर हिस्सा भी वहां से होकर नहीं गुजर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि छ: लेन रोड मध्य प्रदेश में बननी संभव हीं नहीं होगी। ऐसे ही ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर और नार्थ-साऊथ कोरीडोर, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, इन दोनों को अगर मिला लें तो मात्र 621 किलोमीटर सड़कें उस प्रदेश में, जहां देश के 17 राजमार्ग होकर गुजरते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सवाल पूछें।

श्री राकेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पर ही आ रहा हूं, यह उसी से जुड़ा हुआ है, इसके बिना बात पूरी नहीं होगी। उसमें से मात्र 621 किलोमीटर सड़कों का निर्माण वहां होना है। उसमें से भी मात्र 43 किलोमीटर का काम ही प्राधिकरण अभी तक पूरा कर पाया है। इस तरह जबलपुर से भोपाल 303 किलोमीटर है, उसे सन् 2004 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दो लाईन से चार लाईन में बदलने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। उस पर भी अभी तक काम प्रारंभ नहीं हो सका है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण महाकौशल सहित पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश का जो सबसे प्रमुख शहर जबलपुर है, जो मेरा और आपका दोनों का ही संभागी मुख्यालय है, उसे नार्थ-साऊथ कोरीडोर से जोड़ने के लिए जबलपुर से मात्र 85 किलोमीटर की दूरी पर लखनादोन स्थित, जो एन एच 7 पर है, उसे क्या दो लेन से चार लेन में बदलने का निर्णय सरकार लेगी?

श्री कमल नाथ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, खास कर महाकौशल क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश में है, मेरी चिन्ता उनसे कम नहीं है, मेरी भी उतनी ही चिन्ता है, क्योंकि यह क्षेत्र मेरा अपना क्षेत्र भी है। जहां तक दो, चार और छः लेन का प्रश्न है, यह ट्रेफिक पर आधारित है। इसका एक फार्मूला बनाया है कि कितने ट्रेफिक में दो, चार और छः लेन होगी, क्योंकि सीमित संसाधनों में हमें यह देखना है कि जहां ट्रेफिक की क्षमता 15 या 20 साल बाद चार या छः लेन की होगी, वहां अभी चार लेन बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमने ये नियम बनाए हैं कि जहां ट्रेफिक 15 हजार पीसीयू से कम है, उसे हम अभी दो लेन में करेंगे, दो लेन का मतलब दस मीटर है। दस मीटर की सड़क बनाई जाएगी। 15 हजार पैसेंजर कार यूनिट्स का हमने मापदंड बनाया है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि जहां-जहां देश में आज ट्रेफिक के आधार पर आवश्यकता है, यातायात क्या सहन कर सकता है? इसमें जो भी सुविधा हो - चाहे सर्विस लेन की, फ्लाईओवर की या अंडर पास की हो, यह सड़क पर ट्रेफिक की जो केपेसिटी है, उस पर आधारित है। उसे देखते हुए यह निर्णय किया जाता है। माननीय सदस्य ने जो भोपाल-जबलपुर और रीवा-जबलपुर की बात की है, इस बारे में मैंने मध्य प्रदेश सरकार से बात की है। उन्होंने हमें कहा है कि भोपाल-जबलपुर, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन को दे दी जाए, मैं उस प्रस्ताव का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही उनका प्रस्ताव आएगा, उस पर हम विचार करेंगे।

श्री राकेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी को उस क्षेत्र की बराबर चिन्ता है, क्योंकि वह उनका अपना क्षेत्र भी है। मैंने पहले ही प्रश्न में पूछा था कि क्या जबलपुर से लखनावन जो टू लेन है, उसे फोर लेन करने के बारे में विचार करेंगे, उसका उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला है, उसका उत्तर वे दे दें।

मेरा कहना है कि पिछले पांच वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार ने सड़कों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लिया है। ऐसी सड़कें जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य परियोजनाओं में शामिल नहीं हैं, उनके बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने जन-संकल्प 2008 के माध्यम से निर्णय लिया है कि सभी संभागीय मुख्यालयों को आपस में फोर लेन रोड से जोड़ा जाए। इसके लिए 1267 किलोमीटर सड़कों के विस्तार और उन्नयन का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है, यानी उनके मंत्रालय को प्रेषित किया गया है। माननीय मंत्री जी, मैं ऐसा मानता हूं कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि किसी प्रदेश के विकास में सड़कों का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। विशेष रूप से जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो आजादी के बाद से लगातार वह उपेक्षित क्षेत्र रहा है और सड़कों के मामले में तो वह बहुत ही पिछड़ा रहा है। इसलिए ऐसे प्रदेश के लिए इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी देने का काम क्या केन्द्र सरकार करेगी?

श्री कमल नाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले डेढ़ महीने में मैंने मध्य प्रदेश सरकार के साथ मीटिंग्स की हैं और हम योजनाएं बना रहे हैं, ताकि मध्य प्रदेश में जो सड़कों की गति कम रही है, उसे बढ़ाया जा सके और जहां ऐसा अहसास होता है कि वह अपेक्षित रहा है, तो मुझे भी इस बारे में चिन्ता है। मैं बताना चाहता हूं कि सी.आर.एफ. (सेंट्रल रोड फंड) की बात हो, नेशनल हाईवे योजनाओं की गति बढ़ाने की बात हो, उसे आवश्यक प्राथमिकता मिलेगी।

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विश्वस्तरीय सड़कों का निर्माण करके इतिहास बनाया है। लेकिन महोदय अनेक स्थानों पर, अनेक सड़कों पर महत्वपूर्ण जगहों पर मार्ग परिवर्तन (डाइवर्जनों) के बारे में पर्याप्त साइनबोर्ड नहीं लगाए गए हैं जिनके परिणामस्वरूप घातक दुर्घटनाएं हो रही हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह संपूर्ण भारत में टेलीविजन चैनलों के माध्यम से, अपने मंत्रालय के माध्यम से यातायात के नियमों को लोकप्रिय बनाने तथा सड़कों, मार्ग परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करने इसके साथ-साथ मोटरसाइकल सवारों, साइकिल सवारों और पैदलयात्रियों द्वारा नई मार्ग परिवर्तित सड़कों पर एहतियाती उपायों के लिए कदम उठाएं ताकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत बनाई गई नई सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके?

श्री कमल नाथ : सुरक्षा एक बड़ा कारण है। सभी सड़क परियोजनाओं में सुरक्षा चिंताओं के साथ-साथ पर्यावरणीय चिंताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान संकेतों और लोगों को जागरूक करने के प्रश्न की ओर आकृष्ट किया है। इसके लिए अनेक पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यदि संकेत ही मुद्दा है तो मुझे बहुत खुशी होगी।

श्री एन.एस.वी. चित्तन : टी.वी. चैनलों के माध्यम से।

श्री कमल नाथ : जहां तक संकेतों का संबंध है, यदि माननीय सदस्य मेरा ध्यान ऐसे किसी विशेष मामले की ओर आकृष्ट करेंगे जहां संकेतों की आवश्यकता है तो मुझे वह कार्य कराने में बहुत खुशी होगी। दूसरी तरफ जहां तक लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों के बारे में जागरुक करने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेने का संबंध है तो हम इस पर विचार करेंगे। लोगों को जागरूक करने की अनेक पद्धतियां हैं कौन-सा तरीका सबसे सही है; हमें उस पर गौर करना होगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य की सिफारिशों को ध्यान में रखूंगा।

[हिन्दी]

श्री गोरखनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने सड़कों के चौड़ी करने, यानी दो लेन से चार लेन की करने के बारे में अपने उत्तर में कहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग जी.टी. रोड है, जो इलाहाबाद से बनारस के बीच में, जो दो लेन से चार लेन प्रस्तावित थी, वह अभी तक नहीं बन पाई है। उसके कई कारण हैं, जैसे कहीं नगर हैं, कहीं बाजार है, कहीं शहर है, जिनकी वजह से उनके किनारे जो बिल्डिंग्स बनी हैं, वे तोड़ी नहीं जा सकीं, जबकि अब तक उसे दो से चार लेन की बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। उसमें देर भी हो रही है। उसे बनाने में कठिनाई भी आ रही है। इसलिए उसके ऊपर फ्लाई ओवर बनाकर उस रोड का काम किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह सड़क जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पेशावर से दिल्ली तक जाती है और उसे दो से चार लेन बनाने की योजना भी है, लेकिन अभी तक वह पूरी नहीं हो पा रही है, तो उन नगरों में जैसे इलाहाबाद और बनारस के बीच में गोपीगंज है, हंडिया, हनुमानगंज और भी कई कस्बे हैं, वहां चार लेन नहीं बन रही हैं, तो उसे क्या फ्लाई ओवर से जोड़कर, उस व्यवस्था को पूरी करेंगे?

श्री कमल नाथ : जब ऐसी सड़क पर एक शहरी क्षेत्र से या बड़े कस्बे से जाती है तो सभी उपायों पर विचार किया जाता है। यह प्रश्न दूसरा है, पर फिर भी माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है तो मैं इसे अवश्य देखूंगा कि इसका सबसे सही उपाय क्या निकल सकता है ताकि इस सड़क की जो समस्या है, इस समस्या का हल निकल सके।

श्री जगदीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार में जो इनके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, व करीब 90 परसेंट जर्जर और खराब स्थिति में हैं। खासकर एक राजमार्ग एन.एच. 110 है। जहानाबाद जो उग्रवाद प्रभावित इलाका है, आदरणीय मैडम सोनिया गांधी भी 1998 में वहां नरसंहार को देखने गई थीं। वह सड़क 110 (अरवल-जहानाबाद-एकन्तूसराय-बिहार शरीफ) राष्ट्रीय राजमार्ग है। आज उस पर चलना दूभर है और आवागमन बिल्कुल बन्द है। एक भी मोटरकार और बस उस पर नहीं चल रही है। राज्य सरकार ने बार-बार भारत सरकार के इनके मंत्रालय को इस बारे में लिखकर भेजा है। हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार बिहार के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, विशेषकर राजमार्ग 110, जो अरवल से जहानाबाद, बिहार से जाता है, उसके चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और जो जर्जर स्थिति में है, उसको तत्काल बनाकर आवागमन चालू करने का विचार रखती है?

श्री कमल नाथ : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग 110 के बारे में जो माननीय सदस्य ने मुझे जानकारी दी है, यह दो लेन से चार लेन हो सकता है, यह मैं नहीं जानता, क्योंकि यह ट्रैफिक की क्षमता पर निर्भर करता है कि कितना ट्रैफिक है। अगर ट्रैफिक 15 हजार पी.सी.यू. से ज्यादा होता है, यह मापदण्ड है, तो इसको दो लेन से चार लेन बनाने का हम जरूर विचार करेंगे।

श्री जगदीश शर्मा : हम दो लेन का ही कह रहे हैं, आप दो लेन ही बनवा दीजिए, हम चार लेन के लिए नहीं कह रहे हैं।

श्री कमल नाथ : मैं उसी पर आ रहा हूं। माननीय सदस्य ने कहा है कि इस राजमार्ग की मरम्मत की आवश्यकता है, इसकी रिपेयर की आवश्यकता है। मैं इसको जरूर प्राथमिकता दूंगा।

डॉ. संजीव गणेश नाईक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय महामार्ग एन.एच.-4 मुम्बई का सबसे बड़ा ट्रैफिक वाला इलाका है, जहां से मुम्बई में करीब-करीब लाखों की संख्या में ट्रक्स आते हैं। वहां ब्रिज का कोई नया एलाइनमेंट नहीं किया गया है। हमने अधिकारियों से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में कोई सोच-विचार नहीं किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानकारी लेना चाहूंगा कि इस बारे में कोई दोबारा सर्वेक्षण कराने का विचार है?

श्री कमल नाथ : इस राजमार्ग के बारे में, जो माननीय सदस्य ने कहा है, मुझे जानकारी नहीं है। मैं उनको जानकारी भिजवा दूंगा।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि झारखंड राज्य में कोलकाता से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली जो 4 लेन सड़क है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सब तरफ देख रहा हूं और सब को एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : उसे समय सीमा के अंतर्गत जो पूर्ण होना था, वह अभी भी अपूर्ण है। उस 4 लेन रोड पर इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कि हमें लगता है कि एक महीने में वहां पचासों लोग एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह होगा कि कब तक वहां 4 लेन सड़क का निर्माण करवाइएगा? मंत्री महोदय, हमें ऐसी जानकारी है कि उसको दो वर्ष पहले ही पूर्ण होना था। उसमें काम की क्वालिटी भी ठीक नहीं है।

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य ने एक सड़क के बारे में जानकारी दी है। यह बात सही है कि बहुत सारी सड़कों में आज के दिन कुछ डिले हुई है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज सड़कों के लिए लैंड एक्विजीशन की है।...*(व्यवधान)*

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : मंत्री महोदय, सड़क का काम चल रहा है। एक हाई-वे है, कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक, नेशनल हाई-वे नंबर टू है, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कहीं पर लैंड एक्विजीशन का कोई मामला नहीं है, वहां काम चल रहा है।

श्री कमल नाथ : इसके प्रत्येक सड़क के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि यह प्रश्न...*(व्यवधान)* मैं आपको बात रहा हूं।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह राष्ट्रीय राजमार्ग है।

श्री कमल नाथ : यह एनएच टू है, पर यह जो स्ट्रेच है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा है कि इसमें देरी हुई है। मैं एक जनरल बात कह रहा हूं कि देरी का एक प्रमुख कारण है कि लैंड एक्विजीशन की समस्या होती है। किसी सड़क को अगर दो लेन से चार लेन करना है, तो लैंड एक्विजीशन होता है।...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : सब कुछ हो गया है। काफी कुछ कंपलीट हो गया है, केवल कुछ पार्ट में इनकंप्लीट है। भूमि अधिग्रहण कोई समस्या नहीं है।

श्री कमल नाथ : अगर इस सड़क में लैंड एक्विजीशन की समस्या नहीं है, तो मैं उस पर आवश्यक कार्यवाही कराऊंगा।... *(व्यवधान)*

श्री अखिलेश यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जी.टी. रोड ऐतिहासिक सड़क है, जो शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गयी, इसमें आधी सड़क सिक्स-लेन हो चुकी है, कुछ जगह फोर-लेन भी हो चुकी है। कानपुर से लेकर मुगलसराय और बिहार तक के लिए फोर-लेन और सिक्स-लेन का काम चल रहा है। लेकिन कानपुर से पीछे, कन्नौज जहां मेरा संसदीय क्षेत्र आता है, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, होकर दिल्ली तक के रास्ते के लिए अभी तक सिक्स-लेन या फोर-लेन करने की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसको फोर-लेन या सिक्स-लेन बनाने की कृपा करेंगे?

श्री कमल नाथ : ट्रैफिक के आधार पर मैंने जो सीमायें बतायी हैं, अगर ट्रैफिक की क्षमता होगी, मैं नहीं जानता क्योंकि मुझे उस क्षेत्र की...*(व्यवधान)*

श्री अखिलेश यादव : कानपुर से लेकर मुगलसराय तक का तो फार्मूला ठीक है, लेकिन आपका वही ट्रैफिक का फार्मूला कानपुर से आगे क्यों ठीक नहीं है?...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ : यह प्रश्न सर्विस लेन के बारे में है, एक-एक सड़क के बारे में नहीं है। अगर माननीय सदस्य मेरा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो मैं इस पर आवश्यक ध्यान दूंगा। यह फार्मूला के मुताबिक है कि छः लेन होने हैं, उसमें वह क्षमता है कि वहां छः लेन हो सकते हैं। हमें यह देखना है कि इसमें ट्रैफिक की क्या क्षमता है?...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : महोदय, हमें इस पर आधे घंटे की चर्चा कराए जाने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। आप इस पर आधे घंटे की चर्चा करा लीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिए। अगर नोटिस देंगे, तो विचार किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

बॉक्साइट की उपलब्धता

***243. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में एल्यूमीनियम आधारित उद्योग बॉक्साइट की कमी के कारण प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सभी क्षेत्रों को बॉक्साइट की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश में बॉक्साइट की नई खानों/भंडारों की खोज/दोहन के लिए सर्वेक्षण किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो बॉक्साइट खानों के सर्वेक्षण/खोज तथा दोहन के कार्य में शामिल की गई एजेंसियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारत में एल्युमीनियम के पांच मुख्य उत्पादक नामत: नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लि. (नालको), भारत एल्युमीनियम कंपनी लि. (बालको), हिंडालको उद्योग लि., मद्रास एल्युमीनियम कंपनी लि. (मालको) तथा वेदांता एल्युमीनियम लिमिटेड (वाल) है जिनमें से केवल नालको ही सार्वजनिक क्षेत्र में है। ये उत्पादक अपनी एल्युमिना शोधनशालाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बॉक्साइट या तो अपनी गृहीत खानों से प्राप्त करते हैं अथवा बाजार स्रोतों से खरीदते हैं। देश में उपर उल्लिखित पांच उत्पादकों की एल्युमिना शोधनशालाओं की कुल संस्थापित क्षमता 2008-09 के दौरान लगभग 4 मिलियन टन प्रतिवर्ष थी। 4 मिलियन टन एल्युमिना के उत्पादन के लिए औसतन 12 मिलियन टन बॉक्साइट की जरूरत होती है। 2008-09 के दौरान मैटेलर्जिकल बॉक्साइट का घरेलू उत्पादन 11.99 मिलियन टन था। छत्तीसगढ़ सहित बॉक्साइट के राज्यवार संसाधनों तथा बॉक्साइट उत्पादन का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है।

जैसा कि अनुबंध-I से देखा जा सकता है, एल्युमिना/एल्युमीनियम उत्पादकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिन्हें बॉक्साइट की व्यवस्था या तो अपने आप खनन करके अथवा बाजार स्रोतों से बॉक्साइट खरीदकर करनी पड़ती है, देश में बॉक्साइट के पर्याप्त संसाधन हैं। बाजार से बॉक्साइट का अधिप्रापण एक वाणिज्यिक निर्णय होता है जो संबंधित कंपनी द्वारा लिया जाता है। तथापि कोई कंपनी/ व्यक्ति बॉक्साइट का खनन करना चाहता हो, उसे खनन पट्टा प्राप्त करना होता है। खनन पट्टे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) (एम एम डी आर) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत मंजूर किए जाते हैं। भारत सरकार की पूर्व अनुमति बॉक्साइट सहित एमएमडीआर एक्ट, 1957 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित खनिजों के मामले में अपेक्षित होती है।

(ग) और (घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई), खनिज गवेषण निगम लि. (एम ई सी एल), अलग-अलग राज्यों के भूविज्ञान एवं खान निदेशालयों (डी जी एम) आदि जैसी अलग-अलग एजेंसियों द्वारा बॉक्साइट सहित खनिजों का सर्वेक्षण तथा गवेषण कार्य किया जाता है। अलग-अलग एजेंसियों द्वारा बॉक्साइट के संबंध में वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान किए गए ऐसे सर्वेक्षणों/गवेषण कार्यकलापों का ब्यौरा संलग्न विवरण अनुबंध-II में दिया गया है। वर्ष 2008-09 के दौरान देश में 72 एजेंसियां/पट्टाधारी 191 खानों से बॉक्साइट का दोहन कर रहे थे।

अनुबंध-I

1.4.2005 की स्थिति के अनुसार बॉक्साइट का भंडार (संसाधन) (राज्य-वार)

(मिलियन टन में)

राज्य	भंडार	शेष संसाधन	कुल संसाधन
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	0.25	615.02	615.27
बिहार	0	4.11	4.11
छत्तीसगढ़	88.97	59.35	148.32
गोवा	34.63	15.73	50.36

1	2	3	4
गुजरात	68.21	120.12	188.33
जम्मू और कश्मीर	0	2.02	2.02
झारखंड	31.66	85.89	117.55
कर्नाटक	5.73	43.77	49.50
केरल	0.06	14.04	14.10
मध्य प्रदेश	16.84	117.23	134.07
महाराष्ट्र	39.16	72.49	111.65
उड़ीसा	608.00	1200.27	1808.27
राजस्थान	0	0.53	0.53
तमिलनाडु	5.89	20.95	26.84
उत्तर प्रदेश	0	18.91	18.91
कुल योग	899.40	2390.43	3289.83

आंकड़े पूर्णांकित किए गए हैं

स्रोत : भारतीय खान ब्यूरो

बॉक्साइट का राज्यवार उत्पादन 2008-09*

(मिलियन टन में)

राज्य	उत्पादन
छत्तीसगढ़	1.67
गोवा	0.51
गुजरात	3.52
झारखंड	1.62
कर्नाटक	0.14
मध्य प्रदेश	1.13
महाराष्ट्र	1.98
उड़ीसा	4.70
तमिलनाडु	0.27
कुल योग	15.54**

*अनंतिम

**इनमें से मैटेलर्जिकल ग्रेड बॉक्साइट 11.99 मिलियन टन।

स्रोत : भारतीय खान ब्यूरो

अनुबंध-II

बॉक्साइट के लिए गवेषण कार्यकलाप के ब्यौरे (2005-06 से 2007-08)

एजेंसी	अवस्थिति		अनुमानित भंडार/संसाधन
	क्षेत्र/ब्लॉक	जिला/पुरुष	
1	2	3	4
		2005-06	
डी जी एम, छत्तीसगढ़	पाथरिया क्षेत्र, मैनपट, प्लैट्यू	सरगुजा (छत्तीसगढ़)	5.0 लाख टन भंडार आंकलित

1	2	3	4
	कदमपेठ कानपट जमुनिया ब्लॉक	जसपुर (छत्तीसगढ़)	5.0 लाख टन भंडार आंकलित
डी जी एम, उड़ीसा	अरामा रामगढ़	कोरापुट (उड़ीसा)	#
एम ई सी एल	सरेनगडाग ब्लॉक	गुमला (झारखंड)	15.44 मिलियन टन भंडार आंकलित
		2006-07	
जी एस आई	काडलिया ब्लॉक	केन्दुझाड़ (उड़ीसा)	1.97 मिलियन टन भंडार आंकलित
डी जी एम, छत्तीसगढ़	पाथरिया के पश्चिम में बॉक्साइट डिपाजिट का विस्तार	सरगुजा (छत्तीसगढ़)	6.0 लाख टन का भंडार आंकलित
	बंधाटोला क्षेत्र	कबीरधाम (छत्तीसगढ़)	बुलडुंला तथा अकालगढ़ी क्षेत्र में 55 लाख टन अनुमानित श्रेणी आंकलित
	कावर्धा और पनडारिया तहसील	कबीरधाम (छत्तीसगढ़)	110 लाख टन न्यून अनुमानित श्रेणी भंडार
डी जी एम, उड़ीसा	टाडापानी निकट रामगढ़	कोरापुट (उड़ीसा)	#
		2007-08	
डी जी एम, उड़ीसा	उषाबाली प्लेट्यू	कंधमाल (उड़ीसा)	बॉक्साइट के 10 मिलियन टन (अनंतिम) संसाधनों का अनुमान लगाया गया था।
डी जी एम, छत्तीसगढ़	बंधाटोला	कबीरधाम (छत्तीसगढ़)	बॉक्साइट के कुछेक प्रस्फुटन नोट किए गए
डी जी एम, महाराष्ट्र	घूंगर	कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	2.8 मिलियन टन बॉक्साइट संसाधन तथा 4 मिलियन टन लेटराइट संसाधन आंकलित किया गया।
डी जी एम, गुजरात	भाटिया के इर्द-गिर्द	जामनगर (गुजरात)	17 बार होल किए गए परन्तु नतीजा नकारात्मक रहा।

#18.66 मिलियन टन (अनंतिम संसाधन)

[हिन्दी]

श्री प्रभातसिंह पी. चौहान : महोदय, मैं बॉक्साइट के संबंध में कहना चाहता हूं। गुजरात, बॉक्साइट के क्षेत्र में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरे क्रमांक वाला स्टेट है। क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग लिखकर देंगे, तो विचार होगा। प्रश्न के अलावा कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी

*(व्यवधान)**

श्री प्रभातसिंह पी. चौहान : क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि गुजरात में बॉक्साइट की ओर-खदानों के बारे में केंद्र सरकार की क्या योजना है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बी.के. हान्डिक : मैं उनका प्रश्न नही समझ पाया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप दोबारा प्रश्न करिए।

श्री प्रभातसिंह पी. चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गुजरात बॉक्साइट के संबंध में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरे नंबर का स्टेट है। क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि गुजरात में बॉक्साइट की ओर-खदानों के बारे में केंद्र सरकार की क्या योजना है?

[हिन्दी]

श्री बी.के. हान्डिक : महोदय मैं समझता हूं कि वे यह जानना चाहते हैं कि क्या देश में पर्याप्त बॉक्साइट है...*(व्यवधान)* क्या यही बात है?...*(व्यवधान)* आप गुजरात के बारे में पूछ रहे हैं। महोदय, माननीय सदस्य वास्तव में क्या जानना चाहते हैं?...*(व्यवधान)* क्या वे यह जानना चाहते हैं कि हमारे पास कोई योजना है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या गुजरात में बॉक्साइट के आधार पर केन्द्र सरकार ने कारखाना खोलने के लिए कोई योजना बनाई है?

[अनुवाद]

श्री बी.के. हान्डिक : महोदय, मंत्रालय को लोक सभा के माननीय सदस्य श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें गुजरात के जामनगर जिले में बॉक्साइट खानों को बंद किए जाने के बारे में जांच की मांग की गई है। वास्तव में हमने इसमें पूरी रुचि दिखाई है कि गुजरात में वास्तव में जो बॉक्साइट है उसे संरक्षित किया जा सके। यह मामला है। गुजरात सरकार निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहती है जिससे वास्तव में यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। मंत्रालय से हमने कई बार सरकार को यह सुझाव दिया है बॉक्साइट की बिक्री तथा निर्यात पर कई लोगों की आजीविका निर्भर करती है। बॉक्साइट खनन के बारे में राज्य नीति पर पुनर्विचार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि बॉक्साइट खनन कार्यों को पुनः शुरू किए जाने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया जा सके तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा सकें कि राज्य में बॉक्साइट खनन शीघ्र आरंभ हो सके।

महोदय, वास्तव में वे बॉक्साइट का खनन अथवा निर्यात करने की अनुमति नहीं देते हैं क्योंकि वे इसे भविष्य में गुजरात में विकास के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। गुजरात में बॉक्साइट भंडार है। देश में बॉक्साइट भंडार है। इस संबंध में कोई समस्या नहीं है। वास्तव में, हमारे पास पर्याप्त बॉक्साइट है। अभी हमारे पास आवश्यकता से अधिक है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभातसिंह पी. चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बॉक्साइट के खदानों में हो रही धांधली को रोकने के लिए केन्द्र सरकार की क्या योजना है?

[अनुवाद]

श्री बी.के. हान्डिक : मुझे खेद है कि मैं उनका प्रश्न नही समझ सका...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वे यह जानना चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार के पास गुजरात में इस खामी में सुधार के लिए कोई कार्यक्रम है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बी.के. हान्डिक : महोदय, सरकार के पास बॉक्साइट के संबंध में अभी कोई योजना नहीं है। भारत में एल्युमीनियम के पांच प्राथमिक उत्पादक हैं– नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड... *(व्यवधान)* बॉक्साइट पर उत्तर देने के लिए मुझे एल्युमीनियम कंपनियों से जानकारी लेनी होगी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप शान्ति से सुनिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी.के. हान्डिक : महोदय, ये कंपनियां हैं– नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, मद्रास एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड तथा वेदान्ता एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड। वास्तव में हमारी खनिज नीति में अवैध खनन को रोकने के लिए प्रावधान हैं...*(व्यवधान)*

मैं इसका ब्यौरा देता हूं...*(व्यवधान)* यदि अवैध रूप से खनन किया जा रहा है तो हमें उसे रोकना होगा। सांविधिक उपबंध के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पट्टाधारक को विधिवत रूप से प्रदत्त निष्पादित तथा पंजीकृत खनन पट्टे के बिना किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जा सकता...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : इसे रोकने के लिए क्या कानून है? इसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। यही प्रश्न हैं। आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग शोरगुल मत कीजिए। मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी.के. हान्डिक : महोदय, इनका कहना है कि कानून का उल्लंघन हो रहा है। यदि इसका उल्लंघन हो रहा है...*(व्यवधान)* मैं पहले ही कह चुका हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप लोग चुप हो जाइए। मंत्री जी को सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी.के. हान्डिक : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग शांत रहिए और बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रमेश बैस।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ है। आप उनका जवाब तो आने दीजिए। इसके बाद आप क्वैश्चन पूछने के लिए बुलाइये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। वैसे भी मंत्री जी जवाब देंगे, आप नहीं देंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, वह बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग शांति बनाये रखिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी.के. हान्डिक : महोदय, गुजरात में अवैध खनन का यह

प्रश्न उनके द्वारा पूछे गए मुख्य प्रश्न से अलग है। इसलिए, इसके लिए हमें एक अलग नोटिस की आवश्यकता है।

महोदय, इस तथ्य के बावजूद कि इसके लिए एक अलग नोटिस की आवश्यकता है, मैंने उत्तर देने का प्रयास किया परंतु इन्होंने मुझे बोलने ही नहीं दिया। यही समस्या है।

[हिन्दी]

श्री रमेश बैस : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बॉक्साइट एल्युमीनियम बनाने के काम आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि यदि कोई व्यक्ति प्लांट न डालकर बॉक्साइट की लीज लेना चाहे, तो क्या सरकार उसे लीज देगी?

[अनुवाद]

श्री बी.के. हान्डिक : यदि यह बॉक्साइट का अन्वेषण अथवा दोहन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम इसको अनुमति देंगे *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो क्वैश्चन पूछा है, और मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, आप इन दोनों का मिलान करा लीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप शांत रहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के (ग) भाग में पूछा गया है कि क्या देश में बॉक्साइट की नई खानों/भंडारों के अन्वेषण/दोहन हेतु सर्वेक्षण कराए गए हैं। इस संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि पांच दशक बीत जाने के बाद भी देश में खनिजों के बारे में कोई पूर्ण सर्वेक्षण नहीं कराया गया है और न ही सर्वेक्षण मानचित्र को अंतिम रूप दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने सभा पटल पर रखे गए अपने उत्तर में जिस सर्वेक्षण का उल्लेख किया है वह एक सामान्य अथवा नियमित आधार पर कराया गया सर्वेक्षण है।

मैं जिस राज्य से हूं वहां 14 मिलियन टन बॉक्साइट अयस्क का भंडार है। यह प्रारंभिक निष्कर्ष है, परन्तु इस अयस्क का आर्थिक दोहन नहीं किया गया है तथा भारतीय भू-सर्वेक्षण अथवा खान एवं खनिज विकास निगम द्वारा कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं कराया जा रहा है। मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषण प्रयोजनों हेतु पुरानी पड़ चुकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। खनिज किसी भी देश की मुख्य संपदा हैं। क्या मंत्री महोदय भारतीय भू-सर्वेक्षण को बाहर की तकनीकी एजेंसियों के सहयोग से देश की खनिज सम्पदा के बारे में पूर्ण सर्वेक्षण कराने का आदेश देंगे?

महोदय, गहन सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण और अनेक प्रकार के तकनीकी रूप से विकसित सर्वेक्षण प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। अनेक खनिज मौजूद हैं जिनका दोहन नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री पी.सी. चाको : महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। क्या मंत्री महोदय, इस सभा को यह आश्वासन देंगे कि भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा उन तकनीकी एजेंसियों के सहयोग से देश की खनिज सम्पदा के बारे में नया सर्वेक्षण किया जाएगा, जिनके पास नवीनतम जानकारी है और खनिज नक्शा भी प्रकाशित करवाएंगे क्योंकि इससे आगे भी खनिजों का औद्योगिक दोहन संभव हो पाएगा?

श्री भर्तृहरि महताब : शायद, अब माननीय मंत्री जी कहेंगे। कि यह एक राज्य का विषय है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

श्री बी.के. हान्डिक : महोदय, भारतीय भू-सर्वेक्षण (जीएसआई) सभी खनिजों के लिए नियमित सर्वेक्षण करता आ रहा है और वे पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। उन्होंने सभी खनिजों का भूवैज्ञानिक मानचित्र भी तैयार किया हुआ है।

जहां तक बॉक्साइट का संबंध है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे मेरी खातिर यह समझने का प्रयास क्यों नहीं करते कि गुजरात वास्तव में...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अभी प्रश्न गुजरात पर नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री बी.के. हान्डिक : नहीं, मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* मैं दूसरे प्रश्न पर आ रहा हूं...*(व्यवधान)*

भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में कृषि भूमि की खरीद

*244. **श्री एल. राजगोपाल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि कई भारतीय कंपनियां अफ्रीकी देशों में खाद्य वस्तुओं का उत्पादन कर उन्हें भारत को निर्यात करने के लिए बड़े-बड़े कृषि भू-खण्डों की खरीद कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेश स्थिति इन उद्यमों की सहायता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कुछ अफ्रीकी देशों जैसे इथियोपिया और तन्जानिया में वाणिज्यिक कृषि प्रयोजनों हेतु भूमि के पट्टे के माध्यम से भारतीय फर्मों द्वारा वाणिज्यिक अनुबंध करने के संबंध में सरकार को कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इन अनुबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ भारत सहित तृतीय देशों को निर्यात शामिल है। इन सौदों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) ये अधिग्रहण मुख्यतया विकास की इच्छा और मण्डी पहुंच की जरूरत से प्रेरित है और सामान्यतया विदेश में निवेश हेतु सरकार की नीति द्वारा समर्थित है जिसके अनुसार भारतीय कंपनियों को कम्पनी के निवल मूल्य के 400 प्रतिशत तक विदेश में निवेश करने की अनुमति है।

श्री एल. राजगोपाल : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। यह विस्तृत रूप से प्रकाशित हुआ है अर्थात् श्रीमती हिलेरी क्लिंटन का बयान — कि भारत में विश्व की केवल तीन प्रतिशत कृषि भूमि मौजूद है किंतु यहां विश्व की सोलह प्रतिशत से अधिक जनसंख्या मौजूद है।

यह कहा गया है कि भारत सरकार भारतीय कंपनियों द्वारा भूमि संपत्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से विदेश में भूमि अधिग्रहीत करने के लिए भारतीय कंपनियों की सहायता कर रही है। यह नोट कर उत्साहवर्धन हुआ है कि अनेक भारतीय कंपनियों ने विशेषकर इथोपिया, तंजानिया और मेडागास्कर में भूमि अधिग्रहित की है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने ऐसे सौदों पर आपत्ति जताई है जहां अल्प-विकसित राष्ट्रों में भूमि संपत्ति की खरीद नहीं की जा सकती? यदि ऐसा है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार क्या योजना बना रही है?

श्री शरद पवार : हमने किसी भी संगठन की ओर से किसी विरोध के बारे में नहीं सुना है। बल्कि, भारत सरकार अपनी ओर से इस संबंध में कोई पहल नहीं कर रही है क्योंकि विश्वभर में भूमि स्वभाविक रूप से एक राजनैतिक मुद्दा है। अत:, यह एक अति संवेदनशील मुद्दा है।

इसमें दो चीजें जुड़ी हैं। मान लीजिए, हम भारत से बाहर भूमि खरीदने के लिए बढ़ावा दें, तो देश में यह संभावना बन सकती है कि कृषि समुदाय के कतिपय वर्ग अपनी बात रख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि: "हम अनावश्यक रूप से भारत से बाहर निवेश क्यों कर रहे हैं, जब तक कि हम बंजरभूमि को समुचित भूमि का समुचित स्थिति में सफलतापूर्वक परिवर्तित नहीं कर देते।" देश के भीतर यह आपत्ति उठाई जा सकती है।

दूसरे, यदि कोई देश आज या कल या परसों किसी दूसरे देश में व्यापक भूमि खरीद रहा है, तो उस देश के द्वारा कुछ आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इसलिए, कुल मिलाकर भारत सरकार कोई पहल नहीं कर रही है, किंतु निश्चित रूप से हमने सुना है कि कुछ भारतीय कंपनियों ने पहल की है ओर उन्होंने भारत से बाहर कुछ भूमि खरीदी है।

श्री एल. राजगोपाल : माननीय मंत्री जी मैं ये बात जानना चाहता हूं। क्या इथोपिया को कोई ऋण दिया गया है? मुझे बताया गया था कि चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए इथोपिया को 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण दिया गया था, ताकि इसे वापिस भारत को

निर्यात किया जा सके। इथोपिया को दिए गए ऋण के कारण वहां से भारत को कितनी चीनी का निर्यात किया गया है? क्या किसी अन्य राष्ट्र को भी इस प्रकार का ऋण दिया गया है? यदि हां, तो मैं माननीय मंत्री जी से उसके ब्यौरे जानना चाहूंगा।

श्री शरद पवार : वस्तुतः आज की तारीख के अनुसार हम चीनी के निर्यात को कोई बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तकरीबन दो वर्ष पहले जब उत्पादन अधिक हुआ था तो भारत सरकार निर्यात को प्रोत्साहन दे रही थी। परंतु आज स्थिति वैसी नहीं है। आज समग्र उत्पादन में गिरावट आई है और हमारी स्टॉक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए हम इसे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं।

दूसरे, हम सरकार से सरकार आधार पर सीधे आयात नहीं कर रहे हैं। हमने निश्चित रूप से घरेलू चीनी उद्योग को कच्ची चीनी का आयात करने, उसे यहां प्रसंस्कृत करने और अपनी स्टॉक स्थिति को सुधारने के लिए उसे जनता को उपलब्ध कराने की अनुमति दी है। विशेषकर ब्राजील जो कि मुख्य प्रतिभागी है जैसे देशों सहित कई राष्ट्र पहल कर रहे हैं। मुझे इस बात की कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि इथोपिया भारत को किसी प्रकार की चीनी का निर्यात कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि कच्चे म़ाल को मंगाकर, प्रोसेस कराकर, पक्का माल बनाकर यहां बेचा जाए, इसके लिए कुछ कम्पनीज काम कर रही हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वह कच्चे माल को यहां मंगाकर प्रोसेस करके पक्का माल बनाकर बेचेंगे तो बनी बनाई चीनी का आयात क्यों नहीं किया जाता? चाहे नाक इधर से पकड़ो या उधर से, मतलब तो एक ही है। कच्चा माल मंगाओ, प्रोसेस करके बेचो या पक्का माल मंगाकर हिन्दुस्तान में बेचो, एक ही बात है। लेकिन हिन्दुस्तान का जो चीनी उद्योग है और गन्ना उत्पादक हैं, वे क्या करेंगे? हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कई शूगर मिल्स बंद हैं। इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश में जो चीनी के कारखाने बंद हैं, उन्हें खड़ा करने की कोशिश की जाए, ताकि उससे किसान को भी फायदा हो और देश में चीनी का उत्पादन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ चीनी का आयात भी कम होगा। इस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है?

श्री शरद पवार : महोदय, मैंने शुरू में ही कहा था कि इस साल देश में चीनी का उत्पादन कम हुआ है और गन्ने का उत्पादन भी कम हुआ है। इसलिए लोगों की ओर से शिकायत आ रही है कि चीनी के दाम 25, 26, 27 रुपए प्रति किलोग्राम तक और उससे भी ऊपर जा रहे हैं। दो महीने के बाद देश में दशहरा और दीपावली जैसे त्यौहार आएंगे, तब परिस्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इसलिए इस बारे में कुछ न कुछ रास्ता निकाने की आवश्यकता है। रास्ता क्या निकाला जा सकता है, देश में चीनी के स्टॉक की पोजिशन बढ़ाना ही एक रास्ता हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार के सामने दो रास्ते हैं। एक तो यह है कि तैयार चीनी का आयात करके यहां लोगों तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाए। दूसरा रास्ता यह है कि रॉ चीनी यहां लाकर प्रोसेस की जाए और लोगों को अवेलेबल कराया जाए। सरकार ने दूसरा रास्ता स्वीकारा, क्योंकि अगर कच्ची चीनी लाकर यहां प्रोसेस की जाएगी तो देश की इंडस्ट्री की केपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी और यहां के मजदूरों को भी थोड़ा-बहुत काम मिलेगा। इसलिए मिलकर काम करने से परिस्थिति में बदलाव आएगा, इस कारण यह रास्ता स्वीकार किया है। जहां तक मिलें बंद होने का सवाल है, ये मिल्स मैनेजमेंट की समस्या के कारण भी बंद हो सकती हैं। इस पर राज्य सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार किसी बंद पड़ी शूगर मिल को चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेती है, क्योंकि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मगर एक बात है कि शूगर डवलपमेंट नाम का एक फंड है, जिसके माध्यम से चीनी मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए भारत सरकार चार प्रतिशत ब्याज दर पर पैसा देती है। अगर कोई चीनी मिल ज्यादा गन्ना पेरने के लिए सामने आती है तो हम उसे भी इस फंड से चार प्रतिशत की ब्याज दर से पैसा देते हैं। उत्तर प्रदेश से बहुत से प्रस्ताव आए हैं, जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार किया है, लेकिन बिहार की तरफ से एक भी प्रस्ताव नहीं आया...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह : बिहार से भी आया है।...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : नहीं आया है, यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर आया है तो आप मुझे दिखाएं, मैं सदन से माफी मांगूगा कि आया है और हमने उस पर अमल न किया है, लेकिन अगर नहीं आया होगा, तो आप क्या करेंगे, यह आपको बताना होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बिहार की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है। उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, लेकिन बिहार का नहीं है। आएगा तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं।

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. राव : महोदय, देश में तिलहन और दालों की कमी है और हम प्रति वर्ष हजारों करोड़ रुपये के खाद्य तेलों और दालों

का आयात कर रहे हैं। हम कई तरह से मुर्गीपालन, मत्स्यन, डेयरी और कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारा देश कृषि उपकरण बनाने में भी काफी उन्नत है। माननीय प्रधान मंत्री और सोनिया गांधी जी ने गांवों में कृषि मजदूरों को कार्य मुहैया कराने के लिए एनआरईजीएस प्रारंभ की है। जब अफ्रीकी राष्ट्र बेहद उपयुक्त शर्तों पर लाखों एकड़ भूमि मुहैया करा रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री को उसका लाभ नहीं उठाना चाहिए और उसके बाद उन्हें यदि आवश्यक हो तो विदेशी मुद्रा भण्डार से पैसा देकर उन्हें कारपोरेट क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए? इस प्रकार से पारपोरेट क्षेत्र हमारे हजारों कृषकों को उन राष्ट्रों में भेज सकता है और अपने देश में दालों और तिलहनों को सस्ती दरों पर बाजार में मुहैया करवा सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे आगे बढ़ने और बड़ा कदम उठाते हुए विदेशी मुद्रा भण्डार से कारपोरेट क्षेत्र को निवेश मुहैया कराने की दिशा में पहल करेंगे।...*(व्यवधान)*

मध्याहन 12.00 बजे

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। पहले उन्हें जवाब देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री उदय सिंह : मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से सवाल है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, पहले उन्हें जवाब देने दीजिए। दोनों का जवाब तो नहीं होगा।

श्री उदय सिंह : दोनों का जवाब नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि बिहार से सरकार के पास कोई परपोजल नहीं आया। *...(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि बिहार ने परपोजल भेजा है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आपकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*...(व्यवधान)**

श्री शरद पवार : पहले जो सवाल पूछा गया है, उसका जवाब देने की मेरी जिम्मेदारी है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पहले जवाब देने दीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : एक समय में मैं दो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ अनुशासन, कोई तरीका होता है...*(व्यवधान)* विगत दो वर्षों में दालों का कुल आयात तकरीबन 10,000 से 11,000 करोड़ रुपये के बीच रहा है। पिछले वर्ष अन्य देशों से तकरीबन कुल 33,700 करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों का आयात हुआ है। जब हमने भूमि की अनुमति के बारे में चर्चा की तो कई उद्योग संघो द्वारा एक सुझाव दिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि वह भारतीयों को भारत से बाहर जमीन लेने या खरीदने या पट्टे पर लेने और कम से कम उन्हें दाल जो कि देश के आधारभूत मांग है का उत्पादन करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करे। परंतु अभी तक हमने इस दिशा में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय

***245. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में दर्ज घुसपैठ, तस्करी तथा अन्य संबंधित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मामलों में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या विभिन्न अर्ध-सैनिक बलों और इन मामलों से निपटने के कार्य में लगी सुरक्षा एजेंसियों के बीच समुचित समन्वय है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) संबंधित सीमा चौकसी बलों द्वारा अनुरक्षित सूचना के अनुसार सीमा पार की अवैध गतिविधियों और तस्करी तथा संबंधित अपराधों के मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) सीमा पार की अवैध गतिविधियों और/या सीमा पार के अवैध क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करने के दौरान व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के बाद सीमा चौकसी बल इन मामलों पर उपयुक्त कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए इन्हें केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकारों को सौंप देता है। किसी मामले-विशेष में की गई कार्रवाई का ब्यौरा, केन्द्रीय आधार पर नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। अर्द्ध-सैनिक बलों और विभिन्न अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई किए जाने के लिए उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था मौजूद है। प्रत्येक सीमा के लिए एक समर्पित सीमा चौकसी बल है और ऐसे समन्वय के लिए यह अग्रणी आसूचना एजेंजी के रूप में भी कार्य करता है। सीमा पार के अवैध क्रियाकलापों को रोकने के लिए आवधिक निगरानी और बहु/परिचालनात्मक स्तर की बैठकें अयोजित की जाती हैं।

विवरण

सीमा-वार ब्यौरा

भारत-बांग्लादेश सीमा

सीमा चौकसी बल	वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	दर्ज किए गए मामले (तस्करी और अन्य संबंधित अपराध)
सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ)	2006	5130	960
	2007	4206	1114
	2008	2559	1015
	2009 (जून तक)	991	546
	कुल	12886	3635

भारत-पाकिस्तान सीमा

सीमा चौकसी बल	वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	दर्ज किए गए मामले (तस्करी और अन्य संबंधित अपराध)
सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ)	2006	128	45
	2007	128	49
	2008	131	61
	2009 (जून तक)	29	38
	कुल	416	193

भारत-चीन सीमा

सीमा चौकसी बल	वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	दर्ज किए गए मामले
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी)	2006	16	सूचना की अवधि के दौरान आई टी बी पी (सीमा चौकसी बल) की जानकारी में तस्करी और अन्य संबंधित मामला नहीं आया है।
	2007	26	
	2008	01	
	2009 (जून तक)	01	
	कुल	44	

भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा

सीमा चौकसी बल	वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	दर्ज किए गए मामले (मुख्यत: तस्करी संबंधित मामले)
सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी)	2006	—	1327
	2007	—	2111
	2008	—	3023
	2009 (जून तक)	01	1740
	कुल	01	8201

भारत-म्यांमारर सीमा

सीमा चौकसी बल	वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	दर्ज किए गए मामले (मुख्यत: तस्करी संबंधित मामले)
असम राइफल्स	2006	11	26
	2007	07	22
	2008	47	20
	2009 (जून तक)	30	18
	कुल	95	86

मध्यम तथा अल्प अवधि वाली फसलों के बीज

*246. **श्री जगदीश शर्मा :**
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मानसून में हुए विलंब को ध्यान में रखते हुए किसानों को मध्यम तथा अल्पावधि फसलों की किस्मों के बीज उपलब्ध कराए गए है1;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बीजों से खरीफ की फसलों का कुल कितने प्रतिशत उत्पादन होगा: और

(घ) देश में इन बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजानिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) राज्यों द्वारा भारत सरकार को सूचित की गई विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्प एवं मध्यम अवधि फसलों के बीज (उत्तराखंड और बिहार में कुछ स्थानीय किस्मों को छोड़कर)उपलब्ध हैं। बीज की व्यवस्था प्रत्येक कृषि मौसम हेतु इसकी आवश्यकता के आकलन पर प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा की जाती है। खरीफ 2009 के लिए राज्यों द्वारा सूचित की गई कुल राष्ट्रीय आवश्यकता 110.97 लाख क्विंटल है जिसकी तुलना में उपलब्धता 126.51 लाख क्विंटल है। इस तरह से अल्प, मध्यम एवं दीर्घ अवधि सहित 15.54 लाख क्विंटल से अधिक अधिशेष उपलब्ध है।

(घ) भारत सरकार अल्प एवं मध्यम अवधि की किस्मों सहित गुणवत्ताप्रद बीजों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित स्कीमों के तहत बीज संबंधी कार्यकलापों में राज्य सरकारों की सहायता कर रही है:

1. बृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए)
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)
3. समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का (आइसोपाम) स्कीम।
4. कपास प्रौद्योगिकी मिशन।
5. पटसन एवं मेस्ता प्रौद्योगिकी मिशन।
6. गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन व वितरण हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास तथा सुदृढ़ीकरण।
7. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)।

[अनुवाद]

आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करना

*247. **श्री डी.वी. सदानन्द गौडा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीताकान्त महापात्र समिति ने संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए एक सोद्देश्य प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए श्री सीताकान्त महापात्र की अध्यक्षता में सितम्बर, 2003 में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने वर्ष 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

(ग) समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभागों के साथ परामर्श करते हुए विचाराधीन है। आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने की मांग पर विचार करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

कृषि उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

*248. **श्री वरुण गांधी :**
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलवायु परिवर्तन से देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षा प्रभावित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि वैज्ञानिकों से देश की कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में अध्ययन करने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से भारतीय कृषि की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजानिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतरसरकारी पैनल की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट (2007) में प्रक्षेपित किया गया है कि तीन डिग्री तक वैश्विक औसत तापमान में बढ़ोत्तरी से वैश्विक खाद्य उत्पादन की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन इसके अतिरिक्त खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी हो सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) के मॉडलिंग अध्ययनों में भी यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि खाद्यान्नों पर विशेषतौर पर चावल और गेहूं की उत्पादकता और उत्पादन पर तापमान की बढ़ोत्तरी के प्रतिकूल प्रभाव की संभावना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) में दसवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न आईसीएआर संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में ''जलवायु परिवर्तन में भारतीय कृषि का इम्पैक्ट, अनुकूलन और दोषपूर्णता'' संबंधी नेटवर्क परियोजना शुरू की है। परियोजना का उद्देश्य भूमि एवं जल संसाधनों, फसलों पशुधन और मात्स्यिकी इत्यादि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), कटक और चावल अनुसंधान निदेशालय (डीआरआर), हैदराबाद जलवायु परिवर्तन के प्रभावों संबंधी गहन अध्ययन आयोजित करा रहे हैं जिसमें चावल और अन्य फसलों के उत्पादन पर तापमान में बढ़ोत्तरी, कार्बनडाइक्साइड और अन्य गैसें शामिल हैं। गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल का राष्ट्रीय गेहूं कार्यक्रम विशेषतौर पर देर से बुवाई की स्थितियों के लिए उच्च तापमान सह्य गेहूं जीनोटाइप के विकास संबंधी अनुसंधान आयोजित करा रहा है। उच्च तापमान सहय वाले बढ़िया जीनाटाइपों को अभिज्ञात कर लिया गया है और उच्च तापमान वाले वातावरणों के लिए प्रजनक कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है। डब्ल्यूएच 730, एचडी, 2808, आरएजे 3765, एनडब्ल्यू 3765, एनडब्ल्यू 2036, एनडब्ल्यू 1014, एचडब्ल्यू 2045, एचडी 2643 के 8962 जैसी गेहूं की किस्में गर्मी को सहन करने वाली हैं और डीबीडब्ल्यू-14, एक थर्मो सह्य जीनोटाइप का भा.कृ.अनु. परि. द्वारा विकास किया गया है। पृथ्वी विज्ञान ने किसानों के लिए एग्रोमेट परामर्श और जिला स्तर को मौसम पूर्वानुमान जारी करने के लिए ''देश में समेकित एग्रोमेट परामर्शी सेवाएं'' परियोजना भी शुरू की है।

इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्यनीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 30 जून, 2008 को जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी की गई।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किसानों को उन्नत बीज और बेहतर कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिए किसान क्षेत्र स्कूलों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है।

[हिन्दी]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण

***249. श्री प्रहलाद जोशी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु देश के विभिन्न भागों में भूमि का अधिग्रहण किया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि तथा लोगों/किसानों को भुगतान किए गए मुआवजे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी हां। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए राज्य-वार अधिगृहीत की गई भूमि तथा भूमि स्वामियों को मुआवजे की राशि के भुगतान सहित भूमि अधिग्रहण पर किए गए व्यय से संबंधित ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के लिए अधिगृहीत की गई भूमि से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	अधिगृहीत भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)			
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (जून, 2009 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	196.193	361.500	372.907	0.000
2.	असम	763.670	422.360	292.480	39.320
3.	बिहार	131.584	135.452	72.360	0.000
4.	छत्तीसगढ़	0.000	0.000	36.540	0.265
5.	दिल्ली	0.270	0.000	0.180	0.000
6.	गुजरात	161.090	41.066	164.088	0.000
7.	हरियाणा	1.910	58.328	80.073	0.000
8.	जम्मू और कश्मीर	42.500	40.520	1.300	0.000
9.	कर्नाटक	318.304	563.364	148.226	2.350
10.	केरल	355.292	60.784	88.127	50.480
11.	मध्य प्रदेश	1444.360	916.966	537.326	236.250
12.	महाराष्ट्र	8.710	255.050	180.050	9.390
13.	उड़ीसा	6.115	1.813	0.193	3.231
14.	पंजाब	28.593	30.000	131.445	5.122
15.	राजस्थान	1128.076	95.820	29.375	0.000
16.	तमिलनाडु	96.504	184.327	418.079	83.771
17.	उत्तर प्रदेश	707.293	473.911	345.401	15.828
18.	पश्चिम बंगाल	111.230	0.000	2.960	0.000
	जोड़	5501.695	3641.260	2901.100	446-007

विवरण-II

मुआवजे सहित भूमि अधिग्रहण पर व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र.. सं.	राज्य	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (जून, 2009 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	161.26	101.43	37.44	0
2.	असम	151.57	135.97	83.18	37.12
3.	बिहार	26.93	81.61	21.65	0.01
4.	छत्तीसगढ़	0.11	1.89	15.24	0
5.	दिल्ली	0	6.00	3.56	0
6.	गुजरात	31.76	5.3	8.06	0
7.	हरियाणा	0	0	58.3	0
8.	जम्मू और कश्मीर	19.86	232.69	14.97	0
9.	कर्नाटक	25.26	28.70	142.93	30.27
10.	केरल	7.08	121.89	67.66	0.15
11.	मध्य प्रदेश	34.78	52.96	67.87	25.13
12.	महाराष्ट्र	3.72	0.85	46.63	5.88
13.	उड़ीसा	2.06	6.52	0.17	0.03

1	2	3	4	5	6
14.	पंजाब	62.20	61.31	147.78	25.58
15.	राजस्थान	62.29	10.49	88.51	24.79
16.	तमिलनाडु	437.70	254.02	199.17	85.43
17.	उत्तर प्रदेश	84.56	140.33	146.93	87.36
18.	पश्चिम बंगाल	26.21	8.14	18.12	0
	जोड़	1137.35	1250.10	1168.17	321.75

नोट : किसी वित्त वर्ष विशेष में दर्शाया गए व्यय का, उसी वर्ष में अधिगृहीत की गई भूमि से मेल खाना आवश्यक नहीं है क्योंकि मुआवजे का भुगतान, सौंपने की घोषणा, विवादों के निपटारे आदि पर निर्भर करता है और इन कार्यों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही मुआवजे की राशि जारी की जाती है।

[अनुवाद]

सड़कों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पॉलीमर मोडिफाइड बिटुमेन की गुणवत्ता

***250. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में पॉलीमर मोडिफाइड बिटुमेन (पी एम बी) के प्रयोग की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़क परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाला पीएमबी न तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है और न ही भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं जिससे कि इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता से समझौता न हो?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में पॉलीमर संशोधित बिटुमन (पीएमबी) के प्रयोग की अनुमति है। सड़क निर्माण परियोजनाओं में प्रयुक्त किए जाने वाले पीएमबी को भारतीय सड़क कांग्रेस के विशेष प्रकाशन "आईआरसी 53-2002 सड़क निर्माण में पॉलीमर मोडिफाइड बिटुमन के प्रयोग संबंधी दिशानिर्देश" के अनुरूप होना आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं, जिनमें पीएमबी का प्रयोग किया गया है, उपर्युक्त विनिर्देशों को पूरा करती हैं और ये विनिर्देश भारतीय तथा विदेश अनुभव पर आधारित हैं और यह एक प्रकाशित दस्तावेज है। पीएमबी का प्रयोग, निर्मित सड़कों को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए किया जाता है।

दुग्ध उत्पादन

***251. श्री अधलराव पाटील शिवाजी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध उत्पादन हेतु पशुपालन विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभप्रद उद्यम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने दुग्ध उत्पादन को लाभप्रद बनाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों से इस कार्य योजना को कार्यान्वित करने और इसमें सभी दुग्ध उत्पादक संघों को शामिल करने का अनुरोध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजानिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं। दुग्ध उत्पादन के लिए पशुधन पालन लाभप्रद रोजगार सृजित करने और अल्प लागत पोषणिक खाद्यान्न उपलब्ध कराने के अलावा, ग्रामीण क्षेत्र, विशेषकर छोटे और मझोले किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों में पारिवारिक आय की प्रतिपूर्ति करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

(ख) से (ङ) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, यद्यपि पशुपालन और डेयरी राज्य का विषय है, भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास में राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करती है। केन्द्र सरकार पशु रोग नियंत्रण, आनुवांशिक संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और उन्नयन, पोषणिक आहार और चारे की उपलब्धता को बढ़ाने, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं के सतत् विकास तथा पशुधन के उत्पादन और लाभ को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देती रही है।

संगठनों को विदेशी धनराशि

*252. **श्री निशिकांत दुबे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) सहित विभिन्न संगठनों को कुल कितनी राशि का विदेशी अंशदान प्राप्त हुआ;

(ख) क्या ऐसे संगठनों की गतिविधियों और उनके कार्यकरण पर निगरानी रखने और उनकी समीक्षा करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में हाल ही में कोई समीक्षा कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस समीक्षा का ब्यौरा तथा उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत एसोसिएशनों एवं पूर्वानुमति प्राप्त एसोसिएशनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	एसोसिएशनों की संख्या
2005-2006	7877.57
2006-2007	12289.63
2007-2008	9663.46*

*अनंतिम

(ख) से (च) एसोसिएशनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति एवं उसके उपयोग की मानीटरिंग एसोसिएशनों द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षित वार्षिक विवरणियों की संवीक्षा करके की जाती है। अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने की शिकायत या विपरीत जानकारी के मामले में एसोसिएशन की खाताबही एवं अभिलेखों की जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। अगर कोई छोटा उल्लंघन होता है और जहां यह पाया जाता है कि विदेशी अभिदाय का अवांछनीय उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग या विपथन नहीं किया गया है तो मामला दर मामला आधार पर माफी की कार्रवाई पर विचार किया जाता है।

यदि कोई संगठन विदेशी अभिदाय के दुरुपयोग/विपथन के अंतर्ग्रस्त पाया जाता है तो उस एसोसिएशन के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई में (i) एसोसिएशन को पूर्वानुमति श्रेणी में रखना (ii) इसे विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से निषेध करना (iii) विधि के न्यायालय में इस पर अभियोजन करना (iv) इसके बैंक खाते को फ्रीज करना शामिल है। इसके अतिरिक्त गंभीर उल्लंघन के मामले में जहां यह पाया जाता है कि अभिदाय को एसोसिएशन के उद्देश्यों में उल्लिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए विपथित किया जा रहा है तो, इस मामले को, आवश्यक समझे जाने पर, विस्तृत जांच एवं अभियोजन के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) को भेज दिया जाता है।

प्राप्त शिकायतों तथा की गई जांच के आधार पर 41 एसोसिएशनों को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से निषेध किया गया 34 एसोसिएशनों को पूर्वानुमति श्रेणी में रखा गया और 11 एसोसिएशनों के खाते सील कर दिए गए। अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन करने पर जिन एसोसिएशनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई उनकी सूची गृह मंत्रालय की वेबसाइट (httpèmha.nic.inèfcra.htm) पर उपलब्ध है। एफसीआरए का उल्लंघन करने के 13 मामलों को विस्तृत जांच के लिए सी बी आई को भेजा गया है।

कमोडिटी डेरीवेटिव बाजार

*253. **श्री आनंदराव अडसुल** : **क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजानिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कमोडिटी डेरीवेटिव (वस्तु व्युत्पन्न) बाजार के लिए विधिक और विनियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 में संशोधन किया है अथवा संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कमोडिटी डेरीवेटिव बाजार के लिए विधिक और विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वायदा बाजार आयोग को स्वायत्ता प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजानिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (च) अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2008 का प्रख्यापन 31.1.2008 को दिया गया था जिसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

- वायदा बाजार आयोग को स्वायत्तता प्रदान करने के साथ-साथ आयोग का सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन;
- वायदा बाजार आयोग सामान्य कोष का सृजन और वायदा बाजार आयोग को शुल्क वसूली की शक्तियां प्रदान करना;
- मध्यस्थों का पंजीकरण;
- विकल्पों पर से प्रतिबंध हटाना;
- वायदा बाजार आयोग की दाण्डिक शक्तियों में वृद्धि;
- वायदा बाजार आयोग द्वारा निर्णय और जांच; और
- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में पदनामित करना।

उक्त अध्यादेश का स्थान लेने के लिए अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2008 नामक एक विधेयक 13.3.2008 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया। चूंकि लोक सभा में विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी इसलिए अध्यादेश 6 अप्रैल, 2008 को व्यपगत हो गया। अत: अध्यादेश, 2008 का स्थान लेने के लिए लोक सभा में पहले ही पुर:स्थापित अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक 2008 को लेक सभा में पारित करने के लिए विचार किए जाने से पूर्व संशोधित करना अपेक्षित था। इससे पहले कि परिणामी संशोधनों का प्रस्ताव किया जाता 14वीं लोक सभा भंग हो गई। फलत: संविधान के अनुच्छेद 107 (5) के उपबंधों के अनुसार अग्रिम संविदा (विनियमन) विधेयक भी व्यपगत हो गया। अब सरकार को संसद में नया अग्रिम संविदा (विनियमन) विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जिसमें वायदा बाजार आयोग को स्वायत्तता प्रदान करने के साथ-साथ उसके विधायी और विनियामक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान किया जाए। अत: इस प्रयोजन के लिए कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु गेहूं

***254. श्री महेश जोशी** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं के लिए गेहूं की राज्य-वार वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल में गेंहू का कितना भंडार था; और

(ग) सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिए उक्त अवधि के दौरान देश-वार गेहूं की कितनी मात्रा आयात की गई तथा उसकी किस्म क्या थी?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और भारत के महापंजीयक के मार्च, 2000 के आबादी अनुमानों अथवा वास्तव में जारी किए गए ऐसे राशन कार्डों की संख्या, **जो भी कम हो**, के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर किया जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए आबंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टॉक की उपलब्धता और विगत के उठान के आधार पर निर्भर करते हुए किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मध्याह्न भोजन योजना और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम तथा किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन उनसे प्राप्त आवश्यकता अनुसार किया जाता है। गेंहू की आवश्यकता भी आबंटनों में चावल और गेहूं के अनुपात पर निर्भर करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन आबंटनों तथा वर्तमान वर्ष के लिए अनुमानित आवश्यकता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 1-1-2006 से केन्द्रीय पूल में गेहूं के स्टॉक की स्थिति निम्नानुसार रही है:-

निम्न तारीख की स्थिति के अनुसार	गेहूं (लाख टन)
1.1.2006	61.88
1.4.2006	20.09
1.7.2006	82.07
1.10.2006	64.12
1.1.2007	54.28
1.4.2007	47.03
1.7.2007	129.26
1.10.2007	101.21
1.1.2008	77.12
1.4.2008	58.03
1.7.2008	249.12
1.10.2008	220.25
1.1.2009	182.12
1.4.2009	134.29
1.7.2009	329.22

(ग) 2006-07 और 2007-08 के दौरान आयातित गेहूं के ब्यौरे नीचे दिए हैं। 2008-09 के दौरान गेहूं का कोई आयात नहीं किया गया है।

(लाख टन में)

क्र.सं.	मूल देश	2006-07	2007-08
1.	आस्ट्रेलिया	14.28	0.05
2.	अर्जेंटीना	1.52	4.14
3.	ब्राजील	—	0.95
4.	बुलगारिया	0.37	—
5.	कनाड़ा	11.86	3.15
6.	स्लोवाकिया चैक गणराज्य	0.71	—
7.	फ्रांस	2.60	—
8.	हंगरी	4.10	—
9.	रोमानिया	0.67	—
10.	रूस	16.71	9.40
11.	यूक्रेन	1.72	-
	जोड़	54.54	17.69

विवरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के तहत गेहूं का आवंटन दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10(*)
		ल.सा.वि.प्र	कल्याण योजनाएं	ल.सा.वि.प्र	कल्याण योजनाएं	ल.सा.वि.प्र	कल्याण योजनाएं	ल.सा.वि.प्र.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	81.15	16.00	65.38	20.00	35.30	80.37	39.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.59	0.08	11.43	0.08	9.43	7.35	9.43
3.	असम	254.23	0.02	264.41	0.02	224.36	0.02	224.36
4.	बिहार	1132.10	12.55	881.70	13.79	1073.60	16.97	1497.58
5.	छत्तीसगढ़	120.65	41.93	51.50	1.20	169.50	1.20	238.20
6.	दिल्ली	486.30	10.29	509.81	10.37	440.14	19.25	445.34
7.	गोवा	11.53	0.12	9.61	0.14	6.71	0.14	5.98
8.	गुजरात	824.37	120.36	533.23	124.07	738.37	129.29	1357.44
9.	हरियाणा	463.72	55.00	382.20	53.84	591.75	19.30	705.97
10.	हिमाचल प्रदेश	172.68	4.28	226.34	6.28	273.79	6.19	297.24
11.	जम्मू और कश्मीर	243.26	0.00	272.42	3.54	241.63	0.00	235.63
12.	झारखंड	348.39	0.69	343.36	0.65	371.11	3.59	544.69
13.	कर्नाटक	367.87	36.05	311.60	46.29	285.54	63.50	303.93
14.	केरल	330.18	0.73	308.55	14.38	244.88	0.76	224.88
15.	मध्य प्रदेश	1614.27	276.06	1363.26	296.39	1822.47	257.83	2304.92
16.	महाराष्ट्र	2071.72	26.64	1511.63	92.39	1780.24	26.62	2532.05
17.	मणिपुर	11.59	0.12	11.02	0.14	11.77	0.14	13.27
18.	मेघालय	7.70	1.44	10.31	0.00	14.16	0.00	17.16
19.	मिजोरम	10.36	0.00	9.62	0.00	7.49	0.00	7.49
20.	नागालैण्ड	34.71	4.49	36.60	6.61	32.59	13.44	32.59
21.	उड़ीसा	155.73	21.26	137.21	19.00	158.46	21.88	392.82
22.	पंजाब	353.03	53.36	240.65	48.12	662.14	37.79	862.02
23.	राजस्थान	1335.72	348.86	1059.69	209.71	1328.25	108.67	1793.34
24.	सिक्किम	5.35	0.00	4.51	0.00	2.94	0.00	2.94
25.	तमिलनाडु	95.58	10.37	94.07	3.48	125.40	15.84	210.40
26.	त्रिपुरा	26.96	0.00	25.25	0.00	25.04	1.43	28.04
27.	उत्तर प्रदेश	2080.88	492.83	1529.81	487.89	2131.78	334.30	3699.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	उत्तराखंड	143.30	26.49	121.64	18.00	190.29	14.31	244.69
29.	पश्चिम बंगाल	1603.71	0.96	1625.23	0.97	1634.37	0.97	1907.27
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.95	0.02	6.12	0.02	6.22	0.02	8.15
31.	चण्डीगढ़	9.39	0.78	0.71	0.77	2.22	1.32	22.04
32.	दादरा और नगर हवेली	1.60	0.15	1.14	0.01	0.54	0.09	0.64
33.	दमन और दीव	0.73	0.00	0.44	0.00	0.55	0.00	2.03
34.	लक्षद्वीप	0.43	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुदुचेरी	2.05	0.12	2.25	0.12	2.89	0.12	15.48
	जोड़	14418.79	1562.05	11962.99	1477.63	14645.95	1182.71	20227.39

(*) चालू वर्ष के लिए अन्य कल्याण योजनाओं के तहत गेहूं के राज्यवार आवंटनों के अंतिम विवरण अभी प्राप्त होने हैं/जारी किए जाने हैं।

शीतागारों हेतु सहायता

***255. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शीतागार सुविधाओं के संबंध में कोई आकलन किया है तथा इस प्रकार की सुविधाओं के अभाव में पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों सहित कृषि उत्पादन में कितनी हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में, विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में शीतागार सुविधाएं स्थापित करने तथा अन्य योजनाओं के लिए स्वीकृत की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्यों को इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (च) जी, हां। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा फसलोपरांत हानियों में कमी लाने के लिए अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता का आकलन करने तथा रुग्ण एवं बन्द यूनिटों की पुनर्स्थापना एवं आधुनिकीकरण करने एवं देश में शीतागार सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए 1998 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। शीतागार सहित पर्याप्त अवसंरचना के अभाव के कारण खाद्यान्नों की हानि का आकलन 8% से 10% की सीमा में तथा फलों व सब्जियों के मामले में हानि का आकलन 25% से 30% की सीमा में है। अत: सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने के लिए 1999 में "शीतागारों का निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार तथा बागवानी उत्पादों के भण्डारण के लिए पूंजी निवेश सब्सीडी" स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के तहत पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए 60.00 लाख रु. की अधिकतम सीमा में परियोजना लागत के 33.33% की दर पर तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों सहित अन्य राज्यों के लिए 50.00 लाख रु. की अधिकतम सीमा में 25% की दर पर क्रेडिट से जुड़ी हुई बैक एंडेड सब्सीडी दी जाती है। सरकार

ने बागवानी के विकास के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, यथा- "पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में समेकित बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन" तथा "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" की शुरूआत की है जिसके अंतर्गत उपरोक्त प्रतिमानों के अनुसार शीतागारों के निर्माण के लिए भी सहायता दी जाती है। टीएमएनई के तहत सहायता राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से दी जाती है।

विगत दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान/देश में शीतागार सुविधाओं की स्थापना के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा गोवा राज्यों ने विगत दो वर्षों के दौरान राज्य सरकार के प्रस्ताव के अभाव में इस स्कीम का लाभ नहीं उठाया है। इस स्कीम के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण क्षेत्र में उद्योग की कमी, बागवानी उत्पादों की अपर्याप्त मात्रा, सड़क संपर्क में कमी तथा ऋण की आसानी से उपलब्धता में कमी हैं। सरकार ने इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए राज्यों को सलाह दी है।

विवरण

विगत दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान शीतागारों के निर्माण के लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

लाख रु.

क्र.सं.	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1.	असम	0	0	60.0
2.	पंजाब	597.76	161.42	
3.	हरियाणा	0.85	0	5.00
4.	तमिलनाडु	0	53.12	
5.	जम्मू और कश्मीर	0	0	45.58
6.	हिमाचल प्रदेश	1599.00	0	
7.	उत्तर प्रदेश	7010.27	2247.43	38.67
8.	उत्तराखंड	2.67	0	
9.	महाराष्ट्र	131.69	97.30	
10.	राजस्थान	217.46	151.30	
11.	कर्नाटक	642.63	150.86	
12.	गुजरात	566.70	161	
13.	उड़ीसा	141.31	0	
14.	मध्य प्रदेश	0	42.91	
15.	छत्तीसगढ़	25.13	26.01	
16.	पश्चिम बंगाल	142.00	155.61	
17.	आंध्र प्रदेश	906.54	520.97	
18.	बिहार	463.88	75.25	
19.	झारखंड	407.28	0	
20.	दिल्ली	0	6.41	
21.	केरल	0	23.59	
	कुल	12855.17	3873.18	149.25

सड़क परियोजनाओं पर कार्य

***256. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही और प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए हाल ही में एक बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार शुरू की जाने वाली सड़क परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा उनके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) उक्त परियोजनाओं पर कब तक कार्य शुरू हो जाने की संभावना है; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत चालू तथा प्रस्ताविक सड़क परियोजनाओं की समीक्षा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सरकार द्वारा नियमित आधार पर विभिन्न स्तरों पर की जाती है। पिछली ऐसी समीक्षा सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) द्वारा 15 जुलाई, 2009 को की गई थी। वर्ष 2009-10 के दौरान प्रारंभ की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है

(ग) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य, सौंपे जाने की तारीख से 8 माह के अंदर प्रारंभ किए जाने की संभावना है।

(घ) कार्यान्वयन प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर की जाती है और भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, सड़क उपरि पुलों के लिए रेलवे से स्वीकृतियां प्राप्त करने और गैर-निष्पादक ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए उपाय किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2009-10 के दौरान शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित एन एच डी पी परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	रा.रा. संख्या	लंबाई (किमी.)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	एनएच डीपी चरण	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आरमूर-अदलूर-येल्लारेड्डी खंड	आंध्र प्रदेश	7	60.00	490.50	II	कार्य सौंप दिया गया है
2.	विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम	आंध्र प्रदेश	9	65.00	538.00	III	निविदा रद्द कर दी गई है। पुन: आमंत्रित की जानी है।
3.	हैदराबाद-विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	9	181.00	1740.00	III	कार्य सौंप दिया गया है
4.	कुडप्पा-मैदुकुर-कोरनूल	आंध्र प्रदेश	18	188.00	1585.00	III	कार्य सौंप दिया गया है
5.	हैदराबाद-यादगिरि	आंध्र प्रदेश	202	35.65	514.91	III	आर एफ पी आमंत्रित किया गया है। निविदा की देय तारीख 17.08.2009 है
6.	विजयवाड़ा से भद्राचलम (किमी.0/0-169/6)	आंध्र प्रदेश	221	170		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
7.	दिग्मारू से ओंगोल	आंध्र प्रदेश	214ए	255		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	नैल्लूर-चिल्कालूरिपेट	आंध्र प्रदेश	5	184.00	1465.00	V	आरएफक्यू पुन: आमंत्रित की गई है. देय तारीख 28.07.2009 है।
9.	विजयवाड़ा-एल्लूरू-राजमुंदरी	आंध्र प्रदेश	5	198.00	1653.00	V	आरएफक्यू पुन: आमंत्रित की जानी है।
10.	विशाखापट्टनम-राजमुंदरी	आंध्र प्रदेश	5	201		V	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
11.	बालचेरा-हंरगजो	आंध्र प्रदेश	54	31.00	350.00	II	आरएफक्यू आमंत्रित किया जाना है
12.	पटना-बख्तियारपुर	बिहार	30	53		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
13.	खगड़िया-बख्तियारपुर	बिहार	31	120.00	1501.00	III	आरएफक्यू पुन: आमंत्रित की जानी है।
14.	खगड़िया-पूर्णिया	बिहार	31	140.47	1270.00	III	आरएफक्यू पुन: आमंत्रित की जानी है।
15.	सोनबरसा-मुजफ्फरपुर	बिहार	77	89.00	पुनर्रचित की जा रही है	III	आरएफक्यू पुन: आमंत्रित की जानी है।
16.	मोकामा-मुंगेर	बिहार	80	70.00	पुनर्रचित की जा रही है	III	आरएफक्यू पुन: आमंत्रित की जानी है।
17.	पटना-गया-डोभी	बिहार	83	125		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
18.	पटना-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर	बिहार	19 और 77	63.37	671.00	III	निविदाएं पुन: आमंत्रित की गई हैं। निविदा की देय तारीख 03.08.09 है
19.	गोपालगंज-छपरा-हाजीपुर (पैकेज II)	बिहार	19 और 85	71.70	पुनर्रचित की जा रही है	III	आरएफक्यू पुन: आमंत्रित की जानी है।
20.	गोपालगंज-छपरा-हाजीपुर (पैकेज I)	बिहार	19 और 85	83.50	पुनर्रचित की जा रही है	III	आरएफक्यू पुन: आमंत्रित की जानी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	मोतीहारी-रक्सौल	बिहार	28ए	67		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
22.	पटना-बक्सर	बिहार	30 और 84	125.00	1515.00	III	आरएफक्यू पुनः आमंत्रित की जानी है।
23.	फेरबिसगंज-जोगबनी	बिहार	57ए	13		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
24.	महाराष्ट्र/गोवा सीमा-पणजी गोवा/कर्नाटक सीमा	गोवा	17	122.87	2078.00	III	आरएफक्यू का कार्य पूरा हो चुका है। आरएफपी आमंत्रित की जानी है।
25.	गोवा/कर्नाटक सीमा-पणजी	गोवा	4ए	65.00	471.00	III	प्राप्त निविदाओं पर कार्रवाई की जा रही है।
26.	गुजरात/महाराष्ट्र सीमा-सूरत-हजीरा	गुजरात	6	133.00	1509.10	III	कार्य सौंप दिया गया है
27.	गोधरा-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा	गुजरात	59	83.85	747.00	III	आरएफक्यू का कार्य पूरा हो चुका है। आरएफपी आमंत्रित की जानी है।
28.	अहमदाबाद-गोधरा	गुजरात	59	117.60	1025.00	III	आरएफक्यू का कार्य पूरा हो चुका है। आरएफपी आमंत्रित की जानी है।
29.	कांडला-मुंदरा पत्तन	गुजरात	8ए विस्तार	71.40	1031.14	III	आरएफक्यू का कार्य पूरा हो चुका है। आरएफपी आमंत्रित की जानी है।
30.	जैतपुर-सोमनाथ	गुजरात	8डी	127		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
31.	अहमदाबाद-वदोदरा	गुजरात	8	95		V	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	समख्याली-गांधीधाम	गुजरात	8ए	56.00	805.39	V	आरएफक्यू का कार्य पूरा हो चुका है। आरएफपी आमंत्रित की जानी है।
33.	रोहतक-हिसार	हरियाणा	10	97.00	पुनर्रचित की जा रही है	III	आरएफक्यू पुन: आमंत्रित की जानी है।
34.	अंबाला-कैथल	हरियाणा	65	78		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
35.	रोहतक-जिंद	हरियाणा	71	45		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
36.	रोहतक-बावल	हरियाणा	71	82.55	650.00	III	आरएफक्यू का कार्य पूरा हो चुका है। आरएफपी आमंत्रित की जानी है।
37.	पंचकुला-बरवाला-साहा-यमुना-हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा	हरियाणा	73	105.00	667.00	III	आरएफक्यू आमंत्रित की गई है। देय तारीख 30.07.2009 है।
38.	रोहतक-पानीपत	हरियाणा	71ए	80.58	795.00	III	निविदा की देय तारीख 04.08.09 के साथ आरएफक्यू 05.06.09 को जारी किया गया।
39.	दिल्ली-आगरा	हरियाणा/ उत्तर प्रदेश	2	180.00	1433.00	V	आरएफक्यू पुन: आमंत्रित की जानी है।
40.	पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसमार्ग	हरियाणा/दिल्ली/ उत्तर प्रदेश		135.00	2676.00	अन्य पीपीपी परियोजना	निविदा रद्द कर दी गई है। पुन: आमंत्रित की जानी है।
41.	परवानू-सोलन	हिमाचल प्रदेश	22	40.70	535.70	III	निविदा की देय तारीख 04.08.09 के साथ आरएफक्यू 05.06.09 को जारी किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	सोलन-शिमला	हिमाचल प्रदेश	22	60		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
43.	किरतपुर-बिलासपुर	हिमाचल प्रदेश	21	63		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
44.	चेनानी-नश्री खंड	जम्मू और कश्मीर	1ए	12.00	2580.00	II	आरएफक्यू का मूल्यांकन किया जा रहा है।
45.	काजीगुंड-बनिहाल खंड	जम्मू और कश्मीर	1ए	15.00	1987.00	II	आरएफक्यू का मूल्यांकन किया जा रहा है।
46.	रामबान-बनीहाल खंड	जम्मू और कश्मीर	1ए	36.00	986.00	II	आरएफक्यू का मूल्यांकन किया जा रहा है।
47.	उधमपुर-रामबान खंड	जम्मू और कश्मीर	1ए	43.00	971.00	II	आरएफक्यू का मूल्यांकन किया जा रहा है।
48.	जम्मू-उधमपुर खंड	जम्मू और कश्मीर	1ए	65.00	1939.00	II	आरएफक्यू का मूल्यांकन किया जा रहा है।
49.	श्रीनगर-बनिहाल खंड	जम्मू और कश्मीर	1ए	68.00	1166.00	II	आरएफक्यू का मूल्यांकन किया जा रहा है।
50.	बरही-हजारीबाग	झारखंड	33	40		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
51.	हजारीबाग-रांची	झारखंड	33	71.00	625.07	III	प्राप्त निविदाओं पर कार्रवाई की जा रही है
52.	रांची-जमशेदपुर	झारखंड	33	163.50	1436.49	III	10.08.09 की निविदा तिथि के साथ आरएफवी जारी की गई
53.	बरवा अड्डा-पानागढ़	झारखंड/ पश्चिम बंगाल	2	120		V	आरएफक्यू आमंत्रित किया जाना है।
54.	कर्नाटक/आं.प्र.सीमा-मुलगाबल	कर्नाटक	4	22.00	पुनर्रचित की जा रही है	III	आरएफक्यू पुनः आमंत्रित किया जाना है।

1	2	3	4	5	6	7	8
55.	बीजापुर-हंगुड	कर्नाटक	13	97.22	906.80	III	आरएफपी आमंत्रित किया गया है। निविदा की देय तारीख 18.08.2009 है
56.	हंगुड-होसपेट	कर्नाटक	13	97.89	1226.37	III	आरएफपी आमंत्रित किया गया है। निविदा की देय तारीख 18.08.2009 है
57.	कुंडापुर-सुरतकल और मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा	कर्नाटक	17	90.00	671.00	III	प्राप्त निविदाओं पर कार्रवाई की जा रही है।
58.	देवीहल्ली-हासन खंड	कर्नाटक	48	78.00	453.00	III	आरएफक्यू आमंत्रित की गई है। देय तारीख है। 28.07.2009
59.	बेलगाम-गोवा/कर्नाटक सीमा	कर्नाटक	4ए	81.90	655.00	III	आरएफक्यू का मूल्यांकन किया जा रहा है।
60.	चित्रदुर्ग-शिमोगा	कर्नाटक	13	111		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
61.	शिमोगा-मंगलौर	कर्नाटक	13	188		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
62.	गुंडलुपेट-कोलेगाल	कर्नाटक	212	114		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
63.	बेलगाम-धारवाड़	कर्नाटक	4	80.00	480.00	V	आरएफक्यू पुनः आमंत्रित की गई है। देय तारीख है 03.08.2009
64.	तुमकुर-चित्रदुर्ग	कर्नाटक	4	114.00	839.00	V	आरएफक्यू का कार्य पूरा हो चुका है। आरएफपी आमंत्रित की जानी है।
65.	हैदराबाद-बगंलौर खंड के किमी.534.720 से किमी.556.840	कर्नाटक	7	22.12	680.00	VII	आरएफक्यू का मूल्यांकन किया जा रहा है।
66.	वडक्कनचेरी-त्रिशुर खंड	केरल	47	28.36	617.00	II	कार्य सौंप दिया गाया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
67.	वालयार-वडक्कनचेरी खंड	केरल	47	53.42	665.00	II	आरएफक्यू पुनः आमंत्रित की जानी है।
68.	कुन्नूर-कुट्टीपुरम (पैकेज-II)	केरल	17	81.50	1312.00	III	कार्य सौंप दिया गाया है।
69.	कुन्नूर-कुट्टीपुरम (पैकेज-I)	केरल	17	83.20	1366.00	III	कार्य सौंप दिया गाया है।
70.	कुट्टीपुरम-इडापल्ली	केरल	17	112.00	910.00	III	आरएफक्यू पुनः आमंत्रित की गई है। देय तारीख है 20.07.2009
71.	कर्नाटक/केरल सीमा-कुन्नूर	केरल	17	130		III	आरएफक्यू आमंत्रित किया जाना है।
72.	त्रिवेन्द्रम-केरल/तमिलनाडु सीमा	केरल	47	43.00	519.00	III	आरएफक्यू पुनः आमंत्रित की गई है। मूल्यांकन किया जा रहा है।
73.	चरथलई-ओचिरा	केरल	47	83.60	1540.00	III	आरएफक्यू पुनः आमंत्रित की जानी है।
74.	ओचिरा-तिरुवनंतपुरम	केरल	47	85.57	1488.00	III	आरएफक्यू पुनः आमंत्रित की जानी है।
75.	कोचीन बाइपास पर बोडीमेट्टू-कुंदानूर जंक्शन	केरल	49	168		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
76.	कोल्लम-काझुथुरती	केरल	208	82		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
77.	कोजीकोड-मुथंगा	केरल	212	118		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
78.	कोजीकोड-पलक्काड	केरल	213	126		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
79.	कोलम-कुमिली	केरल	220	191		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
80.	भोपाल-राजमार्ग क्रासिंग-जबलपुर	मध्य प्रदेश	12	297		III	आरएफक्यू आमंत्रित किया जाना है।

1	2	3	4	5	6	7	8
81.	इंदौर-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा	मध्य प्रदेश	59	155.15	1297.00	III	आरएफक्यू का कार्य पूरा हो चुका है। आरएफपी आमंत्रित की जानी है।
82.	झांसी-खजुराहो	मध्य प्रदेश	75	163		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
83.	भोपाल-सांची	मध्य प्रदेश	86 (विस्तार)	57		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
84.	जबलपुर से लखनादोन (किमी. 471 से किमी. 544)	मध्य प्रदेश	7	74		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
85.	रीवा बाइपास छोर से कटनी बाइपास छोर (किमी.243/6 से किमी. 299) और मेहर बाइपास छोर से कटनी बाइपास छोर (किमी. 304 से किमी. 361/2)	मध्य प्रदेश	7	103		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
86.	बेतूल से महाराष्ट्र/मध्य प्रदेश सीमा (रारा-69 पर किमी. 143 से किमी.257)	मध्य प्रदेश	69	115		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
87.	बमीथा से बेला (किमी.58/4 से किमी.199/6)	मध्य प्रदेश	75	141		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
88.	ग्वालियर से मध्य प्रदेश/ उत्तर प्रदेश सीमा (किमी. 0 से किमी. 108)	मध्य प्रदेश	92	108		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
89.	सीधी से सिगरौली (किमी. 81 से किमी. 195/8)	मध्य प्रदेश	75 ext.	115		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
90.	इंदौर-देवास	मध्य प्रदेश	3	45.00	325.00	V	आरएफक्यू पुनः आमंत्रित की जानी है।
91.	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा-नागपुर	महाराष्ट्र	7	95.00	1170.52	II	प्राप्त निविदाओं पर कार्रवाई की जा रही है।
92.	पिंपलगांव-नासिक-गोंडे	महाराष्ट्र	3	60.00	940.00	III	कार्य सौंप दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
93.	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा-धुले	महाराष्ट्र	3	97.00	835.00	III	कार्य सौंप दिया गया है
94.	कलामबोली-मुंबरा (6 लेन)	महाराष्ट्र	4	20		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
95.	नागपुर-वेनगंगा पुल	महाराष्ट्र	6	60		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
96.	तेलेगांव-अमरावती	महाराष्ट्र	6	66.73	567.00	III	प्राप्त निविदाओं पर कार्रवाई की जा रही है।
97.	पुणे-शोलापुर (पैकेज-I)	महाराष्ट्र	9	110.00	1110.00	III	कार्य सौंप दिया गया है
98.	पुणे-शोलापुर (पैकेज-II)	महाराष्ट्र	9	110.00	835.00	III	प्राप्त निविदाओं पर कार्रवाई की जा रही है।
99.	शोलापुर-महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा	महाराष्ट्र	13	30		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
100.	पनवेल-इंदापुर	महाराष्ट्र	17	84		III	आरएफक्यू आमंत्रित किया जाना है।
101.	अहमदनगर से पाथरडी (किमी. 232 से किमी. 284)	महाराष्ट्र	222	51		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
102.	पथरी से नांदेड (किमी. 442 से किमी.591)	महाराष्ट्र	222	149		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
103.	सतारा-कागल	महाराष्ट्र	4	133.00	1103.00	V	आरएफक्यू आमंत्रित किया जाना है।
104.	पुणे-सतारा	महाराष्ट्र	4	140.35	1724.55	V	आरएफक्यू का कार्य पूरा हो चुका है। आरएफपी आमंत्रित की जानी है।
105.	सम्बलपुर-बारागढ़-छत्तीसगढ़/ उड़ीसा सीमा	उड़ीसा	6	88		III	आरएफक्यू आमंत्रित किया जाना है
106.	चंडीखोल-दुबरी-तलचर	उड़ीसा	200	133.00	561-00	III	आरएफक्यू पुनः आमंत्रित की जानी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
107.	भुवनेश्वर-पुरी	उड़ीसा	203	59		III	आरएफक्यू आमंत्रित की जानी है।
108.	रिमूली-रौक्सी-राजमुंडा खंड	उड़ीसा	215	96.00	449-00	III	आरएफक्यू पुनः आमंत्रित की जानी है।
109.	पानीकोएली-क्योंझर-रिमूली खंड	उड़ीसा	215	166.00	923-00	III	आरएफक्यू पुनः आमंत्रित की जानी है।
110.	कनकतोरा-झारसूगोड़ा जंक्शन	उड़ीसा	200	68		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
111.	चंडीखोल-जगतपुर-भुवनेश्वर	उड़ीसा	5	70.00	1047.00	V	प्राप्त निविदाओं पर कार्रवाई की जा रही है।
112.	अमृतसर-जालंधर	पंजाब	1	20.00	291.77	II	सहवर्ती पैकेज की व्याप्ति में परिवर्तन होने से इसे शुरू किए जाने पर विचार किया जा रहा है।
113.	अमृतसर-पठानकोट	पंजाब	15	102.00	705.00	III	प्राप्त निविदाओं पर कार्रवाई की जा रही है।
114.	लुधियाना-तलवंडी	पंजाब	95	84		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
115.	किशनगढ़-ब्यावर	राजस्थान	8	94.00	795.00	III	कार्य सौंप दिया गया है।
116.	रींगस-सीकर	राजस्थान	11	42		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
117.	जयपुर-रींगस	राजस्थान	11	54.00	268.00	III	प्राप्त निविदाओं पर कार्रवाई की जा रही है।
118.	देवली-कोटा-झालावाड़ (पैकेज-II)	राजस्थान	12	55		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है
119.	देवली-कोटा-झालावाड़ (पैकेज-I)	राजस्थान	12	124		III	आरएफक्यू आमंत्रित किया जाना है।
120.	जयपुर-टोंक-देवली	राजस्थान	12	149.00	792.00	III	प्राप्त निविदाओं पर कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8
121.	ब्यावर-पाली-पिंडवाड़ा	राजस्थान	14	246		III	आरएफक्यू आमंत्रित किया जाना है।
122.	करौली-धौलपुर	राजस्थान	11बी	72		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
123.	उदयपुर-अहमदाबाद	राजस्थान	8	242.50	1750.00	V	आरएफक्यू पुनः आमंत्रित की गई है।
124.	किशनगढ़-उदयपुर	राजस्थान	76, 79 और 79ए	315.00	2534.00	V	निविदा की देय तिथि 20.08.09 के साथ आरएफपी जारी की गई
125.	चेंगापल्ली-वलयार खंड (कोयम्बतूर बाइपास को छोड़कर)	तमिलनाडु	47	55.00	852.00	II	आरएफक्यू का कार्य पूरा हो चुका है। आरएफपी आमंत्रित की जानी है।
126.	मदुरै-रामनाथपुरम-रामेश्वरम-धनुषकोडी	तमिलनाडु	49	186		III	आरएफक्यू आमंत्रित किया जाना है।
127.	टिंडीवनम-कृष्णागिरी	तमिलनाडु	66	199.94	787.00	III	कोई बोली प्राप्त नहीं हुई पुनः आमंत्रित की जानी है।
128.	कोयम्बतूर-मेट्टूपलायम	तमिलनाडु	67	50.00	पुनर्रचित की जा रही है	III	आरएफक्यू पुनः आमंत्रित की जानी है।
129.	नागपट्नम-तंजौर	तमिलनाडु	67	76.70	392.00	III	आरएफपी पुनः आमंत्रित की जानी है।
130.	कराईकुडी-रामनाथपुरम	तमिलनाडु	210	80.00	490.00	III	आरएफपी पुनः आमंत्रित की जानी है।
131.	त्रिची-करईकुडी	तमिलनाडु	210	120.00	407.00	III	आरएफपी पुनः आमंत्रित की जानी है।
132.	रारा 45 विस्तार डिंडीगुल-पेरीगुलाम-थेनी और रारा 220 थेनी-कुमली	तमिलनाडु	45 और 220	130.00	475.00	III	आरएफपी पुनः आमंत्रित की जानी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
133.	केरल/तमिलनाडु सीमा-कन्याकुमारी	तमिलनाडु	47 और 47बी	70.00	621.00	III	आरएफपी पुन: आमंत्रित की जानी है।
134.	वालाजपेट-पूनमाल्ली	तमिलनाडु	4	92		V	आरएफक्यू आमंत्रित किया जाना है।
135.	होसूर-कृष्णागिरी	तमिलनाडु	7	65		V	आरएफक्यू आमंत्रित किया जाना है।
136.	कृष्णागिरी-वालाजाहपेट	तमिलनाडु	46	148.00	1225.00	V	बोली की देय तिथि 17.08.09 के साथ आरएफपी जारी की गई
137.	चैन्नई पोर्ट से मदुरावोयल तक उत्थापित मार्ग	तमिलनाडु	4	19.00	1345.00	VII	कार्य सौंप दिया गया है।
138.	तिरुपती-तिरुथानी-चैन्ने	तमिलनाडु/ आंध्र प्रदेश	205	125.00	570.71	III	आरएफक्यू पुन: आमंत्रित की गई है। देय तारीख है। 24.08.2009
139.	डिंडीगुल-कर्नाटक सीमा	तमिलनाडु	209	266		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
140.	तंजावुर-पुदूक्कोटई-शिवगंगा-मनामदुरैय	तमिलनाडु	266	122		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
141.	तिरुचिरापल्ली-लगुडी-चिदम्बरम् और मीनुसुरीती-जयमकोंडम-कोटू रोड [किमी. 90.20 से किमी. 93.00 (रारा-227 के किमी. 96.80 से किमी.99.60 तक साझा खंड)]	तमिलनाडु	227 और 45 सी	135		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
142.	विलूपुरम-पोन्डीचेरी-नागापट्टनम	तमिलनाडु	45ए	194		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
143.	कोयम्बतूर-कर्नाटक सीमा	तमिलनाडु	67 विस्तार	103		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7	8
144.	वाराणसी से गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	29	209		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
145.	कानपुर से कबरई खंड	उत्तर प्रदेश	86	123		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
146.	अलीगढ़ से कानपुर	उत्तर प्रदेश	91	268		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
147.	आगरा से अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	93	79		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
148.	रायबरेली से इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	24बी	119		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
149.	सितारगंज से बरेली	उत्तर प्रदेश/ उत्तराखंड	74	87		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
150.	मुरादाबाद-बरेली	उत्तर प्रदेश	24	121.00	1485.00	III	बोली की देय तिथि 17.08.09 के साथ आरएफपी 18.06.09 को जारी की गई
151.	बरेली-सीतापुर	उत्तर प्रदेश	24	152.40	1046.00	III	बोली की देय तिथि 17.08.09 के साथ आरएफपी 18.06.09 को जारी की गई
152.	गाजियाबाद-अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	91	126.00	1141.00	III	प्राप्त निविदाओं पर कार्रवाई की जा रही है।
153.	मुजफ्फरनगर-हरिद्वार	उत्तर प्रदेश/ उत्तराखंड	58	80.00	804.00	III	आरएफक्यू का कार्य पूरा हो चुका है। आरएफपी आमंत्रित की जानी है।
154.	वाराणासी-औरंगाबाद	उत्तर प्रदेश/ झारखंड	2	190.00	2848.00	V	प्राप्त निविदाओं पर कार्रवाई की जा रही है।
155.	हरिद्वार-देहरादून	उत्तराखंड	58/72	37.40	490.00	III	आरएफक्यू का कार्य पूरा हो चुका है। आरएफपी आमंत्रित की जानी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
156.	रामपुर-काठगोदाम	उत्तराखंड	87	88		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
157.	काशीपुर-सितारगंज	उत्तराखंड	74	97		IV	साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
158.	सिलीगुडी-फलकाटा-सालसालाबाड़ी	पश्चिम बंगाल	31,31डी और 31सी	164.00	2492.00	II	आरएफक्यू आमंत्रित किया जाना है।
159.	रायगंज-डबखोला	पश्चिम बंगाल	34	49.53	560.16	III	आरएफक्यू का कार्य पूरा हो चुका है। आरएफपी आमंत्रित की जानी है।
160.	कृष्णानगर-बेहरामपुर	पश्चिम बंगाल	34	78.00	685.00	III	आरएफक्यू का मूल्यांकन किया जा रहा है।
161.	बारासात-कृष्णानगर	पश्चिम बंगाल	34	84.00	890.00	III	आरएफक्यू पुनः आमंत्रित की जानी है।
162.	बेहरामपुर-फरक्का	पश्चिम बंगाल	34	100.85	999-6	III	आरएफक्यू का मूल्यांकन किया जा रहा है।
163.	फरक्का-रायगंज	पश्चिम बंगाल	34	103.00	1144.00	III	आरएफक्यू का मूल्यांकन किया जा रहा है।
164.	बारासात-बेलगांव	पश्चिम बंगाल	35	60		III	डीपीआर/साध्यता अध्ययन कार्य प्रगति पर है।
165.	धनकुनी-बालेश्वर	पश्चिम बंगाल/ उड़ीसा	6 और 60	240		V	आरएफक्यू आमंत्रित किया जाना है।

आरएफक्यू - अर्हता अनुरोध

आरएफपी - प्रस्ताव हेतु अनुरोध

किसानों को राजसहायता

***257. श्री अशोक कुमार रावत : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के किसानों को कितनी वित्तीय सहायता/राजसहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या भारतीय किसानों को उपलब्ध कराई जाने वाली राजसहायता/वित्तीय सहायता की राशि संयुक्त राज्य अमरीका जैसे

विकसित देशों के किसानों को उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी राशि की तुलना में आनुपातिक रूप से कम है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

(घ) क्या देश में किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता/राजसहायता की राशि पिछले कई वर्षों से कम होती जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) केन्द्र सरकार बीजों, सूक्ष्म सिंचाई प्रक्रिया, मशीनरी, फसल बीमा पर प्रीमियम आदि पर राजसहायता प्रदान करती है। सरकार गरीब किसानों को संसाधन जुटाने हेतु हाल ही में चालू की गई केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (2007-08), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2007-08), वृहत प्रबन्धन (2000-01), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (2005-06) तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन (2001-02)के तहत वित्तीय प्रोत्साहन/अनुदान/रियायतें भी प्रदान करती है। विनिर्माताओं/आयातकर्ताओं को उर्वरक राजसहायता भी प्रदान की जाती है, जिसका लाभ किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित अधिसूचित विक्रय मूल्यों के माध्यम से आंशिक रूप से मिलता है। वितरित/बकाया उर्वरक राजसहायता की वर्षवार राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	कुल वितरित/बकाया उर्वरक राजसहायता की राशि
2006-07	26222
2007-08	32490
2008-09*	75849

*अनुमानित (स्त्रोत: व्यय बजट खंड I, 2009-10)

(ख) और (ग) जी, हां। अद्यतन उपलब्ध वर्षों 1999 से 2001 तक के लिए संयुक्त राज्यों, यूरोपीय समुदायों, जापान तथा भारत द्वारा प्रदत्त कुल घरेलू सहायता (राजसहायता) की तुलनात्मक राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

तुलनात्मक घरेलू सहायता का ब्यौरा

(यू.एस. डालर मिलियन)

देश	1999	2000	2001
संयुक्त राज्य	74,054.4	74,200.3	72,129.1
यूरोपीय समुदाय	88,340.3	87,817.6 (वितरण वर्ष 2000/01)	75,083.75 (वितरण वर्ष 2001/02)
जापान	31,908.6	30.551.97	उपलब्ध नहीं
भारत (वर्ष)	8,221.98 (1995-96)	8,288.28 (1996-07)	9,048.13 (1997-98)

(स्त्रोत: विश्व व्यापार संगठन की अधिसूचनाएं)

किसानों को सरकार द्वारा प्रदत्त राजसहायता उनकी क्षमता तथा विश्व व्यापार संगठन के तहत की गई वचनबद्धताओं पर भी निर्भर करती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों को बीजों की उपलब्धता

***258. श्री कमल किशोर कमांडो :**
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को बुवाई के मौसम से पूर्व पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध कराये जाते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) विभिन्न फसलों के बीजों की मांग और उपलब्धता कितनी है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को बीजों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार को सूचित किया गया है खरीफ, 2009 के लिए प्रमाणित/गुणवत्ता बीज की उपलब्धता 110.97 लाख क्विंटल की आवश्यकता की तुलना में 126.51 लाख क्विंटल है। प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम के लिए उसकी आवश्यकता के आकलन के आधार पर बीज की व्यवस्था की जाती है। खरीफ 2009 के लिए 15.54 लाख क्विंटल से भी अधिक अतिरिक्त बीज उपलब्ध है। विभिन्न फसलों के बीजों की आवश्यकता और उपलब्धता संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) भारत सरकार राज्य सरकारों को गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए मुख्यत: निम्नलिखित स्कीमों के अधीन सहायता मुहैया कराती है:-

(i) बृहत् कृषि प्रबंधन (एमएमए)

(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

(iii) समेकित तिलहन, दलहन, ऑयलपाम और मक्का स्कीम (आइसोपाम)

(iv) कपास प्रौद्योगिकी मिशन

(v) जूट और मेस्ता प्रौद्योगिकी मिशन

(vi) गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण

(vii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

विवरण

प्रमाणित/गुणवत्ता बीज की आवश्यकता और उपलब्धता

मात्रा क्विंटल में

खरीफ-2009

फसल	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3
धान	4892892	5273268
मक्का	661072	666463
ज्वार	183636	206096
बाजरा	255910	280149
रागी	33665	33952
अन्य	200	512
कुल अनाज	**6027375**	**6460440**
मटर	350	350
उड़द	113301	151911
मूंग	137467	166337
अरहर	139757	162593
लोबिया	16570	16687
मोठ	16300	15828
राजमा	2140	850
अन्य	10618	10618
कुल दलहन	**436503**	**525174**
मूंगफली	1879010	1954445
तिल	22968	19873
सूरजमुखी	38627	55590
सोयाबीन	2289715	3179144
एरंड	48500	55379
राम तिल	2465	2552
अन्य	13	13
कुल तिलहन	**4281298**	**5267296**

1	2	3
कपास	187732	235246
पटसन	34270	34780
मेस्ता/अन्य	27030	22849
कुल रेशा	**249032**	**292875**
अन्य	102521	105093
सफल योग	**11096728**	**12650976**

[अनुवाद]

भंडारण स्थान की कमी

*259. **श्री उदय सिंह :**
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भंडारण स्थान की कमी तथा खाद्यान्नों के बढ़ते हुए पिछले स्टॉक के कारण हाल ही के रबी विपणन मौसम के दौरान खरीदे गए खाद्यान्नों के भंडारण में समस्या आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गोदामों की आवश्यकता और उपलब्धता का एजेंसी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार सहित विभिन्न राज्यों में मौजूदा गोदामों का नवीकरण किया जा रहा है और नई भंडारण क्षमता का सृजन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रयोजनार्थ सृजित की जाने वाली भंडारण क्षमता, आवंटित की गई धनराशि और अधिग्रहित की गई भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भांडागारों के नवीकरण और भंडारण स्थान के सृजन हेतु राज्य भांडागार निगमों और अन्य राज्य एजेंसियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितना अतिरिक्त भंडारण स्थान सृजित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां। रबी विपणन मौसम 2008-09 (226.89 लाख टन) और रबी विपणन मौसम 2009-10 (16-7-2009 की स्थिति के अनुसार 251.35 लाख टन) में गेहूं और खरीफ विपणन मौसम 2007-08 (284.93 लाख टन) और खरीफ विपणन मौसम (16-7-2009 की स्थिति के अनुसार 316.55 लाख टन) में चावल की रिकार्ड खरीदारी होने के कारण भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों ने भंडारण क्षमता की कमी का सामना किया है।

(ख) 30-6-2009 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 275.59 लाख टन कुल भंडारण क्षमता (अपनी/किराए की/ढकी हुई और कैप) है जिसमें 242.66 लाख टन स्टॉक रखा है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों का आवधिक रखरखाव किया जाता है। 2006-07 से 2008-09 तक के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में सृजित विभिन्न भंडारण क्षमता संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम ने 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007-12 के दौरान नए गोदामों का निर्माण करने की परियोजनाओं का एक शैल्फ तैयार किया है। इन गोदामों के निर्माण की लागत 164 करोड़ रुपये है। तथापि, योजना आयोग ने भारतीय खाद्य निगम के लिए 125 करोड़ रुपये का आबंटन किया है और 24 करोड़ रुपये का आबंटन पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम और जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकारों के लिए किया है। भारतीय खाद्य निगम को रिलीज की गई राशि और 2009-10 में रिलीज की जाने वाली राशि में से 11वीं पंचवर्षीय योजना में सृजित की जाने वाली संभावित क्षमता संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(च) और (छ) सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत अभियांत्रिकी अनुमानों की जांच के रूप में तकनीकी सहायता दी जाती है। 2007-08 और 2008-09 में स्वीकृत निधियों में से 11वीं योजना में राज्य सरकारों द्वारा सृजित की जाने वाली संभावित अतिरिक्त भंडारण क्षमता संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

विवरण-I

भारतीय खाद्य निगम की 31.03.2007 को भंडारण क्षमता की स्थिति

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र. सं.	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	भा.खा.नि. की अपनी	ढकी हुई जहां से किराए पर ली गई				जोड़ किराए की	जोड़ ढकी हुई	कैप (खुली)			कुल जोड़	रखा गया स्टॉक	उपयोग (% में)
				राज्य सरकार	के.भ.नि	रा.भ.नि	निजी पार्टियां			अपनी	किराए की	जोड़			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
पूर्व	1.	बिहार	3.66	0.03	0.05	0.53	0.48	1.54	5.20	0	0	0	5.20	2.64	51
	2.	झारखंड	0.66	0	0.14	0.18	0.25	0.57	1.23	0	0	0	1.23	1.16	94
	3.	उड़ीसा	2.93	0	0.78	2.90	0.15	3.83	6.76	0	0	0	6.76	5.14	76
	4.	पश्चिम बंगाल	8.64	0.23	0.58	0	0.56	1.37	10.01	0	0	0	10.01	3.97	40
	5.	सिक्किम	0.10	0.01	0	0	0	0.01	0.11	0	0	0	0.11	0.06	55
		जोड़	15.99	0.27	2.00	3.61	1.44	7.32	23.31				23.31	12.97	56
उत्तर पूर्व	6.	असम	1.99	0.02	0.10	0.07	0.37	0.56	2.55	0	0	0	2.55	1.06	42
	7.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0	0	0	0	0	0.18	0	0	0	0.18	0.05	28
	8.	मेघालय	0.14	0	0.10	0.05	0	0.15	0.29	0	0	0	0.29	0.16	55
	9.	मिजोरम	0.17	0.01	0	0	0	0.01	0.18	0	0	0	0.18	0.05	29
	10.	त्रिपुरा	0.22	0.05	0.10	0	0	0.15	0.37	0	0	0	0.37	0.24	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	11.	मणिपुर	0.20	0.02	0	0	0	0.02	0.22	0	0	0	0.22	0.04	18
	12.	नागालैंड	0.20	0	0.10	0	0	0.10	0.30	0	0	0	0.30	0.11	37
		जोड़	3.10	0.10	0.40	0.12	0.37	0.99	4.09	0	0	0	4.09	1.71	42
उत्तर	13.	दिल्ली	3.36	0	0	0	0	0	3.36	0.34	0	0.34	3.70	0.88	24
	14.	हरियाणा	7.70	0.69	1.88	3.96	0.90	10.43	18.13	3.17	0	3.17	21.30	6.12	29
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.06	0.07	0	0	0.13	0.27	0	0	0	0.27	0.21	78
	16.	जम्मू और कश्मीर	0.96	0.15	0	0	0.11	0.26	1.22	0	0	0	1.22	0.74	61
	17.	पंजाब	21.84	0.07	1.57	33.69	2.63	37.96	59.8	6.33	0.04	6.37	66.17	44.97	68
	18.	चंडीगढ़	$0.40	0	0.46	0.22	0	0.68	1.08	0.08	0	0.08	1.16	0.93	80
	19.	राजस्थान	7.06	0	0.13	0	0.16	0.29	7.35	1.58	0.10	1.68	9.03	3.37	37
	20.	उत्तर प्रदेश	14.96	0.06	1.77	4.03	0.20	6.06	21.02	4.19	0	4.19	25.21	6.18	25
	21.	उत्तराखंड	0.66	0.11	0.23	0.44	0.05	0.83	1.49	0.09	0.02	0.11	1.60	1.21	76
		जोड़	57.08	4.14	6.11	42.34	4.05	56.64	113.72	15.78	0.16	15.94	129.66	64.61	50
दक्षिण	22.	आंध्र प्रदेश	12.73	0	2.01	18.08	0.00	20.09	32.82	1.97	0	1.97	34.79	17.72	51
	23.	केरल	5.12	0	0	0	0	0	5.12	0.21	0	0.21	5.33	2.53	47
	24.	कर्नाटक	3.73	0	0.38	0.42	0	0.80	4.53	1.37	0	1.37	5.90	3.54	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	25.	तमिलनाडु	5.83	0	0.75	0.31	0	1.06	6.69	0.60	0	0.60	7.49	4.63	62
	26.	पुदुचेरी	0.42	0	0	0.02	0	0.02	0.44	0.08	0	0.08	0.52	0.18	35
		जोड़	27.83	0	3.14	18.83	0	21.97	49.80	4.23	0	4.23	54.03	28.60	53
पश्चिम	27.	गुजरात	5.00	0.14	0.22	0	0	0.36	5.36	0.55	0	0.55	5.91	4.11	70
	28.	महाराष्ट्र	11.77	0.24	1.09	1.19	0.49	3.01	14.78	1.42	0	1.42	16.20	7.19	45
	29.	गोवा	0.15	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0.15	0.14	93
	30.	मध्य प्रदेश	3.37	0	0.60	0.88	0.37	1.85	5.22	0.35	0	0.35	5.57	5.78	104
	31.	छत्तीसगढ़	5.12	0.03	0.21	0.99	0.05	1.28	6.40	0.59	6.16	6.75	13.15	10.86	83
		जोड़	25.41	0.41	2.12	3.06	0.91	6.50	31.91	2.91	6.16	9.07	40.98	28.08	69
		कुल जोड़	129.41	4.92	13.77	67.96	6.77	93.42	222.83	22.92	6.32	29.24	252.07	135.97	54

भारतीय खाद्य निगम की 31.03.2008 को भंडारण क्षमता की स्थिति

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र. सं.	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	भा.खा.नि. की अपनी	ढकी हुई जहां से किराए पर ली गई				जोड़ किराए की	जोड़ ढकी हुई	कैप (खुली)			कुल जोड़	रखा गया स्टॉक	उपयोग (% में)
				राज्य सरकार	के.भ.नि	रा.भ.नि	निजी पार्टियां			अपनी	किराए की	जोड़			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
पूर्व	1.	बिहार	3.66	0.03	0.46	0.68	0.48	1.65	5.31	0	0	0	5.31	3.05	57
	2.	झारखंड	0.66	0	0.14	0.18	0.22	0.54	1.20	0	0	0	1.20	0.79	66
	3.	उड़ीसा	2.93	0	0.64	2.65	0.15	3.44	6.37	0	0	0	6.37	3.85	60
	4.	पश्चिम बंगाल	8.64	0.19	0.62	0	0.56	1.37	10.01	0	0	0	10.01	5.36	54
	5.	सिक्किम	0.10	0.01	0	0	0	0.01	0.11	0	0	0	0.11	0.06	55
		जोड़ (पूर्व जोन)	15.99	0.23	1.86	3.51	1.41	7.01	23.00	0	0	0	23.00	13.11	57
उत्तर-पूर्व	6.	असम	1.99	0	0.16	0.07	0.39	0.62	2.61	0	0	0	2.61	1.74	67
	7.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.02	0	0	0	0.02	0.20	0	0	0	0.20	0.09	61
	8.	मेघालय	0.14	0	0.11	0.05	0	0.16	0.30	0	0	0	0.30	0.09	30
	9.	मिजोरम	0.17	0.01	0	0	0	0.01	0.18	0	0	0	0.18	0.03	17
	10.	त्रिपुरा	0.22	0.05	0.13	0	0	0.18	0.40	0	0	0	0.40	0.18	45
	11.	मणिपुर	0.20	0	0	0	0	0	0.20	0	0	0	0.20	0.05	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	12.	नागालैंड	0.20	0	0.03	0	0	0.03	0.23	0	0	0	0.23	0.18	78
		जोड़ (पूर्वोत्तर अंचल)	3.10	0.08	0.43	0.12	0.39	1.02	4.12	0	0	0	4.12	2.36	57
उत्तर	13.	दिल्ली	3.36	0	0	0	0	0	3.36	0.34	0	0.34	3.70	1.86	50
	14.	हरियाणा	7.70	3.89	1.88	3.96	1.05	10.78	18.48	3.17	0	3.17	21.65	9.84	45
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.06	0.05	0	0	0.11	0.25	0	0	0	0.25	0.16	64
	16.	जम्मू और कश्मीर	0.98	0.15	0	0	0.12	0.27	1.25	0	0	0	1.25	1.04	83
	17.	पंजाब	21.84	0.02	1.80	29.84	2.49	34.25	56.09	6.33	0	6.33	62.42	38.00	61
	18.	चंडीगढ़	0.40	0	0.44	0.22	0	0.66	1.06	0.08	0	0.09	1.14	0.89	78
	19.	राजस्थान	7.06	0	0	0	0.11	0.11	7.17	1.58	0.02	1.60	8.77	2.76	31
	20.	उत्तर प्रदेश	14.96	0.07	1.70	3.99	0.18	5.94	20.9	4.15	0	4.15	25.05	6.81	27
	21.	उत्तराखंड	0.66	0.09	0.13	0.26	0.05	0.53	1.19	0.09	0	0.09	1.28	0.54	42
		जोड़ (उत्तर अंचल)	57.10	4.28	6.00	38.37	4.00	52.65	109.75	15.74	0.02	15.76	125.51	61.9	49
दक्षिण	22.	आंध्र प्रदेश	12.66	0	1.37	17.60	0.00	18.97	31.63	1.97	0	1.97	33.60	19.91	59
	23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.07	0	0.00	0.00	0.00	0	0.07	0	0	0	0.07	0.03	43
	23.	केरल	5.12	0	0	0	0	0	5.12	0.21	0	0.21	5.33	1.59	30
	24.	कर्नाटक	3.78	0	0.38	0.21	0	0.56	4.34	1.37	0	1.37	5,711.88	33.00	3.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	25.	तमिलनाडु	5.83	0	0.53	0.24	0	0.77	6.60	0.60	0	0.60	7.20	1.77	25
	26.	पुदुचेरी	0.42	0	0	0.04	0	0.04	0.46	0.08	0	0.08	0.54	0.21	39
	जोड़ (दक्षिण अंचल)		27.88	0	2.25	18.09	0	20.34	48.22	4.23	0	4.23	52.45	25.39	34
पश्चिम	27.	गुजरात	5.00	0.15	0.18	0	0	0.33	5.33	0.30	0	0.30	5.63	3.70	66
	28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28.	महाराष्ट्र	11.77	0.13	0.69	1.14	0.57	2.53	14.30	1.42	0	1.42	15.72	4.66	30
	29.	गोवा	0.15	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0.15	0.12	80
	30.	मध्य प्रदेश	3.37	0.02	0.87	0.92	0.00	1.81	5.18	0.35	0	0.35	5.53	3.11	56
	31.	छत्तीसगढ़	5.12	0.2	0.08	1.11	0.05	1.44	6.56	0.02	0.25	0.27	6.83	3.14	46
		जोड़ (पश्चिम अंचल)	25.41	0.50	1.82	3.17	0.62	6.11	31.52	2.09	0.25	2.34	33.86	14.73	44
		कुल जोड़	129.48	5.09	12.36	63.26	6.42	87.13	216.61	22.06	0.27	22.33	238.94	117.49	49

भारतीय खाद्य निगम की 31.03.2009 को भंडारण क्षमता की स्थिति

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र. सं.	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	भा.खा.नि. की अपनी	ढकी हुई जहां से किराए पर ली गई				जोड़ किराए की	जोड़ ढकी हुई	कैप (खुली)			कुल जोड़	रखा गया स्टॉक	उपयोग (% में)
				राज्य सरकार	के.भ.नि	रा.भ.नि	निजी पार्टियां			अपनी	किराए की	जोड़			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
पूर्व	1.	बिहार	3.66	0.03	0.66	0.79	0.48	1.96	5.62	0	0	0	5.62	4.20	75
	2.	झारखण्ड	0.66	0.02	0.13	0.17	0.20	0.52	1.18	0	0	0	1.18	0.93	79
	3.	उड़ीसा	2.93	0	0.90	2.94	0.15	3.99	6.92	0	0	0	6.92	4.87	70
	4.	पश्चिम बंगाल	8.59	0.20	0.88	0	0.61	1.69	10.28	0	0	0	10.28	9.12	89
	5.	सिक्किम	0.10	0.01	0	0	0	0.01	0.11	0	0	0	0.11	0.08	73
	जोड़ (पूर्व जोन)		15.94	0.26	2.57	3.90	1.44	8.17	24.11	0	0	0	24.11	19.20	80
उत्तर	6.	असम	2.07	0	0.17	0.10	0.39	0.66	2.73	0	0	0	2.73	1.48	54
	7.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.02	0	0	0	0.02	0.20	0	0	0	0.20	0.09	45
	8.	मेघालय	0.14	0	0.07	0.05	0	0.12	0.26	0	0	0	0.26	0.11	42
	9.	मिजोरम	0.22	0.01	0	0	0	0.01	0.23	0	0	0	0.23	0.12	52
	10.	त्रिपुरा	027	0.05	0.17	0	0	0.22	0.49	0	0	0	0.49	0.26	53
	11.	मणिपुर	0.20	0	0	0	0	0	0.20	0	0	0	0.20	0.06	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	12.	नागालैंड	0.20	0	0.12	0	0	0.12	0.32	0	0	0	0.32	0.21	66
	जोड़ (पूर्वोत्तर अंचल)		3.28	0.08	0.53	0.15	0.39	1.15	4.43	0	0	0	4.43	2.33	53
उत्तर	13.	दिल्ली	3.36	0	0	0	0	0	3.36	0.34	0	0.34	3.70	3.35	91
	14.	हरियाणा	7.68	3.84	1.92	3.99	2.55	12.30	19.98	3.18	0	3.18	23.16	14.24	61
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.06	0.05	0	0	0.11	0.25	0	0	0	0.25	0.20	80
	16.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.16	0	0	0.10	0.26	1.29	0	0	0	1.29	1.03	80
	17.	पंजाब	21.84	0.04	3.00	27.27	3.67	33.98	55.82	6.31	0	6.31	62.13	49.19	79
	18.	चंडीगढ़	0.40	0	0.37	0.20	0	0.57	0.97	0.08	0	0.08	1.05	1.06	101
	19.	राजस्थान	7.06	0	0.36	0.17	0.79	1.32	8.38	1.58	0.07	1.65	10.03	5.98	60
	20.	उत्तर प्रदेश	14.95	0.07	2.22	4.51	0.23	7.03	21.98	4.15	0.00	4.15	26.13	14.53	56
	21.	उत्तराखण्ड	0.66	0.27	0.39	0.56	0.05	1.27	1.93	0.09	0.08	0.17	2.10	1.95	93
	जोड़ (उत्तर अंचल)		57.12	4.44	8.31	36.70	7.39	56.84	113.96	15.73	0.15	15.88	129.84	91.53	70
दक्षिण	22.	आंध्र प्रदेश	12.66	0	3.10	15.09	0.45	18.64	31.30	2.85	0.00	2.85	34.15	30.14	88
	23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.07	0	0.00	0.00	0.00	0	0.07	0	0	0	0.07	0.03	43
	24.	केरल	5.17	0	0	0	0	0	5.17	0.00	0.00	0.00	5.17	4.34	84
	25.	कर्नाटक	3.78	0	1.13	1.24	0	2.37	6.15	0.92	0.00	0.92	7.07	5.85	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	26.	तमिलनाडु	5.80	0	2.04	0.53	0	2.57	8.37	0.58	0.00	0.58	8.95	8.32	93
	27.	पुदुचेरी	0.44	0	0	0.02	0	0.02	0.46	0.08	0.00	0.08	0.54	0.39	72
	जोड़ (दक्षिण अंचल)		27.92	0	6.27	16.88	0.45	23.60	51.52	4.43	0.00	4.43	55.95	49.07	88
पश्चिम	28.	गुजरात	5.00	0.19	0.79	0.00	0.02	1.00	6.00	0.30	0.00	0.30	6.30	5.37	85
	29.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31.	महाराष्ट्र	11.77	0.13	1.96	2.03	0.88	5.00	16.77	0.92	0.00	0.92	17.69	12.41	70
	32.	गोवा	0.15	0	0	0	0	0	0.15	0	0.00	0	0.15	0.17	113
	33.	मध्य प्रदेश	3.37	0.23	1.49	1.56	0.89	4.17	7.54	0.35	0.00	0.35	7.89	6.23	79
	34.	छत्तीसगढ़	5.12	0.13	0.12	0.99	0.07	1.31	6.43	0	0.00	0	6.43	6.27	98
	जोड़ (पश्चिम अंचल)		25.41	0.68	4.36	4.58	1.86	11.48	36.89	1.57	0.00	1.57	38.46	30.45	79
	कुल जोड़		129.67	5.46	22.04	62.21	11.53	101.24	230.91	21.73	0.15	21.88	252.79	192.58	76

भारतीय खाद्य निगम की 30.06.2009 को भंडारण क्षमता की स्थिति

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र. सं.	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	भा.खा.नि. की अपनी	ढकी हुई जहां से किराए पर ली गई				जोड़ किराए की	जोड़ ढकी हुई	कैप (खुली)			कुल जोड़	रखा गया स्टॉक	उपयोग (% में)
				राज्य सरकार	के.भ.नि	रा.भ.नि	निजी पार्टियां			अपनी	किराए की	जोड़			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
पूर्व	1.	बिहार	3.66	0.03	0.66	0.82	0.48	1.99	5.65	0.43	0	0.43	6.08	4.34	71
	2.	झारखंड	0.66	0.02	0.13	0.15	0.20	0.50	1.16	0	0	0	1.16	1.05	91
	3.	उड़ीसा	2.93	0	0.74	2.76	0.15	3.65	6.58	0	0	0	6.58	6.51	99
	4.	पश्चिम बंगाल	8.59	0.19	0.92	0	0.87	1.98	10.57	0	0	0	10.57	9.00	85
	5.	सिक्किम	0.10	0.01	0	0	0	0.01	0.11	0	0	0	0.11	0.07	64
		जोड़ (पूर्व जोन)	15.94	0.25	2.45	3.73	1.70	8.13	24.07	0.43	0	0.43	24.50	20.97	87
उत्तर-पूर्व	6.	असम	2.07	0	0.18	0.10	0.39	0.67	2.74	0	0	0	2.74	1.42	52
	7.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.03	0	0	0	0.03	0.21	0	0	0	0.21	0.08	38
	8.	मेघालय	0.14	0	0.07	0.05	0	0.12	0.26	0	0	0	0.26	0.11	42
	9.	मिजोरम	0.22	0.01	0	0	0	0.01	0.23	0	0	0	0.23	0.03	13
	10.	त्रिपुरा	0.27	0.05	0.17	0	0	0.22	0.49	0	0	0	0.49	0.21	42
	11.	मणिपुर	0.20	0	0	0	0	0	0.20	0	0	0	0.20	0.07	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	12.	नागालैंड	0.20	0	0.12	0	0	0.12	0.32	0	0	0	0.32	0.23	72
		जोड़ (पूर्वोत्तर अंचल)	3.28	0.09	0.54	0.15	0.39	1.17	4.45	0	0	0	4.45	2.15	48
उत्तर	13.	दिल्ली	3.36	0	0	0	0	0	3.36	0.34	0	0.34	3.70	3.40	92
	14.	हरियाणा	7.68	3.84	2.16	4.05	2.18	12.23	19.91	3.21	0.07	3.28	23.19	22.49	97
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.06	0.05	0	0	0.11	0.25	0	0	0	0.25	0.14	58
	16.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.15	0	0	0.11	0.26	1.29	0	0	0	1.29	0.89	69
	17.	पंजाब	21.84	0.48	3.53	30.56	4.15	38.72	60.56	6.35	3.54	9.89	70.45	68.45	97
	18.	चंडीगढ़	0.40	0	0.46	0.20	0	0.66	1.06	0.08	0.14	0.22	1.28	1.25	98
	19.	राजस्थान	7.06	0.13	1.63	2.99	1.54	6.29	13.35	1.58	1.64	3.22	16.57	14.29	86
	20.	उत्तर प्रदेश	14.95	0.06	2.25	4.50	0.23	7.04	21.99	4.69	0.10	4.79	26.78	18.28	68
	21.	उत्तरांचल	0.66	0.30	0.50	0.56	0.05	1.41	2.07	0.09	0.21	0.30	2.37	2.43	103
		जोड़ (उत्तर अंचल)	57.12	5.02	10.58	42.86	8.26	66.72	123.84	16.34	5.70	22.04	145.88	131.63	90
दक्षिण	22.	आंध्र प्रदेश	12.66	0	4.32	16.98	0.52	21.82	34.48	2.62	0.00	2.62	37.10	37.37	101
	23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.07	0	0.00	0.00	0.00	0	0.07	0	0	0	0.07	0.02	29
	24.	केरल	5.17	0	0	0	0	0	5.17	0.20	0.0	0.20	5.37	4.57	85
	25.	कर्नाटक	3.78	0	1.15	1.23	0	2.38	6.16	1.36	0.00	1.36	7.52	6.14	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	26.	तमिलनाडु	5.80	0	2.24	0.50	0.50	3.24	9.04	0.53	0.00	0.53	9.57	9.68	101
	27.	पुदुचेरी	0.44	0	0.05	0.02	0	0.07	0.51	0.05	0.00	0.05	0.56	0.47	82
	जोड़ (दक्षिण अंचल)		27.92	0	7.76	18.73	1.02	27.51	55.43	4.76	0.00	4.76	60.19	58.25	94
पश्चिम	28.	गुजरात	5.00	0.14	0.70	0.02	0	0.86	5.86	0.27	0.00	0.27	6.13	4.52	74
	29.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31.	महाराष्ट्र	11.77	0.13	2.09	2.03	1.17	5.42	17.19	0.92	0.00	0.92	18.11	11.53	64
	32.	गोवा	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15				0.15	0.14	93
	33.	मध्य प्रदेश	3.37	0.29	1.52	1.60	1.61	5.02	8.39	0.35	0.00	0.35	8.74	6.20	71
	34.	छत्तीसगढ़	5.12	0.13	0.29	1.80	0.10	2.32	7.44	0	0.00	0.00	7.44	7.27	98
	जोड़ (पश्चिम अंचल)		25.41	0.69	4.60	5.45	2.88	13.62	39.03	1.54	0.00	1.54	40.57	29.66	73
	कुल जोड़		129.67	6.05	25.93	70.92	14.25	117.15	246.82	23.07	5.70	28.77	275.59	242.66	88

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2006-07 से 2008-09 के दौरान सृजित क्षमता

क्षमता टन में

क्र. सं.	अंचल/केंद्र का नाम	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
	दक्षिण अंचल			
1.	तुमकुर/कर्नाटक		5,000	
	उत्तर अंचल			
1.	बडगांव/जम्मू और कश्मीर	1,250		
2.	कुपवाड़ा/जम्मू और कश्मीर	5,000		
3.	केलोंग/हिमाचल प्रदेश	2,500		
	पूर्वोत्तर, सिक्किम सहित			
1.	लोंगटाले/मिजोरम	3,340		
2.	चन्द्रपुर/त्रिपुरा	5,000		
3.	सेनचोवा/असम	1,670		
4.	बुआलपुई/मिजोरम		4,590	
5.	बदरपुरघाट/असम		5,000	
6.	चौलखोवा/असम	1,670	2,500	
7.	नन्दननगर/त्रिपुरा			2,500
	कुल जोड़	20,430	17,090	2,500

विवरण-III

भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए 11वीं पंचवषीय योजना के दौरान भारतीय खाद्य निगम को जारी की गई इक्विटी का ब्यौरा

वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)
2007-08	4.00
2008-09	16.45

वर्ष 2009-10 में जारी की गई निधियों में से 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सृजित की जाने वाली संभावित क्षमता

क्र. सं.	केंद्र/राज्य का नाम	कुल प्रस्तावित क्षमता (टन में)	परियोजना की कुल अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	वर्षवार निधियों की आवश्यकता (करोड़ रुपए में)#	भा.खा.नि. द्वारा दी गई अनुसूची
1	2	3	4	5	6
	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर सहित				
1.	चांगसारी/असम	50,000	64.00 (भूमि लागत+चारदीवारी+ रेलवे साइडिंग+विकास/ निर्माण लागत)	4.00 (2009-10)	गोदाम के 31 मार्च, 2013 तक पूरे होने की संभावना है

1	2	3	4	5	6
2.	जिरिबम/मणिपुर	2,500	2.00	–	कार्य अभी सौंपा जाना है
3.	कोहिमा/नागालैंड	5,000	4.00	1.50 (2009-10) 0.90 (2010-11)	गोदाम के 31 मार्च, 2011 तक पूरे होने की संभावना है
4.	हेलाकांडी/असम (सिलचर के पास)	5,000	3.25	2.00 (2009-10) 1.25 (2010-11)	गोदाम के 31 मार्च, 2011 तक पूरे होने की संभावना है
5.	जोरथांग/सिक्किम	5,000	–	–	अनुमान लगाया जा रहा है। पूरा होने की संभावित तारीख 31 मार्च, 2011
	जोड़	67,500	73.25	9.65*	

*इसमें से 7.50 करोड़ रुपए चालू वित्त वर्ष के दौरान (अर्थात् 2009-10) के दौरान खर्च किए जाने की संभावना है।

#भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिए गए अनुसार

क्र. सं.	केंद्र/राज्य का नाम	कुल प्रस्तावित क्षमता (टन में)	परियोजना की कुल अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	वर्षवार निधियों की आवश्यकता (करोड़ रुपए में)#	टिप्पणी
	पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़ कर				
1.	डुगरपल्ली/उड़ीसा	9,170	2.35	2.03 (2009-10)	गोदाम के 31 मार्च, 2010 तक पूरे होने की संभावना है
2.	लक्षद्वीप/संघ राज्य क्षेत्र	2,500	3.79	2.00 (2009-10) 0.79 (2010-11)	गोदाम के 30 जून, 2010 तक पूरे होने की संभावना है
3.	जलपाईगुड़ी/पश्चिम बंगाल	10,000	10.00 (5.00 भूमि लागत+5.00 गोदाम निर्माण की लागत	5.00 (2009-10) 3.00 (2010-11) 2.00 (2011-12)	भूमि अभी ली जानी है
	जोड़	21,670	16.14	14.82**	

**इसमें से 9.03 करोड़ रुपए चालू वित्त वर्ष के दौरान (अर्थात् 2009-10) के दौरान खर्च किए जाने की संभावना है।

विवरण-IV

पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकारों को जारी किए गए सहायता अनुदान का ब्यौरा

राज्य/केंद्र	प्रस्तावित वास्तविक क्षमता (टन में)	11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों को जारी की गई निधियां (लाख रुपए में)	निधियां जारी किए जाने का वर्ष
मिजोरम			
चम्पाई	3000	200.00	2007-08
सेरचिब	3000		
जम्मू और कश्मीर			
लेथपोरा	6160	100.00	2008-09
त्रिपुरा			
कंचनपुर	1000	198.00	2008-09
गंडाचेरा	1000		
सिलचारी	500		
गंगानगर	500		
चमानू	1000		
मेघालय			
नांगस्टोइन	2500	200.72	2008-09
खन्नपारा	2000		
कुल जोड़	20660	698.72 लगभग 6.98 करोड़ रुपए	

केन्द्रीय सड़क निधि

•260. **श्री दुष्यंत सिंह :**
श्री जगदम्बिका पाल :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यों से केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निधियां जारी करने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है तथा उक्त अवधि के दौरान लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों को, निर्धारित दिशानिर्देशों, निधियों के उपयोग, उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने तथा राज्य को किए गए समग्र आबंटन के भीतर कार्य की प्रगति को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष राज्यों से नए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इसलिए, पिछले तीन वर्षों 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के संबंध में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। चालू वर्ष के दौरान प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया जाना, उपलब्ध बैंक ऑफ सेंक्शन और राज्यों द्वारा धनराशि के उपयोग पर निर्भर करता है।

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 (30.06.2009 तक) के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 (30 जून, 2009 तक) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा

(धनराशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07		2007-08		2008-09		2009-2010 (जून, 2009 तक)	
		प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	55.17	55.17	246.77	246.77	1086.05	1086.05	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	42.30	42.30	24.92	24.92	1.77	1.77	20.62	20.62
3.	असम	18.42	18.42	86.65	86.65	90.45	90.45	—	—
4.	बिहार	18.46	18.46	85.10	85.40	23.87	23.87	—	—
5.	छत्तीसगढ़	51.14	24.54	65.45	10.02	138.96	102.95	—	—
6.	गोवा	10.59	10.59	—	—	66.04	14.12	—	—
7.	गुजरात	54.77	55.69	102.28	116.08	348.25	389.29	—	—
8.	हरियाणा	29.74	29.74	108.27	108.27	169.90	169.90	154.95	—
9.	हिमाचल प्रदेश	9.83	4.25	12.80	12.80	102.82	52.00	—	—
10.	जम्मू और कश्मीर	131.43	52.35	297.52	156.00	297.52	198.84	—	—
11.	झारखंड	88.97	88.97	—	—	82.99	82.57	—	—
12.	कर्नाटक	228.60	228.60	7.51	7.51	553.50	553.50	—	—
13.	केरल	28.51	28.51	67.38	67.38	110.02	110.02	13.16	1316
14.	मध्य प्रदेश	401.02	103.02	182.93	107.99	393.41	134.65	525.32	—
15.	महाराष्ट्र	843.82	195.47	874.24	171.37	660.52	640.98	727.82	10.30
16.	मणिपुर	7.01	7.01	3.98	3.98	29.39	—	203.20	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मेघालय	—	—	14.39	14.39	12.58	—	—	'11.58
18.	मिजोरम	11.46	11.46	16.25	16.33	—	—	—	—
19.	नागालैंड	—	—	9.81	9.81	6.53	6.53	—	—
20.	उड़ीसा	70.82	70.82	84.45	84.45	207.29	181.53	—	—
21.	पंजाब	51.88	46.89	131.18	57.68	67.30	65.20	—	—
22.	राजस्थान	159.48	159.48	163.92	163.92	214.08	214.08	356.86	—
23.	सिक्किम	2.70	2.70	4.81	4.81	23.82	2.10	—	—
24.	तमिलनाडु	143.80	143.80	39.35	39.35	379.08	379.08	—	—
25.	त्रिपुरा	—	—	20.30	20.30	—	—	—	—
26.	उत्तराखंड	—	—	111.59	—	301.30	76.03	—	—
27.	उत्तर प्रदेश	23.83	183.83	299.93	232.60	1033.07	336.40	109.27	—
28.	पश्चिम बंगाल	47.16	47.16	86.05	—	357.32	163.33	101.24	—
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	13.99	13.99
30.	चंडीगढ़	375.50	—	—	—	29.76	3.76	—	—
31.	दिल्ली	43.67	43.67	54.00	—	106.51	68.98	68.50	45.74
32.	पुदुचेरी	—	—	3.59	3.59	—	—	—	—

*प्रस्ताव फरवरी, 2009 में अनुमोदित परन्तु आचार संहिता के लागू हो जाने के कारण मंजूरी जारी नहीं की जा सकी।

[हिन्दी]

नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

2195. श्री रामसिंह राठवा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो देश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए है; और

(ग) गुजरात सहित विभिन्न राज्यों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कितनी निधियां आबंटित की गयी हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी नहीं। वर्तमान में, सरकार की प्राथमिकता, नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करने की नहीं है, बल्कि पहले से

विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर जोर दिया जा रहा है जिनमें कई न्यूनताएं हैं।

(ख) उक्त को ध्यान में रखते हुए, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) चालू वर्ष 2009.10 के दौरान परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गुजरात सहित विभिन्न राज्यों को आंबटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों का राज्य-वार आबंटन दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	आबंटन 2009.10* (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	78.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.30
3.	असम	40.00
4.	बिहार	50.00
5.	चंडीगढ़	1.30
6.	छत्तीसगढ़	31.50
7.	दिल्ली	5.00
8.	गोवा	11.00
9.	गुजरात	41.70
10.	हरियाणा	35.00
11.	हिमाचल प्रदेश	26.00
12.	झारखंड	40.00
13.	कर्नाटक	65.30
14.	केरल	43.70
15.	मध्य प्रदेश	36.70
16.	महाराष्ट्र	89.30
17.	मणिपुर	13.30
18.	मेघालय	20.00
19.	मिजोरम	9.30
20.	नागालैंड	13.30
21.	उड़ीसा	66.70
22.	पुदुचेरी	2.30
23.	पंजाब	51.30
24.	राजस्थान	61.30
25.	तमिलनाडु	61.50
26.	उत्तर प्रदेश	83.30
27.	उत्तराखंड	30.00
28.	पश्चिम बंगाल	59.30
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.30
	जोड़	1072.70

[अनुवाद]

अग्रिम यात्री सूचना प्रणाली

2196. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर अग्रिम यात्री सूचना प्रणाली (एपीआईएस) शुरू हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना को देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना पूरे देश में कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी हां। अग्रिम यात्री सूचना प्रणाली (ए.पी.आई.एस.) अपने पहले चरण में देश के छः विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, चैन्नें, हैदराबाद, बैंगलोर और कोचिन पर शुरू हो गई है।

(ग) जी हां।

(घ) देश में सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ए.पी.आई.एस. की सुविधा शुरू करने के लिए, एन.आई.सी. ने नेटवर्क ढांचे को लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

कॅयर कामगारों हेतु योजनाएं

2197. श्री के.सी. वेणुगोपाल : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल सहित देश में कॅयर उद्योग के कामगारों हेतु कोई योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी योजनाओं के परिणामस्वरूप कितना लाभ मिला है;

(घ) क्या कॅयर उद्योग/कामगारों हेतु कोई नई केन्द्र प्रायोजित योजना शुरू किए जाने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) कॅयर बोर्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन स्वायत निकाय है, जो कि कॅयर उद्योग के समग्र विकास तथा केरल सहित देश में पारंपरिक उद्योग में लगे हुए कामगारों के रहन सहन में सुधार के लिए बहुत सी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका ब्यौरा निम्नवत दिया गया है:-

(I) कॅयर उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन (आरईएमओटी)

कताईकारों तथा अति लघु घरेलू क्षेत्र की सहायता के लिए मार्च 2008 में "कॅयर उद्योग के नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन (आरईएमओटी)" पर एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना शेरू की गई है। इस योज़ना के तहत कताईकारों तथा अतिलघु क्षेत्र के कामगारों के समूहों को अप्रचलित रैटो/हथकरघों को बदलने तथा वर्कशेडो के निर्माण के लिए सहायता दी जाती है, ताकि ऐसे कामगारों का उत्पादन और आय बढ़ सके। योजना में 11वीं योजना अवधि में केरल सहित देश में, 4000 कताई इकाइयों तथा 3200 अति लघु/घरेलू इकाइयों को कवर करने की परिकल्पना की गई है।

(II) पारंपरिक उद्योगों के पुनुरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति)

"पारंपरिक उद्योगों के पुनुरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति)" शीर्षक योजना अक्तूबर 2005 में खादी, ग्राम एवं कॅयर उद्योग क्षेत्र में पांच वर्षों की अवधि में लगभग 100 क्लस्टर विकसित करने की दृष्टि से शुरू की गई है, ताकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए इन उद्योगों को और अधिक उत्पादनशील और प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके। योजना में उत्पादन उपकरणों को बदलने, सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना करने, उत्पाद विकास, गुणवत्ता सुधार, सुधरे विपणन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण आदि के लिए आवश्यकता आधारित सहायता की परिकल्पना की गई है। स्फूर्ति के तहत कॅयर का उत्पादन करने वाले राज्यों से 26 कॅयर क्लस्टरों को उनके विकास के लिए अनुमोदित किया गया है।

(III) महिला कॅयर योजना (एमसीवाई) सहित कौशल उन्नयनीकरण तथा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

कॅयर बोर्ड अपने प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से दस्तकारों तथा कॅयर उद्योग में लगे हुए कामगारों को कॅयर प्रसंस्करण में प्रशिक्षण प्रदान करता है। कॅयर बोर्ड उन कॅयर कामगारों जो नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्रों तक नहीं पहुंच सकते, के

लाभ के लिए फील्ड प्रशिक्षण क्रियाकलाप भी कराता है। इसके अलावा, बोर्ड उत्पादन केन्द्रों में फाइबर एक्सट्रैक्शन, कताई एवं रंगाई आदि पर गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम आयोजित करता है।

महिला कॅयर योजना कॅयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही महिलोन्मुखी स्वरोजगार योजना है। स्कीम को प्रशिक्षित महिला कारीगरों को मोटरयुक्त रैट/मोटरयुक्त पारपंरिक रैट के वितरण हेतु तैयार किया गया है। मोटरयुक्त रैट तथा मोटरयुक्त पारंपरिक रैट की लागत के क्रमश: 2,956 रुपये तथा 7,500 रुपये की अधिकतम उच्चतम सीमा के अधीन 75% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत 5367 कॅयर कामगारों को प्रशिक्षित किया गया था तथा वर्ष 2008-09 के दौरान 3009 रैटो का वितरण किया गया था।

(IV) कॅयर कामगारों के लिए कॅयर बोर्ड सामुहिक वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना

कॅयर बोर्ड देश में, कॅयर कामगारों के हित के लिए, कॅयर बोर्ड कॅयर कामगार समूह वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। दसवीं योजना अवधि के दौरान 103 बीमा दावों को निपटाया गया तथा इस स्कीम के तहत लाभान्वितों को 28.79 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई थी।

(V) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के जरिए कॅयर कामगारों के कठिन कार्य को सरल बनाने में मदद करने के लिए मैटेलिक हैंडलूम ''अनुग्रह'' तथा न्यूमैटिक पावरलूम ''अनुपम'' विकसित किए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

प्रसार भारती का कार्यकरण

2198. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती की स्थापना के बाद से उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों/कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों/अति कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के प्रतिष्ठापन की गति धीमी पड़ गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रमों को पूरे देश में प्रसारित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्रसार भारती के गठन के समय दूरदर्शन नेटवर्क में ट्रांसमीटरों की संख्या 924 से बढ़कर इस समय 1416 हो गई है। इसी प्रकार, प्रसार भारती के गठन के समय आकाशवाणी (एआईआर) ट्रांसमीटरों की संख्या 299 से बढ़कर आज की तारीख तक 374 हो गई है।

(ग) स्थलीय प्रसारण द्वारा कवर न किए गए क्षेत्रों और देश के शेष भाग में दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा "डीडी डायरेक्ट प्लस" के जरिए बहु-चैनल टीवी कवरेज उपलब्ध करायी गयी है। डीटीएच सिगनलों को पूरे देश (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) में लघु आकार की डिश अभिग्रहण इकाइयों की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। पूरे देश में आकाशवाणी की कवरेज को और बढ़ाने के लिए 11वीं योजना के अंतर्गत विस्तारित स्कीम में 200 नए ट्रांसमीटरों को अनुमोदित किया गया है।

[अनुवाद]

दलहनों और तिलहनों की मांग और उत्पादन

2199. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दलहनों और तिलहनों की अनुमानित मांग, वास्तविक उत्पादन और उपलब्धता कितनी रही तथा इनका कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) देश में अगले तीन वर्षों में दलहनों और तिलहनों का अनुमानित उत्पादन और मांग कितनी रहने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने दलहनों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की कोई समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तिलहनों और दलहनों का उत्पादन बढ़ाने हेतु कौन-सी नयी योजनाएं/प्रोत्साहन शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान दलहनों तथा तिलहनों की अनुमानित मांग, अनुमानित उत्पादन (तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार) तथा उनकी आयात की गई मात्रा निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

(मिलियन टन)

फसल		2005-06	2006-07	2007-08
दलहन	अनुमानित उत्पादन	13.39	14.20	14.76
	अनुमानित मांग	17.38	17.71	16.77
	आयात की गई मात्रा	1.65	2.21	2.79
तिलहन	अनुमानित उत्पादन	27.98	24.29	29.76
	अनुमानित मांग	41.41	43.89	45.46
	आयात की गई मात्रा	0.03	0.06	0.06

टिप्पणी: 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान दलहनों तथा तिलहनों की अनुमानित मांगे नियामक पद्धति पर आधारित हैं

(ख) अगले तीन वर्षों अर्थात 2009-10 से 2011-12 के दौरान दलहनों तथा तिलहनों की प्रक्षेपित मांग तथा प्रक्षेपित उत्पादन निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

फसल		2009-10	2010-11	2011-12
दलहन	प्रक्षेपित उत्पादन	14.86	15.29	15.73
	प्रक्षेपित मांग	18.29	19.08	19.91
तिलहन	प्रक्षेपित उत्पादन	26.71	27.12	27.53
	प्रक्षेपित मांग	49.35	51.34	53.39

(ग) से (ङ) तिलहनों तथा दलहनों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, तिलहन विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम की पहले की योजनाओं की समीक्षा की गई है तथा उन्हें एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित "तिलहनों, दलहनों, पाम आयल तथा मक्का की एकीकृत स्कीम (आइसोपाम)" में विलय कर दिया गया है जो दिनांक 01.04.2004 से देश के 14 तिलहन तथा दलहन उत्पादन राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। दसवीं योजना अवधि के दौरान आइसोपॉम के कार्यान्वयन में हुए अनुभव के आधार पर, सहायता के मापदण्डों तथा पैटर्न के संबंध में आवश्यक सुधार, नये संघटनों आदि का समावेशन, 11वीं योजना अवधि के दौरान पहले ही उक्त स्कीम के कार्यान्वयन हेतु कर दिया गया है।

पुन:, दलहनों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन भी 2007-08 से 14 राज्यों के 171 चिन्हित जिलों में कार्यान्वयन के अधीन है।

कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर

2200. श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री सर्वे सत्यनारायण :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केरल सहित प्रत्येक राज्य हेतु कृषि वृद्धि दर के लिए राज्यवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और क्या उपलब्धियां हासिल हुई;

(ख) क्या कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में गिरावट आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 2009-10 के लिए कृषि क्षेत्र में क्या वृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा वृद्धि दर को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) कृषि क्षेत्र में वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक 10वीं योजना (2002-07) तथा 11वीं योजना (2007-12) हेतु राज्यवार वृद्धि दर पर एक विवरण संलग्न है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 2006-07 में 4% से बढ़कर 2007-08 में 4.9% हो गयी है। 11वीं योजना (2007-12) हेतु कृषि का वृद्धि लक्ष्य 4% निर्धारित किया गया है।

(ङ) कृषि क्षेत्र के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की एक नई राज्य नियोजन योजना यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4% की कृषि वृद्धि प्राप्त करने के लिए 2007-08 के दौरान प्रारंभ की गई है। 4% की कृषि वृद्धि प्राप्त करने की रणनीति निम्नलिखित बिन्दुओं पर जोर देगी:

- दालों तथा तिलहन क्षेत्र पर जोर देते हुए प्रादेशिक विशिष्टता आधार पर प्रमुख खाद्य फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में तेजी लाना।
- कृषि, जीवन निर्वाह प्रणाली तथा बेहतर वाटर शेड प्रबंधन के माध्यम से वर्षासिंचित तथा शुष्क भूमि क्षेत्रों का विकास।
- निचले स्तर (ग्रास रूट) पर सुपुर्दगी तंत्र में सुधार करने के लिए विस्तार प्रणाली को बेहतर बनाना।
- जोखिम कम करने, ग्रामीण संकट में कमी तथा बेहतर सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से किसानों के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करना।
- पंचायत राज संस्थानों की और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका।
- बाजारों को आधुनिक बनाना।
- निवेश क्षमता में सुधार तथा सब्सिडी को न्यायसंगत बनाना।

पुन:, एक केन्द्र प्रयोजित योजना "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" 11वीं योजना (2011-12) के अंत तक खाद्यान्नों का 20 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन जिसमें चावल का 10 मिलियन टन, गेहूं का 8 मिलियन टन तथा दालों का 2 मिलियन टन शामिल है, को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ रबी 2007-08 से 17 राज्यों के 312 चिन्हित जिलों में प्रारंभ की गई है।

विवरण

कृषि क्षेत्र हेतु राज्यवार वृद्धि लक्ष्य तथा वृद्धि दर

(प्रतिशत में वार्षिक औसत)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वृद्धि दर		वृद्धि दर		
	10वीं योजना (2002-07)	11वीं योजना (2007-12)	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	3.05	4.00	8.65	3.82	13.03
अरुणाचल प्रदेश	4.00	2.80	2.15	10.75	3.88
असम	3.82	2.00	2.81	2.75	0.45
बिहार	3.75	7.00	-12.56	34.23	-10.17
चंडीगढ़	-2.00		4.37	-1.30	-2.24
छत्तीसगढ़	3.00	1.70	35.62	5.67	3.02
दिल्ली	-12.21		-2.33	0.01	-3.78
गोवा	-0.90	7.70	16.19	-16.24	-15.52

1	2	3	4	5	6
गुजरात	4.03	5.50	22.89	-0.43	
हरियाणा	4.07	5.30	-1.87	14.48	0.92
हिमाचल प्रदेश	4.55	3.00	1.28	-5.61	9.32
जम्मू और कश्मीर	4.20	4.30	0.53	2.99	1.61
झारखंड	3.00	6.30	-19.31	7.42	0.72
कर्नाटक	4.99	5.40	3.93	-2.12	17.19
केरल	3.05	0.30	3.48	2.70	1.37
मध्य प्रदेश	4.00	4.40	8.02	2.42	-2.14
महाराष्ट्र	3.56	4.40	9.04	10.82	10.78
मणिपुर	3.59	1.20	-9.01	9.26	3.75
मेघालय	4.00	4.70	5.70	4.86	4.86
मिजोरम	2.00	1.60	2.44	1.62	2.74
नागालैंड	4.00	8.40	4.14		
उड़ीसा	4.07	3.00	3.12	3.08	4.48
पुदुचेरी	1.10		-0.09	-0.06	0.81
पंजाब	4.07	2.40	1.90	2.82	4.89
राजस्थान	4.50	3.50	-1.28	6.27	6.75
सिक्किम	5.00	3.30	4.07	4.70	4.93
तमिलनाडु	3.54	4.70	9.59	14.65	-7.22
त्रिपुरा	3.90	1.40	7.32	3.20	
उत्तर प्रदेश	4.67	3.00	1.12	4.72	3.84
उत्तराखंड	3.50	3.00	-1.75	4.80	
पश्चिम बंगाल	5.09	4.00	1.49	1.98	5.14
अखिल भारत	4.00	4.00	5.80	4.00	4.90

स्रोत - वृद्धि लक्ष्य हेतु योजना आयोग और वृद्धि दर हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

लापता बच्चे

2201. श्रीमती सुस्मिता बाउरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश में बच्चों के लापता होने के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश में राज्यवार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए हैं और कितने बच्चों को बचाया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा सभी लापता बच्चों को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2006, 2007 और 2008 के प्रत्येक वर्ष के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार 'लापता' के रूप में सूचित किए गए बच्चों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2006, 2007 और 2008 के प्रत्येक वर्ष के लिए पता लगाए बच्चों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अपराध निवारण करने, उनका पता लगाने, दर्ज करने, जांच-पड़ताल करने और अभियोजना चलाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, केन्द्र सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पृथक सलाह जारी की हैं जिनमें उनसे कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंदर लापता बच्चों के निवारण और नियंत्रण पर अधिक ध्यान केन्द्रित करें। दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में एन.सी.टी. क्षेत्र में लापता व्यक्ति की सूचना देने के लिए 24x7 हेल्प लाइन संख्या, प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन, प्राथमिकी दर्ज करना, वेब-आधारित कंप्यूटर अनुप्रयोग जिपनेट (जेडआईपीएनईटी) का विकास करना शामिल है जिसमें लापता बच्चों की सूचना होती है।

विवरण

वर्ष 2006-2008 के दौरान लापता और पता लगाए गए बच्चों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2006		2007		2008	
		लापता	पता लगाए गए	लापता	पता लगाए गए	लापता	पता लगाए गए
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22	22	35	35	56	53
2.	आंध्र प्रदेश	2312	876	774	535	एन आर	एन आर
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	7	7	12	10
4.	असम	889	311	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
5.	बिहार	524	360	476	346	एन आर	एन आर
6.	चंडीगढ़	104	95	172	139	118	110

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	छत्तीसगढ़	2613	2165	2140	1687	एन आर	एन आर
8.	दादरा और नगर हवेली	17	16	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
9.	दमन और दीव	15	15	11	8	एन आर	एन आर
10.	दिल्ली*	7025	5780	231	128	एन आर	एन आर
11.	गोवा	225	181	272	219	257	271
12.	गुजरात	1996	1904	2382	1990	2644	2662
13.	हरियाणा	461	294	754	400	845	388
14.	हिमाचल प्रदेश	197	144	279	162	362	265
15.	जम्मू और कश्मीर	456	321	445	319	एन आर	एन आर
16.	झारखंड	328	138	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
17.	कर्नाटक	3495	2912	3630	3022	2955	3006
18.	केरल	1047	925	968	829	1206	1312
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	एन आर	एन आर
20.	मध्य प्रदेश	8079	7416	8852	7825	एन आर	एन आर
21.	महाराष्ट्र	13403	10834	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
22.	मणिपुर	7	2	39	25	45	24
23.	मेघालय	17	1	36	12	एन आर	एन आर
24.	मिजोरम	0	0	0	0	एन आर	एन आर
25.	नागालैंड	1	1	0	0	एन आर	एन आर
26.	उड़ीसा	1398	685	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
27.	पुदुचेरी	44	44	68	68	एन आर	एन आर
28.	पंजाब	404	244	564	792	एन आर	एन आर

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	राजस्थान	2155	2073	2425	2157	2477	1975
30.	सिक्किम	193	124	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
31.	तमिलनाडु	1394	1310	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
32.	त्रिपुरा	201	201	193	189	292	427
33.	उत्तर प्रदेश	3974	3401	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
34.	उत्तराखंड	458	368	356	252	एन आर	एन आर
35.	पश्चिम बंगाल	3467	एन आर	11697	5725	11092	9545
	कुल (राज्य)	56923	44165	36806	26871	22361	20048

टिप्पणी: 1. एन आर का तात्पर्य प्राप्त न हुए आंकड़ों से है।

2. *वर्ष 2007 की सूचना, मार्च तक की ही है।

[हिन्दी]

किसानों को वृदावस्था पेंशन

2202. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में किसानों हेतु वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं होता।

ग्रामोद्योगों में स्व-रोजगार

2203. **श्री अर्जुन मुंडा :** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखण्ड सहित विभिन्न राज्यों में हस्तशिल्प, हथकरघा, रेशम, खादी ग्रामोद्योग और पारंपरिक उद्योग क्षेत्र में स्व-रोजगार और आत्म-निर्भरता के उपलब्ध अवसर क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन क्षेत्रों का विकास करके रोजगार के अवसर मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो केवीआईसी द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार ने बेरोजगार युवाओं और परंपरागत कारीगरों के लिए विभिन्न राज्यों में स्व-रोजगार अवसर उपलब्ध कराए हैं। खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा मोटे तौर पर सात समूहों, अर्थात्, (1) खनिज आधारित उद्योग [एमबीआई] (2) वन आधारित उद्योग [एफबीआई] (3) कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

[एएफपीआई] (4) पोलिमर और रसायन आधारित उद्योग [पीसीबीआई] (5) हस्तनिर्मित कागज और रेशा उद्योग [एचएमपीएफआई] (6) ग्रामीण इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग [आरईबीटीआई] और (7) सेवा कार्यकलाप में वर्गीकृत किए गए ग्रामोद्योग इकाइयों/ सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

2006-07 और 2007-08 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे शहरों में केवीआईसी के माध्यम से 01.04.1995 से 31.03.2008 तक कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्र की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना 'ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)' और 2008-09 के दौरान हाल में आरंभ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सृजित स्व रोजगार अवसरों सहित रोजगार से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की झारखंड सहित राज्य/संघ शासित प्रदेश वार संख्या सलग्न विवरण-I में दी गई है और 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योगों में प्रदान किए गए कुल रोजगार का कुल ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। ये उपलब्धियां दर्शाती हैं कि झारखंड और देश के अन्य राज्यों में प्रचुर स्व-रोजगार एवं आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध हैं।

(ग) 2008-09 के दौरान सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) ने खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए निम्नलिखित तीन नई योजनाओं को अनुमोदित किया है:-

(i) सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन के लिए उस समय विद्यमान आरईजीपी के मंत्रालय की दूसरी विद्यमान योजना प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के साथ विलय के द्वारा 'प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना अनुमोदित की गई है।' यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र नोडल एजेंसी के रूप में केवीआईसी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर पर, इस योजना को बैंकों की सहभागिता से केवीआईसी के क्षेत्र कार्यालयों, राज्य/संघ शासित प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) और जिला उद्योग केंद्रों और बैंकों के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत, उद्यमी सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये और विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के केवीआईसी/ केवीआईबी/डीआईसी से मार्जिन मनी सहायता और कार्यान्वयक सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों, आदि से ऋण लेकर ग्रामोद्योग स्थापित कर सकते हैं।

(ii) अन्य बातों के साथ-साथ अप्रचलित और पुरानी मशीनरी तथा उपकरणों को हटाने और मौजूदा/प्रचालनरत मशीनरी तथा उपकरणों की मरम्मत तथा नवीनीकरण के द्वारा खादी कारीगरों और संबंधित सेवा प्रदानकर्ताओं को स्थायी रोजगार दिलाने और अधिक बाजार प्रेरित, गुणवत्ता उत्पादन के साथ 200 चुनिंदा खादी संस्थानों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने तथा खादी कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों, जैसे उत्पादन, वितरण, संवर्धन तथा क्षमता निर्माण में समान रूप से संतुलित और आवश्यकता आधारित सहयोग प्रदान के उद्देश्य से 'खादी उद्योगों और कारीकारों की उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने' की योजना।

(iii) बेहतर कार्य वातावरण के लिए लगभग 38000 वर्कशेडों के निर्माण हेतु खादी कताईकारों व बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए खादी कारीगरों हेतु वर्कशेड योजना।

इसके अतिरिक्त, एक नई योजना 'विद्यमान कमजोर खादी संस्थानों की आधारभूत संरचना के सशक्तीकरण और विपणन तंत्र के लिए सहायता की योजना' को जुलाई 2009 में पहचाने गए लगभग 100 कमजोर खादी संस्थानों की सहायता के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया है ताकि उन संस्थानों को अपनी स्थिति सुधारने और रोजगार की अपनी क्षमता को बहाल करने में सक्षम बनाया जा सके और खादी संस्थानों के चुनिंदा बिक्री आउटलेटों के नवीनीकरण सहित विपणन तंत्र के विकास के द्वारा खादी उत्पादों के विपणन को सुधारा जा सके।

वर्ष 2009-19 के लिए इन तीन नई योजनाओं के लिए केवीआईसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

योजना का नाम	बजट आबंटन	लक्ष्य
पीएमईजीपी	823 करोड़ रुपये	6.17 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन।
खादी कारीगारों के लिए वर्कशेड योजना	15 करोड़ रुपये	6,000 कताईकारों को वर्कशेड प्रदान किया जाना है।
खादी उद्योगों और कारीगरों की उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना	8 करोड़ रुपये	23 खादी संस्थानों की सहायता की जानी है।
विद्यमान कमजोर खादी संस्थानों की आधारभूत संरचना के सशक्तीकरण और विपणन तंत्र के लिए सहायता की योजना	5 करोड़ रुपये	8 चुनिंदा बिक्री आउटलेटों के नवीनीकरण सहित 30 पहचाने गए कमजोर खादी संस्थानों की सहायता और विपणन तंत्र का विकास

(घ) सूक्ष्म उद्यमों, आदि की स्थापना के द्वारा स्व-रोजगार अवसरों के सृजन के लिए पीएमईजीपी योजना को लोकप्रिय बनाने हेतु, केवीआईसी ने कई कदम उठाए हैं जिनमें जागरूकता कार्यक्रम, राज्य/जिला स्तर की कार्यशालाएं, बैंकर समीक्षा बैठकें, व्यापक प्रचार के लिए जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियां आदि शामिल हैं। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के तहत लगभग 300 मॉडल परियोजनाओं जिन्हें पीएमईजीपी के तहत स्थापित किया जा सकता है, को केवीआईसी की वेबसाइट www.kvic.org पर डाला गया है जिन्हें लाभार्थियों द्वारा डाउनलोड और इस्तेमाल किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, व्यापक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है क्योंकि 2008-09 में 5-6 महीनों की अल्प अवधि में 217762 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से जिला कार्य दल समितियों द्वारा 92884 आवेदनों की जांच की गई है और उन्हें बैंकों को अग्रेषित कर दिया गया है। बैंकों ने 36287 मामलों में ऋण स्वीकृत कर दिया है जिनमें 506.03 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी शामिल है जिससे देश में 3.63 लाख रोजगार अवसरों के सृजन का अनुमान है। जिन लोगों को पीएमईजीपी के तहत ऋण स्वीकृत किए गए हैं, उनमें से 20294 उम्मीदवारों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए हैं। उत्पन्न गति को बनाए रखने के लिए, केवीआईसी ने 2009-10 के लिए पीएमईजीपी के तहत 6.17 लाख रोजगार अवसरों का अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें झारखंड में सृजित 19716 अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन की क्षमता के साथ 1972 परियोजनाओं का लक्ष्य है। पीएमईजीपी के तहत 2009-10 के लिए लक्ष्यों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण-I

2006-07 और 2007-08 के दौरान आरईजीपी और 2008-09 के दौरान पीएमईजीपी के तहत सृजित रोजगार के माध्यम से अनुमानित रूप से लाभान्वित व्यक्तियों की राज्य/संघ शासित प्रदेश वार संख्या

(व्यक्तियों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आरईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार		पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार*
		2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	50	199	310
2.	दिल्ली	267	215	50
3.	हरियाणा	28339	45185	8210
4.	हिमाचल प्रदेश	17102	26848	3400
5.	जम्मू और कश्मीर	23274	43865	18210
6.	पंजाब	35604	37412	8870

1	2	3	4	5
7.	राजस्थान	44168	94468	7030
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	323	273	80
9.	बिहार	12334	20057	67410
10.	झारखंड	7289	9064	9400
11.	उड़ीसा	16311	21857	19760
12.	पश्चिम बंगाल	42834	120126	56670
13.	अरुणाचल प्रदेश	2106	1783	1300
14.	असम	30912	48303	7280
15.	मणिपुर	1881	1105	30
16.	मेघालय	2174	3509	30
17.	मिजोरम	16455	17299	230
18.	नागालैंड	3358	6910	310
19.	त्रिपुरा	5851	14178	50
20.	सिक्किम	2208	2260	40
21.	आंध्र प्रदेश	59750	98449	9030
22.	कर्नाटक	42420	58855	24230
23.	केरल	30144	48668	3890
24.	लक्षद्वीप	0	36	40
25.	पुदुचेरी	854	2099	420
26.	तमिलनाडु	25216	54634	14730
27.	गोवा	1389	809	70
28.	गुजरात	13520	19271	3070
29.	दमन और दीव	—	—	60
30.	महाराष्ट्र	27182	32266	33680
31.	छत्तीसगढ़	17719	25933	10780
32.	मध्य प्रदेश	22332	42793	6280
33.	उत्तराखंड	10962	19270	3780
34.	उत्तर प्रदेश	51123	56652	44140
	कुल	595451	975651	362870

•अनंतिम आंकड़े

विवरण-II

वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग में प्रदान किया गया अनुमानित रोजगार (समेकित) का राज्यवार संघ राज्य क्षेत्रवार समग्र ब्यौरा

(लाख व्यक्ति)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2006-07		2007-08		2008-09	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	#	0.15	#	0.18	#	0.19

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	दिल्ली	0.04	0.27	0.04	0.27	0.04	0.28
3.	हरियाणा	0.38	2.07	0.39	2.53	0.41	2.63
4.	हिमाचल प्रदेश	0.08	1.55	0.08	1.81	0.08	1.88
5.	जम्मू और कश्मीर	0.24	1.65	0.25	2.10	0.26	2.19
6.	पंजाब	0.41	2.45	0.42	2.83	0.44	2.95
7.	राजस्थान	0.62	6.42	0.65	7.40	0.68	7.70
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.21
9.	बिहार	1.02	1.96	1.02	2.06	1.06	2.14
10.	झारखंड	0.03	0.32	0.03	0.41	0.03	0.43
11.	उड़ीसा	0.03	2.58	0.03	2.82	0.03	2.94
12.	पश्चिम बंगाल	0.69	5.75	0.72	6.93	0.75	7.21
13.	अरुणाचल प्रदेश	#	0.07	#	0.09	#	0.09
14.	असम	0.12	2.36	0.14	2.84	0.15	2.96
15.	मणिपुर	0.01	0.65	0.01	0.64	001	0.67
16.	मेघालय	#	0.35	#	0.39	#	0.41
17.	मिजोरम	#	0.64	#	0.81	0.00	0.84
18.	नागालैंड	0.01	0.43	0.01	0.51	0.01	0.53
19.	सिक्किम	#	0.19	#	0.22	#	0.23
20.	त्रिपुरा	#	0.45	#	0.59	#	0.61
21.	आंध्र प्रदेश	0.26	5.92	0.27	6.91	0.28	7.19
22.	कर्नाटक	0.29	3.33	0.31	3.94	0.32	4.10
23.	केरल	0.12	3.51	0.13	4.00	0.14	4.16

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	लक्षद्वीप	0.00	0.01	0.00	#	0.00	0.00
25.	पुदुचेरी	#	0.08	#	0.09	#	0.09
26.	तमिलनाडु	0.40	12.81	0.43	13.42	0.45	13.97
27.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
28.	गोवा	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.17
29.	गुजरात	0.28	1.24	0.29	1.48	0.30	1.54
30.	महाराष्ट्र	0.02	6.45	0.03	6.92	0.03	7.20
31.	छत्तीसगढ़	0.03	0.80	0.04	1.07	0.04	1.11
32.	मध्य प्रदेश	0.05	3.04	0.05	3.48	0.05	3.62
33.	उत्तराखंड	0.28	0.58	0.30	0.77	0.31	0.80
34.	उत्तर प्रदेश	3.43	11.63	3.52	12.23	3.66	12.73
	कुल	8.84	80.08	9.16	90.11	9.53	93.78

#500 से कम

विवरण-III

2009-10 के लिए पीएमईजीपी के तहत आबंटित राज्य वार लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	परियोजनाओं की संख्या	मार्जिन मनी (लाख रुपये)	रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3	4	5
1.	संघ शसित प्रदेश चंडीगढ़	50	59.94	500
2.	दिल्ली	750	899.10	7497
3.	हरियाणा	1193	1431.16	11927
4.	हिमाचल प्रदेश	377	452.14	3763
5.	जम्मू और कश्मीर	623	748.14	6238
6.	पंजाब	1340	1608.02	13398
7.	राजस्थान	3343	4011.54	33428
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17	19.98	167
9.	बिहार	5367	6440.22	53665
10.	झारखंड	1972	2366.52	19716
11.	उड़ीसा	2455	2946.68	24554

1	2	3	4	5
12.	पश्चिम बंगाल	4595	5513.74	45947
13.	आंध्र प्रदेश	4433	5319.86	44337
14.	कर्नाटक	2976	3571.24	29764
15.	केरल	1770	2123.80	17695
16.	लक्षद्वीप	5	6.66	52
17.	पुदुचेरी	50	59.94	500
18.	तमिलनाडु	3517	4220.23	35165
19.	गोवा	72	86.59	719
20.	गुजरात	2885	3460.98	28845
21.	दादरा और नगर हवेली	11	13.32	114
22.	दमन और दीव	11	13.32	114
23.	महाराष्ट्र	5526	6628.91	55242
24.	छत्तीसगढ़	1447	1736.78	14473
25.	मध्य प्रदेश	3850	4619.82	38501
26.	उत्तरांचल	534	641.59	5343
27.	उत्तर प्रदेश	9807	11768.96	98072
28.	अरुणाचल प्रदेश	86	102.86	861
29.	असम	1709	2050.54	17083
30.	मणिपुर	195	235.32	1958
31.	मेघालय	202	241.98	2021
32.	मिजोरम	100	119.14	993
33.	नागालैंड	179	215.34	1792
34.	त्रिपुरा	197	236.06	1965
35.	सिक्किम	53	62.90	528
	कुल	61697	74033.32	616937

[अनुवाद]

राजमार्ग परियोजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन

2204. श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने देश में राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा लालफीताशाही समाप्त करने, निजी बोलियों को सीमित करने और राजमार्ग परियोजनाओं की स्वीकृति में विलंब को कम करने हेतु अर्थोपाय और अन्य उपाय सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त सुझावों पर विचार करने का है; और

(घ) यदि हां। तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान समीक्षा के आधार पर इस संबंध में अभिनिर्धारित किए गए मामलों में से कुछ मामले हैं: सुपुर्दगी की विधि, अर्हता पूर्व प्रक्रिया, भूमिअधिग्रहण जल्दी से पूरा करना और वैश्विक मंदी के प्रभाव, आदि। सरकार का यह प्रयास है कि विभिन्न परियोजनाओं का कार्य निष्पादन शीघ्रता से करने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों से उचित परामर्श के पश्चात् इन विभिन्न मुद्दों को निपटाया जाए।

उत्तरी बंगाल के विकास हेतु विशेष पैकेज

2205. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तरी बंगाल के विकास हेतु एक विशेष पैकेज निर्धारित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

ग्रामीण गोदाम

2206. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सहित देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय क्षेत्र ग्रामीण गोदाम योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए गोदामों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2009-10 के दौरान कर्नाटक सहित देश में राज्यवार ऐसे कितने गोदाम स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) ये गोदाम फसलों की कटाई के पश्चात् होने वाली हानियों को रोकने में किस हद तक सहायक हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से 1 अप्रैल, 2001 से "ग्रामीण भण्डारण योजना-(ग्रामीण गोदाम का निर्माण)" की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के तहत, देश भर में 240.75 लाख एमटी क्षमता वाले 20691 ग्रामीण गोदामों की स्वीकृति की गई है और 31 मई, 2009 तक 553.75 करोड़ रुपये की राजसहायता जारी की गई है। स्कीम की भौतिक और वित्तीय प्रगति संलग्न विवरण क्रमशः I और II में दी गई है।

कर्नाटक राज्य में 31 मई, 2009 तक 44.24 करोड़ रुपये की राजसहायता से 15.00 लाख एमटी क्षमता वाले 2051 ग्रामीण गोदामों की स्वीकृति की गई है।

(ख) वर्ष 2009-10 के दौरान ग्रामीण गोदाम स्कीम के तहत देश में 20.00 लाख एमटी भण्डारण क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है। "ग्रामीण भण्डारण योजना" की केन्द्रीय क्षेत्र से जुड़ी स्कीम एक मांग आधारित ऋण से जुड़ी स्कीम है। स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीम के तहत उद्यमी परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता को देखते हुए अपनी पसन्द के अनुसार देश में कहीं भी परियोजना स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) ग्रामीण गोदाम स्कीम के मुख्य उद्देश्यों में कृषि उत्पाद, प्रसंस्कृत कृषि उत्पादन, कृषि आदानों आदि के भण्डारण के लिए किसानों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बद्ध सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता का सृजन और बन्धक ऋण और विपणन ऋण की सुविधा का सृजन करके मजबूरी में की जाने वाली बिक्री को रोकना शामिल है। स्कीम की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, स्कीम सामान्य तौर पर सफल हुई है और अपने अधिकतर उद्देश्यों की पूर्ति में सक्षम हुई है। गोदाम मालिक प्रमुख रूप से किसान हैं और फसलोपरान्त हानियों में कमी, उच्चतर मूल्य प्राप्ति के माध्यम से आय में वृद्धि और बचत और निवेश क्षमता दोनों के योग्य होकर इस स्कीम से लाभान्वित हुए हैं।

विवरण-I

ग्रामीण गोदाम स्कीम की प्रगति दर्शाने वाला विवरण (31.5.2009 की स्थिति)-संचयी (भौतिक)

		नाबार्ड द्वारा स्वीकृत		एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत (नई)		एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत (नवीकरण)		कुल	
1	2	3		4		5		6 (3 से 5)	
क्रम सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता टन में	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता टन में	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता टन में	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता टन में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	781	3081632	16	1600	8	800	805	3084032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	945	0	0	0	0	1	945
3.	असम	171	282044	1	650	0	0	172	282694
4.	बिहार	43	81862	738	74950	120	12100	901	168912
5.	छत्तीसगढ़	231	654531	77	258350	0	0	308	912881
6.	गोवा	3	290	0	0	0	0	3	290
7.	गुजरात	4723	1347993	43	122743	19	19600	4785	1490336
8.	हरियाणा	302	1726883	312	35000	243	244817	857	2006700
9.	हिमाचल प्रदेश	5	1772	32	3700	0	0	37	5472
10.	जम्मू और कश्मीर	1	100	0	0	0	0	1	100
11.	झारखण्ड	4	5848	0	0	0	0	4	5848
12.	कर्नाटक	1942	1416149	107	83665	2	240	2051	1500054
13.	केरल	36	33584	80	21085	21	3730	137	58399
14.	मध्य प्रदेश	1580	3462906	102	93000	120	72616	1802	3628522
15.	महाराष्ट्र	1994	2416063	33	178500	17	61300	2044	2655863
16.	मेघालय	4	8985	34	3450	0	0	38	12435
17.	नागालैंड	1	250	0	0	0	0	1	250
18.	उड़ीसा	259	489993	0	0	4	12000	263	501993
19.	पंजाब	1216	2718048	0	0	208	385600	1424	3103648
20.	राजस्थान	573	452169	156	68150	1	1000	730	521319
21.	तमिलनाडु	120	409473	169	43488	278	37285	567	490246
22.	उत्तर प्रदेश	212	1202313	27	126900	693	955468	932	2284681
23.	उत्तराखण्ड	88	174125	27	19250	4	18600	119	211975
24.	पश्चिम बंगाल	2611	1093614	91	9100	0	0	2702	1102714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	संघ शासित क्षेत्र	0	0	01	4000	0	0	1	4000
26.	नेफेड	0	0	05	30800	0	0	5	30800
27.	एनसीसीएफ	0	0	01	10000	0	0	1	10000
	कुल	16901	21061572	2052	1188381	1738	1825156	20691	24075109

विवरण-II

नाबार्ड और एनसीडीसी (निर्माण + नवीकरण) द्वारा स्वीकृत और निर्मुक्त राजसहायता (31.5.2009 की स्थिति)--संचयी (वित्तीय)

लाख रुपए

राज्य	नाबार्ड		एनसीडीसी (निर्माण)		एनसीडीसी (नवीकरण)		कुल	
	पात्र राजसहायता	निर्मुक्त राजसहायता	पात्र राजसहायता	निर्मुक्त राजसहायता	पात्र राजसहायता	निर्मुक्त राजसहायता	पात्र राजसहायता	निर्मुक्त राजसहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	11649.6070	9592.6020	8.00	0	0.87	0	11658.477	9592.602
अरुणाचल प्रदेश	6.3000	6.3000	0	0	0	0	6.3	6.3
असम	1563.5670	1080.0590	3.33	3.33	0	0	1566.897	1083.389
बिहार	304.8200	268.8000	368.98	250.98	51.49	0.50	725.29	520.28
छत्तीसगढ़	2123.9600	1925.5170	513.87	509.293	0	0	2637.83	2434.81
गोवा	1.8555	0.8970	0	0	0	0	1.8555	0.897
गुजरात	5867.6040	3632.5096	354.999	247.877	9.236	9.236	6231.839	3889.6226
हरियाणा	3652.7780	2875.9803	257.81	127.115	65.06	44.43	3975.648	3047.4753
हिमाचल प्रदेश	8.6573	5.3429	33.326	33.320	0	0	41.9833	38.6629
जम्मू और कश्मीर	0.5000	0.2500	0	0	0	0	0.5	0.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखण्ड	13.9950	4.2870	0	0	0	0	13.995	4.287
कर्नाटक	5517.7440	4346.1768	351.108	77.5633	0.30	0.30	5869.152	4424.0401
केरल	127.4805	105.7565	137.363	45.705	4.26	0	269.1035	151.4615
मध्य प्रदेश	11771.8000	9805.7532	273.74	273.740	41.61	41.6050	12087.15	10121.0982
महाराष्ट्र	8277.0000	6477.1620	295.22	260.220	42.40	34.7985	8614.62	6772.1805
मेघालय	47.3330	29.3783	6.334	6.3335	0	0	53.667	35.7118
नागालैंड	5.0000	0.8333	0	0	0	0	5	0.8333
उड़ीसा	1556.9650	1242.3304	0	0	5.0	0	1561.965	1242.3304
पंजाब	4009.7080	4256.6835	0	0	66.60	66.5980	4076.308	4323.2815
राजस्थान	1406.5650	939.7440	199.866	194.241	1.50	1.50	1607.931	1135.485
तमिलनाडु	1421.5350	1053.0801	146.61	134.8472	45.93	15.3350	1614.075	1203.2623
उत्तर प्रदेश	2629.8720	2367.3492	330.528	268.00	126.6285	126.6285	3087.0285	2761.9777
उत्तराखण्ड	578.0080	452.3020	66.25	63.750	8.85	8.85	653.108	524.902
पश्चिम बंगाल	4349.4770	1912.6018	29.06	25.560	0	0	4378.537	1938.1618
संघ शासित क्षेत्र	0	0	15.00	7.50	0	0	15	7.5
नेफेड	0	0	114.375	76.875	0	0	114.375	76.875
एनसीसीएफ	0	0	37.50	37.50	0	0	37.5	37.5
कुल	66892.1313	52381.6459	3543.269	2643.75	469.7345	349.781	70905.135	55375.1769

नई औद्योगिक इकाइयां

2207. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन दिया गया है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान नई औद्योगिक इकाइयां खोलने हेतु

क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस प्रयोजनार्थ क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 01.04.1995 से 31.03.2008 तक ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत पात्र उद्यमियों को सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारिता बैंकों, आदि से ऋण प्राप्त कर तथा केवीआईसी से अधिकतम 25 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी सहायता (सब्सिडी) प्राप्त करके नई ग्रामोद्योग इकाइयां स्थापित करने में सहायता दी गई थी।

आरईजीपी को वर्ष 2008-09 से बंद कर दिया गया है और इस मंत्रालय की तत्कालीन मौजूदा योजनाओं, आरईजीपी तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) को एकीकृत करके अगस्त, 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) शीर्षक वाली एक नई योजना अनुमोदित की गई थी। यह पीएमआरवाई तथा आरईजीपी की अपेक्षा एक उच्चतर स्तर की सब्सिडी वाली महत्वपूर्ण पहल है। पीएमईजीपी के तहत प्रदत्त स्वीकार्य मार्जिन मनी सहायता निम्न प्रकार है:-

पीएमईजीपी के तहत लाभग्राहियों की श्रेणियां	लाभग्राही का अंशदान (परियोजना लागत का)	सब्सिडी की दर (परियोजना लागत की)	
क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान)		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष श्रेणी (अ.जा./अनु.ज.जा./ अन्य पिछड़ वर्ग/अल्पसंख्यकों/ महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय तथा सीमा क्षेत्रों, आदि सहित)	05%	25%	35%

पीएमईजीपी को केवीआईसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर, यह योजना केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों तथा जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) के माध्यम से बैंकों की सहभागिता से कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान आरईजीपी के तहत तथा वर्ष 2008-09 (अस्थाई आंकड़े) के दौरान पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त ग्रामोद्योग इकाइयों/सूक्ष्म उद्यमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत सृजित अतिरिक्त रोजगार से अनुमानत: लगभग 5,95,451 व्यक्ति लाभान्वित हुए थे तथा 2007-08 के दौरान 9,75,651 व्यक्ति और वर्ष 2008-09 के दौरान (अस्थाई आंकड़े) पीएमईजीपी के तहत अनुमानत: 3,62,870 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

(घ) वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारित अनन्तिम लक्ष्यों के अनुसार 740.33 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी का उपयोग करके लगभग 61,697 सूक्ष्म उद्यमों को सहायता मिलने की संभावना है।

विवरण

2006-07 और 2007-08, के दौरान आरईजीपी और 2008-09 के दौरान पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त ग्रामोद्योगों/सूक्ष्म उद्यमों की राज्य/संघ शासित प्रदेश वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आरईजीपी के तहत ग्रामोद्योग इकाइयों की संख्या		पीएमईजीपी के तहत सूक्ष्म उद्यमों की संख्या*
		2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	2	9	31
2.	दिल्ली	13	12	5
3.	हरियाणा	869	1346	821
4.	हिमाचल प्रदेश	803	1167	340

1	2	3	4	5
5.	जम्मू और कश्मीर	1716	2999	1821
6.	पंजाब	1022	1625	887
7.	राजस्थान	1340	3157	703
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	127	97	8
9.	बिहार	849	927	6741
10.	झारखंड	221	239	940
11.	उड़ीसा	857	1105	1976
12.	पश्चिम बंगाल	2290	7334	5667
13.	अरुणाचल प्रदेश	88	186	130
14.	असम	1599	2560	728
15.	मणिपुर	139	77	3
16.	मेघालय	165	409	3
17.	मिजोरम	990	1290	23
18.	नागालैंड	156	462	31
19.	त्रिपुरा	212	608	5
20.	सिक्किम	89	143	4
21.	आंध्र प्रदेश	2113	3105	903
22.	कर्नाटक	1689	2228	2423
23.	केरल	912	1398	389
24.	लक्षद्वीप	0	6	4
25.	पुदुचेरी	164	380	42
26.	तमिलनाडु	1075	2110	1473
27.	गोवा	104	128	7
28.	गुजरात	412	536	307
29.	महाराष्ट्र	2296	2502	3374
30.	छत्तीसगढ़	691	1282	1078
31.	मध्य प्रदेश	934	1333	628
32.	उत्तराखंड	641	901	378
33.	उत्तर प्रदेश	1509	2624	4414
	कुल	26087	44285	36287

*अनंतिम आंकड़े।

नक्सली और आतंकी गुट

2208. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में सर्वाधिक संख्या में आतंकी और नक्सली गुटों की शरणस्थली है;

(ख) यदि हां, तो देश के भीतर और बाहर उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्त आतंकी और नक्सली गुटों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे गुटों की गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं। इस आशय की कोई सूचना नहीं है जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत विश्व में सर्वाधिक संख्या में आतंकी और नक्सली गुटों की शरणस्थली है।

(ख) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 में अन्य बातों के साथ-साथ इस अधिनियम की अनुसूची में किसी संगठन को जोड़े जाने का प्रावधान है। उपलब्ध सूचना के अनुसार जो आतंकवादी संगठन भारत में आतंकी क्रियाकलापों में संलिप्त हैं उनमें से कुछ का उल्लेख अनुसूची में किया गया है।

(ग) सरकार, उभरती चुनौतियों के संदर्भ में सुरक्षा व्यवस्थाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा करती रही है जिनमें आतंकवादी और नक्सलवादी क्रियाकलाप शामिल हैं और इस संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उपाय किए गए हैं। इन उपायों में केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की संख्या में वृद्धि करना; सी.आई.एस.एफ. अधिनियम में संशोधन करना ताकि संयुक्त उद्यम या प्राइवेट औद्योगिक उपक्रमों में सी.आई.एस.एफ. की तैमाती की जा सके; चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एन.एस.जी. हब स्थापित करना; डीजी एन.एस.जी. की नियुक्ति करना ताकि यह किसी आपात स्थिति में एन.एस.जी. कार्मिकों को लाने ले जाने के लिए हवाई जहाज की मांग कर सके; बहु-एजेंसी केन्द्र को सुदृढ़ बनाना और पुनर्गठित करना ताकि वह 24x 7 के आधार पर वास्तविक समय का मिलान कर सके और अन्य आसूचना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ सूचना का आदान-प्रदान कर सके और आनलाइन का विकास करना तथा बहु-एजेंसी केन्द्र, सहायक बहु-एजेंसी केन्द्रों और राज्य विशेष शाखाओं के बीच संपर्क स्थापित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार, सुरक्षा और विकास के लिए सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सी.पी.एम.एफ. कोबरा बटालियनों की तैनाती करना, हथियारों के आधुनिकीकरण और अन्य सामाजिक-आर्थिक तथा विकासात्मक कार्यों के लिए निधियों का प्रावधान शामिल है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दंडात्मक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन कर दिया गया है और इसे 2008 में अधिसूचित किया गया है। अनुसूची में अधिनियम के तहत अपराधों की जांच-पड़ताल करने और अभियोजन चलाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन कर दिया गया है।

लघु उद्योगों हेतु योजनाएं

2209. **श्री एंटो एंटोनी : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसई) शुरू करने हेतु अनिवासी भारतीयों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को संवितरित किए जा रहे बैंक ऋण की प्रतिशतता पर पुनर्विचार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा वैश्विक मंदी की वजह से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का संवर्धन एवं विकास मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों का कार्य है। केन्द्र सरकार, एमएसई के विकास एवं संवर्धन को बढ़ाने तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि लाने के लिए सहयोगी उपाय प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग करती है। मंत्रालय की देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम शुरू करने के लिए अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई)) हेतु कोई विशिष्ट/विशेष योजना नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ने वर्ष 2005 में लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण में वृद्धि करने हेतु एक पालिसी पैकेज की घोषणा की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: (i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसएमई क्षेत्र को ऋण में कम से कम 20% वर्ष दर वर्ष वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से एसएमई को निधियां प्रदान करने के लिए स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करेंगे, (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उद्यमों की ऋण दर से संबंद्ध ऋण की लागत से एक पारदर्शी दर पद्धति का पालन करेंगे, (iii) वाणिज्यिक बैंक अपने प्रत्येक अर्ध-शहरी/शहरी शाखाओं में प्रत्येक वर्ष औसतन 5 नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण कवर प्रदान करने हेतु ठोस प्रयास करेंगे तथा (iv) बैंकों द्वारा एसएमई वित्त पोषण के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

(ङ) वैश्विक मंदी के कारण एमएसएमई द्वारा जिन चुनौतियों का सामना किया जा रहा उन्हें पूरा करने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं- (i) क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत ऋण सीमा को 50 प्रतिशत के गारंटी कवर के साथ 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करना, (ii) क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 5 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा हेतु गारंटी कवर को 80% से बढ़ाकर 85% करना, (iii) एमएसएमई के बिलों के शीघ्र भुगतान

को सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक परामर्शी, (iv) एसएमई क्षेत्र को प्री एवं पोस्ट शिपमेंट निर्यात ऋण में 2% की ब्याज छूट, (v) एमएसई क्षेत्र को इन्क्रीमेंटल आन लेंडिंग हेतु सिडबी को 7,000 करोड़ रुपये की पुन: वित्त सीमा, (vi) मौजूदा निधि आधारित सीमाओं के 20% तक के आवश्यकता आधारित तदर्थ कार्यशील पूंजीगत मांग ऋण प्रदान करना, तथा (vii) सूक्ष्म, उद्यमों द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए 1% तक ब्याज दरों में कटौती और एसएमई के लिए 0.5% तक की कटौती।

पूर्वोत्तर परिषद को निधियां

2210. **श्री संजय तकाम : क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी.) हेतु कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं;

(ख) क्या पूर्वोत्तर परिषद सिर्फ अंतर्राज्यीय सड़क परियोजनाओं पर विचार करता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूर्वोत्तर परिषद का विचार अरुणाचल प्रदेश में सड़कों के अंत:जिला कनैक्टिविटी शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी.) हेतु 7394 करोड़ रुपए का आबंटन स्वीकृत किया है।

(ख) और (ग) 2002 में यथा संशोधित पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के खण्ड 4(क) (2) में यह प्रावधान है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजनाएं बनाने के दौरान परिषद उन योजनाओं और परियोजनाओं को, सिक्किम के अतिरिक्त जहां परिषद राज्य विशेष की परियोजनाओं का सृजन कर सकती है, प्राथमिकता देगी जिससे दो या अधिक राज्यों को लाभ मिलेगा। माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में अक्टूबर, 2006 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पूर्वोत्तर परिषद को व्यापक प्रभाव के साथ केवल अंतर्राज्यीय परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। इस दृष्टि से, सड़क परियोजनाओं सहित केवल अंतर्राज्यीय प्रभाव वाली परियोजनाओं पर पूर्वोत्तर परिषद द्वारा विचार किया जाता है।

(घ) और (ङ) उत्तर-पूर्वी राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, पूर्वोत्तर परिषद द्वारा चिह्नित की गई 56 सड़कें, जिसमें अंतर्राज्यीय/ अंतरजिला संपर्क के साथ अरुणाचल प्रदेश की 8 सड़कें सम्मिलित हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जानी प्रस्तावित हैं। योजना आयोग 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 16 सड़कों, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के दो अंतर्राज्यीय सड़क परियोजनाएं सम्मिलित हैं, के कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति स्वीकृति दी है। अरुणाचल प्रदेश की सड़कें जिन्हें मंजूर किया गया है- वे लोंगदिंग-नोकजांग सड़क वाया चातिंग गांव तथा तमिंग-दोलुंगमुख सड़क हैं।

[हिन्दी]

अंगूर उत्पादकों को राहत

2211. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में बेमौसम वर्षा होने और ओलावृष्टि की वजह से अंगूर उत्पादकों को भारी हानि उठानी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अंगूर उत्पादकों को राहत प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क)और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) ओलावृष्टि सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सहायता के प्रावधान के लिए दो स्कीमें नामत: आपदा राहत कोष (सीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) हैं। सीआरएफ/एनसीसीएफ से सहायता के लिए व्यय के वर्तमान मानदण्डों के आधार पर 50% और अधिक की फसल हानि के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 2000 रुपए प्रति

हैक्टेयर की दर पर, निश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में 4000 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर पर और सभी तरह की बारहमासी फसलों के लिए 6000 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर पर आदान राजसहायता स्वीकार्य है। 50% और उससे अधिक के फसल क्षति हेतु पहली बार की प्राकृतिक आपदा की दशा में 1 हैक्टेयर प्रति किसान और उत्तरोत्तर प्राकृतिक आपदाओं हेतु 2 हैक्टेयर प्रति किसान के हिसाब से उपरोक्त दरों पर जोत के आकार पर ध्यान दिये बिना, अन्य किसानों (छोटे और मध्यम किसानों के अलावा) के लिए भी आदान राजसहायता स्वीकार्य है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय

2212. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए धनराशि मंजूर की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र हेतु विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु को कितना आबंटन किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) उच्च कृषि शिक्षा राज्य का विषय है। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और उन्नयन से संबंधित विषय राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। तदनुसार, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय का उन्नयन तमिलनाडु राज्य सरकार से संबंधित है। फिर भी संघ सरकार ने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के विकास के लिए 2007-08 के दौरान 50 करोड़ रुपये के एक विशेष अनुदान की घोषणा की थी।

(ग) और (घ) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के लिए (2007-10) अवधि के दौरान 49.99 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान जारी किया गया है जो निम्नानुसार है:-

(लाख रुपये)

क्र. सं.	शीर्षक	स्वीकृति 2007-10	जारी		
			2007-08	2008-09	2009-10
1.	मानव संसाधन विकास	270	135	96	39
2.	आकस्मिक	1459	575	742	142
3.	उपकरण	2199	1310	669	220
4.	निर्माण	680	295	322	63
5.	भूमि	23	0	23	0
6.	फिक्चर एण्ड फर्नीचर	368	185	148	35
	कुल	4999	2500	2000	499

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के लिए विशेष अनुदान दिए जाने के साथ ही विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के तहत 2006-07 के लिए 48.29 करोड़ रु., 2007-08 के लिए 67.31 करोड़ रु. 2008-09 के लिए 68.23 करोड़ रु. और 2009-10 के लिए 48.13 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए तमिलनाडु को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत 2006-07 के लिए 182.88 करोड़ रु. 2007-08 के लिए 640.66 करोड़ रु. 2008-09 के लिए 419.75 करोड़ रु. और 2009-10 के लिए 177.04 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

भारती खाद्य निगम में भ्रष्टाचार

2213. श्री यशवंत लागुरी:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार संबंधी मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम में उजागर हुई भ्रष्टचार/असक्षमता संबंधी घटनाओं की संख्या क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम सौंपे गए दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है;

(च) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम के कुशलता स्तर से संतुष्ट है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ.) जी, हां। संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों और उन अधिकारियों पर उचित निगरानी रखी जा रही है, जिन्हें सहमत सूची में डाला गया है। वर्ष 2009 में पचास अधिकारियों को निलंबित किया गया है। 2006 से की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(च) और (छ) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों और अन्य खाद्य वस्तुओं की खरीदारी, भंडारण, संचलन, परिवहन, वितरण और बिक्री करने के उद्देश्य से खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अधीन की गई थी। भारतीय खाद्य निगम लाभ न कमाने वाला संगठन है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर रहा है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार/अक्षमता की घटनाओं की संख्या

अनियमितता का स्वरूप	2006	2007	2008	2009 (जून तक)
अवैध परितोषण स्वीकार करना/गैर-अनुपातिक परिसंपत्तियां	11	10	6	8
लेखों का गबन/दुर्विनियोजन	79	70	62	49
डैड स्टॉक का दुर्विनियोजन/ गोदामों का निर्माण	6	11	20	8
घटिया स्टॉक की खरीद	569	288	121	148
हैंडलिंग और ढुलाई के ठेके देना	3	11	6	8
मार्गस्थ/भंडारण हानियां	1195	850	369	335
प्रशासनिक चूक/विविध	141	142	213	174
जोड़	2004	1382	797	730

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान जून, 2009 तक दोषियों को दिए गए दण्ड

दिए गए दण्ड का स्वरूप	2006	2007	2008	2009 (जून तक)
1	2	3	4	5
बर्खास्तगी/हटाया जाना/ अनिवार्य सेवानिवृत्ति	79	50	18	9
रैंक में कमी	30	46	14	7

1	2	3	4	5
समय-वेतमान में कमी	318	274	281	87
वेतनवृद्धि रोकना	216	195	107	43
भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि को वेतन से वसूलना	1731	1821	1496	463
प्रोन्नति रोकना	2	66	7	1
सेंस्योर	382	358	476	159
जारी की गई चेतावनी/ आरोपमुक्त करना/बंद किए गए मामले	323	400	376	132

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जून, 2009 तक निलम्बित रखे गए अधिकारियों की श्रेणीवार सूची

वर्ष	श्रेणी-1	श्रेणी-2	श्रेणी-3	श्रेणी-4	जोड़
1	2	3	4	5	6
2006	1	31	73	6	111
2007	3	10	35	5	53
2008	2	6	20	5	33
2009 (जून तक)	3	19	25	3	50

[अनुवाद]

खादी एवं ग्रामोद्योग की प्रगति

2214. प्रो. रंजन प्रसाद यादव : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योगों की प्रगति बिहार सहित विभिन्न राज्यों में असंतोषजनक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यवार इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) बिहार सहित विभिन्न राज्यों में पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान रोजगार और केवीआई क्षेत्र के उत्पादन एवं बिक्री के रूप में खादी एवं ग्रामोद्योग (केवीआई) का संपूर्ण प्रदर्शन निम्नवत् है:-

वर्ष	उत्पादन (मूल्य करोड़ रुपये में)		बिक्री (मूल्य करोड़ रुपये में)		अनुमानित संचयी रोजगार (लाख व्यक्तियों में)	
	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2006-07	491.52	13537.19	663.19	16899.21	8.84	80.08
2007-08	543.39	16134.32	724.39	20819.09	9.16	90.11
2008-09	565.12	16779.69	854.78	21668.48	9.53	93.78

*अनन्तिम

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि केवीआई उत्पादों का अनुमानित उत्पादन एवं बिक्री और केवीआई क्षेत्र में सृतित रोजगार बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति दर्शा रहे हैं। बिहार में केवीआई क्षेत्र में अनुमानित उत्पादन तथा सृजित संचयी रोजगार भी पिछले तीन वर्षों के दौरान संपूर्ण भारत के रुख के समान वृद्धि संरचना को दर्शा रहे हैं। केवीआई उत्पादन बिहार में 11.25% के राष्ट्रीय आंकड़ें की अपेक्षा 13% वार्षिक तक उच्च रूप में बढ़ा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार सहित उत्पादन, बिक्री तथा रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दर्शाया गया है।

(ग) खादी एवं ग्रामोद्योग बढ़ाने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से अनेक कार्यक्रम/योजनायें कार्यान्वित कर रही है, अर्थात् सस्ती ब्याज दरों पर खादी एवं पोली वस्त्र इकाइयों को बैंक ऋण प्रदान करने हेतु ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र (आईएसईसी) योजना, ग्रामोद्योगों को अवसंरचना सहयोग तथा सेवायें प्रदान करने हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना हेतु ग्रामोद्योग सेवा केन्द्र (आरआईएससी), खादी ग्रामोद्योग तथा कॅयर क्षेत्रों में क्लस्टरों के विकास हेतु स्फूर्ति योजना, खादी वस्त्रों के संशोधित डिजाईन तथा पैकेजिंग हेतु उत्पाद विकास, डिजाईन इंटरवेंशन तथा पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य सहयोग सेवायें अर्थात् विपणन, निर्यात संवर्धन, जिला, राज्य, अंचलीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियां, डिजाईन सुविधा, ब्रांड निर्माण, आदि।

इसके अलावा, वर्ष 2008-09 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया है जो मौजूदा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा इस मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार योजना को विलय कर उच्चतर स्तर की सब्सिडी सहित ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म, एवं लघु उद्यमों की स्थापना हेतु एक महत्त्वपूर्ण पहल है ताकि बैंकवर्ड और फारवर्ड संपर्कों के लिए 250 करोड़ रुपये सहित 4735 करोड़ रुपये के कुल योजनागत परिव्यय से 2008-09 से 2011-12 तक के दौरान (लगभग 38 लाख तक) अतिरिक्त रोजगार अवसरों को सृजित किया जा सके। खादी क्षेत्र में दो नई योजनायें शुरू की गई हैं, अर्थात् बेहतर कार्य वातावरण के लिए वर्कशेडों के निर्माणार्थ सहायता प्रदान करने हेतु "खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना" तथा अप्रचलित एवं प्राचीन मशीनरी तथा उपस्कर को बदल कर अधिक बाजार उन्मुखी एवं लाभप्रद उत्पादन करके खादी उद्योग को अधिक प्रतियोगी बनाने हेतु 200 खादी संस्थानों को सहायता देने के लिए "खादी उद्योगों तथा कारीगरों की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु योजना"।

विवरण-I

2006-07 के दौरान उत्पादन, बिक्री और रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उत्पादन (मूल्य लाख रुपये में)		बिक्री (मूल्य लाख रुपये में)		कुल रोजगार (लाख व्यक्ति)	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	0.35	1757.42	61.55	2966.49	#	0.15
2.	दिल्ली	179.54	5588.29	1700.84	5946.26	0.04	0.27
3.	हरियाणा	3687.01	48023.45	3692.56	61760.24	0.38	2.07
4.	हिमाचल प्रदेश	356.50	35648.79	974.43	43816.15	0.08	1.55
5.	जम्मू और कश्मीर	719.54	30131.99	898.43	37104.28	0.24	1.65
6.	पंजाब	1009.25	58854.81	1177.06	63204.11	0.41	2.45

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	राजस्थान	2887.99	123005.95	3727.09	157534.11	0.62	6.42
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1676.10	0.00	2321.29	0.00	0.20
9.	बिहार	764.26	26243.42	1244.85	32043.12	1.02	1.96
10.	झारखंड	311.78	6607.97	887.57	9171.82	0.03	0.32
11.	उड़ीसा	251.99	28218.43	260.01	32300.52	0.03	2.58
12.	पश्चिम बंगाल	4855.40	58551.80	2415.40	76636.51	0.69	5.75
13.	अरुणाचल प्रदेश	6.76	1918.45	14.05	2900.29	#	0.07
14.	असम	490.86	29838.13	424.12	46913.27	0.12	2.36
15.	मणिपुर	62.50	7273.69	62.03	7495.21	0.01	0.65
16.	मेघालय	4.21	6419.31	5.58	8997.72	#	0.35
17.	मिजोरम	59.82	14179.79	3.35	20216.68	#	0.64
18.	नागालैंड	74.85	7672.83	74.48	10002.76	0.01	0.43
19.	सिक्किम	6.28	2330.58	8.70	4810.35	#	0.19
20.	त्रिपुरा	8.46	5461.55	48.55	6766.64	#	0.45
21.	आंध्र प्रदेश	1539.84	92568.42	935.73	109815.80	0.26	5.92
22.	कर्नाटक	3445.66	104353.79	3596.62	121738.85	0.29	3.33
23.	केरल	1512.22	66927.29	3443.35	73756.94	0.12	3.51
24.	लक्षद्वीप	0.00	155.13	0.00	169.58	0.00	0.01
25.	पुदुचेरी	6.56	789.16	1141.56	1630.22	#	0.08
26.	तमिलनाडु	6245.36	91367.21	7470.80	115309.82	0.40	12.81
27.	दादरा और नगर हवेली	0.00	92.26	0.00	87.61	0.00	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	गोवा	0.00	3850.12	0.00	6111.99	0.00	0.16
29.	गुजरात	2908.33	56566.12	4247.01	80201.48	0.28	1.24
30.	महाराष्ट्र	292.18	155974.72	1283.74	178597.44	0.02	6.45
31.	छत्तीसगढ़	697.50	25837.69	678.66	33421.27	0.03	0.80
32.	मध्य प्रदेश	561.37	73968.41	1643.46	100766.50	0.05	3.04
33.	उत्तराखंड	1051.67	15258.89	1887.83	16465.45	0.28	0.58
34.	उत्तर प्रदेश	15153.60	166607.51	22309.43	218940.32	3.43	11.63
	कुल	49151.64	1353719.47	66318.84	1689920.69	8.84	80.08

#500 से कम

विवरण-II

2007-08 के दौरान उत्पादन, बिक्री और रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उत्पादन (मूल्य लाख रुपये में)		बिक्री (मूल्य लाख रुपये में)		कुल रोजगार (लाख व्यक्ति)	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	0.39	1781.83	58.55	3050.05	#	0.18
2.	दिल्ली	218.73	5603.55	2130.27	6118.33	0.04	0.27
3.	हरियाणा	4496.59	61883.86	3784.67	81683.96	0.39	2.53
4.	हिमाचल प्रदेश	392.87	41924.53	755.85	55643.91	0.08	1.81
5.	जम्मू और कश्मीर	1223.26	38913.50	1565.02	48626.29	0.25	2.10
6.	पंजाब	1128.00	74427.40	1225.64	84702.80	0.42	2.83
7.	राजस्थान	3166.94	142388.44	4776.41	183906.72	0.65	7.40

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1733.89	0.00	2549.92	0.00	0.20
9.	बिहार	856.94	32029.86	1322.66	39782.50	1.02	2.06
10.	झारखंड	334.51	8883.57	916.04	12203.85	0.03	0.41
11.	उड़ीसा	294.51	34077.35	252.31	41924.80	0.03	2.82
12.	पश्चिम बंगाल	5490.35	86028.86	2697.45	118790.73	0.72	6.93
13.	अरुणाचल प्रदेश	9.41	2927.51	14.57	5038.17	#	0.09
14.	असम	618.00	40008.88	455.68	65878.13	0.14	2.84
15.	मणिपुर	67.89	7640.64	65.60	8040.88	0.01	0.64
16.	मेघालय	6.32	9101.85	5.81	12361.95	#	0.39
17.	मिजोरम	0.34	17390.14	3.52	27605.86	#	0.81
18.	नागालैंड	55.95	9500.49	78.47	13095.19	0.01	0.51
19.	सिक्किम	0.00	3130.99	9.02	6605.74	#	0.22
20.	त्रिपुरा	2.67	7969.81	55.32	11241.16	#	0.59
21.	आंध्र प्रदेश	2211.83	117646.15	1116.24	145720.08	0.27	6.91
22.	कर्नाटक	3854.84	119344.52	3842.60	143874.71	0.31	3.94
23.	केरल	1574.22	77648.66	3866.00	89479.68	0.13	4.00
24.	लक्षद्वीप	0.00	166.69	0.00	220.63	0.00	#
25.	पुदुचेरी	6.95	1261.65	83.64	2498.10	#	0.09
26.	तमिलनाडु	6316.39	107379.90	8349.20	138937.14	0.43	13.42
27.	दादरा और नगर हवेली	0.00	92.26	0.00	87.61	0.00	0.01
28.	गोवा	0.00	4388.57	49.57	6851.78	0.00	0.16

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	गुजरात	3309.33	62569.32	4431.66	88219.47	0.29	1.48
30.	महाराष्ट्र	395.52	168078.22	1360.63	197089.84	0.03	6.92
31.	छत्तीसगढ़	969.62	33232.52	787.45	45300.53	0.04	1.07
32.	मध्य प्रदेश	888.10	84615.47	1778.43	116029.51	0.05	3.48
33.	उत्तराखंड	1165.89	18810.00	2367.44	23609.61	0.30	0.77
34.	उत्तर प्रदेश	15282.50	190824.48	24233.69	255139.33	3.52	12.23
	कुल	54338.86	1613432.36	72439.41	2081908.96	9.16	90.11

#500 से कम

विवरण-III

2008-09 (अनंतिम) के दौरान उत्पादन, बिक्री और रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उत्पादन (मूल्य लाख रुपये में)		बिक्री (मूल्य लाख रुपये में)		कुल रोजगार (लाख व्यक्ति)	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	0.41	1853.10	69.09	3172.05	#	0.19
2.	दिल्ली	227.48	5855.77	2513.72	6367.96	0.04	0.28
3.	हरियाणा	4676.45	64359.21	4465.91	85016.67	0.41	2.63
4.	हिमाचल प्रदेश	408.58	43601.51	891.90	57914.18	0.08	1.88
5.	जम्मू और कश्मीर	1272.19	40470.04	1846.72	50610.24	0.26	2.19
6.	पंजाब	1173.12	77404.50	1446.26	88158.67	0.44	2.95
7.	राजस्थान	3293.62	148084.00	5636.16	191410.10	0.68	7.70
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1803.25	0.00	2653.96	0.00	0.21
9.	बिहार	891.22	33311.05	1560.74	41405.63	1.06	2.14

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	झारखंड	347.89	9238.91	1080.93	12701.77	0.03	0.43
11.	उड़ीसा	306.29	35440.44	297.73	43635.33	0.03	2.94
12.	पश्चिम बंगाल	5709.96	89470.01	3182.99	123637.40	0.75	7.21
13.	अरुणाचल प्रदेश	9.79	3044.61	17.19	5243.73	#	0.09
14.	असम	642.72	41609.24	537.70	68565.96	0.15	2.96
15.	मणिपुर	70.61	7946.27	77.41	8368.95	0.01	0.67
16.	मेघालय	6.57	9465.92	6.86	12866.32	#	0.41
17.	मिजोरम	0.35	18085.75	4.15	28732.18	0.00	0.84
18.	नागालैंड	58.19	9880.51	92.59	13629.47	0.01	0.53
19.	सिक्किम	0.00	3256.23	10.64	6875.25	#	0.23
20.	त्रिपुरा	2.78	5288.60	65.28	11699.80	#	0.61
21.	आंध्र प्रदेश	2300.30	122352.00	1317.16	151665.50	0.28	7.19
22.	कर्नाटक	4009.03	124118.30	4534.27	149744.80	0.32	4.10
23.	केरल	1637.19	80754.61	4561.88	93130.45	0.14	4.16
24.	लक्षद्वीप	0.00	173.36	0.00	229.63	0.00	0.00
25.	पुदुचेरी	7.23	1312.12	98.70	2600.02	#	0.09
26.	तमिलनाडु	6569.05	111675.10	9852.06	144605.80	0.45	13.97
27.	दादरा और नगर हवेली	0.00	95.95	0.00	91.18	0.00	0.01
28.	गोवा	0.00	4564.11	58.49	7131.33	0.00	0.17
29.	गुजरात	3441.70	65072.09	5229.36	91818.82	0.30	1.54
30.	महाराष्ट्र	411.34	174801.30	1605.54	205131.10	0.03	7.20
31.	छत्तीसगढ़	1008.40	34561.82	929.19	47148.79	0.04	1.11

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	मध्य प्रदेश	923.62	88000.09	2098.55	120763.50	0.05	3.62
33.	उत्तराखंड	1212.53	19562.40	2793.58	24572.88	0.31	0.80
34.	उत्तर प्रदेश	15893.80	198457.50	28595.75	265549.00	3.66	12.73
	कुल	56512.41	1677969.67	85478.50	2166848.42	9.53	93.78

#500 से कम

दलहन की खेती

2215. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू योजना अवधि के दौरान दलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्य हेतु शुरू की गई केन्द्रीय योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के लिए कितनी धनराशि विनिर्दिष्ट की गई है;

(घ) क्या उड़ीसा में दलहन की खेती के लिए क्षेत्र वृद्धि की व्यापक संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(च) विशेषरूप से राज्य के के.वी.के. जिलों में दलहन पैदा करने वाले किसानों को कौन-कौन से प्रोत्साहन दिए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) भारत सरकार 1-4-2004 से 14 मुख्य दलहन उत्पादन राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अर्थात समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का स्कीम (आईसोपाम) कार्यान्वित कर रही है। आईसोपाम के अधीन, दलहनों का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय रूप से विशिष्टिकृत दृष्टिकोण पर आधारित दलहन विकास कार्य के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को लचीलापन प्रदान किया गया है।

भारत सरकार ने चावल, गेहूं तथा दलहनों को शामिल करते हुए वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) भी शुरू किया है। एनएफएसएम-दलहन के अधीन, 14 मुख्य दलहन उत्पादक राज्यों के 171 जिलों को अंतरफसलन के संवर्धन के जरिए तथा चावल की परती भूमियों का उपयोग करके दलहनों के तहत 4 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाने के लिए चुना गया है। प्रजनक बीज के उत्पादन, प्रजनक बीज की खरीद, आधारी और प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, लाईम/जिप्सम, सूक्ष्म पोषक तत्वों, समेकित कृमि प्रबंधन, स्प्रिंकलर सेटों, जीरो टिल सीड ड्रिल, मल्टीपल क्राप प्लांटर, सीड ड्रिल, रोटावेटर, डीजल पम्प सेटों, नैपसैक स्प्रेयर्स के वितरण, विस्तार और मास मीडिया अभियान, पुरस्कार आदि के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है।

(ग) ग्यारहवीं योजना के पिछले तीन वर्षों के दौरान आईसोपाम और एनएफएसएम-दलहन के अधीन आबंटन इस प्रकार है:-

(लाख रुपये में)

वर्ष	आईसोपाम	एनएफएसएम-दलहन
2006-07	525.00	—
2007-08	900.00	9691.00
2008-09	575.00	28593.00

(घ) से (च) उड़ीसा में दलहन उत्पादन की संभावना पर विचार करते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य के लिए

आईसोपाम के अधीन 180.75 लाख रुपए (केन्द्रीय हिस्सा) और एनएफएसएम-दलहन के अधीन 2473.88 लाख रुपए की एक वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया है। इन स्कीमों में केबीके जिलों सहित उड़ीसा राज्य में स्कीमों के अनुमोदित घटकों पर दलहन उत्पादकों सहायता मुहैया कराई जाती है।

चीनी क्षेत्र का विनियंत्रण

2216. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी पर राजसहायता बिल अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राजसहायता बिल को नियंत्रित करने के लिए चीनी क्षेत्र का संपूर्ण विनियंत्रण सहित कोई अन्य उपाय अपनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप किस सीमा तक खुले बाजार में चीनी का मूल्य प्रभावित होगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) देश में लेवी चीनी के वितरण में भारतीय खाद्य निगम/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एजेंसियों को हुई हानि की पूर्ति करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को दी गई राजसहायता की राशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	राजसहायता की राशि
1.	2006-07	182.48
2.	2007-08	67
3.	2008-09	82.13

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि राजसहायता बिल में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों को छह लेनों वाला बनाना

2217. श्री देवजी एम. पटेल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा छह लेनों वाला बनाने का काम शुरू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सहित राज्यवार इन राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसी सड़क परियोजनाओं पर कितना व्यय किया गया तथा कितनी लम्बाई की सड़क का निर्माण किया गया;

(घ) क्या आबू रोड से जोधपुर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 को भी छह लेनों वाला बनाने का कार्य शुरू किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें कितनी प्रगति हुई, कितना व्यय हुआ तथा कब तक कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क)और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है, जहां 6 लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है।

(ग) ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) आबू रोड से जोधपुर तक का खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 17 का भाग नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत आबू रोड से जोधपुर को 6 लेन बनाने के लिए शामिल नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडों का राज्य-वार ब्यौरा जहां 6 लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है

क्रम सं.	रारा सं.	स्टेशन से-तक	लंबाई (किमी)	राज्य
1	2	3	4	5
1.	1	पंछी गुजरान से कमसपुर (सोनीपत) (एनएस-17/एचआर)	21.7	हरियाणा
2.	47	वडक्कनचेरी-त्रिसूर खंड	30	केरल
3.	1	पानीपात से पंछी गुजरान (एनएस-89/एचआर)	20	हरियाणा
4.	7	रारा-7 का बंगलौर-होसूर खंड	14.38	कर्नाटक
5.	8	बदोदरा से भरूच पैकेज बीओटी-I	83.3	गुजरात
6.	8	भरूच से सूरत पैकेज बीओटी-II	65	गुजरात
7.	5	चेन्नै-टाडा	43.4	तमिलनाडु
8.	8	गुडगांव-कोटपूतली-जयपुर	64.3	हरियाणा
			161.3	राजस्थान
9.	8	सूरत-दहीसर	118.23	गुजरात
			120.77	महाराष्ट्र
10.	5	चिल्कालूरिपेट - विजयवाड़ा	82.5	आन्ध्र प्रदेश
11.	1	पानीपत - जालन्धर	116	हरियाणा
			175	पंजाब

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान और जून, 2009 तक किए गए व्यय का परियोजना-वार ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	लंबाई (किमी)	पूरी की गई लंबाई (किमी)	वर्ष वार व्यय (करोड़ रुपए में)			
					2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (जून, 2009 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पांची गुजरान से-कसमपुर (रारा-1 के किमी. 44.300 से 66 एनएस/17 एचआर)	हरियाणा	21.7	21.7	12.41	18.39	20.27	9.61
2.	वडक्कनचेरी-त्रिसूरखंड	केरल	30	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	पानीपत-पंछीगुजरान (रारा-1 पर किमी. 66.00 से 86.00) एनएस-89/एचआर	हरियाणा	20	20	5.27	24.13	67.34	16.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	रारा-7 का बंगलोर-होसूर खंड (किमी. 18.750 से किमी. 33.130)	कर्नाटक	14.38	11	0.00	36.20	41.89	14.50
5.	वदोदरा से भरूच खंड (रारा-8 पर किमी. 108/700 से 192/000) पैकेज-I	गुजरात	83.3	83.3	0.00	269.66	468.67	49.89
6.	भरूच से सूरत खंड (रारा-8 पर किमी. 198/000 से 263.400) पैकेज-II	गुजरात	65	47.1	0.00	287.49	259.73	90.55
7.	चेन्नै टाडा रारा-5 पर- (किमी. 11.00 से किमी. 54.40)	तमिलनाडु	43.4	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुड़गांव-कोटपूतली-जयपुर रारा-8 पर-(किमी. 42.70 से किमी. 273.00)	हरियाणा/ राजस्थान	225.6	0	0.00	0.00	0.00	1.90
9.	सूरत-दहीसर-रारा-8 पर (किमी. 263.00 से किमी. 502.00)	गुजरात/ महाराष्ट्र	239	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	चिल्कालूरीपेट से विजयवाड़ा रारा-5 पर (किमी. 355 से किमी. 434.15)	आन्ध्र प्रदेश	82.5	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	पानीपत-जालन्धर रारा-1 पर (किमी. 96.00 से किमी. 387.10)	हरियाणा/ पंजाब	291	0	0.00	0.00	0.00	112.62

[अनुवाद]

टी.वी. कार्यक्रमों का बच्चों पर असर

2218. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलीविजन कार्यक्रमों से बच्चों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) और (ख) दर्शकों, विशेषकर बच्चों पर कार्यक्रमों और विज्ञापनों के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से, सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित मौजूदा कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति ने दिनांक 5.3.2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जोकि मंत्रालय की वेबसाइट http:èèmib.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त,

व्यापक सहमति प्राप्त करने से पूर्व स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करने की आवश्यकता है।

सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन की जांच करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति (आईएमसी) का भी गठन किया है। आईएमसी स्व:प्रेरणा से अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर उल्लंघन की जांच करती है और तत्पश्चात सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है, जिनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

उपभोक्ता कल्याण निधि

2219. **श्री सुशील कुमार सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता कल्याण निधि में वर्तमान में कितनी राशि है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि का इसमें शामिल एजेंसियों द्वारा पूरी तरह उपयोग कर लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त निधि के आबंटन तथा उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि के उपयोग से संबंधित उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) उपभोक्ता कल्याण कोष में 30.6.2009 की स्थिति के अनुसार वर्तमान राशि 117.07 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) सूचना निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटित राशि	उपयोग की गई राशि
2006-07	33.00	6.72
2007-08	20.60	8.73
2008-09	16.08	4.91
2009-10	13.90	0.82

(घ) लाभकारी परियोजनाएं पर्याप्त संख्या में प्राप्त न होने के कारण कम उपयोग हुआ है।

(ङ) से (ज) 30.6.2009 की स्थिति के अनुसार स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों से 36 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। यह विभाग संबंधित स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहता रहा है। जिन स्वेच्छिक उपभोक्ता संगठनों ने इसके बाद भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं उनके संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों से सीधे राशि वसूल करें।

[हिन्दी]

सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार

2220. **श्री अधीर चौधरी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रत्यायोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जी नहीं। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 4 में केन्द्र के सशस्त्र बलों को अधिनियम की धारा 3 के तहत "विक्षुब्ध" घोषित क्षेत्रों में अभियान चलाने के लिए पहले से ही विशेष शक्तियां दी हुई हैं।

नई इथेनॉल आधारित मेगा परियोजनाओं का स्थापित करना

2221. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या **उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सहित कई राज्यों से नई इथेनाल आधारित मेगा परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) राज्यों में इथेनॉल आधारित परियोजनाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजमार्गों के प्रदाय के वैकल्पिक तरीके

2222. **श्री सुरेश कलमाडी :**
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री तथागत सत्पथी :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राजमार्गों के प्रदाय के वैकल्पिक तरीकों हेतु अव्यवहार्य परियोजनाओं के मामलों में वित्तपोषण तंत्र में परिवर्तन सहित कोई नई नीति/पद्धति विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की सुपुर्दगी के वैकल्पिक तरीकों पर सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित व्यापक नीति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III और उसके बाद के चरणों के अधीन शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का निर्माण और विस्तार, सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (पथ-कर) विधि से; इसके विफल होने पर निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (वार्षिकी) विधि से और इसके भी विफल होने पर इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन विधि से किया जाता है।

कालीसूची में डाली गई उत्पादन कंपनियां

2223. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :**
श्री एल. राजगोपाल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उत्पादन कंपनियों/घरानों को अल्पावधि अधिग्रहण योजना के अंतर्गत कालीसूची में डाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कंपनियों/घरानों के खिलाफ कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) और (ख) जी, हां। काली सूची में डाली गई निर्माता कंपनियों से संबंधित ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। दूरदर्शन ने अनुशंसित कार्यक्रमों की शेष कड़ियों को उनके द्वारा प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन करने के उद्देश्य से अल्प-कालिक अधिग्रहण स्कीम-2006-07 के अंतर्गत खाली/पूर्व प्रसारित टेप प्रस्तुत करने के कारण उन्हें काली सूची में डाल दिया था।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उन्होंने अप्रैल, 2009 से इन निर्माता कंपनियों पर दूरदर्शन के साथ भविष्य में कोई भी कारोबार करने पर 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

विवरण

काली सूची में डाली गई निर्माता कंपनियों की सूची

क्र.सं.	निर्माता/बैनर
1	2
1.	श्री पी.के. श्रीवास्तव, मैसर्स रेनबो फिल्म्स, बी-37, स्वामी नगर, नई दिल्ली-110017
2.	सुश्री मधु राने, मैसर्स मैट्रिक्स एंटरटेनमेंट, जे-48, पांडव नगर, मदर डेयरी के सामने, दिल्ली-110092
3.	श्री तलत सईद और श्री जावेद खान मैसर्स मैजिक वर्क्स, ब्लाक संख्या बी, फ्लैट संख्या-6, वर्सोवा हैवन, जे.पी.रोड, सात बंगला, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400063
4.	श्री दीपक भारद्वाज, मैसर्स वैशणु फिल्म्स, डी-899, भू-तल, टाइप ए, पाकेट-III, ई.एच.एस. बिंदापुर, डीडीए फ्लैट्स, द्वारिका परियोजना, नई दिल्ली-110059
5.	सुश्री, रमा दीपक, मैसर्स तिरुपति प्रोडक्शन, ई-98, कमला नगर, दिल्ली-110007
6.	श्री संदीप ग्रोवर, मैसर्स श्रेय मीडिया एंटरटेनमेंट्स, ए-2/49, आशीर्वाद अपार्टमेंट्स, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63
7.	सुश्री रमा पांडे, मैसर्स मानटेज फिल्म्स, 332, तीसरा तल, डीएलएफ गैलेरिया, डीएलएफ सिटी फेज-IV, गुड़गांव-122002
8.	श्री सुधीर एस. जामवाल, मैसर्स एस्ट्रा प्रोडक्शंस, 151-एफ, दूरदर्शन लेन, ओल्ड जैनपुर, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)
9.	श्री किरज कुमार, मैसर्स टचस्टोन कम्युनिकेशंस, जेई-31, खिरकी एक्सटेंशन, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
10.	श्री उस्मान सैफ, मैसर्स सैफ एंटरटेनमेंट, सी-1, 32, संदोईपनी टीचर्स अपार्टमेंट्स, ओशिवाड़ा, न्यू लिंक रोड, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई-400102
11.	श्री नंदन शर्मा, मैसर्स मेघना यू-मैटिक विजन, 138, मैत्री अपार्टमेंट्स आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092
12.	सुश्री अनुराधा प्रसाद, मैसर्स बी.ए.जी. फिल्म एंड मीडिया लि. एफसी-23, सेक्टर-16ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301
13.	श्री अमन बजाज, मैसर्स बजाज एनिमेशन केंद्र ए-5, मायापुरी, फेज-1 नई दिल्ली

बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता

2224. **श्री वैजयंत पांडा :**
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री तथागत सत्पथी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बाढ़ प्रभावित राज्यों से वित्तीय सहायता के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक केन्द्रीय दल ने पुनर्वास उपायों के लिए धनराशि प्रदान करने हेतु हानि का आकलन करने के लिए इन राज्यों का दौरा किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी राशि आबंटित/जारी की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) दक्षिण-पश्चिम मानसून 2009 के दौरान, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने "आइला" चक्रवात से हुई क्षति के कारण एन.सी.सी.एफ. से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया है। पश्चिम बंगाल की सरकार से एक ज्ञानन मिलने पर, एक अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने 6-9 जून, 2009 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और एक विस्तृत क्षति आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ) से सहायता की सिफारिश की। ये सिफारिशें व्यक्ति की मृत्यु, मकानों की क्षति, पशुओं एवं खाद्यान्न की हानि के साथ-साथ राज्य में अवसंरचनात्मक एवं कृषि फसलों की हानि के मामले में राहत की मात्रा से संबंधित हैं।

उच्च-स्तरीय समिति ने राज्य सरकार की मांग पर विचार किया है और पश्चिम बंगाल की सरकार से क्षेत्रवार ब्यौरे प्राप्त न होने के कारण आवास एवं सड़क के क्षेत्रों से संबंधित मदों पर निर्णय को आस्थगित करने का निर्णय लिया है। अन्य क्षेत्रों के मामले में, एन.सी.सी.एफ. से 478.27 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की गयी है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून 2009 के दौरान आई बाढ़ों के मद्देनजर किसी अन्य राज्य से वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) से जारी की गई निधि तथा आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) से केन्द्रीय अंशदान के आबंटन एवं रिलीज को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	आपदा राहत कोष के अंतर्गत आबंटन				रिलीज किए गए आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंशदान				राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि			
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (आज तक)	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (आज तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	361.28	379.35	398.31	418.22	335.48	219.99	298.73	156.84	203.06	37.51	29.82	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.12	29.97	30.87	31.81	21.84	22.48	23.15	0.00*	44.38	0.00	26.40	32.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	असम	198.62	204.48	210.63	217.06	221.37#	153.36	157.97	0.00*	0.00	0.00	300.00	0.00
4.	बिहार	153.23	157.74	162.48	167.45	55.85*	233.24#	121.86	0.00*	0.00	0.00	1000.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	114.98	118.35	121.91	125.62	150.33	65.57	45.72	45.72#	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	2.21	2.32	2.44	2.56	2.45	1.74	1.83	0.00*	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	258.30	271.22	284.77	299.00	246.87	48.57	315.29#	112.13	545.69	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	130.60	137.13	143.99	151.18	107.28	102.85	54.00	53.99#	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	103.60	106.65	109.87	113.21	77.70	79.99	103.63	0.00*	25.14	24.59	40.33	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	88.96	91.58	94.33	97.21	66.72	68.68	35.38	35.38#	0.00	13.51	0.00	0.00
11.	झारखंड	129.71	133.53	137.55	141.75	48.64	148.79#	51.58	51.58#	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	120.39	126.41	132.73	139.36	113.98	71.11	99.55	52.26	384.97	68.89	189.11	0.00
13.	केरल	89.77	94.26	98.98	103.91	67.33	70.70	74.23	38.96	0.00	50.81	9.48	0.00
14.	मध्य प्रदेश	261.58	269.29	277.39	285.88	246.67	151.48	208.04	107.21	30.85	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	234.05	245.75	258.04	270.94	220.00	47.70	0.00*	0.00*	589.90	168.92	0.00	0.00
16.	मणिपुर	5.72	5.89	6.05	6.25	0.00*	10.67#	4.48#	0.00*	0.00	0.00	5.45	0.00
17.	मेघालय	11.61	11.95	12.31	12.68	12.95	8.96	9.23	0.00*	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	6.77	6.97	7.19	7.40	5.01	7.77#	0.00*	2.70#	0.00	8.81	49.60	0.00
19.	नागालैंड	3.94	4.05	4.16	4.30	0.00*	7.42#	3.12	0.00*	0.81	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	310.24	319.38	328.97	339.03	291.34	180.87	324.50@	49.37	25.00	0.00	98.87	0.00
21.	पंजाब	153.33	160.99	169.04	177.49	112.26	178.24#	126.78	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	436.42	458.25	481.16	505.21	413.66	257.34	360.87	189.45	100.00	0.34	0.00	0.00
23.	सिक्किम	18.04	18.57	19.13	19.70	0.00*	27.46#	14.35	0.00*	5.20	0.00	8.36	0.00
24.	तमिलनाडु	219.53	230.51	242.03	254.13	243.06	172.88	229.17	0.00*	0.00	0.00	522.51	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	त्रिपुरा	13.32	13.61	14.03	14.44	14.60#	10.07#	10.37#	0.00*	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	304.48	313.45	322.87	332.75	228.36	235.10	242.15	0.00*	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	96.59	98.58	100.67	101.85	36.22	73.19#	112.47#	0.00*	7.06	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	241.50	248.62	256.09	263.92	181.12	186.48	192.07	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	4097.79	4258.85	4427.99	4604.31	3521.07	2842.67	3220.48	1061.09	1962.06	373.38	2279.92	32.29

*पूर्व में रिलीज की गई निधि को क्रेडिट करने, प्रमाणपत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित जानकारी की आवश्यकता के कारण आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंशदान को रिलीज नहीं किया गया।

#पूर्व वर्ष हेतु आपदा राहत कोष में बकाया सहित।

खनन लाइसेंस

2225. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी निजी समूह को उड़ीसा के नीयामगिरी जंगल में बॉक्साइट के खनन का लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने आदिवासी विस्थापित तथा प्रभावित होंगे;

(घ) क्या सरकार ने प्रभावित आदिवासियों को कोई मुआवजा मंजूर किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) से (ग) खनिज रियायतें (खनन पट्टा, पूर्वेक्षण लाइसेंस एवं टोही परमिट) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती हैं। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों (बॉक्साइट सहित) के संबंध में, राज्य सरकारों द्वारा खनिज रियायतें प्रदान करने से पूर्व केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित है। कालाहांड़ी के नीयामगिरी डोंगरा क्षेत्र और रायगड़ा जिले के 721.323 हैक्टेयर क्षेत्र में बॉक्साइट के लिए मैं. उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को खनन पट्टा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 13.9.2004 को पूर्व अनुमोदन प्रदान किया गया। उड़ीसा सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, इस क्षेत्र से उत्खनित किए जाने वाले बॉक्साइट की संपूर्ण मात्रा केवल मै. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड/वेदांत एल्युमीनियम लि. द्वारा लंजीगढ़ में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एल्युमिना संयंत्र में प्रयोग की जाएगी। तथापि कंपनी को उक्त खनन पट्टा वन मंजूरी के अभाव में प्रदान नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने कंपनी को सूचित किया है कि खनन पट्टा प्रदान किया जाना, कंपनी द्वारा वन और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए जाने के अध्यधीन होगा। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि उक्त खनन पट्टे के क्षेत्र के अंतर्गत कोई मानव अधिवास नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि कटाव तथा जल भराव रोकने के लिए केन्द्रीय सहायता

2226. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान भूमि कटाव तथा जल भराव रोकने के लिए बिहार सहित विभिन्न राज्यों द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) मृदा निर्माण और मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पारिस्थितिकी प्रणाली में संतुलन बनाये रखने के लिए साथ-साथ चलती रहती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भू उपयोग योजना ब्यूरो (एनबीएसएस एण्ड एलयूबी)-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) क्षेत्रीय केन्द्र, नागपुर द्वारा आयोजित अध्ययन (2005) के अनुसार, देश के कुल 328.60 मिलियन हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 146.82 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र (45%) विभिन्न किस्म के भूमि अवक्रमण से ग्रस्त है जैसाकि निम्न ब्यौरे में दिया गया है।

क्र.सं.	भूमि अवक्रमण की किस्म	क्षेत्र मि. हैक्टेयर में
1	2	3
1.	जल अपरदन	93.68
2.	वायु अपरदन	9.48
3.	जल भराव	14.30
4.	लवणीयता/क्षारीयता	5.95
5.	मृदा अम्लीयता	16.03
6.	सम्मिश्र समस्या	7.38
	योग	146.82

मृदा अपरदन और भूमि अवक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से कृषि मंत्रालय भारत सरकार बिहार सहित देश में विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रम नामत: (i) राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए), (ii) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी (आरवीपी और एफपीआर) के स्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण (iii) क्षारीय और अम्लीय मृदाओं का सुधार और विकास (आरएडीएएस), (iv) झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए) कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रमों के तहत पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2006-07 से 2008-09) में 1839.85 करोड़ की धनराशि आबंटित की गई थी जिसमें से 1737.38 करोड़ रु. राज्यों द्वारा उपयोग कर लिए गए हैं और वर्तमान वर्ष (2009-10) के दौरान 490.48 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। पिछले तीन वर्षों में राज्यवार आबंटित धनराशि, उपयोगित धनराशि और वर्ष 2009-10 के लिए आबंटित निधि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों (2006-07 से 2008-09 तक) के दौरान कृषि मंत्रालय के विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार आबंटित निधियों तथा वर्ष 2009-10 के लिए निधियों के आवंटन दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्यों के नाम	2006-07 तक		2007-08 तक		2008-09 तक		तीन वर्ष के लिए कुल		2009-10 के लिए आबंटन
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1831.44	1750.92	940.36	943.89	1143.47	1116.90	3915.27	3811.71	1305.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	1082.57	971.37	778.36	829.04	1020.86	818.31	2881.79	2618.72	595.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	1444.15	1484.90	684.80	676.95	1031.05	679.03	3160.00	2840.88	1007.80
4.	बिहार	1143.38	1079.95	100.00	98.10	589.88	67.27	1833.26	1245.32	734.09
5.	छत्तीसगढ़	2084.90	1954.57	724.19	1151.07	1689.86	1503.70	4498.95	4609.34	1088.15
6.	गुजरात	5085.60	5120.47	5282.68	4516.63	4889.67	4202.62	15357.95	13839.72	2656.86
7.	हरियाणा	990.03	989.16	797.41	792.61	693.03	666.91	2480.47	2448.68	300.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1704.41	1574.79	1383.25	1234.39	1425.83	1731.70	4513.49	4540.88	1238.89
9.	झारखंड*	2003.80	2080.43	574.33	1333.45	312.28	1330.31	2890.41	4744.19	1816.59
10.	जम्मू और कश्मीर**	2353.73	2433.97	2920.43	2497.53	3618.70	3291.86	8892.86	8223.36	2700.00
11.	कर्नाटक	4032.76	4032.76	3675.70	3577.53	4698.39	4194.34	12406.85	11804.63	1300.00
12.	केरल	1905.34	1475.97	1310.90	1189.98	1410.01	417.46	4626.25	3083.41	474.22
13.	मध्य प्रदेश	3561.61	3484.26	4512.84	4257.58	5389.67	5380.03	13464.12	13121.87	4750.00
14.	महाराष्ट्र	6837.36	6165.14	7523.97	6249.52	5331.98	5326.99	19693.31	17741.65	4364.32
15.	मणिपुर	1582.23	1582.22	1888.00	1713.00	1728.50	1723.50	5198.73	5018.72	1612.00
16.	मेघालय	1274.38	1022.59	1167.00	1374.13	1298.37	1217.00	3739.75	3613.72	650.00
17.	मिजोरम	1509.00	1346.00	2163.00	1913.00	2337.56	2322.52	6009.56	5581.52	2249.74
18.	नागालैंड	2112.50	1962.50	2231.70	2232.00	2000.00	2000.00	6344.20	6194.50	1200.00
19.	उड़ीसा	3419.92	3389.92	2212.00	1741.73	2751.47	1323.42	8383.39	6455.07	1644.44
20.	पंजाब	1117.07	1113.07	811.84	565.62	857.63	681.26	2786.54	2359.95	240.00
21.	राजस्थान	7044.98	6847.49	4412.69	4464.21	4253.20	4926.52	15710.87	16238.22	4352.00
22.	सिक्किम	430.25	307.52	438.20	404.08	645.52	645.17	1513.97	1356.77	810.00
23.	तमिलनाडु	4719.55	4650.17	2575.00	2552.57	2064.12	1615.65	9358.67	8818.39	2487.52
24.	त्रिपुरा	816.02	762.13	865.20	623.70	840.87	840.85	2522.09	2226.68	1206.57
25.	उत्तर प्रदेश	2513.09	2552.52	3003.68	2996.28	8039.58	7937.93	13556.35	13486.43	7184.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	उत्तराखंड	1835.10	1835.10	1931.54	1931.64	1807.00	1705.07	5573.64	5471.81	400.00
27.	पश्चिम बंगाल	728.22	680.06	361.04	211.69	604.95	490.77	1694.21	1382.52	604.00
28.	गोवा	400.00	400.00	281.00	290.10	284.20	155.97	965.20	846.07	75.34
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
	कुल	86576.39	63062.95	55651.11	62362.02	62857.65	58312.76	183985.15	173737.73	49047.80

*झारखंड के आबंटन और व्यय दामोदर घाटी को भी शामिल करता है।

**जम्मू और कश्मीर के आबंटन और व्यय प्रधानमंत्री पैकेज को भी शामिल करता है।

नोट: वर्ष 2007-08 और 2008-09 के आबंटनों में पिछले वर्षों से आगे लाई गई राशि भी शामिल है।

[हिन्दी]

बाल सुधार गृह से लापता बच्चे

2227. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 2008 के दौरान दिल्ली में बाल सुधार गृह से कई बच्चों के लापता होने का समाचार प्रकाश में आया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई जांच का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि सरकार द्वारा दिल्ली में चलाए जा रहे किसी भी बाल सुधार गृह से मई, 2008 में बच्चों के लापता होने का कोई मामला नहीं हुआ। तथापि, मई, 2008 के दौरान तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली स्थित 'प्रयास' बाल सुधार गृह से दो लड़कियों के लापता होने की रिपोर्ट है।

(ख) दिल्ली पुलिस ने इन दोनों गुमशुदा लड़कियों का पता लगाने के लिए जांच के दौरान गुहार नोटिस जारी किए, इस घटना को सम्पूर्ण भारत में वायरलेस पर फ्लैश किया, लापता व्यक्ति स्क्वाड, एन.सी.आर.बी, एस.सी.आर.बी, जेड.आई.पी.नेट, अपराध आसूचना प्रकोष्ठ, सी.बी.आई, पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित किया। तथापि सभी प्रयास निरर्थक रहे।

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा बाल सुधार गृहों के प्राधिकारियों को सहवासियों पर समुचित नजर रखने और द्वारों पर सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी गई है।

अवैध उत्प्रवास को रोकने के उपाय

2228. श्री शेख सैदुल हक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अवैध उत्प्रवास को रोकने के लिए देश के सीमावर्ती राज्यों में जिलेवार कंप्यूटरीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त 'क' को देखते हुए प्रश्न पैदा नहीं होता।

राष्ट्रवर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण का पुनर्गठन

2229. **श्री प्रदीप माझी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त उद्देश्य के लिए कोई रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) राष्ट्रीय वर्ष क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) का गठन संघीय सरकार ने नवम्बर, 2006 में देश के शुष्क भूमि क्षेत्र एवं वर्षा सिंचित कृषि के प्रणालीबद्ध संवर्धन और प्रबंधन के संबंध में ज्ञान प्रदान करने के लिए एक सलाहकारी नीति निर्माता और अनुवीक्षण निकाय के रूप में किया है। प्राधिकरण पहले से ही कार्य कर रहा है और अत्याधुनिक पनधारा कार्यक्रमों के लिए एक नए खाके के साथ पनधारा विकास परियोजनाओं के लिए सामान्य दिशा-निर्देश प्रकाशित किये हैं। अंतर्निहित लचीलेपन के साथ ये दिशा-निर्देश देश में सभी पनधारा विकास परियोजनाओं के नियोजन, डिजाइन, प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए एक योग्य खाका प्रदान करेंगे। इन सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसरण में 1 अप्रैल, 2008 से नई पनधारा परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। प्राधिकरण ने एक अवलोकन दस्तावेज ''वर्षा सिंचित क्षेत्रों में अवसर बढ़ाना'' भी तैयार किया है।

राष्ट्रमंडल खेल

2230. **श्री के.सी. सिंह ''बाबा''** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमंडल खेल 2010 की तैयारी की परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन खेलों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण/कोचिंग देने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कतिपय स्वैच्छिक संघों और संगठनों को इससे संबंधित कार्य में लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन संघों/संगठनों को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010, भारतीय खेल प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली सरकार, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा अखिल भारतीय टेनिस संघ के खेल स्टेडियमों में आयोजित किए जाएंगे। सभी उपर्युक्त प्रतियोगिता स्थलों पर कार्य तेजी से चल रहा है। विभिन्न स्टेडियमों के कार्य पूरा होने की समय सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां। राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में भारतीय दल के प्रदर्शन को सुधारने के लिए 678 करोड़ रु. (2008-09 से 2010-11 हेतु) के आबंटन के साथ एक स्कीम ''राष्ट्रमंडल खेल, 2010 हेतु भारतीय टीम की तैयारी'' जुलाई, 2008 से कार्यान्वित की जा रही है,? जिसके अंतर्गत राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की सभी खेल विधाओं के विशिष्ट खिलाड़ियों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण, विदेश में प्रदर्शन के अवसर, वैज्ञानिक समर्थन आदि प्रदान किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए खेल स्थलों का कार्य पूरा होने की समय सूची

क्र. सं.	खेल विधा	स्टेडियम का नाम	पूरा होने की तारीख
1.	एथलेटिक्स	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम	31.12.2009
2.	तीरंदाजी	युमना खेल परिसर	31.12.2009
3.	एक्वाटिक्स	एस.पी. मुखर्जी तरणताल	31.12.2009
4.	बैडमिंटन	सीरी फोर्ट खेल परिसर	31.12.2009
5.	मुक्केबाजी	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम	31.12.2009
6.	साइक्लिंग	वेलोड्रम इंदिरा गांधी खेल परिसर	31.03.2009
7.	जिम्नास्टिक्स	इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम	31.12.2009
8.	हांकी	मे. ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम	31.12.2009
9.	लान बाल्स	जवाहरलाल नेहरू खेल परिसर	31.12.2009
10.	नेटबाल	त्यागराज खेल परिसर	31.12.2009
11.	रग्बी 7 एस	दिल्ली विश्वविद्यालय	31.12.2009
12.	निशानेबाजी	डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज	31.12.2009
		कादरपुर शूटिंग रेंज	31.12.2009
13.	स्क्वैश	सीरी फोर्ट खेल परिसर	31.12.2009
14.	टेबल टेनिस	यमुना खेल परिसर	31.12.2009
15.	टेनिस	आर.के. खन्ना टेनिस परिसर	31.12.2009
16.	भारोत्तोलन	जवाहरलाल नेहरू खेल परिसर	31.12.2009
17.	कुश्ती	इंदिरा गांधी खेल परिसर	31.12.2009

[अनुवाद]

प्लैनटेशन फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य

2231. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्लैनटेशन बागवानी फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी फसलवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) भारत सरकार 25 कृषि जिन्सों नामत: धान, ज्वार, बाजरा, रागी, गेहूं, जौ, चना, अरहर (तूर), मूंग, उड़द, मसूर (लेन्टिल), कपास, छिलका सहित मूंगफली, पटसन, रेपसीड/सरसों, सूरजमुखी बीज, सोयाबीन कुसुम्भ, तोरिया, तम्बाकू (वी. एफ.सी.), खोपरा, छिलका रहित नारियल, तिल तथा रामतिल हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। गन्ने के मामले में सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है। फसल मौसम 2009 के लिए भारत सरकार ने 4450 रुपए प्रति क्विंटल पर मिलिंग खोपरा तथा उचित औसत किस्म हेतु 4700 रुपए प्रति क्विंटल पर बाल खोपरा हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है जो 2008 फसल मौसम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 790 रुपए प्रति क्विंटल पर अधिक है। छिलका रहित नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2009 फसल मौसम के लिए 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है।

अन्य कृषि जिन्सों वृक्षारोपण फसलें शामिल हैं, के लिए भारत सरकार ऐसी कृषि तथा बागवानी जिन्सों जो सामान्यत: स्वभाव में नश्वर होती हैं व जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत शामिल नहीं है, के प्रापण के लिए राज्य/संघशासित क्षेत्र की सरकार के अनुरोध पर बाजार हस्तक्षेप योजना का क्रियान्वयन करती हैं इसका उद्देश्य बम्पर फसल होने की स्थिति में इन जिन्सों के उत्पादकों को संकट बिक्री के कारण होने वाली हानियों से सुरक्षा प्रदान करना है। प्रापण एजेन्सियों द्वारा वहन की गई हानियों, यदि होती है, को केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार के बीच 50:50 आधार पर (उत्तरपूर्वी राज्यों के मामले में 75:25) वहन किया जाता है। उठाई जाने वाली हानि की राशि की सीमा प्रापण लागतकी 25% तक है।

कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर बाजार हस्तक्षेप योजना क्रियान्वित की गई है तथा दिनांक 01.03.2009 से 30.06.2009 तक 6000 मीट्रिक टन सफेद किस्म की सुपारी तथा 4000 मीट्रिक टन लाल किस्म

की सुपारी का प्रापण क्रमश: 6900 रुपए तथा 8900 रुपए प्रति क्विंटल के बाजार हस्तक्षेप मूल्य के अंतर्गत किया गया।

अनन्नास उत्पादकों को सहायता

2232. श्री पी.टी. थॉमस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल सहित देश के अनन्नास के किसानों की सहायता केरने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनन्नास के मूल्य में आ रहे उतार-चढ़ाव ने उन अनेक किसानों को प्रभावित किया है जो इस मौसमी फसल पर निर्भर हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किसानों की सहायता करने हेतु क्या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या अनन्नास हेतु प्रसंस्करण इकाइयां शुरू करने तथा इसके किसानों को राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी निधियों का आबंटन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी हां, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लिए समेकित बागवानी विकास पर प्रौद्योगिकी मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) नामक चल रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत, सरकार केरल सहित देश में अनन्नास की खेती को बढ़ावा दे रही है। इन स्कीमों के तहत अनन्नास की खेती के लिए किसानों को 15,000 रु. प्रति है. की दर से 4 है. प्रति लाभार्थी तक सीमित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, अनन्नास सहित बागवानी के विकास के लिए पौधशालाओं की स्थापना, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन/समेकित कीट प्रबंधन, जैविक खेती को अपनाने तथा जल संसाधनों के सृजन हेतु सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) अनन्नास के मामले में मंडी में मूल्य का उतार-चढ़ाव बिल्कुल सामान्य है। उत्पादकों ने एरनाकुलम, कोट्टायम, इडुकी, पाथनामथिट्टा एवं त्रिसूर जिलों में वृद्धित उत्पादन के कारण कुछ स्तर तक मूल्य में उतार-चढ़ाव का अनुभव किया। अनन्नास के मूल्य को स्थिर रखने के उद्देश्य से नाडुक्कारा कृषि प्रसंस्करण कम्पनी लि. केरल राज्य सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र एक का उपक्रम राज्य के किसानों से अनन्नास की खरीद कर रहा है।

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआई) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण की स्कीम के तहत पौध एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से जो कि सामान्य क्षेत्रों में अधिकतम 50.00 लाख रु. या जटिल क्षेत्रों में 33.33% अधिकतक 75 लाख रुपए के अधीन है, सभी कार्यान्वयन एजेंसी को अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में समेकित बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के तहत निर्माण के लिए 4 करोड़ रु. और फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन के लिए 1.00 करोड़ रु. तक 50% की दर से उच्च स्तर की सहायता प्रदान की जाती है।

(च) 2009-10 के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 66.00 करोड़ रु. की धनराशि निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

राजमार्ग परियोजनाओं के ऊपर निर्धारित से अधिक समय एवं लागत लगना

2233. श्री गणेश सिंह :
श्री भक्त चरण दास :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर निर्धारित से अधिक समय एवं लागत आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी हां। 5.00 करोड़ रुपए और

उससे अधिक लागत की 231 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं जिनमें गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अधिक समय और लागत की खपत हुई है जिनका राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए किए गए सुधारात्मक उपायों में शामिल हैं:- विभिन्न स्तरों पर नियमित निगरानी, भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण तथा विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में समन्वय के लिए प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी की नियुक्ति, भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, रेलवे के साथ समन्वय करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में रेलवे के एक अधिकारी की नियुक्ति करना, ठेकेदारों को अग्रिम राशि प्रदान करना और गैर-निष्पादक ठेकेदारों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई।

विवरण

उन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्य वार ब्यौरा जिनमें गत तीन वर्षों अर्थात् 2006.07, 2007.08 और 2008.09 और चालू वर्ष 2009-10 (30.06.2006 की स्थिति के अनुसार) के दौरान समय और लागत अधिक है

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	असम	19
3.	बिहार	15
4.	छत्तीसगढ़	28
5.	गोवा	2
6.	गुजरात	17
7.	हरियाणा	3
8.	जम्मू और कश्मीर	7
9.	झारखंड	1
10.	कर्नाटक	5
11.	केरल	1
12.	मध्य प्रदेश	12
13.	महाराष्ट्र	37
14.	उड़ीसा	7
15.	पुदुचेरी	1
16.	पंजाब	5
17.	राजस्थान	15
18.	तमिलनाडु	24
19.	उत्तर प्रदेश	21
20.	पश्चिम बंगाल	5

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम

2234. श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी पटेल :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम में तेजी लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने देश में राजमार्ग विकास कार्यक्रम के पुनरुद्धार के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न ठेकेदारों की जमा धनराशि को वापस नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को हाल ही में उक्त कार्यक्रम के हिस्सेदारों से कोई शिकायत मिली है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 132 परियोजनाओं के लिए कार्य योजना तैयार करने का कार्य शुरू किया है और तद्नुसार बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।

(घ) बोली दस्तावेज में लागू शर्तों और निबंधों का पालन न करने के कारण बोलीदाताओं द्वारा जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाती है।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। तथापि, हितधारकों से समय-समय पर प्राप्त होने वाले किन्हीं सुझावों का समाधान सभी संबंधितों से उचित विचार-विमर्श करने के बाद किया जाता है।

बोडोलैण्ड प्रादेशिक परिषद क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां

2235. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोडोलैण्ड प्रादेशिक परिषद क्षेत्र में कतिपय उग्रवादी गुटों के आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने की खबर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार कानून एवं व्यवस्था एवं पुलिस से संबंधित विषयों को बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद को अन्तरित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले पर कोई निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एन डी एफ बी) (वार्ता विरोधी) जैसे भूमिगत दल बक्स, चिरांग, उदलगुडी तथा कोकड़ाझार नामक बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आने वाले चार जिलों में सक्रिय रहे हैं। वर्तमान वर्ष (15 जुलाई, 2009 तक) के दौरान भूमिगत दल असम के इन चार जिलों में 58 हिंसक घटनाओं में शामिल रहे हैं; जिसके कारण 7 नागरिकों की जान चली गई। भूमिगत दल की गतिविधियों को रोकने के क्रम में बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आने वाले चार जिलों सहित असम में घुसपैठ-रोधी कार्रवाइयों को गति प्रदान की गई है। बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में घुसपैठ-रोधी कार्रवाइयों के दौरान, वर्तमान वर्ष में 15 जुलाई, 2009 तक भूमिगत दल के 31 काडर कार्रवाई में मारे गए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि संविधान के संगत प्रावधानों के अनुरूप इन विषयों को अन्तरित करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेतु दिशानिर्देश

2236. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में आने वाले आपत्तिजनक मामलों/दृश्यों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशानिर्देश बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) से (ग) सभी निजी चैनलों को केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का अनुपालन करना होता है। मंत्रालय ने कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के उल्लंघन से संबंधित विशेष शिकायतों की जांच करने या स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेने

के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। जब कभी कोई विशेष उल्लंघन पाया जाता है तो केबल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। सरकार ने मौजूदा कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता को अधिक विशिष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से उसकी समीक्षा करने के लिए भी एक समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर उपलब्ध है। इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व मामले पर स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

जहां तक प्रिंट मीडिया का संबंध है, सरकार ने भारतीय प्रैस परिषद का गठन किया है जोकि प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय है जिसका लक्ष्य भारत में प्रैस की आजादी को बनाए रखना और समाचारपत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मानकों को कायम रखना और इनमें सुधार करना है तथा प्रैस के मन में स्व-विनियमन के सिद्धांतों को बिठाना है। भारतीय प्रैस परिषद ने प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 के अनुच्छेद 13 (2)/(ख) के अंतर्गत पत्रकारिता आचरण संबंधी मानदंड बनाए हैं। संगत मानदंडों में मानदंड 6: व्यक्ति के निजता के अधिकार; मानदंड-17: अश्लीलता एवं अभद्रता से परहेज किया जाए; मानदंड 19: हिंसा का महिमामंडन न किया जाए तथा मानदंड 20: सामुदायिक विवादों/झगड़ों की कवरेज से संबंधित है। दिशा-निर्देश भारतीय प्रैस परिषद की वेबसाइट presscouncil.nic.in पर उपलब्ध हैं।

आनुवांशिक रूप से संवर्धित बीज

2237. श्री प्रबोध पांडा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आनुवांशिक रूप से संवर्धित बीजों के परिणाम का भारतीय कृषि पर विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आनुवांशिक रूप से संवर्धित बीजों के बजाए परम्परागत बीजों का उपयोग करने हेतु किसानों को सलाह जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) बीटी कपास केवल आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति (जीईएसी) द्वारा व्यावसायिक रूप से अनुमोदित है। देश के कपास के उत्पादन में बीटी कपास का प्रदर्शन अभूतपूर्व अर्थात् करीब-करीब दो गुना हुआ है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथा आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज तथा पारम्परिक बीजों को विशिष्ट क्षेत्रों/रीजन में प्रचलित पर्यावरण दशाओं तथा मृदा उर्वरता के अनुसार बोने का सुझाव दिया जाता है।

कृषि उत्पादन विपणन समिति

2238. श्री जोस के. मणि : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कृषि उत्पाद विपणन समितियां (एपीएमसी) का गठन करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

आपदा प्रबंधन विभागों की स्थापना

2239. श्री नरहरि महतो : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु अलग विभागों की स्थापना करने हेतु राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे संबंधित दिशानिर्देशों का राज्यों द्वारा क्रियान्वयन किए जाने की स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अपने-अपने राहत एवं पुनर्वास

विभागों को आपदा प्रबंधन विभागों में बदलने के लिए कहा था जिसको आपदा प्रबंधन के समूचे चक्र अर्थात् आपदा की रोकथाम, नियंत्रण, तैयारी, कार्रवाई, राहत एवं पुनर्वास की निगरानी करने का दायित्व सौंपा जाए।

(ख) अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन एवं दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पुडुचेरी, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने अपने-अपने राहत विभागों को पहले ही परिवर्तित/पुनः नामोदिष्ट कर दिया है ताकि आपदा प्रबंधन को उनकी नामावली में शामिल किया जा सके।

नारियल की खेती का नुकसान

2240. **श्री पी. करुणाकरन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान केरल सहित विभिन्न राज्यों में 'बड रूट' बीमारी के फैलने के कारण नारियल की खेती का कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है तथा इससे कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) सर्वेक्षण की रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2007-08 के दौरान नारियल की खेती करने वाले राज्यों से कली के सड़ जाने के रोग नारियल बागानों के नष्ट हो जाने की किसी गम्भीर घटना की सूचना नहीं है। वर्ष 2008-09 के दौरान केरल के कासरगोड जिले के पहाड़ी इलाकों में गम्भीर रोगग्रस्तता की सूचना मिली है।

(ख) और (ग) वर्ष 2008-09 के दौरान, रोगनिरोधी और उपचारात्मक उपायों, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए तथा 67, 121 पूर्णतया क्षतिग्रस्त पामवृक्षों के काटने तथा हटाए जाने के लिए क्षतिपूर्ति देने हेतु 373.10 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की गई थी।

[हिन्दी]

ऋण माफी हेतु मानदण्ड

2241. **श्री आर.के. सिंह पटेल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों के ऋण माफ करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित है;

(ख) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों से उन किसानों का ऋण माफ नहीं करने की शिकायतें मिली हैं जिन्होंने अपने ऋण की कुछ किस्तें अदा कर दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

श्रीरामपुर-सिल्चर गलियारे की स्थिति

2242. **श्री बदरुद्दीन अजमल :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में पूर्व-पश्चिम गलियारे के श्रीरामपुर-सिल्चर खंड के पूर्ण होने की स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) श्रीरामपुर-सिल्चर गलियारे का कार्य पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) असम में श्रीरामपुर से सिल्चर तक पूर्व पश्चिम महामार्ग का 678 किमी लंबाई का संपूर्ण खंड 28 पैकेजों में विभाजित है। इनमें से गुवाहाटी बाइपास का एक पैकेज (18 किमी) पूरा कर लिया गया है और बालचेरा से हरंगजो तक 31 किमी का एक पैकेज अभी सौंपा जाना है। 622 किमी लंबाई के 26 पैकेजों के कार्यों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पूर्व पश्चिम महामार्ग के लिए असम में विल्लंगम से मुक्त भूमि सौंपी गई भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	असम
1	2
2006-07	633.65 हैक्टेयर
2007-08	329.01 हैक्टेयर
2008-09	249.23 हैक्टेयर
2009-10	37.78 हैक्टेयर
जोड़	1249.67 हैक्टेयर

(ग) श्रीरामपुर से सिल्चर तक महामार्ग के चालू 26 पैकेजों के कार्यों को दिसंबर, 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बालचेरा से हरंगजो तक 31 किमी के पैकेज को पूरा करने का कार्य, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा दी जाने वाली अनुमति में लगने वाले समय पर निर्भर करता है क्योंकि यह खंड बोरैल वन्य जीव अभयारण्य से गुजरता है और इसलिए इस पैकेज को पूरा करने की लक्ष्य तिथि के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

विवरण

श्रीरामपुर-सिल्चर गलियारे की स्थिति

क्र.सं.	ठेका खंड	पैकेज नं.	रारा सं.	लंबाई (किमी)	कार्य शुरू होने की तारीख	भौतिक प्रगति (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	सिलचर से बालाचेरा खंड के किमी 306.54-किमी 275 तक चार लेन बनाना	[एएस-1]	54	25.88	सितंबर, 2004	42.6
2.	हरंगजो जतिंगा खंड के किमी 190.587-किमी 165.4 तक चार लेन बनाना	[एएस-21]	54	25.19	जनवरी, 2007	2.19
3.	जतिंगा से नरीमबंगलो खंड के किमी 165.4-किमी 140.7 तक चार लेन बनाना	[एएस-22]	54	23.38	जनवरी, 2007	0.1
4.	नरीमबंगलो से मैबंग खंड के किमी 140.70-किमी 127 तक चार लेन बनाना	[एएस-23]	54	15.57	अगस्त, 2006	20.22
5.	मैबंग से लुमडिंग खंड के किमी 127-किमी 111 तक चार लेन बनाना	[एएस-24]	54	16	मई, 2006	1.28
6.	मैबंग से लुमडिंग खंड के किमी 111-किमी 83.40 तक चार लेन बनाना	[एएस-25]	54	27.6	अक्तूबर, 2006	1.79
7.	मैबंग से लुमडिंग खंड के किमी 83.40-किमी 60.50 को चार लेन बनाना	[एएस-26]	54	22,9	मई, 2006	6.65

1	2	3	4	5	6	7
8.	मैबंग से लुमडिंग खंड के किमी 60.5-किमी 40 तक चार लेन बनाना	[एएस-27]	54	20.5	अक्तूबर, 2006	3.71
9.	लंका बाइपास सहित लंका से लुमडिंग खंड किमी 40.0 से किमी 22.00 तक चार लेन बनाना	[एएस-15]	54	18.5	मार्च, 2008	7.48
10.	4.2 किमी लंबाई के बाइपास और लुमडिंग से दाबोका खंड के किमी 22.0 से किमी 2.40 तक चार लेन बनाना	[एएस-16]	54	24	दिसंबर, 2005	62.41
11.	दाबोका से नगांव खंड के किमी 36.0 से किमी 5.5 तक चार लेन बनाना	[एएस-17]	36	30.5	दिसंबर, 2005	51.76
12.	नगांव बाइपास का निर्माण और नगांव से धरमतुल खंड के किमी 262.725 से किमी 255.00 तक चार लेन बनाना	[एएस-18]	37	23	दिसंबर, 2005	75.06
13.	नगांव से धरमतुल खंड के किमी 255.05 से किमी 230.50 तक चार लेन बनाना	[एएस-02]	37	25	दिसंबर, 2005	30.01
14.	धरमतुल से सोनापुर खंड के किमी 230.50 से किमी 205.00 तक चार लेन बनाना	[एएस-19]	37	25	दिसंबर, 2005	31.26
15.	धरमतुल से सोनापुर खंड के किमी 205.00 से किमी 183.00 तक चार लेन बनाना	[एएस-20]	37	22	नवंबर, 2005	20.00
16.	सोनापुर से गुवाहाटी खंड के किमी 183.00-किमी 163.90 तक चार लेन बनाना	[एएस-3]	37	19	सितंबर, 2005	16.00
17.	गुवाहाटी से नलबाड़ी खंड के किमी 1121 से किमी 1093 तक चार लेन बनाना	(एएस-4)	31	28	दिसंबर, 2005	20.70
18.	गुवाहाटी से नलबाड़ी खंड के किमी 1093 से किमी 1065 तक चार लेन बनाना	(एएस-5)	31	28	अक्तूबर, 2005	34.26
19.	नलबाड़ी से बिजनी खंड के किमी 1065.00 से किमी 1040.30 तक चार लेन बनाना	(एएस-6)	31	25	नवंबर, 2005	37
20.	नलबाड़ी से बिजनी खंड के किमी 1040.30 से किमी 1013.00 तक चार लेन बनाना	(एएस-7)	31	27.3	अक्तूबर, 2005	21.16

1	2	3	4	5	6	7
21.	किमी 1121-1126 तक ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल का निर्माण	(एएस-28)	31	5	अक्तूबर, 2006	18
22.	नलबाड़ी से बिजनी खंड के किमी 1013.00 से किमी 983.00 तक चार लेन बनाना	[एएस-8]	31	30	दिसंबर, 2005	60.49
23.	नलबाड़ी से बिजनी खंड के किमी 983.00 से किमी 961.50 तक चार लेन बनाना	[एएस-9]	31	21.5	दिसंबर, 2005	49.74
24.	बिजनी से प बं खंड के किमी 93.0-किमी 60.00 तक चार लेन बनाना	[एएस-10]	31-सी	33	नवंबर 2005	18.37
25.	बिजनी से प बं सीमा खंड के किमी 60.0-किमी 30.00 तक चार लेन बनाना	[एएस-11]	31-सी	30	नवंबर, 2005	19.55
26.	बिजनी से श्रीरामपुर खंड के किमी 30.0-किमी 0.00 तक चार लेन बनाना	[एएस-12]	31-सी	30	नवंबर, 2005	20.85

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर बाई-पास

2243. योगी आदित्यनाथ :
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-28 सहित विभिन्न राज्यों के अनेक राजमार्गों पर बाई-पास के शुरू किये गये कार्य में विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह : (क) और (ख) यह मंत्रालय, मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है और राष्ट्रीय राजमार्गों से इतर सड़कें संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 26 स्वतंत्र बाइपासों और उत्तर प्रदेश में रारा-28 पर 3 बाइपासों, जो 4/6 लेन बनाने की परियोजनाओं का हिस्सा हैं, का कार्य नियत समय से पीछे चल रहा है। अलग-अलग पैकेजों और स्वतंत्र बाइपासों के विलंब के कारणों में शामिल हैं-भूमि अधिग्रहण में विलंब, अतिक्रमण हटाने में विलंब ठेकेदार द्वारा धीमी गति से सामग्री जुटाना, सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब, ठेकेदारों द्वारा अपेक्षित स्तर का कार्य निष्पादन न करने के कारण कतिपय ठेकों को समाप्त किया जाना आदि।

(ग) परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों में विभिन्न स्तरों पर नियमित निगरानी, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, सुविधाओं के स्थानांतरण तथा विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में समन्वय के लिए प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी की नियुक्ति, भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, ठेकेदारों को अग्रिम राशि प्रदान करना और गैर-निष्पादक ठेकेदारों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किया जाना शामिल है।

[अनुवाद]

बीजों और उर्वरकों का प्रावधान

2244. श्री यशवंत सिन्हा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किसान बीजों एवं उर्वरकों को प्राप्त करने के हकदार है;

(ख) यदि हां, तो झारखंड सहित देश में किसानों को कितनी मात्रा में बीजों और खादों का वितरण किया गया हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस मिशन के अंतर्गत कितने किसानों को लाभ मिला है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) (और (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएस) तीन घटकों अर्थात एनएफएसएस-चावल, एनएफएसएम-गेहूं तथा एनएफएसएस-दलहन के साथ अक्टूबर, 2007 से प्रचालन में है। वर्तमान में, यह स्कीम झारखंड सहित 17 राज्यों में कार्यान्वयनाधीन है। झारखंड में, केवल एनएफएसएम-चावल का कार्यान्वयन किया जा रहा है। स्कीम के अंतर्गत, किसान बीजों तथा सूक्ष्म पोषक-तत्वों की खरीद हेतु सहायता लेने के पात्र हैं। झारखंड सहित कार्यान्वियक राज्यों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टें दर्शाती हैं कि वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान किसानों के बीच चावल, गेहूं तथा दलहनों के 42.6 लाख क्विंटल बीजों का वितरण किया गया है। इसी तरह से इसी अवधि के दौरान लगभग 16.9 लाख है. क्षेत्र में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग किया गया है।

(ग) एनएफएसएम के कार्यान्वयन के पिछले दो वर्षों के दौरान बीजों और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से लगभग 72 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। जहां तक वर्तमान वर्ष (2009-2010) का संबंध है, चूंकि यह कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, इस लिए वर्ष के समाप्त होने पर अर्थात् 2010 के पश्चात् इसका आकलन किया जा सकता है।

[हिन्दी]

खेलों के लिए अवसंरचना का विकास

2245. श्री जगदानंद सिंह :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार सहित विभिन्न राज्यों में खेलों की अवसंरचना की अत्यंत कमी है जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते हैं एवं अपनी क्षमता का पूरा विकास नहीं कर पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

(ग) अवसंरचना के विकास हेतु चल रही परियोजनाओं, उनकी वर्तमान स्थिति और प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण का विचार बिहार सहित विभिन्न राज्यों में अवसंरचना सुविधाएं बढ़ाने और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) देश में खेलों के विकास एवं संवर्धन हेतु सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यकरण से संबंधित अनेक शिकायतें मिली हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल) : (क) से (च) खेल अवसंरचना की अपर्याप्तता की समस्या, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस समस्या का समाधान करने की दृष्टि से भारत सरकार ने पहली बार, ''पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका)'' नामक राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 1500 करोड़ रु. का परिव्यय उपलब्ध कराया है। इस स्कीम के तहत लगभग 2.50 लाख ग्राम पंचायतों तथा 6400 ब्लाक पंचायतों (उनके समकक्ष यूनिटों को सम्मिलित करके) को चरणरबद्ध तरीके से बुनियादी खेल अवसंरचना उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। खेल सुविधाओं के सृजन के साथ-साथ, इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारों को ब्लाक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर खेल स्पर्धाओं के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। 2008-09 के दौरान,

23,000 ग्राम पंचायत केन्द्रों और 600 ब्लाक पंचायतों के लिए 251 करोड़ रु. अनुमोदित किए गए थे, इसमें से पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 92 करोड़ रु. वितरित किए जा चुके हैं। ऐसी आशा की जाती है कि इस स्कीम से खेलों में न केवल बड़े पैमाने पर प्रतिभागिता को बढ़ावा मिलेगा वरन इससे छिपी हुई प्रतिभाओं का विस्तार भी होगा जिससे अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन हो सकेगा।

2008-09 के दौरान बिहार राज्य सहित जारी की गई संस्वीकृतियों तथा निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) और (ज) हजारी बाग भा.खे.प्रा. केन्द्र के ठीक रूप में कार्य न करने के बारे में कुछ समय पहले एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो निरीक्षण करने पर सही नहीं पायी गई।

विवरण

2008-09 के दौरान पीवाईकेकेए योजना के अंतर्गत राज्यों को स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता तथा जारी की गई धनराशि

'क' अवसंरचना विकास

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की की सं.	अनुमोदित ब्लाक पंचायतों की सं.	स्वीकृत कुल धनराशि	2008-09 के दौरान जारी की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2190	113	25.98	12.99
2.	असम	333	22	4.81	*
3.	बिहार	847	53	10.44	5.22
4.	छत्तीसगढ़	982	14	10.11	*
5.	गोवा	19	4	0.35	*
6.	गुजरात	1369	22	14.20	
7.	हरियाणा	619	12	6.51	3.26
8.	हिमाचल प्रदेश	324	8	4.02	2.01
9.	जम्मू और कश्मीर	413	14	5.32	2.66
10.	केरल	100	15	1.60	0.80
11.	मध्य प्रदेश	2304	31	23.65	11.82
12.	महाराष्ट्र	2689	35	27.55	8.91
13.	मणिपुर	79	4	1.08	0.87
14.	मिजोरम	82	3	1.07	0.85
15.	नागालैंड	110	5	1.48	1.18
16.	उड़ीसा	623	31	7.34	3.67
17.	पंजाब	1233	14	12.55	6.27
18.	राजस्थान	869	24	9.43	3.71
19.	सिक्किम	16	10	0.67	0.54
20.	तमिलनाडु	1261	38	13.82	5.00
21.	त्रिपुरा	104	4	1.36	1.09
22.	उत्तर प्रदेश	5203	82	53.91	10.00
23.	उत्तराखंड	750	10	8.89	3.00
24.	पश्चिम बंगाल	375	33	4.63	*
	कुल	22,854	601	250.77	83.85

*राज्य जिन्होंने आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं की अर्थात राज्यों के बजट आदि में राज्यों के हिस्से का प्रावधान नहीं किया।

'ख' खेल प्रतियोगिताएं - 2008.09 के दौरान प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए उपर्युक्त धनराशि के अतिरिक्त भारतीय खेल प्राधिकरण को 8.15 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

2008-09 के दौरान कुल धनराशि का उपयोग =

83.85 करोड़ रु. + 8.15 करोड़ रु. = 92 करोड़ रु.

[अनुवाद]

कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता

2246. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कृषि योग्य उपलब्ध भूमि का राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कृषि भूमि को उद्योग के लिए उपयोग करने हेतु परिवर्तन को अनुमति देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) उपलबध अनुमानों के अनुसार, देश में कुल कृष्य भूमि 182.71 मिलियन हैक्टेयर (2006-07) है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'भूमि' संबंधी विषय राज्य सरकारों के दायरे में आता है और इसीलिए यह राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वे कृषि भूमि के अन्यत्र कार्यों में उपयोग और भूमि उपयोगों के परिवर्तन किए जाने से रोकने के लिए उपयुक्त विधान बनाएं।

विवरण

कृष्य भूमि का राज्यवार क्षेत्र

(क्षेत्र हजार हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कृष्य भूमि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	15911.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	422.00
3.	असम	3224.00
4.	बिहार	6638.00
5.	छत्तीसगढ़	5581.00
6.	गोवा	197.00
7.	गुजरात	12412.00
8.	हरियाणा	3782.00
9.	हिमाचल प्रदेश	813.00
10.	जम्मू और कश्मीर	1048.00
11.	झारखंड	4184.00
12.	कर्नाटक	12894.00
13.	केरल	2329.00
14.	मध्य प्रदेश	17312.00
15.	महाराष्ट्र	21162.00
16.	मणिपुर	231.00
17.	मिजोरम	213.00
18.	मेघालय	1057.00
19.	नगालैंड	657.00
20.	उड़ीसा	7473.00
21.	पंजाब	4270.00
22.	राजस्थान	25600.00
23.	सिक्किम	155.00

1	2	3
24.	तमिलनाडु	8148.00
25.	त्रिपुरा	310.00
26.	उत्तर प्रदेश	19268.00
27.	उत्तराखंड	1504.00
28.	पश्चिम बंगाल	5751.00
29.	दिल्ली	54.00
30.	पुदुचेरी	31.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	47.00
32.	चंडीगढ़	2.00
33.	दादरा और नगर हवेली	24.00
34.	दमन और दीव	3.00
35.	लक्षद्वीप	3.00
	कुल	182710.00

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित कृषि सांख्यिकी एक नजर में-2008

खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत

2247. श्री भर्तृहरि महताब : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की खपत गिर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खाद्यान्नों की खपत को बढ़ावा देने तथा देश में खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट संख्या 509 में निहित विभिन्न वस्तुओं की पारिवारिक खपत से संबंधित उपभोक्ता व्यय आंकड़े के अनुसार यह देखा गया है कि 1993-94 और 2004-05 के बीच अनाजों और दालों की प्रति व्यक्ति खपत में गिरावट आई है। 30 दिन में प्रति व्यक्ति किलोग्राम में उपभोग की मात्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	ग्रामीण		शहरी	
	अनाज	दाल	अनाज	दाल
1993-94	13.4	0.76	10.6	0.86
2004-05	12.12	0.71	9.94	0.82

खाद्यान्न की खपत के पैटर्न में परिवर्तन का कारण आय में परिवर्तन, स्वाद और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों सहित पसन्द में परिवर्तन, खाद्य वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्य आदि जैसे कई घटक हैं।

देश की लक्षित गरीब आबादी की खपत के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु सरकार 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन करती है। केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए भी खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन इन खाद्यान्नों की आपूर्ति केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर की जाती है जो अत्यधिक राजसहायता प्राप्त और खुले बाजार मूल्यों से कम होते हैं।

उपर्युक्त के अलावा सरकार विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन करती है, जिनमें अन्नपूर्णा योजना, मध्याह्न भोजन योजना, गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम, किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम और ग्रामीण अनाज बैंक की स्कीम शामिल हैं। स्कीमों का उद्देश्य लक्षित आबादी के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करना है, ताकि वे अपना उपभोग स्तर बढ़ा सकें।

[हिन्दी]

पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत सृजित रोजगार

2248. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री भक्त चरण दास :
श्री जयवंत गंगाराम आवले :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.आई.जी.पी.) के अंतर्गत राज्य-वार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों सहित कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कुल कितनी राशि आबंटित की गई;

(ग) क्या पूर्ण आबंटित राशि संवितरित की गई तथा उपयोग में लाई गई;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा आबंटित पूरी राशि के संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि शिक्षित बेरोजगार युवक पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत लाभों को प्राप्त कर पाने में असमर्थ हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस योजना को अधिक कारगार बनाने के लिए इस पर क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय में संघ सरकार ने, इस मंत्रालय में विद्यमान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) तथा प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमआरवाई) नामक रोजगार सृजन कार्यक्रम का विलय करके वर्ष 2008-09 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) प्रारंभ किया है। बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज के लिए 250 करोड़ रुपये सहित कुल 4735 करोड़ रुपये की प्रस्तावित योजना परिव्यय सहित वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान लगभग 38 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने के लिए पूर्व के उपर्युक्त दो कार्यक्रमों की तुलना में लाभार्थियों को उच्चतर स्तर की सब्सिडी वाला यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा/व्यापार क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक की लागत वाले तथा विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख की लागत वाले प्रत्येक सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए बेरोजगार युवा सहित उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विशेष घटक उप-योजना (एससीएसपी), आदिवासी उप-योजना (टीएसपी) इत्यादि के संबंध में निम्नलिखित ब्रेकअप सहित वर्ष 2008-09 के दौरान केवीआईसी को मंत्रालय द्वारा (बैकवर्ड फारवर्ड लिंकेज के लिए 83 करोड़ रुपये सहित) 823 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी:-

(करोड़ रुपयों)

गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र	547.05
पूर्वोत्तर क्षेत्र	85.00
विशेष घटक उप-योजना	123.45
आदिवासी उप-योजना	67.50
कुल योग	823.00

इसके अतिरिक्तए अगस्त, 2008 में पीएमईजीपी को अनुमोदित किया गया। पीएमईजीपी के विस्तृत दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाईट : www.msme.gov.in पर उपलब्ध हैं। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों तथा देश के आम चुनाव, 2009 के कारण मॉडल आचार संहिता के लागू होने के मद्देनजर जिला कार्यबल समितियां (डीटीएफसी) यथासमय गठित नहीं की जा सकीं तथा 2008-09 के दौरान प्राप्त हुए सभी 217762 आवेदनों पर डीटीएफसी द्वारा जांच नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप वर्ष 2008-09 के लिए आबंटित समग्र मार्जिन मनी का 31 मार्च, 2009 तक पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका। कार्यान्वयन अभिकरणों को केवीआईसी द्वारा आबंटित मार्जिन मनी सब्सिडी, उसकी उपयुक्तता तथा वर्ष 2008-09 के दौरान एस.सी, एस.टी. और ओ.बी.सी. सहित सृजित (अनंतिम) आकलित रोजगार अवसरों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) वर्ष 2008-09 में उपलब्ध प्रभावी अवधि के मात्र कुछ महीनों में ही प्राप्त हुए 2.17 लाख आवेदनों के रूप में आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया सृजित की गई है जिसमें शिक्षित बेरोजगार

युवा भी शामिल हैं। एमएसएमई मंत्रालय अभी भी उन निम्नलिखित कारणों से अवगत नहीं है कि पीएमईजीपी के तहत लाभान्वित होने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवा क्यों सक्षम नहीं है। इस स्कीम की प्रगति की, नोडल अभिकरण अर्थात् केवीआईसी तथा मंत्रालय में राष्ट्रीय स्तरीय मानिटरिंग समिति द्वारा नियमित रूप से मानिटरिंग की जा रही है। राज्य सरकारों को भी अपने स्तर पर स्कीम के कार्यान्वयन की निकट से मानिटरिंग करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

2008-09 में पीएमईजीपी के तहत मार्जिन मनी आबंटन तथा सृजित रोजगार की अनुमानित संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आबंटित मार्जिन मनी (लाख रुपये)	शामिल मार्जिन मनी *(लाख रुपये)	सृजित अनुमानित रोजगार* (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3	4	5
1.	छत्तीसगढ़	1736.78	1942.19	10780
2.	मध्य प्रदेश	3695.85	1351.48	6280
3.	उत्तरांचल	1162.25	466.77	3780
4.	उत्तर प्रदेश	11768.96	10660.40	44140
5.	संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़	59.94	8.09	310
6.	दिल्ली	285.51	4.15	50
7.	हरियाणा	1431.16	1437.76	8210
8.	हिमाचल	452.14	452.11	3400
9.	जम्मू और कश्मीर	1300.00	1452.17	18210
10.	पंजाब	1800.00	1407.93	8870
11.	राजस्थान	3313.19	1461.95	7030
12.	गोवा	86.59	12.95	70
13.	गुजरात	3460.98	445.22	3070
14.	दादरा और नगर हवेली	13.32	0	0
15.	दमन और दीव	13.32	2.71	60
16.	महाराष्ट्र	6628.91	4192.19	33680
17.	आंध्र प्रदेश	5319.86	2605.60	9030
18.	कर्नाटक	3571.24	3246.82	24230
19.	केरल	2123.80	610.79	3890
20.	लक्षद्वीप	6.66	5.33	40
21.	पुदुचेरी	59.94	15.96	420
22.	तमिलनाडु	4220.23	2926.56	14730
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	46.25	2.36	80
24.	बिहार	5152.18	4524.59	67410
25.	झारखंड	2366.52	1128.00	9400
26.	उड़ीसा	2946.68	3004.88	19760
27.	पश्चिम बंगाल	6500.00	6465.81	56670
28.	अरुणाचल प्रदेश	205.72	95.00	1300
29.	असम	2050.54	525.16	7280
30.	मणिपुर	188.25	1.80	30
31.	मेघालय	483.96	3.00	30
32.	मिजोरम	238.28	71.23	230
33.	नागालैंड	430.68	61.08	310

1	2	3	4	5
34.	त्रिपुरा	472.12	4.30	50
35.	सिक्किम	125.80	6.70	40
	कुल	73717.61	50603.04	362870

*अनंतिम

बिहार में पूर्व-पश्चिम गलियारा

2249. श्री मंगनी लाल मंडल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पूर्व-पश्चिम गलियारे के निर्माण कार्य की प्रगित संतोषजनक है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-57 के निर्माण कार्य में शामिल एजेंसियां परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए यथेष्ट कार्यवाही कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कोशी नदी के तट के किनारे किया गया निर्माण कार्य असंतोषजनक है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) बिहार में पूर्व-पश्चिम महामार्ग के निर्माण कार्य में विलंब हुआ है और यह विलंब मुख्यत: भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों की कटाई, वर्ष 2007 और 2008 के दौरान अभूतपूर्व बाढ़ और ठेकेदारों द्वारा घटिया कार्य-निष्पादन के कारण हुआ है।

(ग) और (घ) बिहार में रा रा - 57 के मुज्जफरपुर से पूर्णिया खंड को पूर्व-पश्चिम महामार्ग (एनएचडीपी चरण-II) के अंतर्गत चार लेन का बनाने की परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है किन्तु इनमें विलंब मुख्यत: भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों की कटाई, वर्ष 2007 और 2008 के दौरान बिहार में अभूतपूर्व बाढ़ और ठेकेदारों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुआ है। इस समय निर्माण कार्य में लगी सभी फर्मों और एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) और (च) जी नहीं। कोसी नदी के गाइड बंद और एफ्लक्स बंद, पहुंच मार्गों सहित इस नदी पर पुल के निर्माण कार्य की ध्यानपूर्वक निगरानी के लिए भा.रा.रा.प्रा. के परियोजना निदेशक के परामर्श से आवधिक नियंत्रण जांच के द्वारा कार्य की गुणता का पर्यवेक्षण करने के लिए स्वतंत्र परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और गुणता बनाए रखने के लिए स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा इन परियोजनाओं की दिन-प्रतिदिन प्रगति की निगरानी रखी जा रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-8 का गांधीधाम-मुंद्रा खंड

2250. श्री हरिन पाठक : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 गांधीधाम-मुंद्रा खंड को चार लेन का बनाए जाने के कार्य को शुरू करने तथा पूरा करने की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा अधियोजित समय-सारणी क्या है;

(ख) क्या इस खंड को सरकारी निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) पद्धति से विकसित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) इस परियोजना को 910 दिनों की निर्माण अवधि के साथ वर्ष 2009-10 के दौरान सौंपे जाने का लक्ष्य है।

(ख) जी हां। बीओटी (पथकर) आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि से विकसित किए जाने वाले इस खंड के लिए रियायतग्राही की पूर्व-अर्हता का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) रारा-8ए (विस्तार) के गांधीधाम-मुंद्रा खंड को चार लेन का बनाए जाने के लिए साध्यता-सह-प्राथमिक डिजाइन रिपोर्ट तैयार

कर ली गई है। परियोजना प्रस्ताव, सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति को अनुमोदनार्थ भेज दिया गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात्, कार्य को सौंपे जाने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध, पूर्व-अर्हता प्राप्त निविदादाताओं से आमंत्रित किया जाएगा।

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान

2251. **श्री अवतार सिंह भडाना : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को विशेष अनुदान प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के लिए विशेष अनुदान प्रदान करने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एफ.सी.आई. के गोदामों में जमाखोरी

2252. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदामों का जमाखोरी तथा कालाबाजारी के लिए दुरुपयोग किए जाने की घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए (एफ. सी.आई.) के गोदामों पर नियमित रूप से छापे मारे जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं। इस बारे में ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खनिजों पर रायल्टी

2253. **श्री चंद्रकांत खैरे : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायल्टी भुगतान में संशोधन कर इसे बढ़ाए जाने के परिणामस्वरूप बाजार में उस वस्तु/खनिज अयस्क के मूल्य में वृद्धि होगी;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किस तरीके से लौह/अलौह तथा अन्य कंपनियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की मूल्य वृद्धि पर निगरानी रखने का प्रस्ताव है; और

(ग) खनिजों पर रायल्टी की नई प्रणाली की स्थिति में कितना अतिरिक्त राजस्व सृजन होने की संभावना है?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) से (ग) रायल्टी दरों में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। संशोधन के प्रभाव का आकलन और मात्रा का निर्धारण सरकार द्वारा किसी संशोधन के यथोचित रूप से अनुमोदन/अधिसूचित करने के बाद ही किया जा सकता है। वर्तमान में, राज्य सरकारें 14.10.2004 को सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार रायल्टी वसूल रही हैं।

[हिन्दी]

सी.आर.पी.एफ. कार्मिकों को चिकित्सा सहायता

2254. **श्री रमेश बैस :**
श्री राधा मोहन सिंह :

श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :
श्री बाल कुमार पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) कार्मिकों के स्वास्थ्य की समय-समय पर जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कई कार्मिक कैंसर, अत्यधिक तनाव, एच.आई.वी., हृदय संबंधी तथा मानसिक रोगों सहित गंभीर स्वास्थ्य रोगों से ग्रस्त पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे रोगों के कारण मरने वाले कार्मिकों की संख्या सहित इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कार्मिकों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का समाधान करने तथा उन्हें समुचित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी हां। सी.आर.पी.एफ. कार्मिकों की वार्षिक चिकित्सा जांच के माध्यम से समय-समय पर स्वास्थ्य की जांच की जाती है तथा पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण के दौरान भी समय-समय पर चिकित्सा जांच की जाती है।

(ग) कुछ कार्मिक कैंसर, अत्यधिक तनाव, एच.आई.वी, हृदय संबंधी तथा मानसिक रोगों से ग्रस्त है।

(घ) वर्ष 2008 में मरने वाले मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

रोग	मौतें
कैंसर	26
अत्यधिक तनाव	19
एचआईवी/एड्स	26
हृदय रोग	83
मानसिक रोग	15

(ङ)(i) यूनिट होस्पिटलों से प्राइमरी मेडिकल कवर, आवधिक और वार्षिक चिकित्सा जांच से नियमित जांच, अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल और उसमें अनुवर्तन हेतु विशेषज्ञ के अनुमोदन के साथ कम्पोजिट होस्पिटलों के माध्यम से सैकेण्डरी हेल्थ केयर।

(ii) एचआईवी/एड्स के रोगियों के उपचार हेतु तीन एंटी रेटरोवायरल ट्रिटमेंट सेंटरों (ए.आर.टी.), एचआईवी/एड्स काउंसलरों को प्रशिक्षित करने के लिए तीन संयुक्त प्रशिक्षण केन्द्रों तथा नियमित एचआईवी/एड्स की जांच के लिए 64 वी.सी.सी.टी. के सेंटरों की स्थापना करना।

(iii) चिकित्सा अधिकारी और कमांडेंट, जवानों के साथ लगातार परस्पर संवाद करते रहते है तथा एचआईवी/एड्स और एमटीडी के विरुद्ध रोगनिरोधी उपायों पर जवानों को शिक्षा देते रहते है।

(iv) बेहतर तनाव प्रबंधन के लिए योग कक्षाएं शुरू की गई है।

(v) मनोरंजनात्मक और खेल सुविधाएं शुरू की गई है।

(vi) जवानों और उनके परिवारों हेतु मूलभूत सुविधाएं शुरू की गई है।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग

2255. **डॉ. भोला सिंह :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 107 के कई खंडों तथा इन पर निर्मित पुल सहित राष्ट्रीय राजमार्ग जीर्ण-शीर्ण दशा में हैं जिसके परिणामस्वरूप यातायात के सुचारु प्रवाह में बाधा आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इनकी मरम्मत के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या बिहार में एन.एच.ए.आई. की पटना-बक्सर तथा खगड़िया-बख्तियारपुर सड़क परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति सामान्यत: यातायात योग्य है। जहां तक राट्रीयराजमार्ग-107 का संबंध है कुछ सड़क खंडों और कुछ पुलों में सुधार/पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। ये कार्य, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं। कोशी नदी में बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-107 पर हुई क्षति की मरम्मत और पुनरुद्धार के लिए 4.47 करोड़ रुपए की अनुमानित धनराशि 2008-2009 में स्वीकृत की गई थी।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत चार लेन बनाने के लिए पटना-बक्सर और खगड़िया-बख्तियारपुर खंडों की पहचान की गई थी। हालांकि बीओटी (पथकर) के अधीन अर्हता के लिए अनुरोध दो बार 24.05.2008 और 19.01.2009 को आमंत्रित किए गए थे परन्तु बोलीदाताओं से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। प्रस्ताव की पुनर्संरचना का निर्णय लिया गया है। इस कार्य के पूरा किए जाने की संभावित तारीख बता पाना अभी संभव नहीं है।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानियों की पहचान

2256. श्रीमती जयाप्रदा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों की पहचान करने के लिए केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राज्य-वार क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या 6 महीने से कम समय तक कारावास में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्रीय योजनाओं का कोई लाभ नहीं दिया जाता हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) केन्द्रीय स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत पात्रता मानदण्डों में, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल है कम से कम छह माह (महिलाओं तथा अजा/अजजा स्वतंन्त्रता सेनानियों के मामलों में तीन माह) का कारावास/भूमिगत प्रताड़ना, कम से कम छह माह के लिए घर में नजरबंदी/जिले से निकासी, सम्पत्ति को जब्ती, स्थाई अशक्तता या कार्य क्षति, जो राष्ट्रीय स्वतंन्त्रता संग्राम के संबंध में दावाकर्ता को सहन करनी पड़ी।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के तहत स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले पात्रता मानदंड अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सैनानी एवं उनके परिवार को पेंशन नियमावली 1975 के नियम 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण दो माह के कारावास की सजा काटी हो या जो तीन माह के लिए घर में नजरबंद या जेल में विचारणाधीन कैदी रहा हों या जिसे दस बेंत मारने की सजा दी गई हो या जिसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया हो या गोलीवारी में जख्मी हो गया हो या जो शहीद हो गया हो उसे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में माना जाएगा। इन नियमों में आगे प्रावधान है कि अन्य लोग जिन्हें अलग-अलग समय पर अल्पावधि के लिए नजरबंद या विचारणाधीन कैदी बना के रखा गया हो, उन्हें भी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि नजरबंदी अथवा विचाणाधीन कैदी की कुल अवधि तीन माह या उससे अधिक हो।

(ख) और (ग) कुछ आन्दोलनों के मामले में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पैंशन योजना, 1980 के लिए पात्रता शर्त में इन आन्दोलनों की विशेष परिस्थितियों के आधार पर छूट दी गई है।

[हिन्दी]

फसल क्षेत्र में कमी

2257. श्री संजय सिंह चौहान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा किए गए आकलन के अनुसार आगामी खरीफ मौसम के दौरान की जाने वाली फसलों की बोआई के कुल क्षेत्र में कमी आने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो मानसून के आने में विलम्ब के कारण खरीफ फसल की बोआई के कुल क्षेत्र में प्रतिशत तथा हैक्टेयर के रूप में कितनी कमी दर्ज किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या इन प्रभावित राज्यों की पहचान की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रारम्भिक सूचनाओं के अनुसार, चालू खरीफ मौसम के दौरान अब तक बोया गया क्षेत्र गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान बोए गए 524.84 लाख हैक्टेयर की तुलना में 480.32 लाख हैक्टयेर है। तथापि, खरीफ फसलों के अंतर्गत आने वाले सामान्य क्षेत्र का लगभग 46% ही अब तक बोया गया है और इस प्रकार अब तक, क्षेत्र व्याप्ति में गिरावट की सूचना देने वाले प्रमुख राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश हैं। जून, 2009 के गत सप्ताह में मानसून के पुन: सक्रिय होने के साथ ही, प्रमुख फसल उत्पादक राज्यों में बुआई के कार्य ने जोर पकड़ लिया है तथा खरीफ फसलों की क्षेत्र व्याप्ति में उल्लेखनीय अन्तरण नहीं होने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

टी.पी.डी.एस. संबंधी अभिजीत सेन समिति

2258. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभिजीत सेन समिति ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) को समाप्त किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशों के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) देश के लिए दीर्घकालिक अनाज नीति तैयार करने हेतु प्रो. अभिजीत सेन, तत्कालीन अध्यक्ष, कृषि लागत और मूल्य आयोग, की अध्यक्षता में 16 नवम्बर, 2000 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था जिसने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि अधिग्रहण लागत के आधार पर केन्द्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित करके एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली तत्काल शुरू की जानी चाहिए।

तथापि, सरकार द्वारा यह महसूस किया गया कि चूंकि पूर्व की सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पर्याप्त ध्यान भुखमरी पर केन्द्रित नहीं था और शहरों की ओर इसका झुकाव था, इसलिए समाज के कमजोर वर्गों को लक्षित करने की दृष्टि से जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की थी। अत: यह महसूस किया गया था कि सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ध्यान गरीबों की जरूरत पूरी करने पर से हट जाएगा।

(ग) उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई 13 प्रमुख सिफारिशों के क्रियान्वयन पर स्थिति रिपोर्ट संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उच्च स्तरीय समिति ने 22 जुलाई, 2002 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य सिफारिशें और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार है। 13 मुख्य सिफारिशों में से भारत सरकार ने 10 को स्वीकार कर लिया है और 3 को स्वीकार नहीं किया है।

क्रम सं.	दीर्घकालीन अनाज नीति के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की मुख्य सिफारिशें	की गई कार्रवाई की स्थिति	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	अधिक सक्षम क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण उत्पादन की सी-2 लागत (सभी लागतों में पारिवारिक श्रम की आरोपित लागत, अपनी पूंजी तथा भूमि पर किराया शामिल है) के आधार पर किया जाना चाहिए।	स्वीकार नहीं किया गया।	सरकार ने यह निर्णय लिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा प्रणाली जारी रहनी चाहिए।

1	2	3	4
2.	केन्द्रीय सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करों और लेवी का अधिकतम 4 प्रतिशत भुगतान करना चाहिए।	आंशिक रूप से स्वीकृत।	पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, जहां राज्य कर और लेवी अधिक (10 प्रतिशत से अधिक) है, की राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कर संबंधी प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। तथापि, इसे उक्त राज्यों सरकारों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।
3.	भारतीय खाद्य निगम को पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में खरीद छोड़ देनी चाहिए और पूर्वी तथा मध्य भारत में अपनी जनशक्ति तैनात करनी चाहिए।	स्वीकृत	भारतीय खाद्य निगम धीरे-धीरे पंजाब और हरियाणा से अपनी जनशक्ति कम करेगा और उसे पूर्वी और मध्य भारत में तैनात करेगा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार में धीरे-धीरे खरीद बढ़ी है।
4.	विकेन्द्रीकृत खरीद योजना में संशोधन करना चाहिए और उसे राज्य सरकारों के लिए अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।	स्वीकृत	विभाग ने विकेन्द्रीकृत खरीद को आकर्षक बनाने के लिए पहले से ही कार्रवाई कर दी है। खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद की प्रणाली को 11 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।
5.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज की सभी प्रकार की खरीद में एफ.ए.क्यू. मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।	स्वीकृत	खरीद करने वाली एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे एफ.ए.क्यू. खाद्यान्नों की खरीद करें। केवल आपवादिक मामलों में, राज्य सरकारों के अनुरोध पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्टियों में ढील दी जाती है ताकि किसानों द्वारा व्यथित होकर बिक्री न की जाए।
6.	चावल के मिल मालिकों पर सभी लेवी आदेश हटा लिए जाने चाहिए।	स्वीकार नहीं किया गया।	विभाग की यह राय है कि धान की खरीद और लेवी चावल की सुपुर्दगी की दोहरी प्रणाली जारी रहनी चाहिए।
7.	न्यूनतम समर्थन मूल्य में सी-2 स्तर पर सुधार के साथ-साथ राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति पैकेज दिया जाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल वे, अन्य बातों के साथ-साथ फसलों की विविधता के लिए कर सकती हैं।	स्वीकृत	इसे कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा बनाया और कार्यान्वित किया जा रहा है।
8.	एकीकृत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए जिसमें केन्द्रीय निर्गम मूल्य का निर्धारण अधिग्रहण लागत के आधार पर किया जाए।	स्वीकार नहीं किया गया।	सरकार यह महसूस करती है कि समाज के वंचित वर्ग को लक्षित करने के उद्देश्य से जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी क्योंकि पूर्व की सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर्याप्त रूप से भूख पर केन्द्रित नहीं थी और उसका झुकाव शहरों की ओर था सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के परिणामस्वरूप गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रित नहीं रही।

1	2	3	4
9.	भारतीय खाद्य निगम को अपने कार्य का तरीका बदलने की जरूरत है ताकि वह तीव्रता से वाणिज्योन्मुख निर्णय लेने में सक्षम हो सके।	स्वीकृत	भारतीय खाद्य निगम इस निर्णय पर कार्रवाई कर रहा है।
10.	सरकार को खाद्य आधारित एक प्रमुख रोजगार कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।	स्वीकृत	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
11.	खुला बाजार बिक्री के संबंध में एक स्थिर और भविष्यवाणी करने में सक्षम नीति होनी चाहिए।	स्वीकृत	खुला बाजार बिक्री उस समय की जाती है जब केन्द्रीय पूल के स्टॉक बफर मानदंडों से अधिक रहते हैं और जब स्टॉक बफर मानदंडों से कम हो जाते हैं तब उसे रोक दिया जाता है। खुला बाजार बिक्री योजना खुले बाजार में मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता करती है।
12.	खाद्यान्नों का निर्यात पूरी तरह निजी तौर पर किया जाना चाहिए। सभी प्रकार की राजसहायता निर्यात पर केन्द्रित होनी चाहिए, सार्वजनिक स्टॉक से बिक्री पर नहीं।	स्वीकृत	वाणिज्य मंत्रालय वर्तमान में उचित योजना को अंतिम रूप दे रहा है।
13.	ढील दी गई विनिर्दिष्टियों के तहत लाए गए तीन वर्ष पुराने अनाज के सभी स्टॉकों को तुरन्त वाणिज्यिक शर्तों पर बेचा जाना चाहिए।	स्वीकृत	ऐसे स्टॉकों के निष्पादन के लिए किए गए उपायों के बाद 90 प्रतिशत से ज्यादा वर्तमान स्टॉक अब दो वर्ष से कम पुराने हैं।

[हिन्दी]

शुष्क भूमि कृषि प्रौद्योगिकी

2259. **श्री सज्जन वर्मा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई बीज नीति लाने के साथ ही मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में शुष्क भूमि कृषि के लिए नई कृषि प्रौद्योगिकी शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उपायों का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) एक नई बीज नीति लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने 1988 में नई बीज विकास नीति तैयार की थी जिसका उद्देश्य मुख्यतया विश्व में कहीं भी उपलब्ध सर्वोत्तम बीज और रोपण सामग्री तक भारतीय किसानों की पहुंच बनाना है। राष्ट्रीय बीज नीति, 2002 मंडी रुखों के अनुकूल उपजातीय विकास को प्रेरित करने के लिए उचित नीतिगत कार्य ढांचा तथा कार्यक्रमगत हस्तक्षेपों को अपनाने, वैज्ञानिक-प्रौद्योगिकीय प्रगति, जैव एवं अजैव दबावों के लिए उपयुक्तता, स्थानीय स्वीकार्यता एवं किसानों की जरूरतों पर बल देती है। सरकार ने शुष्क भूमि और वर्षा सिंचत कृषि के प्रणालीबद्ध उन्नयन एवं प्रबंधन के संबंध में ज्ञान प्रदान करने के लिए एक सलाहकारी नीति निर्माता और मानिटिरिंग निकाय के रूप में राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) का गठन किया है। एनआरएए ने आधुनिकतम पनधारा कार्यक्रमों के लिए नए कार्य ढांचे के साथ पनधारा विकास परियोजना संबंधी सामान्य दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। अंतर्निहित लचीलेपन के साथ ये दिशानिर्देश मध्य प्रदेश सहित देश में सभी पनधारा विकास परियोजनाओं के नियोजन, रूपरेखा तैयार करने, प्रबन्धन एवं कार्यान्वयन हेतु एक योग्य कार्य ढांचा प्रदान करेंगे। प्राधिकरण ने वर्षासिंचित क्षेत्रों

के विकास हेतु 'राष्ट्रीय संदर्श योजना' के लिए एक दृष्टिकोण दस्तावेज भी तैयार किया है।

[अनुवाद]

एन.एच.ए.आई. के अंतर्गत राजमार्गों संबंधी कार्य में तेजी

2260. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चरण II, III तथा IV के अंतर्गत राजमार्ग विकास का कार्य पुन: शुरू करने तथा इनमें तेजी लाने के लिए कई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा परियोजनाओं को त्वरित रूप से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों में कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। समय-समय पर प्रगति की समीक्षा और प्राप्त सुझावों के आधार पर, कार्यान्वयन के दौरान आने वाली विभिन्न कठिनाइयां अभिनिर्धारित की जाती हैं और परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं। सुपुर्दगी की विधि, पूर्व-अर्हता प्रक्रिया, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तीव्र करना और वैश्विक मंदी का प्रभाव आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें इस संबंध में अभिनिर्धारित किया गया है। सरकार का यह प्रयास रहता है कि विभिन्न परियोजनाओं का निष्पादन तीव्र करने के लिए सभी संबंधित अधिकरणों से उचित परामर्श के पश्चात् ही विभिन्न मुद्दों का निराकरण करे। परियोजनाओं को तीव्रता से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए सरकार के उपाय

(क) पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित निगरानी की जाती है। अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के स्तर पर भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है। ये नोडल अधिकारी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए समय-समय पर बैठकें करते हैं तथा समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करते हैं।

(ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केन्द्र-राज्य मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया आसान बना दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत पहले सभी अधिसूचनाओं की विधि मंत्रालय द्वारा विधीक्षा की जाती थी। हाल ही में कार्य आबंटन नियमावली में एक संशोधन किया गया है जिसके तहत इन अधिसूचनाओं को विधि मंत्रालय को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। विधि मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाओं की समान प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अधिसूचनाओं के मानक मसौदों को अनुमोदित कर दिया है।

(ङ) रेल उपरि पुलों (आर.ओ.बी.) के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके। कुछ रेल उपरि पुलों के निर्माण के लिए मै. इरकॉन इंटरनेशन लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(च) गैर-निष्पादक ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है और उन्हें तब तक भावी परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे विद्यमान ठेकों में अपने निष्पादन में सुधार नहीं कर लेते।

(छ) समाप्त कर दिए गए ठेके पुनः सौंप दिए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को चार लेन वाला बनाया गया

2261. **श्री के.पी. धनपालन :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के कार्य को त्वरित ढंग से पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर अंडरपास/क्रॉसिंगों के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव एन.एच.ए.आई. के पास लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण और ठेकेदार के घटिया कार्य निष्पादन आदि से संबंधित समस्याओं के कारण रारा-47 पर निर्माण कार्य में कुछ विलंब हुआ है। परियोजनाओं के शीघ्रता से कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और ठेकेदार के साथ, नियमित बैठकों के द्वारा कार्य-की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

(ग) और (घ) पुडुक्कड़ शहर (रारा-47 के किमी. 280/550) में भूमिगत पास बनाने के और मेलूर शहर (रारा-47 के किमी. 299/220) में मीडियन क्रॉसिंग बनाने के प्रस्तावों की तकनीकी व्यवहार्यता की जांच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।

[हिन्दी]

हथियारों के लाइसेंसों की वैधता

2262. **श्री यशवीर सिंह :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथियारों के लाइसेंसों की अखिल भारतीय वैधता के संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या आयुध अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या हथियारों के लाइसेंसों को अखिल भारतीय वैधता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों में जालसाजी किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) गृह मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 1995 में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-निषिद्ध बोर के शास्त्रों के लाइसेंसों, के क्षेत्र की वैधता बढ़ाने के अनुरोधों पर आवश्यकता की यथार्थता जिलें/राज्य में व्याप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशों के आधार पर, गुण-दोषों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाता है। निषिद्ध बोर के शस्त्रों के लाइसेंसों के संबंध में क्षेत्र की वैधता संपूर्ण भारत में बढ़ाने के अनुरोधों पर राज्य सरकार और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ परामर्श करके गुण-दोनों के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) शस्त्र नीति समीक्षाधीन है और जहां कहीं आवश्यक होगा, आवश्यक होगा, आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा शस्त्रों के लाइसेंसों के क्षेत्र की वैधता संबंधी दिशानिर्देशों की कथित जालसाजी किए जाने के बारे में श्री अशोक अर्गल, माननीय संसद सदस्य से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस मामले की जांच की गई थी। जैसा कि इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में पहले ही बता दिया गया है कि शस्त्रों के लाइसेंसों के क्षेत्र की वैधता बढ़ाये जाने के अनुरोधों पर विचार करने की शक्तियां, राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी

गई हैं। उनसे कहा गया है कि वे ऐसे अनुरोधों पर गुणदोषों के आधार पर विवेकसम्मत ढंग से विचार करें जो जरूरत की वास्तविकता, स्थानीय कारकों और राज्य में व्याप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति पर आधारित हो। इस प्रकार ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारें पूरी तरह सक्षम हैं इसलिए यह पाया गया है कि इस मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कोई जालसाजी नहीं की है। तदनुसार दिनांक 13.04.2009 को माननीय संसद सदस्य को उत्तर भेज दिया गया था।

[अनुवाद]

ऐतिहासिक स्मारकों को सुरक्षा कवर

2263. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुमायूं का मकबरा तथा लाल किला सहित देश में ऐतिहासिक स्मारकों को प्रदान किए जा रहे सुरक्षा कवर का स्तर ताजमहल को प्रदान किए गए सुरक्षा के स्तर की तुलना में कम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संरक्षित स्मारकों तथा देश में आने वाले पर्यटकों को यथेष्ट सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) यह मूलत: संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व होता है कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐतिहासिक स्मारकों को खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा कबच मुहैय्या कराएं। चूंकि ताजमहल एक विश्वविख्यात ऐतिहासिक स्मारक है इसलिए ताजमहल को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए केन्द्रीय सरकार ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की परिकल्पना की है। धमकी की उपलब्ध जानकारी के आधार पर हिमायूं का मकबरा तथा लाल किला की समुचित सुरक्षा व्यवस्था करने की संबंधित प्राधिकारियों को सलाह दी गई है।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनूसूची के अनुसार ''कानून एवं व्यवस्था'' तथा ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं। अत: ऐतिहासिक स्मारकों तथा वहां आने वाले पर्यटकों की समुचित सुरक्षा करना अनिवार्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय सरकार धमकियों संबंधी जानकारियों का समुचित रूप से आदान-प्रदान करती है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर परामर्शी पत्र जारी करती है।

डेयरी क्षेत्र में महिला स्व-सहायता समूह

2264. श्री गजानन ध. बाबर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर डेयरी क्षेत्र में स्व-सहायता समूहों के साथ और अधिक संख्या में महिलाओं को जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रों में आधुनिकी के उपयोग के लिए डेयरी क्षेत्र से महिलाओं को जोड़ने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) महिला और बाल विकास मंत्रालय निर्धन, सीमांत महिलाओं के लाभ के लिए 10 अभिज्ञात पारंपरिक क्षेत्रों में एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना ''महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए समर्थन'' चला रही है। डेयरी क्षेत्र भी इन 10 अभिज्ञात क्षेत्रों में से एक है और व्यवहार्य सहकारिताओं/स्वसहायता समूहों में महिलाओं को एकजुट करके, विपणन लिंकेजेज, समर्थन सेवाओं तथा ऋण आदि के लिए सुगमता की व्यवस्था करके इस योजना के तहत उनके दक्षता उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के तहत दक्षता उन्नयन के लिए स्वसहायता समूहों के साथ जुड़ी महिलाओं की संख्या विभिन्न राज्यों की राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा भेजी गई व्यवहार्य परियोजना की संख्या पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ) भारत सरकार देश के 586 जिलों में "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों के लिए समर्थन" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है। इसका उद्देश्य कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के रूप में जिला स्तर पर गठित संस्थागत प्रबंध के माध्यम से विकेन्द्रीकृत, मांग आधारित और किसान अनुकूल विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराना है।

महिला समूहों सहित कृषक समूहों को एकजुट करना इस योजना के तहत एक अनुमोदित गतिविधि है जिसमें क्षमता सृजन और दक्षता विकास के लिए 5000/- रुपए प्रति समूह प्रतिवर्ष तथा बीज धन अथवा भ्रूण कोष के रूप में 10,000/- रुपए प्रति समूह प्रतिवर्ष का प्रावधान है। 2005-06 में इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक 35847 समूह गठित किए जा चुके हैं।

17.97 लाख महिला किसानों सहित 91 लाख से अधिक किसान इस योजना की गतिविधियों से अब तक लाभान्वित हो चुके हैं।

(ङ) भारत सरकार ने निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

(करोड़ रुपए)

	योजना का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (16.7.09 तक)
1.	सघन डेयरी विकास कार्यक्रम	33.61	34.68	31.62	3.75
2.	गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	24.65	20.00	21.29	2.58
3.	सहकारिताओं को सहायता	4.50	5.05	9.00	1.20
4.	डेयरी उद्यम पूंजीगत कोष	12.20	49.99	35.00	0.00
	कुल	74.96	110.60	96.91	7.53

[हिन्दी]

पर्वतीय राज्यों में राजमार्गों का निर्माण

2265. श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री वीरेन्द्र कश्यप :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पर्वतीय राज्यों में जिलों को जोड़ने वाली सड़कों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में इन राज्यों में राज्य-वार कितनी लंबी ऐसी सड़कों का निर्माण/विकास किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान आबंटित तथा व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) यह मंत्रालय मुख्यतः, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। तथापि, देश के पर्वतीय राज्यों के जिलों को जोड़ने वाली सड़कों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करने का अलग से कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

के.वी.आई.सी. के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऋण

2266. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में खादी ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रदान किए गए ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या योजना के कार्यान्वयन/ऋण के संवितरण में अनियमितताओं का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविषय में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विशिष्ट रूप से कोई ऋण प्रदान नहीं करती।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा

2267. श्री सुरेश कोडिकुन्नील : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विभिन्न राज्यों में लागू किए जा रहे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी हां। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में संघ सरकार ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) नामक मौजूदा रोजगार सृजन कार्यक्रम और इस मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार योजना को एकीकृत करके अगस्त, 2008 में 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' को अनुमोदन प्रदान किया है। यह पूर्ववर्ती दो कार्यक्रमों की तुलना में लाभग्राहियों को उच्चतर स्तर की सब्सिडी सहित एक महत्वपूर्ण पहल है ताकि बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंको के लिए 250 करोड़ रुपये सहित 4735 करोड़ रुपये के कुल प्रस्तावित योजनागत परिव्यय से 2008-09 से 2011-2012 तक के दौरान अतिरिक्त रोजगार के अवसर (लगभग 38 लाख) सृजित किये जा सकें। इस क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम के तहत सेवा/व्यापार क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक तथा विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक की लागत वाले सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएमईजीपी के तहत प्रदत्त स्वीकृत मार्जिन मनी सहायता निम्न प्रकार है:-

पीएमईजीपी के तहत लाभग्राहियों की श्रेणियां क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान)	लाभग्राहियों का अंशदान (परियोजना लागत का)	सब्सिडी की दर (परियोजना लागत की)	
		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्संख्यक/ महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय तथा सीमा क्षेत्र आदि)	05%	25%	35%

पीएमईजीपी का कार्यान्वयन केवीआईसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल एजेंसी के रूप में किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर, यह योजना बैंकों की सहभागिता से केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डो तथा जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.msme.gov.in पर उपलब्ध है।

पीएमईजीपी के कार्यान्वयन की समीक्षा इस मंत्रालय में हाल ही में 10 जून, 2009 को की गई है जिसमें केवीआईसी/केवीआईबी, कुछ राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक तथा चुनिंदा सहभागी प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि शामिल थे। यह पाया गया है। कि पीएमईजीपी ने सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए देश में काफी उत्साह पैदा किया है और 2008-09 में उपलब्ध मात्र कुछ महीनों के प्रभावी काल में ही कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 217762 आवेदन प्राप्त किए गए थे। इसमें से 92884 आवेदनों की जिला कार्यबल समिति द्वारा जांच कर ली गई है और बैंकों को अग्रेषित कर दिया गया है। बैंकों ने 36287 मामलों में ऋण संस्वीकृत किए हैं जिसमें 506.03 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी शामिल है जिससे देश में अनुमानत: 3.63 लाख रोजगार के अवसर देश में सृजित होंगे। राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पीएमईजीपी के तहत किए गए निष्पादन का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कार्य दल द्वारा चुने गए आवेदनों की संख्या	बैंकों को अग्रेषित परियोजनाओं की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	शामिल मार्जिन मनी (लाख रुपये)	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	छत्तीसगढ़	6058	3102	2825	1078	1942.19	10780
2.	मध्य प्रदेश	2900	2546	2075	628	1351.48	6280
3.	उत्तरांचल	1300	821	787	378	466.77	3780
4.	उत्तर प्रदेश	23982	13221	13221	4414	10660.40	44140
5.	चंडीगढ़	213	156	139	31	8.09	310
6.	दिल्ली	196	81	68	5	4.15	50
7.	हरियाणा	3187	1505	1450	821	1437.76	8210
8.	हिमाचल प्रदेश	1654	672	440	340	452.11	3400
9.	जम्मू और कश्मीर	11697	6885	4140	1821	1452.17	18210
10.	पंजाब	3595	2455	2360	887	1407.93	8870
11.	राजस्थान	6309	2231	1864	703	1461.95	7030
12.	गोवा	64	57	7	7	12.95	70
13.	गुजरात	5097	2007	1664	307	445.22	3070
14.	दमन और दीव	12	7	6	6	2.71	60
15.	महाराष्ट्र	13018	10705	10654	3368	4192.19	33680
16.	आंध्र प्रदेश	9642	3483	2660	903	2605.60	9030
17.	कर्नाटक	16759	5504	5257	2423	3246.82	24230
18.	केरल	3874	1713	1192	389	610.79	3890

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	लक्षद्वीप	49	16	8	4	5.33	40
20.	पुडुचेरी	400	400	205	42	15.96	420
21.	तमिलनाडु	11032	4199	4051	1473	2926.56	14730
22.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	38	38	38	8	2.36	80
23.	बिहार	26259	7748	7748	6741	4524.59	67410
24.	झारखंड	6406	2938	2938	940	1128.00	9400
25.	उड़ीसा	14465	5937	3826	1976	3004.88	19760
26.	पश्चिम बंगाल	19090	10843	10642	5667	6465.81	56670
27.	अरुणाचल प्रदेश	1085	205	205	130	95.00	1300
28.	असम	21404	2374	2198	728	525.16	7280
29.	मणिपुर	195	21	21	3	1.80	30
30.	मेघालय	2093	382	135	3	3.00	30
31.	मिजोरम	803	256	256	23	71.23	230
32.	नागालैंड	3188	179	179	31	61.08	310
33.	त्रिपुरा	1575	164	162	5	4.30	50
34.	सिक्किम	123	33	33	4	6.70	40
	कुल योग	217762	92884	83454	36287	50603.04	362870

[हिन्दी]

कृषि विश्वविद्यालयें में पाठ्यक्रम

2268. श्री राकेश सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एकरूपता की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों में संरचनात्मक परिवर्तन लाने का कोई प्रस्ताव है ताकि इनमें एकरूपता लाई जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) :

(क) और (ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिक समानता की आवश्यकता है, तथापि स्थानीय कृषि तथा कृषि दशाओं की शिक्षण आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए इसमें कुछ सीमा तक लचीलापन अनुमन्य किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, शैक्षणिक मापदंडों, मानकों, विनियमनों तथा पाठ्यक्रम के संशोधन हेतु लगातार प्रयास कर रही है ताकि समस्त कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा इन्हें अंगीकृत करके इनमें एकरूपता को बढ़ाया जा सके।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही (2009) में देश में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या को संशोधित किया है। देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा एकरूपता की वृद्धि के लिए इन्हें तेजी से अपनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

बी.पी.एल. परिवारों के लाभों का दुर्विनियोजन

2269. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले (ए.पी.एल.) परिवारों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों के लिए निर्धारित आर्थिक/लाभों/खाद्यान्नों के अन्यत्र उपयोग की कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसमें कितने प्रतिशत खाद्यान्न का नुकसान हुआ है;

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है जिसमें जिम्मेदारियों के हिस्सेदारी होती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंदर खाद्यान्नों का आबंटन करने, योजना आयोग के अनुमानों पर आधारित गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड जारी करने तथा उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्डधारकों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

जब कभी व्यक्तियों अथवा संगठनों और प्रैस रिपोर्टों के जरिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जिंसों के लीकेज/विपथन के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त होती हैं इन्हें जांच और कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा जाता है।

सरकार समय-समय पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण का आकनल करवाती है। नवीनतम आकलन 12 राज्यों में राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है जिसके संबंध में नवम्बर, 2007 और जनवरी, 2009 में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

इन रिपोर्टों में कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के विपथन की बात कही गई है। तथापि, खाद्यान्नों के विपथन की मात्रा का सही आकलन उपलब्ध नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में आदेश है कि राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुचारु कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दंडनीय है।

पिछले तीन वर्षों (2006, 2007 और 2008) के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पाए गए विभिन्न कदाचारों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचना दी है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अधीन 15,553 व्यक्तियों को गिरफ्तार/अभियोजित किया गया है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 442 मामलों में नजरबंदी आदेश दिए गए थे।

सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ निम्नलिखित बातें लगातार उठा रही है:-

(i) गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की सूचियों की लगातार समीक्षा करना और उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(ii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करना;

(iii) विभिन्न स्तरों पर निगरानी तथा सतर्कता में सुधार करना; उचित दर दुकानों के लाइसेंसधारकों द्वारा राशन कार्डधारकों को आवश्यक वस्तुओं की सुपुर्दगी के लिए मासिक प्रमाण-पत्र दिया जाना; और

(iv) विभिन्न स्तरों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण करने, आवश्यक वस्तुओं की स्मार्ट कार्ड आधारित सुपुर्दगी करने आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियां लागू करना।

(v) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अवधिक रूप से मूल्यांकन कराना।

परंपरागत मछुआरों के लिए सहायता

2270. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परंपरागत मडुआरों को सहायता प्रदान करने के लिए क्रियान्वयनाधीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने परंपरागत मछुआरों के लिए बचत-सह-राहत योजना पुनः शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों क्रमशः की परस्पर हिस्सेदारी कितनी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात सहित राज्य सरकारों को उनका हिस्सा जारी कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना मछुआरों को मूल नागरिक सुविधाएं तथा सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित की गई है। योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया है।

(ख) और (ग) जी, हां। बचत-सह-राहत योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) राज्यों को केंद्रीय अनुदान पहले के वर्षों में जारी अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्रों के साथ व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति पर जारी किया जाता है। गुजरात सरकार से बचत-सह-राहत योजना के अंतर्गत केन्द्रीय अनुदान जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बचत-सह-राहत घटक के अंतर्गत राज्य सरकारों को जारी केंद्रीय अनुदान का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना

मछुआरों को मूल नागरिक सुविधाएं तथा सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया गया है। योजना के निम्नलिखित चार घटक हैं:-

(क) बचत-सह-राहत;

(ख) आदर्श मछुआरा गांव का विकास;

(ग) सक्रिय मछुआरों के लिए सामुहिक दुर्घटना बीमा; तथा

(घ) प्रशिक्षण एवं विस्तार।

(क) बचत-सह-राहत:

यह मछुआरों (समुद्री तथा अंतर्देशीय दोनों) को कमी की अवधि (मछली पकड़ने पर प्रतिबंध वाली अवधि) में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने की 9 महीनों की अवधि में 600/- रुपए का अंशदान किया जाता है। 1200/- का सरकारी अंशदान 50:50 आधार पर केंद्र तथा राज्य द्वारा वहन किया जाता है और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में 100% केंद्र द्वारा

वहन किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में सरकारी अंशदान केंद्र तथा राज्य के बीच 75:25 आधार पर वहन किया जाता है। मछुआरों को कुल 1800/- रुपए की राशि मछली पकड़ने की प्रतिबंधित अवधि के तीन महीनों में 600/- रुपए प्रतिमाह की दर से वितरित की जाती है।

(ख) आदर्श मछुआरा गांव का विकास

इसके तीन उप घटक हैं अर्थात (1) मछुआरा घरों का निर्माण; (2) पीने के पानी के लिए ट्यूबवैलों का निर्माण; तथा (3) सामूहिक कार्य/मनोरंजन स्थल के रूप में सामुदायिक भवनों का निर्माण। मछुआरा घर की यूनिट लागत 50,000/- रुपए है, ट्यूबवैल के लिए यूनिट लागत 30,000/- रुपए (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 35,000/- रुपए) तथा सामुदायिक भवन की लागत 1,75,000/- रुपए है। संपूर्ण लागत केन्द्र तथा राज्य द्वारा वहन की जाती है।

(ग) सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा:

सक्रिय मछुआरों को मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता के मामले में 1,00,000/- रुपए तथा आंशिक स्थायी अपंगता के मामले में 50,000/- रुपए की बीमा कवर प्रदान किया जाता है। यह योजना मछुआरा सहकारिताओं का राष्ट्रीय स्तर का परिसंघ, फिशकापफेड के जरिए क्रियान्वित किया जाता है, जो कि देश के सभी मछुआरों के लिए नीति बनाती है। इसके लिए, सेवा प्रभार के रूप में प्रति मछुआरा 1/- रुपए के भुगतान का प्रावधान है। 28/- रुपए के वार्षिक प्रीमियम को केन्द्र और राज्यों द्वारा पूरा किया जाता है। अत: यह बीमा कवर मछुआरों को निशुल्क प्रदान किया जाता है। केरल और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार इस बीमा योजना को उनके अपने मछुआरा सहकारिताओं के जरिए क्रियान्वित करते हैं। अत: मछुआरों के वार्षिक प्रीमियम की केन्द्रीय हिस्सेदारी को सीधे इन राज्य सरकारों को जारी की जाती है।

(घ) प्रशिक्षण एवं विस्तार:

इस घटक का उद्देश्य आधुनिक मत्स्यन प्रौद्योगिकी के संबंध में मछुआरों की कौशल, क्षमता और ज्ञान का उन्नयन करना है। इस प्रयोजन के लिए, मछुआरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, प्रशिक्षण और विस्तार पुस्तिका प्रकाशित किए जाते हैं और प्रशिक्षण-व-जागरूकता केन्द्र स्थापित किए जाते हैं।

वित्त पोषण की प्रक्रिया:

हालांकि प्रशिक्षण और विस्तार घटक के लिए वित्त पोषण की प्रक्रिया केन्द्र और राज्यों के बीच 80:20 के आधार पर है, अन्य तीन घटकों के लिए राज्यों के मामले में 50:50 के आधार पर भागीदारी है जिसमें पूर्वोत्तर राज्य शामिल नहीं हैं जिनके लिए केन्द्र द्वारा लागत का 75% वहन किया जाता है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में, चारों घटकों के लिए संपूर्ण लागत को केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के बचत-सह-राहत घटक के अंतर्गत राज्य सरकारों को जारी केन्द्रीय अनुदान का राज्यवार ब्यौरा।

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी राशि (लाख रुपए)			
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15.36	0	40.34	0
2.	छत्तीसगढ़	1.12	0	3.37	0
3.	गोवा	0	0	2.15	6.00
4.	हिमाचल प्रदेश	5.10	5.00	5.50	6.26
5.	कर्नाटक	48.20	0	104.08	88.02
6.	केरल	0	0	200.00	214.54
7.	मध्य प्रदेश	15.07	0	31.46	0.
8.	उड़ीसा	39.92	0	89.64	0

1	2	3	4	5	6
9.	राजस्थान	2.62	1.68	3.72	0
10.	तमिलनाडु	300.00	269.94	240.00	0
11.	पश्चिम बंगाल	30.00	30.00	0	60.00
12.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.48	1.36	1.68	0
13.	पुदुचेरी	150.00	126.00	150.00	0
	कुल	608.87	433.98	871.94	374.82

[हिन्दी]

कृषि में अनुसंधान हेतु धनराशि

2271. **श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कृषि में अनुसंधान और विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कृषि अनुसंधान के व्यय और प्रगति की निगरानी के लिए किसी निगरानी समिति का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान कृषि में अनुसंधान तथा विकास कार्य के लिए क्रमश: 1400 करोड़ रुपये, 1620 करोड़ रुपये तथा 1760 करोड़ रुपये की निधि आबंटित की गई।

(ख) वर्ष 2006-07, 2007-08, तथा 2008-09 के दौरान क्रमश: 1368.03 करोड़ रुपये, 1284.26 करोड़ रुपये तथा 1653.81 करोड़ रुपये की आबंटित निधियों का उपयोग किया गया।

(ग) जी हां।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि अनुसंधान की प्रणाली के प्रबोधन हेतु संस्थान अनुसंधान परिषद (आईआरसी), अनुसंधान परामर्शदात्री समिति (आरएसी) तथा पंचवर्षीय समीक्षा दल स्थापित किये है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने स्वतंत्र अभिकरणों के जरिए मूल्यांकन के लिए मैकेनिज्म भी विकसित किया है।

आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षा तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी), भारत सरकार द्वारा व्यय का प्रबंध किया जाता है।

[अनुवाद]

अमरनाथ तीर्थयात्री

2272. **श्री एस.एस. रामासुब्बू :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ की यात्रा की है और चालू वर्ष के दौरान कितने तीर्थयात्रियों द्वारा यात्रा किए जाने का अनुमान है तथा इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार तीर्थयात्रियों को राजसहायता के साथ-साथ अन्य सुविधाएं प्रदान करने का हैं;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान अमरनाथ यात्रा पर गए यात्रियों की वर्ष-वार संख्या तथा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा किया गया कुल व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	यात्रियों की संख्या	व्यय लाख रुपये
2006	3,37,000	265.69
2007	2,96,656	300.18
2008	5,33,368	284.95

15 जुलाई, 2009 तक चालू वर्ष के दौरान, कुल 301297 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में अपने श्रद्धा सुमन भेंट किए। चालू वर्ष में लगभग चार लाख लोगों के यात्रा पर आने की संभावना है।

श्राइन बोर्ड के अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर सरकार ने भी विभिन्न नागरिक सुविधाए प्रदान करने के लिए धन विनिर्दिष्ट किया है। ऐसे व्यय के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं जाते है।

(ख) अमरनाथ यात्रियों को इमदाद देने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न पैदा नहीं होता।

सिग्नल फ्री एलिवेटिड राजमार्ग

2273. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-आगरा, चेन्नई-तिरूपति और चेन्नई-बंगलौर के बीच सिग्नल फ्री एलिवेटिड राजमार्ग का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) एलिवेटिड राजमार्गों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

किसानों की समस्याएं

2274. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान के लिए कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त तंत्र के अंतर्गत किसानों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) भारतीय किसान मौसम की मौजों, संसाधन उपलब्धता, आदान आपूर्ति, पूंजी/ऋण उपलब्धता, विपणन इत्यादि से संबंधित असंख्य समस्याओं का सामना करते हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार कई स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है, उनमें उललेखनीय है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) स्कीम के माध्यम से विस्तार कार्यक्रम,सूक्ष्म सिंचाई स्कीम, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन, व्यापक ऋण पैकेज और ऋण छूट तथा ऋण राहत स्कीम।

समय-समय पर सरकार कृषि क्षेत्र से संबंधित विविध विषयों का अध्ययन करने के लिए आयोगों/समितियों का भी गठन करती है जिसमें किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याएं और उपयुक्त उपायों के सुझाव शामिल हैं उदाहरणार्थ प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग गठित किया गया था जिसकी मुख्य सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति घोषित की है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने कई अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संपूर्ण देश में फैले सहयोग, ऋण, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में संस्थान स्थापित किए हैं जो किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्यओं को सुलझाने में व्यस्त हैं। राज्य सरकारें अपनी पहलों के साथ इन प्रयासों का संपूरण कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त, किसानों को उनकी समस्याओं सहित दैनिक विषयों में परामर्श देने के लिए किसान कॉल सेंटर स्कीम को यथा स्थान रखा गया है। किसान ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केकेएमएस) का विकास किया जा रहा है जिसमें अनसुलझे विषयों के मामलों में मैट्रिक्स वृद्धि के साथ किसानों के प्रश्नों के सही और शीघ्र उत्तर उपलब्ध कराए जाएंगे।

[अनुवाद]

एन.डी.एम.सी. क्षेत्रों में विद्युत की चोरी

2275. श्री आनंदराव अडसुल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा विद्युत चोरी को रोकने एवं निवारण के लिए क्या तंत्र अपनाया जाता हैं;

(ख) क्या स्ट्रीट पोलो विशेषकर चाणक्यपुरी, सत्य मार्ग और मधु लिमये मार्ग में विद्युत चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए कोई औचक निरीक्षण किया गया हैं;

(ग) यदि हां, तो गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विद्युत चोरी के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को विद्युत चोरी के मामलों में एन.डी.एम.सी. के कर्मचारियों की मिलीभगत की कोई शिकायत मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) के वाणिज्यिक विभाग का प्रवर्तन सैल मीटर से होने वाली विद्युत चोरी के मामलों की जांच करता है और इस संबंध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। इसके अलावा एन.डी.एम.सी. का विद्युत विभाग चोरी रोकने और उसकी जांच करने के लिए नियमित गश्त करता है।

(ग) एन.डी.एम.सी. ने जानकारी दी है कि विगत एक वर्ष तथा चालू वर्ष में ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

(घ) जी हां।

(ङ) एन.डी.एम.सी. को विगत एक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान चार शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें विद्युत चोरी में इसके कार्मिकों की मिलीभगत की शिकायत की गई थी। तीन मामलों में, प्रारम्भिक जांच के दौरान विद्युत चोरी का कोई मामला नहीं देखा गया। चौथे मामले में प्रथम दृष्टया विद्युत चोरी का मामला प्रकाश में आया और तीन कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। तदुपरान्त, तीनों कर्मचरियों पर अल्प जुर्माना लगाया गया।

किसानों को टोल फ्री नम्बर की सुविधा

2276. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टोल फ्री नम्बरों से किसानों को मार्गदर्शन प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां।

(ख) किसान कॉल सेंटर स्कीम कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्कीम है जो आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कवर करते हुए 21 जनवरी, 2004 से आरंभ हुई तथा देश के 25 विभिन्न स्थलों पर कार्य कर रही है। किसान कॉल सेंटर स्कीम के तहत कृषि तथा संबद्ध विषयों के सभी पहलुओं पर किसानों के प्रश्नों के संदर्भ में टोल फ्री दूरभाष सं. 1800-180-1551 पर स्थानीय भाषाओं में किसानों को दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। किसान कॉल सेंटर सेवा सप्ताह के सातों दिन 6.00 बजे पूर्वाह्न से 10.00 बजे अपराह्न तक मोबाईल फोन सहित सभी टेलीफोन नेटवर्कों पर उपलब्ध है।

किसान कॉल सेंटर का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक आंध्र प्रदेश के लिए किसान कॉल सेंटर का संबंध है, किसान कॉल सेंटर हैदराबाद में स्थित है। किसान कॉल सेंटर हैदराबाद को जून, 2009 तक 1,07,528 कालें प्राप्त हुई।

विवरण

केसीसी की अवस्थिति का राज्य ब्यौरा तथा शामिल राज्य/संघ शासित क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य/संघ शा. का नाम	अवस्थिति
1	2	3
1.	आंध प्रदेश	हैदराबाद

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
3.	असम, मणिपुर, नागालैंड	गुवाहाटी
4.	बिहार	समस्तीपुर
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर
6.	दिल्ली	नई दिल्ली
7.	गुजरात, दादरा और नगर हवेली और दमन	अहमदाबाद
8.	हरियाणा और पंजाब	चंडीगढ़
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
10.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
11.	झारखंड	रांची
12.	कर्नाटक	बंगलौर
13.	केरल और लक्षद्वीप	त्रिचूर
14.	मध्य प्रदेश	जबलपुर
15.	महाराष्ट्र, गोवा	नागपुर
16.	मेघालय	शिलांग
17.	मिजोरम	आइजोल
18.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
19.	राजस्थान	जयपुर
20.	सिक्किम	गंगटोक
21.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	कोयम्बटूर
22.	त्रिपुरा	अगरतला
23.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
24.	उत्तराखंड	देहरादून
25.	पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	कोलकाता

किसान कॉल सेंटर स्कीम के तहत 30 जून, 2009 तक रिसीव किए गए कॉलों की संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	कालों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7185
2.	आंध्र प्रदेश	107528
3.	अरुणाचल प्रदेश	2034
4.	असम	33110
5.	बिहार	71508
6.	छत्तीसगढ़	42195
7.	दादरा और नगर हवेली	81
8.	दिल्ली	70070
9.	गोवा, दमन और दीव	3128
10.	गुजरात	269573
11.	हरियाणा	123043
12.	हिमाचल प्रदेश	61118
13.	जम्मू और कश्मीर	76836
14.	झारखंड	24925

1	2	3
15.	कर्नाटक	207394
16.	केरल	172001
17.	लक्षद्वीप	944
18.	मध्य प्रदेश	272897
19.	महाराष्ट्र	256036
20.	मणिपुर	23242
21.	मेघालय	6925
22.	मिजोरम	6367
23.	नागालैंड	1442
24.	उड़ीसा	66425
25.	पंजाब	205189
26.	राजस्थान	353618
27.	सिक्किम	688
28.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	223451
29.	त्रिपुरा	16417
30.	उत्तर प्रदेश	525938
31.	उत्तरांचल	84676
32.	पश्चिम बंगाल	151773
	कुल	34,67,757

स्रोत- टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लि., नई दिल्ली द्वारा कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किसान कॉल सेंटरों के लिए मासिक प्रचालन रिपोर्ट, जून, 2009

[हिन्दी]

ग्रामीण उद्योगों का उत्पादन

2277. श्री अशोक कुमार रावत : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान हाथ से बुनी एवं हाथ से कताई की गई वूलन और सिल्क खादी कपड़ों/उत्पादों के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान खनिज, वन उत्पाद, कृषि, खाद्य, रासायनिक, पोलीमर, हाथ से बने कागज और ग्रामीण इंजीनियरिंग सहित ग्रामीण उद्योगों की उत्पादन/विनिर्माण इकाइयों का राज्यवार तथा उत्पादवार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान देश में उत्पादित हाथ से काते गए, हाथ से बुने गए सूती, ऊनी और सिल्क खादी की मात्रा का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है। 2008-09 के लिए इन आंकड़ों का संग्रह अभी नहीं किया गया है और 2009-10 के लिए आंकड़े वर्ष समाप्त होने और आंकड़ों के संग्रह के बाद ही उपलब्ध हो पाएंगे।

(ख) खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा संवर्धित ग्रामीण/ग्राम उद्योगों को मोटे तौर पर सात समूहों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात, (1) खनिज आधारित उद्योग [एमबीआई] (2) वन आधारित उद्योग [एफबीआई] (3) कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग [एएफपीआई] (4) पोलिमर और रसायन आधारित उद्योग [पीसीबीआई] (5) हस्तनिर्मित कागज और रेशा उद्योग [एचएमपीएफआई] (6) ग्रामीण इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग [आरईबीटीआई] और (7) सेवा कार्यकलाप। 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान ग्राम उद्योगों के इन सात समूहों के उत्पादन के मूल्य का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण IV, V और VI में दिया गया है। 2008-09 के लिए इन आंकड़ों का अभी संग्रह नहीं किया गया है और 2009-10 के लिए आंकड़े वर्ष समाप्त होने और आंकड़ों के संग्रह के बाद ही उपलब्ध हो पाएंगे।

विवरण-I

2005-06 के दौरान खादी के उत्पादन का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा

(लाख वर्ग मीटर)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सूती खादी	ऊनी खादी	सिल्क खादी	कुल खादी
1	2	3	4	5	6
1.	चंडीगढ़	0.01	0.00	0.00	0.01
2.	दिल्ली	3.54	0.86	0.00	5.40
3.	हरियाणा	31.53	12.72	0.00	44.25
4.	हिमाचल प्रदेश	0.82	1.35	0.00	2.17
5.	जम्मू और कश्मीर	0.13	2.88	0.01	3.02
6.	पंजाब	12.57	10.80	0.00	23.37
7.	राजस्थान	23.59	10.66	0.00	34.25
8.	बिहार	8.17	0.55	0.76	9.48
9.	झारखंड	0.99	0.01	0.92	1.92
10.	उड़ीसा	1.04	0.00	0.98	2.02
11.	पश्चिम बंगाल	11.57	0.00	23.39	34.96
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.02	0.03
13.	असम	0.48	0.00	3.42	3.90
14.	मणिपुर	0.48	0.00	0.17	0.65
15.	मेघालय	0.01	0.01	0.02	0.04
16.	मिजोरम	0.01	0.00	0.04	0.05
17.	नागालैंड	0.01	0.016	0.31	0.48
18.	त्रिपुरा	0.17	0.00	0.00	0.17
19.	सिक्किम	0.04	0.02	0.00	0.06
20.	आंध्र प्रदेश	13.42	0.29	1.94	15.68
21.	कर्नाटक	34.51	5.96	4.50	44.97
22.	केरल	17.26	0.00	0.21	17.47
23.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.01	0.01
24.	तमिलनाडु	35.22	0.00	5.85	41.07
25.	गुजरात	29.23	1.39	0.08	30.70
26.	महाराष्ट्र	4.35	0.00	0.01	4.36
27.	छत्तीसगढ़	1.02	0.05	2.77	3.84
28.	मध्य प्रदेश	2.32	1.72	1.25	5.29
29.	उत्तराखंड	15.92	2.34	0	18.26
30.	उत्तर प्रदेश	337.01	12.26	2.32	351.59
	कुल	586.46	64.03	48.98	699.47

विवरण-II

2006-07 के दौरान खादी का उत्पादन का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा

(लाख स्क्वायर मीटर)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सूती खादी	ऊनी खादी	सिल्क खादी	कुल खादी
1	2	3	4	5	6
1.	चंडीगढ़	0.01	0.00	0.00	0.01
2.	दिल्ली	4.04	0.86	0.00	4.90
3.	हरियाणा	34.94	13.56	0.00	48.50

1	2	3	4	5	6
4.	हिमाचल प्रदेश	0.85	2.06	0.00	2.91
5.	जम्मू और कश्मीर	0.15	2.96	0.01	3.12
6.	पंजाब	12.69	10.69	0.00	23.38
7.	राजस्थान	24.86	12.71	0.00	37.57
8.	बिहार	8.17	0.55	0.76	9.48
9.	झारखंड	0.99	0.01	0.92	1.92
10.	उड़ीसा	1.28	0.00	1.04	2.32
11.	पश्चिम बंगाल	11.84	0.00	23.49	35.33
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.02	0.03
13.	असम	0.51	0.00	3.59	4.10
14.	मणिपुर	0.48	0.00	0.19	0.67
15.	मेघालय	0.01	0.01	0.02	0.04
16.	मिजोरम	0.01	0.00	0.04	0.05
17.	नागालैंड	0.00	0.16	0.18	0.34
18.	सिक्किम	0.09	0.01	0.00	0.10
19.	त्रिपुरा	0.18	0.00	0.00	0.18
20.	आंध्र प्रदेश	15.05	0.25	0.76	16.06
21.	कर्नाटक	35.75	6.05	4.86	46.66
22.	केरल	21.63	0.00	0.30	21.93
23.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.01	0.01
24.	तमिलनाडु	38.91	0.00	6.23	45.14
25.	गुजरात	29.53	1.39	0.08	31.00
26.	महाराष्ट्र	4.70	0.00	0.02	4.72
27.	छत्तीसगढ़	1.21	0.04	3.17	4.42
28.	मध्य प्रदेश	2.39	1.74	1.27	5.40
29.	उत्तराखंड	15.92	2.34	0.00	18.26
30.	उत्तर प्रदेश	334.64	13.18	2.38	350.20
	कुल	600.84	68.57	49.34	718-75

विवरण-III

2007-08 के दौरान खादी के उत्पादन का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा

(लाख स्क्वायर मीटर)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सूती खादी	ऊनी खादी	सिल्क खादी	कुल खादी
1	2	3	4	5	6
1.	चंडीगढ़	0.01	0.00	0.00	0.01
2.	दिल्ली	5.04	0.10	0.00	5.14
3.	हरियाणा	36.50	14.13	0.00	50.63
4.	हिमाचल प्रदेश	0.90	2.22	0.00	3.12
5.	जम्मू और कश्मीर	0.20	3.11	0.35	3.66
6.	पंजाब	13.82	11.58	0.00	25.40
7.	राजस्थान	25.98	12.55	0	38.53
8.	बिहार	9.10	0.52	0.75	10.37
9.	झारखंड	1.04	0.01	0.96	2.01
10.	उड़ीसा	1.34	0.00	2.16	3.50

1	2	3	4	5	6
11.	पश्चिम बंगाल	13.52	0.00	24.44	37.96
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.00	0.03	0.05
13.	असम	0.37	0.00	3.91	4.28
14.	मणिपुर	0.51	0.00	0.20	0.71
15.	मेघालय	0.06	0.00	0.04	0.10
16.	मिजोरम	0.42	0.00	0.00	0.42
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.17	0.17
18.	त्रिपुरा	0.05	0.00	0.00	0.05
19.	आंध्र प्रदेश	26.75	0.28	0.85	27.88
20.	कर्नाटक	38.78	6.70	5.14	50.62
21.	केरल	25.46	0.00	0.31	25.77
22.	पुडुचेरी	0	0.00	0.01	0.01
23.	तमिलनाडु	44.03	0.00	6.95	50.98
24.	गुजरात	32.63	1.48	0.09	34.20
25.	महाराष्ट्र	1.30	0.00	0.00	1.30
26.	छत्तीसगढ़	1.67	0.06	4.20	5.93
27.	मध्य प्रदेश	3.88	1.90	1.37	7.15
28.	उत्तराखंड	19.46	2.85	0.00	22.31
29.	उत्तर प्रदेश	334.01	14.43	1.73	350.17
	कुल	636.85	71.92	53.66	762.43

विवरण-IV

2005-06 के दौरान ग्रामोद्योगों के उत्पादन का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	एमबीआई	एफबीआई	एएफपीआई	पीसीबीआई	एचएमपी एफआई	आरईबी टीआई	सेवा कार्यकलाप	कुल ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चंडीगढ़	245.71	133.97	534.62	275.93	78.93	329.27	153.66	1752.09
2.	दिल्ली	816.61	447.12	1568.32	912.27	273.10	1040.59	479.67	5537.68
3.	हरियाणा	6644.91	2809.59	13238.96	4512.08	1809.81	9409.14	1204.82	39629.31
4.	हिमाचल प्रदेश	4474.01	2781.74	8867.80	4560.10	1356.59	7715.92	1846.24	31602.40
5.	जम्मू और कश्मीर	3811.90	2049.67	7559.18	3861.10	1325.31	6261.37	2444.66	27313.19
6.	पंजाब	8055.57	5627.63	12485.94	8035.93	2321.30	11314.56	2324.81	50165.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	राजस्थान	21210.03	8788.40	32086.04	15285.85	4872.66	23140.40	6855.69	112239.07
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	277.29	123.22	539.87	129.82	44.68	359.75	102.24	1576.87
9.	बिहार	3115.84	582.79	13503.63	1803.24	80.75	3202.93	569.68	22858.86
10.	झारखंड	1921.32	421.94	1126.64	171.22	99.12	828.13	405.51	4973.88
11.	उड़ीसा	3859.81	1762.24	7129.41	2980.50	1068.96	5020.05	1096.43	22917.40
12.	पश्चिम बंगाल	6926.95	4802.15	11492.11	9062.48	3356.89	6285.74	4600.00	46526.32
13.	अरुणाचल प्रदेश	136.28	234.28	148.84	120.25	62.76	406.76	86.58	1195.75
14.	असम	4112.48	2063.42	6374.96	2935.73	530.21	4563.17	675.65	21255.62
15.	मणिपुर	1020.21	507.30	1851.03	1026.41	442.14	1294.05	503.73	6644.87
16.	मेघालय	1107.77	586.91	1605.53	622.78	168.26	1195.38	236.23	5522.86
17.	मिजोरम	1499.67	592.57	2904.06	832.23	285.48	1999.59	840.55	8954.15
18.	नागालैंड	1182.22	549.91	1994.70	810.53	275.34	1683.58	430.90	6927.18
19.	सिक्किम	240.39	126.72	498.69	78.75	79.98	385.52	163.92	1573.97
20.	त्रिपुरा	1207.22	159.20	527.80	649.40	177.54	1181.83	539.73	4442.72
21.	आंध्र प्रदेश	17252.86	7120.67	22188.32	9181.06	3015.58	13795.57	2603.52	75157.58
22.	कर्नाटक	15407.82	6245.06	28755.03	13864.15	4306.70	17786.09	5826.83	92191.68
23.	केरल	10088.89	5143.01	17622.08	8260.40	2882.77	12885.45	2891.88	59774.48
24.	लक्षद्वीप	33.56	9.44	58.06	16.01	3.68	23.64	10.74	155.13
25.	पुदुचेरी	70.52	51.19	133.48	64.87	30.36	180.87	89.70	620.99
26.	तमिलनाडु	13204.68	6033.65	22723.24	12275.29	4818.35	17894.27	7245.94	84195.42
27.	दादरा और नगर हवेली	14.79	3.73	36.32	8.13	0.15	9.35	19.79	92.26
28.	गोवा	500.94	323.63	910.54	778.72	146.06	643.71	239.10	3542.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	गुजरात	7746.99	3622.55	14643.90	7967.18	2437.14	10426.05	5916.38	52760.19
30.	महाराष्ट्र	22942.11	12051.87	42388.84	22851.96	7000.03	29011.10	10560.83	146806.74
31.	छत्तीसगढ़	6329.77	1324.03	6239.38	2173.88	496.85	2899.51	527.39	19990.81
32.	मध्य प्रदेश	18513.00	2649.51	15915.49	10054.01	2413.88	12688.07	4850.44	67084.40
33.	उत्तराखंड	1979.38	1204.87	3894.94	1582.73	949.71	2937.03	549.79	13098.45
34.	उत्तर प्रदेश	23501.05	14161.97	45255.19	21520.60	6718.03	30214.40	11102.17	152473.41
	कुल	209452.55	95095.95	346802.94	169265.59	53929.10	239012.84	77995.20	1191554.17

इस्तेमाल किए गए संकेताक्षर: एमबीआई - खनिज आधारित उद्योग, एफबीआई - वन आधारित उद्योग, एएफपीआई - कृषि व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पीसीबीआई - पोलिमर व रसायन आधारित उद्योग, एचएमपीएफआई - हस्तनिर्मित कागज व रेशा उद्योग, आरईबीटीआई - ग्रामीण इंजीनियरिंग व जैव प्रौद्योगिकी उद्योग

विवरण-V

2006-07 के दौरान ग्रामोद्योगों के उत्पादन का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	एमबीआई	एफबीआई	एएफपीआई	पीसीबीआई	एचएमपी एफआई	आरईबी टीआई	सेवा कार्यकलाप	कुल ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चंडीगढ़	245.71	133.97	534.62	279.61	78.93	329.27	155.31	1757.42
2.	दिल्ली	819.76	447.12	1593.73	922.19	280.98	1040.59	483.92	5588.29
3.	हरियाणा	8271.09	4159.89	14587.79	5152.11	2146.28	12387.31	1318.98	48023.45
4.	हिमाचल प्रदेश	4775.99	2941.07	10099.35	4874.31	1580.40	9302.52	2075.15	35648.79
5.	जम्मू और कश्मीर	4043.22	2340.84	8464.39	3954.87	1372.50	6911.64	3044.53	30131.99
6.	पंजाब	9863.04	6800.11	15409.04	9014.90	2566.16	12777.05	2424.51	58854.81
7.	राजस्थान	24044.19	9627.36	35665.78	16179.92	5268.62	25116.71	7103.37	123005.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	294.72	127.84	581.71	139.11	46.78	381.80	104.14	1676.10
9.	बिहार	3429.48	814.11	15355.56	2002.95	117.03	3913.20	611.09	26243.42
10.	झारखंड	2719.79	451.39	1390.35	267.40	118.28	1227.08	433.68	6607.97
11.	उड़ीसा	4691.04	2039.28	9346.01	3534.64	1329.62	6128.32	1149.52	28218.43
12.	पश्चिम बंगाल	8813.38	5430.73	16255.66	10603.36	3985.63	8801.07	4661.97	58551.80
13.	अरुणाचल प्रदेश	250.00	272.19	452.18	196.06	99.04	558.43	90.55	1918.45
14.	असम	5464.88	2514.17	9981.40	3837.31	949.95	6366.39	724.03	29838.13
15.	मणिपुर	1191.37	602.43	2053.52	1035.86	442.14	1439.00	509.37	7273.69
16.	मेघालय	1459.52	623.19	1901.21	650.19	184.27	1315.08	285.85	6419.31
17.	मिजोरम	2321.51	866.52	5095.62	1380.11	551.97	3095.37	868.69	14179.79
18.	नागालैंड	1197.97	673.55	2190.58	818.40	280.85	2051.34	460.14	7672.83
19.	सिक्किम	359.66	166.46	816.74	158.24	116.73	544.54	168.21	2330.58
20.	त्रिपुरा	1469.56	233.70	735.44	755.14	212.24	1466.54	588.93	5461.55
21.	आंध्र प्रदेश	25626.67	7638.95	27012.60	9848.01	3535.49	16099.27	2807.43	92568.42
22.	कर्नाटक	17316.92	6881.41	33845.96	15136.86	4936.70	20331.55	5904.39	104353.79
23.	केरल	12249.53	5598.97	19122.79	9045.06	3172.57	14688.98	3049.39	66927.29
24.	लक्षद्वीप	33.56	9.44	58.06	16.01	3.68	23.64	10.74	155.13
25.	पुदुचेरी	102.55	53.60	173.33	69.44	33.92	260.36	95.96	789.16
26.	तमिलनाडु	14464.68	6391.76	25410.97	13057.65	5296.84	19429.11	7316.20	91367.21
27.	दादरा और नगर हवेली	14.79	3.73	36.32	8.13	0.15	9.35	19.79	92.26
28.	गोवा	517.85	415.61	1016.48	831.53	164.44	643.71	260.50	3850.12
29.	गुजरात	8077.31	3622.55	15078.92	8654.62	2502.28	12652.57	5977.87	56566.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	महाराष्ट्र	24396.15	12620.92	46149.73	23738.32	7446.39	31007.47	10615.74	155974.72
31.	छत्तीसगढ़	8947.16	1382.88	8394.56	2446.82	524.31	3527.78	614.18	25837.69
32.	मध्य प्रदेश	21029.33	2908.17	18379.63	10433.85	2502.13	13732.77	4982.53	73968.41
33.	उत्तराखंड	2301.15	1337.69	4412.96	1856.20	1108.73	3580.52	661.64	15258.89
34.	उत्तर प्रदेश	26360.51	14664.93	51714.47	22647.99	7062.38	32559.26	11597.97	166607.51
	कुल	247164.04	104796.53	403317.46	183547.17	60018.41	273699.59	81176.27	1353719.74

इस्तेमाल किए गए संकेताक्षर: एमबीआई - खनिज आधारित उद्योग, एफबीआई - वन आधारित उद्योग, एएफपीआई - कृषि व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पीसीबीआई - पोलिमर व रसायन आधारित उद्योग, एचएमपीएफआई - हस्तनिर्मित कागज व रेशा उद्योग, आरईबीटीआई - ग्रामीण इंजीनियरिंग व जैव प्रौद्योगिकी उद्योग

विवरण-VI

2007-08 के दौरान ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	एमबीआई	एफबीआई	एएफपीआई	पीसीबीआई	एचएमपी एफआई	आरईबी टीआई	सेवा कार्यकलाप	कुल ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चंडीगढ़	255.16	133.97	545.12	279.61	78.93	329.27	159.77	1781.83
2.	दिल्ली	819.76	447.12	1617.15	929.80	280.98	1043.22	492.52	5630.55
3.	हरियाणा	10870.42	5985.16	17297.32	6518.21	2774.39	16848.97	1589.39	61883.86
4.	हिमाचल प्रदेश	5596.57	3095.84	11789.12	5271.11	1922.60	11804.57	2444.72	41924.53
5.	जम्मू और कश्मीर	5424.34	2801.21	12147.42	4875.62	1818.75	8753.18	3092.98	38913.50
6.	पंजाब	12319.25	7975.74	21270.35	10991.74	3234.38	16026.59	2609.35	74427.40
7.	राजस्थान	34075.89	10724.56	38316.30	17167.66	5476.78	28166.91	8460.34	142388.44
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	294.72	137.84	625.60	139.11	46.78	381.80	118.04	1733.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	बिहार	3936.68	985.16	18591.61	2237.73	337.22	5234.26	707.20	32029.86
10.	झारखंड	3731.94	500.22	1833.45	502.65	152.14	1703.78	459.39	8883.57
11.	उड़ीसा	6548.65	2206.13	11482.13	4004.25	1536.68	6888.47	1411.04	34077.35
12.	पश्चिम बंगाल	13827.92	7102.23	29627.83	13946.40	5322.81	10806.99	5394.68	86028.86
13.	अरुणाचल प्रदेश	362.93	474.95	733.69	222.52	119.52	845.45	168.45	2927.51
14.	असम	7967.45	3147.43	14041.59	4260.83	1128.82	8170.45	1292.31	40008.88
15.	मणिपुर	1278.78	644.06	2141.72	1035.86	442.14	1575.03	523.05	7640.64
16.	मेघालय	2018.86	659.05	3242.38	704.63	333.53	1853.73	289.67	9101.85
17.	मिजोरम	2543.64	964.12	6461.62	1443.95	551.97	4256.04	1168.80	17390.14
18.	नागालैंड	1387.71	883.50	2402.58	849.90	285.37	3159.51	531.92	9500.49
19.	सिक्किम	375.31	334.88	1120.40	168.01	116.73	776.80	238.86	3130.99
20.	त्रिपुरा	2065.17	337.23	1392.74	1061.53	293.72	2111.45	707.97	7969.81
21.	आंध्र प्रदेश	40533.95	7866.12	31876.10	10625.59	4105.06	19375.11	3264.22	117646.15
22.	कर्नाटक	22750.72	7134.25	37917.55	15943.52	5189.65	23905.12	6503.71	119344.52
23.	केरल	15557.61	6424.80	21475.32	10279.55	3602.39	16917.24	3391.75	77648.66
24.	लक्षद्वीप	33.56	9.44	58.06	16.01	3.68	31.94	14.00	166.69
25.	पुडुचेरी	182.46	127.26	303.85	83.62	54.92	388.93	120.61	1261.65
26.	तमिलनाडु	18045.81	6750.76	29256.60	14257.22	8144.49	22518.79	8406.23	107379.90
27.	दादरा और नगर हवेली	14.79	3.73	36.32	8.13	0.15	9.35	19.79	92.26
28.	गोवा	606.58	445.17	1253.20	890.70	164.44	762.05	266.43	4388.57
29.	गुजरात	9008.77	3644.92	16389.16	9614.79	2629.17	13993.89	7288.62	62569.32
30.	महाराष्ट्र	28332.29	13210.67	49420.22	24735.66	7690.57	33771.92	10916.89	168078.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	छत्तीसगढ़	12447.97	1672.94	10559.03	2733.79	644.38	4181.35	993.06	33232.52
32.	मध्य प्रदेश	24956.80	3120.32	22450.74	11214.68	2646.56	14825.09	5401.28	84615.47
33.	उत्तराखंड	2718.89	2101.36	5208.86	2142.59	1194.57	4527.20	916.53	18810.00
34.	उत्तर प्रदेश	31839.16	16000.01	61467.40	24182.57	7542.97	36548.27	13244.10	190824.48
	कुल	322730.51	118042.15	484352.53	203339.54	69867.24	322492.72	92607.67	1613432.36

इस्तेमाल किए गए संकेताक्षर: एमबीआई - खनिज आधारित उद्योग, एफबीआई - वन आधारित उद्योग, एएफपीआई - कृषि व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पीसीबीआई - पोलिमर व रसायन आधारित उद्योग, एचएमपीएफआई - हस्तनिर्मित कागज व रेशा उद्योग, आरईबीटीआई - ग्रामीण इंजीनियरिंग व जैव प्रौद्योगिकी उद्योग

कृषि उपकरणों के मूल्य में वृद्धि

2278. श्री राधा मोहन सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान कृषि उपकरणों के मूल्यों में वृद्धि का रुझान देखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उपकरण-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) कृषि उपकरण व्यापक प्रकारों तथा आमाप के हैं तथा समूचे देश में विद्यमान संगठित तथा असंगठित, दोनों क्षेत्रों के बड़ी संख्या में विनिर्माता इसके विनिर्माण में लगे हुए है। साथ ही, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, फसलों के प्रकार, विनिर्माताओं के स्थल आदि के आधार पर कृषि उपकरणों का मूल्य राज्य के अनुसार बदलता रहता है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उपकरणों के मूल्यों का आकलन तथा तुलना कठिन हो जाता है। कृषि उपकरणों के विनिर्माण में कास्ट आयरन, स्टील, एल्युमीनियम, कॉपर, निकल, शीट मेटल आदि जैसी व्यापक अपरिष्कृत सामग्री का प्रयोग किया जाता है और इन अपरिष्कृत सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। तथापि, सरकार द्वारा सभी कृषि उपकरणों पर उत्पाद शुल्क में छूट जैसे बहुत से उपाय किए गए हैं और विभिन्न सरकारी स्कीमों के तहत विभिन्न कृषि उपकरणों की खरीद के लिए वर्ष 2007-08 से किसानों के लिए सब्सीडी की राशि में वृद्धि की गई है।

कुटीर उद्योग के लिए श्रमोन्मुखी नीति

2279. श्री जगदम्बिका पाल : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुटीर उद्योग के विकास के लिए कोई श्रमोन्मुखी नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) 2008-09 के दौरान सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) ने कार्यान्वयन के लिए खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए निम्नलिखित तीन नई योजनाओं को अनुमोदित किया है:-

(i) सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन के लिए 'प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)।' यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र नोडल एजेंसी के रूप में केवीआईसी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। राजय/संघ शासित प्रदेश

स्तर पर, इस योजना को केवीआईसी के क्षेत्र कार्यालयों, राज्य/संघ शासित प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) और जिला उद्योग केंद्रों और बैंकों के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत, उद्यमी सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये और विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपये की परियोजनाओं के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी से मार्जिन मनी सहायता और कार्यान्वयक सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों, आदि से ऋण लेकर ग्रामोद्योग भी स्थापित कर सकते हैं।

(ii) 'खादी उद्योगों और कारीगरों की उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने' की योजना, जिसके उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ, अधिक बाजार केंद्रित, लाभदायक उत्पादन और खादी कारीगरों व संबंधित सेवा प्रदानकर्ताओं के लिए स्थायी रोजगार के साथ खादी उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसके लिए अप्रचलित और पुरानी मशीनरी तथा उपकरणों को हटाया जाएगा और मौजूदा/प्रचालनरत मशीनरी तथा उपकरणों की मरम्मत तथा नवीनीकरण किया जाएगा, खादी कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों, जैसे उत्पादन, वितरण, संवर्धन तथा क्षमता निर्माण, में एक बराबर संतुलित और आवश्यकता आधारित सहयोग प्रदान किया जाएगा।

(iii) विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) रहने वाले खादी बुनकरों और कताईकारों के वर्कशेडों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना।

इसके अतिरिक्त, एक नई योजना 'विद्यमान कमजोर खादी संस्थानों की आधारभूत संरचना के सशक्तीकरण और विपणन तंत्र के लिए सहायता की योजना' को जुलाई 2009 में पहचाने गए कमजोर खादी संस्थानों की सहायता के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया है ताकि उन संस्थानों को अपनी स्थिति सुधारने और पुनः रोजगार की अपनी क्षमता को बहाल करने में सक्षम बनाया जा सके और एक सीमित आधार पर खादी संस्थानों के चुनिंदा बिक्री आउटलेटों के नवीनीकरण सहित विपणन तंत्र के विकास के द्वारा खादी उत्पादों के विपणन को सुधारा जा सके।

वर्ष 2009-10 के लिए उन तीन नई योजनाओं के लिए केवीआईसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

योजना का नाम	बजट आबंटन	लक्ष्य
पीएमईजीपी	823 करोड़ रुपये	6.17 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसरों का का सृजन
खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना	15 करोड़ रुपये	6,000 कताईकारों को वर्कशेड प्रदान किया जाना है।
खादी उद्योगों और कारीगरों की उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना	8 करोड़ रुपये	23 खादी संस्थानों की सहायता की जानी है।
विद्यमान कमजोर खादी संस्थानों की आधारभूत संरचना के सशक्तीकरण और विपणन तंत्र के लिए सहायता की योजना	5 करोड़ रुपये	8 चुनिंदा बिक्री आउटलेटों के नवीनीकरण सहित 30 पहचाने गए कमजोर खादी संस्थानों की सहायता और विपणन तंत्र का विकास

[अनुवाद]

खाद्य तेल संबंधी आयात शुल्क

2280. श्री एंटो एंटोनी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पामोलीन सहित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को कम किए जाने के कारण घरेलू नारियल और अन्य खाद्य तेलों के मूल्यों में गिरावट आई है जिससे किसानों तथा घरेलू विनिर्माताओं को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों पर लगाए गए विद्यमान आयात शुल्क को दर्शाते हुए ततसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों और घरेलू विनिर्माताओं की सहायता तथा उनके लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) सरकार द्वारा सभी क्रूड और रिफाइंड तेलों पर आयात शुल्क को क्रमश: कम करके शून्य तथा 7.5 प्रतिशत करने और प्रमुख खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जैसे उपाय किए जाने तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी होने के कारण पिछले एक वर्ष में सभी प्रमुख खाद्य तेलों के मूल्यों में गिरावट आई है। नारियल तेल के निर्यात को कोचीन पत्तन के जरिए अनुमति दी गई है और केरल में स्थित पत्तनों के जरिए पाम तेल के आयात को निषेध कर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों पर विभिन्न तारीखों को किए गए आयात शुल्क के समायोजनों के ब्यौरे बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) भारत सरकार तिलहनों के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है और यदि मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाते हैं तो समर्थन मूल्य प्रचालन चलाती है। किसानों, उपभोक्ताओं और घरेलू निर्माताओं के हितों को ध्यान में रखकर सीमा शुल्क का समयोजन किया जाता है।

तेल का नाम	आयात शुल्क की दर/प्रभावी तारीखें					
कच्चा पाम तेल	70% (11-08-06)	60% (24-01-07)	50% (13-04-07)	45% (23-07-07)	20% (21-03-08)	शून्य (01-04-08)
आरबीडी पामोलीन	80% (11-08-06)	67.5% (24-01-07)	57.5% (13-04-07)	52.5% (23-07-07)	27.5% (21-03-08)	7.5% (01-04-08)
कच्चा सोयाबीन तेल	40% (23-07-07)	शून्य (01-04-08)	20% (18-11-08)	शून्य (24-03-09)		
रिफाइण्ड सोयाबीन तेल	40% (23-07-07)	7.5% (01-04-08)	7.5% (01-04-08)	7.5% (01-04-08)		
कच्चा सूरजमुखी तेल	65% (24-01-07)	50% (01-03-07)	40% (23-07-07)	20% (21-03-08)	शून्य (01-04-08)	
रिफाइंड सूरजमुखी तेल	75% (24-01-07)	60% (01-03-07)	50% (23-07-07)	27.5% (21-03-08)	7.5% (01-04-08)	

राष्ट्रीय राजमार्ग-17 को चार लेन का बनाना तथा पुलों की मरम्मत

2281.. **श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलों की मरम्मत तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-17 को चार लेन का बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार तटीय कर्नाटक होते हुए गोवा तथा केरला सीमा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-17 को चार लेन का बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार

द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर पुलों की बहाली का कोई प्रस्ताव मंत्रालय में लंबित नहीं है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग 17 को 4 लेन का बनाने का संबंध है, इसकी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	लंबाई (किलोमीटर में)	4 लेन बनाने की स्थिति
1.	महाराष्ट्र	475	राष्ट्रीय राजमार्ग चरण-III के अंतर्गत प्रस्तावित 85 किलोमीटर, साध्यता स्तर पर हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) योजना के अंतर्गत राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अन्य 21.50 किलोमीटर में 4 लेन बनाई जा रही हैं। इस समय शेष 369.50 में 4 लेन बनाया जाना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
2.	गोवा	139	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत प्रस्तावित पूर्ण 139 किलोमीटर, साध्यता स्तर पर है।
3.	कर्नाटक	300	17.30 किलोमीटर में कार्य प्रगति पर है जिसको दिसंबर, 2009 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा, 192 किलोमीटर साध्यता स्तर पर है और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत प्रस्तावित शेष 90.70 किलोमीटर, सौंपे जाने के विभिन्न स्तरों पर हैं।
4.	केरल	421	संपूर्ण 421 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है जिसमें से 170 किलोमीटर के लिए स्वीकृति पत्र जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा, 131 किलोमीटर परियोजना तैयार करने के चरण में है और शेष 120 किलोमीटर, निविदा प्रक्रिया में है।
	जोड़	1335	

सीमा पर तस्करी

2282. श्री वरुण गांधी :
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बांग्लादेश सीमा सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर मवेशियों और मादक पदार्थों की तस्करी में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पता चले ऐसे प्रत्येक मामले तथा जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा एवं जब्त किए गए मवेशियों की संख्या का सीमा-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या तस्कर अपनी गतिविधियों में महिलाओं और बच्चों को भी शामिल कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान पता चले ऐसे प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सीमा पर तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

2283. श्री महेश जोशी : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल विज्ञान के अध्ययन को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में प्रशिक्षकों को पर्याप्त जानकारी/प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई पहल की है/किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल) : (क) और (ख) जी हां। खेल विज्ञान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण का अभिन्न अंग है जिसे भा.खे.प्रा. द्वारा कार्यान्वित की जा रही निम्नलिखित खेल संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है:-

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) योजना
2. सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी) योजना
3. एसएआई प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी) योजना
4. विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) योजना
5. व्यापक कवरेज के लिए स्कूलों/कालेजों को कवर करने के लिए एसटीसी/एसएजी के विस्तार केन्द्र
6. उत्कृष्टता केन्द्र योजना

राष्ट्रीय शिवरों के लिए चयनित खिलाड़ियों को आवश्यक वैज्ञानिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) और (घ) जी हां। खिलाड़ियों को वैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में राष्ट्रीय कोचों को वैज्ञानिक सहायता प्रदान की जा रही है। खेलों के अध्ययन/प्रशिक्षण में वैज्ञानिक निवेश से एथलीटों के प्रदर्शन में सुधार होता है। सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए भारतीय टीमों की तैयारी की अपनी योजना में 17+1 खेल विधाओं में प्रमुख संभावित दावेदारों के प्रशिक्षण के लिए 80 खेल वैज्ञानिकों/सहायक स्टाफ के लिए अनुमोदन दिया है।

ग्रेनाइट का उत्खनन एवं निर्यात

2284. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रेनाइट के उत्खनन तथा खान प्रौद्योगिकी को सुधारने एवं उसे उन्नत बनाने हेतु चलाई गई योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में राज्य-वार तथा स्थान-वार ग्रेनाइट के कितने भंडार उपलब्ध हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में कितनी मात्रा में ग्रेनाइट का निर्यात किया गया;

(घ) क्या हाल के वर्षों में ग्रेनाइट के निर्यात में कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर.एक्ट) की धारा 3 (ङ) के अंतर्गत ग्रेनाइट को गौण खनिज परिभाषित किया गया है और एम.एम.डी.आर.एक्ट, 1957 की धारा 15 के अनुसार, गौण खनिजों के लिए नियम बनाने और खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को सभी शक्तियां दी गई है। पूरे देश में ग्रेनाइट के क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विदोहन के संबंध में एकसमान ढांचा निर्धारित करने और ग्रेनाइट संसाधनों के संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार ने 1 जून, 1999 को ग्रेनाइट संरक्षण और विकास नियमावली, 1999 को अधिसूचित किया है।

केन्द्र सरकार ने ग्रेनाइट उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने और सुधार करने के लिए विभिन्न हिस्सेदारों को शामिल करते हुए ग्रेनाइट विकास परिषद (जी.डी.सी.) गठित की है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1.4.2005 को लगाए गए अनुमान के अनुसार देश में 1130 मिलियन घन मीटर के भंडार उपलब्ध हैं जिसमें से 86 प्रतिशत मध्य प्रदेश में, 7 प्रतिशत उड़ीसा में अवस्थित हैं और शेष 7 प्रतिशत झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में अवस्थित हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक मात्रा और मूल्य अनुसार भारत से ग्रेनाइट और ग्रेनाइट उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	मूल्य (लाख रुपए)
2005-06	349059.10
2006-07	472484.20
2007-08	428748.50
2008-09 (अनुमानित)	437052.10

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2007-08 में, पिछले वर्ष की तुलना में ग्रेनाइट के निर्यात उत्पादों में 9 प्रतिशत की कमी हुई है। ग्रेनाइट का निर्यात, रेडियोधर्मी रेडॉन के उत्सर्जन संबंधी आरोप के कारण विशेष रूप से अमेरीकी बाजार और अन्य विकसित बाजारों में प्रभावित हुआ है।

(च) सरकार निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम, शुल्क हकदारी पासबुक क्रेडिट आदि जैसी स्कीमों के माध्यम से रासायनिक और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (केपेक्सिल) और उद्योग के संवर्धन के माध्यम से क्रेता-विक्रेता बैठक के लिए अवसर प्रदान करती है।

आई.पी.सी. की धारा 377 में संशोधन

2285. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समलैंगिकता संबंधी कानूनों की समीक्षा करने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को संशोधित/निरसित करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दायर की गई रिट पिटीशन (सिविल) सं. 2001 की 7455 के संबंध में अभी हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था दी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377, जहां तक उसका संबंध किसी वयस्क व्यक्ति की निजी तौर पर सहमति पूर्वक किए जाने वाले यौन कृत्यों को अपराध माने जाने से है, संविधान के अनुच्छेद 21,14 और 15 का उल्लंघन करने वाली धारा है। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश को श्री सुरेश कुमार कौशल एवं अन्य द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस प्रकार यह मामला न्याय निर्णयाधीन है।

[अनुवाद]

कीनिया के साथ औद्योगिक समझौता

2286. **श्री प्रदीप माझी :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कीनिया औद्योगिक सम्पदा लिमिटेड के साथ दोनों देशों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास हेतु किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त समझौते से देश को कितना लाभ होगा?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एसएसएमई)

मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने कीनिया औद्योगिक संपदा (केआईई) लिमिटेड, कीनिया राज्य निगम की सरकार के साथ दोनों देशों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास के लिए 12.05.09 को नैरोबी, कीनिया, में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंश के रूप में एनएसआईसी द्विपक्षीय समझौता शर्तों पर कीनिया में लघु उद्यमों के विकास के लिए संभाव्य क्षेत्रों तथा अवसरों की पहचान करने के लिए केआईई को औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण तथा व्यवहार्यता अध्ययन कराने में सहायता देगा। एनएसआईसी, कीनिया के नए उद्यमियों के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी प्रदर्शनों एवं प्रशिक्षण के लिए व्यापार उद्भवन केन्द्र स्थापित करने में भी केआईई की सहायता करेगा। एनएसआईसी, केआईई को कीनिया में द्विपक्षीय समझौता शर्तों पर एसएमई के विकास के लिए नीति तथा संस्थागत ढांचा विकसित करने में सहायता करेगा और क्षमता निर्माण, विपणन, क्रेटिड सहयोग तथा प्रौद्योगिकी समर्थन के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करेगा। एनएसआईसी केआईई के सहयोग से विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में भारत से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को भी सुविधाजनक बनाएगा। केआईई, भारतीय प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए कीनिया में मशीनरी तथा उपस्करों की प्रदर्शनियों के आयोजन को सुगम बनाएगा और इसके लिए एनएसआईसी की सहायता करेगा। एनएसआईसी तथा केआईई दोनों ही भारत और कीनिया में उद्यमों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण एवं स्थायी व्यापार गठबंधन बनाने संबंधी सहायता देने के लिए व्यापारिक उद्देश्यों के आदान-प्रदान को सुगम बनाएगें। इसके अलावा दोनों देशों में एसएमई द्वारा आफर किए गए उत्पादों औ ावाओं संबंधी उनकी अपनी-अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शनियां आयोजित करने में भी एक दूसरे की सहायता करेंगे। भारत और कीनिया में एमएसएमई के मध्य यी व्यापार गठबंधनों के विकास और प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण से दोनों देशों को पारस्परिक लाभ होगें। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक शर्तों पर एनएसआईसी द्वारा प्रस्तुत की जा रही परामर्शी सेवाएं, देश के लिए पर्याप्त ख्याति अर्जित करने के अलावा विदेशी मुद्रा में राजस्व सृजित करने में भी सहायक होंगी।

कर्नाटक और तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग

2287. **श्री बी.वाई. राघवेन्द्र : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में तमिलनाडु और कर्नाटक में तैयार तथा आरम्भ किए गए नए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन व्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो इन असंतुलनों को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में घोषित किए गए नए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा, राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए की जाती है न की क्षेत्रीय और जनसांख्यिकीय आधार पर।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु और कर्नाटक में घोषित किए गए नए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का ब्यौरा

2006-07

राज्य	रारा सं.	खंड	अनुमानित लंबाई कि.मी. में
तमिलनाडु	226	तंजावूर-गंधर्वकोट्टई-शिवगंगा-मनमदुरै	144
	227	तिरुचिरापल्ली-लालगुडी-कुमारात्वी-चिदम्बरम	135
कर्नाटक	शून्य		

2007-08

राज्य	रारा सं.	खंड	अनुमानित लंबाई किमी. में
तमिलनाडु	शून्य		
कर्नाटक	शून्य		
		2008-09	
तमिलनाडु	रारा-226 का विस्तार	पेराम्बलूर-पेराली-कीलापलूर-अरियालूर-कुन्नाम-तिरुवैयारू-कांडीयूर-तंजावुर	85
	230	मदुरै-तिरुपुवनम-पूवांधी-शिवगंगा-कलैयरकोयल-तिरुवदनै-टोंडी पोर्ट टाउन	82
	234	पेरणमपेट-गुड्डियट्टम-कटपडी-वेल्लौर-पुष्पगिरि-पोलुर-तिरुवनमलाई-विल्लुपुरम	190
कर्नाटक	234	मंगलौर-बेल्टनगडी-मुदीगेरे-बेलूर-हुलियार-सीरा-मधुगिरि-चिंतामणि	553
		2009-10	
तमिलनाडु	शून्य		
कर्नाटक	शून्य		

[अनुवाद]

गेहूं का आयात

2288. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में सरकार द्वारा गेहूं का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान गेहूं के आयात मूल्य तथा खरीद मूल्य संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) वर्तमान वर्ष अर्थात 2009-10 के दौरान सरकार द्वारा गेहूं का कोई आयात नहीं किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केवल 2006-07 और 2007-08 में गेहूं का आयात किया गया था और 2008-09 के दौरान गेहूं का कोई आयात नहीं किया गया था।

(ख) 2006-07 और 2007-08 के दौरान क्रमश: 53.79 लाख टन और 18.44 लाख टन गेहूं का आयात किया गया था।

(ग) 2006-07 और 2007-08 के दौरान आयातित गेहूं का औसत भारित मूल्य क्रमश: 205.34 यूएस डालर प्रति टन अर्थात

8214.00 रुपये (लगभग) और 366.83 यूएस डालर प्रति टन अर्थात अर्थात 14673.00 रुपये (लगभग) था।

पिछले तीन रबी विपणन मौसमों और वर्तमान मौसम के दौरान गेहूं के लिए निर्धारित खरीद मूल्य (न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रोत्साहन बोनस) निम्नानुसार हैं:-

रबी विपणन मौसम	न्यूनतम समर्थन मूल्य (बोनस सहित)
2006-07	700 रुपये
2007-08	850 रुपये
2008-09	1000 रुपये
2009-10	1080 रुपये

[हिन्दी]

कृषि पर निर्भरता

2289. श्री अर्जुन मुंडा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड सहित हमारी जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत कृषि से अपनी आजीविका कमाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा प्रतिशत-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में दो फसलों, मृदा परीक्षण, बीजों की समय पर उपलब्धता तथा किसानों हेतु उचित प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) भारत में जनगणना 2001 के अनुसार, 58.20% कृषक तथा झारखंड में 66.68% कृषक कृषि से अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। कुल कार्मिकों में राज्यवार कुल मजदूरों की संख्या कुल कार्मिकों में कृषि श्रमिक तथा कृषि श्रमिकों की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) सरकार विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गुणवत्ता बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास, राष्ट्रीय भू स्वास्थ्य एवं उर्वरक परियोजना, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन एजेन्सी के माध्यम से विस्तार प्रणाली पुर्नरुद्धार, कृषि स्नातकों के लिए कृषि क्लीनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना आदि के माध्यम से किसानों को मृदा परीक्षण, बीजों की समयानुसार उपलब्धता तथा समुचित प्रशिक्षण के क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करती हैं।

विवरण

जनगणना 2001 के अनुसार कुल कार्मिकों में कुल राज्यवार कार्मिक, कृषि कार्मिक एवं कृषि कार्मिकों की प्रतिशतता

(हजार संख्या में)

राज्य/संघशासित	कृषि पर निर्भर जनसंख्या	कुल कार्मिक	कुल कार्मिकों में कृषक की प्रतिशत्ता
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	21692	34894	62.17
अरुणाचल प्रदेश	298	483	61.70
असम	4994	9539	52.35
बिहार	21611	27975	77.25
छत्तीसगढ़	7420	9860	76.47
दिल्ली	53	4545	1.17
गोवा	86	523	16.44
गुजरात	10964	21256	51.58
हरियाणा	4297	8377	51.30

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	2049	2992	68.48
जम्मू और कश्मीर	1838	3754	48.96
झारखंड	6741	10109	66.68
कर्नाटक	13111	23535	55.71
केरल	2345	10284	22.80
मध्य प्रदेश	18439	25794	71.49
महाराष्ट्र	22629	41173	54.96
मणिपुर	493	945	52.17
मेघालय	639	970	65.88
मिजोरम	283	467	60.60
नागालैंड	580	848	68.40
उड़ीसा	9247	14276	64.77
पंजाब	3555	9127	38.95
राजस्थान	15664	23767	65.91
सिक्किम	148	263	56.27
तमिलनाडु	13754	27878	49.34
त्रिपुरा	589	1160	50.78
उत्तराखंड	1892	3134	60.37
उत्तर प्रदेश	35568	53984	65.89
पश्चिम बंगाल	13017	29482	44.15
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27	136	19.85
चंडीगढ़	3	340	0.88
दादरा और नगर हवेली	54	114	47.37
दमन और दीव	5	73	6.85
पांडिचेरी	83	343	24.20
लक्षद्वीप	—	15	—
भारत	234088	402235	58.20

स्रोत:- जनगणना 2001

[अनुवाद]

घटिया कीटनाशकों का इस्तेमाल

2290. श्री उदय सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घटिया कीटनाशकों के इस्तेमाल के कारण किसानों की फसलों का भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) सरकार को मंडी में नकली कीटनाशकों के निर्माण एवं बिक्री के संबंध में कीटनाशक उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ''बिजनेस स्टैण्डर्ड'' अखबार के दिनांक 22.9.2008 के अंक में प्रकाशित समाचार में नकली कीटनाशकों के कारण 6,000 करोड़ रु. के समतुल्य वार्षिक फसल हानि का उल्लेख किया गया है।

(ग) कीटनाशकों की गुणवत्ता की जांच राज्य सरकारों द्वारा कृमिनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत कीटनाशी विश्लेषकों, कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा कीटनाशकों के नमूनों के नियमित आहरण एवं विश्लेषण के जरिए की जाती है। 21 राज्यों तथा 1 संघ शासित क्षेत्र में 55 राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है जिनकी वार्षिक क्षमता 52,940 से अधिक कीटनाशक नमूनों का विश्लेषण

करने की है। चंडीगढ़ तथा कानपुर में स्थित दो क्षेत्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाएं जिनकी वार्षिक क्षमता 2000 नमूनों की है, कीटनाशकों के विश्लेषण में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संसाधनों को अनुपूरित करती हैं। इसके अलावा, सरकार ने एक रेफरल प्रयोगशाला के रूप में फरीदाबाद में एक केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला की स्थापना की है।

स्वर्ण भंडार

2291. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सहित देश में स्वर्ण भंडार वाले किन-किन नए क्षेत्रों की पहचान की गई हैं;

(ख) इन ब्लॉकों में स्वर्ण का राज्य-वार लगभग कितना भंडार है;

(ग) क्या इन खानों से स्वर्ण का खनन करने हेतु कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार इसके क्या परिणाम निकले?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) ने देश में अपने क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के फलस्वरूप कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों में अनेक स्वर्ण भंडारों की पहचान की है जहां अन्वेषणों के परिणामस्वरूप संसाधनों का निम्नानुसार अनुमान लगाया गया है:-

राज्य	वर्ष	ब्लॉक/जिला	स्वर्ण अयस्क का संसाधन	स्वर्ण का ग्रेड (ग्राम/टन)
1	2	3	4	5
राजस्थान	2005-06 और 2006-07	देलवाड़ा पश्चिम ब्लॉक, भूकिया स्वर्ण पट्टी, जिला बांसवाड़ा	4.78 मिलियन टन	1.32 ग्राम/टन
		देलवाड़ा ब्लॉक, भूकिया स्वर्ण पट्टी, जिला बांसवाड़ा	1.30 मिलियन टन	1.5 ग्राम/टन
		खंकरिया गारा ब्लॉक, भूकिया स्वर्ण पट्टी, जिला बांसवाड़ा	1.24 मिलियन टन	0.96 ग्राम/टन
		दुगोचा मेन (सेंट्रल) ब्लॉक और दुगोचा नॉर्थ ब्लॉक, जिला उदयपुर	0.16 मिलियन टन के अतिरिक्त संसाधन	–
	2007-08	देलवाड़ा पश्चिम ब्लॉक, बांसवाड़ा	5.36 मिलियन टन	2.09 ग्राम/टन
छत्तीसगढ़	2007-08	बाघमारा ब्लॉक, सोनाखान क्षेत्र, जिला रायपुर	0.09 मिलियन टन	0.93 ग्राम/टन
झारखंड	2005-06	परासी, जिला रांची	1.11 मिलियन टन	2.24 ग्राम/टन
		पहाडिया, जिला पश्चिम सिंहभूम	0.33 मिलियन टन	3.65 ग्राम/टन
कर्नाटक	2005-06	अज्जनहल्ली ईस्ट ब्लॉक, जिला तुमकुर	0.293 मिलियन टन	

1	2	3	4	5
	2006-07	अज्जनहल्ली ईस्ट ब्लॉक (नॉर्थ सेक्टर), जिला तुमकुर	0.38 मिलियन टन	1.70 ग्राम/टन

(ग) और (घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संसाधनों की उपलब्धता का अनुमान लगाने के लिए क्रमबद्ध रूप से खनिजों हेतु क्षेत्रीय गवेषण करता हैं पूर्वेक्षण और खनन, तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक लाभ के आधार पर मुख्यतया निजी उद्यमों द्वारा किया जाता है। खनिज राज्य सरकारों की सम्पत्ति हैं और राज्य सरकारों द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार, उन्हें प्रस्तुत किए गए आवेदनपत्रों के आधार पर खनन पट्टे प्रदान किए जाते हैं और इन आवेदनपत्रों की सूचना भारत सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है। तथापि, खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम ई सी एल) ने जी एस आई द्वारा पूर्व में पहचाने गए स्वर्ण भंडारों के लिए निम्नलिखित नए क्षेत्रों में विस्तृत गवेषण (पूर्वेक्षण) किया है:-

क्रम सं.	ब्लॉक का नाम	जिला	राज्य	भंडार (मिलियन टन)	स्वर्ण का ग्रेड
1.	भूकिया ईस्ट	बांसवाड़ा	राजस्थान	11.74	2.51 ग्राम/टन
2.	परासी सेंट्रल (चरण I व II)	रांची	झारखंड	फील्ड कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रतिचयन और प्रयोगशाला कार्य प्रगति पर है।	

वर्ष 2008-09 के दौरान, एम ई सी एल ने धानी बसरी प्रॉस्पेक्ट, जिला दौसा, राजस्थान में विस्तृत गवेषण भी पूरा किया है जहां 1.17 प्रतिशत तांबा और 1.27 ग्राम/टन स्वर्ण वाले कुल 5.13 मिलियन टन तांबा और स्वर्ण अयस्क का अनुमान लगाया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु धनराशि

2292. श्री गणेश सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु विभिन्न राज्यों को प्रति किलोमीटर राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश राज्य हेतु धनराशि का हिस्सा अन्य राज्यों की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार मध्य प्रदेश राज्य को अन्य राज्यों के समान ही राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु धनराशि प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन केवल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पर निर्भर नहीं करता अपितु लेन की चौड़ाई, भूस्थलाकृति के प्रकार, यातायात घनत्व, मिट्टी के प्रकार, क्षति की सीमा, वर्षा के घनत्व आदि पर भी निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान आबंटन में से किए गए व्यय और अनुमानित अपेक्षित निधि के संदर्भ में राज्यों के कार्य निष्पादन की भी समय-समय पर समीक्षा आबंटनों के संशोधन के समय की जाती है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए निधियों की आवश्यकता की तुलना में, निधियों की उपलब्धता सीमित होती है। उपर्युक्त कारणों से प्रति किलोमीटर आबंटन, प्रत्येक राज्य के लिए भिन्न होता है।

वर्ष 2008.09 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए प्रति किलोमिटर आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए प्रति किलोमीटर आबंटित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 के दौरान कुल आबंटन (करोड़ रुपए)	प्रति किलोमीटर की दर से आबंटन (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	83.25	3.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.82	2.22
3.	असम	40.20	3.00
4.	बिहार	44.50	1.56
5.	चंडीगढ़	0.68	2.83
6.	छत्तीसगढ़	27.26	1.48
7.	गोवा	5.01	1.96
8.	गुजरात	42.04	2.67
9.	हरियाणा	19.64	1.89
10.	हिमाचल प्रदेश	18.84	1.78
11.	झारखंड	20.38	1.29
12.	कर्नाटक	71.24	2.48
13.	केरल	21.75	1.85
14.	मध्य प्रदेश	48.66	1.24
15.	महाराष्ट्र	62.92	2.17
16.	मणिपुर	10.24	3.85
17.	मेघालय	17.53	2.82
18.	मिजोरम	9.20	2.71
19.	नागालैंड	10.78	3.98
20.	उड़ीसा	52.56	1.72
21.	पुदुचेरी	1.10	2.15
22.	पंजाब	25.58	2.22
23.	राजस्थान	72.35	1.75
24.	तमिलनाडु	49.40	3.96
25.	उत्तर प्रदेश	55.22	1.54
26.	उत्तराखंड	21.87	2.02
27.	पश्चिम बंगाल	31.49	2.52

[अनुवाद]

खादी के उत्पादों हेतु बाजार विकास योजना

2293. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार विकास योजना के संदर्भ में खादी उत्पादों की बिक्री के लिए छूट दी जाती है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस योजना से शिल्पकार की बजाए विक्रेता को ही लाभ होता है।

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार योजना को नया रूप देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) सरकार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उपलब्ध कराये गये खादी एवं खादी उत्पादों की खुदरा बिक्री पर खादी में छूट एक सरकारी सब्सिडी है। वर्ष भर ग्राहकों को खादी बिक्री पर 10% की सामान्य छूट प्रदान की जाती है और स्थानीय उत्सवों आदि के अवसर पर 108 दिवसों के लिए 10% की दर से एक अतिरिक्त विशेष छूट भी दी जाती है। सरकार द्वारा गठित अनेक समितियों ने यह पाया कि इस क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से अन्तर्निहित निम्न उत्पादकता के मद्देनजर खादी को सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि यह मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके तथा केवल छूट देकर ही नहीं बल्कि गुणवत्ता, डिजाइन एवं अपील द्वारा ग्राहकों को आकर्षित कर सके।

विभिन्न समितियों की सिफारिशों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर यह महसूस किया गया है कि छूट योजना का कारगर विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है और सरकार खादी के उत्पादन पर बाजार विकास सहायता (एमडीए) की बेहतर आकर्षक योजना पर विचार कर रही है। आशा है कि खादी संस्थानों को एमडीए के तहत सहायता से कारीगरों की मजदूरी बढ़ेगी, संस्था को अपनी अवसंरचना सुधारने में सहायता मिलेगी, यदि आवश्यक हो तो सीजनल छूट मिलेगी, कारीगरों का कौशल उन्नयन होगा, खादी की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा सहायता का उपयोग करने में कुछ लचीलापन प्रदान करके विपणन संपर्क बढ़ेंगे।

तालिबान आतंकवादियों की घुसपैठ

2294. श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर तालिबान आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के समाचार हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में प्रकाश में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या हैं; और

(घ) तालिबान आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ से उत्पन्न खतरे का सामना करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सरकार को व्यक्तियों की अवैध सीमा पार की गतिविधियों की जानकारी है। तथापि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तालिबानी उग्रवादियों के घुसपैठ की कोई पुष्टि नहीं हुई है।

(घ) भारत-पाक सीमा पर अवैध घुसपैठ को नियंत्रित करने तथा व्यक्तियों की अवैध सीमा-पार की गतिविधियों को रोकने के क्रम में, भारत सरकार ने एक बहुआयामी नीति अपनाई है, यथा:–

(i) सीमा सुरक्षा बल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर चौबीस घंटे निगरानी की जाती है।

(ii) सम्पूर्ण भारत-पाक सीमा के साथ-साथ बाड़ लगाने, तेज रोशनी की व्यवस्था करने और चौकसी सड़कों का निर्माण करने का कार्य शुरू किया गया है।

(iii) ढ़ांचे को मजूबत बनाने के लिए अतिरिक्त 126 सीमा चौकियों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रभावी वर्चस्व कायम करने के लिए रात्रि अवलोकन उपकरणों सहित आधुनिक निगरानी उपकरण सीमा सुरक्षा को प्रदान किए गए हैं।

(v) सीमा सुरक्षा बल ने अन्य आसूचना एजेन्सियों के साथ समन्वय एवं आसूचना तंत्र को भी सुदृढ़ बना दिया है।

प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2295. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अधिकतम सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो ट्राई द्वारा की गई सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में हिस्सेदारों के साथ कोई चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने प्रिंट मिडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उच्चतम सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

2296. श्री जोस के. मणि : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फसलों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अपनाया/नहीं अपनाया है;

(घ) क्या केरल सहित किसी राज्य ने उक्त योजना को कार्यान्वित करने में कठिनाई व्यक्त की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। मौजूदा फसल बीमा स्कीमों में अपेक्षित सुधारों का अध्ययन करने के लिये सरकार द्वारा गठित संयुक्त समूह ने राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) की प्रगति की समीक्षा की तथा महत्वपूर्ण सिफारिशें की जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख फसलों के लिये बीमा के एकल क्षेत्र में कटौती, थ्रेशहोल्ड उपज के परिकलन की उन्नत विधि, उच्च क्षतिपूर्ति स्तर, अतिरिक्त जोखिमों का कवरेज आदि शामिल हैं।

(ग) उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सूची जिन्होंने एनएआईएस को अपनाया/नहीं अपनाया है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) देश में एनएआईएस का सुचारू क्रियान्वयन करने के लिये भारत सरकार सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को स्कीम के क्रियान्वयन की विस्तृत शर्तों सहित प्रशासनिक निर्देश जारी करती है और पर्याप्त बजटीय प्रावधान करती है। स्कीम के संबंध में जागरूकता लाने के लिये राज्य/क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से मुद्रण तथा इलेक्ट्रानिक, दोनों माध्यमों से व्यापक जागरूकता अभियान; राज्य सरकार की एजेंसियों तथा बैंकों के साथ सक्रिय सम्पर्क; कृषि मेलों/किसान मेलों में भागीदारी; राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं के साथ स्कीम की प्रगति की आवधिक समीक्षा आदि किये जाते हैं।

विवरण

क्र. सं.	उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम जहां एनएआईएस क्रियान्वित किया जा रहा रहा है	उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम जहां एनएआईएस क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश
2.	असम	नागालैंड
3.	बिहार	पंजाब
4.	छत्तीसगढ़	चंडीगढ़
5.	गुजरात	दिल्ली
6.	हरियाणा	दमन और दीव
7.	हिमाचल प्रदेश	दादरा और नगर हवेली
8.	गोवा	लक्षद्वीप
9.	जम्मू और कश्मीर	

1	2	3
10.	झारखंड	
11.	कर्नाटक	
12.	केरल	
13.	महाराष्ट्र	
14.	मध्य प्रदेश	
15.	मणिपुर	
16.	मिजोरम	
17.	मेघालय	
18.	उड़ीसा	
19.	राजस्थान	
20.	सिक्किम	
21.	तमिलनाडु	
22.	त्रिपुरा	
23.	उत्तर प्रदेश	
24.	उत्तराखण्ड	
25.	पश्चिम बंगाल	
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	
27.	पुदुचेरी	

हिमाचल प्रदेश में मत्स्यन

2297. श्री वैजयंत पांडा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्यन हिमाचल प्रदेश में रोजगार सृजन के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार केन्द्रीय राजसहायता प्रदान करके हिमाचल प्रदेश मॉडल को देश के अन्य भागों में दोहराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) मात्स्यिकी हिमाचल प्रदेश राज्य में एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि नहीं हैं। इस राज्य में प्रतिवर्ष मात्र लगभग 7500 टन मछली उत्पादन होता है। जिसमें मुख्यत: जलाशय और नदीय मात्स्यिकी शामिल है तथा ट्राऊट पालन का एक छोटा सा योगदान है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शरणार्थियों को नागरिकता का दर्जा

2298. योगी आदित्यनाथ : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1947 में पाकिस्तान से आकर जम्मू में बस गए शरणार्थियों को नागरिकता का दर्जा विवादित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे व्यक्तियों को भारत के संविधान में दिए गए अधिकारों से वंचित रखा गया हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) जम्मू एवं कश्मीर में वर्ष 1947 से रह रहे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी भारत के नागरिक हैं और उन्हें संसद के चुनावों में मतदान करने का अधिकार है, परन्तु, राज्य के स्थायी निवासी न होने के कारण वे राज्य विधान सभा के चुनावों में मत देने के पात्र नहीं है। इस कारण उन्हें निम्नलिखित परेशानियां होती हैं:-

(i) वे जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थायी सम्पत्ति धारण नहीं कर सकते।

(ii) वे अपने धारणाधिकार वाली जमीन ऋण लेने के लिए गिरवी नहीं रख सकते।

(iii) वे राज्य सरकार में नौकरी प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

(iv) उनमें से अनुसूचित जाति के लोग राज्य में अनुसूचित जाति के लिए उपलब्ध आरक्षण कोटा प्राप्त करने के पात्र नहीं है

(v) उनके बच्चे राज्य के सरकारी व्यावसायिक/तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

उनकी दिक्कतों को कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25.04.2008 को जम्मू-कश्मीर के लिए एक पैकेज की घोषणा की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में रह रहे पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के बच्चों एवं प्रपौत्रों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) से मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने के मामले में रियायत का प्रावधान किया गया है। इन शरणार्थियों को बिना संपार्श्विक गारंटी के बैंक ऋण लेने की सुविधा भी दी गई है और भारतीय स्टेट बैंक ने 45 लाभग्रहियों को लगभग 28.80 लाख रुपये का ऋण दिया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी दक्षता विकास पहल के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान करने के संबंध में रियायतों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी कर रहा है।

[अनुवाद]

खरीद के लिए लक्ष्य

2299. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2008-09 के दौरान खाद्यान्नों की खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित और हासिल किए गए;

(ग) यदि नहीं, तो घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आगामी वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा के उत्पादन और खरीद के लिए कोई कार्यनीति तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2009-10 के दौरान खाद्यान्नों की अनुमानित मांग और लक्षित खरीद का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के अधीन खाद्यान्नों की खरीदारी खुली होती है और कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी के लिए किसानों द्वारा पेशकश किए गए गेहूं और चावल को भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों द्वारा खरीदा जाता है। तथापि, प्रत्येक रबी विपणन मौसम और खरीफ विपणन मौसम की शुरुआत से पहले राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक में अनुमान लगाए जाते हैं। 2008-09 के दौरान गेहूं और चावल की अनुमानित तथा वास्तविक खरीद की सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 2009-10 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए गेहूं और चावल की अनुमानित मांग क्रमशः 214.77 लाख टन और 270.52 लाख टन है। रबी विपणन मौसम 2009-10 में 244.2 लाख टन गेहूं की खरीद होने का अनुमान लगाया गया था। खरीफ विपणन मौसम 2009-10 में चावल की खरीद के अनुमानों को 1.10.2009 को मौसम की शुरुआत से पहले राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ होने वाली बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ङ) 2009-10 में खाद्यन्नों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 के दौरान गेहूं और चावल की अनुमानित तथा वास्तविक खरीद निम्नानुसार है:

(लाख टन)

गेहूं

क्र. सं.	राज्य	अनुमानित खरीद	2008-09 में वास्तविक खरीद*
1	2	3	4
1.	पंजाब	80	99.41

1	2	3	4
2.	हरियाणा	40	52.37
3.	उत्तर प्रदेश	20	31.37
4.	राजस्थान	5	9.35
5.	चंडीगढ़	—	0.10
6.	झारखंड	—	0.01
7.	जममू और कश्मीर	—	0.01
8.	मध्य प्रदेश	3	24.10
9.	गुजरात	2	4.15
10.	बिहार	2	5
11.	उत्तराखंड	1	0.85
12.	महाराप्ट्र	—	0.10
13.	दिल्ली	—	0.07
	कुल	153	226.89

*16.7.2009 की स्थिति के अनुसार

चावल

(लाख टन)

क्र. सं.	राज्य	अनुमानित खरीद	2008-09 में वास्तविक खरीद*
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	55	78-69
2.	असम	1	0.01
3.	बिहार	6.7	10.39
4.	छत्तीसगढ़	24	25.90
5.	गुजरात	1	0
6.	हरियाणा	13	14.25
7.	झारखंड	1	1.33
8.	केरल	2.7	2.37
9.	कर्नाटक	2	1.06
10.	मध्य प्रदेश	1	2.09
11.	महाराष्ट्र	2	2.51
12.	उड़ीसा	27.8	26.30
13.	पंजाब	85	85.45
14.	तमिलनाडु	10	11.35
15.	उत्तर प्रदेश	31.9	36.12
16.	उत्तराखंड	2.0	3.49
17.	पश्चिम बंगाल	15.8	14.56
18.	अन्य		0.34
	कुल	282.0	316.21

*16.7.2009 की स्थिति के अनुसार

विवरण-II

वर्ष 2009-10 की मांग को पूरा करने के लिए गेहूं ओर चावल की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

गेहूं

- रबी विपणन मौसम 2008-09 में गेहूं के खरीद मूल्य (न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा प्रोत्साहन बोनस) को 1000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ा कर रबी विपणन मौसम 2009-10

में 1080 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप रबी विपणन मौसम 2009-10 में (17.07.2009 की स्थिति के अनुसार) गेहूं की 251.42 लाख टन खरीद हुई है, जबकि रबी विपणन मौसम 2008-09 में कुल खरीद 226.89 लाख टन हुई थी।

- राज्य सरकारों को अधिकतम खरीद करने के लिए सभी प्रयास करने के लिए राजी किया गया है। इन प्रयासों के पाणिामस्वरूप रबी विपणन मौसम 2009-10 में खरीद उच्चतम स्तर के रिकार्ड पर पहुंच गई है।

- निजी तौर पर शून्य शुल्क पर अगले आदेशों तक गेहूं के आयात की अनुमति दी गई है।

- गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रखा गया है।

चावल

- खरीफ विपणन मौसम 2007-08 में सामान्य तथा श्रेणी-क के धान का खरीद मूल्य (न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा प्रोत्साहन बोनस) 745/- रुपए तथा 775/- रुपए था, जिसे खरीफ विपणन मौसम 2008-09 में बढ़ा कर 900/- रुपए और 930/- रुपए कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप खरीफ विपणन मौसम 2008-09 में (07.07.2009 की स्थिति के अनुसार) चावल की 316.55 टन खरीद हुई, जबकि खरीफ विपणन मौसम 2007-08 में कुल खरीद 284.93 लाख टन थी।

- राज्य सरकारों को अधिकतम खरीद करने के लिए सभी प्रयास करने के लिए राजी किया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप खरीफ विपणन मौसम 2008-09 में खरीद उच्चतम स्तर के रिकार्ड पर पहुंच गई है।

- गैर-बासमती चावल के निर्यात को सीमित किया गया है और बाद में 01.04.2008 से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

- शून्य शुल्क पर चावल के आयात की अनुमति दी गई है।

- बासमती चावल के निर्यात को 6 निर्धारित पत्तनों के जरिए ही 1100 डालर प्रति टन (फॉब) के न्यूनतम निर्यात मूल्य तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।

- जमाखोरी को रोकने के लिए धान और चावल पर स्टॉक सीमाएं लगाने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान की गई हैं।

राट्रीय खेल

2300. श्री यशवंत सिन्हा :
श्री सर्वे सत्यनारायण :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि, :

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड में आयोजित होने वाले 34वें राष्ट्रीय खेलों को स्थगित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त खेलों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्टें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या 35वें राष्ट्रीय खेलों का स्थल निश्चित कर लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय खेल, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) द्वारा आबंटित किए जाने के बाद मेजबान राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। आईओए ने सूचित किया है कि 34वां राष्ट्रीय खेल 21 नवंबर से 5 दिसंबर, 2009 तक झारखंड में आयोजित किया जाएगा।

(ग) और (घ) 34वें राष्ट्रीय खेलों के लिए परियोजनाओं का निष्पादन कार्य झारखंड राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) ने राष्ट्रीय खेलों के लिए झारखंड राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है और परियोजनाओं के निष्पादन की मानीटरिंग भी नहीं कर रहा है।

(ङ) और (च) भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 35वां राष्ट्रीय खेल, केरल राज्य को आबंटित किया गया है और उसे मई 2010 में आयोजित किया जाना है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जागरूकता

2301. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए किसानों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) से यह पता चला है कि में लगभग 71 प्रतिशत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संकल्पना की जानकारी नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो किसानों के लाभ के लिए चल रहे विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने और इनका प्रचार-प्रसार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा अपने 59वें दौर (जनवरी-दिसम्बर 2003) में किए गए किसानों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) के अनुसार 19 प्रतिशत किसान न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य को समझते थे बल्कि उन एजेन्सियों (भले ही इसका नाम और स्थिति से अनभिज्ञ) को जानते थे जिसको वे बाजार मूल्य के नीचे न्यूनतम समर्थन मूल्य के आ जाने पर अपनी फसल को बेचते। 10 प्रतिशत किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को समझते थे लेकिन प्रापण एजेन्सियों को नहीं समझते थे। शो 71 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य से अनभिज्ञ अथवा इसकी अवधारणा को नहीं जानते थे।

(ख) किसानों के बीच जागरूकता लाने के लिए बहुत सी स्कीमों के माध्यम से विस्तार कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करते हुए राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न स्कीमों में शामिल हैं:

विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों के लिए सहायता, कृषि को जन संचार समर्थन, किसान काल सेन्टर तथा कृषि स्नातकों द्वारा कृषि-क्लीनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना। कृषि को जन संचार समर्थन पर केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अन्तर्गत कृषि समुदाय को कृषि संबंधी सूचना तथा जानकारी 180 सूक्ष्म निक्षेपण केन्द्रों, 18 क्षेत्रीय केन्द्रों, 1 राष्ट्रीय दूरदर्शन केन्द्र एवं 96 एफ.एम. रेडियों स्टेशनों के माध्यम से प्रदान की जाती है। कृषि सूचना प्रसार के अन्तर्गत किसानों को कृषि के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर उपयोगी सूचना प्रदान की जाती है जिसमें प्रिन्ट मीडिया, स्थानीय स्तर की कृषि प्रदर्शनियों तथा इलैक्ट्रानिक फार्म में प्रौद्योगिकी पैकेजों के विकास के माध्यम से उनकी उपज तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि का विपणन शामिल है। प्रौद्योगिकी प्रसार हेतु देश में 583 जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सियां (आतमा) स्थापित की गई हैं।

[हिन्दी]

गन्ने का उत्पादन

2302. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री सर्वे सत्यनारायण :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गन्ने का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या गन्ने के उत्पादन में कमी ने उच्च कीमतों पर कच्ची शक्कर के आयात की आवश्यकता को बढ़ावा दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या गन्ना उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य नहीं प्रदान किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) गत तीन वर्षों अर्थात 2005-06 से 2007-08 तथा चालू वर्ष के दौरान गन्ने का राज्य-वार उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) 2007-08 की तुलना में गन्ना मौसम 2008-09 में गन्ने के उत्पादन में गिरावट हुई है। अत: चीनी के घरेलू स्टॉक में वृद्धि करने तथा इसे उपभोक्ताओं को उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार ने कतिपय कदम उठाए हैं। केन्द्र सरकार ने दिनांक 01.08.2009 तक खुला सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत कच्ची शक्कर के शुल्कमुक्त आयात की अनुमति दी है। अग्रिम अनुज्ञप्ति योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए भारत में कच्ची शक्कर के बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंधों के इसके संसाधन तथा बिक्री हेतु दिनांक 30.09.2006 तक शुल्क मुक्त

आयात की अनुमति प्रदान की गयी है। व्यापारिक समुदायों के अनुसार भारतीय चीनी फैक्ट्रियों द्वारा 25 लाख टन कच्ची शक्कर का अनुबंध किया गया है जिसमें से 18.20 लाख टन कच्ची शक्कर पहले ही आ चुकी है अथवा जुलाई, 2009 की समाप्ति पर शीघ्र ही आने वाली है।

(घ) से (च) नहीं महोदया जी। गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्र सरकार विभिन्न कारकों यथा गन्ने उत्पादन लागत; वैकल्पिक फसलों से किसानों को लाभ तथा कृषि जिन्सों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति; उचित दर पर उपभोक्ताओं को चीनी की उपलब्धतता एवं गन्ने से चीनी की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गन्ना मौसम हेतु गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3 के संदर्भ में गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती रही है। गन्ना (नियन्त्रण) आदेश को इसके उप-उत्पादों यथा शीरा, खोई प्रेस-मड की प्राप्ति अथवा गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के निर्धारण में आरोपित मूल्य पर भी विचार करने के लिए दिनांक 29.12.2008 को संशोधित किया गया है। पुनः, गन्ना (नियन्त्रण) आदेश के खंड 5ए के अनुसार किसान सांविधिक न्यूनतम मूल्य पर एक अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने के हकदार हैं जो चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित आधिक्य पर निर्भर करता है।

गन्ने से अन्य फसलों की ओर कृष्य भूमि में अंतरण की रोकथाम करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि गन्ने की खेती गेहूं तथा धान की तुलना में आकर्षणहीन तथा अलाभदायक न हो, सरकार ने हाल ही में गत गन्ना मौसम हेतु निर्धारित 81.18 रुपए प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की तुलना में 107.76 रुपए प्रति क्विंटल पर 2009-10 गन्ना मौसम हेतु गन्ने का उच्चतर सांविधिक न्यूनतम मूल्य के निर्धारण का अनुमोदन किया है।

विवरण

वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान गन्ने उत्पादन के राज्य-वार अनुमान

राज्य/संघशासित क्षेत्र	उत्पादन ('000 टन)			
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	17656.0	21692.0	20296.0	16612.0
अरुणाचल प्रदेश	16.8	16.8	21.8	#
असम	871.2	1055.0	980.0	996.0
बिहार	4337.9	5955.5	3854.9	4980.0
छत्तीसगढ़	16.4	18.7	27.5	39.0
गुजरात	14580.0	15630.0	15190.0	15040.0
गोवा	55.9	58.0	56.0	#
हरियाणा	8180.0	9580.0	8860.0	5688.0
हिमाचल प्रदेश	25.1	59.0	58.4	53.0
जम्मू और कश्मीर	0.8	0.8	0.2	0.6
झारखंड	142.0	142.0	150.0	150.0
कर्नाटक	18267.0	28669.7	26240.0	23505.0
केरल	916.5	440.0	218.0	256.0
मध्य प्रदेश	2425.0	2806.0	3180.0	2705.0
महाराष्ट्र	38853.0	78568.0	88437.0	50813.0
मणिपुर	23.0	23.0	16.8	#
मेघालय	0.2	0.2	0.3	#
मिजोरम	4.6	4.6	0.8	#
नागालैंड	210.9	233.9	247.3	#
उड़ीसा	1073.0	1274.4	1096.2	634.0
पंजाब	4860.0	6020.0	6690.0	4880.0
राजस्थान	482.6	629.7	593.8	414.0
तमिलनाडु	35106.5	41124.0	38071.0	33283.0
त्रिपुरा	52.6	42.4	46.7	#

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	125469.9	133949.4	124665.3	121408.0
उत्तरांचल	6134.0	6100.0	7686.0	5555.0
पश्चिम बंगाल	1247.7	1266.7	1272.0	1600.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.9	2.6	3.5	#
पांडिचेरी	157.3	157.3	228.4	#
अन्य	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	622.0
अखिल भारत	281171.8	355519.7	348187.9	289233.6

*तीसरे अग्रिम अनुमान

#अन्य में शामिल

एन.ए. लागू नहीं

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की खरीद के लिए धनराशि का आवंटन

2303. **श्री अधीर चौधरी :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों की खरीद के लिए राज्यों को धनराशि आवंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो धान की खरीद के लिए राज्यों को आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और उनसे राज्य-वार कितनी मात्रा में धान की खरीद की गई; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं/दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) भारत सरकार खाद्यान्नों की खरीदारी के लिए राज्य सरकारों को कोई धन आबंटित नहीं करती है। भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत खाद्यान्न की खरीदारी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से नकद ऋण का उपयोग करती हैं। कुछ राज्य सरकारें खरीदारी कार्यों को करने के लिए राज्य एजेंसियों को बजटीय समर्थन भी प्रदान करती है।

[हिन्दी]

सीआरपीएफ में स्थानान्तरण/तैनाती नीति

2304. **श्री रमेश बैस :**
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री बाल कुमार पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीआरपीएफ कार्मिकों के लिए स्थानान्तरण/तैनाती नीति बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इस नीति का सावधानी के साथ अक्षरश: पालन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी हां।

(ख) सी.आर.पी.एफ. कार्मिकों के लिए स्थानातंरण नीति सीआरपीएफ में पहले से ही विद्यमान है जिसमें सेवा संबंधी विभिन्न पहलुओं जैसे कि पेशागत अपेक्षाएं, कैरियर प्रबंधन इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

चीनी मिलों की क्षमता को बढ़ाना

2305. **डॉ. भोला सिंह :**
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में चीनी मिलों की अर्थक्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से एथनाल के उत्पादन की अनुमति देने के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों और चीनी उद्योग से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चीनी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गन्ना नियंत्रण आदेश में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) चीनी कारखानों को इथानॉल का उत्पादन करने की पहले ही अनुमति है। शीरे से इथानॉल का उत्पादन करने से चीनी कारखानों की व्यवहार्यता में सुधार होता है।

(ख) शीरे से इथानॉल का उत्पादन करने के लिए परियोजनाएं लगाने हेतु चीनी कारखानों को चीनी विकास निधि से 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर रियायती ऋण प्रदान किया जा रहा है। इथानॉल के लिए आश्वस्त बाजार प्रदान करने हेतु सरकार ने अक्तूबर, 2007 से पैट्रोल में 5 प्रतिशत इथानॉल का मिश्रण अनिवार्य करने का निर्णय लिया है, जिसे पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू और कश्मीर और द्वीपसमूहों को छोड़कर सम्पूर्ण देश में बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाना था। सरकार ने 21.50 रुपये प्रति लीटर का एक समान निकासी खरीद मूल्य भी निर्धारित किया है।

(ग) और (घ) गन्ने के रस से इथानॉल का उत्पादन करने के लिए चीनी कारखानों को अनुमति देने हेतु गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 को पहले ही संशोधित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

टैक्सीचालकों द्वारा अधिक किराया वसूलना

2306. श्रीमती जयाप्रदा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर प्रीपेड टैक्सी चालकों की सेवाएं लेने वाले यात्रियों के उत्पीड़न, अधिक किराया वसूलने और यात्रियों द्वारा प्री-पेड टोकन प्राप्त करने के बावजूद कम दूरी की यात्रा से इनकार करने की रिपोर्टें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उपचारात्मक कार्रवाई करने और प्रीपेड टोकनों पर टैक्सी की पंजीकरण संख्या देने के साथ इनका कम्प्यूटरीकरण करने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) और (घ) प्रीपेड सेवा प्राप्त करने वाले यात्रियों को अभी हाल तक कम्प्यूटरीकृत वाउचर जारी किए जा रहे थे। आई.जी.आई. हवाई अड्डे पर प्रीपेड सेवाओं को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण करना एक पायलट परियोजना है। जब तक उपर्युक्त परियोजना कार्य करना शुरू नहीं करती है तब तक यात्रियों की आवाजाही के लिए मैनुअल वाउचर जारी किए जाते है।

विवरण

वर्ष	शिकायतों की संख्या	शिकायतों का निस्तारण	यातायात पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
2008	100	100	इस मामले में अभियोजन का विवरण निम्नलिखित है:- 1. नोटिस शाखा द्वारा चालान किया गया - 04

1	2	3	4
			2. शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने पर नियन्त्रण कक्ष द्वारा की गई कार्रवाई - 01 3. विविध शिकायतों पर की गई कार्रवाई - 02 4. क्षेत्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित के लिए की गई कार्रवाई:- अस्वीकरण - 45 अधिक किराया वसूलना - 26 परमिट उल्लंघन - 22 कुल 93
2009 (30.6.2009 तक)	36	36	इस मामले में अभियोजन का विवरण निम्नलिखित है:- 1. नोटिस शाखा द्वारा चालान किया गया-05 2. शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने पर नियन्त्रण कक्ष द्वारा की गई कार्रवाई-03 3. क्षेत्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित के लिए की गई कार्रवाई:- अस्वीकरण - 03 अधिक किराया वसूलना - 66 परमिट उल्लंघन - 09 कुल 28

[हिन्दी]

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना

2307. श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों को उक्त योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है/कराए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. एम.एस.गिल) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने पहली बार, देश के सभी गांवों तथा ब्लाक पंचायतों में बुनियादी खेल अवसंरचना और खेल प्रतिस्पर्धाओं के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम प्रारंभ

की है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रारंभ की गई इस स्कीम के लिए XIवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय 1500 करोड़ रु. है। स्कीम में 10 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से 10% वार्षिक कवरेज की दर से 2.50 लाख ग्राम पंचायतों और 6,400 ब्लाक पंचायतों को (उनकी समतुल्य इकाइयों सहित) शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) इस स्कीम के तहत सहायता की निम्नलिखित पद्धति को अपनाया गया है:-

क्र.सं.	घटक	ग्राम पंचायत	ब्लॉक पंचायत
1.	एकमुश्त अनुदान (केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 75:25 के आधार पर; विशेष श्रेणी के राज्यों/उत्तर-पूर्व राज्यों के मामलों में 90:10 के आधार पर) 100% केन्द्रीय अनुदान	1 लाख रु.	5 लाख रु.
2.	वार्षिक अधिग्रहण अनुदान	10,000/-रु.	20,000/-रु.
3.	वार्षिक प्रचालन अनुदान	12,000/-रु.	24,000/-रु.
4.	वार्षिक प्रतिस्पर्धा अनुदान		
	क. ब्लाक स्तरीय प्रतिस्पर्धा	50,000/-रु.	
	ख. जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धा	3 लाख रु.	
	ग. राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा	राज्य के लिए 10 लाख रु.	
		संघ राज्य क्षेत्र के लिए 5 लाख रु.	
	घ. राष्ट्र स्तरीय प्रतिस्पर्धा	मेजबान राज्य (20 खेल विधाओं के लिए प्रति खेल विधा 3.5 लाख रु.) के लिए 70 लाख रु.	
5.	ब्लाक और जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में विजेता के लिए पुरस्कार राशि		
	क. ब्लॉक स्तरीय प्रतिस्पर्धा	प्रथम तीन स्थानों पर आने वाली गांव पंचायतों के लिए 25,000/-रु; 15,000/-रु. और 5,000/-रु.	
	ख. जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धा	प्रथम तीन स्थानों पर आने वाली ब्लाक पंचायतों के लिए 50,000/-रु; 30,000/-रु. और 10,000/-रु.	
6.	उत्तर-पूर्व खेल महोत्सव/खेल	ग्राह्य अनुदान के अनुसार	

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तावों को प्रस्तुत करने तथा उनके द्वारा सभी अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2008-09 के दौरान, 24 राज्यों के लिए 22,854 गांवों तथा 601 ब्लॉक पंचायतों

योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए कार्यान्वित की जाती है।

में खेल अवसंरचना के सृजन के लिए 250.77 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता को संस्वीकृति प्रदान की गई। इस स्कीम के लिए 2008-09 के बजट में 92.00 करोड़ रु. के आबंटन में से, 92.00 करोड़ रु. राज्यों को जारी किए गए थे। 2009-10 में बजट आबंटन 160.00 करोड़ रु. हैं जिसमें से अभी तक 19.92 करोड़ रु. राज्यों को जारी किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

एनएचआरसी में रिक्त पद

2308. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पदाधिकारी के सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस रिक्त पद को अतिशीघ्र भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी नहीं।

(ख) न्यायमूर्ति एस राजेन्द्र बाबू ने 31 मई, 2009 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 7(1) के तहत 1 जून, 2009 से न्यायमूर्ति जी.पी. माथुर को नया अध्यक्ष नियुक्त होने तक एन.एच.आर.सी. के अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर रखा है।

दूसरी हरित क्रांति

2309. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूसरी हरित क्रांति शुरू करने के संबंध में किसान आयोग सहित विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) समय-समय पर सरकार उसी कृषि क्षेत्र का पुनरूद्धार करने, उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने, क्षेत्रों की विकास दरों में वृद्धि करने, किसानों की आयों के संवर्धन के लिए सुझाव प्राप्त करती रहती है। प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने यह कहते हुये अपनी पांचवी और अंतिम रिपोर्ट में ''सदाहरित क्रांति'' के लिये पिछला हवाला दिया कि जैव प्रौद्योगिकी, सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों और नानों प्रौद्योगिकी जैसी सीमान्त प्रौद्योगिकियां सदाहरित कांति शुरू करने के लिये अवसर उपलब्ध कराती हैं।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये सरकार पहले से ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना तथा पादप किस्मों तथा कृषक अधिकार प्राधिकरण का संरक्षण करने, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) स्कीम, राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम, व्यापक ऋण पैकेज, ऋण छूट स्कीम, सहकारी ऋण संस्थानों के पुनर्गठन, तिलहनों एवं दलहनों संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन जैसे कई पहलें शुरू कर चुकी है। इसके अतिरिक्त सरकार ने एनसीएफ की कई सिफारिशों को शामिल करते हुये 2007 में किसान नीति घोषित की जिसका उद्देश्य किसानों के आर्थिक कल्याण पर विशेष बल देते हुए भारतीय कृषि का पुनर्गठन करना है।

[हिन्दी]

ड्रिप/छिड़काव के माध्यम से सिंचाई

2310. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बिहार सहित देश के कुल कितने क्षेत्र को ड्रिप/छिड़काव के माध्यम से सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा राज्यों को मुहैया कराई गयी सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रयोग में आई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उससे राज्य-वार कितने कृषक लाभान्वित हुए है; और

(ङ) देश में ड्रिप/छिड़काव को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार सहित देश में सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिकल) के अंतर्गत लाया गया कुल क्षेत्र निम्न प्रकार से है।

वर्ष	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)
2006-07	3.46
2007-08	4.32
2008-09	5.59

(ख) से (घ) बिहार सहित राज्यवार, वर्षवार सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिकलर) के अंतर्गत और उपलब्ध कराई गई सहायता, उपयोग की गई राशि तथा लाभान्वित किसानों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ङ) ड्रिप/स्प्रिकलर सिंचाई पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने जनवरी, 2006 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित सूक्ष्म सिंचाई स्कीम शुरू की है और ग्यारहवीं योजनावधि में इसे जारी रखा जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रणाली के संस्थापन के लिये केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 40:10 के अनुपात में कुल लागत की 50% की दर से तथा प्रणाली के प्रदर्शन के लिये 75% की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण

दी गई सहायता, प्रयुक्त धनराशि तथा लाभान्वित किसानों की संख्या का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य	2006-07			2007-08			2008-09		
		दी गई राशि	प्रयुक्त राशि	लाभान्वित किसानों की सं.	दी गई राशि	प्रयुक्त राशि	लाभान्वित किसानों की सं.	दी गई राशि	प्रयुक्त राशि	लाभान्वित किसानों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	19519.68	11277	42312	5747.76	14559.42	57423	9727.31	15408.40	61790
2.	अरुणाचल प्रदेश	91.20	91.20	160	71.25	71.25	125	0	0	0
3.	असम	57.00	57.00	100	82.65	82.65	145	312.08	234.27	411
4.	बिहार	2482.10	0	0	0	26.10	121	0	12.86	169
5.	छत्तीसगढ़	3032.88	256.21	2374	783.39	1750.98	18696	954.45	2165.80	18154
6.	दिल्ली	15.71	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गोवा	12.13	1.00	4	0	6.92	56	2.00	6.95	39
8.	गुजरात	3355.90	3930.95	12169	7349.60	5200.55	215.18	4898.61	7322.67	26714
9.	हरियाणा	443.89	231.79	1338	604.19	468.89	3893	1207.28	1277.13	11152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	हिमाचल प्रदेश	21.09	21.09	37	22.23	22.23	39	125.25	51.63	125
11.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	12.75	0.15	1
12.	झारखंड	229.92	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	कर्नाटक	2456.75	4451.69	17917	6864.51	7597.97	30628	7318.66	6006.71	51036
14.	केरल	636.30	80.67	824	0	263.55	1114	0	154.73	776
15.	मध्य प्रदेश	401.16	401.00	2341	700.46	839.22	1193	4649.84	4159.36	19183
16.	मणिपुर	28.50	28.50	50	57.00	57.00	100	135.75	135.75	250
17.	महाराष्ट्र	8796.55	13466.37	33872	13897.34	12792.07	41113	14748.06	16161.71	50220
18.	मेघालय	79.80	79.80	140	331.00	331.00	556	296.40	296.40	500
19.	मिजोरम	121.98	121.98	214	79.00	79.00	140	96.40	96.90	170
20.	नागालैंड	80.08	80.08	140	57.00	57.00	100	94.88	94.38	225
21.	उड़ीसा	454.26	143.19	611	108.40	248.33	1535	337.94	337.09	1339
22.	पंजाब	0	183.72	712	427.05	613.02	2093	504.88	530.46	1604
23.	राजस्थान	2833.34	2687.46	33864	2341.14	2908.85	33795	2382.31	3658.28	38876
24.	सिक्किम	21.38	21.38	37	232.26	232.26	407	26.79	25.30	47
25.	तमिलनाडु	1200.64	0	0	2200.00	1559.91	3910	0	2607.18	5799
26.	त्रिपुरा	85.00	0	0	52.73	52.73	92	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	145.67	932	0	562.71	2330	150	306.15	644
28.	उत्तराखंड	199.50	199.50	350	69.83	69.83	122	147.53	25.51	70
29.	पश्चिम बंगाल	195.67	0	0	0	2.42	6	0	30.67	121
	कुल	47418.55	37957.25	150498	42078.79	50455.86*	221250	48129.67	61089.53*	289415

*वर्तमान वर्ष में प्राप्त सहायता तथा पिछले वर्ष की शेष राशि में से प्रयुक्त धनराशि

[अनुवाद]

प्रसारण क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2311. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डायरेक्ट टू होम सेवा और एफ. एम. रेडियो प्रसारण सेवाओं हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने की स्थिति में सरकार देश में इन सेवाप्रदाताओं/प्रसारकों को किस प्रकार विनियमित करेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने समय-समय पर अपनी विभिन्न सिफारिशों में डीटीएच सेवाओं और एफ.एम. रेडियो प्रसारण सेवाओं, जिन दोनों क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मौजूदा उच्चतम सीमा 20% है, सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भिन्न-भिन्न उच्चतम सीमाएं होने के मुद्दे को उठाया है।

ट्राई ने प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न खंडों के लिए बनाये गये नियमों में और अधिक सुसंगति लाने के लिए तथा दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों के बीच अभिसारिता के स्वरूप के मद्देनजर भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीति की समग्र रूप से समीक्षा करने की सिफारिश की है। ट्राई की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी मौजूदा मानदंडों की समीक्षा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन मानदंडों में कोई भी परिवर्तन करते समय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उच्चतम सीमाओं को बढ़ाने से संबंधित विनियामक मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

अयस्क की ढुलाई

2312. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्विक मंदी से खान क्षेत्र प्रभावित हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पश्चिम से पूर्वी तट तक अयस्क की ढुलाई के लिए स्वदेशी बेड़े का उपयोग करने पर बल देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार खनिज क्षेत्र में वृद्धि की दर पिछले वर्ष की 4.76 प्रतिशत की दर की तुलना में वर्ष 2008-09 में 2.58 प्रतिशत थी।

(ग) और (घ) पश्चिम से पूर्व को अयस्क के परिवहन के लिए देशी बेड़े को शामिल करने के लिए खान मंत्रालय द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

खेल संघों को अनुदान

2313. श्री सज्जन वर्मा: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मान्यता प्राप्त खेल संघों/एसोसिएशन का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा संघ-वार/एसोसिएशन-वार कितना अनुदान प्रदान किया गया है;

(ख) क्या उक्त खेल संघों/एसोसिएशनों ने उक्त अनुदान के उपयोग प्रमाणपत्र जमा कराए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार के निकायों की सूची का ब्यौरा क्या है जिन्होंने प्रमाणपत्र नहीं दिए हैं तथा इसके क्या कारण हैं और उनकी वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पावर लिफ्टिंग और बाडी बिल्डिंग सहित विभिन्न खेलों के लिए होने वाली डोप जांच में कितने खिलाड़ी असफल रहें हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार के खिलाड़ियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का खेल-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल) : (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रदान किए

गए अनुदानों सहित मान्यता-प्राप्त खेल परिसंघों/संघों का परिसंघ तथा संघवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सभी परिसंघ/संघ जो सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, उनको जारी अनुदानों के लिए उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। परिसंघों द्वारा अनुदानों के उपभोग को जिसके प्रयोजन के लिए वह स्वीकृत किया गया था, सुनिश्चित करने के लिए सरकार आगे अनुदान केवल तभी जारी करती है जब पिछले अनुदानों के उपभोग प्रमाण-पत्र तथा परीक्षित लेखें प्राप्त हो जाते हैं।

(घ) और (ङ) जनवरी, 2006 से आज की तारीख तक, विभिन्न खेलों में 194 खिलाड़ी डोप परीक्षण में दोषी पाए गए तथा विश्व डोप विरोधी एजेंसी (वाडा) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे खिलाड़ियों के खिलाफ संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

विवरण

क्र. सं.	परिसंघ का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 14 जुलाई, 09 तक
1	2	3	4	5	6
1.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ, नई दिल्ली	12.69	15.21	19.09	5.14
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ, चेन्नई	112.46	239.94	221.40	82.92
3.	अखिल भारतीय कराटे-डू-परिसंघ,	3.46	00	00	00
4.	अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद, नई दिल्ली	19.15	17.24	42.38	0.94
5.	अखिल भारतीय एम्येचोर बेसवाल परिसंघ, केशवपुरम, दिल्ली	15.49	9.00	11.00	6.00
6.	भारतीय एम्येचोर हैंडबाल परिसंघ, जम्मू और कश्मीर	38.64	18.03	72.38	8.01
7.	भारतीय अटया पटया परिसंघ, नागपुर	15.50	8.50	16.50	1.42
8.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	0.00	00	00	00
9.	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ, नई दिल्ली	36.31	71.44	44.52	14.07
10.	भारतीय साइकिल पोलो परिसंघ, नई दिल्ली	30.01	14.82	15.90	1.96
11.	भारतीय फेन्सिग संघ, पटियाला	45.70	6.61	24.75	6.52
12.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ, जोधपुर, (राजस्थान)	66.47	39.65	18.54	6.60

1	2	3	4	5	6
13.	भारतीय शरीर शौष्ठव परिसंघ,	00	00	00	00
14.	भारतीय कयाकिंग और केनोइंग संघ, नई दिल्ली	21.23	43.52	30.51	3.00
15.	भारतीय पोलो संघ, नई दिल्ली	1.55	2.11	6.48	00
16.	भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ, नई दिल्ली	8.50	11.50	16.00	7.00
17.	भारतीय जूडो परिसंघ, नई दिल्ली	48.62	92.23	62.55	17.25
18.	भारतीय खो-खो परिसंघ कोलकाता	2.00	00	00	00
19.	भारतीय कार्फबाल परिसंघ, नई दिल्ली	12.50	13.50	12.72	4.06
20.	अखिल भारतीय टेनिस, संघ, नई दिल्ली	90.07	92.63	79.14	62.31
21.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, नई दिल्ली	373.19	717.24	324.88	9.75
22.	भारतीय नेटबाल परिसंघ, शाहदरा, दिल्ली	9.50	14.99	18.78	00
23.	भारतीय रोलर स्केटिंग परिसंघ, कोलकाता	00	00	00	00
24.	भारतीय रोइंग परिसंघ, सिकंदराबाद	9.75	65.20	57.05	25.18
25.	भारतीय सेपक टकरा परिसंघ, नागपुर, महाराष्ट्र	13.00	11.95	12.00	4.50
26.	भातीय शूटिंग बाल परिसंघ,	00	00	9.00	00
27.	भारतीय साफ्टबाल परिसंघ, जोधपुर	12.00	9.00	00	3.00
28.	भारतीय स्क्वैश रैकेट परिसंघ, चेन्नई	21.94	11.37	33.88	12.00
29.	भारतीय तैराकी परिसंघ, अहमदाबाद	13.59	84.14	15.10	17.50
30.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ, नई दिल्ली	178.75	332.97	102.90	19.38
31.	भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ, बंगलौर	0.00	00	00	4.50
32.	भारतीय टेनीकोट परिसंघ, नई दिल्ली	13.00	9.00	16.50	2.25
33.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	11.50	8.00	16.00	3.50

1	2	3	4	5	6
34.	भारतीय रस्साकशी परिसंघ, नई दिल्ली	20.75	3.50	6.00	6.00
35.	भारतीय वालीवाल परिसंघ, चेन्नई	58.17	104.81	63.51	37.94
36.	भारतीय याचिंग संघ, नई दिल्ली	78.40	117.91	36.71	136.77
37.	भारतीय वुशु संघ, नई दिल्ली	13.50	11.41	31.24	23.55
38.	भारतीय थ्रोबाल परिसंघ, बंगलौर	0.00	19.82	00	00
39.	पारा ओलंपिक, बंगलौर	33.34	219.19	40.10	8.39
40.	भारतीय तीरंदाजी संघ, नई दिल्ली	96.48	81.67	96.10	108.01
41.	भारतीय बिलियर्ड्स एंड स्नूकर परिसंघ, कोलकाता	16.13	33.49	37.02	19.33
42.	भारतीय एम्येचोर मुक्केबाजी परिसंघ, नई दिल्ली	81.79	154.76	165.41	59.21
43.	हाकी (पुरुष)	92.09	125.18	156.99	95.47
44.	भारतीय महिला हाकी परिसंघ, नई दिल्ली	111.64	191.65	74.51	11.40
45.	भारतीय एम्येचोर कबड्डी परिसंघ, जयपुर	13.95	25.68	32.08	00
46	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ, नई दिल्ली	3.28	00	26.17	16.37
47.	भारतीय एथलेटिक्स परिसंघ, नई दिल्ली	86.83	233.19	228.40	1.77
48.	भारतीय बैडमिंटन संघ, राजस्थान	117.65	199.75	170.02	17.24
49.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ, नई दिल्ली	29.06	61.99	86.26	00
50.	अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ, दिल्ली	30.55	68.15	52.58	38.15
51.	भारतीय गोल्फ संघ, नई दिल्ली	23.65	56.64	18.24	7.67
52.	भारतीय कुश्ती परिसंघ, इंदिरा गांधी स्टेडियम, दिल्ली	32.58	6.15	200.42	00
53.	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ, (डब्ल्यूजीएफआई), दरियागंज	1.65	00	2.07	00

1	2	3	4	5	6
54.	भारतीय महिला क्रिकेट परिसंघ, दिल्ली	1.00	1.87	00	00
55.	भारतीय साइक्लिंग परिसंघ, दिल्ली	1.00	27.91	00	00
56.	भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड	00	00	00	00
57.	विशेष ओलंपिक भारत, नई दिल्ली	4.50	87.22	53.30	0.81
58.	एयरो क्लब आफ इंडिया	00	00	00	00
59.	भारतीय मलखंब परिसंघ	00	3.75	9.00	00
60.	भारतीय ट्रायथाल परिसंघ	00	00	00	00
61.	भारतीय एम्येचोर साफ्ट टेनिस परिसंघ	00	00	6.86	7.50
62.	भारतीय ब्रीज परिसंघ	00	00	3.00	00
63.	भारतीय मोटर स्पोर्ट्स परिसंघ	00	00	00	00
64.	आइस हाकी	00	00	1.50	00
65.	भारतीय स्कूल खेल परिसंघ	00	00	13.36	12.36
66.	भारतीय टेन पिन बाउलिंग परिसंघ	00	00	00	00
67.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	00	00	00	8.45
68.	भारतीय ओलंपिक संघ, नई दिल्ली	538.10	244.28	238.96	46.21
69.	भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली	500.00	1700.00	1000.00	700.00

[अनुवाद]

धान और गेहूं को औने-पौने दामों में बेचना

2314. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में औने-पौने दामों पर धान और गेहूं बेचने की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने ऐसे राज्यों में धान और गेहूं की खरीद बढ़ाने के संबंध में निदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) :

(क) जी, नहीं। किसी भी राज्य सरकार से धान की मजबूरन बिक्री की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

फसल योजना

2315. **श्री गजानन ध. बाबर :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि भारत में 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है भारत जल्द ही गेहूं का सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस रुझान को बन्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या देश में विभिन्न फसल उगाने के संबंध में योजना का अभाव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) नहीं, श्रीमान जी। तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2008-09 हेतु गेहूं का उत्पादन 77.63 मिलियन टन था, जबकि 2008-09 में गेहूं की प्रक्षेपित मांग 72.72 मिलियन टन है। यह प्रक्षेपित मांग जनसंख्या वृद्धि, प्रति व्यक्ति निपटान आय तथा व्यय की लोच में वृद्धि पर आधारित है।

(ग) से (ङ) वाणिज्यिक आसूचना सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, गेहूं का आयात 2006-07 में 6.1 मिलियन टन से घटकर 2007-08 में 1.8 मिलियन टन हो गया है तथा यह 2008-09 में पात्र 30 टन रह गया है। नई योजनाएं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इन फसलों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए प्रारम्भ की गई हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तीन घटक यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-चावल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं तथा राष्ट्रीय खाद्य मिशन मिशन-दालें हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं के अंतर्गत, देश के 141 जिलों को शामिल किया गया है। मूल्य समर्थन नीति के माध्यम से फसलों के बीच अन्तर-मूल्य समता को बनाए रखा जाता है जो किसानों को भिन्न-भिन्न फसलों की कृषि के लिए प्रोत्साहित करती है। किसानों को और अधिक गेहूं उगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 2009-10 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2008-09 में 1000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1080 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

[हिन्दी]

गाय की स्वदेशी नस्ल

2316. **श्री राकेश सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्यादा दुग्ध उत्पादन हेतु संकर गायों के आने से देश में गाय की स्वदेशी नस्लों की उपेक्षा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में गाय की स्वदेशी नस्लों की रक्षा करने, उसमें सुधार करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार द्वारा 2007 के दौरान पहली बार नस्लवार गणना की गई है जिसे अभी प्रकाशित किया जाना है। अत: पहले की गणनाओं की संख्या के साथ स्वदेशी नस्लों की मौजूदा संख्या की तुलना करना और कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है।

तथापि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्वदेशी नस्लों के महत्व को देखते हुए सरकार ने उनके विकास और संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) विभाग अक्तूबर, 2000 से एक राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना क्रियान्वित कर रहा है जिसमें स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर जोर दिया है। परियोजना

के चरण-1 के दौरान केवल स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए 58 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के चरण-2 के तहत स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए 356.78 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

(2) आनुवांशिक रूप से बेहतर सांड बछड़ा नस्लों के उत्पादन, बेहतर किस्म के हिमित वीर्य और देश में कुछ महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के सांडों और हिमित वीर्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गोपशु और भैंसों के बेहतर जर्मप्लाज्म के स्थान का पता लगाने के लिए सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की तीन योजनाएं भी क्रियान्वित कर रही है, नामत: केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेल, 2010

2317. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत का दौरा करने वाले राष्ट्रमंडल परिसंघ के शिष्टमंडल ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की तैयारी का मूल्यांकन/समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल)": (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ से एक प्रतिनिधिमंडल ने मई, 2009 में अपने दौरे के दौरान, भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और आयोजन समिति, राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के विभिन्न स्वामित्वधारियों के साथ बैठकें आयोजित की। प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न प्रतियोगिता और गैर प्रतियोगिता स्थलों का दौरा भी किया और इन स्थलों पर कार्य की प्रगति पर अपना संतोष व्यक्त किया।

एलपीटी को एचपीटी में परिवर्तित करना

2318. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार कितने कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों (एलपीटी)/बहुत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों (वीएलपीटी) को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों (एचपीटी) में परिवर्तित किया गया;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों और जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने राज्यों में एचपीटी की स्थापना करने तथा वीएलपीटी/एलपीटी को एचपीटी में परिवर्तित करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेरह अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का उन्नयन उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों के रूप में किया गया। इन ट्रोसमीटरों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान किसी अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर का उन्नयन उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के रूप में नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) विभिन्न क्षेत्रों में नए ट्रांसमीटर स्थापित करने और अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का उन्नयन करने संबंधी अनुरोध समय-समय पर प्राप्त होते हैं तथा टीवी का विस्तार करने संबंधी योजनाओं को निरूपित करते समय इन पर विचार किया जाता है।

(घ) स्थलीय प्रसारण द्वारा कवर न किए गए क्षेत्रों और देश के शेष भाग में दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डीटीए सेवा "डीडी डायरेक्ट प्लस" के जरिए बहु-चैनल टीवी कवरेज उपलब्ध करायी गयी है। डीटीएच सिगनलों को पूरे देश (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर) में लघु आकार की डिश अभिग्रहण इकाइयों की मदद से प्राप्त किया जा सकता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09
1.	असम		1	
2.	बिहार		1	
3.	गुजरात	1		
4.	हरियाणा	2		
5.	हिमाचल प्रदेश		1	
6.	मध्य प्रदेश	1		1
7.	राजस्थान		1	
8.	तमिलनाडु	2		
9.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		2	

[हिन्दी]

मछलियों की लुप्त होती प्रजातियां

2319. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक दोहन और प्रदूषण के कारण देश में मछलियों की कई प्रजातियां लुप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मछलियों की संकटापन्न प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किए गए/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संकटापन्न मत्स्य प्रजातियों का संरक्षण वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, चुनिंदा संकटापन्न प्रजातियों के लिए रिकवरी योजना के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश में बाह्य (एक्ससीटू) जीन बैंक स्थापित/प्रस्तावित किए गए हैं।

[अनुवाद]

दक्षिण भारत में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

2320. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण राज्यों, विशेषकर केरल के कुट्टानड क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित गोदामों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) फिलहाल किसी दक्षिणी राज्य में भारतीय खाद्य निगम के नए गोदाम का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम के लिए गोदामों का निर्माण करने की पांच वर्षीय गारंटी योजना निजी उद्यमियों के जरिए भंडारण अवधारण 2008 के तहत उच्च स्तरीय समिति ने संलग्न विवरण के अनुसार दक्षिणी राज्यों के लिए 4.71 लाख टन भंडारण क्षमता सृजित करने का अनुमोदन किया है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम के लिए गोदामों के निर्माण हेतु स्कीम के तहत दक्षिण अंचल के लिए उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित क्षमता-निजी उद्यमियों के जरिए भंडारण आवश्यकता-2008

(i) केरल के लिए उच्च स्तरीय समिति ने तीन केंद्रों पर कुल 15000 टन क्षमता का निम्नानुसार अनुमोदन किया है:

क्र.सं.	स्थान	क्षमता
1.	चिंगावनम	5,000 टन
2.	एराकुलम	5,000 टन
3.	मीनांगडी	5,000 टन
	जोड़	15,000 टन

(ii) कर्नाटक के लिए उच्च स्तरीय समिति ने पांच केंद्रों पर कुल 100000 टन क्षमता का निम्नानुसार अनुमोदन किया है:

क्र.सं.	स्थान	क्षमता
1.	बागलकोट	20,000 टन
2.	बीजापुर	15,000 टन
3.	बेलगांव	35,000 टन
4.	यादगीर	15,000 टन
5.	कारवार	15,000 टन
	जोड़	1,00,000 टन

(iii) आंध्र प्रदेश के लिए उच्च स्तरीय समिति ने दो केंद्रों पर कुल 36000 टन क्षमता का निम्नानुसार अनुमोदन किया है:

क्र.सं.	स्थान	क्षमता
1.	अम्दलवल्सा	20,000 टन
2.	टेक्काली	16,000 टन
	जोड़	36,000 टन

(iv) तमिलनाडु के लिए उच्च स्तरीय समिति ने 18 केंद्रों पर कुल 320000 टन क्षमता का निम्नानुसार अनुमोदन किया है:

क्र.सं.	स्थान	क्षमता
1	2	3
1.	तिरुवनमाली	20,000 टन
2.	मधुरंतगम	20,000 टन
3.	सेलम जंक्टिन	15,000 टन
4.	नमक्कल	15,000 टन
5.	धरमपुरी	20,000 टन
6.	विरुदुनगर	15,000 टन
7.	अरुपुकोट्टई	15,000 टन
8.	कराईकुडी	30,000 टन
9.	राजापलयम	15,000 टन
10.	तेनकासी	15,000 टन
11.	तेनी	15,000 टन
12.	नांगुनेरी	25,000 टन
13.	कोविलपट्टी	15,000 टन
14.	डिंडिगुल	25,000 टन
15.	विल्लुपुरम्	20,000 टन
16.	उलुन्दुरपेट	15,000 टन
17.	चिन्नासलेम	15,000 टन
18.	अरियालुर	10,000 टन
	जोड़	3,20,000 टन

[हिन्दी]

भूमि की उर्वरता में कमी

2321. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रसायनों, उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरता में कमी आने और भूजल के संदूषण संबंधी खतरे की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि की उर्वरता में आयी कमी की सीमा का पता लगाने के लिए देश में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के किन भागों में उक्त कमी दर्ज की गयी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उर्वरता में उक्त कमी को रोकने के लिए कोई कार्रवाई करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) रासायनिक उर्वरकों और पंजीकृत कृमिनाशियों के संतुलित और उचित उपयोग से मृदा स्थिति और उर्वरता को किसी प्रकार के नुकसान होने की जानकारी नहीं है। तथापि ऐसा देखा गया है कि रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित और अनुचित उपयोग ने देश में कुछ भागों में मृदा स्थिति और उत्पादकता को प्रभावित किया है।

पंजाब और आंध्र प्रदेश के क्रमशः लुधियाना और पश्चिम गोदावरी जिलों में ऐसा देखा गया है, खासकर हल्की मृदाओं में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण भूजल में नाइट्रेट संदूषण की संभावना है।

(ग) और (घ) सिंधु गंगा के मैदान में पंजाब और हरियाणा राज्यों में किए गए अध्ययन के अनुसार मृदा स्थिति और उर्वरता को प्रभावित करते हुए मृदा जैविक कार्बन में कमी आई है।

(ङ) और (च) जैविक खादों को मिलाकर रासायनिक उर्वरक के मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान मृदा स्थिति और उर्वरता के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना नामक एक नई स्कीम लागू की गई है। नई स्कीम ने 11वी. पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पांच सौ नई स्थिर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं और 250 नई चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना पर विचार किया है।

के.वी.आई.सी. को वित्तीय सहायता

2322. श्री अशोक कुमार रावत : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) को कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आबंटित, जारी की गयी और उपयोग में लाई गयी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान जिन के.वी.आई.सी. इकाइयों को वित्तीय सहायता मुहैया करायी गयी है उनके नाम, उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। हालांकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय में सरकार राज्यों को खादी व ग्रामोद्योग कार्यकलापों के लिए प्रत्यक्ष रूप से निधि प्रदान नहीं करती, वह इन कार्यकलापों के लिए खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को निधियां प्रदान करती है और फिर केवीआईसी राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केवीआईसी द्वारा आबंटित, जारी की गई और उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	बजट आबंटन (संशोधित अनुमान)	मंत्रालय द्वारा वास्तव में जारी की गई राशि	केवीआईसी द्वारा उपयोग* में लाई गई राशि
2006-07	592.93	589.82	586.31
2007-08	650.40	622.99	673.12
2008-09	1104.95	1104.94	1220.95

*पिछले वर्ष के आरंभिक शेष अतिरिक्त बजटीय संसाधन, आदि सहित। 2008-09 के आंकड़े अनंतिम हैं।

(ग) केवीआईसी खादी तथा ग्रामोद्योग के संवर्धन और विकास में संलग्न एक वैधानिक संगठन है और वह अपनी कोई खादी तथा ग्रामोद्योग इकाई नहीं चलाता। यह राज्य निदेशालयों, राज्य/संघ शासित प्रदेशों के खादी व ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी), पंजीकृत संस्थानों, सहकारी सोसाइटियों और भागीदार बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। तथापि, वह खादी संस्थानों की कुछ स्लिवर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छह सेंट्रल स्लिवर प्लांट (सीएसपी) चलाता है। केवीआईसी के छह सीएसपी की कुल वार्षिक इंस्टाल्ड क्षमता 36.5 लाख किलोग्राम है।

इन स्लिवर प्लांटों द्वारा किया गया कुल स्लिवर उत्पादन और आपूर्ति निम्नलिखित है:

मात्रा: लाख कि.ग्रा.

मूल्य: करोड़ रुपये

वर्ष	उत्पादन		आपूर्ति	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2006-07	24.46	21.32	25.94	22.36
2007-08	29.86	26.91	32.73	27.18
2008-09 (अनंतिम)	33.96	33.34	30.06	29.51

[अनुवाद]

स्क्रीन पर आपत्तिजनक दृश्य दिखाने पर प्रतिबंध

2323. श्री आनंदराव अडसुल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्क्रीन पर बलात्कार तथा हत्या जैसे आपत्तिजनक दृश्य दिखाने पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) से (ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार फिल्मों को प्रमाणित करता है। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये कुछ दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:

(i) हिंसा जैसी असामाजिक गतिविधियों को महिमामंडित न किया जाए अथवा न्यायोचित न ठहराया जाए;

(ii) हिंसा, क्रूरता और वीभत्सता के बेतुके अथवा परिहार्य दृश्य, मुख्यत: दर्शकों का मनोरंजन करने के उद्देश्य से हिंसा के दृश्य और ऐसे दृश्य नहीं दिखाए जाएं जो लोगों को संवेदनहीन अथवा अमानवीय बना सकते हों;

(iii) अभद्रता, अश्लीलता अथवा भ्रष्टता से माननीय संवेदनाओं को ठेस न पहुंचे;

(iv) किसी भी तरीके से महिलाओं की निंदा या उनका अपमान करने वाले दृश्यों को नहीं दिखाया जाए;

(v) महिलाओं के साथ यौन हिंसा वाले दृश्यों जैसे बलात्कार का प्रयास, बलात्कार अथवा किसी भी तरह की छेड़छाड़ अथवा सदृश स्वरूप के दृश्यों से बचा जाए और यदि ऐसी कोई घटना फिल्म के विषय से संबंधित हो तो उसे न्यूनतम करके न कि विस्तृत रूप में दिखाया जाए;

(vi) यौन विकृतियां दर्शाने वाले दृश्यों से बचा जाए और यदि ऐसे मामले फिल्म के विषय से संबंधित हों तो उन्हें न्यूनतम करके न कि विस्तृत रूप से दिखाया जाए।

[हिन्दी]

आरक्षित श्रेणियों के आई.पी.एस. अधिकारी

2324. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) अधिकारी कार्यरत हैं;

(ख) पूरे आई.पी.एस. संवर्ग में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आई.पी.एस. अधिकारियों की राज्य-वार अलग-अलग संख्या कितनी हैं;

(ग) क्या आई.पी.एस. में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के मानदंडों का समुचित अनुपालन नहीं हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिनांक 1.1.09 की स्थिति के अनुसार देश में सेवारत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या 3327 है।

(ख) देश में सेवारत भारतीय पुलिस सेवा के कुल अधिकारियों में से 949 का पदोन्नति द्वारा भारतीय पुलिस सेवा में समावेशन किया गया है और 2378 की सीधी भर्ती की गई है। सीधी भर्ती के अधिकारियों में से 328 अधिकारी अनुसूचित जाति श्रेणी के तथा 157 अधिकारी अनुसूचित जन जाति श्रेणी के हैं। राज्य एवं श्रेणीवार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) आई.पी.एस. में अजा/अजजा के आरक्षण मानदंडों का पालन किया जाता है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

संवर्गवार विवरण (01.01.09 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	सवंर्ग का नाम	अनुसूचित जाति श्रेणी	अनुसूचित जनजाति श्रेणी
1	2	3	4
1.	एजीएमयू	17	05
2.	आंध्र प्रदेश	18	07
3.	असम और मेघालय	11	12
4.	बिहार	11	08
5.	छत्तीसगढ़	05	05
6.	गुजरात	14	07
7.	हिमाचल प्रदेश	03	02
8.	हरियाणा	12	00
9.	जम्मू और कश्मीर	11	04
10.	झारखंड	11	07
11.	कर्नाटक	19	05
12.	केरल	07	04
13.	मध्य प्रदेश	22	10
14.	महाराष्ट्र	24	05
15.	मणिपुर और त्रिपुरा	05	17
16.	नागालैंड	05	08
17.	उड़ीसा	19	03
18.	पंजाब	15	03
19.	राजस्थान	14	09
20.	सिक्किम	02	02
21.	तमिलनाडु	23	08
22.	उत्तराखंड	03	05
23.	उत्तर प्रदेश	39	10
24.	पश्चिम बंगाल	18	11
	कुल	328	157

[अनुवाद]

सुपारी की खरीद

2325. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा :
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत लाल सुपारी खरीदने की अनुमति देने और इसकी खरीद हेतु समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) कर्नाटक सरकार सहित देश में सुपारी उत्पादों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कर्नाटक सहित देश में सुपारी उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने और सुपारी की खरीद सीधे कृषकों से करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) मंडी हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) के अंतर्गत 10,000 टन सुपारी (6000 टन सफेद और 4000 टन लाल किस्म) की खरीद के लिए 28.1.2009 को इस विभाग में कर्नाटक सरकार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। एमआईएस के दिशानिर्देशों के अनुसार उक्त प्रयोजनों हेतु गठित समिति ने 27.2.2009 को सम्पन्न अपनी बैठक में 1.3.2009 से 31.3.2009 तक खरीद के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया। तत्पश्चात राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर खरीद की अवधि 30.4.2009 तक और बाद में 30.6.2009 तक बढ़ा दी गई। तथापि एमआईएस के अंतर्गत 1.08 लाख मी. टन (कुल उत्पादन) की खरीद हेतु कर्नाटक सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि एमआईएस का विद्यमान दिशानिर्देश कुल अनुमानित के 10 प्रतिशत से अधिक खरीद की अनुमति नहीं देता। इस संबंध में कर्नाटक सरकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग) से (ङ) किसानों को गारंटीकृत मूल्य दिलाने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग पूरे देश में सुपारी, जो नाशवान किस्म की है और जिसे एमएसपी के अधीन शामिल नहीं किया गया है, सहित कृषि और बागवानी जिन्सों की खरीद के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम चला रहा है। एमआईएस राज्य सरकारों के विशेष अनुरोध पर उस स्थिति में क्रियान्वित की जाती है जब इन जिंसों के मूल्य लाभदायक स्तर से नीचे गिर जाता है। एमआईएस के अधीन कई अन्य किस्मों के समान न्यूनतम गारंटी मूल्य देकर सुपारी उत्पादकों के हितो की रक्षा की जाती है। एमआईएस के अधीन खरीद मूल्य राज्य सरकार और अन्य स्टैक होल्डरों के परामर्श से एक समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। एमआईएस के अधीन केन्द्र और राज्य एजेन्सियों द्वारा खरीद शुरू की जाती है।

[हिन्दी]

डोलोमाइट भंडार

2326. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में डोलोमाइट भंडारों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) उक्त क्षेत्रों से डोलोमाइट के अधिकतम दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) देश में डोलोमाइट संबंधी राज्य-वार सूचना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल ईअर बुक में दी गई है, जिसकी प्रति संसद पुस्तकालय को सप्लाई की गई है।

(ख) डोलोमाइट भंडार प्रदान करने के लिए गवेषण और गुणवत्ता और ग्रेड प्रमाणित करने का कार्य लगातार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राज्य भूविज्ञान और खनन विभाग द्वारा किया जाता है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का आकलन

2327. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नक्सलवादियों से भारी मात्रा में विस्फोटक, शस्त्र और गोला-बारूद बरामद हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए इस प्रकार के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या राज्य और आस-पास के क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक और विकास आवश्यकता तथा सुरक्षा इन्तजामों का आकलन करने के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में कैबिनेट शिष्टमंडल ने झारखंड का दौरा किया हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गयी; और

(ङ) नक्स्लवादियों का हिंसा छोड़ने और मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) वर्ष 2009 के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक ट्रक जब्त किया

और 10 टन से अधिक विस्फोटक पदार्थ तथा गोलाबारूद के 19000 राउंड बरामद किए और बिहार पुलिस ने एक ट्रक जब्त किया जो विस्फोटक पदार्थों का मिशन (20 बोरे), डिटोनेटर (81 पैकेट) और फ्यूज वायर (20 कोइल) ले जा रहा था। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जब्त किए गए हथियारों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

(ग) और (घ) मंत्रिमंडल सचिव ने केन्द्र सरकार के अन्य सचिवों के साथ दिनांक 28 और 29 जून, 2009 को झारखंड का दौरा किया और विकासात्मक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों की प्रगति की समीक्षा की। इस दल ने अन्य बातों के साथ-साथ रेल और सड़क जुडाव में सुधार करने और इस प्रयोजनार्थ सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने, रिक्त पदों को भरने, अपेक्षित क्षमता का निर्माण करने, और अधिक अंतर-विभागीय और अंतर-राज्य समन्वय स्थापित करने, केन्द्रीय योजनाओं के तहत निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने और राज्य में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

(ङ) राज्य, अपनी और पुनर्वास नीतियां कार्यान्वित करते रहे हैं ताकि नक्सली हिंसा त्याग दें और मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। केन्द्र सरकार, राज्यों द्वारा इस संबंध में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति, सुरक्षा से संबंधित व्यय योजना के तहत करती है।

विवरण

वर्ष 2006-2009 (दिनांक 30 जून, तक) के दौरान पुलिस द्वारा नक्सलियों से जब्त किए गए हथियारों की संख्या

राज्य	2006	2007	2008	2009 (30 जून तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	191	103	102	33
बिहार	70	41	72	32
छत्तीसगढ़	133	52	194	67
झारखंड	106	104	163	76
मध्य प्रदेश	—	—	2	—
महाराष्ट्र	45	17	179	47
उड़ीसा	18	13	777	12
अन्य राज्य	21	22	22	06
कुल	584	352	1511	273

झारखंड में सड़कें

2328. श्री अर्जुन मुंडा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य में हो रही व्यापक खनन गतिविधियों के कारण झारखंड में सड़कों को भारी नुकसान हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो झारखंड में सड़कों को मजबूत करने और चौड़ा करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क), (ख) और(घ) जी नहीं। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग-80 और राष्ट्रीय राजमार्ग-75 (विस्तार) के कुछ खंडों को छोड़ कर राष्ट्रीय राजमार्ग सामान्यत: यातायात योग्य स्थिति में हैं। प्रभावित खंडों का सुधार कार्य, यातायात की आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर चरणों में किया जाता है।

(ग) जी हां।

[अनुवाद]

चीन से आयात का प्रभाव

2329. श्री उदय सिंह : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन से होने वाले सस्ते आयातों का देश में लघु और मध्यम उद्यमों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लघु और उण्यम उद्यमों ने सरकार से चीन से होने वाले सस्ते आयातों को रोकने के लिए कड़े पाटन रोधी उपाय करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) चीन सहित अन्य देशों से आयातित सामग्री या तो प्रगामी उत्पादन के लिए कच्चे माल/घटकों के रूप में अथवा देशीय रूप के उत्पादित सामग्री के स्थानापन्न रूप से उपयोग की जा सकती थी। अत: देश में लघु और मध्यम उद्यमों पर आयातित सामग्री का सूक्ष्म प्रभाव बदलता रहता है और आकलन योग्य नहीं है।

(ग) और (घ) एंटी डपिंग और सह-शुल्क (डीजीएडी) महानिदेशालय स्वदेशी उद्योगों को क्षेपित आयातों तथा आरोपित क्षति के मध्य क्षेपण, क्षति तथा आकस्मिक संबंध के साक्ष्य द्वारा समर्थित स्वदेशी उद्योगों द्वारा दर्ज किए गए आवेदनपत्रों के आधार पर एंटी-डपिंग अन्वेषण कराता है। स्वदेशी उद्योग द्वारा दर्ज किए गए ऐसे आरोपों पर, सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1995 में यथा संशोधित) की प्रक्रिया अनुसार तथा निर्दिष्ट समयसीमा के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। डीजीएडी आवेदनों के आकार/श्रेणी (सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम) संबंधी कोई रिकार्ड नहीं रखता। चीनी पीआर को शामिल करते हुए, डीजीएडी द्वारा इस समय अठारह नए एंटी डपिंग अन्वेषण करवाए जा रहे हैं। इन अठारह एंटी-डपिंग अन्वेषणों में से दस में चीनी पीआर के अलावा विभिन्न अन्य देश भी अहम देशों के रूप में शामिल हैं तथा बाकी आठ अन्वेषणों में चीनी पीआर ही मात्र अहम देश हैं। अठारह एंटी-डपिंग अन्वेषणों में से दस में प्रारंभिक निष्कर्ष अभी तक जारी किए जा चुके हैं।

होडा समिति की सिफारिशें

2330. **श्री दुष्यंत सिंह :**
डॉ. के.एस. राव :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खनिज नीति पर होडा समिति द्वारा दी गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या खनिज उत्पादन करने वाले राज्यों ने इस नीति के विभिन्न उपबंधों पर आपत्ति की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने होडा समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के साथ सर्वसम्मति बनाने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) श्री अनवरुल होडा की अध्यक्षता में गठित की गई उच्च स्तरीय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ विलम्ब को कम करने के लिए खनिज रियायतें प्रदान करने की प्रक्रियाओं को सुप्रवाही और सरल बनाने हेतु राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 और खनन कानूनों में परिवर्तन करने, खनन कार्यकलापों हेतु अवसंरचना को मजबूत बनाने तथा खनन क्षेत्र में निवेश हेतु माहौल को सुधारने के लिए सिफारिशें की हैं। होडा समिति की सिफारिशें मंत्रालय की वेबसाइट (http//mines.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

(ख) से (ङ) सरकार को कुछ राज्य सरकारों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ खनिज रियायतें प्रदान करने में राज्य सरकार को मूल्यवर्धन को तरजीह देने हेतु स्वीकृति देने की आवश्यकता, निर्बाध अंतरण संबंधी नीति, पट्टा अवधि की सुरक्षा, खनिज रियायतें प्रदान करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को तरजीह देने हेतु स्वीकृति तथा मूल्यानुसार आधार पर रायल्टी की वसूली करने के संबंध में चिंता व्यक्त की गई थी। नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 की घोषणा करने से पहले सरकार द्वारा इन मुद्दों पर विचार करके इनका उचित समाधान किया गया था। नई राष्ट्रीय खनिज नीति को कार्यान्वित करने की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में खान मंत्रालय द्वारा कुछ उपाय किए गए हैं और कुछ उपाय संबंधित मंत्रालयों द्वारा किए जाने हैं। अत: राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 को कार्यान्वित करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग को उत्तर-दक्षिण-पूर्व पश्चिम कारिडोर के साथ जोड़ना

2331. श्री गणेश सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई कितनी है जिन्हें उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कारिडोर योजना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग का राज्य वार ब्योरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	उत्तर दक्षिण महामार्ग राज्य में लंबाई (किमी में)	पूर्व पश्चिम महामार्ग राज्य में लंबाई (किमी में)	कुल लंबाई (किमी में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	770.94		770.94
2.	असम		679.3	679.3
3.	बिहार		501.23	501.23
4.	दिल्ली	21.4		21.4
5.	गुजरात		634	634
6.	हरियाणा	182.7		182.7
7.	हिमाचल प्रदेश	11		11
8.	जम्मू और कश्मीर	399.47		399.47
9.	कर्नाटक	93.38		93.38
10.	केरल	161.6		161.6
11.	मध्य प्रदेश	535.02	118	653.025
12.	महाराष्ट्र	270		270
13.	पंजाब	270.87		270.87
14.	राजस्थान	29	527.4	556.4
15.	तमिलनाडु	749.58		749.58
16.	उत्तर प्रदेश	204.3	652.71	857.01
17.	पश्चिम बंगाल		330.85	330.85
	जोड़	3699.27	3443.49	714276

[अनुवाद]

जेल सुधार

2332. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में जेल सुधार आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जेल सुधारों को आरंभ करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) इस संबंध में राज्य-वार कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(घ) क्या सरकार जेल में बंद सभी कैदियों के लिए बायोमीट्रिक प्रणाली आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार की योजना सभी जेलों को कम्प्यूटर/इंटरनेट से जोड़ने की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या सरकार द्वारा इस प्रकार की प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार ने देश में विभिन्न जेल सुधारों के लिए विगत में निम्नलिखित समितियां गठित की थी:-

(i) न्यायमूर्ति ए.एन. मुल्ला (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में 1980 में अखिल भारत जेल सुधार समिति, जिसने 1983 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

(ii) विशेष रूप से कारागारों में सुरक्षा और अनुशासन के संदर्भ में व्यक्तियों के प्रशासन और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं की जांच और समीक्षा करने तथा उनमें सुधार करने के सुझाव देने के लिए कपूर समिति (1986)।

(iii) जेलों में महिलाओं की स्थिति की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में महिला कैदियों के संबंध में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति (1986)।

(iv) डीजी, वीपीआर एंड डी की अध्यक्षता में कारागार सुधार और सुधारात्मक प्रशासन संबंधी राष्ट्रीय नीति पर समिति।

उपर्युक्त समितियों ने कारागार भवनों, कारागार में रहने की स्थिति, कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण, सुरक्षा सुदृढ़ बनाने, कैदियों को चिकित्सा और मनोचिकित्सा सेवायें प्रदान करने और महिला कैदियों और उनके बच्चों को सेवायें प्रदान किए जाने के संबंध में कई सिफारिशें की हैं। इनमें से अधिकांश सिफारिशों का संबंध राज्य सरकारों से है। चूंकि 'कारागार' राज्य का विषय है इसलिए राज्य सरकारों से संबंधित सिफारिशों पर उचित कार्रवाई किए जाने के लिए उन्हें राज्य सरकारों को भेज दिया गया था।

सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच क्रमश: 75:25 के अनुपात में लागत हिस्सेदारी के आधार पर 1800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 27 राज्यों में वर्ष 2002-2003 में "कामगारों का आधुनिकीकरण" नामक एक योजनेतर स्कीम शुरू की थी। यह योजना अब दिनांक 31.3.2009 को समाप्त हो गई है।

इसके साथ ही कारागार आधारभूत संरचना और सुधारात्मक प्रशासन के लिए और वित्तीय सहायता मंजूर किए जाने के लिए विभिन्न राज्यों की मांगों को देखते हुए और कारागारों के आधुनिकीकरण संबंधी संसदीय स्थाई समिति की सिफारिशों को भी ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने योजना का दूसरा चरण तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। योजना के प्रस्तावित दूसरे चरण के मुख्य घटकों में नई जेलों का निर्माण करना, कारागार प्रबंधन का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन करना, कारागार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, कैदियों आदि की सुधारात्मक योजना शामिल है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, दिल्ली जेलों और अहमदाबाद केन्द्रीय कारागार और बड़ोदरा केन्द्रीय कारागारों में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बायोमैट्रिक प्रणाली शुरू कर दी गई है। चूंकि कारागार, राज्य का विषय है इसलिए इस सुविधा का कार्यान्वयन, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-48 परियोजनाओं में विलम्ब

2333. श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय से स्वीकृति मिलने में विलम्ब के कारण विभिन्न राज्यों में एनएचडीपी के तहत 48 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में विलम्ब हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजनाओं के शीघ्र अनुमोदन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग

परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को तीव्रता से समय पर पूरा करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए सरकार के प्रयास

(क) पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित निगरानी की जाती है। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के स्तर पर भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है। ये नोडल अधिकारी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए समय-समय पर बैठकें करते हैं तथा समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करते हैं।

(ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केन्द्र-राज्य मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया आसान बना दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत पहले सभी अधिसूचनाओं की विधि मंत्रालय द्वारा विधीक्षा की जाती थी। हाल ही में कार्य आबंटन नियमावली में एक संशोधन किया गया है जिसके तहत इन अधिसूचनाओं को विधि मंत्रालय को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। विधि मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाओं की समान प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अधिसूचनाओं के मानक मसौदों को अनुमोदित कर दिया है।

(ङ) रेल उपरि पुलों (आर.ओ.बी.) के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके। कुछ रेल उपरि पुलों के निर्माण के लिए मै. इरकान इंटरनेशनल लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(च) गैर-निष्पादक ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उन्हें तब तक भावी परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे विद्यमान ठेकों में अपने निष्पादन में सुधार नहीं कर लेते।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

2334. श्री वैजयंत पांडा : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुल निर्यात में लघु उद्योगों का कितना हिस्सा है;

(ख) क्या यह क्षेत्र गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नकदी की कमी, घटते निर्यात तथा पेटेंटों सहित इनकी अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2006-07 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान देश के कुल निर्यात में लघु उद्योगों की हिस्सेदारी 31.92% थी।

(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र उद्यमों के आकार तथा इसके क्षेत्रीय गठन, दोनों अर्थों में एक विविधीकृत क्षेत्र है। अत: इस क्षेत्र

द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, वे विविध हैं। ये ऋण की समय पर तथा पर्याप्त उपलब्धता में कमी, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, अवसंरचना संबंधी कठिनाई, विपणन कठिनाइयों, बड़ी इकाइयों द्वारा उनकी बकाया राशि के विलम्बित भुगतानों, उदारीकृत व्यापार शासन के कारण संवर्धित प्रतिस्पर्धा, आदि से संबंधित हैं।

(ग) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के संवर्धन एवं विकास को सुकर बनाने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सरकार ने 10 अगस्त, 2005 को "लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के ऋण को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत पैकेज" की घोषणा की थी जिसमें परिकल्पना की गई है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसएमई क्षेत्र को ऋण में वर्ष-दर-वर्ष कम से कम 20% वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से लघु एवं मध्यम उद्यमों को निधियां प्रदान करने के लिए स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करेंगे। सरकार ने फरवरी, 2007 में ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, अवसंरचना, आदि के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से "सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज" की भी घोषणा की है। इसके अलावा, सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है जो 2 अक्तूबर, 2006 से प्रभावी हुआ है। सरकार सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करने में सहायता देने हेतु ऋण, अवसंरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता विकास आदि से संबंधित अनेक योजनाएं/कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है। कार्यान्वित की जा रही कुछ प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम हैं: क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, निष्पादन एवे क्रेडिट रेटिंग स्कीम, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम (एनएमसीपी), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं बाजार विकास सहायता योजना। एनएमसीपी के घटकों में से एक है एमएसएमई के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संबंधी जागरूकता पैदा करना। इस योजना के तहत आईपीआर संबंधी विभिन्न कार्यकलापों से उनकी बौद्धिक शक्तियों के परिक्षण हेतु अधिक सूचना, प्रत्रोधन तथा सुविधाएं प्राप्त होंगी।

इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर वैश्विक मंदी के प्रभाव के मद्देनजर, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की सुरक्षा तथा प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: (i) क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 50% के गारंटी कवर के साथ ऋण सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करना; (ii) 5 लाख रुपये तक की क्रेडिट सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत क्रेडिट कवर को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत करना; (iii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बिलों के शीघ्र भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक परामर्शी; (iv) लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्री पोस्ट शिपमेन्ट निर्यात ऋण में 2 प्रतिशत की ब्याज कटौती; (v) सूक्ष्म, एवं लघु उद्यम क्षेत्र को इन्क्रीमेंटल आन लेडिग हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 7,000 करोड़ रुपये की पुन: वित्त सीमा। (vi) मौजूदा निधि आधारित सीमाओं के 20 प्रतिशत तक के आवश्यकता आधारित तदर्थ कार्यक्षम पूंजीगत मांग ऋण प्रदान करना; और (vii) सूक्ष्म उद्यमों द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए ब्याज में 1 प्रतिशत तक और लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 0.5% तक की कटौती।

[हिन्दी]

आतंकवादी गातिविधियां

2335. **योगी आदित्यनाथ :**
श्री गुरूदास दासगुप्त :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :
श्री हुक्मदेव नारायण यादव :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए महिलाओं को विशेष रूप से पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में प्रशिक्षित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या लश्कर-ए-तैयबा सहित आतंकवादी संगठनों द्वारा हमले की कोई आशंका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा इससे निपटने के लिए क्या तैयारी है;

(ङ) क्या बिहार राज्य में आतंकवादियों तथा व्यक्ति विशेष/संगठनों के बीच किसी संपर्क का पता चला है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हुई आतंकवादी घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई और सरकार द्वारा सीमा पार से आतंकवाद सहित आतंकवाद को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (छ) ऐसी रिपोर्टें हैं जिनसे संकेत मिलता है कि आतंकवादी गतिविधियाँ करने के लिए महिलाओं को पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसी रिपोर्टें हैं कि पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर आधारित आतंकवादी, जिसमें लश्कर-ए-तैय्यबा (एलईटी) भी शामिल है, आतंक के संगठित कृत्यों में सक्रिय है। उपलब्ध जानकारी से संकेत मिलता है कि आतंकवादी तत्वों और बिहार के कुछ लोगों के बीच सम्पर्क हैं।

जम्मू एव कश्मीर पूर्वोत्तर राज्य, नक्सल प्रभावित राज्यों तथा अन्त: भूमि में घटित आतंकवादी घटनाओं तथा उनमें मारे गए सिविलियनों एवं सुरक्षाबल कार्मिकों की संख्या, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संलग्न विवरण में गई है।

सरकार, आतंकवादी घटनाओं सहित, उभरती चुनौतियों के आलोक में सुरक्षा व्यवस्था की सतत आधार पर समीक्षा कर रही है और आतंकवादी घटनाओं का मुकाबला करने के लिए तैयारी के स्तर को बढ़ाने, आसूचना एवं सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और आतंकवाद का प्रतिरोध करने के लिए विधायी एवं जांच संबंधी उपबंधों को करने जैसे कई महत्वपूर्ण उपाए किए गए हैं।

विवरण

जम्मू और कश्मीर

वर्ष	घटनाओं की संख्या	मारे गए सिविलियनों एवं सुरक्षा बल कार्मिकों की संख्या
1	2	3
2006	1667	540
2007	1092	268
2008	708	166
2009 (मई 2009 तक)	186	49

पूर्वोत्तर

वर्ष	घटनाओं की संख्या	मारे गए सिविलियनों एवं सुरक्षा बल कार्मिकों की संख्या
2006	1366	385
2007	1489	577
2008	1561	512
2009 (मई 2009 तक)	624	153

नक्सल प्रभावित राज्य

वर्ष	घटनाओं की संख्या	मारे गए सिविलियनों एवं सुरक्षा बल कार्मिकों की संख्या
2006	1509	678
2007	1565	696
2008	1591	721
2009 (मई 2009 तक)	915	348

उपयुक्त के अतिरिक्त वर्ष 2006 में अन्त: भूमि में जो बड़ी आतंकी घटनाएं हुई उनमें शामिल हैं वाराणसी कैण्ट स्टेशन, और संकट मोचन मंदिर, वाराणसी, दिल्ली की जामा मस्जिद परिसर में, मुम्बई की लोकल गाड़ियों में एवं मालेगांव में हुए धमाका/विस्फोट जिनमें 232 व्यक्ति मारे गए। वर्ष 2007 में हुई घटनाओं में शामिल

हैं समझौता/अटारी एक्सप्रेस के दो अनारक्षित डिब्बों में दिवाना स्थल पर, मक्का मस्जिद, हैदराबाद में, लुम्बिनी पार्क तथा गोकुल चाट भंडार, हैदराबाद में, अजमेर शरीफ अजमेर राजस्थान में, लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा हाल में तथा वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ के न्यायालय परिसरों में हुए विस्फोट जिनमें 143 व्यक्ति मारे गए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008 में हुई बड़ी आतंकवादी घटनाओं में निम्नलिखित स्थानों पर धमाके/विस्फोट हुए सी.आर.पी.एफ. ग्रुप केन्द्र, रामपुर (उत्तर प्रदेश), जयपुर, अहमदाबाद, बंगलौर, दिल्ली, मालेगांव (महाराष्ट्र) और मोदासा गुजरात इनमें 168 व्यक्तियों की जानें गईं। नवम्बर, 2008 में मुम्बई में हुए आतंकी हमले में 164 व्यक्ति मारे गए। उपर्युक्त मारे गए व्याक्तियों में 41 सुरक्षा बल कार्मिक भी शामिल है।

बाइकर्स गैंग

2336. **श्री राधा मोहन सिंह :**
श्री लालजी टन्डन :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोएडा, गाजियाबाद तथा गुड़गांव सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बाइकर्स गैंग द्वारा विभिन्न आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान तथा मौजूदा वर्ष में पृथक रूप से इस प्रकार के गैंग द्वारा पेट्रोल पम्पों, डेयरी बूथ की लूट सहित मारे गए, लूटे गए और घायल हुए लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) गाजियाबाद-2008 में बाइकर्स गैंग द्वारा की गयी वारदातों में एक व्यक्ति मारा गया था, एक व्यक्ति को लूट लिया गया था और दो व्यक्ति घायल हो गए थे। इस संबंध में, दो व्यक्तियों को हत्या के लिए और एक व्यक्ति को लूटपाट के लिए 2008 में गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2009 में, बाइकर्स गैंग द्वारा की गयी वारदातों में 13 व्यक्तियों को लूट लिया गया था और 2 व्यक्ति घायल हो गए थे। इस संबंध में, 3 व्यक्तियों को लूटपाट के लिए गिरफ्तार किया गया था। ऐसी वारदातों को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों को सक्रिय कर दिया गया था।

नोएडा-वर्ष 2008 एवं 2009 (16 जुलाई, 2009 तक) के दौरान, मोटरसाइकिलधारी अपराधियों द्वारा किसी डेयरी बूथ एवं पेट्रोल पम्प के लूटे जाने की कोई सूचना नहीं मिली है। 2008 में बाइक का प्रयोग कर अपराधियों द्वारा लूटने की एक घटना का पता चला था जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था। इस घटना में, चार अपराधियों के शामिल होने की जानकारी मिली थी और अपराधियों से लूटी गयी सम्पत्ति वापिस मिल गयी थी। समस्त चार व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज किए गए थे। नोएडा पुलिस योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। अपराधों का समयवार और स्थानवार आकलन किया गया है और इसके अनुसार ड्यूटी का निर्धारण किया गया है। मोबाईल चौकसी को भी बढ़ा दिया गया है। मोबाईल चौकसी के मार्गों में असुरक्षित स्थान भी शामिल हैं। इसी तरह से नोएडा के विभिन्न पुलिस थानों में तैनात पुलिस कर्मियों को भी इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दैनिक कार्य सौंपे गए हैं। विभिन्न स्थानों पर प्रतिदिन संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की तलाशी के साथ-साथ स्थानों की भी तलाशी ली जाती है।

गुड़गांव-2008 में बाइकर्स गैंग की भागीदारी वाली किसी आपराधिक घटना की सूचना नहीं मिली थी। 2009 तक (17 जुलाई, 2009 तक) में गुड़गांव में बाइकर्स गैंग द्वारा लूटपाट या लूटपाट के प्रयास की 7 घटनाओं की सूचना मिली थी। बाइकर्स गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। भविष्य में ऐसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए गुड़गांव पुलिस ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) बाइकों पर घूमने वाले युवाओं की सख्त जांच की जाती है और ऐसे व्यक्तियों की पहचान नियमित आधार पर की जाती है।

(ii) बाईकों पर सवार ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए पुलिस उपायुक्त (अपराध) के

पर्यवेक्षण में विशेष अपराध दलों का गठन किया गया है।

(iii) ऐसी आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए गुड़गांव कमीश्नरी के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 85 पी.सी.आर./राईडरों को चौबीस घंटे तैनात रखा गया है।

(iv) एस.एच.ओ./पुलिस पोस्ट इंचार्जों को भी उनसे संबंधित क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है।

दिल्ली-जिन वारदातों में मोटरसाईकलों का इस्तेमाल किया गया, उन मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) 2008 में मोटरसाईकलधारी अपराधियों द्वारा पेट्रोल पम्प पर किए गए अपराध के मामले

शीर्ष	सूचित मामले	मारे गए व्यक्ति	घायल व्यक्ति	गिरफ्तार व्यक्ति
लूटपाट	01	00	00	02

(ii) 2009 (30-6-09 तक) में मोटरसाईकलधारी अपराधियों द्वारा पेट्रोल पम्प पर किए गए अपराध के मामले

शीर्ष	सूचित मामले	मारे गए व्यक्ति	घायल व्यक्ति	गिरफ्तार व्यक्ति
हत्या	01	01	00	04

(iii) 2008 में मोटरसाईकलधारी अपराधियों द्वारा किए गए अपराध के मामले

शीर्ष	सूचित मामले	मारे गए व्यक्ति	घायल व्यक्ति	गिरफ्तार व्यक्ति
हत्या	4	6	00	12
लूटपाट	81	00	37	159
झपटमारी	847	00	00	730

(iv) 2009 (30-6-09 तक) में मोटरसाईकलधारी अपराधियों द्वारा किए गए अपराध के मामले

शीर्ष	सूचित मामले	मारे गए व्यक्ति	घायल व्यक्ति	गिरफ्तार व्यक्ति
हत्या	2	2	00	06
लूटपाट	41	00	09	58
झपटमारी	429	00	00	346

इन आपराधिक गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें बीट/डिवीजन/पुलिस स्टेशन स्टाफ द्वारा रेहड़ी/पटरीवालों, सिक्यूरिटी गार्डों/चौकीदारों/थ्री व्हीलरों/टी.एस.आर. ड्राईवरों, टैक्सी स्टैंडों/पार्किंग लॉट अटेंडेंटों/पोर्टरों आदि के साथ ''आईज एंड ईयर्स स्कीम'' के अंतर्गत बेहतर सहयोग हासिल करने के लिए नियमित सम्पर्क बनाए रखना; बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों के समीप गहन मोटरसाईकल एवं पैदल चौकसी, मोबाईल एवं स्टैटिक पिकेटों की स्थापना द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की नियमित जांच करना; रेजीडेंट एवं मार्केट वेलफेयर एसोशिएसनों को उनके साथ बैठकें आयोजित कर ऐसी अपराधों को रोकने के लिए सावधानी बरतने हेतु सक्रिय बनाना; स्थानीय पुलिस द्वारा 18/2/09 से प्रारंभ करके 2,04,200 मोटरसाईकलों की जांच की गयी है; बिना हेल्मट वाले दोपहिया चालकों/पिलन राईडरों पर तथा तीन सवारी वालों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियमित अभियोग चलाया जाना; आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

रोजगार के अवसर

2337. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :**
श्री जगदम्बिका पाल :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में महिला उद्यमियों को लघु उद्यमों की स्थापना में सक्षम बनाने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए कई योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। ये योजनाएं नए उद्यमों की स्थापना को सुगम बनाती हैं और इस भांति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए रोजगार अवसर उत्पन्न करती हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का लक्ष्य स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना करके ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार अवसर पैदा करना है। ताकि व्यापक रूप से फैले हुए पारंपरिक कारीगरों/शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाया जा सके और उन्हें स्व-रोजगार अवसर, आदि प्रदान किए जा सकें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोग भी इन योजनाओं से लाभान्वित होते हैं।

(ग) और (घ) महिला उद्यमियों को अपने उद्यम स्थापित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ''महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास (ट्रैड)'' नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत महिला समूह को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए एनजीओ/एसएचजी को बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि के 30% तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। पीएमईजीपी के तहत सेवा/व्यापार क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक तथा विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक की लागत वाले सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% तक, (महिलाओं सहित कमजोर वर्गों के लिए 35%) तथा शहरी क्षेत्रों में 15% (महिलाओं सहित कमजोर वर्गों के लिए 25%) तक सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है। एमएसई-क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत महिला स्वामित्व वाले क्लस्टरों के विकास हेतु 90% तक (अधिकतम 9 करोड़ रुपये) केन्द्रीय अनुदान प्रदान किया जाता है। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के तहत महिला उद्यमियों को 80% तक का क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा आयोजित उद्यमिता/प्रबंध विकास कार्यक्रमों में महिला प्रशिक्षणार्थियों को पाठ्यक्रम शुल्क में 50% की रियायत दी जाती है। इसके अलावा कुल आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों/उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रमों में से 20% कार्यक्रम विशिष्ट रूप से कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांगों) के लिए आयोजित किए जाते हैं, जो नि:शुल्क हैं तथा प्रत्येक प्रशिक्षु को 500/- रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाती है।

[हिन्दी]

पुलों/उपरिपुलों की मियाद

2338. श्री जगदम्बिका पाल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़ी संख्या में निर्मित पुलों/उपरिपुलों की मियाद खत्म हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार के पुलों/उपरिपुलों के पुनर्निर्माण/नवीनीकरण के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्ष के दौरान संस्वीकृत पुलों/उपरिपुलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त पुलों पर कार्य की प्रगति की स्थिति क्या है तथा इस प्रकार के पुलों के पुनर्निर्माण हेतु कितनी निधियां आबंटित तथा जारी की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) जी नहीं। पुलों/उपरि पुलों का पुनर्निर्माण/पुनरुद्धार एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य चरणबद्ध रूप में किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित खराब हालत वाले पुलों/उपरि पुलों का पुनर्निर्माण/पुनरुद्धार, धनराशि की उपलब्धता और उनकी पारस्परिक प्राथमिकता के अनुसार किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) चालू वित्त वर्ष और गत तीन वर्षों के दौरान पुनर्निर्माण/पुनरुद्धार के लिए संस्वीकृत पुलों/उपरि पुलों के कार्यों की प्रगति की स्थिति और ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

विवरण-I

चालू वर्ष के दौरान किया गया पुलों का पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण कार्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	पुनरुद्धार				पुनर्निर्माण			
		पुलों की संख्या	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए)	कार्य की स्थिति		पुलों की संख्या	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए)	कार्य की स्थिति	
				प्रगति पर	पूर्ण			प्रगति पर	पूर्ण
1.	बिहार	1	4.30	1	—	7	30.93	7	—
2.	मध्य प्रदेश	1	1.67	1	—	—	—	—	—
3.	उड़ीसा	1	1.56	8	—	—	—	—	—

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य का नाम	नवीकरण				पुनर्निर्माण			
		पुलों की संख्या	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए)	कार्य की स्थिति		पुलों की संख्या	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए)	कार्य की स्थिति	
				प्रगति पर	पूर्ण			प्रगति पर	पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	15	103.21	13	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	10.92	शून्य	शून्य
4.	बिहार	2	60.32	2	शून्य				
5.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	छत्तीसगढ़								
7.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	गुजरात	4	15.13	2	2	24	17.30	20	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	गोवा								
10.	हरियाणा	6	3.52	1	5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	हिमाचल प्रदेश	1	1.02	1	शून्य	3	23.01	2	1
12.	जम्मू और कश्मीर								
13.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	16	76.60	16	शून्य
14.	कर्नाटक	5	5.04	4	1	21	65.32	5	16
15.	केरल	6	4.61	2	4	1	3.52	1	शून्य
16.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	4.31	2	शून्य
17.	महाराष्ट्र								
18.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	11	37.86	11	शून्य
20.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	उड़ीसा	3	1.8	8	शून्य	5	20.90	4	1
23.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	1.71	1	1
25.	राजस्थान	2	3.16	2	शून्य	13	35.55	13	शून्य
26.	सिक्किम								
27.	तमिलनाडु	1	0.63	1	शून्य	26	21.41	18	8
28.	त्रिपुरा								
29.	उत्तराखंड	6	10.65	6	शून्य	2	2.78	2	शून्य
30.	उत्तर प्रदेश	9	3.86	6	3	4	2.83	3	1
31.	पश्चिम बंगाल	2	1.14	2	शून्य	7	22.55	7	शून्य

कृषि ऋण में वृद्धि

2339. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र हेतु ऋण संवितरण में वृद्धि देखी गयी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋणों में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई;

(ग) क्या ऋण की उपलब्धता में वृद्धि के बावजूद कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	ऋण प्रवाह	प्रतिशत वृद्धि
2006-07	229400	27.10
2007-08	254658	11.01
2008-09	287149	12.76

(ग) जी, नहीं। देश में कृषि उत्पादन ऋणों की उपलब्धता सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। तथापि, कृपि और समवर्गी क्षेत्रों के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (स्थिर मूल्यों पर) में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	कृपि जीडीपी
1	2
2006-07	5.31 लाख करोड़ रुपये
2007-08	5.57 लाख करोड़ रुपये
2008-09	5.66 लाख करोड़ रुपये

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

टोरसा नदी पर पुल का निर्माण

2340. श्री नृपेन्द्र नाथ राय : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर टोरसा नदी पर पुल निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष मे उक्त पुल के लिए कितना बजटीय आबंटन किया गया है; और

(घ) इस पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर तोरसा नदी पर पुल का निर्माण कार्य पहले ही पूर्ण कर लिया गया है और इसे दिनांक 16.07.2008 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-37, पश्चिम बंगाल से होकर नहीं गुजरता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नए राष्ट्रीय राजमार्गों को स्वीकृति प्रदान करना

2341. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्यों में नए राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) को स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ीसा में उन सड़कों का ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का चालू राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियों का आबंटन बढ़ाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो खुर्दा से बोलंगिर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए कितनी निधियां अपेक्षित और स्वीकृत की गई हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) वर्तमान में, सरकार की प्राथमिकता, नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करने की नहीं है, बल्कि पहले से विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर जोर दिया जा रहा है जिनमें कई न्यूनताएं हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटन, कार्य-वार और खण्ड-वार नहीं किया जाता है।

रणनीतिक खाद्यान्न भंडार

2342. **श्री गजानन ध. बाबर** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपात स्थिति का सामना करने के लिए बफर स्टॉक के अतिरिक्त रणनीतिक खाद्यान्न भंडार सृजित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अतिरिक्त स्टॉक का सृजन और इसका रखरखाव किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितने गोदामों/भांडागारों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इन पर आने वाले समस्त खर्च को वहन करने का भी निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) जी, हां। बफर मानदंडों में संशोधन के लंबित होने तथा देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने निर्णय किया है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का 50 लाख टन रणनीतिक रिजर्व बनाया जाएगा। रणनीतिक रिजर्व 2008-09 से शुरू करके एक समायावधि के भीतर बनाया जाएगा। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टॉक, जिसमें रणनीतिक रिजर्व शामिल है, को उपलब्ध गोदामों तथा भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित अतिरिक्त गोदामों में रखा जाएगा।

(घ) और (ङ) रणनीतिक रिजर्व को बनाने की लागत राजसहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

नए आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र

2343. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से देश में नए आकाशवाणी (एआईआर) और दूरदर्शन (डीडी) केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार की देश में नए टीवी केन्द्र स्थापित करने और पुराने टीवी-केन्द्रों की कवरेज क्षमता को बढ़ाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार, स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त केन्द्रों के कब तक स्थापित किये जाने और प्रचालन शुरू किये जापे की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) 10वीं योजना की सतत स्कीमों के भाग के रूप में अनुमोदित नए दूरदर्शन केंद्रों की परियोजनाएं तथा मौजूदा केंद्रों के संवर्धन के संबंध में परियोजनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ङ) वर्तमान संकेतों के अनुसार, उपर्युक्त परियोजनाओं के वर्ष 2011 तक पूरे किए जाने एवं शुरू हो जाने की संभावना है।

विवरण

नए दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना/मौजूदा दूरदर्शन केन्द्रों की संवर्धन संबंधी परियोजनाएं

I. **नया स्टुडियो केन्द्र :** तिरुपति (आंध्र प्रदेश)

II. **नए ट्रांसमीटर :**

1. उ.श.ट्रां., मेहबूबनगर (आंध्र प्रदेश)
2. उ.श.ट्रां., बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
3. अ.अ.श.ट्रां., गांधीनगर (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

III. **मौजूदा दूरदर्शन केन्द्रों की संवर्धन संबंधी परियोजनाएं**

1. चंडीगढ़ (चंडीगढ़)-अतिरिक्त स्टुडियो
2. जम्मू (ज. एवं क.)-अतिरिक्त स्टुडियो
3. लेह (ज. एवं क.)-स्थाई स्टुडियो ढांचा
4. देहरादून (उत्तराखंड)-स्थाई स्टुडियो ढांचा

IV. **ट्रांसमीटरों का उन्नयन**

(क) **स्थाई उ.श.ट्रां. ढांचा**

1. कोकराझार (असम)
2. कन्नानोरे (केरल)
3. अमृतसर (डी.डी. 1 एवं डीडी न्यूज-पंजाब)
4. बाड़मेर (राजस्थान)
5. कुम्भाकोनाम (तमिलनाडु)

(ख) **पुराने 100 वाट अ.श.ट्रां. का 500 वाट (1+1) आटोमोड अ.श.ट्रां. से प्रतिस्थापन**

आंध्र प्रदेश :	खम्माम	काकीनाडा	निजामाबाद		
छत्तीसगढ़ :	बैलाडिला				
गुजरात :	वेरावाल	भावनगर	अहवा	दीसा	अमरेली
	केवडिया कालोनी				
हरियाणा :	नारनौल	भिवानी			
कर्नाटक :	बेलगांव	बीजापुर	रानीबेन्नूर	कोलार-गोल्ड फील्ड	सिरसी

केरल :	चंगनचेरी	पालघाट	शोरानूर	मल्लापुरम	त्रिचूर
मध्य प्रदेश :	बेतूल	रतलाम	चंदेरी	दमोह	राजगढ़
	भिंड	खंडवा	छिन्दवाड़ा	शेओपुर	शाजापुर
	खरगोन	सतना	पन्ना		
महाराष्ट्र :	बर्शी	परभानी	सांगली	नान्देड़	गडचिरोली
	किनवत	अहमदनगर	यवतमाल	सोलापुर	बुलधाना
	बीड	घूले	अकोला	नासिक	अमरावती
मेघालय :	जोवई				
उड़ीसा :	बारीपड़ा	बोलंगीर	क्योंझरगढ़		
पंजाब :	गुरदासपुर				
राजस्थान :	चित्तौड़गढ़	अलवर	झुनझुनू	जैसलमेर	सीकर
	हनुमानगढ़	बाड़मेर	पाली	सिरोही	दीग
तमिलनाडु :	वानीयाम्बदी	तिरुचेंदूर	कोटीलाम	सलेम	कूनूर
	तिरुपत्तूर (डीडी न्यूज)	नेयवेली	वेल्लोर		
उत्तर प्रदेश :	आजमगढ़ (न्यूज)	शाहजहांपुर	गोंडा	इटावा	मऊ (डीडी न्यूज)
	फतेहपुर	फतेहगढ़	जगदीशपुर	ओरई	पीलीभीत
	मथुरा (डीडी न्यूज)	रामपुर (डीडी न्यूज)	झांसी	लालगंज (प्रतापगढ़)-डीडी न्यूज	
उत्तराखंड :	काशीपुर	नैनीताल			
पश्चिम बंगाल :	अलीपुरदौड़	कोनतई			

[हिन्दी]

चरागाह भूमि में कमी

2344. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चरागाह भूमि लगातार घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने घटती चरागाह भूमि के छोटे किसानों पर कुप्रभाव का आकलन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान स्थायी चारागाह के तहत कुल क्षेत्र क्रमशः 10.44, 10.42, 10.41 मिलियन हैक्टेयर था (डीओएसी, 2008)। राज्यों में पॉश्चर भूमि के तहत क्षेत्र में धीरे-धीरे आई कमी का कारण यह रहा है कि इस प्रकार की भूमि में से अधिकतर का उपयोग या तो अन्य कृषि प्रयोजनों के लिए कर दिया गया है या इस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। जिससे पशुधन के चरने के लिए उपलब्धता सीमित हो गई है।

(ग) और (घ) चारागाह क्षेत्र की कमी के दुष्प्रभाव को (i) चरने वाले पशुओं को पोषक तत्त्वों की उपलब्धता की कमी के परिणामस्वरूप निम्न उत्पादन और उत्पादकता (ii) खरीदे गए अपशिष्टों तथा सांद्रितों के माध्यम से पौषणिकता की कमी को पूरा करने संबंधी उत्पादन की लागत में वृद्धि के रूप में देखा गया है।

(ङ) और (च) विभाग देश भर में केंद्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें घास रिजर्व सहित घास भूमि का विकास नामक घटक शमिल है। इस घटक के तहत, राज्यों को वर्ष 2007-08 के तहत 828.19 लाख तथा 2008-09 में 535.20 लाख रुपए जारी गए थे।

गो-हत्या के विरुद्ध केन्द्रीय कानून

2345. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर :**
श्री वीरेन्द्र कश्यप :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अवैध बूचड़खानों के होने के कारण गायों की संख्या कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गो-हत्या पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधान पारित करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को देश में गो-हत्या निवारण संबंधी एक केन्द्रीय कानून अधिनियमित करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, नहीं। 1997 से 2003 तक के वर्षों में देश में गायों की संख्या 64.43 से बढ़कर 64.51 मिलियन हो गई है।

(ग) निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने गोवध पर पाबंदी लगाने अथवा प्रतिबंधित करने के लिए कानून पास किए हैं:-

(1) आंध्र प्रदेश, (2) असम, (3) बिहार, (4) गोवा, (5) गुजरात, (6) हरियाणा, (7) हिमाचल प्रदेश, (8) जम्मू और कश्मीर, (9) कर्नाटक, (10) मध्य प्रदेश, (11) महाराष्ट्र, (12) उड़ीसा, (13) पंजाब, (14) राजस्थान, (15) सिक्किम, (16) तमिलनाडु, (17) उत्तर प्रदेश, (18) पश्चिम बंगाल, (19) मणिपुर, (20) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, (21) उत्तरांचल, (22) झारखंड, (23) छत्तीसगढ़, (24) केरल, (25) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, (26) चंडीगढ़, (27) दादरा और नगर हवेली, (28) दमन ओर दीव, (29) पुड्डुचेरी।

(घ) जी, हां।

(ङ) राज्य का विषय होने के कारण संसद गोवध पर कानून लागू करने में सक्षम नहीं है।

पशुधन और पोल्ट्री में स्वाइन फ्लू का फैलना

2346. **श्री राकेश सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वाइन फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए केन्द्रीय पशु रोग प्रयोगशालाओं और केन्द्रीय/राज्य सरकार के पशुपालन विभागों को क्या कार्य सौंपा गया है;

(ख) क्या सरकार उनके कार्यनिष्पादन से संतुष्ट है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस समस्या पर काबू पाने और देश में पशुधन और पोल्ट्री को बचाने के लिए कोई आकस्मिक योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) केन्द्रीय/क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाएं पशुधन रोगों के निदान के लिए रेफरल प्रयोगशालाओं के रूप में काम करती हैं। ये प्रयोगशालाएं पशु रोगों के निवारण, नियंत्रण और रोकथाम की दिशा में राज्य सरकारों और उनकी प्रयोगशालाओं के प्रयासों को समर्थन देती हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। राज्यों ने सुअरों की संख्या की सघन वास्तविक निगरानी की है। सूअरों में किसी भी असामान्य मृत्यु की निकट से जांच की जाती है और नमूनों को उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला, भोपाल को भेजा जाता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सभी राज्यों को अप्रैल, 2009 में एक सलाह पत्र तथा स्वाइन इंफ्लूएंजा के बारे में एक तथ्य पत्र सर्कुलेट किया गया था। सरकार देश में पशुओं में स्वाइन फ्लू की घटना की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निगरानी रख रही है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

2347. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का कृषि सुधार के लिए राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का विचार है ताकि कृषि क्षेत्र में लक्षित चार प्रतिशत विकास दर को हासिल किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कौन-कौन सी नई योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ग) विश्वव्यापी आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में सुधार करने और इसमें जान फूंकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ऐसी राजसहायता के परिणामस्वरूप छोटे किसानों को होने वाले लाभ क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार के पास कृषि क्षेत्र में लक्षित 4 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के लिए कृषि में सुधार हेतु राज्यों को कोई विशेष केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि कृषि और सहकारिता विभाग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दो स्कीमें शुरू की हैं- (i) 25000 करोड़ रुपये से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और (ii) 4883 करोड़ रुपये से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ताकि कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत विकास प्राप्त करने के उपाय के रूप में कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके। इन दोनों स्कीमों हेतु वर्ष 2009-10 के लिए राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कृषि और सहकारिता विभाग कृषि क्षेत्र के सुधार और पुनः सक्रियकरण तथा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई केन्द्र प्रायोजित स्कीमें/केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें क्रियान्वित करता है। सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत-2008 की स्कीम भी कार्यान्वित की है।

(घ) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें छोटे किसानों सहित समस्त कृषक समुदाय के लाभ के लिए है।

अब तक 65318.33 करोड़ रुपये की ऋण माफी और ऋण राहत को शामिल करते हुए इस स्कीम से कुल 3.01 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों और 67 लाख अन्य किसानों को लाभ मिला है।

विवरण

क्र. सं.	राज्यों का नाम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) आबंटन 2009-10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) आबंटन 2009-10
1	2	3	4
1.	आंध प्रदेश	12504.90	31533.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	1439.00
3.	असम	2727.70	4753.00

1	2	3	4
4.	बिहार	8188.40	7050.00
5.	झारखंड	1193.10	9714.00
6.	गोवा	0.00	432.00
7.	गुजरात	1510.60	29448.00
8.	हरियाणा	2940.60	9691.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	2445.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	3338.00
11.	कर्नाटक	4873.20	24362.00
12.	केरल	347.20	9948.00
13.	मध्य प्रदेश	8435.00	20239.00
14.	छत्तीसगढ़	5083.40	28839.00
15.	महाराष्ट्र	7256.20	30270.00
16.	मणिपुर	0.00	483.00
17.	मिजोरम	0.00	327.00
18.	मेघालय	0.00	1991.00
19.	नागालैंड	0.00	1854.00
20.	उड़ीसा	4310.40	9674.00
21.	पंजाब	4859.40	6529.00
22.	राजस्थान	4216.10	14572.00
23.	सिक्किम	0.00	1233.00
24.	तमिलनाडु	3237.70	8757.00
25.	त्रिपुरा	0.00	2466.00
26.	उत्तर प्रदेश	25303.20	31533.00
27.	उत्तराखंड	0.00	5856.00
28.	पश्चिम बंगाल	7228.90	12155.00
	जोड़	104216.00	311931.00

*सभी आंकड़े अंतरिम बजट पर आधारित है।

**आबंटनों में संशोधन हो सकता है।

[हिन्दी]

टीवी ट्रांसमीटर्स

2348. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में और उच्च शक्ति वाले टेलीविजन (टीवी) ट्रांसमीटर लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्य-वार टीवी ट्रांसमीटर/उच्च शक्ति वाले टीवी ट्रांसमीटर लगाने से संबंध में प्राप्त/लंबित/स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(घ) इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं और लंबित प्रस्तावों को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) और (ख) 10वीं योजना की सतत स्कीमों के अतर्गत महबूबनगर (आंध्र प्रदेश) एवं बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में दो नए उच्च शक्ति टीवी ट्रांसमीटर अनुमोदित कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) नए टीवी ट्रांसमीटरों को लगाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं और टीवी का विस्तार करने संबंधी योजनाओं को तैयार करते समय इनको ध्यान में रखा जाता है।

दुधारू पशु

2349. श्री अशोक कुमार रावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुधारू पशुओं की संख्या घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया जाता है;

(घ) यदि हां, तो विगत वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रवृत्ति से देश में दुग्ध उत्पादन के किस हद तक प्रभावित होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां।

(ख) देश में दुधारू गोपशु की संख्या 1997 की पशुधन संगणना में 58.2 मिलियन से मामूली तौर पर घटकर 2003 की पशुधन संगणना में 58.1 मिलियन हो गई है। यह कमी स्वदेशी दुधारू गोपशु की संख्या में कमी के कारण आई है। तथापि, इसी अवधि के दौरान दूध दे रहे गोपशुओं की संख्या 33.3 मिलियन से बढ़कर 35.8 मिलियन हो गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) 1997 और 2003 की पशुधान संगणना के अनुसार दुधारू पशुओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) देश में दूध उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। देश में दूध उत्पादन 1999-2000 में 78.3 मिलियन टन से बढ़कर 2007-08 में 104.8 मिलियन टन हो गया है।

विवरण

1997 और 2003 के पशुधन संगणना के आधार पर दुधारू गोपशु की राज्यवार संख्या

(हजार)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ण संकरित		स्वदेश		कुल दुधारू गोपशु	
		1997	2003	1997	2003	1997	2003
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	294	475	2234	1934	2528	2409
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	5	95	111	98	116
3.	असम	132	161	2006	2035	2138	2195
4.	बिहार	68	569	5451	2840	5519	3408
5.	छत्तीसगढ़	40	67	2482	2313	2522	2380
6.	गोवा	4	6	21	17	25	23
7.	गुजरात	170	318	2000	2120	2170	2437
8.	हरियाणा	260	263	431	309	691	572
9.	हिमाचल प्रदेश	147	334	515	479	662	812

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू और कश्मीर	328	543	650	598	978	1141
11.	झारखंड	0	69	0	1830	0	1898
12.	कर्नाटक	690	903	2978	2500	3668	3403
13.	केरल	1050	791	271	152	1321	943
14.	मध्य प्रदेश	83	136	5643	5704	5726	5840
15.	महाराष्ट्र	1132	1389	4219	3532	5351	4921
16.	मणिपुर	22	23	88	78	110	101
17.	मेघालय	10	15	213	215	223	230
18.	मिजोरम	3	4	7	7	10	11
19.	नागालैंड	41	87	53	50	94	137
20.	उड़ीसा	354	386	3399	3235	3753	3621
21.	पंजाब	866	741	287	124	1153	865
22.	राजस्थान	78	235	4557	4248	4635	4483
23.	सिक्किम	20	33	28	26	48	60
24.	तमिलनाडु	1377	2351	1795	1341	3172	3693
25.	त्रिपुरा	26	25	384	215	410	240
26.	उत्तर प्रदेश	638	642	4633	4901	5271	5543
27.	उत्तराखंड	43	99	572	595	615	694
28.	पश्चिम बंगाल	411	489	4799	5293	5210	5782
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	5	19	15	21	20
30.	चंडीगढ़	4	3	0.45	1	4.45	4
31.	दादरा और नगर हवेली	0	1	10	10	10	11
32.	दमन और दीव	0.03	0.03	1	1	1.03	1.03

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दिल्ली	36	34	22	20	58	54
34.	लक्षद्वीप	0.4	1	1	0.48	1.4	1.48
35.	पुदुचेरी	24	28	10	7	34	34
	कुल	8356	11231	49874	46856	58231	58084

[अनुवाद]

अवैध अप्रवास संबंधी

2350. श्री उदय सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अवैध अप्रवास और घुसपैठ के संबंध में सरकार को निदेश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बांगलादेश से आए अवैध आप्रवासियों की समस्या के हल के संबंध में दिनांक 15.4.2009 के अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि संघ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिप्रेक्ष्य में, अवैध आप्रवासियों को रोकने के लिए समस्त संभव कदम उठाने हेतु संघ सरकार को निदेश दिए जाने के अतिरिक्त किसी अगले आदेश की आवश्यकता नहीं है।

बांगलादेश से गैर कानूनी घुसपैठ को रोकने के क्रम में, भारत सरकार ने निम्नलिखित सहित बहुआयामी नीति को अपनाया है:

(i) सीमा पर बाड़ लगाना, सड़कों का निर्माण करना तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करना।

(ii) सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा की चौबीस घंटे निगरानी करना।

(iii) सीमा पर प्रभावी वर्चस्व कायम करने के लिए सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करने हेतू भारत बांगलादेश सीमा के साथ 1185 सीमा चौकियों की स्थापना करना, जिसमें से 802 सीमा चौकियों को स्थापित कर लिया गया है। शेष 383 सीमा चौकियों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

(iv) नाइट विजन डिवाइस सहित हाईटेक सर्विलेंस इक्विपमेंट को सम्मिलित किया जाना।

केन्द्र सरकार को विदेशी विपयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के अंतर्गत विदेशी नागरिकों को निर्वासित करने का अधिकार सौपा गया है। गैरकानूनी ढंग से रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाने एवं उन्हें निर्वासित करने के अधिकार राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासकों को भी सौंपे गए हैं। गैरकानूनी बांगलादेशी आप्रवासियों का पता लगाने एवं निर्वासित करने की प्रक्रिया भी निर्धारित कर ली गई है और राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र की प्रशासनों को वितरित कर दी गई है। अवैध बांगलादेशी आप्रवासियों का पता लगाना एवं उनका निर्वासन करना एक अनवरत चलाने वाली प्रक्रिया है।

राजसहायता प्राप्त खाद्य तेलों की आपूर्ति

2351. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बीपीएल परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के परिवारों को राजसहायता प्राप्त खाद्य तेलों की आपूर्ति के लिए योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) :

(क) और (ख) वर्ष 2008-09 के दौरान 'राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जरिए राजसहायता प्राप्त आयातित खाद्य तेलों का वितरण करने की स्कीम' शुरू की गई थी। इस स्कीम में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात एसटीसी, एमएमटीसी, पीईसी और नेफेड के जरिए 10 लाख टन खाद्य तेल का आयात करने, इसका प्रसंस्करण करने और राज्यों को एक लीटर अथवा आधे लीटर के पैक में इसकी सुपुर्दगी करने की परिकल्पना की गई है ताकि राज्य लाभार्थियों को अधिक से अधिक एक किलोग्राम प्रति राशन कार्ड प्रति माह की दर से आगे इसका वितरण कर सकें। 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनमें से प्रत्येक राज्य की आवश्यकता और राज्य में गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के अनुसार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खाद्य तेलों का आबंटन किया गया था। केन्द्रीय राजसहायता जनवरी तक 15 रुपये प्रति किलोग्राम और उसके बाद 31.3.2009 तक 25 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

इस स्कीम के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 3.6 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया था। इस स्कीम के अधीन खाद्य तेलों का वितरण 12 राज्यों द्वारा किया गया है। इस स्कीम के अधीन इन राज्यों को 2.61 लाख टन पैक खाद्य तेल (आरबीडी पामोलिन और रिफाइंड सोयाबीन तेल) सुपुर्द किया गया था। यह स्कीम 31.3.2009 को समाप्त हो गई।

जमाखोरी के विरुद्ध उपाय

2352. श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों की प्रभावोत्पादकता के संबंध में कोई आकलन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और स्टॉक सीमाओं के संबंध में मारे गए छापों, जब्त किए गए माल और नियमों के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किए गए व्यापारियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त नियमों के उल्लंघन के लिए दोषी अधिकारियों सहित व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) संसदीय स्थायी समिति ने अपने 28वें प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया था कि विभाग इस बात की जांच करे कि क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 में कोई कमी है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से समिति द्वारा की गई सिफारिश पर अपना अभिमत भेजने का अनुरोध किया गया था। 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जबाव प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच कर ली गई है। यह महसूस किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में कोई कमी नहीं है और उपलब्ध उपबंध, यदि समुचित रूप से कार्यान्वित किए जाएं तो वांछित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पर्याप्त हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2006, 2007, 2008 और 2009 (16.07.2009 तक) मारे गए छापों, जब्त किए गए माल के मूल्य और नियमों के उल्लंघन के लिए बुक किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I से IV पर दिए गए हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा केंद्र सरकार को दी गई सूचना के अनुसार 1.1.2006 से 16.7.2009 तक अवधि के दौरान चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत नजरबंदी आदि के ब्यौरे संलग्न विवरण नीचे दिए गए हैं :-

राज्य का नाम	2006	2007	2008	2009 (16.7.2009 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
गुजरात	85	50	16	10
तमिलनाडु	74	65	141	69
उड़ीसा	01	—	01	02

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	01	01	—	01
मध्य प्रदेश	—	03	—	—
आंध्र प्रदेश	—	—	04	—
कुल	161	119	162	82

(ङ) राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के उपबंधों के तहत कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जमाखोरी रोधी प्रचालन शुरू करने के लिए प्रभावी कार्रवाई जारी रखने हेतु सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकारों को दालों, खाद्य तेलों खाद्य तिलहनों, चावल, धान और चीनी के संबंध में 15.2.2002 के केंद्रीय आदेश के कुछ उपबंधों आस्थगित रखकर स्टॉक होल्डिंग सीमाएं जैसे प्रतिबंध लगाने के लिए सक्षम बनाने का निर्माण लिया गया गेहूं, जिसको उक्त सूची में शामिल किया गया था, को 1.4.2009 से सूची से हटा दिया गया है। इसके अलावा, चीनी के संबंध में भारत सरकार ने निम्नलिखित स्टॉक-होल्डिंग/टर्न ओवर सीमाएं भी तय की है।

स्टॉकहोल्डिंग (i) कोलकाता और विस्तारित क्षेत्र में-

(क) मान्यताप्राप्त ब्यौहारी जो पश्चिम बंगाल के बाहर से आयात करते हैं - 10,000 क्विंटल

(ख) अन्य मान्यताप्राप्त व्यौहारी - 2000 क्विंटल

(ii) अन्य स्थानों में - 2000 क्विंटल

टर्न-ओवर कोई भी व्यौहारी चीनी के स्टॉक को उसके द्वारा ऐसे स्टॉक को प्राप्त किए जाने की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं रख सकेगा।

विवरण-I

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वर्ष 2006 के लिए प्राप्त सूचना (1.1.2006 से 31.12.2006 तक)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध पाए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (लाख रुपए)	तक सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8747	190	20	40	106.2	नवम्बर
2.	असम	947	161	4	1	0.26	जून
3.	अरुणाचल प्रदेश	20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	फरवरी
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सूचित नहीं
5.	छत्तीसगढ़	341	17	175	94	165.5	नवम्बर
6.	दिल्ली	67	32	शून्य	शून्य	0.47	नवम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गुजरात	31816	55	116	शून्य	47.8	नवम्बर
8.	गोवा	17	शून्य	शून्य	शून्य	0.1	दिसम्बर
9.	हरियाणा	28	23	13	शून्य	1.16	नवम्बर
10.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	अक्तूबर
11.	जम्मू और कश्मीर	230	188	104	शून्य	0.43	मार्च
12.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	सूचित नहीं
13.	कर्नाटक	2887	53	3	शून्य	26.9	नवम्बर
14.	केरल	3795	3	3	शून्य	0.21	अगस्त
15.	मध्य प्रदेश	29465	85	249	337	244.16	2005-06
16.	महाराष्ट्र	2466	1514	2190	शून्य	118.24	नवम्बर
17.	मणिपुर	68	9	9	9	9.2	अक्तूबर
18.	मेघालय	56	7	7	शून्य	0.06	नवम्बर
19.	मिजोरम	47	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मई
20.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
21.	उड़ीसा	1218	27	93	शून्य	9.89	सितम्बर
22.	पंजाब	32634	19	4	शून्य	0.4	सितम्बर
23.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सूचित नहीं
24.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	अगस्त
25.	तमिलनाडु	2063	171	शून्य	शून्य	125.71	अप्रैल*
26.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सूचित नहीं
27.	उत्तराखंड	13398	10	23	शून्य	2.33	2005-06
28.	उत्तर प्रदेश	4163	55	163	17	114.54	सितम्बर$
29.	पश्चिम बंगाल	270	73	31	शून्य	2.91	सितम्बर**

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	128	2692	शून्य	शून्य	शून्य	सितम्बर
31.	चंडीगढ़	3	4	4	शून्य	0.13	अक्तूबर$$
32.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	अगस्त
33.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सूचित नहीं
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	नवम्बर
35.	पुदुचेरी	151	33	33	शून्य	0.61	नवम्बर
	कुल	135025	5421	3244	498	977.21	

*केवल जनवरी और अप्रैल $ केवल जून, जुलाई और सिम्बर

$$ मई को छोड़कर **अप्रैल को छोड़कर

विवरण-II

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वर्ष 2007 के लिए प्राप्त सूचना (31.12.2006 तक)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध पाए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (लाख रुपए में)	तक सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6766	67	11	11	28.79	नवम्बर
2.	असम	1768	108	32	शून्य	0.26	दिसम्बर
3.	अरुणाचल प्रदेश	33	1	1	शून्य	0.09	अक्तूबर
4.	बिहार	20	2	शून्य	शून्य	शून्य	जुलाई*
5.	छत्तीसगढ़	243	15	89	76	199.04	सितम्बर
6.	दिल्ली	94	63	8	1	24.91	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गुजरात	32142	60	134	शून्य	270.09	दिसम्बर
8.	गोवा	2	1	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
9.	हरियाणा	20	17	15	1	3.57	दिसम्बर
10.	हिमाचल प्रदेश	24212	4	330	शून्य	5.13	नवम्बर
11.	जम्मू और कश्मीर	588	555	342	शून्य	2.91	अक्तूबर
12.	झारखंड						सूचित नहीं
13.	कर्नाटक	3722	70	शून्य	शून्य	39.68	दिसम्बर
14.	केरल	36661	शून्य	1	शून्य	41.68	दिसम्बर$
15.	मध्य प्रदेश						सूचित नहीं
16.	महाराष्ट्र	2134	2798	1888	शून्य	611.56	दिसम्बर
17.	मणिपुर	94	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
18.	मेघालय	66	7	9	शून्य	1.25	दिसम्बर
19.	मिजोरम	232	शून्य	शून्य	शून्य	6.06	दिसम्बर
20.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	अक्तूबर
21.	उड़ीसा	4897	31	179	शून्य	135.04	दिसम्बर
22.	पंजाब	60431	12	5	2	0.6	दिसम्बर
23.	राजस्थान	196	12	52	4	28.86	मार्च
24.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	फरवरी
25.	तमिलनाडु	12634	1452	138	676	977.69	दिसम्बर
26.	त्रिपुरा	48	12	शून्य	शून्य	1.55	अक्तूबर
27.	उत्तराखंड						सूचित नहीं
28.	उत्तर प्रदेश	47304	1430	1548	251	1613.94	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	पश्चिम बंगाल	227	174	43	शून्य	2.95	नवम्बर
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	324	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
31.	चंडीगढ़	3	9	3	शून्य	1.21	जुलाई
32.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सितम्बर
33.	दमन और दीव						सूचित नहीं
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सितम्बर
35.	पुदुचेरी	544	44	44	शून्य	7.1	दिसम्बर
	कुल	235405	6944	4872	1022	4003.96	

*-जनवरी को छोड़कर $ - अगस्त को छोड़कर

15.4.2008 तक अद्यतन

विवरण-III

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वर्ष 2008 के लिए प्राप्त सूचना (31.12.2006 तक)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध पाए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (लाख रुपए में)	तक सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	17235	29	6	—	86.12	दिसम्बर
2.	असम	1419	14	19	शून्य	2.37	दिसम्बर*
3.	अरुणाचल प्रदेश	23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	नवम्बर
4.	बिहार	16	9	शून्य	शून्य	शून्य	सितम्बर
5.	छत्तीसगढ़	225	1	32	1	102.03	मार्च

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	दिल्ली	153	135	119	4	61.7	दिसम्बर
7.	गुजरात	31098	20	142	शून्य	253.15	दिसम्बर
8.	गोवा	121	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
9.	हरियाणा	46	8	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
10.	हिमाचल प्रदेश	25634	13	49	शून्य	15.52	दिसम्बर$$
11.	जम्मू और कश्मीर	422	376	94	शून्य	शून्य	सितम्बर
12.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	अप्रैल
13.	कर्नाटक	3396	74	1	4	580.95	दिसम्बर
14.	केरल	87305	12	2	शून्य	12.98	दिसम्बर
15.	मध्य प्रदेश	14921	52	107	शून्य	405.15	अप्रैल
16.	महाराष्ट्र	2551	3376	2595	शून्य	2365.92	दिसम्बर
17.	मणिपुर	99	4	3	3	0.16	दिसम्बर
18.	मेघालय	70	1	2	1	0.05	दिसम्बर
19.	मिजोरम	61	शून्य	शून्य	शून्य	0.49	जुलाई**
20.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
21.	उड़ीसा	2001	22	117	शून्य	17.51	नवम्बर
22.	पंजाब	20632	22	9	4	3.08	नवम्बर
23.	राजस्थान	450	13	170	4	18.12	जुलाई
24.	सिक्किम	1	2	2	शून्य	0.01	दिसम्बर
25.	तमिलनाडु	20268	2525	1127	761	683.33	नवम्बर
26.	त्रिपुरा	35	12	9	शून्य	2.69	दिसम्बर
27.	उत्तराखंड						सूचित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	उत्तर प्रदेश	39474	1047	1734	शून्य	1410.49	दिसम्बर
29.	पश्चिम बंगाल	176	142	5	शून्य	58.83	दिसम्बर
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	291	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर***
31.	चंडीगढ़	6	9	शून्य	शून्य	2.01	दिसम्बर
32.	दादरा और नगर हवेली	13	2	शून्य	शून्य	5.49	दिसम्बर
33.	दमन और दीव						सूचित नहीं
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
35.	पुदुचेरी	633	81	81	8	7.07	दिसम्बर
	कुल	268775	8001	6425	790	6095.22	

* - जनवरी और फरवरी को छोड़कर

**-अप्रैल, मई और जून को छोड़कर

$$ -अक्तूबर को छोड़कर

***-सितम्बर और अक्तूबर को छोड़कर

विवरण-IV

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वर्ष 2009 के लिए प्राप्त सूचना (31.12.2006 तक)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध पाए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (लाख रुपए में)	तक सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2455	1	शून्य	1	47.73	मई
2.	असम	1103	2	शून्य	शून्य	शून्य	अप्रैल
3.	अरुणाचल प्रदेश						सूचित नहीं
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	अप्रैल

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़						सूचित नहीं
6.	दिल्ली	33	22	31	शून्य	शून्य	मई
7.	गुजरात	9271	7	33	शून्य	184.76	मई
8.	गोवा	12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मई
9.	हरियाणा	34	2	शून्य	शून्य	शून्य	अप्रैल*
10.	हिमाचल प्रदेश	9002	3	शून्य	शून्य	3.76 अप्रैल	
11.	जम्मू और कश्मीर						सूचित नहीं
12.	झारखंड						सूचित नहीं
13.	कर्नाटक	317	18	3	शून्य	0.71	अप्रैल*
14.	केरल	15179	11	शून्य	शून्य	23.14	मई
15.	मध्य प्रदेश						सूचित नहीं
16.	महाराष्ट्र	447	736	515	शून्य	184.9	अप्रैल
17.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मई***
18.	मेघालय	2	शून्य	2	शून्य	शून्य	जून
19.	मिजोरम						सूचित नहीं
20.	नागालैंड						सूचित नहीं
21.	उड़ीसा	296	1	7	शून्य	0.87	अप्रैल
22.	पंजाब	11	17	11	11	1.22	अप्रैल
23.	राजस्थान						सूचित नहीं
24.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	मई
25.	तमिलनाडु	5614	1970	587	शून्य	282.31	मई
26.	त्रिपुरा	2	शून्य	शून्य	शून्य	0.03	मई
27.	उत्तराखंड						सूचित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	उत्तर प्रदेश	12992	283	477	शून्य	570.55	अप्रैल
29.	पश्चिम बंगाल	45	52	शून्य	शून्य	13.85	अप्रैल
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	29	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मार्च
31.	चंडीगढ़	2	2	शून्य	शून्य	0.33	अप्रैल
32.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मई*
33.	दमन और दीव						सूचित नहीं
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मई
35.	पुदुचेरी	144	25	25	12	0.63	मई
	कुल	56990	3152	1691	24	1314.79	

*-मार्च को छोड़कर **-केवल अप्रैल

***-मार्च और अप्रैल को छोड़कर 16.7.2009 तक की स्थिति

[हिन्दी]

भारत विरोधी गतिविधियां

2353. योगी आदित्यनाथ : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत-नेपाल सीमा पर हो रही अवैध और भारत विरोधी गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पता लगे ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नेपाल के साथ खुली सीमा को सुरक्षित करने सहित इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क)भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ "अवांतर भूमि" पर अवैध कब्जा किए जाने और नेपाल की तरफ से सीमा के खम्भों को क्षति पहुंचाए जाने के दृष्टांतों की सूचना समय-समय पर दी जाती रही है।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान "अवांतर भूमि" पर अवैध कब्जा किए जाने और सीमा के खम्भों को क्षति पहुंचाए जाने के दृष्टांत निम्नवत हैं:

वर्ष	सूचित की गई घटनाएं
1	2
2006	बहराइच जिले (उत्तर प्रदेश) में अवांतर भूमि पर अवैध कब्जा और लखीमपुर खीरी जिले (उत्तर प्रदेश) में सीमा के खंम्भों को क्षति।
2007	लखीमपुर खीरी जिले (उत्तर प्रदेश) में सीमा के खम्भों को क्षति और पीलीभीत जिले (उत्तर प्रदेश) में "अवांतर भूमि" पर अवैध कब्जा।

1	2
2008	पीलीभीत जिले (उत्तर प्रदेश) में "अवांतर भूमि" पर अवैध कब्जा।
2009 (अब तक)	पश्चिमी चम्पारण जिले (बिहार) में सीमा के खंम्भों को क्षति, झापा जिले (नेपाल) के आस-पास वाले भारतीय भू-भाग में सीमा खंभे स्थानांतरित करना, जोगबनी, अररिया जिले (बिहार) में "अवांतर भूमि" पर नाला/नालियां बनाना और श्रावस्ती जिले (उत्तर प्रदेश) में सीमा खंभों को क्षति पहुंचाना।

(ग) भारत-नेपाल सीमा (आई एन बी) सुभेद्य सीमा होने के कारण इसमें ऐसे कई ज्ञात मार्ग हैं जो दोनों देशों के नागरिकों के प्रवेश करने और बाहर जाने को सुकर बनाते हैं। आई एन बी के साथ किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि को रोकने के लिए एस एस बी तैनात की गई है और वह सीमा पर कड़ी सतर्कता बरतती है। आई एन बी के साथ निवारात्मक उपाय के रूप में एस एस बी की गश्त और नाकेबंदी जैसी परिचालनात्मक गतिविधियों को तेज कर दिया गया है। इसके अलावा, संबंधित राज्य पुलिस भी सर्तकता रखती है।

अवैध कब्जा, तस्करी, राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप, सीमा के खंभों को क्षति आदि पहुंचाने जैसे विभिन्न सीमावर्ती मुद्दों से कारगर ढंग से निपटने के लिए दोनों देशों के पदाधिकारियों के बीच सीमा जिला समन्वय समिति (बी डी सी सी) की बैठकें आयोजित किए जाने जैसे संस्थागत तंत्र मौजूद हैं। इन मुद्दों को दोनों देशों के राजनयिक चैनलों के माध्यम से भी उठाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन संयुक्त कार्य दल और गृह सचिव स्तर की कार्ता जैसी द्विपक्षीय संस्थागत व्यवस्था मौजूद है जो इन समस्याओं को और प्रभावी ढंग से हल करती है।

भारत द्वारा नेपाली भू-भाग पर कथित रूप से अवैध कब्जा किए जाने के संबंध में नेपाल में हाल में छपी कुछ मीडिया रिपोर्टों की जांच-पड़ताल की गई है और इन्हें असत्य पाया गया है।

[अनुवाद]

सिलीगुड़ी आकाशवाणी केन्द्र

2354. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिलीगुड़ी आकाशवाणी केन्द्र कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए आत्मनिर्भर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त केन्द्र को अपग्रेड करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का उत्तर बंगाल लोक संस्कृति कार्यक्रमों के लिए टाइम स्लाट बढ़ाने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) आकाशवाणी, सिलीगुड़ी 200 कि.वा. मीडिया वेव ट्रांसमीटर (प्राथमिक चैनल), स्टुडियों निर्माण संबंधी सुविधाओं, उपग्रह अभिग्रहण सुविधाओं और विविध भारती के कार्यक्रमों के रिले हेतु 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर के साथ एक पूर्ण-विकसित स्टेशन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। 11वीं योजना के मसौदे में मौजूदा स्टुडियों उपस्करों और मी.वे. ट्रांसमीटर को नई डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपस्कर से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। 11वीं योजनागत स्कीम के मसौदे के अंतर्गत इस स्कीम को अभी अनुमोदित किया जाना है।

(ङ) उत्तर बंगाल संस्कृति कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए कोई विशिष्ट समय उद्दिष्ट नहीं किया गया है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र आयोग

2355. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग की संरचना और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या आयोग ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में पेश आ रही समस्याओं की जांच के लिए सरकार ने सितंबर 2004 में असंगठित क्षेत्र में उद्यमों हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की तथा इन उद्यमों को तकनीकी, विपणन और ऋण सहायता प्रदान करने के लिए समुचित सिफारिशें कीं। 30 अप्रैल 2009 को आयोग की कार्यावधि समाप्त हो गई। आयोग के विचारार्थ विषय और आयोग के संगठन के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। आयोग ने समय-समय पर असंगठित क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों ग्यारह रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। ये रिपोर्टें http://ncens.gov.in पर एनसीईयूएस की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कार्यवाही योग्य बिंदुओं की पहचान, कार्रवाई बिंदुओं के कार्यान्वयन हेतु रीति-निर्धारण तथा इनके कार्यान्वयन हेतु समय सीमाएं निर्धारित करने और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्रवाई के समन्वयन तथा समयबद्ध रूप से कार्यान्वयन को मानिटर करने के उद्देश्य से इन रिपोर्टों में निहित सिफारिशों की जांच हेतु सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक अंर्तमंत्रालयीन दल गठित किया गया है।

विवरण-I

असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग के विचारार्थ विषय

आयोग के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं:-

(i) उद्यम की प्रकृति, उसके आकार, विस्तार एवं क्षेत्र तथा रोजगार की प्रमात्रा सहित भारत में असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा करना।

(ii) उद्योग चलाने की स्वतंत्रता, कच्चे माल, वित्त, उद्यमिता विकास, आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी तथा बाजारों तक अभिगम्यता के संबंध में लघु उद्योगों द्वारा झेले जा रहे प्रतिबंधों का अभिज्ञान तथा उन तक सुगत अभिगम्यता सुविधाजनक बनाने के लिए संस्थागत सहायता और संपर्क प्रदान करने के लिए उपाय सुझाना।

(iii) अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र की वृद्धि, रोजगार, निर्यात तथा संवर्धन शासित करने वाला वैध और नीतिपरक वातावरण सुझाना।

(iv) अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन संबंधी विद्यमान कार्यक्रमों की श्रृंखला की जांच करना और उनके रिडिजाइन करने के लिए सुधार सुझाव।

(v) अनौपचारिक क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रवर्तित विधिपरक और वित्तीय संसाधनों का अभिज्ञान।

(vi) अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार और बेरोजगारी आकलन हेतु विद्यमान प्रबंधों की समीक्षा करना और इस बात की जांच करना कि 1990 में रोजगार में वृद्धि दरें क्यों अवरुद्ध हुई।

(vii) अनौपचारिक क्षेत्र में एक संकेन्द्रित रोजगार योजना के अनुकूल वातावरण सुझाना।

(viii) श्रमिक अधिकारों से सुसंगत तथा विशेषत: अनौपचारिक क्षेत्र में उद्योग तथा सेवाओं की वृद्धि के विस्तार की अपेक्षाओं के अनुरूप भारतीय श्रम कानूनों की समीक्षा तथा उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार।

(ix) अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिक के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा और इसकी कवरेज के विस्तार हेतु सिफारिशें करना।

विवरण-II

असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन।

(सदस्य और उनकी कार्यावधि)

प्रोफेसर अर्जुन सेनगुप्ता अध्यक्ष, विकास और मानवाधिकार केन्द्र नई दिल्ली	**अध्यक्ष** [20.09.2004 से 01.07.2005 और 17.11.2005 से 30.4.09 तक]
प्रोफेसर के.पी. कानन फेलो सेन्टर फार डेवलपमेंट स्टडीज उलूर, थिरुवनंतापुरम 695011, केरल	**पूर्णकांलिक सदस्य** [01.11.2004 से 30.4.09 तक]
प्रोफेसर रवि एस. श्रीवास्तव प्रोफेसर, सेंटर फार स्टडीज इन रीजनल डेवलपमेंट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली-110067	**पूर्णकालिक सदस्य** [01.05.2006 से 30.04.09 तक]
श्री वी.के. मल्होत्रा, आईएएस (सेवानिवृत्त)	**सदस्य सचिव** [01.03.2006 से 30.04.09 तक]
श्री बी.एन. युगांधर सदस्य योजना आयोग नई दिल्ली 110001	**अंशकालिक सदस्य** [05.11.2004 से 30.04.09 तक]
प्रोफेसर टी.एस. पापोला निदेशक इंस्टयूट फॉर स्टडीज इल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वसंत कुंज इंस्टीटयूशनल एरिया, नई दिल्ली 110070	**अंशकालिक सदस्य** [06.04.2005 से 30.04.2009 तक]
प्रोफेसर के. जयशंकर पूर्व वाइस चासंलर, काकातीया यूनिवर्सिटी, वारंगल, आंध्र प्रदेश	**पूर्णकालिक सदस्य** [01.12.2004 से 9.03.2006 तक]

श्री बिबेक डेबरॉय,
निदेशक,
राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फार
कंटेपरेरी स्टडीज,
नई दिल्ली 110001

अंशकालिक सदस्य
[27.10.2004 से 20.12.2005 तक]

श्री के.के. जासवाल,
आईएएस (सेवानिवृत्त)

सदस्य सचिव
[01.11.2004 से 18.02.2006 तक]

[हिन्दी]

हॉकी और अन्य खेलों को लोकप्रिय बनाना

2356. श्री जगदम्बिका पाल :
श्री अंजन कुमार एम. यादव :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निधियों की कमी के कारण हॉकी और अन्य खेल पिछड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में हॉकी और अन्य खेलों के संवर्धन और इन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सफलता हासिल की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता की स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त खेल परिसंघों को राष्ट्रीय कोचिंग कैंपों के संचालन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चैम्पियनशिप/टूर्नामेंटों के आयोजन, विदेशों में प्रतियोगिताओं के अवसर, विदेशी कोचों की नियुक्ति, खेल उपस्कर और उपभोज्य वस्तुओं की खरीद आदि के लिए सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान, 32.23 करोड़ रु., वर्ष 2007-08 के दौरान 57.40 करोड़ रु. तथा 2008-09 के दौरान 41.50 करोड़ रु. उपलब्ध कराएं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार विभिन्न खेल विधाओं के संवर्धन और विकास के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को सहायता देती है। भारतीय खेल प्राधिकरण खेल प्रतिभा की पहचान करने तथा उनका पोषण करने पर केन्द्रित स्कीमों का संचालन करता है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अवसरों सहित, सभी राष्ट्रीय एथलीट बनने वालों को अनुकूलतम प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(घ) सभी स्वामित्वधारियों के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत के खेल प्रदर्शन में पिछले समर ओलंपिक सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में सुधार आया है।

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए विशेष प्रकोष्ठ

2357. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की परियोजनाओं/तैयारी की प्रगति की निगरानी के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के संबंध में सामूहिक निर्णय लेने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा कोई समन्वय समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विशेष प्रकोष्ठ में कुशल कार्मियों को नियुक्त करने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान चालने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (घ) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में अगस्त, 2006 से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में "अंतरराष्ट्रीय खेल प्रभाग" का गठन किया गया है। यह प्रभाग केवल राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित कार्य देख रहा है। इसके अतिरिक्त, अवसंरचना संबंधी प्रत्येक परियोजना के लिए वेब आधारित निगरानी तंत्र भी तैयार किया गया है।

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित मुद्दों पर मुख्यमंत्री, दिल्ली तथा अध्यक्ष आयोजन समिति, राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के साथ विचार विमर्श करने के लिए तत्कालीन युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री की अध्यक्षता में वर्ष 2008 में एक समन्वय समिति गठित की गई थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री की अध्यक्षता में अब इस समिति की सभी संबंधितों के साथ नियमित रूप से बैठक होती हैं जिसमें राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित विभिन्न मामलों की प्रगति की समीक्षा होती है। इसके अलावा, सचिव (खेल) की अध्यक्षता में अवसंरचना समन्वय समिति और प्रत्येक स्थल की स्टेडियम समिति के साथ नियमित आधार पर परियोजनाओं की समीक्षा भी की जाती है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की कमी

2358. श्री दुष्यंत सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अधिसंख्य राज्य खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन राज्यों की समस्याओं को दूर करने हेतु प्रदत्त अनुदानों और सहायता की प्रकृति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव

2359. श्री अशोक कुमार रावत : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव/विकास/सुधार हेतु आबंटित, जारी और उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटित और प्रयुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटित और प्रयुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन*	व्यय**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	65.76	65.40	82.44	81.59	192.97	196.38	79.38	54.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.30	8.29	6.00	5.65	1.10	1.10	3.30	0.00
3.	असम	79.11	77.10	87.96	86.00	88.25	87.65	40.68	31.50
4.	बिहार	111.26	106.17	96.82	90.28	104.02	95.02	54.31	42.47
5.	चंडीगढ़	1.00	0.96	2.00	2.00	3.39	3.39	1.30	0.00
6.	छत्तीसगढ़	39.45	36.19	42.19	40.15	67.42	65.74	32.75	24.48
7.	दिल्ली	3.00	1.47	9.00	8.30	15.80	15.80	5.00	2.39
8.	गोवा	2.95	2.64	15.00	15.00	34.39	34.39	11.00	1.73
9.	गुजरात	67.69	68.92	67.70	65.16	102.33	101.06	43.23	31.66
10.	हरियाणा	64.00	64.00	81.25	81.24	103.23	103.23	35.00	26.71
11.	हिमाचल प्रदेश	39.50	39.44	57.00	57.00	76.21	76.21	26.00	14.73
12.	झारखंड	34.86	35.00	57.25	57.24	96.41	96.41	40.00	9.96
13.	कर्नाटक	88.91	86.75	104.21	106.51	215.30	214.91	66.57	37.73
14.	केरल	62.02	54.44	58.48	50.10	72.53	73.20	46.54	36.49
15.	मध्य प्रदेश	98.73	91.71	80.88	76.40	110.14	98.35	43.40	28.38
16.	महाराष्ट्र	158.20	159.32	142.55	144.79	195.18	196.87	91.95	71.87
17.	मणिपुर	14.74	14.65	12.14	10.34	23.77	23.65	13.34	0.34
18.	मेघालय	25.40	24.31	22.88	22.33	51.60	50.77	20.27	0.89
19.	मिजोरम	15.53	15.53	15.00	15.00	13.55	13.55	9.30	0.82
20.	नागालैंड	11.82	11.81	12.00	10.20	30.60	30.60	13.30	0.00
21.	उड़ीसा	73.37	72.22	139.31	138.87	209.55	208.84	67.39	61.07
22.	पुडुचेरी	5.00	4.99	7.55	7.49	2.95	2.95	2.30	0.01
23.	पंजाब	75.34	74.69	85.95	85.47	156.77	156.77	52.01	37.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	राजस्थान	80.37	80.78	103.18	102.81	214.35	216.54	62.56	52.07
25.	तमिलनाडु	84.69	79.40	94.03	94.48	133.77	131.96	62.12	43.00
26.	उत्तर प्रदेश	97.35	101.36	135.87	132.50	223.51	222.20	86.21	84.80
27.	उत्तराखंड	54.61	52.86	41.30	38.98	112.40	112.29	30.89	19.26
28.	पश्चिम बंगाल	47.00	46.77	58.00	57.99	95.30	95.30	59.30	46.67
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00

नोट : राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटन में रारा (मूल) और पीबीएफएफ शामिल हैं।

*लेखानुदान के अनुसार आबंटन

**जून, 2009 तक

विवरण-II

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए आबंटित और प्रयुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन*	व्यय**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	61.19	56.59	78.13	77.36	83.25	89.65	20.08	2.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.30	0.09	0.37	0.33	1.82	0.00	0.50	0.00
3.	असम	25.98	21.18	41.62	32.46	40.20	39.01	9.80	0.93
4.	बिहार	34.34	24.58	29.90	25.32	44.50	14.09	18.17	5.03
5.	चंडीगढ़	0.66	0.64	0.98	0.84	0.68	0.73	0.25	0.00
6.	छत्तीसगढ़	24.15	23.52	27.19	26.58	27.26	24.01	10.50	5.11
7.	दिल्ली	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	गोवा	3.51	3.30	4.92	4.74	5.01	2.64	2.05	1.00
9.	गुजरात	33.99	33.95	40.27	39.56	42.04	34.03	12.00	5.88
10.	हरियाणा	24.27	21.34	18.13	17.95	19.64	18.11	5.95	1.14
11.	हिमाचल प्रदेश	18.90	18.28	17.70	17.07	18.84	20.91	6.60	1.12
12.	झारखंड	22.27	21.68	27.82	23.38	20.38	12.78	11.13	3.10
13.	कर्नाटक	39.88	39.88	59.45	60.30	71.24	64.54	18.37	1.53
14.	केरल	19.30	29.54	27.36	55.80	21.75	26.10	8.58	5.50
15.	मध्य प्रदेश	51.70	50.89	59.03	58.22	48.66	49.37	18.25	0.68
16.	महाराष्ट्र	59.54	59.16	63.16	57.54	62.92	35.17	24.93	6.40
17.	मणिपुर	3.04	2.91	14.30	11.52	10.24	4.47	2.05	0.00
18.	मेघालय	9.84	7.09	13.39	8.19	17.53	13.27	3.25	0.01
19.	मिजोरम	5.19	3.42	7.25	4.27	9.20	6.59	1.50	0.72
20.	नागालैंड	3.91	2.63	7.43	4.88	10.78	10.939	2.50	0.00
21.	उड़ीसा	43.70	43.78	50.51	50.28	52.56	55.20	15.80	1.23
22.	पुडुचेरी	0.94	0.30	0.91	0.91	1.10	1.18	0.83	0.00
23.	पंजाब	17.44	15.20	23.82	20.40	25.58	24.32	7.75	2.21
24.	राजस्थान	67.58	67.54	70.57	70.56	72.35	71.14	24.08	6.65
25.	तमिलनाडु	25.67	23.71	30.16	30.35	49.40	34.53	10.36	1.93
26.	उत्तर प्रदेश	45.63	48.54	62.48	62.21	55.22	51.163	21.50	14.67
27.	उत्तराखंड	15.80	15.39	19.10	17.12	21.87	20.37	7.79	4.60
28.	पश्चिम बंगाल	18.50	16.38	24.08	23.26	31.49	20.38	6.60	0.00
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00

*लेखानुदान के अनुसार आबंटन

**जून, 2009 तक

दिल्ली नगर निगम अधिकारियों द्वारा यात्राएं

2360. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों द्वारा कुल कितनी घरेलू और विदेश यात्राएं की गई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितना व्यय हुआ और इन यात्राओं से दिल्ली नगर निगम को कितना लाभ मिलने की संभावना है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली नगर निगम द्वारा मितोपभोग के क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : *(क) और (ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान दिल्ली नगर निगम (एम सी डी) के अधिकारियों द्वारा घरेलू एवं विदेशी भ्रमणों की संख्या तथा उन पर होने वाला व्यय निम्नलिखित है:-

वर्ष	किए गए भ्रमणों की संख्या		हुआ व्यय (रुपयों)	
2006-2007	48	4	20,14,311	2,55,987
2007-2008	63	3	27,83,044	9,24,903
2008-2009	79	3	29,42,243	9,24,903
चालू वर्ष (2009-2010)	22	1	12,66,345	1,01,710

एम सी डी ने सूचित किया है कि ये दौरे सार्वजनिक स्वास्थ्य, बच्चें एवं महिलाओं का कल्याण, निगम की सुचारू कार्यप्रणाली, भवन उपविधियाँ एवं मास्टर प्लान, रोगी और मलेरिया जैसे रोगों के नियन्त्रण के लिए रणनीतियाँ, जानवरों के लिए निवारणात्मक/उपचारात्मक उपाय, खाद्य स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वच्छता लैण्डफिल स्थल के अनुरक्षण, ठोस कचरा प्रबंधन आदि के सम्बंध में दक्षता एवं ज्ञान उन्नयन के लिए किए गए थे।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने जानकारी दी है कि ये दौरे आवश्यक समझे जाने पर तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार किए गए थे।

[अनुवाद]

*दिनांक 21.07.2009 के वाद-विवाद में अतारांकित प्रश्न संख्या 2360 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में तदनंतर दिनांक 04.08.2009 को सभा में दिए गए शुद्धि करने वाले विवरण के माध्यम से शुद्धि की गई और तदनुसार वर्ष 2007-2008 के अंतर्गत तालिका में संख्याओं को इस प्रकार संशोधित किया गया है;

"2007-2008 63 3 27,83,044 2,55,370"

चीनी पर जमाखोरी अधिसूचना का विस्तार

2361. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री एल. राजगोपाल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी की जमाखोरी को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम (इसीए), 1955 के अंतर्गत जारी किए गए आदेश केवल कुछ राज्यों द्वारा अधिसूचित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी राज्यों द्वारा उक्त आदेशों को शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) केंद्र सरकार सरकार ने 4 महीने की अवधि के लिए चीनी के डीलरों पर स्टॉक रखने की सीमा और कारोबारी अवधि की सीमा लागू करते हुए क्रमशः 9.3.2009 और 12.3.2009 को अधिसूचनाएं जारी की थीं। दिनांक 2.7.2009 और 16.7.2009 की अधिसूचनाओं और स्टॉक रखने और कारोबारी अवधि की सीमा को और 6 महीने बढ़ा दिया गया है। इन अधिसूचनाओं के अनुसरण में 11 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अर्थात् आंध्र प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह में अब तक अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्टॉक रखने और कारोबारी अवधि की सीमा क्रियान्वित कर दी है।

(ग) केंद्र सरकार ने उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने अभी तक स्टॉक रखने और कारोबारी अवधि की सीमा लागू नहीं की हैं, से पुन: अनुरोध किया है कि वे इस सीमा को शीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक लाइसेंसिंग तंत्र बनाएं।

मत्स्यन क्षेत्र को बढ़ावा

2362. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में रोजगार के अवसरों के विकास हेतु अंतर्देशीय मत्स्यन सहित मत्स्यन को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विद्यमान/प्रस्तावित केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा किन राज्यों में इसे लागू का दिया गया है/लागू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में मत्स्यन क्षेत्र के लिए आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने धनराशि के न्यून उपयोग के मुद्दे को गुजरात सहित संबंधित राज्यों के समक्ष उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त अवधि के दौरान देश में उक्त क्षेत्र से सृजित आय और रोजगार का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार, गुजरात सहित देश में मत्स्यन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं क्रियान्वित कर रही है, नामत: अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास, समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास, राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना और मात्स्यिकी क्षेत्र के डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण। ये योजनाएं मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने और उसके द्वारा रोजगार और जीविका के अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ग) से (ङ) गुजरात सहित धनराशि के राज्यवार रिलीज और उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से IV में दिया गया है। धनराशि के उपयोग से संबंधित मामले को संबंधित राज्य सरकारों के साथ आवधिक रूप से उठाया जाता है।

(च) मत्स्य उत्पादन, जो आय और रोजगार पर प्रभाव डालता है, हाल ही के वर्षों में निरन्तर बढ़ रहा है। मात्स्यिकी क्षेत्र में 14.48 मिलियन लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कार्यरत हैं। 2003 में राज्यवार मछुआरों की संख्या संलग्न विवरण-V में दी गई है। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार मत्स्य उत्पादन विवरण-VI में दिया गया है।

(छ) और (ज) प्रशिक्षण व जपागरूकता केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना में मौजूद है। तथापि, राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर गुण दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

विवरण-I

अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि के विकास योजना के तहत जारी और उपयोग की गई धनराशि

(लाख रुपए)

क्रम. सं.	राज्य का नाम	2006-07 तक जारी	उपयोगिता	2007-08 तक जारी	उपयोगिता	2008-09 तक जारी	उपयोगिता	2009-10 तक जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	363	363	0.00	0.00	36.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00		
3.	असम	40.00	40.00	0.00	0.00	75.02		
4.	बिहार	40.00	40.00	20.00	20.00	0.00		
5.	छत्तीसगढ़	80.00	80.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
8.	हरियाणा	20.00	20.00	100.00	100.00	25.00	10.94	
9.	हिमाचल प्रदेश	20.00	20.00	32.43	22.39	27.00	17.077	
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00		
11.	झारखंड	0.00	0.00	50.00	50.00	62.50	62.50	
12.	कर्नाटक	165.60	111.00	0.00	0.00	0.00		
13.	केरल	50.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
14.	मध्य प्रदेश	160.00	160.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00
15.	महाराष्ट्र	23.00	9.90	0.00	0.00	20.00		
16.	मणिपुर	75.00	75.00	0.00	0.00	40.00		
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18.	मिजोरम	61.00	61.00	50.00	50.00	40.00		
19.	नागालैंड	90.00	90.00	62.55	62.55	90.00	50.00	
20.	उड़ीसा	200	200.00	50.00	50.00	190.00	134.00	
21.	पुदुचेरी	5.00	3.37	0.00	0.00	5.00		
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
23.	राजस्थान	44.05	44.05	0.00	0.00	24.05	4.05	
24.	सिक्किम	30.00	30.00	0.00	0.00	34.98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	तमिलनाडु	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00		
26.	त्रिपुरा	40.00	40.00	47.35	47.35	24.00		
27.	उत्तर प्रदेश	250.00	250.00	288.57	288.57	88.00	88.00	
28.	उत्तराखंड	20.00	20.00	9.00	9.00	33.45		
29.	पश्चिम बंगाल	225.00	225.00	200.00	200.00	100.00	100.00	

विवरण-II(क)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाएं तथा पोस्ट हार्वेस्ट संचालन का विकास के अंतर्गत समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए जारी की गई धनराशि तथा उपयोगिता

(लाख रुपए)

क्रम. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	वित्तीय वर्ष						
		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10
		जारी	उपयोग की गई	जारी	उपयोग की गई	जारी	उपयोग की गई	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पश्चिम बंगाल	—	—	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2.	उड़ीसा	40.00	40.00	20.00	20.00	100.00	100.00	0.00
3.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	93.00	0.00
4.	तमिलनाडु	259.00	259.00	300.00	300.00	350.00	350.00	300.00
5.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	कर्नाटक	384.65	384.65	414.50	414.50	274.70	263.00	300.00
8.	गोवा	133.35	133.35	270.00	270.00	105.00	0.00	0.00
9.	महाराष्ट्र	300.00	300.00	450.00	450.00	200.00	200.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	गुजरात	400.00	400.00	200.00	200.00	326.60	0.00	0.00
11.	दमन और दीव	54.00	54.00	38.00	38.00	75.00	0.00	0.00
12.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	लक्षद्वीप	15.00	15.00	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	1586.00	1586.00	1830.35	1792.50	1626.30	1005.00	600.00

विवरण-II (ख)

समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाएं तथा पोस्ट हार्वेस्ट संचालन के विकास पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत ड्रेजर टीएसडी सिंधुराज के रख-रखाव सहित मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने वाले केन्द्रों के निर्माण के लिए जारी की गई धनराशि तथा उपयोगिता

(लाख रुपए)

क्रम. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	वित्तीय वर्ष						
		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10
		जारी	उपयोग की गई	जारी	उपयोग की गई	जारी	उपयोग की गई	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पश्चिम बंगाल	500.00	500.00	273.12	273.12	995.22	805.94	—
2.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	—
3.	आंध्र प्रदेश	91.34	91.34	—	—	—	—	—
4.	तमिलनाडु	119.48	119.48	56.14	56.14	200.00	—	—
5.	पुडुचेरी	999.00	999.00	1500.00	1404.00	907.50	741.21	—
6.	केरल	728.52	728.52	200.00	200.00	700.00	700.00	—
7.	कर्नाटक	8.70	8.70	—	—	—	—	102.00
8.	गोवा	75.00	75.00	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	3.48	—	—
10.	गुजरात	200.00	200.00	25.00	25.00	—	—	—
11.	दमन और दीव	—	—	—	—	22.50	—	—
12.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	—
13.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—
14.	केएसएमडीसीएल कोची (ड्रेजर टीएसडी सिंधुराज का रख-रखाव	21.00	21.00	55.79	55.79	226.93	226.93	—
	कुल	2743.04	2743.04	2110.05	2014.05	3055.63	2474.08	102.00

विवरण-II (ग)

समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाएं तथा पोस्ट हार्वेस्ट संचालन के विकास पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना के पोस्ट हार्वेस्ट बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण घटक के अंतर्गत जारी की गई धनराशि तथा उपयोगिता

क्रम सं.	राज्य/संगठन का नाम	2006-07	उपयोगिता	2007-08	उपयोगिता	2008-09	उपयोगिता	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अरुणाचल प्रदेश	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	हरियाणा (कृषि विपणन बोर्ड)	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	हिमाचल प्रदेश (सोसायटी)			0	0.00	25.00	0.00	0.00
4.	सुमन महिला विकास समिति, झारखंड	18.00	13.80	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	कर्नाटक मात्स्यिकी विकास निगम	74.00	74.00	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00
6.	महाराष्ट्र मात्स्यिकी विकास निगम	26.21	26.21	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	मिजोरम	32.50	31.16	0		0.00	0.00	0.00
8.	उड़ीसा	18.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00
9.	राजस्थान			15.00	10.51	0.00	0.00	0.00
10.	तमिलनाडु	50.00	28.25	26.25	0	0.00	0.00	0.00
11.	त्रिपुरा	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	फिशकॉपफेड	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	कैनारा आइस प्लांट, कर्नाटक			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	माल्पे मछुआरा प्राथमिक सहकारिता, कर्नाटक	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	सीसाईन आइस प्लांट, कर्नाटक	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मंगलौर ट्राल वोट सहकारिता समिति, कर्नाटक	22.48	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00
17.	मंगलौर यंत्रिका सहकारी संघ, कर्नाटक	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
18.	कर्नाटक सहकारी मात्स्यिकी परिसंघ	25.00	25.00	30.00	30.00	20.22	20.22	0.00
19.	एनसीडीसी	14.00	14.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20.	मत्स्य कन्या सहकारी समिति, औरंगाबाद	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	मत्स्यराज आइस प्लांट, माल्पे, कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	0.00
22.	दयालक्ष्मी आइस प्लांट, उदुपि, कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	विनायक आइस प्लांट, पंडुबेटु, कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00	0.00
24.	ज्वाइंट सेल्यूकॉम पीसीकल्चर सहकारी समिति, मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
25.	नागालैंड एग्री एंड हार्टि. प्रौडयूस मार्किटिंग सोसायटी, दीमापुर	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
26.	उत्तर कनारा जिला सहकारी मत्स्य विपणन लि., करवार, कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	कुल	470.38	362.77	179.12	123.38	186.22	101.22	0.00

विवरण-III

केन्द्रीय प्रायोजित योजना ''राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना'' के अंतर्गत जारी की गई तथा उपयोग की गई धनराशि

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	2006-07 के दौरान जारी की गई धनरशि	उपयोग की गई धनराशि	2007-08 के दौरान जारी की गई धनरशि	उपयोग की गई धनराशि	2008-09 के दौरान जारी की गई धनरशि	उपयोग की गई धनराशि	2009-10 के दौरान जारी की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	65.36	65.36	100.00	100.00	140.34	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	32.00	32.00	16.00	16.00	0	0	0
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4.	बिहार	60.79	60.79	43.14	29.05	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	21.02	21.02	0.00	0.00	3.38	0	0
6.	गोवा	15.00	15.00	8.00	0.00	2.15	0	6
7.	गुजरात	0.00	0.00	70.00	70.00	86.03	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	5.10	5.10	4.99	4.99	5.5	0	6.26
10.	जम्मू और कश्मीर	20.00	20.00	25.00	25.00	29.58	0	60
11.	झारखंड	258.40	258.40	327.20	327.20	123.6	0	0
12.	कर्नाटक	348.20	348.20	0.00	0.00	304.08	0	88.02
13.	केरल	162.96	162.96	150.00	150.00	232.21	0	214.54
14.	मध्य प्रदेश	33.82	33.82	21.20	21.20	31.46	0	0
15.	महाराष्ट्र	61.86	61.86	143.10	143.10	20	0	0
16.	मणिपुर	0.00	0.00	4.26	0.00	22.16	0	0
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
18.	मिजोरम	0.00	0.00	25.18	0.00	0	0	0
19.	नागालैंड	54.00	54.00	29.50	29.50	96.5	0	0
20.	उड़ीसा	39.92	39.92	50.00	50.00	89.64	0	0
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
22.	राजस्थान	31.36	31.36	11.98	3.36	5.40	0	0
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
24.	तमिलनाडु	300.00	300.00	269.93	269.93	240	0	26
25.	त्रिपुरा	24.00	24.00	24.00	24.00	36	0	0
26.	उत्तराखंड	0.00	0.00	8.60	8.60	6	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	350.00	350.00	165.50	165.50	200	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	241.20	241.20	243.20	243.20	361	0	60
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.48	1.48	1.37	1.37	1.68	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
35.	पुदुचेरी	150.00	150.00	126.00	126.00	150	0	0
36.	फिशकॉपफेड	104.35	104.35	131.65	131.65	192.82	0	0
37.	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	कुल	2380.82	2380.82	1999.80	1939.65	2380.18	0	474.82

विवरण–IV

केंद्र प्रायोजित योजना ''मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए डाटाबेस तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत जारी की गई तथा उपयोग की गई धनराशि

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2006–07 के दौरान जारी की गई धनराशि	2006–07 के दौरान उपयोग की गई धनराशि	2006–07 के दौरान जारी की गई धनराशि	2006–07 के दौरान उपयोग की गई धनराशि	2006–07 के दौरान जारी की गई धनराशि	2006–07 के दौरान उपयोग की गई धनराशि	2009–10 के दौरान जारी की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	9.55	9.34	12.72	12.72	11.30	15.29	0.00
2.	बिहार	0	0	0.44	0.44	6.00	0.17	0
3.	गोवा	4.00	4.62	6.41	3.43		0	5.00
4.	गुजरात	0	7.21	6.09	6.09	11.30	9.23	0.00
5.	हरियाणा	10.5	9.92	8.50	6.50	9.20	3.28	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	6.15	6.21	7.42	7.42	5.00	5.00	9.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	कर्नाटक	19.93	17.24	11.47	11.47	7.65	7.17	11.50
8.	केरल	0	0	0	0	0	17.45	0
9.	मध्य प्रदेश	0	22.95	0	0	0	14.72	0
10.	महाराष्ट्र	49.37	37.00	0	0	0	7.92	0
11.	उड़ीसा	0	0	0	0.00	0	0	0
12.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0
13.	राजस्थान	9.07	7.52	5.00	5.00	9.96	8.92	8.00
14.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0
15.	उत्तर प्रदेश	31.20	29.85	8.00	3.41	0.00	6.34	0
16.	पश्चिम बंगाल	6.00	7.82	6.15	4.10	9.30	6.62	0.00
17.	उत्तराखंड	14.00	0	0	0.00	0	14.00	0
18.	झारखंड	0	0	0	0	0.00	0	0
19.	छत्तीसगढ़	0.23	4.37	1.80	0.15	0.00	0	0
20.	अरुणाचल प्रदेश	7.45	7.67	10.20	10.20	10.00	0	0
21.	असम	0	10.08	8.30	0.00	0.00	0.00	0
22.	सिक्किम	0	0	5.30	0.00	0.00	2.50	0
23.	मणिपुर	0	0	0	0.00	0.00	0	0
24.	मेघालय	0	0.18	0	0.00	0	1.65	2.34
25.	मिजोरम	3.89	5.81	8.50	8.50	9.72	9.72	0
26.	नागालैंड	0	0	0.00	0	0	0	0
27.	त्रिपुरा	4.87	5.37	3.00	3.00	3.00	2.86	3.00
28.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0
30.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
31.	पुदुचेरी	4.50	0	0	0.00	0	4.49	5.00
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0.00	0	0
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
34.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
35.	सीआईएफआरआई	151.42	176.61	125.00	117.55	135.00	75.25	0.00
36.	एफएसआई	15.53	15.53	19.25	19.95	17.28	12.36	0
37.	सीएमएफआरआई	10.37	10.37	0	0	0	0.00	10.00
38.	अन्य		0	0	0	2.72	0.00	
39.	डीएएचडी मुख्यालय (कॉम.)	5.18	5.18	0	0	0	0	0
	कुल	363.21	400.85	254.25	219.93	247.43	224.94	53.89

विवरण-V

मछुआरों की संख्या, 2009

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मछुआरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	893365
2.	अरुणाचल प्रदेश	4399
3.	असम	390380
4.	बिहार	4959516
5.	छत्तीसगढ़	1911368
6.	गोवा	13970
7.	गुजरात	493255
8.	हरियाणा	16491
9.	हिमाचल प्रदेश	5622
10.	जम्मू और कश्मीर	30453
11.	झारखंड	1930920
12.	कर्नाटक	158952

1	2	3
13.	केरल	747837
14.	मध्य प्रदेश	716974
15.	महाराष्ट्र	171830
16.	मणिपुर	70468
17.	मेघालय	2383
18.	मिजोरम	17907
19.	नागालैंड	14862
20.	उड़ीसा	180026
21.	पंजाब	9085
22.	राजस्थान	7316
23.	सिक्किम	26814
24.	तमिलनाडु	476618
25.	त्रिपुरा	46733
26.	उत्तर प्रदेश	179064
27.	उत्तराखंड	90
28.	पश्चिम बंगाल	911622
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17552
30.	चंडीगढ़	479
31.	दादरा और नगर हवेली	0
32.	दमन और दीव	25485
33.	दिल्ली	2515
34.	लक्षद्वीप	13029
35.	पुदुचेरी	37974
	कुल	14485354

विवरण-VI

2005-06 से 2007-08 के दौरान मत्स्य उत्पादन

(टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	891090	856928	1010087
2.	अरुणाचल प्रदेश	2750	2770	2830
3.	असम	188010	181479	190320
4.	बिहार	279530	267040	319100
5.	गोवा	104950	102395	33428
6.	गुजरात	733820	747332	721907
7.	हरियाणा	48200	60080	67236
8.	हिमाचल प्रदेश	7295	6887	7851
9.	जम्मू और कश्मीर	19150	19200	17330
10.	कर्नाटक	297569	292463	297690
11.	केरल	636893	677629	667327
12.	मध्य प्रदेश	61077	65038	63893
13.	महाराष्ट्र	580540	595938	556447
14.	मणिपुर	18220	18614	18600
15.	मेघालय	4120	5487	4000
16.	मिजोरम	3750	3760	3760
17.	नागालैंड	5500	5800	5800
18.	उड़ीसा	325449	342040	349483

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	85640	86700	78730
20.	राजस्थान	18500	22200	25700
21.	सिक्किम	150	150	175
22.	तमिलनाडु	463028	542281	559356
23.	त्रिपुरा	23871	28634	36245
24.	उत्तर प्रदेश	289575	306728	325950
25.	पश्चिम बंगाल	1250005	1359103	1447262
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12096	28685	28685
27.	चंडीगढ़	87	173	214
28.	दादरा और नगर हवेली	48	48	48
29.	दमन और दीव	17788	16412	26358
30.	दिल्ली	700	610	610
31.	लक्षद्वीप	11964	11751	11042
32.	पुदुचेरी	21450	39668	39013
33.	छत्तीसगढ़	131752	137753	139373
34.	उत्तराखंड	2789	3003	3092
35.	झारखंड	34270	34270	67890
	कुल	6571626	6869049	7126832

चीनी के मूल्य में वृद्धि

2363. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, **खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने चीनी के तेजी से बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय पूल के विशेष कोटा से चीनी जारी करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और केन्द्रीय पूल से प्रत्येक राज्य को उपलब्ध कराई जाने वाली चीनी का वर्तमान कोटा कितना है तथा इसमें कितनी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) हाल ही में चीनी के तेजी से बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए चीनी का विशेष कोटा रिलीज करने के लिए किसी राज्य सरकार से हाल ही में कोई अनुरोध केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, वर्तमान चीनी मौसम 2008-09 के दौरान आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने लेवी चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया था। 2008-09 चीनी मौसम में चीनी के अपेक्षाकृत कम उत्पादन, जिसके फलस्वरूप लेवी चीनी की उपलब्धता कम है, को देखते हुए उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका। लेवी चीनी का राज्यवार मासिक कोटा और वार्षिक त्यौहार कोटा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वर्तमान में, बिहार और झारखंड को छोड़कर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को पूरा कोटा मुहैया कराया जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लेवी चीनी के कोटे को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यवार लेवी कोटा

(मीटरी टन)

क्रम सं.	राज्य	मासिक कोटा	वार्षिक कोटा	वार्षिक त्यौहार कोटा	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9690	116280	7614	123894
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	389	4668	74	4742

1	2	3	4	5	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	834	10008	94	10102
4.	असम	18337	220044	2896	222940
5.	बिहार	20516	246192	7527	253719
6.	चंडीगढ़	62	744	112	856
7.	दादरा और नगर हवेली	48	576	14	590
8.	दिल्ली	2610	31320	2316	33636
9.	गोवा	120	1440	150	1590
10.	दमन और दीव	11	132	12	144
11.	गुजरात	5841	70092	4878	74970
12.	हरियाणा	2485	29820	1924	31744
13.	हिमाचल प्रदेश	4698	56376	608	56984
14.	जम्मू और कश्मीर	6962	83544	868	84412
15.	कर्नाटक	8636	103632	5350	108982
16.	केरल	4103	49236	3600	52836
17.	लक्षद्वीप	115	1380	22	1402
18.	मध्य प्रदेश	12441	149292	5523	154815
19.	महाराष्ट्र	16792	201504	9014	210518
20.	मणिपुर	1763	21156	208	21364
21.	मेघालय	1704	20448	200	20648
22.	मिजोरम	666	7992	78	8070
23.	नागालैंड	1179	14148	128	14276
24.	उड़ीसा	8707	104484	3730	108214
25.	पुदुचेरी	243	2916	88	3004
26.	पंजाब	1385	16620	2392	19012
27.	राजस्थान	7342	88104	5092	93196
28.	सिक्किम	391	4692	50	4742
29.	तमिलनाडु	10820	129840	6790	136630
30.	त्रिपुरा	2647	31764	302	32066
31.	उत्तर प्रदेश	33013	396156	15154	411310
32.	पश्चिम बंगाल	14087	169044	7796	176840
33.	छत्तीसगढ़	4512	54144	2013	56157
34.	झारखंड	6948	83376	2551	85927
35.	उत्तराखंड	6033	72396	782	73178
	जोड़	216129	2593560	99950	26934210

[हिन्दी]

सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता

2364. श्री जयवंत गंगाराम आवले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सहकारी समितियों के सामने आ रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) इन कठिनाइयों से उबरने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) :

(क) से (ग) जी हां। सरकार को यह जानकारी है कि सहकारी संस्थाएं विशेषरूप से आत्मवलम्बी बनने में पर्याप्त संसाधनों को लामबंद करने और आर्थिक रूप से व्यवहार्य इकाइयों के रूप में कार्य करने में अपनी असमर्थता संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। इन कठिनाइयों का सामना करने और सहकारी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं-

(i) वैद्यनाथन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) के लिए एक सुधार पैकेज का अनुमोदन किया है। इस सुधार पैकेज में एसटीसीसीएस के पुनर्पूंजीकरण के लिए 13,597 करोड़ रुपये का परिव्यय परिकल्पित है।

अब तक 25 राज्यों ने भारत सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। दस राज्यों में 37599 पीएसीएस के पुर्नपूंजीकरण के लिए भारत सरकार के शेयर के रूप में नाबार्ड द्वारा अब तक 6072.71 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है जबकि राज्य सरकार ने अपने शेयर के रूप में 608.13 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए थे। राज्यों को निर्मुक्त की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ii) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम-सरकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर्गत देश में सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) को सहायता दी गई है। वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान एनसीयूआई और एनसीसीटी को क्रमशः 68.00 करोड़ रुपये, 32.25 करोड़ रुपये और 35.00 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए थे। समूचे देश में अपने सदस्य सहकारी संस्थाओं के संवर्धन और विकास के लिए छः राष्ट्रीय स्तर के संघों को भी वित्तीय सहायता दी जा रही है। इन संघों को वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान क्रमशः 1.25 करोड़ रुपये, 1.25 करोड़ रुपये और 1.00 करोड़ रुपये दिए गए।

(iii) भारत सरकार भी राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से अपने सहकारिता विकास कार्यक्रमों को कार्यनिवत करती है। एनसीडीसी के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम/स्कीम हैं- (i) चुने हुए जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजनाएं (ii) सहकारी रूप से कम विकसित/अल्प विकसित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सहकारी विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण कार्यक्रमों के लिए सहायता (iii) उत्पादक/बुनकर सहकारिता स्पिनिंग कारखानों में शेयर पूंजी सहभागिता। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से सहकारी संस्थाओं को राज्यवार वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य	पीएसीएस की सं.	कुल पुर्नः पंजीकृत सहायता	भारत सरकार का निर्मुक्त शेयर	राज्य सरकार का निर्मुक्त शेयर	सीसीएस शेयर
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	2,523	1953.01	1,575.11	213.26	164.64
छत्तीसगढ़	929	525.42	162.47	25.89	64.06
गुजरात	5702	372.49	325.20	27.20	20.09
हरियाणा	532	509.23	455.12	21.32	32.79

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	2,921	104501	888.13	63.29	93.59
महाराष्ट्र	12,998	1061.65	820.07	28.06	213.52
उड़ीसा	2,528	710.12	593.70	67.44	48.98
तमिलनाडु	2,819	1007.28	777.09	101.96	128.23
उत्तर प्रदेश	3,710	581.63	340.85	44.12	196.66
पश्चिम बंगाल	2,937	162.23	134.97	15.59	11.67
कुल	37,599	7655.07	6072.71	608.13	974.23

विवरण-II

राज्य	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (15.7.2009 तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	48010.69	29576.64	5839.39	551.39
असम	12.80	—	—	—
बिहार	998.85	344.45	575.44	37.56
गुजरात	33710.01	33091.89	18815.81	1546.32
हरियाणा	1554.39	1691.93	1114.28	0.89
हिमाचल प्रदेश	1408.60	814.42	618.47	41.46
जम्मू और कश्मीर	—	148.87	71.83	—
कर्नाटक	6572.54	707.09	1011.00	15.55
केरल	31059.81	33073.45	30869.56	99.86
मध्य प्रदेश	4643.65	4342.40	4490.43	—
महाराष्ट्र	19959.91	23177.27	33487.71	15684.99

1	2	3	4	5
मणिपुर	—	—	—	—
मेघालय	463.42	13.70	185.58	—
नागालैंड	152.15	96.99	217.09	754.30
उड़ीसा	20024.37	30040.70	36925.40	173.00
पंजाब	—	—	—	343.60
राजस्थान	4596.61	5321.77	6059.10	4.00
तमिलनाडु	31279.95	36745.34	3502.57	—
त्रिपुरा	43.29	—	—	—
उत्तर प्रदेश	31856.10	2004.14	23720.27	7.00
पश्चिम बंगाल	11595.94	11500.28	28015.56	3.27
झारखंड	882.32	840.98	11.25	—
उत्तराखंड	3222.13	718.17	2026.42	1.85
छत्तीसगढ़	55124.33	125026.43	9521.05	250.00
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.66	—	1350.00	—
अरुणाचल प्रदेश	—	310.49	17.81	—
मिजोरम	—	9.61	4.75	—
पुदुचेरी	3457.00	1495.47	—	—
गोवा	22.37	35.60	45.95	13.78
दमन और दीव	34.52	—	—	—
एएफसीओएसपीआईएन	1.12	—	—	—
नेफेड	30056.25	15078.00	50000.00	35075.00
इफ्को	60000.00	—	100000.00	—

1	2	3	4	5
एनसीसीएफ	112.50	—	—	—
विविध	181.52	135.75	194.60	1.95
कुल	401039.82	356341.83	358691.35	54605.77

पीएमजीपी के अंतर्गत राज्यों को आवंटित धनराशि

2365. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त धनराशि के आवंटन के लिए सरकार ने क्या मानदंड निर्धारित किए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) संघ सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) नामक उस समय विद्यमान रोजगार सृजन कार्यक्रमों का विलय कर वर्ष 2008-09 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज के लिए 250 करोड़ रुपये सहित कुल 4735 करोड़ रुपये की प्रस्तावित योजना परिव्यय सहित वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान लगभग 38 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने के लिए पूर्व के उपर्युक्त दो कार्यक्रमों की तुलना में उच्च स्तर की सब्सिडी वाला यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पीएमईजीपी खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक एकल नोडल अभिकरण के रूप में इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय है। राज्य स्तर पर, यह स्कीम केवीआईसी के राज्य निदेशालयों, राज्य/संघ राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

सरकार पीएमईजीपी के कार्यान्वयन हेतु (मार्जिन मनी सब्सिडी) निधियां सीधे राज्यों को जारी नहीं करती। सरकार केवीआईसी, जो कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक एकल नोडल अभिकरण है, जो निधियां जारी करती है, जो बाद में, बैंकों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों, नामत: केवीआईसी, राज्य निदेशालयों, केवीआईबी तथा जिला उद्योग केन्द्रों को निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित (अर्थात् 30:30:40 के अनुपात में) एक वर्ष के लिए निधियां जारी करता है। वर्ष 2008-09 और 2009-10 में आबंटित राज्य वार निधि (मार्जिन मनी सब्सिडी) संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पीएमईजीपी के तहत निधियों को वर्ष के लिए आबंटित राज्यवार लक्ष्यों के अनुसार जारी किया जाता है जो कि मानदंडों के निश्चित समुच्चय के आधार पर किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण जनसंख्या की सीमा, पिछड़ापन, शहरी बेरोजगारी के प्रचलन, दक्षता और कच्चे माल की उपलब्धता, आरईजीपी जैसी स्कीमों में विगत निष्पादन के आधार पर किया जाता है।

विवरण

वर्ष 2008-2009 तथा 2009-10 पीएमईजीपी के अधीन निर्धारित मार्जिन मनी

(लाख रुपयों)

क्र.सं.	राज्य/सं.रा. क्षेत्र	2008-09	2009-10
1	2	3	4
1.	छत्तीसगढ़	1736.78	1736.78
2.	मध्य प्रदेश	3695.85	4619.82
3.	उत्तराखंड	1162.25	641.59
4.	उत्तर प्रदेश	11768.96	11768.96

1	2	3	4
5.	संघ राज्य चंडीगढ़	59.94	59.94
6.	दिल्ली	285.51	899.10
7.	हरियाणा	1431.16	1431.16
8.	हिमाचल प्रदेश	452.14	452.14
9.	जम्मू और कश्मीर	1300.00	748.14
10.	पंजाब	1800.00	1608.02
11.	राजस्थान	3313.19	4011.54
12.	गोवा	86.59	86.59
13.	गुजरात	3460.98	3460.98
14.	दादरा और नगर हवेली	13.32	13.32
15.	दमन और दीव	13.32	13.32
16.	महाराष्ट्र	6628.91	6628.91
17.	आंध्र प्रदेश	5319.86	5319.86
18.	कर्नाटक	3571.24	3571.24
19.	केरल	2123.80	2123.80
20.	लक्षद्वीप	6.66	6.66
21.	पुदुचेरी	59.94	59.94
22.	तमिलनाडु	4220.23	4220.23
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	46.25	19.98
24.	बिहार	5152.18	6440.22
25.	झारखंड	2366.52	2366.52
26.	उड़ीसा	2946.68	2946.68
27.	पश्चिम बंगाल	6500.00	5513.74
28.	अरुणाचल प्रदेश	205.72	102.86
29.	असम	2050.54	2050.54
30.	मणिपुर	188.25	235.32
31.	मेघालय	483.96	241.98
32.	मिजोरम	238.28	119.14
33.	नागालैंड	430.68	215.35
34.	त्रिपुरा	472.12	236.06
35.	सिक्किम	125.80	62.90
	कुल योग	73717.61	74033.32

[अनुवाद]

पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण

2366. श्री आनंदराव अडसुल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस कार्मिकों को नागरिकों के साथ सभ्य और उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करने का कोई प्रशिक्षण प्रदान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) पुलिस राज्य का विषय होने के कारण, राज्य पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों की होती है। तथापि, भारत और विदेशों में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है। सुकुशलता, आचरण और मानवाधिकारों के विकास के लिए अपेक्षित मॉड्यूलों को पुलिसकार्मिकों के बुनियादी प्रशिक्षण के साथ-साथ सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पशुधन नीति

2367. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय पशुधन नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां तो इसकी मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पशुधन क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी अभियान शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पशुधन के लिए राष्ट्रीय नीति और प्रौद्योगिकी अभियान को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय पशुधन नीति विभिन्न राज्य विशिष्ट कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को सामान्य दिशानिर्देश उपलब्ध कराएंगे ताकि पशु उत्पादकता में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन के उद्देश्य से उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को शामिल करने, विपणन लिंकेज, विस्तार सेवाओं, संस्थानों की पुनर्संरचना और बढ़े हुए निवेश के संदर्भ में समर्थन तथा उसे बनाए रखने के लिए प्रभावी तंत्र की स्थापना से संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। प्रस्तावित राष्ट्रीय पशुधन नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(1) पशुधन में उत्पादकता को बढ़ाना और उत्पादकता में बाधा पहुंचाने वाली कमियों को दूर करना।

(2) पशु प्रोटीन की उपलब्धता को एक दशक के भीतर मौजूदा 10 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर 20 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करना।

(3) छोटी जोत प्रणालियों से संबंधित सामाजिक-आर्थिक समस्याओं में समझबूझ को सुधारना तथा छोटे खेत उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए उपयुक्त विस्तार मॉड्यूलों का विकास।

(4) पशुधन उत्पादों में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार के उद्देश्य से प्रत्येक पशुधन प्रजाति के लिए प्रजनन नीति तैयार करना।

(5) गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए समूची खाद्य श्रृंखला ने गुणवत्ता आश्वासन उपलब्ध कराना।

(6) प्राकृतिक आपदाओं और रोग प्रकोपों से संबंधित आकस्मिक योजना तैयार करना जिसमें उपयुक्त बीमा पैकेज भी शामिल होंगे।

(7) पशुचिकित्सा स्नातकों/सहायक स्टाफ तथा किसानों को प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के लिए शिक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करना।

(8) पशुओं की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए प्रमुख पशु रोगों का उन्मूलन और नियंत्रण तथा पशुधन और पशुधन उत्पादों की निर्यात क्षमता का दोहन।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय पशुधन नीति सक्रिय विचाराधीन है। अतः यह बताना संभव नहीं है कि इसे कब तक क्रियान्वित किया जा सकेगा।

जेल में बंद कैदी

2368. **श्रीमती जयाप्रदा** :
श्री नवजोत सिंह सिद्धू :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जेलों की संख्या राज्य-वार कितनी है और इनकी क्षमता कितनी है;

(ख) विभिन्न विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण कानूनों के अंतर्गत बंद अव्यस्कों सहित कैदियों की राज्य-वार संख्या अलग-अलग कितनी है;

(ग) उक्त कठोर अधिनियम के अंतर्गत अव्यस्कों को निरुद्ध किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा समेकित आंकड़े के अनुसार, 2007 के अंत तक देश में 1276 जेलें थीं जिनकी प्राधिकृत क्षमता 277304 कैदियों की थी। कारागारों में रखे गए कैदियों की कुल संख्या 376396 थी। जेलों की कुल संख्या, प्राधिकृत क्षमता एवं रखे गए कैदियों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) किसी अव्यस्क कैदी को कारागार में नहीं रखा जाता है। किशोर न्याय (बच्चे की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार, अव्यस्कों को मात्र सुधार गृहों/प्रेक्षा गृहों/तरुण गृहों में ही रखा जाता है, जिनका संचालन कारागार विभाग के सहयोग से संबंधित राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। मात्र 6 वर्षों से कम आयु के बच्चों को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से उनकी माता के साथ जेल में रखने की अनुमति है।

भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए कारागारों के पर्यवेक्षण एवं प्रबंध संबंधी आदर्श कारागार नियमावली में भी कारागारों में अव्यस्कों को रखने का प्रावधान नहीं है। इस नियमावली को इसके अनुपालन हेतु 31.12.2003 को समस्त राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित किया गया था। इसके बाद, समय-समय पर इससे संबंधित दिशा-निर्देश सभी राज्य सरकारों को जारी किए जाते हैं। कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं।

विवरण

31.12.2007 के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जेलों की संख्या, उपलब्ध क्षमता एवं बंदियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जेलों की कुल संख्या	उपलब्ध क्षमता	बंदियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	134	12710	15045
2.	अरुणाचल प्रदेश*	—	—	—
3.	असम	27	6357	8705
4.	बिहार	55	29598	39638
5.	छत्तीसगढ़	27	5407	10451
6.	गोवा	5	356	366
7.	गुजरात	24	6519	11842
8.	हरियाणा	18	10482	13093
9.	हिमाचल प्रदेश	13	1131	1435
10.	जम्मू और कश्मीर	12	3050	2299
11.	झारखंड	27	10738	17936
12.	कर्नाटक	99	12144	13052
13.	केरल	43	3765	6742
14.	मध्य प्रदेश	120	20448	32712
15.	महाराष्ट्र	153	20901	25892
16.	मणिपुर	2	970	444
17.	मेघालय	4	530	665
18.	मिजोरम	6	1163	941
19.	नागालैंड	10	1290	501
20.	उड़ीसा	70	10603	15368
21.	पंजाब	26	11742	15972
22.	राजस्थान	105	17554	14687
23.	सिक्किम	2	196	226
24.	तमिलनाडु	134	20321	16599

1	2	3	4	5
25.	त्रिपुरा	11	1065	1317
26.	उत्तर प्रदेश	61	37843	76180
27.	उत्तराखंड	9	2139	2709
28.	पश्चिम बंगाल	53	20222	18598
	कुल (राज्य)	1250	269244	363415
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	309	413
30.	चंडीगढ़	1	1000	501
31.	दादरा और नगर हवेली	1	60	28
32.	दमण और दीव	2	120	66
33.	दिल्ली	10	6250	11605
34.	लक्षद्वीप	4	16	22
35.	पुदुचेरी	4	305	346
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	26	8060	12981
	कुल (अखिल भारत)	1276	277304	376396

*जेलें मौजूद नहीं हैं।

[अनुवाद]

आदर्श रियायत समझौते में परिवर्तन

2369. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री नामा नागेश्वर राव :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान आदर्श रियायत समझौते (एमसीए) में परिवर्तन करने सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के चार लेनों को बनाओ-चलाओ और सौंपो की वार्षिकी प्रक्रिया अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो विद्यमान प्रणाली की तुलना में प्रस्तावित एमसीए के लाभ का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु धन की कमी

2370. श्री अधलराव पाटील शिवाजी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार राजमार्ग परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों से वित्त पोषण प्राप्त करने की योजना बना रही है; और

(ग) इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए शुरू की गई चालू सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए सामान्यत: निधियों की कोई कमी नहीं है तथापि, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना का विकास करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। इसके अलावा, एक नीति के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग चरण-III और उसके बाद के चरणों को मुख्यत: सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा। सरकारी नीति, सड़क क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करती है।

सिंचाई एवं बीज विकास

2371. श्री अधलराव पाटील शिवाजी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कृषि की बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों से सिंचाई एवं बीज विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से गेहूं, चावल तथा दालों हेतु विशेष कार्यक्रम बनाने को भी कहा है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई विस्तृत कार्य योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई अथवा प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में बीज उपलब्धता की लगातार समीक्षा की जाती है। प्रत्येक आने वाले कृषि मौसम के पहले आयोजित आचंलिक बीज समीक्षा बैठकों और राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय बीज योजना के अनुसार विभिन्न फसलों में अपेक्षित बीज प्रतिष्ठापन दर प्राप्त करने के लिए बीज उत्पादन में वृद्धि पर बार-बार जोर दिया जाता है। साथ ही भारत सरकार बीज से संबंधित कार्यकलापों के लिए विभिन्न स्कीमों के अधीन राज्यों को सहायता देती आ रही है।

जहां तक सिंचाई का संबंध है राज्यों से जल उपयोग सक्षमता और जल संरक्षण में सुधार लाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और लघु सतही सिंचाई स्कीम के अधीन वृहत्/मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों को ऋण सहायता और अनुदान दिए जाते हैं।

(ग) से (च) 11वीं योजना के अंत तक चावल, गेहूं और दलहन का उत्पादन क्रमश: 10 मिलियन टन, 8 मिलियन टन और 2 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए देश में खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद में यथा अंगीकृत संकल्प को ध्यान में रखते हुए 3 मुख्य घटकों अर्थात् एनएफएसएम-चावल, एनएफएसएम-गेहूं और एनएफएसएम-दलहन के साथ रबी 2007-08 से 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की गई है। जिला और राज्य स्तरों पर क्रमश: जिला स्तरीय कार्यकारी समिति और राज्य स्तरीय राज्य समिति द्वारा कार्य योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। राट्रीय स्तर पर राष्ट्र स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा राज्य कार्य योजना अनुमोदित की जाती है जो शीर्ष निकाय अर्थात् सामान्य परिषद का अनुमोदन मांगती है। वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान प्रदत्त केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति (करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	चावल निर्मुक्त	गेहूं निर्मुक्त	दलहन निर्मुक्त	प्रचार निर्मुक्त	निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	15.75	0	28.11	0.76	44.62
2.	असम	11.24	0	0	0.16	11.4
3.	बिहार	2.63	28.92	3.38	1.38	36.31
4.	छत्तीसगढ़	4.41	0	9.63	0.51	14.55
5.	गुजरात	0	4.8	2.26	0.31	7.37

1	2	3	4	5	6	7
6.	हरियाणा	0	18.37	2.15	0.62	21.14
7.	मध्य प्रदेश	2.42	0	5.11	0.34	7.87
8.	महाराष्ट्र	0	26.11	16.94	3.06	46.11
9.	उड़ीसा	0.87	3.97	8.58	0.72	14.14
10.	पंजाब	6.46	0	4.57	0.31	11.34
11.	राजस्थान	0	31.08	0.66	1.14	32.88
12.	सिक्किम	0	15.01	8.53	1.05	24.59
13.	तमिलनाडु	9.1	0	3.46	0.25	12.81
14.	उत्तर प्रदेश	0	70.79	8.41	4.59	83.79
15.	पश्चिम बंगाल	6.09	4.27	1.86	0.78	13
	कुल	58.97	203.32	103.65	15.98	381.92
16.	आईआईपीआर, कानपुर	0	0	1.06	0	1.06
17.	आईसीआरईएसएटी	0	0	0.88	0	0.88
18.	एनएससी (बीज मिनीकीट-गेहूं)	0	3.27	0	0	3.27
19.	एसएफसीआई (बीज मिनीकीट-गेहूं)	0	1.6	0	0	0.6
20.	विस्तार निदेशालय	0	0	0	10	10
	सकल योग	58.97	208.19	105.59	25.98	398.73

दिनांक 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2008-09 के लिए एनएफएसएम के अंतर्गत निधियों का आबंटन और निर्मुक्ति (करोड़ रुपए)

राज्य	चावल निर्मुक्त	गेहूं निर्मुक्त	दलहन निर्मुक्त	प्रचार-प्रसार निर्मुक्त	स्थानीय प्रयास			अन्य व्यय	कुल निर्मुक्ति
					चावल निर्मुक्त	गेहूं निर्मुक्त	दलहन निर्मुक्त		
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
आंध्र प्रदेश	1719.648	0.000	4816.518	100.000	694.969	0.000	1082.813	0.000	8413.948

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
असम	2377.650	0.000	0.000	20.000	308.000	0.000	0.000	0.000	2705.650
बिहार	2941.470	1644.360	1245.050	0.000	758.340	758.330	758.330	0.000	8105.880
छत्तीसगढ़	2710.220	0.000	4075.182	0.000	189.500	0.000	189.500	0.000	7164.402
गुजरात	141.320	109.062	169.504	10.000	134.330	134.330	134.340	0.000	832.886
हरियाणा	0.000	535.380	0.000	0.000	0.000	494.000	75.000	0.000	1104.380
झारखंड	831.912	0.000	0.000	30.000	118.500	0.000	0.000	0.000	980.412
कर्नाटक	1299.200	0.000	717.740	50.000	474.000	0.000	474.000	0.000	3014.940
केरल	188.850	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	188.850
मध्य प्रदेश	989.152	2191.311	1978.296	0.000	426.500	426.500	426.500	0.000	6438.259
महाराष्ट्र	978.940	1407.640	3282.895	125.000	474.000	474.000	474.000	0.000	7216.475
उड़ीसा	2764.180	0.000	2204.373	70.000	800.100	0.000	384.900	0.000	6223.533
पंजाब	0.000	3035.367	0.000	0.000	0.000	355.500	177.750	0.000	3568.617
राजस्थान	0.000	658.562	0.000	75.000	0.000	437.468	711.000	0.000	1882.030
तमिलनाडु	2897.537	0.000	0.000	50.000	201.500	0.000	201.500	0.000	3350.537
उत्तर प्रदेश	3873.596	8345.052	1454.231	0.000	615.830	615.830	615.840	0.000	15520.379
पश्चिम बंगाल	4618.980	86.120	1228.534	0.000	134.330	134.330	134.340	0.000	6336.634
कुल	28332.635	18012.854	21172.323	530.000	5329.899	3830.288	6839.813	0.000	83047.812
एनपीसी								62.969	62.969
आईआईपीआर, कानपुर	0.000	0.000	315.140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	315.140
आईसीआरईएसएटी	0.000	0.000	161.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	161.200
	0.000		238.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	238.000
एनएससी (बीज मिनीकीट)	59.520	682.648	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	742.168

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
एसएफसीआई (बीज मिनीकीट)	127.318	683.288	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	810.606
एसएफसीआई (बीज मिनीकीट)	13.908	14.446	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	28.354
दलहन बीज उत्पादन के लिए एसएफसीआई	0.000	0.000	1000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1000.000
केन्द्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार	0.000	0.000	0.000	1793.970	0.000	0.000	0.000	0.000	1793.970
केन्द्रीय स्तर पर अन्य व्यय	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125.967	125.967
सकल योग	28533.381	19393.236	22886.663	2323.970	5329.899	3830.288	5839.813	188.938	88326.186

02-07-2009 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान एनएफएसएम के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्ति
(करोड़ रुपए में)

क्र सं.	राज्य	चावल निर्मुक्त राशि	गेहूं निर्मुक्त राशि	दलहन निर्मुक्त राशि	प्रचार निर्मुक्त राशि	कुल निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	28.990		64.920		93.910
2.	बिहार			18.340		18.340
3.	छत्तीसगढ़	20.660				20.660
4.	हरियाणा			7.380		7.380
5.	झारखण्ड	4.680				4.680
6.	कर्नाटक	1.340		28.850		30.190
7.	केरल	2.780				2.780
8.	मध्य प्रदेश			27.330		27.330
9.	महाराष्ट्र	12.210		43.790		56.000
10.	उड़ीसा	22.730		11.930		34.660

1	2	3	4	5	6	7
11.	राजस्थान			8.330		8.330
12.	तमिलनाडु	5.880		9.640		15.520
13.	उत्तर प्रदेश	9.800		49.190		58.990
	कुल	109.070		269.700		378.770

नयी राष्ट्रीय खनिज नीति की समीक्षा

2372. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से नयी राष्ट्रीय खनिज नीति की समीक्षा करने का अनुरोध किया है जैसाकि प्रस्तावित नीति खनिज उत्पादक राज्यों के अधिकार को सीमित करती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन पर अंतिम निर्णय लेने से पहले केंद्र सरकार से उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करने के लिए विशेष कार्यबल के गठन का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) और (ख) सरकार को कुछ राज्य सरकारों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ खनिज रियायतें प्रदान करने में राज्य सरकार को मूल्यवर्धन को तरजीह देने हेतु स्वीकृति देने की आवश्यकता, निर्बाध अंतरण संबंधी नीति, पट्टा अवधि की सुरक्षा, खनिज रियायतें प्रदान करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को तरजीह देने हेतु स्वीकृति तथा मूल्यानुसार आधार पर रायल्टी की वसूली करने के संबंध में चिंता व्यक्त की गई थी। राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 की घोषणा करने से पहले सरकार द्वारा इन मुद्दों पर विचार करके इनका उचित समाधान किया गया था।

(ग) और (घ) नई खनिज नीति में घोषित नीतिगत दिशानिर्देशों तथा प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करके गठित किए गए टास्क फोर्स के साथ विचार-विमर्श के आधार पर सरकार, खनन कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

फसलों में कीटनाशक अवशेष

2373. **श्रीमती मेनका गांधी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कीटनाशकों की उच्च खपत दर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कुल घरेलू उत्पादन की तुलना में खपत की कितनी प्रतिशत है एवं देश में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली कीटनाशक कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या विश्व में अन्यत्र पाए जाने वाले स्तर की तुलना में भारतीय फसलों में पाए जाने वाले कीटनाशकों के अवशेष का स्तर अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के कदमों सहित इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत में कीटनाशी की खपत 280 ग्राम प्रति हैक्टेयर अनुमानित है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.5 से 3.0 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर और जापान में 10 से 12 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर है। देश में वर्ष 2007-08 के दौरान कीटनाशियों की खपत 43.630 मीट्रिक टन थी जो कि 79.756 मीट्रिक टन के घरेलू उत्पादन का 54.70 प्रतिशत थी। देश में सामान्य रूप से सर्वाधिक प्रयुक्त कीटनाशी सल्फर, एन्डोसल्फन और फोरेट हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में (2003) कीटनाशी अवशेषों वाले 31 प्रतिशत नमूना और यूरोपीय संघ (2006) में कीटनाशी अवशेषों वाले 41 प्रतिशत नमूनों की तुलना में भारत में वर्ष 2007-08 के दौरान विश्लेषित विभिन्न जिन्सों के 8.6 प्रतिशत नमूनों में कीटनाशी अवशेष की उपस्थिति दर्शाता है। भारत सरकार अनुमोदित कीटनाशियों के सुरक्षिम, उचित और आवश्यकता आधारित प्रयोग और अन्य कीट प्रबंधन पद्धतियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए किसान फील्ड स्कूलों के माध्यम से समेकित कीट प्रबंधन (आइपीएम) को बढ़ावा दे रही है।

आदिवासी भू-स्वामी को रायल्टी

2374. **श्री पी. बलराम :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन के लिए भूमि अधिगृहीत किए जाने के बाद आदिवासी भूस्वामी खनन या खनिज के दोहन पर रायल्टी प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) और (ख) भारत के संघीय ढांचे में, राज्य सरकारें संबंधि राज्य की सीमा में अवस्थित खनिजों की मालिक होती हैं। रायल्टी, खनिज संसाधनों के विदोहन के प्रतिफल स्वरूप, खनिजों के मालिकों को, खनन पट्टाधारक द्वारा किया गया भुगतान है। खनिजों (गौण खनिज, कोयला, लिग्नाइट और भराई हेतु बालू को छोड़कर) की रायल्टी दरें भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं और खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अनुसार, पट्टा क्षेत्र से उपभोग किए गए अथवा हटाए गए खनिजों पर लगाई जाती हैं। यदि खनिजों का निष्कर्षण नहीं किया जा रहा हो तो इस धारा में खनन पट्टे में शामिल क्षेत्र के लिए डैड रेंट लगाए जाने का भी प्रावधान है। रायल्टी भूमि के स्वामी को देय नहीं होती है।

पशुधन और मत्स्य पालन पर जलवायु परिवर्तन

2375. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पशुपालन और मत्स्य पालन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने निम्नलिखित ब्यौरे दिए हैं:

I. **पशुधन**

(i) विभिन्न उत्पादन प्रणालियों के तहत पशुधन से उत्सर्जित मीथेन का मूल्यांकन करने तथा मीथेन उत्पादन के संबंध में डाटाबेस विकसित करने और मीथेन उत्पादन को न्यूनतम करने के लिए पौषणिक/जैव-प्रौद्योगिकीय रणनीति विकसित करने के लिए 8 सहयोगी केन्द्रों के साथ मिलकर पहले से ही वर्ष 2008-09 में मीथेन उत्सर्जन संबंधी आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ii) विभिन्न पशुधन प्रजातियों पर जलवायु बदलाव के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथा शेल्टर प्रबंधन के जरिए पशुधन के अनुकूलन के लिए रणनीति विकसित करने के लिए वर्ष 2009-10 में 8 सहयोगी केन्द्रों के साथ शेल्टर प्रबंधन के जरिए सन्निकट जलवायु बदलाव के लिए पशुधन के अनुकूलन संबंधी नेटवर्क परियोजना पहले ही शुरू कर दी गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पशु उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागत प्रभावी शेल्टरों को उपलब्ध कराकर ताप के दबाव को कम करना है।

II. **मात्स्यिकी**

समुद्र क्षेत्र

(i) समुद्री मछलियां जैसे आयल सरडाइन तथा भारतीय मैकरील उत्तरी अक्षांश की ओर वितरण को बढ़ाकर तथा गहराई की ओर फैलकर समुद्र की सतह के तानमान में हुई वृद्धि को अपनाने के योग्य हुई हैं।

ये मछलियां पहले केरल तथा कर्नाटक तक सीमित थीं, अब महाराष्ट्र तथा गुजरात में भी पाई जाती हैं।

(ii) थ्रेडफिन ब्रीम्स जैसी मछलियों ने अपने अंडे देने के मौसम को ठंडे महीनों में बदल दिया है।

(iii) प्लवक एव्यूडेंस ठंडे महीनों की ओर बदली है।

(iv) समुद्र तटीय राज्यों के मछुआरा गांवों में उपलब्ध जनसांख्यिक ब्यौरे बुनियादी ढांचों के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं। भारतीय तट के साथ-साथ लगभग 2643 मछुआरा गांव हैं, जिनमें से 458 गांव ज्वार से 100 मीटर की दूरी के भीतर हैं, इनमें से अधिकांश केरल (लगभग 200) में हैं।

अंतर्देशीय मात्स्यिकी

(i) तीन नदी प्रणालियों, गंगा, महानदी तथा ब्राह्मणी में अंतर्देशीय मात्स्यिकी संसाधनों पर जलवायु बदलाव के प्रभाव का मूल्यांकन।

(ii) भारतीय प्रमुख कार्पों का प्रजनन, जोकि मानसून (जून-जुलाई) के दौरान होता है और सितम्बर तक बढ़ जाता है, उसे पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में पहले ही मार्च में परिपक्व होते तथा अंडा देते देखा गया है।

मूंगफली गिरी की गुणवत्ता

2376. श्री वरुण गांधी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मूंगफली की गिरी का उपज में एफ्लोटाक्सिन सहित कीटनाशक के अवशेषों की अधिक मात्रा पाई गई है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय मूंगफली की गिरी की खेप को यूरोपियन यूनियन द्वारा कीटनाशकों के अधिक अवशेषों के कारण लौटा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में कीटनाशक मुक्त मूंगफली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तथा इसकी निर्यात सम्भाव्यता को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) देश में उत्पादित मूंगफली की गिरी में एफ्लोटाक्सिन सहित अधिक मात्रा में कृमिनाशी अवशेषों के होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

(ग) और (घ) अधिक कृमिनाशी अवशेषों के कारण यूरोपीय संघ द्वारा भारतीय मूंगफली की गिरी के अस्वीकरण की सूचना नहीं दी गई है।

(ङ) भारत सरकार अनुमोदित कृमिनाशियों के सुरक्षित, उचित और आवश्यकता आधारित उपयोग पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कृषक फील्ड स्कूलों के जरिए समेकित कृमि प्रबंधन तथा अन्य कृमि प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा दे रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (अपेडा) ने यूरोपीय संघ को मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात हेतु एफ्लोटाक्सिन के नियंत्रण पर विनियम सहित मूंगफली की गुणवत्ता में सुधार करने के उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

झारखंड में कृषि योग्य भूमि

2377. श्री अर्जुन मुंडा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है तथा राज्य में अकृषित भूमि की तुलना में इसकी प्रतिशतता क्या है;

(ख) इस भूमि का बहुउद्देश्यीय उपयोग करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) झारखंड राज्य में कुल कृषि की गई भूमि, जिसमें बुआई की गई एवं वर्तमान परती भूमि निहित हैं, की प्रतिशतता प्रतिवेदित क्षेत्र का 38% है जबकि अकृष्य भूमि की प्रतिशतता 62% है। झारखंड में वर्ष 2006-07 के लिए कृषि के तहत लाई गई भूमि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(हजार हैक्टेयर में क्षेत्र)

भूमि उपयोग सांख्यिकी के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र	वर्तमान परती भूमि	बोया गया निवल क्षेत्र	खेती की गई भूमि	**प्रतिवेदित** क्षेत्र में खेती की गई भूमि की प्रतिशतता	खेती न की गई भूमि	**प्रतिवेदित** क्षेत्र में खेती न की गई भूमि की प्रतिशतता
7970	1244	1769	3013	38	4957	62

(ख) और (ग) झारखंड राज्य में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के विकास के लिए, वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलसम्भर विकास परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को 2000 से कृषि योजना की वृहत प्रबंधन के तहत शामिल किया गया है। कृषि उत्पादकता में सुधार करने के लिए योजना के तहत भू एवं जल संरक्षण संबंधी उपाय किए गए हैं। 10वीं योजना अंत तक, योजना के तहत 50.20 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करके 1.09 लाख हैक्टेयर भूमि का विकास किया गया है। 11वीं योजना में, 94 जलाशयों में कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें 60,550 हैक्टेयर भूमि को समाश्रित किया गया है। 11वीं योजना के पहले 2 वर्षों में, 7258 हैक्टेयर भूमि का विकास किया गया है जिसमें 8.71 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

[अनुवाद]

पशुधन बीमा योजना

2378. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पशुधन बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि संबंधी स्थायी समिति (2007-08) ने अपने 35वें प्रतिवेदन की सिफारिश में इस विषय पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां।

(ख) गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही पशुधन बीमा योजना के दो उद्देश्य हैं। ये हैं: किसानों तथा गोपशु पालकों को उनके पशुओं की मृत्यु के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिए संरक्षण तंत्र उपलब्ध कराना तथा लोगों को पशुधन बीमा के लाभों को बताना और पशुधन एवं उनके उत्पादों में गुणात्मक सुधार पाने के अंतिम लक्ष्य के साथ इसे लोकप्रिय बनाना है।

योजना के अंतर्गत, वर्ण संकरित तथा उच्च उत्पादक गोपशु तथा भैंसों का उनकी अधिकतम मौजूदा कीमत पर बीमा किया जाता है। बीमा का केवल 50% प्रीमियम लाभार्थी द्वारा दिया जाता है।

यह योजना देश भर के 100 चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान क्रियान्वित की गई थी। वर्ष 2007-08 के लिए, यह योजना इसी प्रारूप में इन्हीं 100 जिलों में जारी रही। पशुधन बीमा से संबंधित एक पूर्ण योजना, जिसे 20.11.2008 को अनुमोदित किया गया था, उसे 100 नए चुने हुए जिलों में नियमित आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। 2008-09 तक, 12,82,904 पशुओं का बीमा किया गया है।

(ग) और (घ) कृषि संबंधी स्थायी समिति ने "पशुधन बीमा" विषय पर चर्चा की तथा शुरू में अपनी 29वीं रिपोर्ट में सिफारिश की। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर, समिति ने अपनी 35वीं रिपोर्ट में आगे और टिप्पणी की। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा 35वीं रिपोर्ट पर दिया गया अगला उत्तर संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सीसीईए ने पशुधन बीमा योजना के पायलट आधार पर 2007-08 के दौरान उसी फार्मे में तथा उन्हीं जिलों में जारी रखने के लिए

13 सितम्बर, 2007 को अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जहां कि यह 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान क्रियान्वित की गई थी। यह योजना देश भर के 100 चुनिंदा जिलों में पूरी तरह से चल रही है। योजना के उद्देश्य से वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान पायलट योजना के क्रियान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद को चालू वर्ष के दौरान एक मूल्यांकन अध्ययन दिया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों तथा सुझावों के आधार पर, वर्ष 2008-09 तथा उससे आगे भी पूरे देश में और पशुधन की अन्य प्रजातियों के लिए योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। वर्ष 2008-09 के दौरान और उससे आगे भी पूरे देश में इसके क्रियान्वयन के लिए नया प्रस्ताव करते समय, राजसहायता के संबंध में संसदीय स्थायी समिति के विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

भारत में चीन के अवैध कामगार

2379. श्री एल. राजगोपाल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का दौरा करने के लिए काफी बड़ी संख्या में चीन के नागरिकों को व्यवसाय वीजा जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपनी वीजा शर्तों का उल्लंघन करते हुए देश में अवैध रूप से अर्द्ध-कुशल और तकनीकी काम करने वाले इस प्रकार के चीन के नागरिकों की संख्या बढ़ने की रिपोर्ट मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चीन स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा जारी किए गए व्यवसाय वीजाओं की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	जारी किए गए व्यवसाय वीजा
1	2
2007	58406
2008	69084
2009 (30.6.2009 तक)	32700

(ग) और (घ) इस मंत्रालय की जानकारी में आया है कि अर्धकुशल श्रमिकों सहित बड़ी संख्या में चीनी श्रमिक भारत में विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित/निष्पादित करने के लिए व्यवसाय वीजा पर आए हैं। इस मामले की जांच की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि परियोजनाओं/ठेकों को निष्पादित करने हेतु आने वाले चीनी नागरिकों सहित विदेशी नागरिक रोजगार वीजा पर आने के लिए योग्य होंगे। रोजगार वीजा को वीजा नियमावली में निहित प्रावधानों के सख्त अनुपालन में जारी किया जाएगा।

[हिन्दी]

सूखा प्रभावित क्षेत्रों हेतु सिंचाई

2380. श्री घनश्याम अनुरागी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मानसून की कमी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र सहित देश में बुआई के मौसम में कृषकों की सहायता करने और फसल बचाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय मानसून की मंद प्रगति की स्थिति में बैठकों, वीडियों सम्मेलनों के जरिए राज्यों में खरीफ बुआई प्रगति का निकट से मानीटरन कर रहा है। राज्य वार वैकल्पिक कार्यनीतियां तैयार की गई हैं और तदनुसार राज्यों को कम वर्षा की स्थिति में खासकर बीज की अतिरिक्त मात्रा की खरीद और वितरण, लघु सिंचाई हेतु सहायता आदि के लिए आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार की स्कीम की निधियों के उपयोग में लचीलापन प्रदान किया गया है।

इसके अलावा भू-संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम के अधीन तथा एनआरईजीए के अधीन निधियां उपलब्ध हैं जिनका उपयोग स्थानीय जल संसाधनों की वृद्धि में किया जाता है।

कम वर्षा की स्थिति में कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय ने उपलब्ध जल के कुशल उपयोग हेतु राज्य सरकारों को सलाह जारी की है। इस संबंध में राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे उपलब्ध वर्षा के अनुकूल उपयोग हेतु वैकल्पिक कार्यनीतियों के नियोजन और कार्यान्वयन में केवीके, कृषि विश्वविद्यालय की तकनीकी सहायता तथा आईसीएआर के वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना का उपयोग करें।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेल के लिए परियोजनाओं की धीमी प्रगति

2381. श्री निशिकांत दुबे : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए कई खेल अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य को पूरा करने में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सभी परियोजनाओं के समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस खेल के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण/कोचिंग देने के लिए कोई योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस संबंध में इस क्षेत्र में कार्य करने वाली कुछ स्वयंसेवी एसोसिएशनों/संस्थाओं को भी शामिल किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी एसोसिएशनों/संस्थाओं को कितनी राशि आबंटित की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल) : (क) से (ग) जी नहीं। खेल अवसंरचना कार्य तेजी से चल रहा है तथा खेलों के लिए समय से पूरा हो जाएगा। खेल अवसंरचना सहित राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित विभिन्न मामलों की प्रगति की समीक्षा के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री सभी संबंधितों के साथ नियमित रूप से समन्वय बैठकें आयोजित करते हैं। कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए एक वेब आधारित निगरानी तंत्र भी तैयार किया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। राष्ट्रतंडल खेल, 2010 में भारतीय दल के प्रदर्शन को सुधारने के लिए 678 करोड़ रुपए (2008-09 से 2010-11 हेतु) के आबंटन के साथ एक स्कीम 'राष्ट्रमंडल खेल, 2010 हेतु भारतीय टीम की तैयारी'' जुलाई, 2008 से कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की सभी खेल विधाओं के विशिष्ट खिलाड़ियों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण, विदेश में प्रदर्शन के अवसर, वैज्ञानिक समर्थन आदि प्रदान किया जाता है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

बायोमीट्रिक विशिष्ट पहचान पत्र

2382. श्री पी. लिंगम :
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी :
श्री गुरूदास दासगुप्त :
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :
श्री नामा नागेश्वर राय :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री राकेश सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी नागरिकों को बायोमीट्रिक विशिष्ट पहचान-पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका प्रयोजन क्या है एवं इस प्रकार के पहचान-पत्रों के माध्यम से क्या उपयोगिता फायदा होगा;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने परियोजना के सफल तथा दोषरहित कार्यान्वयन के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना में उपयोग में लाये जाने वाले आंकड़ों का स्रोत क्या है तथा क्या इसके लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (च) बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र संबंधी प्रायोगिक परियोजना का 12 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, और पुडुचेरी के चयनित क्षेत्रों में कार्यान्वियन किया गया है। इस परियोजना के तहत 28.62 लाख व्यक्तियों को डाटाबेस तैयार किया गया है। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 12.88 लाख पहचान (स्मार्ट) पत्र जारी किए गए हैं और शेष को राष्ट्रीय पहचान संख्यांक दिया गया है। प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य 31.03.2009 को समाप्त हो चुका है।

प्रायोगिक परियोजना के अनुभव के आधार पर सरकार ने 2011 की जनगणना के साथ देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का प्रस्ताव किया है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की फोटो और उनकी अंगुली की छाप के साथ प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं संबंधी ब्यौरे एकत्रित किए जाएंगे। तथापि, 9 समुद्री राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और 4 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और पुडुचेरी के तटीय गांवों के संबंध में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का कार्य 2009-10 के दौरान किया जाएगा। यह निर्णय 26/11 की घटना के बाद तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से लिया गया है। प्रथम चरण में 3331 तटीय गांवों को कवर करने की योजना को अनुमोदित किया गया है। नगरों/शहरों सहित शेष तटीय क्षेत्रों को 2011 की जनगणना के साथ कवर किया जाएगा।

तटीय क्षेत्रों की योजना के अंतर्गत 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों को पहचान पत्र दिए जाने की योजना है। तथापि, देश के शेष हिस्सों में सामान्य निवासियों को पहचान (स्मार्ट) पत्र जारी करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकार ने विशिष्ट पहचान पत्र योजना की देखरेख के लिए एक अधिकार प्राप्त समूह के गठन का प्रस्ताव किया है। समूह के संघटन की जानकारी इसके औपचारिक गठन के बाद ही प्राप्त हो सकेगी।

[हिन्दी]

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

2383. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा इनका ब्यौरा एवं स्थिति क्या है;

(ख) कितने राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत की जाएगी तथा इनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए राज्य-वार विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या और उनकी कुल लंबाई का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और तदनुसार, देश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंदर, यातायात घनत्व और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) और (घ) नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। संसाधनों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए इस समय और सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बजाए पहले से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित सड़कों के विकास पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के आवधिक नवीकरण के लिए वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक

प्राथमिकता के अनुसार ये प्रस्ताव, संस्वीकृतियों के विभिन्न चरणों में हैं। वर्ष 2009-10 में, बाढ़ क्षति मरम्मत कार्यों के लिए प्राक्कलनों की संस्वीकृति के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, वर्षा/बाढ़ आदि के कारण क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों की बहाली के लिए आवश्यक अस्थायी उपाय प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या और उनकी कुल लंबाई (किमी.) का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कुल लंबाई (किमी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 18, 43, 63, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221, 222 और 234	4,537
2.	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए, 153, 229, 52बी विस्तार. और 37 विस्तार.	1,992
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153, और 154	2,836
4.	बिहार	2, 2C, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, and 110	3,642
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 202, 216, 217, 111, और 221	2,184
7.	दिल्ली	1, 2, 8, 10 और 24	72
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	269
9.	गुजरात	एनई-I, 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 59, 113 और 228	3,245
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 72, 73, 73ए, 71बी और एनई-II	1,512
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 20ए, 21, 21ए, 22, 70, 72, 72बी, 88 और 73ए	1,409
12.	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी, 1सी और 1डी	1,245
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100	1,805
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212, 218 और 234	4,396
15.	केरल	17, 47, 47ए, 47सी, 49, 208, 212, 213 और 220	1,457

1	2	3	4
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 27, 59, 59ए, 69, 75, 76, 78, 86 और 92	4,670
17.	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204, 211 और 222	4,176
18.	मणिपुर	39, 53, 150 और 155	959
19.	मेघालय	40, 44, 51 और 62	810
20.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	927
21.	नागालैंड	36, 39, 61, 150 और 155	494
22.	उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224	3,704
23.	पुदुचेरी	45ए और 66	53
24.	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1,557
25.	राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 11बी, 11सी, 12, 14, 15, 65, 71बी, 76, 79, 79ए, 89, 90, 113, 112, 114 और 116	5,585
26.	सिक्किम	21ए,	62
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226, 226ई, 227, 230 और 234	4,832
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए	400
29.	उत्तराखंड	58, 72, 72ए, 72बी, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 123, 119, 121, 87 विस्तार और 125	2,042
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 24बी, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93, 96, 97, 119, 231, 232, 232ए, 233, 235 और एनई-II	6,774
31.	पश्चिम बंगाल	2,2बी, 2बी विस्तार, 6, 31, 31ए, 31सी, 31डी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81, और 117	2,578
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	223	300
		जोड़	70,548

विवरण-II

25.2.2004 के बाद नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावों की कुल संख्या	लंबाई किमी.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	22	6192.35
2.	असम	1	250
3.	बिहार	1	—
4.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	240
5.	गुजरात	19	3806.00
6.	हरियाणा	4	63.00
7.	हिमाचल प्रदेश	11	1793.50
8.	झारखंड	1	310
9.	कर्नाटक	28	7020
10.	केरल	1	164
11.	महाराष्ट्र	3	1190.87
12.	मेघालय	2	442
13.	मणिपुर	1	163
14.	मिजोरम	1	179
15.	मध्य प्रदेश	1	217.76
16.	नागालैंड	3	725
17.	उड़ीसा	13	1584.87
18.	पुदुचेरी	5	—
19.	पंजाब	3	2480
20.	राजस्थान	34	4673
21.	सिक्किम	4	—
22.	तमिलनाडु	7	753.20
23.	त्रिपुरा	1	310
24.	उत्तर प्रदेश	11	1291.065
25.	उत्तराखंड	3	773
26.	पश्चिम बंगाल	1	102

विवरण-III

राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के आवधिक नवीकरण के लिए 2009-10 के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवधिक नवीकरण प्रस्तावों की अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	3.54
2.	असम	63.63
3.	चंडीगढ़	0.56
4.	छत्तीसगढ़	40.94

1	2	3
5.	गुजरात	20.40
6.	हरियाणा	10.95
7.	हिमाचल प्रदेश	25.47
8.	कर्नाटक	21.00
9.	केरल	28.00
10.	मणिपुर	4.15
11.	मेघालय	25.11
12.	मिजोरम	8.25
13.	नागालैंड	6.38
14.	उड़ीसा	51.80
15.	पुदुचेरी	0.52
16.	पंजाब	19.61
17.	राजस्थान	70.58
18.	उत्तर प्रदेश	59.62
19.	उत्तराखंड	12.43
20.	पश्चिम बंगाल	12.25

[अनुवाद]

सीमा सुरक्षा बल में भर्ती

2384. श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमा सुरक्षा बल में भर्ती में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए किसी वार्षिक भर्ती योजना को अंतिम रूप दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सीमा सुरक्षा बल में वर्तमान में कितनी बटालियन हैं तथा उक्त भर्ती के बाद अनुमानित कितनी बटालियन बढ़ाए जाने की संभावना है;

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमा सुरक्षा बल के कितने कार्मिक सेवानिवृत्त हुए; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान इन रिक्त पदों को भरने हेतु कितने कार्मिक भर्ती किए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों में यू.पी.एस.सी, एस.एस.सी. और बल भर्ती बोर्डों की सहायता से भर्ती किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है तथा वर्ष 2009 के लिए भर्ती योजना को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है। विभिन्न बलों में भर्ती वर्ष भर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। भर्ती की आवश्यकता मुख्यत: विस्तार के बाद नए पदों की मंजूरियों के फलस्वरूप तथा सेवानिवृति, त्याग पत्र इत्यादि के कारण रिक्तियों को भरने के लिए होती है।

(ङ) वर्तमान में बी.एस.एफ. की 155 बटालियने (जीडी ड्यूटी पैटर्न) और 02 बटालियने (एन.डी.आर.एफ-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल पैटर्न) है। 29 बटालियने चरण-वार बनाई जानी है।

(च) ब्यौरे निम्नानुसार है:

वर्ष	अधिवर्षिता स्वैच्छिक सेवा निवृति, त्याग पत्र, बरखास्ती, चिकित्सा बोर्ड द्वारा निकाले गए, मृत्यु के मामलों सहित सेवानिवृत कार्मिकों की संख्या
2006	5039
2007	4961
2008	7053

(छ) ब्यौरे निम्नानुसार है:

वर्ष	भर्ती कार्मिकों की संख्या
2006	5352
2007	3928
2008	6113

[हिन्दी]

कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को निधियां

2385. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गुजरात सहित राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने कृषि और ग्रामीण उद्योग चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार सरकार द्वारा कितनी निधिया दी गई और इनका कितना उपयोग किया गया है;

(ग) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) गुजरात सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों को सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) द्वारा तीन क्रेडिट लिंक्ड यब्सिडी योजनाओं, अर्थात, (i) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी), जो सरकार द्वारा 01.04.1995 से 31.03.2008 तक खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया; (ii) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई), जो 02.10.1993 से 31.03.2008 तक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वित की गई, और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जो 2008-09 से बैंकों की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल एजेंसी के रूप में केवीआईसी के माध्यम से और राज्य/संघ शासित प्रदेशों के स्तर पर केवीआईसी के क्षेत्र कार्यालयों, राज्य/संघ शासित प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्डों तथा जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएमआरवाई (ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित) के तहत स्थापित लगभग पचास प्रतिशत इकाइयां अनुमानित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। अपने कार्यान्वयन की पूरी अवधि के दौरान आरईजीपी के तहत स्थापित परियोजनाओं और पीएमआरवाई के तहत स्थापित स्व रोजगार उद्यमों, और अपने आरंभिक वर्ष 2008-09 (अनंतिम) के दौरान पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त 'सूक्ष्म उद्यमों' का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) आरईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी और योजना के लिए अनुमोदित अनुदान केवीआईसी को जारी किए जाते थे जो बदले में निधियों (मार्जिन मनी सहायता हेतु) को हर राज्य/संघ शासित प्रदेश (यूटी) में संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए बैंकों को जारी करता था। आरईजीपी के तहत केवीआईसी द्वारा आबंटित मार्जिन मनी और 2006-07 और 2007-08 के दौरान उपयोग में लाई गई मार्जिन मनी का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। पीएमआरवाई के तहत, सब्सिडी का आबंटन और निधियों का जारी होना राज्यों/यूटी के लिए लक्ष्यों पर आधारित थे। सब्सिडी राशि सीधे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को जारी की जाती थी जो बदले में आवश्यक राशि को कार्यान्वयन बैंकों को जारी करता था। 2006-07 और 2007-08 के दौरान पीएमआरवाई के तहत आरबीआई को जारी सब्सिडी की राशि निम्नलिखित है:

वर्ष	पीएमआरवाई के तहत जारी सब्सिडी (करोड़ रुपये)
2006-07	228.82
2007-08	283.20

उद्यमिता विकास और आकस्मिकताओं के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आबंटित (जारी) निधियों और 2006-07 और 2007-08 के दौरान पीएमआरवाई के तहत उपयोग में लाई गई निधियों का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

वर्ष 2008-09 के दौरान इन दो योजनाओं यानि आरईजीपी और पीएमआरवाई के तहत कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि अब 'प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' नामक एक नई योजना में उनका विलय कर दिया गया है, जिसका ब्यौरा भाग (क) के उत्तर में दिया गया है। 2008-09 (अनंतिम) के दौरान पीएमईजीपी के तहत उपयोग में लाई गई मार्जिन मनी का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) 2009-10 के लिए निर्धारित अस्थायी लक्ष्यों के अनुसार 740.33 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी के उपयोग से कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों सहित 61,697 सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान किए जाने का अनुमान है।

विवरण-I

आरईजीपी, पीएमआरवाई और पीएमईजीपी के तहत स्थापित परियोजनाओं का राज्य/संघ शासित प्रदेशवार समग्र ब्यौरा

(इकाइयों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	इन योजनाओं के आरंभ से 31.03.2008 तक		अपने आरंभिक वर्ष 2008-09 (अनंतिम) के दौरान पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यम/परियोजनाएं
		पीएमआरवाई के तहत स्व-रोजगार उद्यमों की संख्या	आरईजीपी के तहत सहायता प्राप्त ग्रामोद्योग इकाइयों की संख्या	
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	1661	170	31
2.	दिल्ली	12107	268	5
3.	हरियाणा	102767	9522	821
4.	हिमाचल प्रदेश	34412	4994	340
5.	जम्मू और कश्मीर	13866	13673	1821
6.	पंजाब	115548	13554	887
7.	राजस्थान	159674	34064	703
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1599	1244	8
9.	बिहार	144875	3568	6741
10.	झारखंड	32578	1735	940
11.	उड़ीसा	109129	6769	1976
12.	पश्चिम बंगाल	63164	31509	5667
13.	अरुणाचल प्रदेश	4396	772	130
14.	असम	84209	10253	728
15.	मणिपुर	8982	1121	3

1	2	3	4	5
16.	मेघालय	5524	4073	3
17.	मिजोरम	4201	3715	23
18.	नागालैंड	6378	5875	31
19.	त्रिपुरा	15613	624	5
20.	सिक्किम	1080	1792	4
21.	आंध्र प्रदेश	243242	22354	903
22.	कर्नाटक	197631	19324	2423
23.	केरल	202327	12868	389
24.	लक्षद्वीप	245	42	4
25.	पुदुचेरी	4256	1556	42
26.	तमिलनाडु	205073	10962	1473
27.	दादरा और नगर हवेली	630	0	0
28.	दमन और दीव	196	0	6
29.	गोवा	3109	2807	7
30.	गुजरात	108134	2938	307
31.	महाराष्ट्र	347442	29617	3368
32.	छत्तीसगढ़	26110	4311	1078
33.	मध्य प्रदेश	291882	22887	628
34.	उत्तराखंड	42833	4376	378
35.	उत्तर प्रदेश	506341	23390	4414
	विनिर्धारित नहीं	7102	—	—
	कुल	3108316	306727	36287

विवरण-II

2006-07 और 2007-08 के दौरान आरईजीपी और 2008-09 के दौरान पीएमईजीपी के तहत उपयोग में लाई गई मार्जिन मनी का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आरईजीपी के तहत उपयोग में लाई गई राशि		पीएमईजीपी के तहत उपयोग में लाई गई राशि 2008-09
		2006-07	2007-08	
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	3.47	12.30	8.09
2.	दिल्ली	18.37	13.23	4.15
3.	हरियाणा	1749.31	2949.39	1437.76
4.	हिमाचल प्रदेश	1165.42	1799.85	452.11
5.	जम्मू और कश्मीर	1565.20	1753.83	1452.17
6.	पंजाब	1826.00	3273.35	1407.93
7.	राजस्थान	2106.77	3871.78	1461.95
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22.15	34.84	2.36
9.	बिहार	715.67	1163.37	4524.59
10.	झारखंड	357.92	461.04	1128.00
11.	उड़ीसा	1055.54	1456.41	3004.88
12.	पश्चिम बंगाल	2396.03	6367.70	6465.81
13.	अरुणाचल प्रदेश	144.45	325.67	95.00
14.	असम	1717.35	2887.94	525.16
15.	मणिपुर	128.99	82.39	1.8
16.	मेघालय	255.06	512.55	3.00
17.	मिजोरम	1043.60	1125.97	71.23
18.	नागालैंड	192.13	471.18	61.08
19.	सिक्किम	151.47	681.83	6.70
20.	त्रिपुरा	278.41	273.58	4.30
21.	आंध्र प्रदेश	3674.06	5456.10	2605.60
22.	कर्नाटक	2424.27	3315.56	3246.82
23.	केरल	1567.36	2358.49	610.79
24.	लक्षद्वीप	0.00	7.78	5.33
25.	पुदुचेरी	42.76	132.25	15.96
26.	तमिलनाडु	1438.04	3163.38	2926.56
27.	गोवा	95.25	112.73	12.95
28.	गुजरात	756.10	1075.28	445.22
29.	महाराष्ट्र	1837.03	2770.70	4194.90
30.	छत्तीसगढ़	1215.03	1788.20	1942.19
31.	मध्य प्रदेश	1531.38	2291.58	1351.48
32.	उत्तराखंड	601.44	1074.43	466.77
33.	उत्तर प्रदेश	2903.32	4994.83	10660.40
	कुल योग	34979.35	58059.59	50603.04

विवरण-III

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान पीएमआरवाई के तहत प्रशिक्षण और आकस्मिकता के लिए दी गई/ जारी की गई और उपयोग में लाई गई निधियों का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2006-07		2007-08*	
		जारी की गई निधियां	उपयोग में लाई गई गई निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग में लाई गई निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	191.95	एन.आर.	199.28	एन.आर.
2.	असम	1.73	एन.आर.	5.38	एन.आर.
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.42	0.42	6.00	6.15
4.	बिहार	0.00	6.64	56.38	एन.आर.
5.	छत्तीसगढ़	38.06	40.77	57.11	79.53
6.	दिल्ली	0.00	एन.आर.	2.63	एन.आर.
7.	गोवा	0.00	0.12	0.38	0.13
8.	गुजरात	0.00	34.64	69.89	69.50
9.	हरियाणा	38.60	68.18	182.74	159.04
10.	हिमाचल प्रदेश	26.77	18.05	24.62	25.58
11.	जम्मू और कश्मीर	10.30	एन.आर.	1.00	एन.आर.
12.	झारखंड	14.62	14.99	41.81	57.85
13.	कर्नाटक	165.91	159.10	306.22	346.29
14.	केरल	202.33	205.31	377.94	530.98
15.	मध्य प्रदेश	209.89	230.91	115.45	261.35
16.	महाराष्ट्र	112.62	132.67	198.93	457.34

1	2	3	4	5	6
17.	मणिपुर	8.24	1.77	16.18	4.86
18.	मेघालय	5.52	5.88	15.59	8.93
19.	मिजोरम	0.00	5.76	7.59	13.24
20.	नागालैंड	6.79	10.12	30.62	30.54
21.	उड़ीसा	128.31	122.67	167.99	216.91
22.	पंजाब	0.00	0.00	64.92	68.58
23.	राजस्थान	124.90	127.14	244.11	244.60
24.	तमिलनाडु	156.28	एन.आर.	311.79	एन.आर.
25.	त्रिपुरा	20.39	20.56	33.69	35.92
26.	उत्तर प्रदेश	388.87	388.87	659.39	625.47
27.	उत्तराखंड	83.49	78.26	81.14	एन.आर.
28.	पश्चिम बंगाल	4.96	21.60	256.85	256.95
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.89	0.09	1.17	0.27
30.	चंडीगढ़	1.15	0.87	1.03	2.30
31.	दमन और दीव	0.11	एन.आर.	0.10	एन.आर.
32.	दादरा और नगर हवेली	0.12	एन.आर.	0.45	एन.आर.
33.	लक्षद्वीप	0.04	एन.आर.	0.07	एन.आर.
34.	पुदुचेरी	3.38	3.51	8.63	6.42
35.	सिक्किम	0.52	एन.आर.	3.08	0.41
	कुल	1947.16	1698.90	3550.12	3509.14

एन.आर. - राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार/प्रशासन द्वारा जानकारी नहीं दी गई।

*नए घटक 'चयन पूर्व अभिप्रेरणा अभियान' के लिए जारी की गई और उपयोग में लाई गई निधियों सहित

[अनुवाद]

विशिष्ट पहचान-पत्र योजना का क्रियान्वयन

2386. श्री मनीष तिवारी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक क्रियान्वित की गई विशिष्ट पहचान-पत्र योजना की प्रायोगिक परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किसी नागरिक द्वारा इस विशिष्ट पहचान पत्र को किन-किन उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाए जाने की संभावना है;

(ग) इस योजना का पर्यवेक्षण करने वाले अधिकार प्राप्त दल के सदस्य कौन-कौन हैं;

(घ) क्या राज्यों के अभ्यावेदनों को अधिकार प्राप्त समिति में भी शामिल किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र संबंधी प्रायोगिक परियोजना का 12 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के चयनित क्षेत्रों में कार्यान्वयन किया गया है। इस परियोजना के तहत 28.62 लाख व्यक्तियों का डाटाबेस तैयार किया गया है। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 12.88 लाख पहचान (स्मार्ट) पत्र जारी किए गए हैं और शेष को राष्ट्रीय पहचान संख्यांक दिया गया है। प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य 31.03.2009 को समाप्त हो चुका है। प्रायोगिक परियोजना के अनुभव के आधार पर सरकार ने 2011 की जनगणना के साथ देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का प्रस्ताव किया है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की फोटो और उनकी अंगुली की छाप के साथ प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं संबंधी ब्यौरे एकत्रित किए जाएंगे। तथापि, 9 समुद्री राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और 4 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और पुडुचेरी के तटीय गांवों के संबंध में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का कार्य 2009-10 के दौरान किया जाएगा। यह निर्णय 26/11 की घटना के बाद तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से लिया गया है। प्रथम चरण में 3331 तटीय गांवों को कवर करने की योजना को अनुमोदित किया गया है। नगरों/शहरों सहित शेष तटीय क्षेत्रों को 2011 की जनगणना के साथ कवर किया जाएगा।

तटीय क्षेत्रों की योजना के अंतर्गत 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों को पहचान पत्र दिए जाने की योजना है। तथापि, देश के शेष हिस्सों में सामान्य निवासियों को पहचान (स्मार्ट) पत्र जारी करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकार ने विशिष्ट पहचान पत्र योजना की देखरेख के लिए एक अधिकार प्राप्त समूह के गठन का प्रस्ताव किया है। समूह के संघटन की जानकारी इसके औपचारिक गठन के बाद ही प्राप्त हो सकेगी।

तटवर्ती क्षेत्रों से घुसपैठ

2387. श्री वैजयंत पांडा :
श्री उदय सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तटवर्ती क्षेत्रों से घुसपैठ की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तटवर्ती चौकसी के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं अपनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मुम्बई की घटनाओं को अंजाम देने वाले 26 नवम्बर, 2008 के समुद्री मार्ग द्वारा किए गए घुसपैठ से संबंधित एक मामले की सूचना को छोड़कर, विगत तीन वर्षों के दौरान किसी अन्य मामले की सूचना नहीं है। यह मामला जांच एवं न्याय के लिए निर्णयाधीन है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत सरकार ने समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण के रूप में भारतीय नौ सेना का नामित किया है जिसमें तटीय सुरक्षा और तट से कुछ दूर समुद्री सुरक्षा शामिल है। भारतीय तटरक्षक को भी अलग से तटीय पुलिस द्वारा चौकसी किए जाने वाले क्षेत्रों सहित प्रादेशिक समुद्र में तटीय सुरक्षा के लिए

उत्तरदायी प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। तटरक्षक के महानिदेशक को तटीय सुरक्षा से संबंधित समस्त मामलों में केन्द्रीय एवं राज्य एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी कमाण्डर कोस्टल कमाण्ड नामित किया गया है। ये निर्णय रक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

तटरक्षक, नौसेना एवं अन्य एजेंसियों द्वारा ऑपरेशन स्वान के अंतर्गत गुजरात तथा महाराष्ट्र के तटों के साथ-साथ संयुक्त तटीय चौकसी भी की जा रही है।

भारतीय समुद्री क्षेत्र में कार्यरत समस्त एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय स्थापित करने के लिए भारतीय तटरक्षक समस्त तटीय राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय एजेंसियों के साथ परामर्श करके तटीय सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करने की प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली

2388. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में ऑनलाइन/इंटरनेट लाटरी को स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में ऑनलाइन/इंटरनेट लाटरी को विनियमित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और ऑनलाइन लाटरियों में जालसाजी सहित धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) लाटरियां, भारत के संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 40 अर्थात "भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित लाटरियां" के अंतर्गत आती हैं। तदनुसार भारत सरकार ने लाटरियां (विनियमन) अधिनियम, 1998 तैयार किया जिसमें वे शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनके अध्यधीन राज्य सरकारें, लाटरी आयोजित करेंगी, चलाएंगी या उनका संवर्धन करेंगी। यद्यपि लाटरियां (विनियमन) अधिनियम, 1998 में ऑनलाइन लाटरियों के बारे में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है फिर भी कानून मंत्रालय की राय के अनुसार अधिनियम के तहत की गई लाटरी की परिभाषा इतनी व्यापक है कि ऑनलाइन लाटरी सहित जितने भी रूपों में लाटरी आयोजित की जाती है इसमें आ जाती हैं।

2. इसलिए ऑनलाइन/इंटरनेट लाटरियां, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत आती हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 12 (1) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए नियम बना सकती है"।

तदनुसार, अलग-अलग राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में लाटरियां चलाने के लिए अपने-अपने नियम बनाए हैं। कुछ राज्यों ने ऑनलाइन लाटरियों का परिचालन करने के लिए विशिष्ट नियम भी तैसार किए हैं। उदाहरणार्थ, सिक्किम ऑनलाइन नेटवर्क लाटरी नियम, 2001, महाराष्ट्र ऑनलाइन लाटरियां (विनियमन) नियम, 2001 अरुणाचल प्रदेश स्टेट ऑनलाइन नियम, 2002 मेघालय स्टेट कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन लाटरी (विनियमन) नियम, 2002 मणिपुर स्टेट ऑनलाइन लाटरी (विनियमन) नियम, त्रिपुरा कम्प्यूटरीकृत नेटवर्क नियम, 2004 आदि।

तदनुसार, इंटरनेट/ऑनलाइन लाटरियां, लाटरियां (विनियमन) अधिनियम, 1998 के उपबंधों और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के तहम विनियमित होंगी। इस संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा आगे आवश्यक कार्रवाई की जाती है। उदाहरणार्थ केरल सरकार ने सूचित किए गए धोखाधड़ी के कुछ मामलों में अपने सतर्कता विभाग से जांच करवाई थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य ने पूरी ऑनलाइन लाटरी पर ही प्रतिबंध लगा दिया था।

[अनुवाद]

फिशिंग यार्ड का निर्माण

2389. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिशिंग यार्ड के निर्माण के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने देश में मछुआरों की सुरक्षा हेतु कोई कदम उठाया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार केंद्रीय प्रायोजित योजना समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट आपरेशनों का विकास के तहत मत्स्यन बंदरगाहों, मछली उतारने के केंद्रों तथा पोस्ट हार्वेस्ट आपरेशनों व विपणन सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, पोर्ट ट्रस्टों व अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

(ग) जी, हां। कृषि मंत्रालय केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (जीपीएस), संचार उपकरण, इको-साउण्डर तथा खोजी व बचाव दीप वाले एक किट के यूनिट लागत पर 75% की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, भारतीय तटरक्षक नियमित रूप से सहक्रिया कार्यक्रम आयोजित करते हैं तथा समुद्र में संकट में होने पर मछुआरों की मदद करते हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : महोदय मैं, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और माप मानक (सामान्य) संशोधन नियम, 2009 जो 5 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 151(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 382/15/09]

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 383/15/09]

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 384/15/09]

(तीन) नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्टस एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 385/15/09]

(चार) नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंक कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 386/15/09]

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 96(अ) जो 17 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो यूरेनियम के लिए रायल्टी की दरों तथा अनिवार्य भाटक के संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 387/15/09]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (लेखाओं का वार्षिक विवरण) संशोधन नियम, 2009 जो 25 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 199(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 388/15/09]

(2) जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत जनगणना (संशोधन) नियम, 2009 जो 3 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 458(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 389/15/09]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : महोदय, अपने सहयोगी प्रो. के.वी. थॉमस की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2009 जो 26 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 128(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 390/15/09]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 391/15/09]

(दो) नेशनल सीड्स कारपोरेशन तथा कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 392/15/09]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कवरत्ती के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कवरत्ती के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 393/15/09]

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 473(अ) जो 13 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा 31 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1310(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 509(अ) जो 18 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो मासिक आधार पर विहित प्रपत्र में टन-दर-टन नीति के अध्यधीन अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत कच्ची चीनी के आयातों के बारे में है।

(तीन) सा.का.नि. 164(अ) जो 12 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जो चीनी के डीलरों पर चाह माह के लिए स्टाक-धारण तथा कारोबार सीमा लगाए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 1067(अ) जो 29 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा

18 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 509(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) सा.का.नि. 303(अ) जो 1 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जो किसी चीनी उत्पादक द्वारा आयातित कच्ची चीनी से प्रसंस्कृत चीनी के संबंध में तथा एसटीसी/एमएमटीसी/पीईसी/नेफेड द्वारा 10 लाख टन तक आयातित सफेद या शोधित चीनी के संबंध में उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं के उपबंधों की 1 अगस्त, 2009 तक अप्रयोज्यता के बारे में है।

(छह) सा.का.नि. 304(अ) जो 1 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जो एसटीसी/एमएमटीसी/पीईसी/नेफेड द्वारा 10 लाख टन तक आयातित सफेद या शोधित चीनी के संबंध में उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं के उपबंधों की 1 अगस्त, 2009 तक अप्रयोज्यता के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 394/15/09]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 9 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 84(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 4 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 148(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। *देखिये* संख्या एल.टी. 395/15/09]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 21 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन आफ इंडिया) के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 396/15/09]

(3) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इंडिया पुणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इंडिया पुणे के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 397/15/09]

(5) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 398/15/09]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 399/15/09]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का.आ. 548(अ) जो 25 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई है।

(दो) का.आ. 1051(अ) जो 24 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 1290(अ) जो 20 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(चार) का.आ. 1068(अ) जो 30 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (करूर-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(पांच) का.आ. 1249(अ) जो 18 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सलेम-उलुंडूरपेट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 1265(अ) जो 19 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को आपस में जोड़ने वाले चेन्नई बाइपास (फेज-II) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 1271(अ) और का.आ. 1272(अ) जो 19 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरुपुक्कोट्टई-तूतुक्कुडि खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1341(अ) जो 25 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1368(अ) जो 28 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 (मेनामबेडू गांव) को जोड़ने वाले चेन्नई बाइपास (फेस-II) के निर्माण (बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 1369(अ) जो 28 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एग्मोर-नुंगाम्बक्कम तालुक के कोयम्बेडू और अरुम्बक्कम गांवों में कोयम्बेडू जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1435(अ) जो 10 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के निर्माण (चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1226(अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सलेम-कोयम्बटूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1233(अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सलेम-कोयम्बटूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1237(अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 2126(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का.आ. 1248(अ) जो 18 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सलेम-उलुंडूरपेट खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1269(अ) और का.आ. 1270(अ) जो 19 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सलेम-उलुंडूरपेड खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1339(अ) जो 25 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरुप्पुकोट्टई-तूतुक्कुडि खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 1340(अ) जो 25 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पांडिचेरी-डिंडीबनम खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 1342(अ) जो 25 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1442(अ) जो 11 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुरै खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 1443(अ) जो 11 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुरै खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 2913(अ) जो 17 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 193(अ) जो 19 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 196(अ) जो 19 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकलूरीपेट-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 354(अ) जो 28 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 369(अ) जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (थोंडापली-जडचेरला खंड) के उक्त खंड के प्रयोगकताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 933(अ) जो 8 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 852(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अट्ठाईस) का.आ. 934(अ) जो 8 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 935(अ) जो 8 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ. 936(अ) जो 8 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 1163(अ) जो 5 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 1266(अ) जो 19 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 1349(अ) जो 26 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयनगर-मछलीपट्टनम खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 1350(अ) जो 26 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयनगर-मछलीपट्टनम खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 1351(अ) जो 26 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयनगर-मछलीपट्टनम खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 1352(अ) जो 26 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 819(अ) जो 23 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (पिंडवाड़ा-जसवंतगढ़ खंड) के चार लेन वाले खंड के प्रयोक्ताओं से वसूल की जानी वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 875(अ) जो 27 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (गडावली नदी-राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के चार लेन वाले खंड के प्रयोक्ताओं से वसूल की जानी वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 1625(अ) जो 3 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (ब्यावर-गोमती चौराहा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 954(अ) जो 13 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (चंदाप्पुरा-कोट्टाप्पुरम खंड) के निर्माण/बनाने, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 400/15/09]

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1050(अ) जो 24 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौपा गया है।

(दो) का.आ. 1289(अ) जो 20 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौपा गया है।

(एक) का.आ. 1291(अ) जो 20 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौपा गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 401/15/09]

अपराह्न 12.02 बजे

'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' के बारे में दिनांक 7.7.2009 के तारांकित प्रश्न सं. 48, के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : महोदय, 'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' के संबंध में 7.7.2009 को

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 402/15/09

[श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन]

श्री रुद्र माधव राय और डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी के तारांकित प्रश्न संख्या 48 के उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण को सभा पटल पर रखता हूं।

मैं, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण विषय पर दिनांक 07.07.2009 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 48 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में निम्नवत् सुधार करने का अनुरोध करता हूं:

दिए गए उत्तर के प्रश्न का भाग	अशुद्ध	शुद्ध
(ग) और (घ)	दिनांक 01.04.2009 की स्थिति के अनुसार सी.पी.एफ. कार्मिकों के लिए कुल 1,19,948 रिहायशी यूनिटें उपलब्ध हैं जिससे आवास संतोष स्तर 15.93% है।	दिनांक 01.04.2009 की स्थिति के अनुसार सी.पी.एफ. कार्मिकों के लिए कुल 1,19,948 रिहायशी यूनिटें उपलब्ध हैं जिससे आवास संतोष स्तर 15.39% है।

असुविधा के लिए खेद है।

अपराह्न 12.03 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

अंतिम उपयोग निगरानी प्रबंध के बारे में

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अविलंबलीय लोक महत्व के मामलों पर विचार करेगी।

श्री यशवंत सिन्हा

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सदन के सामने रखना चाहता हूं। अमरीका के विदेश मंत्री का भारत दौरा अभी-अभी समाप्त हुआ है। उस दौरे के दरम्यान भारत और अमरीका के बीच में कई समझौते हुए हैं, जिन पर कल दोनों देशों के विदेश-मंत्रियों ने हस्ताक्षर किये हैं। उसमें एक समझौता है जिसे "एंड यूज मानिटरिंग एग्रीमेंट" कहते हैं। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि अमरीका सरकार ने ऐसे आइटम्स की एक लिस्ट बनाई है जिसका उपयोग दोनों तरफ हो सकता है, ड्यूल उपयोग हो सकता है- सामरिक क्षेत्र में भी उपयोग हो सकता है, सिविल क्षेत्र में भी उपयोग हो सकता है। उनके देश का कानून है कि अगर वे ड्यूल यूज आइटम्स का किसी भी देश को एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पर जाकर, स्पाट पर, वे उसका वैरीफिकेशन करेंगे ड्यूल यूज आइटम्स का सिविलियन यूज हो रहा है या सामरिक यूज हो रहा है।

इसके लिए अपने देश के कानून को लागू करने के लिए जब वे दूसरे देशों के साथ समझौता करते हैं, तो एंड-यूज मोनिटरिंग एग्रीमेंट उनके साथ करते हैं, ताकि उनको यह अधिकार रहे कि उस देश में जा कर ऐसे उपकरणों का, टेक्नोलोजी का सत्यापन कर सकें कि वह देश उसका उपयोग कैसे कर रहा है। इस प्रकार का एक समझौता भारत सरकार ने अमरीका के साथ कल किया है। इसमें सबसे चिंता की बात यह है कि वह स्पाट पर जा कर फिजिकल वेरीफिकेशन करेंगे। मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि भारत सरकार ने कहा है कि समय और स्थान हम तय करेंगे। अब समय के लिए तो हम समझ सकते हैं कि दोनों देशों की सुविधा के अनुसार तय किया जाएगा, लेकिन स्थान के बारे में भारत सरकार का कहना है कि अगर हवाई जहाज का इंस्पेक्शन होना है, तो हम एयरफोर्स बेस पर इंस्पेक्शन न करा कर, किसी सिविलियन बेस पर इंस्पेक्शन करा लेते हैं। मेरा सवाल है कि जो कारखाना बना है, जो फिक्स्ड एसेट है, जिसे आप उठा कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाएंगे, उस पर कैसे वैरीफिकेशन होगा? वहां आन दि स्पाट ही

इंस्पेक्शन हो सकता है। इसमें सबसे चिंता का विषय यह है कि तीसरे मुल्कों से भी हम जो सामान मंगाते हैं, उसमें अगर अमरीकी ड्युअल यूज आइटम लगा हुआ है, तो उसका भी इंस्पेक्शन करने का अधिकार अमरीका ले लेता है कि हमने रूस से मंगाया, हमने ब्राजील से मंगाया, फ्रांस से मंगाया। वे कहेंगे कि हम इनका भी इंस्पेक्शन करेंगे कि इनका सही इस्तेमाल हो रहा है या गलत इस्तेमाल हो रहा है। अमरीका में जो नए-नए शब्द इजाद होते हैं, उसमें एक शब्द फायरवाल है कि मिलिट्री यूज और नोन मिलिट्री यूज में यानी सिविलियन यूज में फायरवाल क्रियेट होना चाहिए। उस तरह का फायरवाल हमने क्रियेट किया या नहीं, इसकी भी जांच अमरीकी करेंगे।

यह क्यों किया गया, क्योंकि अमरीका की रुचि जागी है भारत को डिफेंस इक्विपमेंट्स सप्लाई करने की। अभी सरकार के पास साढ़े दस बिलियन अमरीकी डालर के फाइटर प्लेन्स खरीदने का प्रस्ताव है। अमरीका इन्हें बेचने में रुचि रखता है। इसमें अमरीका की गरज है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें भारत की गरज नहीं है। इस कारण हम मजबूती के साथ भारत की तरफ से बातचीत करके समझौता कर सकते थे और अमरीका जो नाजायज मांग हम पर रख रहा है, उसे हम नकार सकते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और उनकी बात मान ली। मैं सदन को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि एक समय आया था, जब स्पेस में जाने के लिए हमें क्रायोजेनिक इंजन की आवश्यकता थी, जब हमें वैदर तथा दूसरे कामों के लिए सुपर कम्प्यूटर्स की आवश्यकता थी, अमरीका ने न केवल अपने यहां से उसका आयात मना कर दिया, बल्कि रूस पर भी दबाव डाला कि आप क्रायोजेनिक रोकेट टेक्नोलोजी भारत को नहीं देंगे। हमें वह टेक्नोलोजी नहीं मिली। मैं भारत के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं, उनका नमन करना चाहता हूं कि चाहे वह क्रायोजेनिक इंजन हो, चाहे सुपर कम्प्यूटर हो, हमारे वैज्ञानिकों ने ये चीजें भारत में बनाई। हमें किसी दूसरे देश पर इनके आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज कौन सी मजबूरी है कि हम इस बात को मान गए कि अमरीका के इंस्पेक्टर्स आएं और हमारी जितनी सामरिक फैसिलिटीज हैं, उनमें घूमें, उनका सत्यापन करें। मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह जो एंड-यूज एग्रीमेंट हुआ है, टेक्नोलीजी वेरिफिकेशन एग्रीमेंट हुआ है, उसके बारे में सरकार सदन को विश्वास में ले और पूरी तरह से बताए कि क्या हुआ है। उस टैक्स्ट को सदन की टेबल पर रखा जाए, ताकि हम लोग उसका अध्ययन कर सकें और सरकार ने अगर गलती की है, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस एग्रीमैंट को रेक्टीफाई न करें, इसे अंजाम में न लाए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, यह समझौता जिसपर कल हस्ताक्षर हुए थे, वह काफी गंभीर मुद्दा है। मैं अपने आपको श्री यशवंत सिंहा ने जो कहा उससे संबद्ध करता हूं तथा यह मांग भी करता हूं कि सरकार सभापटल पर समझौते का मसौदा रखे; तथा सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे समझौते पर हमारे प्रतिनिधि द्वारा कैसे हस्ताक्षर किए गए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो अपना नोटिस दिया है, उसमें बोलिए। यह तो हो गया।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : सभा में चर्चा होनी चाहिए; ऐसा लगता है कि समझौता हमारे देश के हितों के विरुद्ध है; समझौते को समाप्त किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका विचार इसपर गया है। आप अपने विषय पर बोलिए।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (घाटल) : मैं इस मुद्दे के साथ पूरी तरह संबद्ध हूं। सरकार द्वारा की गई यह बहुत बड़ी गलती है। यह भारत की संप्रभुता का आत्मसमर्पण है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जो जो माननीय सदस्य इससे एशोसिएट करना चाहते हैं, वे अपने नाम दे दें।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त : हम सरकार से तत्काल वक्तव्य चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार को यहां सभा के उठने से पहले वक्तव्य देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : उपाध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं। इसलिए मैं यह चाहूंगी क्योंकि यहां रक्षा मंत्री नहीं हैं, विदेश मंत्री यहां नहीं हैं, प्रधान मंत्री भी नहीं हैं। लीडर आफ दि हाउस आ गये हैं, इसलिए या तो नेता सदन बोलें नहीं तो संसदीय कार्य मंत्री हमें बताएं कि इस पर जवाब आज कब आएगा? जवाब आज ही चाहिए। कितने बजे बोलेंगे? बता दें। संसदीय कार्य मंत्री रैस्पांड करें।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, कल भी हमने इस सवाल को उठाया था। मुझे खुशी है कि यशवंत सिन्हा जी ने आज इसे और गंभीरता से लिया है। एंड-यूज मानीटरिंग का जो यहां एग्रीमेंट हुआ है, यह केवल सदन तक नहीं है। सदन तो पूरे देश का एक दर्पण है। पूरी जनता में भी यह मामला चला गया है। आम लोग इस बात को पूछते हैं कि आखिर हिन्दुस्तान हर बात में आत्मसमर्पण कर रहा है चाहे वह अमेरिका के सामने हो या कोई भी हो। जब यह बता दिया गया है कि हमारा देश कई मामलों में आत्मनिर्भर है और यहां के वैज्ञानिकों को अवसर दिया जाए। यह बात मैंने उस दिन भी कही थी और आज भी कह रहा हूं। हिन्दुस्तान के वैज्ञानिक और शिक्षाविद दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं लेकिन उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है। विदेशों पर विश्वास किया जा रहा है। पता नहीं विदेशी वैज्ञानिक और चीजें क्यों पसंद आ रही हैं? हमारा हिन्दुस्तान किसी से पीछे नहीं है। आप देख रहे हैं कि हथियारों के मामले में मिसाइल भी हमारे देश के ही वैज्ञानिक और राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाले व्यक्ति ने ही बनायी है। इसी तरह से वैज्ञानिकों को अवसर नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम इतना जरूर कहेंगे कि माननीय नेता सदन ने कल कहा था कि हम इसी सत्र में इसे पेश करेंगे और बहस भी कराएंगे। इसलिए हमारी अपील है कि आज ही बहस हो जानी चाहिए। इस मामले पर तत्काल बहस हो जानी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। देश के हितों के खिलाफ काम हो रहा है और देश के हितों के खिलाफ किसी बात को हम लोग पसन्द नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आज ही इस पर बहस होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आपका हो गया। आप बैठ जाइए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मै। यशवंत जी का और सभी सदन के लोगों की जो भावना है, उसके साथ कहना चाहूंगा कि सरकार चाहे वह बाहर समझौता कर रही है और चाहे वह भीतर समझौता कर रही है, विदेश मंत्री फारेन सैक्रेटरी हिलेरी क्लिंटन यहां आई हुई हैं, सदन चल रहा है और यशवंत सिन्हा जी ने एंड-यूज मोनीटरिंग का जो मामला उठाया, सारे सदन की चिंता उनके साथ है। इधर से माननीय सदस्य ने और भाई मुलायम सिंह जी ने अभी ठीक कहा। इस पर सरकार बयान देने का काम तत्काल करे। यह चिंता बढ़ती जा रही है। भारत जो इतना बड़ा देश है, उसकी जो विदेश नीति है, वह एक तरफ झुकती जा रही है और इतनी झुक रही है कि हर सवाल पर हम हर तरह से झुक रहे हैं और ऐसा लग रहा है अमरीका की जो ताकत है, उसके सामने हम अपने राष्ट्रीय हितों का पूरी तरह से समर्पण कर रहे हैं।

हम समर्पण कर रहे हैं। प्रणब बाबू यहां हैं। सारे देश के विपक्ष ने चिंता व्यक्त की है, चाहे यह हमारी तरफ से हो, वामपंथी दल की तरफ से हो या और साथियों की तरफ से हो। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनसे देश का मान-सम्मान और सुरक्षा जुड़ी होती है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है और जो लगातार बयान आ रहे हैं, इन सब चीजों से पूरा सदन और पूरा देश चिंतित है। सरकार को खुद ही, अपने आप ही, इस सवाल के बारे में तत्काल बयान देकर सारी स्थिति को पूरी तरह से पारदर्शी बनाकर आगे बढ़ना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अभी तत्काल आपको जरूर इस बारे में कुछ कहना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बात कही है वह चिंता का विषय है। इस चिंता को आप अकेले अपनी मत मानिए, यह देश की चिंता है। हमने 60 वर्ष से अपनी तरह की हैसियत दुनिया में बनाई है और यह पूरी तरह से हिल रही है, एक पक्ष में जा रही है। मैं नेता सदन से कहूंगा कि वे इस बारे में तत्काल बयान दें।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न दलों के अनेक नेताओं द्वारा सभा में व्यक्त की गई शंकाएं, मीडिया में उजागर की गई शंकाएं चिंता का विषय हैं तथा इसे तभी समाप्त किया जा सकता है जब प्रधानमंत्री या सरकार इस सभा में आज कोई वक्तव्य दे। चिंता का विषय केवल 'अंतिम उपयोग' को लेकर ही नहीं है तथा अमेरिका द्वारा 'फायर बाल' शब्द का उपयोग किया गया है लेकिन मैं कहूंगा कि चिंता का विषय यह है कि जब सभा का सत्र चल रहा हो तथा इस प्रकार के समझौते किए जा रहे हों, तो सभा को विश्वास में नहीं लिया जाता है। हम इसे आज

उठा रहे हैं जब दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। मैं सरकार से ऐसी गतिविधियां में शामिल नहीं होने का अनुरोध करूंगा तथा इस चिंता से भी पूरी तरह संबद्ध करूंगा जो श्री यशवंत सिन्हा उठाई है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण) : माननीय सभापति महोदय, यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है, यह सवाल देश का है। देश की अखंडता, सुरक्षा और स्वाभिमान का सवाल है। इस बारे में सभी पार्टी के नेताओं ने आशंका ही नहीं की बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को रखा है। मैं इससे अपने को संबद्ध करते हुए आपको और सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि सद्दाम हुसैन के पास, इराक के पास कोई खतरनाक हथियार नहीं थे, कैमिकल भी नहीं था। हिन्दुस्तान ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत, यूएनओ, के लोग जांच करने आए। सुरक्षा परिषद आई, सब चीजों की जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला लेकिन सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई, देश को दखल कर दिया। देश की सुरक्षा से जुड़ा इतना बड़ा सवाल है इसलिए सरकार को बिना विलंब किए हुए सदन के माध्यम से पूरे देश को आज ही बता देना चाहिए। हम जो भी सामान खरीदेंगे उसकी जांच करने अमरीका के इंस्पेक्टर आएंगे। वे हमारे हथियारों का लेखाजोखा देखेंगे औा देखेंगे कि कहां से क्या-क्या किया गया। वे ही सब हिसाब-किताब लेंगे। यह बड़ी खतरानाक बात है। हमारी सरकार से अपेक्षा है कि तत्काल आज ही सफाई दे देनी चाहिए ताकि देश को पता चल जाए क्योंकि यह मामूली सवाल नहीं है।

महोदय, मैं उस समय केरल में था, जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी जा रही थी। हमने दिन भर भोजन नहीं किया था। उसी दिन दुनिया को यह चेतावनी मिल गई थी कि जो भी अमरीका के खिलाफ बोलेगा उसका यही हश्र होगा। इसके लिए बकरीद का दिन चुना गया था। हम अपना स्वाभिमान और प्रतिष्ठा कहां गंवाने जा रहे हैं? अगर हमने दस्तखत किये हैं तो बिना छिपाये हुए बात को साफ-साफ आज ही सदन के सामने रख देना चाहिए, ताकि फिर हम लोग सब उस पर विचार कर सकें।

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी ए.आई.ए.डी.एम.के. भी सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौते से चिंतित हैं जब सभा का सत्र चल रहा होता है तब सभा के सभी सदस्य, तथा पूरा देश यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि इस संबंध में क्या हो रहा है। अतएव, मैं सरकार से हस्ताक्षर किए गए समझौते को सभा पटल पर रखने का अनुरोध करूंगा। सरकार को किसी अन्य देश के दवाव में नहीं आना चाहिए। अतएव, मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार सभापटल पर वक्तव्य रखने के लिए तुरंत आगे आए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री गुरूदास दासगुप्त बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : उन्होंने नहीं पुकारा है। मैंने एक टिप्पणी की...*(व्यवधान)* महोदय, यह अविश्वसनीय है कि भारत जैसा महान देश अमेरिका के दवाब में कैसे झुक सकता है। यह अविश्वसनीय है; यह अपमानजनक है तथा यह भारत की संप्रभुता का आत्मसमर्पण है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोल चुके हैं, दोबारा मत बोलिये। आप पहले बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नागेश्वर राव, आप बोलिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम नहीं बुलाया गया है। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। हमने आपको नहीं बुलाया है, आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*(व्यवधान)**

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : उपाध्यक्ष महोदय, जो इश्यु अभी सदन में आया है, तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से अपने आपको उससे पूरी तरह एसोसिएट करते हैं। हर बार जब सदन का सत्र चल रहा होता है, तभी यह सरकार ऐसा करती है। इससे पहले भी जब सरकार ने पैट्रोल के रेट्स बढ़ाये तो हाउस चल रहा था। अभी सरकार ने जो एग्रीमैन्ट किया है, यह हाउस के चलते हुए किया है और हाउस को अंधेरे में रखकर किया है। इसलिए सदन में जो इश्यु आया है, हम उससे अपने आपको फुल्ली एसोसिएट कर रहे हैं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों तथा विभिन्न समूहों के नेताओं ने अमेरीका तथा भारत सरकार के बीच समझौते पर अपनी चिंताएं तीन बातों पर जाहिर की है, मैं सभा को आश्वासन देना चाहूंगा कि आज सभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सरकार वक्तव्य देगी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : आज ही क्यों नहीं करेंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : मैंने कहा है कि सभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सरकार एक वक्तव्य देगी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 12.23 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को सदन के सभा पटल पर रखा जाता है।

(एक) पश्चिम बंगाल में दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में दुग्ध यूनियनों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर) : भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने वाली श्वेत क्रांति के अनुसरण में पश्चिम बंगाल में 16 दुग्ध उत्पादक संघों की स्थापना की गई थी ताकि उन गांववालों से दुग्ध की खरीद की जा सके जो आसानी से बाजार तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन विगत वर्षों से पश्चिम बंगाल के दुग्ध उत्पादक संघ घाटा उटा रहे हैं और इनमें से अधिक घाटे में हैं। गाय-भैसों को पालने वाले लाखों दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध उत्पादक संघों से अतिरिक्त आय हो जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में सभी दुग्ध उत्पादक संघ ग्रामीण लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल रहे हैं। सभी दुग्ध उत्पादक संघों को अमूल माडल को दोहराने के लिए गठित किया था। सहकारिता की अवधारणा अनिवार्यत: दुग्ध उत्पादक संघों की स्थापना का आधार है।

मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि पश्चिम बंगाल में दुग्ध उत्पादक संघों को सुदृढ़ किया जाए ताकि गांव के दुग्ध उत्पादकों की आय में सुधार किया जा सके।

(दो) उत्तर पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर सीवर और ड्रेनेज सिस्टम के लिए योजना बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली) : राजधानी दिल्ली में ड्रेनेज और सीवर सिस्टम लगभग 42 वर्ष पुराना है। इसमें समय-समय पर रद्दोबदल तो हुए, लेकिन बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरत के हिसाब से इसे विकसित नहीं किया गया। राजधानी दिल्ली की विशेष उत्तर-पूर्व संसदीय क्षेत्र की प्रमुख समस्या वह ड्रेनेज सिस्टम है, जो सड़कों, गलियों और विभिन्न इलाकों को नालों से जोड़ता है। इसे बदलने के लिए अभी तक कोई कारगर योजना नहीं बनाई गई है। राजधानी दिल्ली में अगर कहीं ड्रेनेज सिस्टम बदला भी जाता है तो वहां मौजूदा जरूरत को देखते हुए सीवर लाइनें बिछाई जाती है, जबकि उसे भविष्य की जरूरत के हिसाब से डालना चाहिए।

आज भी राजधानी दिल्ली की विशेषकर उत्तर-पूर्व संसदीय क्षेत्र की अधिकृत की गयी कालोनियों सहित अनेक गांवों और पुनर्वास कालोनियों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। उत्तर-पूर्व संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कई इलाके ऐसे भी हैं, जहां सड़कें बार-बार बनने से ऊंची हो गयी है और कालोनी नीचे रह गयी हैं। इस कारण भी पूरे क्षेत्र में जल-भराव हो जाता है, जिसकी वजह से नागरिकों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। यहां की डी.डी.ए. कालोनियों का ड्रेनेज सिस्टम भी पूरी तरह से जाम पड़ा हुआ है। उत्तर-पूर्व संसदीय क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक कारगर योजना बनाये जाने की आवश्यकता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्व संसदीय क्षेत्र के लिए सीवर एवं ड्रेनेज समस्या के निदान

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

हेतु प्लान तैयार किए जाने और इस क्षेत्र के लिए विद्युत, पानी, सड़क की समस्या के निराकरण एवं सर्वांगीण विकास हेतु एक विशेष योजना बनाकर उसको तीव्रता से क्रियान्वित किये जाने हेतु कारगर कदम उठाए।

(तीन) आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी के जल का उचित हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी (अनन्तपुर) : कर्नाटक सरकार कृष्णा नदी पर 55 पुल-सह-बांधों का निर्माण कर रही है। इन बांधों के माध्यम से कर्नाटक के द्वारा अपने प्रयोजनार्थ 100 टीएमसी अतिरिक्त पानी का उपयोग किए जाने का अनुमान है। कृष्णा नदी का पानी कर्नाटक से निम्नवर्ती तटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होता है और यहां से यह तुंगभद्रा सहित दूसरे उन बांधों में प्रवाहित होता है जो मुख्यतया आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के सूखा-प्रवण क्षेत्रों की सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं। यह पानी रायलसीमा क्षेत्र के चार जिलों में लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने के साथ ही इन क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थान के पश्चात् देश में सबसे कम वर्षा वाले अनन्तपुर जिला के लोगों को पेय जल प्रदान करने का मुख्य स्रोत है और उनकी जीवन रेखा है।

कर्नाटक सरकार मुख्य कृष्णा नदी पर बड़े पैमाने पर बांधों के साथ-साथ इसकी सहायक नदियों मालप्रभा पर 10 बांध घाटप्रभा पर 20 बांध तथा भीमा पर 18 बांधों का निर्माण कर रही है। आंध्र प्रदेश पानी के अपने उचित हिस्से से वंचित है। अगर इस प्रकार पुल-सह-बांधों का निर्माण जारी रहता है तो रायलसीमा क्षेत्र के लोगों को पेयजल भी मिल सकेगा।

यह पहली बार नहीं है कि कर्नाटक सरकार अलमही बांध का निर्माण कर रही है जिससे रायलसीमा क्षेत्र के किसान काफी प्रभावित हुए हैं। उक्त पुल-सह-बांधों के निर्माण के फलस्वरूप किसान पूर्णतया दिवालिया हो जाएंगे तथा पहले से ही सूखा का सामना कर रहे क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जायेगी।

मैं माननीय जल संसाधन मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे तत्काल हस्तक्षेप कर कर्नाटक सरकार को इन पुल-सह-बांधों के निर्माण को रोकने का निर्देश दें तथा भारत सरकार के अंतर्राज्यीय नदी जल पंचाट को कार्यान्वित करें तथा आंध्र प्रदेश जितने पानी का हकदार है उसे उतना पानी दिया जाये।

(चार) पूर्वी उत्तर प्रदेश में गहरे बोरिंग के माध्यम से भूमिगत जल का उपयोग करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती) : उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की शिवालिक पहाड़ियों के तराई अंचल की जमीन पथरीली है। सिंचाई के पर्याप्त संसाधनों के अभाव में यहां का किसान प्रकृति के भरोसे रहने को मजबूर है। यह सूखाग्रस्त असिंचित क्षेत्र है क्योंकि यहां सामान्य रूप से ट्यूबवैल लगाकर भूमिगत जल का दोहन नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है।

आवश्यकता इस बात की है कि इस क्षेत्र के बलरामपुर श्रावस्ती, बहराइच व सिद्धार्थनगर में किसानों की दशा सुधारने व पानी की समुचित व्यवस्था हो। इसके लिए रिंग बोरिंग व डीप बोरिंग कर भूमिगत जल का उपयोग जरूरी है ताकि कृषि व आम जनजीवन को खुशहाल व समृद्धशाली बनाया जा सके।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस क्षेत्र में रिंग बोरिंग व डीप बोरिंग किए जाने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए।

(पांच) महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर) : महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के जिलों के किसानों के लिए सिंचाई हेतु घोषित की गयी लघु तथा वृहत परियोजनाएं वन क्षेत्र होने के कारण आज भी पलवित हैं जिससे किसानों के लिए बनायी गयी सिंचाई परियोजनाओं में लगातार देरी हो रही हैं तथा साथ ही ऐसी परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो रही है। पर्यावरण विभाग की ओर से नो ओब्जेक्शन प्रमाण-पत्र क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए नहीं दिया जा रहा है अथवा देरी की जा रही है। केन्द्र शीघ्र इसके समाधान हेतु कदम उठायें जिससे विदर्भ क्षेत्र के किसानों का हित हो सके।

(छह) उत्तर प्रदेश के कानपुर में टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया के भूतपूर्व कर्मचारियों को उनके आवास से निकाले जाने को रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर) : टेनरी एण्ड फुटवेयर कारपोरेशन आफ इंडिया कम्पनी जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है, का भारत सरकार

[श्री राजाराम पाल]

के भारी उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 23.5.1969 को अधिग्रहण किया था। प्रशासनिक विफलता के कारण कम्पनी को बंद कर दिया गया और श्रमिकों को वी.आर.एस. दे दिया गया। लेकिन श्रमिकों व कम्पनी प्रबंधन के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि श्रमिकों की आवासीय कालोनी एलनगंज, कानपुर कों एच.ई.सी. रांची की तर्ज पर 90 साल की लीज पर दे दिया जाएगा। इस संदर्भ में कम्पनी श्रमिकों से अंशदान के रूप में रुपया भी लिया गया व काटा गया। लेकिन अब भारी उद्योग मंत्रालय इन आवासीय कालोनी को खाली कराने हेतु पुलिस प्रशासन की मदद ले रहे हैं।

अत: माननीय भारी उद्योग मंत्री से मांग करता हूं कि इन आवासीय कालोनी में 15 हजार श्रमिक व परिवारों के साथ अविलम्ब न्याय करें ताकि इन्हें जीवनयापन हेतु छत मिल सके।

(सात) देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में श्वेत पत्र लाए जाने की आवश्यकता

श्री दत्ता मेघे (वर्धा) : मानसून हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। इस वर्ष हमारे देश में मानसून की वर्षा देर से और कम मात्रा में होने के कारण अनेक भागों में सूखे की जैसी स्थिति पैदा हो गई है, खासतौर पर उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, विदर्भ आदि स्थानों में 46 फीसदी से भी कम वर्षा हुई है। खरीफ की बुवाई प्रभावित हो चुकी है। अभी तक बुवाई के आकड़ों के अनुसार खरीफ के उत्पादन में 25 फीसदी की कमी का अनुमान है। बांधों में पानी घटने से बिजली उत्पादन में कमी आई है।

ऐसी स्थिति में किसान दोबारा बीज खरीदने की हालत में नहीं है। गांवों में पेयजल और चारे की समस्या पैदा हो गई है। हमारे विदर्भ क्षेत्र में हर 15 दिनों में किसानों द्वारा आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं। सरकार ने इस सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए क्या योजना बनाई है, इसका विस्तृत विवरण सदन को बताया जाना चाहिए। सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने, भूजल स्तर को सुधारने और बारिश के जल के संरक्षण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इन सब बातों के संबंध में सरकार को एक श्वेत-पत्र प्रकाशित करना चाहिए। धान, गन्ने, सोयाबीन और कपास को जुलाई में भरपूर बारिश चाहिए और तिलहन, दलहन की बुवाई के लिए खेतों में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। सरकार किसानों को इस दिशा में मदद करने के क्या कदम उठा रही है, इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए।

(आठ) छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित कोरबा फर्टिलाइजर्स फैक्टरी को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

डॉ. चरण दास महन्त (कोरबा) : कोरबा खाद परियोजना का कार्य सन 1962 में आरंभ किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश ज्यों ही कार्य आरंभ हुआ इस परियोजना को बंद कर दिया गया। तत्पश्चात् कोरबा खाद परियोजना का कार्य सन् 1973 में पुन: आरंभ हुआ। यह परियोजना कोयले पर आधारित थी एवं इसकी क्षमता 900 टन प्रतिदिन अमोनिया एवं 1500 टन प्रतिदिन यूरिया निर्धारित की गई थी। कोरबा उर्वरक संयंत्र की टेक्नोलॉजी एवं उत्पादन क्षमता रामागुण्डम (आंध्र प्रदेश) एवं तालचर (उड़ीसा) की उर्वरक संयंत्रों जैसी ही थी। उन दोनों परियोजनाओं को तो पूरा होने दिया गया लेकिन पुन: कोरबा परियोजना का कार्य सन् 1975 में बंद कर दिया गया। इस अवधि में लगभग 6000 टन माल (मशीनें उपकरण) एवं अन्य सामग्री जो विदेशों से आयात की गई थी, वे निर्माण स्थल पर पहुंच चुकी थी। यह मशीनें अभी तक ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। कोरबा खाद परियोजना पूर्ण होने पर आदिवासी-बाहुल्य प्रदेश का विकास होगा। इस परियोजना में कम से कम 2000 व्यक्तियों को स्थायी रूप से काम मिल सकेगा। प्रदेश शासन ने सन् 1974 में 906 एकड़ भूमि भारतीय उर्वरक निगम, कोरबा को मुफ्त प्रदान की है। इसके अलावा रेलवे साइडिंग हेतु 0.59 एकड़ व्यक्तिगत भूमि अधिग्रहण कर 0.23 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं। सन् 1962 में अस्थायी कॉलोनी बंदोबस्त के लिय 29.5 एकड़ भूमि नगद भुगतान कर अधिग्रहीत की गई। भवन निर्माण पर करोड़ों रुपया व्यय किया गया है। प्रस्तावित कोरबा खाद कारखाने पर अनुमानित 80 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। 25 वर्षों के अंतराल के बाद वस्तुओं की कीमत 12 गुनी वृद्धि हो चुकी है, जो कि आज की दर में लगभग 1000 करोड़ रुपया पहुंच चुका है। बंद पड़ी कोरबा खाद कारखाना को पुनर्जीवित कर निर्माण कार्य आरंभ किया जाये।

(नौ) गुजरात स्थित सरदार सरोवर परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने तथा इस योजना हेतु निधियों के लिए पर्याप्त उपबंध किए जाने और इसे समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व) : गुजरात सरकार सरदार सरोवर (नर्मदा) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है जो कि देश में अपनी तरह की सबसे बड़ी जल संसाधन विकास परियोजना है तथा

जिसको दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परियोजना कहा जा रहा है। सरदार सरोवर परियोजना एक बहुआयामी परियोजना है तथा इससे पश्चिम क्षेत्र का विशाल क्षेत्र लाभान्वित होता है जिसमें चार राज्य नामत: गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान शामिल हैं। परियोजना के पूरा होने पर 18 लाख हेक्टेयर भूमि से अधिक की सिंचाई की जा सकेगी। इसमें गुजरात के 12 जिलों के लगभग 4000 गांव शामिल हैं, जिसमें अधिकतर सूखा-प्रवण क्षेत्रों में स्थित हैं। राजस्थान के बाड़मेर तथा जालौर जिलों के शुष्क क्षेत्रों में लगभग 2,25,000 हेक्टेयर भूमि को भी पानी मिलेगा। परियोजना से 1370 मेगावाट जल विद्युत (अंततोगत्वा 1450 मेगावाट क्षमता) का भी उत्पादन होगा, जो कि सस्ती तथा पर्यावरण अनुकूल विद्युत है, जिससे पश्चिमी ग्रिड को स्थिरता मिलेगी तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। इससे गुजरात के साथ ही राजस्थान के कई गांवों तथा शहरी क्षेत्रों को घरेलू तथा पेयजल की भी आपूर्ति की जाती है। परियोजना से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़े हुए कृषि उत्पादन तथा पर्यावरण अनुकूल विद्युत के रूप में अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा। गुजरात सरकार भारत सरकार से बार-बार यह अनुरोध करती रही है कि इसे अवसंरचना परियोजना का दर्जा दिया जाए तथा सरकार सरोवर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया जाए तथा इसके लिए आवश्यक निधि का आबंटन किया जाए। महोदय, मैं भारत सरकार से इस मामले में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने तथा योजना के लिए यथेष्ट प्रावधान करके इसे समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं।

(दस) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति के मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अवर्षा के कारण समूचे देश में सूखे की गंभीर स्थिति निर्मित हो रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि राज्यों में पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पिछले कई वर्षों से केवल गत वर्ष को छोड़कर बारिश नहीं हुई है। इस वर्ष जिन किसानों ने खेतों में बीज बो दिये हैं उनके चेहरे पर भविष्य की चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर आदि जिलों में किसान बहुत घबरा रहा है। क्योंकि नदियों में पानी नहीं है। तालाब सूख गये हैं। ट्यूबवेलों का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। सूखा पूरे देश की समस्या बन रहा है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर आदि जिलों के साथ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जिलों में भी केन्द्रीय अध्ययन दल भेजकर वहां के किसानों की जमीनों के बोचे बीजों की स्थिति तथा पानी संबंधी अध्ययन कर सहायता के विशेष प्रबंध करवाने का सहयोग करें।

(ग्यारह) जबलपुर स्थित बारगी बांध मुख्य नहर परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने तथा इसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की परिधि में : लाए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : मध्य प्रदेश में जबलपुर स्थित बरगी डैम देश के प्रमुख बांधों में से एक है जो नर्मदा नदी पर बना है। इसकी दायीं तट मुख्य नहर परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे कृषि क्षेत्र में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ होगा। यह परियोजना विंध्य क्षेत्र में सोन एवम् रोन नदियों के कछार को जो गंगा कछार के हिस्से हैं, में भी सिंचाई व ग्रामीण विकास की दृष्टि से लाभ पहुंचायेगी। आज जब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कम वर्षा तथा सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है उसको कम करने में भी यह परियोजना सहायक सिद्ध होगी। सिंचाई के मामले में राष्ट्रीय निर्धारित अनुपात से भी कम असिंचित क्षेत्रों को कृषि की दृष्टि से सम्पन्न बनाने में यह परियोजना महत्वपूर्ण है तथा औद्योगिक व घरेलू क्षेत्रों को 78 एम.जी.डी. जल इस परियोजना से उपलब्ध होगा। भारत सरकार की जलनीति के तहत नदियों को जोड़ने की योजना में भी यह परियोजना सहायक होगी। अत: आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि देश में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर इसे एक्सीलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में शामिल करें ताकि निर्धारित समयावधि में पूर्ण होकर यह देश के विकास को गति प्रदान कर सके।

(बारह) उत्तर प्रदेश के इटावा और मध्य प्रदेश में भिंड के बीच रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल (भिंड) : गुना इटावा रेल परियोजना को अभी भिंड तक चालू किया गया है। भिंड से इटावा तब जब लाइन एवं नदियों पर पुल का कार्य पूरा नहीं किया जायेगा तब तक यात्रियों

[श्री अशोक अर्गल]

को असुविधा होती रहेगी। उक्त रेल परियोजना को पूरा करने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त भिंड-इटावा रेल मार्ग को शीघ्र पूरा किया जाये, जिससे जनता इसका लाभ प्राप्त कर सके।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को एक राष्ट्रीय पर्यटक स्थल घोषित किए जाने तथा पर्यटकों के लिए आवश्यक बुनियादी संरचना उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : उत्तर प्रदेश के नवसृजित कौशाम्बी जनपद को देश का प्रमुख पर्यटक स्थल घोषित करते हुए तत्संबंधी सुविधाएं भारत सरकार प्रदान करे क्योंकि चन्द्रवंशीय राजा कुशम्ब के नाम से इसका नाम कौशाम्बी पड़ा था। यहां श्री राम का वनगमन विश्राम स्थली चरवा, कुरईघाट है। संदीपन गुरू का आश्रम व कृष्णा सुदामा की मैत्री स्थल संदीपन घाट है। वत्सराज उदयन व उज्जैन की राकुमारी वासवादत्त की क्रीड़ा स्थली कौशाम्बी में ही है। गौतमबुद्ध एवं महावीर जैन की कर्म स्थली है। तीर्थकार पदम प्रभु की जन्मतप स्थली है। सम्राट अशोक का स्तम्भ, पूजा व साधना स्थल है। घोषित राम विहार का भग्नावशेष है। चीनी यात्री ह्वेनसांग का गमन स्थल है। 1875 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक मौलवी लियाकत अली की जन्मस्थली महगांव है, जिसका इतिहास अंडमान (पोर्ट ब्लेयर) मजार पर लिखित सरकारी गजट सेलुलर जेल का इतिहास गवाह है। प्रकृति की मनोरम छटा बिखेरती हुई हजारों एकड़ में फैली अलवारा झील है। राजा उदयन का किला है। ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी कड़ा, सिरायू है। मुगल काल में सूबे के रूप में स्थापित कड़ा ख्वाजा कडक शाह का मजार है। संत मलूक दास एवं कड़कशाह की सिद्ध स्थली है। मां शीतला धाम का प्रसिद्ध सिद्ध धार्मिक मंदिर है। जापान, तिब्बत, कोरिया, श्रीलंका, चीन, थाईलैंड आदि देशों के यात्रियों का प्रतिवर्ष आवागमन होता है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त ऐतिहासिक धरोहर को देखते हुए राष्ट्रीय पर्यटक स्थल घोषित करते हुए राष्ट्रीय मानचित्र में शामिल करते हुए सभी सुविधाएं मुहैया कराये।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले के खुर्जा में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्ध नगर) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने संपूर्ण देश में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बुलंदशहर जिले के खुर्जा में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की तत्काल आवश्यकता है मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित खुर्जा शैक्षिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ कस्बा है। इस कस्बे में न तो कोई केन्द्रीय विद्यालय है और न ही कोई केन्द्रीय पाठ्यक्रम पद्दति पर आधारित कोई विद्यालय है। यहां भी 35 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है। इसके अतिरिक्त इसके आस-पास के क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और वंचित लोगों की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। इन परिस्थितियों में, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से इस मामले पर गौर करने का अनुरोध करता हूं और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति हेतु विचार करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निदेश देने का अनुरोध करता हूं।

(पंद्रह) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 का मरम्मत कार्य किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया) : बिहार राज्य के एन.एच. 107 के 36 से 67वें कि.मी. का पथ काफी जर्जर है, जिससे आवागमन बाधित रहता है। उक्त पथ के 36वें, 41वें एव 51वें कि.मी. में अवस्थित स्क्रूपाईल तथा लौह के खम्भे परबना 10 फीट चौड़ाई का बहुत पुराना बना पुल जो राष्ट्रीय राजमार्ग के मानक के अनुसार नहीं है, काफी जर्जर हो गया है। किसी भी समय उसके ध्वस्त हो जाने की संभावना है। उक्त पथ जब से राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित किया गया तब से अब तक उसके निर्माण का कोई कार्य नहीं किया गया। यह काफी महत्वपूर्ण पथ है, जो अनुमंडल जिला को राजधानी से जोड़ती है।

अत: राष्ट्रीय राजमार्ग-107के 36 से 67वें कि.मी. पथ के निर्माण के साथ इसमें पड़ने वाले स्क्रूपाईल ब्रिज एवं लौह के खंभे पर बने पुल के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग मानक के अनुसार उच्चस्तरीय सीमेंट क्रव्वीट पुल का निर्माण कराया जाये।

(सोलह) वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारत लौटकर आने वाले बेरोजगार अनिवासी भारतीयों के लिए कल्याण निधि की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए. सम्पत (अटिंगल) : वैश्विक आर्थिक संकट के कारण लगभग 2 लाख अनिवासी भारतीय या तो भारत लौट चुके है या लौटने की प्रक्रिया में है। अकेले केरल से ही लगभग 3 मिलियन

लोग जीविकोपार्जन के लिए विदेश गए हुए है। इनमें से अधिकतर लोग मध्य-पूर्वी देशों में गए हुए है। उनके द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा के रूप में राज्य को कुल बजटीय सहायता के सात गुना से अधिक धनराशि भेजी जाती है। विदेशों में अन्य राज्यों से गए हुए लोगों को भी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें अपनी नौकरी चले जाने तथा हमेशा के लिए कमाई बंद होने का डर सता रहा है।

वर्तमान केन्द्रीय बजट में उनके पुनर्वास के लिए कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। उत्प्रवासन शुल्क के रूप में पहले ही 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि एकत्रित की जा चुकी है और यह धनराशि भारत सरकार के पास सुरक्षित रखी हे लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या यह धनराशि वित्त मंत्रालय या विदेश मंत्रालय या फिर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय या गृह मंत्रालय के पास है।

चूंकि अनिवासी भारतीयों की स्थिति बद से बदत्तर हो रही है इसलिए मैं भारत सरकार से केवल उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए एक कल्याण कोष की तत्काल स्थापना करने का अनुरोध करता हूं।

(सत्रह) तमिलनाडु के चेन्नई में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुबल्लूर) : भारत में लगभग एक करोड़ लोग मानसिक रूप से विकलांग हैं। उनके निकट संबंधियों द्वारा उन्हें एक बोझ माना जाता है। बदनामी, अंधविश्वास और सामाजिक आर्थिक परेशानियों के कारण उनके स्वय के रिश्तेदारों द्वारा उन्हें त्याग दिया जाता है।

देश के विभिन्न भागों के मानसिक दृष्टि से विकलांग अधिकतर बेघर लोग तमिलनाडु विशेषकर रामेश्वरम, कन्याकुमारी और वेदारणयम में है। चेन्नई के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में लगभग 400 से 500 रोगी भर्ती है। भाषा की समस्या और वित्तीय स्थिति के कारण उनकी स्थिति बेहद दयनीय है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऐसे राज्य सरकारी अस्पतालों में केवल 2500 बिस्तर है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन्हें स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लेकर सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से कम्युनिटी मैंटल हैल्थ सेन्टर्स खोलने की व्यवस्था करे ताकि अस्पतालों में लम्बे समय से बड़ी संख्या में भर्ती मानसिक रोगियों की देखभाल की जा सके।

(अट्ठारह) तीस्ता बैराज परियोजना के समापन कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार) : मैं तीस्ता बैराज परियोजना के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसका निर्माण उत्तरी बंगाल के सभी जिलों के लाभ के लिए किया गया था। यह परियोजना वर्ष 1976 में शुरू की गई थी। यह एशिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना को 500 करोड़ रु. के व्यय से तीन राज्यों में अनंतिम रूप से पूरा किया जाना था। यदि यह परियोजना समय पर पूरी हो जाती, तो उत्तरी बंगाल के किसान इस परियोजना से जल का उपयोग करके 62000 मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन कर सकते थे। न केवल इतना है बल्कि संपूर्ण उत्तरी बंगाल की मांग को पूरा करने के पश्चात् 20,000 मीट्रिक टन की अधिशेष पैदावार मौजूद रहती। इसके अतिरिक्त कृषि कार्य पर निर्भर रहने वाले किसानों को भी 40 करोड़ श्रम दिवसों का लाभ मिलता। इतना ही नहीं बल्कि उत्तरी बंगाल की मांग को पूरा करने के लिए इस मेगा परियोजना से 1300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता था। किंतु यह उल्लेख करना खेदजनक है कि 33 वर्ष के पश्चात् राज्य और केंद्रीय राजस्व से 1000 करोड़ रु. से अधिक रुपए खर्चा करने के बावजूद इस परियोजना के पहले चरण का छोटा सा विवरण ही पूरा किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस परियोजना को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए ताकि उत्तरी बंगाल में एक अन्य हरित क्रांति शुरू की जा सके और उत्तरी बंगाल के उन लोगों का आर्थिक स्तर विकसित हो सके, जो पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर हैं।

(उन्नीस) एस.एस.बी. के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के बच्चों को रोजगार प्रदान किए जाने तथा एस.एस.बी. के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को वित्तीय अनुग्रह राशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : अनेक दशकों से, देश भर में कई लाख प्रशिक्षित एस.एस.बी. स्वयं सेवक पर्याप्त राहत और पुनर्वास उपलब्ध न कराए जाने के अभाव में हतोत्साहित हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनके व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में बेशुमार मुसीबतें और परेशानियां आ रही है। त्रासदी-पीड़ित इन एस. एस.बी. स्वयं सेवकों ने युद्ध और संघर्षों विशेषकर वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध, भारत-पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान बड़ा योगदान किया है। वे अभी भी रक्षा संबंधी सूचना और डाटा तथा उग्रवाद संबंधी आसूचना आदानों को एकत्रित करने के मामले में देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए बहुमूल्य सेवाएं प्रदान

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

कर रहे हैं। ये अत्यधिक अभिप्रेरित और प्रतिबद्ध एस.एस.बी. स्वयं सेवक देश के लिए निरंतर अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। ये बी.एस.एफ., आई.टी.बी.सी. और देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रखवाली करने वाली अनेक अन्य रक्षा सेनाओं के सहायक के रूप में वास्तविक मार्गनिर्देशक और अग्रगामी जनशक्ति हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वे भारत सरकार से साम्यपूर्ण और निष्पक्ष न्याय पाने के हकदार हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त कदम उठाए:-

(एक) प्रशिक्षित एस.एस.बी. स्वयं सेवकों के बच्चों के लिए रोजगार के अवसर; और

(दो) देश की ओर से सराहना और देश के प्रति उनकी बहुमूल्य और प्रतिबद्ध सेवा की मान्यता के प्रतीक के रूप में एस.एस.बी. स्वयं सेवकों के प्रत्येक सदस्य को 12.0 लाख रु. की न्यूनतम अनुग्रह राहत अनुदान राशि।

अपराह्न 12.25 बजे

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2009-10 — *जारी*

विद्युत मंत्रालय

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब आइटम नम्बर 11 लेते हैं।

सभा अब विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74 चर्चा तथा मतदान के लिए लेगी।

सदन में उपस्थित माननीय सदस्य, जिनके विद्युत मंत्रालय से संबंधित कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं, तो वे उनके द्वारा पेश किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या को सूचित करते हुए 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को पेश किया गया माना जाएगा जिनके बारे में सभा पटल पर सूचना प्राप्त हुई है।

ऐसे कटौती प्रस्तावों के क्रम संख्या को दर्शाने वाली एक सूची, जिन्हें पेश किया गया माना गया है, उसके तुरंत पश्चात् नोटिस बोर्ड में लगा दी जायेगी। यदि कोई सदस्य सूची में कोई विसंगति पाते हैं, तो वे कृपया इसकी सूचना तुरंत सभा पटल के अधिकारी को दें।

[अनुवाद]

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 74 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2009-10 के लिए विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृति अनुदानों की मांगों की राशि		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
74	विद्युत मंत्रालय	2205,91,00,000	629,67,00,000	5411,82,00,000	1259,33,00,000

श्री उदय सिंह (पूर्णिया) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2009-10 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा प्रारंभ करने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारत में विद्युत की स्थिति और विद्युत मंत्रालय के कार्यनिष्पादन की समीक्षा तीखी आलोचना की हकदार है। माननीय वित्त मंत्री ने विद्युत मंत्रालय के बजट अनुदान को पूर्ववर्ती स्तर 40,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये करके उदारता का परिचय दिया है। उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। परंतु भारतीय ऊर्जा क्षेत्र कई प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है जिनमें आपूर्ति संबंधी अडचनें, मांग-उपबंधन तथा वितरण में अत्यधिक वित्तीय नुकसान शामिल है और इनका कोई सरल समाधान नहीं है। परंतु जब तक सभी हितधारको द्वारा पूरी प्रतिबद्धता से युद्ध स्तर पर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक हमारी आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहेगा। मैं निष्पक्ष होकर यह बात कहना चाहूंगा कि इस खराब स्थिति के लिए अकेले सरकार ही जिम्मेवार नहीं है बल्कि स्वतंत्रता के बाद अधिकांश सरकारों ने अपनी असमर्थता या दुर्भावना किसी भी कारण के चलते यह सुनिश्चित करने में सहयोग करने का प्रयास किया कि भारत के विकास के लिए ऊर्जा की जो अत्यंत आवश्यकता है उसकी आपूर्ति कम ही रहे और यह आज भी कम ही है। नीतियां अस्पष्ट थी और जो सत्ता में थे उनके अनुकूल थीं। ऊर्जा भागीदारिता के लिए कोई स्थान नहीं था, क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा दिया गया जिसे ठीक करना अब नामुमकिन सा हो गया हैं मैं न तो जरा सा भी नाराज हुआ और न ही मुझे इस बात का खेद है कि कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में विद्युत उत्पादन की क्षमता अधिक हैं। परंतु मैं यहां राज्यों के बीच विद्यमान व्यापक असमानताओं को सामने लाना चाहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हर व्यक्ति थोड़ा विस्मित जरूर होगा।

गुजरात के मामले में, प्रत्येक 4000 व्यक्तियों पर उनके 1 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है। तमिलनाडु के मामले में यह संख्या 4000 ही है। महाराष्ट्र में प्रति पांच हजार से कम व्यक्तियों पर एक मेगावाट और कर्नाटक में पांच हजार से ज्यादा व्यक्तियों पर एक मेगावाट उत्पादन क्षमता विद्यमान है। उत्तर प्रदेश के मामले में यह आंकड़े 18,000 के पार पहुच गए हैं और स्थिति बिहार की है। उस समय बिहार और झारखंड के अधिकांश उत्पादन संयंत्र ताप विद्युत आधारित थे और वर्तमान झारखंड राज्य में सभी विद्युत उत्पादन केन्द्र कोयले से परिचालित हैं और इसमें कोयले की खपत उतनी ही होती है जितनी अविभाजित बिहार में हुआ करती थी, इस पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक 42,000 व्यक्तियों पर यहां उत्पादन क्षमता एक मेगावाट ही है। यदि यह विषमता नहीं है तो क्या है? इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इन वर्षों के दौरान विद्युत की राजनीति की शक्ति पर पूरी तरह हावी रही।

महोदय, इस क्षेत्र का प्रथम प्रमुख सुधार स्वतंत्रता के 50 वर्षों के पश्चात् राजग सरकार ने दिया था जब 2003 में ऊर्जा अधिनियम, बनाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रणाली में प्रतिस्पर्धा और दक्षता लाना था जिसमें खुली पहुंच, ऊर्जा विक्रय तथा उपलब्धता आधारित टैरिफ जैसी अवधारणाएं भी शामिल थीं। इसलिए यहां पर यह बात हम सबके लिए कई कारणों से चिंता का विषय होना चाहिए कि इन युगांतकारी सुधारों को अभी तक पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाना शेष है।

महोदय, आज भारत को उद्यीमान राष्ट्रों में से एक माना जाता है और प्राय: इसकी तुलना चीन से की जाती है। हमारे निकट के पड़ोसी होने और जनसंख्या में कमोवेश एक जैसा होने के कारण दोनों राष्ट्र 1960 से विकासशील हैं और अब एक ही वैश्विक बाजार के लिए कड़ी स्पर्धा कर रहे हैं। यह तुलना बिल्कुल स्वभाविक है। परंतु आइए इस पर चर्चा करें। संयुक्त राष्ट्र जिसके बारे में हम इस समय बात कर रहे हैं जहां विश्व की कुल जनसंख्या की 4.5 प्रतिशत जनता ही रहती है वहां विश्व की कुल विद्युत उत्पादन के 22 प्रतिशत भाग का ही उत्पादन होता है।

चीन में विश्व जनसंख्या का 20 प्रतिशत भाग रहता है लेकिन वह 16.5 प्रतिशत उत्पादन करता है। वही भारत में विश्व जनसंख्या का 17% भाग रहता है और विद्युत उत्पादन केवल 4 प्रतिशत ही है। भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 500-600 यूनिट है जो कि निम्न मध्यम आय राष्ट्र के समूह की लगभग आधी के करीब है। प्रति व्यक्ति खपत के संदर्भ में हम गाबन, जाम्बिया और यहां तक कि जिम्बाबे से भी पीछे हैं।

प्रति व्यक्ति ज्यादा बिजली खपत का आशय क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि लोगों द्वारा ज्यादा बल्ब जलाने या ज्यादा देर तक एयाकंडीशनर चलने से हैं? नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ज्यादा बिजली का उपयोग और अधिक उत्पाद के लिए किया जा रहा है फिर चाहे यह कृषि, विनिर्माण अथवा सेवा किसी भी ऐसे क्षेत्र को दी जा रही हों जो उनकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। इसलिए, कोई अचरज की बात नहीं

[श्री उदय सिंह]

कि इन दिनों जब आप कोई भी चीज उठाये भले ही ये खिलौने हो या इलेक्ट्रानिक्स वस्तुएं इस बात की पूरी सभावना है कि उस पर लिखा होगा "चीन में निर्मित"।

इसके आलोक में, कोई भी यह कह सकता है कि हमारी नियोजित क्षमता विस्तार यहां होना चाहिए था उसके आस पास ही है? यहां तक कि यह मानते हुए कि सभी नियोजित वृद्धि फलीभूत हुई हैं हालांकि हमारा रिकार्ड ऐसा नहीं रहा है। हमारा ट्रैक रिकार्ड 11वीं योजनावधि के दौरान भी बेहद खराब रहा है, यहां तक कि इस वर्ष भी हम अपनी लक्षित नियोजित वृद्धि से काफी पीछे चल रहे हैं।

विद्युत की कमी लगातार बढ़ती जा रही है जिससे आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो रही है। व्यस्त समय में विद्युत की कमी 2008-2009 में अपने उच्चतम स्तर 12 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। 148 मेगावाट (जी डब्ल्यू) उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता होने के बावजूद हम अपनी 110 जीडब्ल्यू की व्यस्त विद्युत मांग को पूरा नहीं कर सकते। विभिन्न अध्ययनों में यह सुझाव दिया गया है कि विद्युत की कम उपलब्धता और घटिया गुणवत्ता के कारण प्रतिवर्ष केवल विनिर्माण क्षेत्र को ही 22,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है जो कि कुल औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की सकल आउटपुट का तकरीबन 2.2 प्रतिशत बनता है। इसलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि 2008-09 हेतु विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कम्पीटिटिवनेस रिपोर्ट के अनुसार विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता के लिए किए गए लेखापरीक्षा में 134 राष्ट्रों में भारत काफी पीछे 108 वें स्थान पर है।

व्यावहारिक ज्ञान से पता चलता है कि 8 प्रतिशत की वार्षिक आर्थिक विकास दर हासिल करने के लिए हमें अपनी उत्पादन क्षमता में 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ोतरी करनी होगी। इसके अतिरिक्त लगातार बढ़ते घरेलू उपयोग और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जैसे आवश्यक कार्यक्रमों से विद्युत की मांग और बढ़ेगी जिससे मांग आपूर्ति संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैकिन्से विश्लेषण के अनुसार सामान्य कारोबर के परिदृश्य के परिणामस्वरूप 2017 तक 95-140 जी डब्ल्यू की कमी हो जाएगी। अतएवं, यह जरूरी है कि यह सरकार आपूर्ति के अवरोधों को हटाने के लिए सिर्फ कदम उठाने की बजाय इस दिशा में पुरजोर प्रयास करे। हमने ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान उत्पादन 78700 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है तथापि 41,000 मेगावाट के पूर्ववर्ती योजना लक्ष्यों से यह निश्चित रूप से अधिक है। परंतु क्या इसे पूरा किया जा सकता है?

औसतन भारत में एक ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा होने में चीन के तीन वर्ष की तुलना में 6 से 8 वर्ष लगते हैं। जैसा कि स्वयं माननीय मंत्री महोदय ने माना है कि ईसीपी की अडचनों, भूमि अधिग्रहण की राजनीति, आवश्यक अनुमोदन तथा उसके बाद उपस्करों की कमी के कारण विलम्ब की पर्याप्त संभावना होती है। उपस्कर विनिर्माता समस्याओं का सामना करते है जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

परियोजना पूरी करने की अवधि कम करने की तत्काल आवश्यकता है। अगर हम अपनी ईपीसी क्षमता को बढ़ाएं, आईटीआई को सुदृढ़ करें तथा औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों की संस्थापना करें तो इसमें होने वाले विलम्ब को कम किया जा सकता है। उपस्कर विनिर्माताओं की एक मुख्य शिकायत है कि उनके पास कुशल या इन संयंत्रों का निर्माण करने के लिए अपेक्षित श्रमशक्ति का अभाव है। नि:संदेह स्थल अधिग्रहण तथा अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को भी तेज करने की तत्काल आवश्यकता है।

उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई विद्युत उत्पादन इकाइयों की स्थापना करने के अतिरिक्त मौजूदा संयंत्रों के पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण और लम्बे समय तक उनके कार्यक्रम को बनाने के लिए पर्याप्त निवेश करना होगा ताकि वे अपनी उत्पादन क्षमता के शीर्ष पर रहें। हमारी संस्थापित उत्पादन क्षमता की 12% विद्युत 30 वर्ष से भी पुराने संयंत्रों से प्राप्त हो रही है। कार्यक्रम को तीव्र गति देने तथा निगरानी करने की आवश्यकता है चूंकि आर एड एम हेतु 77 संयंत्रों तथा एल ई हेतु 81 संयंत्रों के लक्ष्यों के मुकावले जनवरी 2009 की स्थिति के अनुसार क्रमश: 13 और 6 इकाइयां ही पूरी की गई हैं।

ईंधन की कमी ने हमारे विद्युत क्षेत्र को और पंगु बना दिया है। यह ध्यान में रखते हुए कि हमारी 70 प्रतिशत विद्युत उत्पादन इकाइयां कोयला पर आश्रित हैं, हम इस क्षेत्र में बड़े सुधारों की आशा कर रहे हैं।

अनुमान है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, विद्युत क्षेत्र में कोयले की मांग 650 एमएमटी तक पहुंच जायेगी जबकि संभावित उत्पादन 500 एमएमटी रहेगा। आशा है कि यूपीए-II ने अपने आप को झारखंड की राजनीति से अलग कर लिया है तथा कोयला क्षेत्र सुधारों को वह महत्व प्रदान करेगा जो इसे मिलना चाहिए। परन्तु यदि रांची की राजनीति ने कोयले को नियंत्रित किया है तो मुबई की राजनीति गैस को नियंत्रित करती है। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि सरकार ने अब, भले ही देर से परंतु सौभाग्यवश जिसे राष्ट्रीय परिसम्पत्तियां

तथा संसाधन घोषित किए है, उस पर दो भाईयों के झगड़े का ठीक ढ़ंग से निपटारा करने हेतु प्रयत्नशील है। परंतु अब बहुत हो चुका है अब, श्री शिंदे के विद्युत संयंत्रों में गैस आने दीजिये, क्योंकि हमें बिजली की जरूरत है।

यद्यपि भारत में प्रारंभिक विद्युत उत्पादन लागत अतंर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सकती है इसलिए विद्युत का औसत बिक्री मूल्य इसकी औसत उत्पादन लागत से हमेशा कम रहा है, जिससे राज्य विद्युत बोर्ड घाटे वित्तीय संकट में आ जाते हैं। तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों के अस्वीकार्य स्तर जिसे सामान्य बोलचाल में कुशलता या चोरी कहा जाता है तथा कृषि और घरेलू क्षेत्रों हेतु मुफ्त या रियायती दर पर दी गई विद्युत के लिए राज्य सरकारों से वसूली नहीं की गई राजसहायता राज्य विद्युत बोर्डों की समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। उनके नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए, रा.वि.बो. उद्योगों पर बहुत अधिक विद्युत प्रशुल्क लगाते हैं। भारत की औसत औद्योगिकी प्रशुल्क दर चीन के मुकाबले चार गुना है तथा विश्व में सबसे अधिक प्रशुल्क दर वाले देशों में से है। इसलिए, अनियमित विद्युत आपूर्ति के अतिरिक्त बहुत ही अधिक औद्योगिक प्रशुल्क दर भारतीय उद्योगों को और भी अधिक नुकसान पहुंचाती है।

जांच और त्रुटि की प्रक्रिया के माध्यम से दीर्घकालीन विद्युत क्रम समझौतों के लिए प्रशुल्क पद्धति विकसित हुई है 1990 में सुधारों की प्रथम लहर में स्वंतत्र विद्युत उत्पादकों के साथ लागत और विद्युत क्रम समझौतों के परिणामस्वरूप जिस विद्युत का उत्पादन हुआ वह राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा निर्मित संयंत्रों से प्राप्त विद्युत से अधिक मंहगी थी जिससे एक ऐसी बेचैनी फैल गई जिसे समझा जा सकता था। परंतु उस मोर्चे पर विफल रहने के बाद अब विद्युत विनियामक आयोगों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि विनियमित प्रशुल्कों के औचित्य पूर्ण निर्धारण के माध्यम से उपभोक्ताओं का संरक्षण करने और रा.वि.बो. को स्वतंत्रता देने समेत आपूर्ति क्रम के विभिन्न खंडों में कार्यकुशलता तथा प्रतिस्पर्धा लाकर आपूर्ति लागत कम करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 के दोनों उद्देश्यों को विधिवत रूप से पूरा किया जाए। कुछ स्वतंत्र रा.वि. बोर्डों ने महत्वपूर्ण परिणाम दर्शाए हैं और इसी का अनुपालन करने के लिए दूसरे राज्य विद्युत बोर्डों पर दबाव डाला जाए।

मैं पुर्नगठित एपीडीआरपी पर कुछ कहना चाहता हूं। यह अनुमान है कि हम कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों के कारण लगभग 32 प्रतिशत विद्युत गंवा देते हैं। काल्पनिक रूप से कहें तो यदि हम मात्र 12% विद्युत भी बचाएं तो आज हमारी ऊर्जा की जरूरत पूरी हो जाएगी। एपीडीआरपी आरंभ किए जाने से, राजसहायता को छोड़कर समग्र वाणिज्यिक हानियां 29000 करोड़ रु. से घटकर 27000 करोड़ रुपये रह गयी हैं, देखने से तो यह एक निराशाजनक परिणाम लगता है, परंतु इस तथ्य के प्रकाश में यह समझा जा सकता है कि राज्य विद्युत बोर्ड अपने अंदर ढाचागत परिवर्तन कर रहे हैं तथा वे इस योजना का लाम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं।

इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, मैं यह समझाने में असमर्थ हूं कि किसी और के नहीं बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री महोदय के एक आश्वासन के बावजूद पुर्नगठित एपीडीआरपी को लागू करने में दो महत्वपूर्ण वर्ष क्यों बर्बाद हो गए। मौजूदा कमियां पहले कार्यक्रम के अंतिम दो वर्षों में दिखाई देने लग गई थी और इसलिए बिना ज्यादा सोच विचार के पहले से दूसरा कार्यक्रम अपना लिया जाना चाहिए था। मैं इस पर विस्तार पूर्वक कह रहा हूं क्योंकि दो वर्षों के लम्बे अंतराल ने रा.वि.बोर्डों को भ्रामक संकेत भेजे जिसमें से अधिकांश कमी भी उत्साहित नहीं थे।

वितरण में 27,000 करोड़ रुपये की हानि हुई, जिसने समग्र रूप से इस संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र के विकास को बाधित कर दिया। अत्यधिक मांग को पूरा करने के लिए अल्पावधि में रा.वि. बोर्ड अतिरिक्त बिजली खरीदने की स्थिति में नहीं हैं जिससे अव्यवस्थित लोड शेडिग होती है तथा रा.वि.बो. की वित्तीय अनिश्चितता की स्थिति जो निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा आपूर्ति की दिशा में निवेश को निरुत्साहित करती है। इससे क्षमता विस्तार का कार्य पिछड़ जाता है। पारेषण में अकार्यकुशलता विद्युत हेतु अर्थक्षम व्यापार बाजार के विकास में भी बाधक बनता है जिसकी वजह से इनमें कम लेन देन होता है। जबकि उनमें वृद्धि के कुछ संकेत तो नजर आ रहे हैं, परंतु यह बहुत कम है। पुर्नगठित एपीडीआरपी की सफलता विद्युत क्षेत्र की उत्तर जीविता तथा विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिए वर्तमान स्थिति की अपेक्षा विद्युत मंत्रालय को अधिक आगे बढ़ने वाला द्रष्टिकोण अपनाना चाहिए। परिणामों की देख-रेख करने तथा नियंत्रण करने के लिए अपेक्षित शक्तियों के साथ नोडल ऐजसिंयों की नियुक्ति करनी पड़ सकती है। ग्यारहवीं योजना अवधि के अंत तक इन हानियों को 15% तक कम करने के लिए नियोजित लक्ष्य सुधार की वर्तमान दर पर कही दिखाई देता प्रतीत नहीं होता।

पारेषण के क्षेत्र में विनियामक मुद्दों को हल किया जाना है। राष्ट्रीय प्रभुल्क नीति 2006 के तहत सीआरसी द्वारा विनियमों की शीघ्र

[श्री उदय सिंह]

घोषणा की जानी चाहिए जिससे पारेषण प्रशुल्क को तर्कसंगत बनाना अपेक्षित है। पीजीसीआईएल पारेषण गतिविधियों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। प्रतिस्पर्द्धा लाने के लिए बराबरी का दर्जा मिलना आवश्यक है।

महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय वित्तमंत्री ने इस वर्ष पावर ग्रिड कारपोरेशन को अधिक धन उपलब्ध कराया है। लेकिन उन्हे इस पैसे का उपयोग कुशलता में वृद्धि करने तथा ऐसी परिस्थिति का निर्माण करने के लिए करना चाहिए जहां निजी कंपनियों भी आसकें तथा उनके बीज प्रति सपर्धा हो सके।

कुछ राज्य सरकारों ने चोरी को रोकने के लिए आर्थिक, कानूनी तथा सामाजिक उपायों का मिला-जुला उपयोग शुरू किया है। आर्थिक उपायों से मतलब औद्योगिक प्रशुल्क को कम करना है जिससे चोरी कम होगी। कानूनी उपायों का मतलब राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ-साथ कड़े चोरी-विरोधी कानूनों को पारित करना है। विहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश सरकारों ने कड़े कानून पारित किए हैं जिनके अंतर्गत हजारों पर अभियोग चलाया गया है तथा विद्युत की चोरी में काफी हद तक कमी आई है। वस्तुतः बिहार सरकार ने विद्युत की चोरी के मामलों की सुनवाई के लिए तीन विशेष -फास्ट ट्रैक कोर्ट' गठित करने का निर्णय लिया है। अन्य राज्यों को भी विद्युत चोरी रोकने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय को बिल्डिंग व्यवस्था में सुधार के लिए स्मार्ट कार्ड तथा इलेक्ट्रानिक मीटरों पर आधारित टेक्नालॉजी प्लेटफार्म को अपनाने की दिशा में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि वे इस दिशा में कुछ कर रहे हैं। प्रयास में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि उचित मीटरिंग तथा नकदी संग्रह हो। इन टेक्नालाजी प्लेटफार्मों की मांग में उतार-चढ़ाव के बेहतर प्रबंधन के लिए 'टाइम्स-आफ-डे मीटरिंग' शुरू करने का भी आधार बनाया जा सकता है।

महोदय, अब मैं उस विषय पर बोलता हूं जो मेरे विचार से काफी संवेदनशील है।

मैं इस तथ्य से भली-भांति परिचित हूं कि राजसहायता अलंघ्य है तथा इसके साथ खिलवाड़ करना खुदकुशी के समान है। राजसहायता सदुपयोग होना चाहिए। वर्तमान रूप में, कृषि हेतु विद्युत पर राजसहायता, जो कुल विद्युत उपयोग का लगभग 23 प्रतिशत है, अपने अपेक्षित उद्देश्य को पूरा नहीं करती है तथा संसाधनों के अकुशल उपयोग की ओर ले जाती है। पहली बात, यह अमीर तथा गरीब के बीच भेद नहीं करती समान मूल्य दर होने के कारण यह लघु तथा सीमांत किसानों की अपेक्षा बड़े भूस्वामियों को ज्यादा लाभ पहुंचाती है। ग्रिड प्रबंधकों इस 'रनअवे लोड्स' को नियंत्रित करने के लिए विद्युत को प्रतिदिन कम व्यस्त दरों में ही आपूर्ति करने की कोशिश करते हैं जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप किसान दिन भर अपने पंप चालू अवस्था में छोड़ देते हैं। इसके चलते भू-जल स्तर नीचे जा रहा है, पानी का जमाव होता है तथा लवणता बड़ी है जिससे खेती योग्य भूमि की कमी हुई है तथा इसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक लोड के चलते लगातार कम बोल्टेज बने रहने से ट्रांसफार्मरों तथा पंप सेटों का लगातार जलना होता है। इससे भी ज्यादा खराब बात यह है कि मुफ्त या राजसहायता प्राप्त विद्युत मिलने से किसान अपने पंप सेटों के अधिक ऊर्जा, कुशल पंप सेटों में बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं करते।

मेरा सुझाव है कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए तथा अंतिम प्रयोक्ता की पुराने पड़ गए विद्युत उपस्कर बदलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उदाहरण के रूप में मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जानते होंगे कि जबकि एक आधुनिक सीलिंग फैन केवल 40 वाट विद्युत का उपयोग करता है, पुराने पंखे इससे 10 गुना ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं। यही हाल कृषिगत पंप सेटों का है। कुल मिलाकर यह कि बिना मीटर की यह राजसहायता पर्यावरण सामाजिक तथा अधिक दृष्टि से अनुचित है। हमें वर्तमान राजसहायता व्यवस्था को ऐसे कार्यक्रम से बदलने की आवश्यकता है जिसमें नकदी अन्तरण जैसे कुशल सुपुर्दगी तंत्र का उपयोग करके तथा कृषि हेतु विद्युत के और तार्किक उपयोग को प्रोत्साहन देकर उसे छोटे तथा सीमांत किसानों पर बेहतर रूप से लक्षित किया जा सके। देर से ही सही, पर इस सरकार का विशिष्ट पहचान संख्या कार्यक्रम जो एक सराहनीय पहल है, उस का उपयोग उन छोटे तथा सीमांत किसानों को राजसहायता पहुचाने में ज्यादा कुशल ढंग से किया जा सकता है जिनको लक्षित कर राजसहायता की शुरूआत की गयी है...*(व्यवधान)*

सरकार को और अधिक उत्साह से ऊर्जा संरक्षण की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। अमेरिका, ब्राजील तथा चीन के ऊर्जा कुशल ट्रांसफार्मरों, सीएफएल बल्बों तथा 'डे-प्राइशिंग' के समय को अपनाकर मांग में 20 प्रतिशत तक कमी लाने में सफल रहे है। सीएफएल के संबंध में कुछ पर्यावरणीय चिंताएं हैं तथा सरकार को एलईडी बल्बों के संवर्धन की संभावना की जांच भी करनी चाहिए जो ज्यादा ऊर्जा कुशल तथा पर्यावरणी सुरक्षित है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा

संरक्षण तथा कुशलता के संबंधन के संबंध में नई-नई योजनाएं है। तथा यह आवश्यक है कि विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यान्वयन एजेन्सियों को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार बनाया जाये।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पास न्यूनतम मानक पूरा नहीं करने वाले उत्पाद के उत्पादन, बिक्री तथा आयात पर रोक लगाने के लिए न्यूनतम दक्षता मानकों को लागू करने का कानूनी अधिकार है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं इसे रख देता हूं, पढ़ता नहीं हूं। अगर इसमें एक-दो गलतियों हो जाए तो माफ कीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री उदय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारा पढ़कर नहीं बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

प्राधिकारियों के अधिकारों का उपयोग इसे प्रभावी बनाने के लिए वास्तविकता से लागू करने की आवश्यकता होती है। इसे केवल कानून की किताबों में नहीं रहना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री उदय सिंह : अब तो मैं पढ़कर नहीं बोल रहा हूं। ये बजटरी ग्रांट है, इसे कंठस्थ कर लूं, आप पढ़ लेंगे। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना पर मुझे बोलना है।

[अनुवाद]

अब मैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर आता हूं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस सदस्य इस परियोजना को लेकर काफी चिंतित होंगे। एक भाजपा सदस्य के रूप में मैं स्वयं चिंतित हूं- इस तथ्य के अलावा कि यह काफी महत्वपूर्ण उपाय है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। यह हमारे देश के सबसे बड़े नेता तथा अत्यधिक कर्मठ नेता के नाम से जुड़ा है। लेकिन जिस प्रकार से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिस प्रकार से इस कार्यक्रम की रचना की गई है, इसका बुरा हश्र होने वाला है। यद्यपि कारण व्यापक हैं मैं केवल कुछ कारण आपको बताऊंगा।

2004 की परिभाषा के अनुसार किसी गांव में कम से कम 10 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को विद्युत कनेक्शन मिलने पर ही उस गांव विद्युतीकृत गांव कहा जा सकता है। यह परिवर्तन पहले के सीमित परिभाषा से अलग एक स्वाशत योग्य परिवर्तन है। लेकिन अब एक परिस्थिति की कल्पना करें जहां एक गांव में 10% गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के पास विद्युत कनेक्शन है, 90% के पास नहीं है तथा शत प्रतिशत गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे परिवारों के विद्युत कनेक्शन नहीं है, तो क्या आप सोचते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा? यह गांव में जिस तरह के सामाजिक विवाद, सामाजिक तनाव को जन्म देगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अतएव, मैं सरकार से इसपर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में ही सभी को कनेक्शन देने का प्रावधान है चाहे वे ए.पी.एल. हों अथवा बी.पी.एल.। बी.पी.एल. के लिए इसमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि कनेक्शन नि:शुल्क होगा, जबकि ए.पी.एल. के लिए यह कहा गया है कि इसके लिए शुल्क लिया जाएगा। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है? मैं बिहार में स्वयं अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा होता देख रहा हूं। उदाहरणार्थ, पुर्णिया में 3,66,000 बी.पी.एल. परिवार हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 25,650 कनेक्शन दिए जाएंगे। अब, शेष का क्या होगा?

दूसरी बात यह है कि इस एक फेज वाले ट्रांसफार्मर के लिए बनाई जा रही अवसंरचना के प्रकार पर विचार किया जाना चाहिए। बात यह है कि 16 तथा 25 के.वी.ए. ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा रहे हैं। यद्यपि वहां 11 के.वी.ए. की लाइन जा रही है, लेकिन ग्रामीण अवसंरचना में मात्र एक फेज वाला 16 के.वी.ए. अथवा 25 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर होगा। हम इस संबंध में काफी चिंतित हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है। हमें तीन फेज वाला लाइन चाहिए। हम ऐसा कनेक्शन चाहते हैं जो घरेलू उपयोग के अलावा भी उपयोगी हो। हम इस प्रकार की अवसंरचना चाहते हैं जिससे सभी को कनेक्टीविटी मिल सके। हम समावेशी विकास की बात करते हैं। दूसरों की अपेक्षा स्वयं आप समावेशी विकास पर ज्यादा जोर देते हैं। अत:, आपको यह जानना चाहिए कि अगर आप मात्र 16 के.वी.ए. अथवा 25 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर देते हैं, तो किस प्रकार समावेशी विकास होगा। अत:, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरी काफी आश्चर्यजनक बात यह है कि निर्दिष्ट लागत मानदंड है। लागत मानदण्ड यह है कि ग्राम विद्युतीकरण की लागत 14 लाख

[श्री उदय सिंह]

रुपए होगी...*(व्यवधान)* इसकी लागत 14 लाख रुपए होगी। आप सभी गांवों के लिए एक नियत राशि कैसे रख सकते हैं? हम सभी यह जानते हैं कि किसी गांव अधिक अथवा कम लागत लग सकता है। अत:, मैं यह आशा करता हूं कि ये मात्र निदर्शी प्रयोजन के लिए है, न कि वास्तविक प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश। अत: इनके साथ मुद्दे ये हैं:

तीन फेज वाला लाइन, ग्राम अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण तथा आर.जी.जी.वी.वाई. के लिए फ्रैंचाइजी। मैं यह सुझाव दूंगा कि पंचायत संस्थाओं को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि ये लोग ही परिसम्पत्ति की देखभाल करेंगे; ये लोग ही यह सुनिश्चित करेंगे कि परिसंपत्तियों के वितरण को बेचा अथवा नष्ट नहीं किया जाए तथा सामुदायिक भागीदारी बढ़ेगी। अत:, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री उदय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट और बोलूंगा।

मान्यवर, इस सरकार के साथ एक फैशन सा बन गया है कि इनसे जो कहें, ये ट्रैफिक पुलिस की तरह हाथ कर देते हैं कि आप राज्य सरकार की तरफ चले जाइए। हम इनसे जिस किसी भी कार्य के लिए कहते हैं, ये हमें राज्य सरकार की तरफ भेज देते हैं। उस दिन, पिछले शुक्रवार को, पता नहीं कोई खास वजह होगी, आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी, बहुत गुस्से में थे। 'नरेगा' पर एक प्रश्न था, उसके ऊपर बहुत गुस्से में थे और सांसदों को करीब-करीब हंस कर यह कह रहे थे कि तुम्हारे राज्यों ने काम नहीं किया। अब किसी के राज्य ने काम किया हो या नहीं, केन्द्र ने काम किया हो या नहीं, सांसद ने काम किया हो या नहीं, पिस तो गरीब आदमी रहा है। इस प्रकार गरीब आदमी पर हंसने का हम लोगों को क्या अधिकार है, क्या हमें यही करना चाहिए? उस दिन हमारे आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी बता रहे थे कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता और सांसदों को कह रहे थे कि राज्य सरकार से कहो कि वे जल्दी-जल्दी पॉवर प्लांट लगाएं।

महोदय, बिजली को स्टेट लिस्ट से, कन्करेंट लिस्ट में इसलिए लाया गया था कि केन्द्र सरकार की ज्यादा कड़ाई के साथ यह काम कर सके, लेकिर अगर हमें यही सुनना है, तो क्या केन्द्र सरकार ने अपने आपको देश का बैंकर और एडवाइजर बना लिया है? अगर इनको फैडरल सिस्टम में इतनी तकलीफ है, तो सबसे पहले ये ही चिल्ला पड़े थे, जब हमारे पूर्व प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिर्फ कहा था कि हमारे संविधान में शायद कुछ ऐसी चीजें हों, जो आज के हिन्दुस्तान, आज के भारतवर्ष को तरक्की की तरफ ले जाने में बाधक बन रही हों, तो एक एक्सपर्ट ग्रुप उसे देख ले। उस समय ये तो ऐसे शोर मचाने लग गए जैसे हम लोग कोई संविधान को निगल गए हों। संविधान कौन ने निगला और हमने कैसे निकाला, वह सब को मालूम है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : महोदय, मैं यहां हस्तक्षेप करना चाहूंगा। यह पूरी तरह से गलत है। यह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संविधान में संशोधन से संबंधित था। वे पूरी अवधारणा में परिवर्तन करना चाहते थे। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। हम उस पक्ष से आंदोलित थे। ये दो मुद्दे पूर्णतया अलग हैं।

[हिन्दी]

श्री उदय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस समय चूंकि इस सदन का सदस्य नहीं था, इसलिए मैं अपने साथियों की बात मानूंगा। मेरे पास इस समय उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे साथीगण कह रहे हैं कि...*(व्यवधान)* यह गलत है, तो हो सकता है, यह गलत हो,...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : प्रमोशन में 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन हमने बढ़ाया था।...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह : मैं अब राज्य सरकार की बात पर आ रहा हूं। राज्य सरकार की बात बहुत की जाती है। अब जरा राज्य सरकार की कहानी सुनिए। जब बिहार, झारखंड से विभाजित हो गया, तो हमारे पास, लालू जी जरा ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई बिजलीघर नहीं बचा, जो बिजली पैदा कर सके। हमारे पास दो पॉवर हाउस, बरौनी और मुजफ्फरपुर थे, वे दोनों क्षीण हालत में थे, यह सबको मालूम है। हमने एन.टी.पी.सी. के साथ बात की, एग्रीमेंट किया और एन.टी.सी.पी. को यह काम सौंपा गया कि आप उन्हें ठीक कर दें और उन्हें ठीक करने के लिए 1000 करोड़ रुपए भी तय हो गए। 'योजना आयोग', जिसे आजकल लोग 'योजना-रोग' कह रहे हैं। योजना आयोग ने उस पर मोहर भी लगा दी, लेकिन आज तक वह 1000 करोड़

रुपए हमें नहीं मिले। उसके बाद सुनिए, जब हमारे पास बिजली का उत्पादन करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम तो केन्द्रीय क्षेत्र पर ही आश्रित होंगे। हम 2500 मेगावाट रोज बिजली मांगते हैं, लेकिन केन्द्र के लोगों ने कहा कि नहीं 2500 नहीं देंगे, 1500 मेगावाट देंगे। हमने कहा कि हमारे पास बिजली पैदा करने का कोई और तरीका नहीं है, इसलिए चलो, 1500 दे दो, लेकिन वही काफी नहीं था, हमें आप केवल 800-900 मेगावाट ही बिजली देते हैं। आप बिहार के साथ ऐसा क्यों करते हैं, वह भी मैं बताना चाहता हूं, इसलिए करते हैं माननीय मंत्री जी के पहले लालू जी नहीं चाहते थे कि बिहार को बिजली जाए, क्योंकि एन.डी.ए. सरकार के समय कहीं बिहार को बिजली मिल गई, तो इनका क्या होगा? अब इनका क्या हुआ, वह तो बिहार के लोग बता रहे हैं। अब एक फितूर कांग्रेस पार्टी के दिमाग में घुस गया है और वह फितूर यह है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब हम मुक्त हो गए हैं और जितने भी हमारे मित्र वगैरह थे वे बिहार चले गए, केन्द्र में भी हम दुबारा आ गए हैं, इसलिए अगर हम बिहार में यह दिखाएं कि एन.डी.ए. सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो शायद हमारी सरकार बन जाए। आप बिहार की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री उदय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, केवल पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी पांच मिनट कहते हैं। आप कृपया समाप्त कीजिए।

श्री उदय सिंह : माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बिहार मजबूरी के सामने घुटने नहीं टेकता है। बिहारी मजबूरियों से लड़ना जानते हैं, बल्कि जब मौका आता है तो दूसरों को मजबूर कर देते हैं। लालू जी ने आपको मजबूर कर दिया था न, आपके सिर पर आठ मंत्री बिठाए हुए थे। यह बिहारी ही कर सकता है। बिहारी अपनी मजबूरी को झेल लेता है। इसलिए हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि पावर सैक्टर में इसलिए काम नहीं हो रहा है कि राज्य सरकार काम नहीं कर रही है।

अब जरा आगे चलिये। अभी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मुझे 2-4 मिनट का समय और चाहिए। *...(व्यवधान)* अगर आप पहले कह देते तो मैं हिन्दी में बोलने लगता। इसमें कौन सी बात है। प्रधानमंत्री जी को हमने लिखा, माननीय मंत्री जी सुनिएगा, क्योंकि आप डायरैक्टली कनैक्टिड नहीं हैं, उससे आपको भी लाभ मिलता।

[अनुवाद]

बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में बताया गया है:-

"खनिज तथा उत्खनन उद्योगों की कमी के दृष्टिगत हमने अपने प्रतिस्पर्धी कारक लाभ को कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर केन्द्रित किया है। राज्य सरकार द्वारा इथनाल के उत्पादन के लिए 5 बिलियन डॉलर के निवेश से 3000 मेगावाट के सह-उत्पादन वाली 23 नई चीनी मिलों तथा मेगा परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।"

विधेयक सहमति के लिए यहां रखा हुआ है। यह वापस नहीं गया है। बल्कि वापस क्या गया है एक आदेश गया है कि गन्ने से सीधे इथनाल का उत्पादन करने हेतु मौजूदा चीनी मिलों को ही अनुमति दी जाएगी। बिहार के लिए आपने यही किया है।

पुन: पत्र में यह लिखा गया है तथा यह सीधे आपसे संबंधित है:-

"राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड ने 14 ताप विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी है जिसकी कुल क्षमता 17,817 मेगावाट होगी और यह राशि 72,511 करोड़ रुपए होगी। यह बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली 5000 मेगावाट की नई उत्पादन इकाई के अलावा है। ये सभी परियोजनाएं कोयला लिंकेज के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। यह दु:खद है कि हमारी ऊर्जा उपलब्धता में सुधार के लिए न तो ग्यारहवीं और न ही बारहवीं योजना परियोजनाओं के लिए कोयला लिंकेज उपलब्ध हैं।"

[हिन्दी]

आप बोल रहे हैं कि राज्य सरकार नहीं करती है। यह लीजिए, राज्य सरकार क्या करे, प्रधानमंत्री से ऊपर कौन सा दरवाजा है, हम कहां खटखटायें। हमारी बात ही नहीं सुनी जाती है।*...(व्यवधान)* बस मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं।

मैंने सदन में यह पहले कहा है, आज फिर कह रहा हूं। यहां हम सभी सांसद हैं। हममें से किसी का दिल यह इजाजत नहीं देगा, हममें से किसी की यह जुर्रत नहीं है कि हम अपने क्षेत्रों में जाकर अपने क्षेत्रवासियों से यह कह सकें कि भाई देखो, हम तुम्हें बिजली नहीं दे सकते, हम तुम्हें रोजगार नहीं दिलवा सकते, हम तुम्हें शिक्षा

[श्री उदय सिंह]

नहीं दे सकते, हम तुम्हें स्वास्थ्य सेवा नहीं दे सकते, क्योंकि भईया, यह संघीय मामला है और संघीय व्यवस्था के अंतर्गत यह राज्य का मामला है और मैं तो सिर्फ सांसद हूं। उसी तरह कोई विधान सभा का सदस्य (विधायक) जाकर यह नहीं कह सकता कि क्योंकि, यह मामला केन्द्र का है, इसलिए वह अपने क्षेत्रवासियों के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए करना यह है? यह मामला आपस में दोषारोपण का तो है नहीं, आरोप-प्रत्यारोप का तो है नहीं, यह बिल्कुल साफ है मैंने जैनरेटिंग कैपेसिटी के बारे में सब पढ़कर बता दिया। अन्त में मैंने बता दिया कि बिहार के कौन-कौन से प्रपोजल्स यहां पर पैंडिंग हैं। दोनों से यह सिद्ध होता है कि यहां केन्द्र सरकार शुद्ध रूप से राजनीति कर रही है, इसलिए इस राजनीति को बंद किया जाये।

मैं इतना ही कहते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा *[अनुवाद]* कि हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक डा. होमी भाभा ने एक बार कहा था और मैं उद्धृत करता हूं:

"कोई भी बिजली, बिजली नहीं होने की तुलना में ज्यादा मंहगी नहीं है।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2 बजे के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.58 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2009-2010 — *जारी*

विद्युत मंत्रालय

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आइटम संख्या 11 — वर्ष 2009-2010 के लिए विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा करेंगे।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) : आरदणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऊर्जा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

आप जानते हैं कि बिजली आधुनिक विकास का एक प्रतीक है। यदि किसी गांव में बिजली नहीं होती है, तो लगता है कि विकास की गाड़ी वहां तक नहीं पहुंची है। मैंने अनेक ऐसे उदाहरण देखे हैं कि यदि किसी गांव में बिजली नहीं है, तो उस गांव में बेटी की शादी करने से लोग मना कर देते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण है कि जब हम क्षेत्र में जाते हैं, तो जो-जो गांव या मज़रे इससे बचे हैं, उनमें विद्युतीकरण करने के लिए एमपीलैड फंड की मांग भी की जाती है।

उपाध्यक्ष जी, यह क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते समय तीन प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख किया था। सबसे पहली चुनौती जिसका उन्होंने उल्लेख किया था, वह है

[अनुवाद]

अर्थव्यवस्था को जल्दी से जल्दी पूर्व की 9 प्रतिशत विकास दर की ओर ले जाने हेतु।

[हिन्दी]

नौ प्रतिशत रेट ऑफ ग्रोथ लाना तभी संभव है जब हर क्षेत्र का विकास हो, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, यह तभी संभव है जब विद्युत की उपलब्धता हो। बिना बिजली के न कृषि का विकास हो सकता है, न उद्योगों का विकास हो सकता है और न ही सर्विसेज़ सैक्टर्स का विकास हो सकता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। पहला, सन् 2012 तक ऊर्जा का कन्जम्शन एक हजार यूनिट प्रति व्यक्ति उपलब्ध होगा, दूसरा, सन् 2012 तक हर घर तक बिजली उपलब्ध हो जाएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है और इसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि विद्युत की उपलब्धता हो। आज जैसी स्थिति है, उसे देखते हुए यह संभव नहीं लगता। इसके लिए हमें विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करनी होगी, आज देश में एक लाख 48 हजार मेगावाट की उत्पादन क्षमता है जिसमें 94 हजार थर्मल पावर, 37 हजार जल, विद्युत और बाकी 4 हजार 120 परमाणु ऊर्जा उपलब्ध है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी हर इकाई साल में एक बार ऐनुवल मेनटेनैंस के लिए बंद की जाती है, कुछ रिपेयर के लिए बंद की जाती है। इस तरह

लगभग 15 प्रतिशत इकाइयां साल में बंद रहती हैं। एक लाख 48 हजार मेगावाट में से 15 प्रतिशत वैसे कम कर दीजिए। बची हुई क्षमता में 85 से 86 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर रहता है। इस तरह हमारी उपलब्ध उत्पादन क्षमता लगभग एक लाख 10 हजार मेगावाट रह जाती है। हमारे डौक्यूमैंट्स में यह उल्लिखित है और यह मान्य है कि पीक लोड में समय लगभग 11 से 12 प्रतिशत डैफीसिट विद्युत क्षमता है। उसे पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, यह प्रस्ताव भी यूपीए सरकार द्वारा, ऊर्जा मंत्री जी द्वारा रखा गया है। यह इसी बजट में है। ग्यारहवीं योजना में इसका उल्लेख है कि हम विद्युत की 78 हजार मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे। उसमें लगभग 20 प्रतिशत हाइड्रो, 76 प्रतिशत थर्मल और बाकी परमाणु विद्युत सर्जित करेंगे।

उपाध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी इसका उल्लेख किया गया था कि हम प्रति वर्ष 13 हजार मेगावाट बिजली सर्जित करेंगे। एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना ऊर्जा मंत्री जी के विवेक और दूरदर्शिता से आई है और वह अल्ट्रा मेगा पावर प्रौजेक्ट है। चार हजार क्षमता के अल्ट्रा मेगा पावर प्रौजेक्ट्स पीपी मॉडल के अंतर्गत बनाने का निर्णय लिया गया है। यह बिल्कुल नया कन्सेप्ट है। इसमें पीएफसी के माध्यम से जमीन एक्वायर की जाती है, पानी का लिंकेज स्थापित किया जाता है, कोल माइन्स का लिंकेज स्थापित किया जाता है और यह सब करने के बाद बिडिंग के लिए ऑफर दिया जाता है। जब यह सब हो जाता है, पीपी के अंतर्गत प्राइवेट इंटरप्रिन्योर देखता है कि ये सब सुविधाएं पहले ही उपलब्ध हैं, इसकी सारी तैयारी हो चुकी है और उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना है, तब वह आता है और जल्दी इसके लिए ऑफर देकर बहुत सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित होगा। संभवत: आपको जानकारी होगी कि इन प्रौजेक्ट्स के माध्यम से सस्ती बिजली के लिए एक जगह से एक रुपये 77 पैसे प्रति यूनिट का ऑफर आया और दूसरी परियोजना से एक रुपये 19 पैसे प्रति यूनिट का ऑफर आया। यह बहुत ही लाभप्रद योजना है जिसे यूपीए सरकार बिजली की समस्या का समाधान करने एवं विकास के लिए लायी है। हाइड्रो प्रौजेक्ट की भी बहुत आवश्यकता है, इसलिए इस पर जोर दिया गया है। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में अनेक जगहों पर इन योजनाओं को प्रारंभ किया गया है। इससे जहां एक ओर वहां की अर्थव्यवस्था में सुधार आयेगा, वहीं दूसरी तरफ वहां लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके साथ-साथ हमारी विद्युत आपूर्ति की क्षमता बढ़ाने के अभिमान में, कार्यक्रम में मदद मिलेगी।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एपीडीपीआर यानी त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम योजना प्रारंभ की गयी है। राज्य के विद्युत परिषदों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए उनका पुनर्गठन अधिकांश जगह किया गया है। उसके साथ-साथ एनर्जी ऑडिट की व्यवस्था भी इसके माध्यम से की गयी है। हम बिजली का उत्पादन करते रहें, लेकिन जब यह पता न हो कि बिजली कहां गयी है, क्या उसके सापेक्ष हमें रिवेन्यू मिला, कहीं चोरी तो नहीं हो रही है, आदि के लिए एनर्जी ऑडिट की व्यवस्था की गयी है। इसकी बहुत वर्षों से आवश्यकता थी और यह बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से अब तक जो नतीजे आये हैं, उनसे पता लगा है कि पूरे हिन्दुस्तान में 80 प्रतिशत फीडर मीटरिंग की व्यवस्था की गयी है। 86 प्रतिशत उपभोक्ताओं के वहां मीटरिंग की व्यवस्था हो गयी है। 23 राज्यों में 100 प्रतिशत फीडर मीटरिंग की व्यवस्था है। इस तरह से किस फीडर से कितनी बिजली जा रही है और उसके बाद वह कहां चली गयी है, उसकी जवाबदेही बढ़ गयी है। इस तरह से एनर्जी ऑडिट के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है, इसके लिए मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना यूपीए सरकार की भारत निर्माण के अंतर्गत फ्लैगशिप...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पन्ना लाल पुनिया : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने अपनी बात शुरू ही की है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री पन्ना लाल पुनिया : आप मुझे थोड़ा समय और दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह बहुत से लोग बोल नहीं पायेंगे।

श्री पन्ना लाल पुनिया : राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत यह बहुत ही क्रान्तिकारी योजना है। वर्ष 2009-10 के लिए 7 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 28 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में एक नयी क्रान्ति का सूत्रपात हुआ है। जहां लोग समझते थे कि बिजली सिर्फ शहरों में ही उपलब्ध रहती है, वह आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे कि हर घर तक बिजली पहुंचे। हर घर तक बिजली तभी पहुंचेगी जब राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें इसमें दिलचस्पी लेकर इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलायेंगी।

[श्री पन्ना लाल पुनिया]

मान्यवर, मैं एक-दो सुझाव देना चहूंगा। विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि का जो कार्यक्रम सरकार ने बनाया है, उसमें पिछले दो सालों में जितना सोचा गया था, उतनी वृद्धि नहीं हुई है। उसके अनेक कारण हो सकते हैं। जब नये प्रोजेक्ट्स लगते हैं, तो उनमें प्रोजेक्ट इक्विपमैंट्स की आवश्यकता होती है। हमारे पास प्रोजेक्ट इक्विपमैंट्स सप्लाई करने के लिए सिर्फ एकमात्र बीएचईएल है। चीन में बीएचईएल जैसी पांच कम्पनियां हैं। हम क्यों नहीं इस तरह की कम्पनियां डेवलप कर सकते हैं, ताकि यह क्षमता हमारे पास उपलब्ध रहे।

प्रोजेक्ट इक्विपमेंट के अलावा ऐश हैण्डलिंग, कोल हैण्डलिंग के लिए भी हमारे पास ज्यादा वेंडर्स नहीं हैं, इसको हमें एनकरेज करना चाहिए। पीएलएफ में सुधार आना चाहिए। हमारी मशीनें पुरानी हैं, कोल की कमी आ जाती है, कोल की क्वालिटी खराब होती है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं रहती है, पैसे की व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। इन सभी चीजों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। यदि हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो इन सभी की व्यवस्था करनी होगी, हर प्लांट की अलग से मॉनीटरिंग और समीक्षा करनी होगी तथा उसमें जो समस्याएं हैं, उनका निदान करने का प्रयास करना होगा।

मान्यवर, वैकल्पिक ऊर्जा पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और विशेषकर सौर ऊर्जा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फोटोवोल्टिक सेल्स वाली टेक्नोलॉजी महंगी हैं, इसके ऊपर हमने ज्यादा आर एंड डी नहीं किया है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। विकासशील देशों में विद्युत की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने न ज्यादा समय दिया है, न ही ज्यादा धनराशि व्यय की है। हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री पन्ना लाल पुनिया : राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में कुछ कमियां हैं। राज्य सरकारों द्वारा जिस ढंग से इसको लागू करना चाहिए, उसमें बहुत सी कमियां हैं। जगह-जगह पर शिकायत मिलती है कि गांव में पोल तो पहुंच गए, लेकिन कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। इसकी समीक्षा केन्द्र सरकार की ओर से होनी चाहिए। गांवों में सभी के पास कनेक्शन नहीं पहुंचे और मजरों में बिजली नहीं पहुंची है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारे अनेक साथियों ने इस विषय को उठाया है कि मजरों में बिजली नहीं पहुंची है। यदि सभी मजरों में बिजली नहीं पहुंचेगी, तो वर्ष 2012 तक, जो हमाने सपना देखा है कि हम हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, वह सपना पूरा नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में एक श्वेत पत्र जारी किया गया है जो श्वेत ही पत्र है, वह श्वेत ही है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। वह आगे की बात बताते हैं कि हम क्या करेंगे, पीछे की बात नहीं बताते हैं कि अब तक क्या किया गया है। पीछे जितना भी काम हुआ है, वह कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। जितने भी प्लांट्स लगाए गए, वह कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए। वर्ष 1989 के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी...*(व्यवधान)* और थोड़े-थोड़े समय के लिए वहां सरकारें आती रहीं। उनकी सोच दीर्घकालिक नहीं रही। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व में जो किया गया है, उसका अनुसरण करना चाहिए और अगर वे आगे ऐसा करें तो मैं उनका आभारी रहूंगा। राज्य सरकारों की यह कहने की प्रवृत्ति है कि इस काम को केन्द्र सरकार ही जाने, बात को केन्द्र सरकार पर टाल दिया जाता है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगना चाहिए।...*(व्यवधान)* मैंने आपके नेता के साथ तीन बार काम किया, तो उनका कार्यकाल बहुत अच्छा माना जाता है, अब चौथी बार मैं नहीं हूं तो आज क्या छीछालेदर हुई है, यह भी आपको अच्छी तरह से पता है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पन्ना लाल पुनिया : मान्यवर, ऊर्जा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जो भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स लगी, वह सिर्फ कांग्रेस की सरकार के समय में लगी ओर आगे भी यह काम समय आने पर होगा। श्वेत पत्र की बात यहां हुई है, मैं कहना चाहूंगा कि श्वेत पत्र में बहुत सी चीजें लिखी हैं, लेकिन दादरी प्रोजेक्ट का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। दादरी प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2004 में जमीन ली गयी, 2500 एकड़ जमीन ली गयी। एक पावर प्रोजेक्ट पांच सौ एकड़ जमीन में बन जाता है, इससे ज्यादा जमीन की आवयकता नहीं होती है। किसानों से लेकर वह जमीन दे दी गयी। उस जमीन पर आज तक एक भी ईंट नहीं लगी। क्यों नहीं यह राज्य सरकार उस जमीन के एग्रीमेंट को कैंसिल करके, उस जगह पर अपना पावर प्लांट बैठा लेती?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पन्ना लाल पुनिया : अगर उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसी उसकी क्षमता नहीं है तो यहां पर यूपीए सरकार को कह दें कि एनटीपीसी इत्यादि के माध्यम से इस काम को कराया जाए।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत दुरदर्शिता वाला एक बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। अब आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा देश का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आपने मुझे उस पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं मंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं। वह मुख्य मंत्री भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं और आज हमारे बीच केन्द्रीय मंत्री के रूप में बैठे हैं। जहां तक इस यूपीए सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2012 तक सबके घरों में बिजली पहुंचा दी जाएगी, तो मैं उस पर कुछ कहना चाहूंगा।

बिजली का उतपादन हम कई स्रोतां जैसे जल, कोयला, परमाणु, अक्षय, पवन और सौर से करते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी ने कहा है कि 78,000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। दूसरी तरफ आप देखें कि आज भी पूरे में जो 2.45 करोड़ बीपीएल परिवार हैं, अधिकांश बिजली से वंचित हैं। सरकार की योजना थी कि इन सभी परिवारों के घरों में एक बल्ब के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप भी अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो कितने बीपीएल परिवारों के घरों में एक बल्ब बिजली दी जा रही है, यह सब आप अच्छी तरह जानते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बातें न करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, हृदय प्रदेश है। मेरा ऐसा मानना हे कि अगर इसका विकास नहीं हुआ तो पूरे देश का विकास नहीं हो सकता। इस बात का उल्लेख भारत के मानचित्र में भी है, इसे हम अपने को कभी अलग नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की पिछले 15 वर्षों में 420 मेगावाट बिजली उत्पादन की उपलब्धि रही, जबकि लक्ष्य 1826 में मेगावाट का था।

पुनिया साहब अभी बोल रहे थे। मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश सरकारों में चीफ सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी का प्रदेश में बहुत बड़ा ओहदा होता है। वह सारी फाइलें लेकर जाता है। पुनिया साहब ने जो कहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे, उस समय रोजा शाहजहांपुर का पावर प्रोजेक्ट था, दूसरा, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, तीसरा, इलाहाबाद में मेजा, करछना और बारां में, चौथा, पारीक्षा- झांसी जिसकी केपेसिटी बढ़ाए जाने की बात थी और पांचवां, हरदवागंज की क्षमता बढ़ाए जाने की बात थी। इन सब पर उस सरकार ने पैसा देकर क्षमता बढ़ाने का काम किया था। आप जाकर प्रदेश की हालत देखें तो मालूम होगा कि उस वक्त ग्रामीण क्षेत्रों में जो 14 से 16 घंटे तक बिजली मिलती थी, वर्तमान में मेरे ख्याल से हफ्ते में चार-छः घंटे ही बिजली मिल पाए तो बहुत बड़ी बात समझी जाती है। इस समय वहां दो-चार घंटे ही बिजली मिल पाती है।

पुनिया साहब ने उत्तर प्रदेश सरकार के श्वेत पत्र के बारे में भी कहा। मैं भी कल उसे देख रहा था। उसमें इतनी बढ़ा-चढ़ाकर बात कही गई है, जिससे लगता है कि वर्तमान सरकार ने ही जीरो से लेकर अब तक का बिजली उत्पादन किया है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही या कोई और सरकार रही, किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसा उन्होंने श्वेतपत्र जारी किया है। ठीक है, आप 24 घंटे उत्तर प्रदेश को बिजली दे दें, तो बहुत अच्छी बात होगी। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में, दादरी प्रोजेक्ट गैस पर आधारित था, जिसमें 27500 मेगावाट बिजली पेदा करने की योजना थी। माननीय पुनिया साहब उस बारे में विस्तार से कह रहे थे। मैं कहना नहीं चाहूंगा कि यह किसकी देन है? मैंने माननीय मंत्री जी से सप्लीमेंट्री क्वेश्चयन में कहा था कि अगर उस समय गैस मिल जाती है, कांग्रेस गवर्नमेंट अगर उस समय गैस दे देती, ते उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली रहती और अन्य प्रदेशों को उसे भेजने का कार्य भी हम करते। यह उपलब्धि थी।. ..*(व्यवधान)* लेकिन आपने बड़ा सकारात्मक जवाब दिया कि हम पेट्रोलियम मंत्री जी से बात करके गैस उपलब्ध कराएंगे, ताकि वह प्रोजेक्ट चालू हो और प्रदेश आत्म-निर्भर बने। यह अच्छी बात है और इसके लिए हम माननीय मंत्री जी से बहुत आभार व्यक्त करते हैं।

राजीव गांधी विद्युतीकरण के बारे में यहां पर बात कही गयी है। यह योजना वर्ष 2005 से लागू हुई, जिसमें कहा गया कि 1.25 लाख गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। उत्तर प्रदेश की बात मैं बता रहा हूं। आज भी करीब डेढ़ लाख मज़रों में जो गांव हैं, उनमें आज भी बिजली का नामोनिशान नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमने समय-समय पर आपको पत्र भी लिखे हैं, आपने इस बजट में उनके लिए प्रावधान भी किया है। इसमें

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

आपने 100 से 200 आबादी वाले जो गांव हैं, उनमें 27000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है और कहा है कि राजीव गांव विद्युतीकरण योजना के तहत हम उनमें विद्युत पहुंचाएंगे। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में आप 20,000 किलोवाट बिजली का करंट प्रवाहित करते हैं, लेकिन छोटे-छोटे ट्रांसफोरमर्स आप लगाते हैं। उसमें एक ट्रांसफॉरमर में केवल 10 व्यक्ति कनैक्शन ले सकते हैं। वे जल्दी-जल्दी जल जाते हैं, जिससे वह योजना असफल है। मैं चाहूंगा कि बड़े ट्रांसफॉरमर आप लगाएं। अगर किसी गांव का विद्युतीकरण हो तो वहां बड़ा ट्रांसफॉरमर लगे, ताकि पूरे गांव में विद्युत प्रवाहित हो सके। होता क्या है कि आपने विद्युतीकरण कर दिया और हर गांव में एक या दो ट्रांसफॉरमर्स लगे, लेकिन कनैक्शन्स लेने वाले लोग हजारों में हैं। मैं चाहूंगा कि 10 किलोवाट का ट्रांसफॉरमर हटाकर ज्यादा बड़े किलोवाट का ट्रांसफॉरमर लगाए ताकि पूरे गांव में बिजली प्रवाहित हो और लोग कनैक्शन लेकर घर को रोशन कर सकें।

उत्तर प्रदेश की पुरानी विद्युतीकरण परियोजना पर ध्यान दें तो पता लगेगा कि अगर गांव में चार-पांच खम्बे भी लगे हैं तो मान लिया गया कि उस गांव का विद्युतीकरण हो गया। हम लोग अपनी निधि से दो खम्बे, चार खम्बे, पन्द्रह खम्बे, बीस खम्बे लगवाते हैं, जबकि निधि बहुत कम है। अभी माननीय पुनिया साहब निधि की ओर ध्यान दिला रहे थे। मैं चाहूंगा कि या तो इस निधि को बढ़ाया जाए या इस निधि को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। इस निधि को खत्म करके आप खुद विद्युतीकरण करवाएं। हमसे पेयजल के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए भी निधि मांगी जाती है। हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि है, इसलिए स्कूल और कॉलिज के लिए भी वे हमसे अपेक्षा करते हैं। लेकिन हम सब चीजों के लिए निधि दे नहीं पाते हैं और हम लोग बदनाम भी होना नहीं चाहते।...*(व्यवधान)*

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी) : आप पूछिये कि जो आप बिजली के लिए पैसा देते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय मंत्री जी को सब पता है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है कि 100 दिन में 5653 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। 2300 मेगावाट बिजली क्षमता स्थापित हो चुकी है, ऐसा आपने दावा किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई कार्यक्रम आपने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके यहां से चार आदमी और बोलने वाले हैं, उन्हें भी बोलने, का मौका मिलना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि इस पंचवर्षीय योजना में 78 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता करेंगे, लेकिन दो वर्षों में केवल 15 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाई है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, यूपीए सरकार के साथ हैं कि आपने जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य के मुताबिक कम से कम आप बिजली का उत्पादन करें। अगर देखा जाए, तो पूरे देश की इक्नोमिक व्यवस्था एक कृषि पर आर्धारित है और दूसरी विद्युत पर आधारित है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर बिजली नहीं है, तो कोई भी काम, कोई भी उत्पादन चाहे लघु उद्योग हों, बड़े उद्योग हों, किसी भी तरह के काम में प्रगति नहीं हो सकती है। छोटे-छोटे उद्यमी भी बिजली पर निर्भर करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति इतनी खराब है कि सभी कल-कारखाने, छोटे-बड़े उद्योग करने वाले व्यापारी हों, सबका काम ठप पड़ा हुआ है।

महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आप यहां से राज्य सरकार को पैसा भेजते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो श्वेत पत्र जारी किया है, मैं चाहूंगा कि कम से कम इतना कर दीजिए कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली रहे। लेकिन जो पैसा आप दे रहे हैं, उसका भी आपको मूल्यांकन करना चाहिए। आज अगर आप पैसा दे रहे हैं, तो पूरा का पूरा पैसा पार्कों में पत्थर लगाने पर, मूर्तियां लगाने पर खर्च किया जा रहा है।...*(व्यवधान)* वहां कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में पर्यावरण को इतना खतरा हो गया है कि चहे वह लखनऊ की जेल हो या नोएडा में जो पार्क पत्थर में तबदील हो रहे हैं, वहां हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए हैं। वहां पशु-पक्षी बेघर हो गए हैं, लोग मर रहे हैं।... *(व्यवधान)* आदमी को ही नहीं, पूरे पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है। आप वहां केंद्र की टीम भेजें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप देखिए कि वहां बिजली की क्या हालत है। मैं केवल एक और बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

महोदय, नए हाइडल बनाने के लिए आप जो जमीन का अधिग्रहण करते हैं, वहां जमीन का जो मुआवजा दिया जाता है, वह बहुत नामिनल

होता है। मार्केट वैल्यु पर किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। ऊसर, बंजर जमीन को अधिग्रहण करने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत किसान की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, तो मार्केट वैल्यु के आधार पर मुआवजा देना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं। उन्होंने कई बार सदन में स्वीकार किया है कि आज पूरे देश बिजली के गंभीर संकट से जूझ रहा है। केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश के बिजली संकट की बात को मंत्री जी ने स्वीकार किया है। जैसा माननीय विद्वान साथी कह रहे थे, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि किसी दूसरे हैड का पैसा किसी और हैड में खर्च नहीं किया जा सकता है। आज पूरे देश की महत्वपूर्ण आवश्यकता ऊर्जा है, जो हर आदमी के घर से, कुटीर उद्योग से शुरू हेती हैं विद्युत छोटे, कुटीर, बड़े उद्योगों के लिए बहुत आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के राष्ट्र निर्माताओं ने आजादी के बाद विद्युत क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सन् 1948 में विद्युत अधिनियम को डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। उन्होंने विद्युतीकरण को आम आदमी की अनिवार्य आवश्यकता बताते हुए इसकी जिम्मेदार केंद्र पर डाली, क्योंकि उन्हें पता था कि कृषि और ग्रामीण उद्योग, जो निजी क्षेत्र में उत्पादन करते हैं, वे बिजली नहीं खरीद पाएंगे और न ही किसानों को कृषि से इतना लाभ मिल पाएगा कि वे बिजली की उचित कीमत देकर बिजली खरीद सकें।

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आजादी से लेकर 1989 तक प्रदेश में कुछ समय अगर 2-4 महीना या सल भर छोड़ दिया जाए ते यह देखेंगे कि 42 साल तक कांग्रेस की हुकूमत रही है और 4700 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन हो पाया। 1989 से लेकर वर्ष 2002 के बीच में 13 वर्ष में 1000 मेगावाट बिजली पैदा हुई है। वर्ष 2000 में उत्तरांचल बंटने के बाद 1000 मेगावाट बिजली जो पन बिजली परियोजना एनएचपीसी के द्वारा बनाई जाती थी, अलग होने के बाद वह उत्तराखंड को चली गई और इसके बाद हमारे पास कुल 4700 मेगावाट बिजली रह गई। इसलिए मैं बार-बार उत्तर प्रदेश को लाना चाहता हूं क्योंकि बार-बार इसकी चर्चा हुई है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। वहां पर केवल 4700 मेगावाट बिजली 1989 से लेकर वर्ष 2002 के बीच में पहुंची। हम इस बात को केवल आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि जहां हम नयी बिलली नहीं पैदा कर पा रहे हैं, वहीं 1982 में ऊंचाहार तापी विद्युत परियोजना जो 420 मेगावाट की थी, एनटीपीसी को 1992 में बेच दी गई। ...*(व्यवधान)* इसीलिए तो संज्ञान में लाना चाहता हूं। अगर सरकार इस बात को नोटिस में लेती तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती।

तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2000 में टांडा तापी बिजली परियोजना जो 440 मेगावाट की थी, यह भी एनटीपीसी को बेच दी गई है। उस समय बीएसपी की सरकार नहीं थी। अब आप लोग निर्णय कर सकते हैं कि सरकार किसकी थी?...*(व्यवधान)* इस प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के विकास को भारी झटका लगा और उत्तर प्रदेश की बिजली की आपूर्ति में काफी कमी आई। वर्ष 2002 में बीएसपी की सरकार बनने के 14 वर्ष बाद 420 मेगावाट की क्षमता का जो परीक्षा विस्तार की बात हमारे साथी कह रहे थे और जहां उत्पादन शुरू हो चुका है, पूर्व की सरकारों ने ऊर्जा उत्पादन को गंभीरता से नहीं लिया और ऊर्जा उत्पादन हेतु परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गईं। इसलिए उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में विद्युत की 7500 से लेकर 8000 मेगावाट की मांग की सापेक्ष केन्द्रीय परियोजनाओं के हिस्से को मिलाकर उपलब्धता जो 6500 मेगावाट है, इस प्रकार जो डिमांड और सप्लाई में 1000 मेगावाट का अंतर रहता है और पीक ऑवर में यह लगभग 3000 मेगावाट बढ़ जाता है, इसलिए इस तरफ मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसलिए मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के उपक्रम के साथ संयुक्त क्षेत्र में भी ऊर्जा उत्पादन हेतु दो समझौते किये गये थे जिसमें मेजर परियोजना जो 1320 मेगावाट की फतेहपुर की 2000 मेगावाट परियोजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद निगम के माध्यम से जहां एक ओर जो परीछा विस्तार – 2 में जून, 2010 में 500 मेगावाट हरदुआगंज विस्तार में जून, 2010 तक 500 मेगावाट व अनपारा-डी परियोजना से दिसम्बर 2011 तक 1000 मेगावाट उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा। वहीं पर ओबरा-सी परियोजना जो 1320 मेगावाट पर हो जाएगी, इसके अतिरिक्त 5 वर्षों में 5000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है जिसमें से 1320 मेगावाट क्षमता जो अनपारा-ई परियोजना की स्वीकृति दी जा चुकी है, यह परियोजना मैं समझता हूं कि 2014 तक पूरी हो जाएगी।...*(व्यवधान)* आगे की भी बता रहा हूं। वर्तमान सरकार द्वारा इस श्रेणी में बारा परियोजना जो 1980 मेगावाट करछना परियोजना 1320 मेगावाट की स्वीकृत की है जिसका 4 वर्षों में उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा। ओबरा-सी परियोजना 1320 मेगावाट की कार्य योजना शीघ्र प्रारंभ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त पांच वर्षों में 5000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन

[श्री दारा सिंह चौहान]

क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है जिसमें से 1320 मेगावाट क्षमता अनपारा-ई परियोजना की सहमति दी जा चुकी है। मैं समझता हूं कि यह परियोजना 2014 तक पूरी हो जाएगी।...*(व्यवधान)* आप क्यों बोल रहे हैं आज तो आपको सुनने वाला भी कोई नहीं है।...*(व्यवधान)* वर्तमान सरकार द्वारा इस श्रेणी में बारा परियोजना 1980 मेगावॉट की करछना परियोजना में 1320 मेगावाट की स्वीकृति की है, इसमें चार वर्षों में उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। कुछ परियोजना दो-तीन वर्षों में आएंगी, इसमें रोजा परियोजना से जून, 2010 तक 600 मेगावाट, अनपारा-सी परियोजना से दिसंबर, 2010 तक 1200 मेगावाट और श्रीनगर परियोजना से 2011 तक 300 मेगावाट ऊर्जा मिलने लगेगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 तक 15000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन हेतु एटा में 1320 मेगावाट, सोनभद्र में 1980 मेगावाट और ललितपुर में 4000 मेगावाट व यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के अंतर्गत 2000 मेगावाट परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है।

माननीय महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा पारेषण वितरण क्षेत्र में नई क्षमता सृजन करने के लिए कई विस्तार योजनाएं तैयार की गई हैं इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में उपभोक्ता की बेहतर आपूर्ति के लिए प्रदेश में कानपुर, आगरा जैसे एनपुट बेस्ड फ्रेन्चाइजी प्रारंभ किए गए हैं। यह व्यवस्था शीघ्र ही अन्य सात शहरों में शुरू करने की योजना बनाई गई है। ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : शहरों में बिजली की कटौती पांच घंटे की है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ कर न बोलें।

श्री दारा सिंह चौहान : मैं इसके बारे में ही बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)* प्रदेश में ओवरलोडिंग की समस्या खत्म करने के लिए 1341 करोड़ रुपए की योजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। पारेषण के क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2012 तक 20000 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृति किया गया है, जिसमें से 8000 करोड़ रुपए का निवेश निजी क्षेत्र के माध्यम से किए जाने की कार्यवाही चल रही है। 452 नए विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण पर लगभग 766 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 557 सब स्टेशनों की क्षमतावृद्धि के लिए 310 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : यह श्वेत पत्र है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महेदय : आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान : यह श्वेत पत्र नहीं सच्चाई है।...*(व्यवधान)* सच्चाई देखकर सरकार कुछ बोल रही है। मैं सच्चाई को सामने लाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं में 20000 मेगावाट की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार से कोयला एवं गैस आबंटित किए जाने की सदस्यों ने मांग की है लेकिन इस संबंध में सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी केन्द्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया गया वरना इस प्रदेश में नागरिकों को 24 घंटे बिजली मिलने लगती। मैं इस तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

महोदय, वर्तमान सरकार द्वारा भारत सरकार को कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अनुरोध किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई खदान नहीं है। वहां कोयला उपलब्ध नहीं हो सकता है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से और यूपीए सरकार से कहना चाहता हूं कि राज्यों को कोयला आबंटन में वरीयता देनी चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा इस सुझाव पर कोई निर्णय नहीं लिए जाने के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब हो रहा है। केन्द्र सरकार पूरे देश में 28000 मेगावाट क्षमता के 7 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स लगाने की बात कर रही है लेकिन प्रदेश को कुछ आबंटित नहीं किया गया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी स्पीज पार्टली ले कर दें।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान : मेरे पास समय है, मुझे अपनी बात कहने दी जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अपको जितना समय दिया गया था आपने उससे ज्यादा बात कही है।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान : केंद्र सरकार के पास उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय परियोजनाओं में 1749 मेगावाट का विवेकाधीन कोटा है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के मात्र 406 मेगावाट बिजली मिलती है। उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति में लगभग 3000 मेगावाट का अंतर है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर जरूर आकृष्ट करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा है इसलिए इस तरफ ध्यान देने की

जरूरत है। उत्तर प्रदेश में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की सिंगरौली विद्युत संयंत्र की कोई न कोई इकाई अक्सर खराब रहती है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। जगदीश शर्मा जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)*

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती) : महोदय, यह उत्तर प्रदेश का मामला है इसलिए इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विद्युत उत्पादन वितरण के क्षेत्र में खामियां हैं। प्राइवेट एजेंसियों से बिजली मिलती है और वितरित की जाती है। लेकिन हरियाणा में कितनी वितरित करते हैं और यहां कितनी करते हैं?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दारा सिंह जी, आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य अपना भाषण लिखकर देना चाहते हैं, वे सभा पटल पर 'ले' कर दें।

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। आज पूरे देश में बिजली का संकट है। कुछ राज्यों को आप छोड दें तो पूरा देश बिजली संकट से गुजर रहा है और बिजली आज के समय में जीवन रेखा है। कहावत है – 'जल ही जीवन' लेकिन जल भी बिजली के बिना लोगों तक नहीं पहुंच सकता, आज यह स्थिति है। केन्द्र सरकार की इसमें जो भूमिका है, माननीय मंत्री, शिंदे साहब, अनुभवी और जानकार हैं और एक प्रश्न के उत्तर में जवाब देते समय जब यह कह रहे थे तो मैं सुन रहा था कि यह राज्य सरकारों का दायित्व हैं। मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन पूरे देश में संघीय व्यवस्था में सरकार चलती है और जो केन्द्र सरकार की भूमिका है, वह एक अभिभावक की भूमिका है। आज जो पिछड़े प्रदेश हैं, गरीब राज्य हैं, अविकसित राज्य हैं, उन्हें बिजली के क्षेत्र में विशेष अवसर देकर उनके क्षेत्रों में बिजलीकरण का काम कराना है। शिंदे साहब को मैं बताना चाहता हूं कि आप बिहार में कांग्रेस के प्रभारी भी रहे हैं और बिहार के एक-एक जिले की आपको जानकारी है। बिहार कितना पिछड़ा है, बिहार में आपने कांग्रेस प्रभारी की हैसियत से बहुत समय दिया हैं मैं उस समय विधान सभा में एम.एल.ए. था। मैं जानता हूं, आपको वहां की जानकारी है। आप जहानाबाद जैसे पिछड़े इलाके में भी गये हैं और आपको उस इलाके का पूरा तजुर्बा है। बिहार में बिजली के क्षेत्र में पिछले 15-16 सालों में एक मेगावाट बिजली बढ़ोतरी का काम भी नहीं हुआ है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के मुख्य मंत्री थे, यह इतिहास है और माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरु वहां प्राइम मिनिस्टर थे। बिहार में पहला यूनिट लगा। प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरु के नेतृत्व में श्री बाबू जो वहां के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने बरौनी, कांटी और पतरातू में यूनिट लगवाये। लेकिन झारखंड के बंटवारे के बाद पतरातू झाराखंड में चला गया और बरौनी और कांटी दो इकाई बच गईं। बिहार में जब श्री नीतीश कुमार की सरकार आई तो उन्होंने ईमानदारी से प्रयास किया और आज भी प्रयासरत हैं। आज हम बरौनी में 60, 70 और 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, जो पहले शून्य पर था। कांटी को उन्होंने एन.टी.पी.सी. के हवाले किया, समझौता हुआ। लेकिन मैं बता रहा हूं कि वहां प्रगति बहुत धीमी है। काम बहुत मंद गति से चल रहा है और यदि इसी गति से काम चलता रहा तो बिहार में बिजली के क्षेत्र हम बिल्कुल ही नाकारा साबित हो जायेंगे।

आज बिहार में सूखे की स्थिति है। सैंट्रल ग्रिड से हमारा एलोकेशन 1300 मेगावाट है। हमारे बिहार का डिमांड 2500 मेगावाट का है। 2500 के विरुद्ध आपने 1300 मेगावाट सैंट्रल ग्रिड से एलोकेट किया है और हमें आठ सौ, साढे आठ सौ मेगावाट मिल रहा है। हमें इससे अधिक नहीं मिल रहा है। मैं मंत्री से निवेदन करता चाहता हूं कि बिहार से आपका अटूट रिश्ता रहा है। आप बिहार के लिए एलोकेशन बढ़ाइये और बिहार सरकार आपका पैसा भी चुकता कर रही है। वहां की सरकार के जिम्मे आपका कोई पैसा बकाया नहीं है। जो बिहार सरकार खरीद रही है, उसका पेमेन्ट भी करती जा रही है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि कांटी का काम त्वरित गति से हो और समय सीमा के अंदर हो और बिहार का जो एलोकेशन 1300 मेगावाट है, उसे बढ़ाकर कम से कम 1500 मेगावाट तत्काल जरूर किया जाए, कृषि वहां सुखाड़ की स्थिति है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जगदीश शर्मा]

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि बिहार के प्राइवेट सैक्टर्स के कुछ प्रस्ताव बिजली उत्पादन के लिये आये थे जिन्हें बिहार सरकार ने केन्द्र के विद्युत मंत्रालय को भेजे हैं लेकिन स्वीकृति इसलिये नहीं मिली कि कोल लिंकेज नहीं है। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि आप बिहार सरकार को कोल लिंकेज दीजिये ताकि प्राइवेट सैक्टर्स को बिजली उत्पादन के क्षेत्र में मंजूरी मिल सके और बिहार विद्युत के मामले में अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके अलावा बिजली का सब से सस्ता साधन पनबिजली है। बिहार की सीमा नेपाल से लगी हुई है। नेपाल की नदियों में बराबर प्रयास चल रहा है इस प्रश्न को हमारे नेता शरद यादव जी ने बार-बार उठाया है कि नेपाल में हाई डैम बनाकर बिजली का उत्पादन किया जाये ताकि नेपात के साथ-साथ बिहार और पूरे देश को बिजली मिल सके। इसका दूसरा बड़ा फायदा बाढ़ से होने वाली क्षति से बिहार को निज़ात मिल सकेगी। बिहार बाढ़ की समस्या से मुक्त हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि केन्द्र से एक स्पेशल टीम गठित होकर जाये और इस का सर्वेक्षण करे। मैं इस सदन के माध्यम से प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह बहुत बड़ा संकट हैं कोसी त्रासदी के बारे में बार-बार पार्लियामेंट में सवाल उठता है लेकिन कोई कारगर कदम नहीं उठाया जाता है। नेपाल सरकार से समय सीमा के अंतर्गत बातचीत करके पनबिजली, जो सब से सस्ती है, के उत्पादन के बारे में प्रयास किया जा सकता है। इससे न केवल बिहार को बल्कि पूरे देश को बिजली मिल सकेगी। इस ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलाकर बहुत अच्छा काम किया है। यह योजना देश के महान नेता के नाम पर है जिन्हें हम श्रद्धा से देखते हैं। वह देश के लिये शहीद हो गये। मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार के प्रभारी मंत्री रहे हैं जिन्हें जमीनी हकीकत की जानकारी है। आज जहां-जहां बिजली का काम हो रहा है, वहां बड़ा-बड़ा बोर्ड लगा दिया जाता है लेकिन बोर्ड पर गांव का नाम नहीं लिखते हैं। आप चाहें तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं चूंकि मैं 33 साल तक विधानसभा का सदस्य रहा हूं और आज सांसद बनकर आया हूं तो मुझे मालूम है। बोर्ड पर गांव का नाम लिखा जाना चाहिये। बिहार के 24 जिले पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है? बिजली के लिये कांट्रेक्ट अलॉट करते हैं लेकिन उनके आफिसर पटना में बैठते हैं। हम एम.एल.ए. थे और आज एम.पी. हैं लेकिन आज तक किसी आफिसर से मुलाकात नहीं हुई है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर पावर ग्रिड कारपोरेशन के आफिसर से एक एम.पी. बात करना चाहे तो वह बात नहीं हो सकती है। मैं सच्चाई बता रहा हूं। यही जमीनी हकीकत है। मैं अपने क्षेत्र में गया तो पाया कि पाल गाड़ दिया गया है लेकिन तार नहीं लगा है। ट्रांसफॉर्मर लगा दिया गया। 11000 का एलटी लाइन का ट्रांसफॉर्मर लगाया गया। मैंने स्थानीय कांट्रेक्टर से पूछा तो उसने बताया कि पोल गाड़ने का काम मेरा है लेकिन ट्रांसफॉर्मर लगाने वाला दूसरा है जो पेमेंट लेकर चला गया है। स्व. राजीव गांधी के नाम पर कम से कम उस महान आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम न करें। मेरे दिल में भी दर्द है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो खमियां हैं, उन्हें दूर किया जाये। गांव में एक लाइन जा रही है जिसे कई माननीय सदस्य ने कहा है लेकिन मैं इसलिये दोहराना नहीं चाहता क्योंकि यह एक गांव का मामला नहीं सारे गांवों की बात है। 11000 एलटी की तार जा रही है, उस पर कीमती सामान लग गया है लेकिन गांव में केवल एक तार दी है उससे क्या होगा? क्या उससे टी.वी. देख सकेगा या एक बल्ब से काम चल जायेगा? गांव में आप जिसे बीपीएल कहते हैं, आज उनमें से 80 परसेंट लोग खेतिहर हैं और खेती कर रहे हैं उन्हें भी जरूरत है, आप गांव को लाइन देना नहीं चाहते है, कहते हैं कि पैसा नहीं हैं तो एक हजार गांव मत करिए, सौ गांवों को ही दीजिए। इन सौ गांवों के लिए, चाहे एपीएल हो, बीपीएल हो, एपीएल के लिए पैसा लेकर कीजिए।

महोदय, गांव में क्या हो रहा है, आपका अधिकारी जाता है, कहता है कि यह बीपीएल के लिए है। गांव में भेदभाव शुरू हो गया है। एपीएल कहता है कि हमने भी तो सरकार को वोट दिया है। इससे समाज और गांव में तनाव पैदा हो जाता है। यह योजना सबके लिए है। हम आपसे एकदम ईमानदारीपूर्वक कह रहे हैं कि इसे सबके लिए कीजिए। बीपीएल को आप मुफ्त बिजली दीजिए लेकिन इसे सबके लिए कीजिए। हम बीपीएल के लिए भी आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि बीपीएल के लिए भी आपने लिख दिया है कि महीने में इन्हें 50, 55 या 75 रुपए देने पड़ेंगे। उसके यहां बिजली नहीं हैं और उसके पास बिल जाता है तो वह कहता है, अभी वह हमें एमपी नहीं मान रहा है क्योंकि हम विधायक 33 साल से हैं। वह कहता है कि विधायक जी मेरी लाइन कटवा दीजिए। यह बताइए कि बिजली जलाने के लिए गरीब आदमी 55 रुपए कहां से देगा?

महोदय, यह निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप बीपीएल को लाइन दे रहे हैं तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए, मुफ्त बिजली दीजिए।

आप मेरे साथ चलिए, वह चाहता है कि उसकी लाइन कट जाए। ठेकेदार क्या कर रहा है, काम पूरा किया नहीं है और कागज में लाइन जोड़ दी हैं उसके पास बिल जा रहा है, इससे वहां हाहाकार मचा हुआ है। हम एक बात का निवेदन करना चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में पैसा तो 10 केवीए, और 25 केवीए का लग रहा है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपको देना ही है तो हर गांव में 100 केवीए का एल.टी.थ्री फेज़ और 100 केवीए का ट्रांसफॉर्मर दीजिए। आपके पैसे में अंतर नहीं आएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जगदीश शर्मा : यह जो 10 केवीए का है, आप उसमें टोटा फंसाने का काम रोकिए। पुलिस कहां-कहां बैठेगी, वहां चार आदमी गये, 10 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, उसमें टोटा फंसा दिया और फटाक से ट्रांसफॉर्मर जल गया। इसका क्या मतलब है, अगर आपको देना ही है तो 100 केवीए का दीजिए ताकि खेती-किसानी का भी काम हो, गांव का भी काम हो, एपीएल का भी काम हो, बीपीएल का भी काम हो यानि सर्वे समाज को इसका लाभ मिले। इससे शिंदे साहब का भी नाम होगा और श्री राजीव गंधी जी का भी नाम होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : महोदय, मैं मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं। जो बिजनेस मैन हैं, प्राइवेट लोग हैं, उन्हें तो ब्लॉक का एलॉटमेंट हो रहा है। ये इतने मामले पैंडिंग हैं और अभी माननीय सदस्य ने बिहार की बिजली की हालत बतायी है। ब्लॉक का एलॉटमेंट प्राइवेट लोगों और बिजनेस मैनों को तो हो रहा है, लेकिन सरकार के जो ब्लॉक हैं, उन्हें नहीं हो रहा है। यह आपको पर्सनली देखना चाहिए।

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : मैं इसका जवाब दूंगा। सरकारों को भी दे दिया है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सरकार को दे दिया है।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर) : महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बिहार में राजीव गांधी विद्यतीकरण योजना में सेकेंड फेज़ का कई जिलों का प्रस्ताव, डीपीआर आपके यहां एक साल से पैंडिंग है। आप उसे क्लियर कीजिए।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : इसका जवाब मैं अपने उत्तर में दूंगा।

***श्री मिथिलेश कुमार** (शाहजहांपुर) : नये हाइडल बनने पर विभाग द्वारा जो जमीन अधिग्रहीत की जाती है। जिसका मुआवजा नहीं दिया जाता है जिससे किसानों को बड़ी समस्या है। कृपया किसानों को मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की जाये।

अत: आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि 33 केवीए अथवा 132 केवीए में नये हाइडल निर्माण हेतु सरकार को जमीन की व्यवस्था कराने हेतु किसानों को मुआवजा दिलाने का निर्देश देने की कृपा करें।

अपराह्न 2.59 बजे

[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर) : सभापति महोदय, मैं यहां पर माननीय विद्युत मंत्री द्वारा यथा प्रस्तावित विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2009-10 की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय मंत्री की मंशा सराहनीय है लेकिन मुझे इस बात में संदेह है क्या ये लक्ष्य प्राप्त करने योग्य है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में देश में बिजली की मांग और आपूर्ति में अंतर को कम करने के लिए त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के लिए आबंटन को बढ़ाकर 2080 करोड़ रुपए कर दिया है। राष्ट्रीय विद्युत नीति में वर्ष 2012 तक सभी को बिजली उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिजली की क्षमता में लगभग 78700 मेगावाट की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सरकार को यह भी आशा है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रक्षित विद्युत प्रणाली के अंतर्गत 12000 मेगावाट की क्षमता वृद्धि होगी। यदि सरकार इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेती है तो यह बड़े गर्व की बात होगी।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय, इस सम्मानीय सभा में दिनांक 03-07-2009 को एक प्रश्न पूछा गया था उस समय मंत्री जी ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपेक्षित धनराशि, धनराशि की उपलब्धता और धनराशि में अंतर संबंधी विवरण सभा पटल पर रखा था। राज्य क्षेत्र में उत्पादन,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री टी.के.एस. इलेंगोवन]

पारेषण, वितरण और आर एंड एम के लिए लगभग 5,31,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। जबकि राज्यों के पास 2,51,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध है। भारत सरकार ने 2,79,000 करोड़ रुपए की धनराशि के अंतर का अनुमान लगाया है। केन्द्रीय योजनाओं के लिए 37,000 करोड़ रुपए के अंतर की कल्पना की गई है। निजी क्षेत्र में 1,04,000 करोड़ रुपए के अंतर का अनुमान लगाया गया है। अत: यहां धनराशि में कुल 4,21,000 करोड़ रुपए का अंतर है। हम इस अंतर को किस तरह पूरा करेंगे। इस अंतर को कम करने के लिए धनराशि जुटाने हेतु सरकार की क्या योजना है।

महोदय, हमने विगत में कई लक्ष्य प्राप्त किए हैं लेकिन हम योजना आयोग द्वारा बनाई गई उसकी सभी पंचवर्षीय योजनाओं विशेषकर विद्युत क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं। लक्ष्य मात्र वास्तविक ही नहीं होने चाहिए अपितु ये प्राप्ति योग्य भी होने चाहिए। मैं सरकार की आकांक्षाओं की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं सरकार की योजनाओं का पूरा समर्थन करता हूं। लेकिन कमियां निकालना और उन्हें सरकार के ध्यान में लाना भी मेरा कर्तव्य है।

महोदय, मेरे गृह राज्य तमिलनाडु में हाल ही में बिजली की भारी कमी रही है। क्योंकि पवन चक्र की विफलता के कारण पवन चक्कियां बंद हो गई जिनसे 1000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन होता था। अत: वहां भारी कमी हैं इसलिए सरकार को पावर कट बढ़ाने पड़े।

महोदय, 1999 के बाद के युग में हमारे देश के लोगों की जीवन शैली में काफी बदलाव आए हैं। बिजली के जिन उपकरणों को विलासिता के साधन माना जाता था वो आज एक जरूरत बन गए हैं। घरेलू बिजली खपत में भारी वृद्धि हुई है। अत: केन्द और राज्य दोनों सरकारों को विद्युत उत्पादन में प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। नए संयंत्रों की स्थापना और शुरू होने में समय लगेगा। विद्यमान विद्युत संयंत्रों को इस तरीके से तैयार करना चाहिए ताकि उनसे प्रतिवर्ष बिजली की आपूर्ति में वृद्धि की जा सके। तमिलनाडु में कुन्दनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना 10 वर्ष पहले शुरू की गई थी। इस संयंत्र से 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाना था। लेकिन आज दस वर्ष बाद भी वहां एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ है। पिछले वर्ष सरकार ने रूस के साथ इसी इकाई में 8000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन की क्षमता के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। मंत्री जी को यह स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए कि इस इकाई से बिजली उत्पादन कब शुरू होगा।

महोदय, एनटीपीसी ओर एनएचपीसी का नाम बदलकर नार्थ उत्तर भारत ताप विद्युत निगम और उत्तर भारत जलविद्युत निगम कर देना चाहिए क्योंकि इन दोनों निगमों ने पूरे दक्षिण भारत में एक भी विद्युत संयंत्र स्थापित नहीं किया है। अब एनटीपीसी दो विद्युत संयंत्र, एक आंध्र प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित करने पर विचार कर रही है।

महोदय, जहां तक उत्तर भारत का संबंध हैं तो यहां पर पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है। यहां बारहमासी नदियां भी हैं जो इस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं में काफी मदद करती हैं। गुजरात के दाहेज में एक एलएनसी टर्मिनल स्थापित किया गया है जो गैस आधारित विद्युत योजनाओं में सहायता करेगा। लेकिन दक्षिण में कोयला केवल नवेली में उपलब्ध है और वह कोयला भी बहुत घटिया है। जल विद्युत बहुत विश्वसनीय नहीं है क्योंकि तमिलनाडु में बहने वाली नदियों का नियंत्रण पड़ौसी राज्यों द्वारा किया जाता है। अत: इस सच्चाई के बावजूद कि तमिलनाडफ देश के कुल निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान करता है और राज्य सरकार ने वहां निवेशकों के अनुकूल माहौल बनाया है लेकिन फिर राज्य में पर्याप्त बिजली उत्पादन नहीं होता। अत: मैं सरकार से उसकी विद्युत परियोजनाओं में तेजी लाने का अनुरोध करता हूं।

डॉ. कैलगनार एम. करुणानिधि के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार, भारत की ऐसी पहली सरकार है जो 1989 से किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। आमतोर पर इसे लोकप्रियता हासिल करने का उपाय समझा जाता है। लेकिन चूंकि सिंचाई के लिए जल पर अब तमिलनाडु सरकार का नियंत्रण नहीं है। इसलिए कृषि उत्पादों की पैदावार को बनाए रखने के लिए निवेश करना आवश्यक हो गया है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे किसान अधिकतर भूजल पर निर्भर है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़े दर्शाते हैं कि जबकि पूरे भारत में बिजली की स्थिति में सुधार आ रहा है लेकिन दक्षिण क्षेत्र मांग को पूरा करने में असमर्थ है। इसमें आगे कहा गया है कि देश के केवल दक्षिण भाग में बिजली क्षमता में वृद्धि नहीं हो रही है।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन, जोकि दक्षिण भारत में स्थिति हैं, में भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस पाई गई है। लेकिन इस सारी गैस को विद्युत

उत्पादन के लिए गुजरात या उत्तर प्रदेश ले जाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि कृष्णा-गोदावरी बेसिन की गैस का उपयोग दक्षिण राज्यों में विद्युत उत्पादन और आपूर्ति के लिए किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय विद्युत मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री प्रेमदास** (इटावा) : आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार द्वारा किसी भी जगह एन.टी.पी.सी. प्लांट की स्थापना होती है। हजारों एकड़ जमीन की जरूरत होती है। सरकार एक्वायर करती है। उस क्षेत्र के किसानों द्वारा एवं अन्य जनमानस द्वारा पूरा सहयोग किया जाता है एवं उस प्लांट से कुछ सहयोग नहीं मिलता है। दूसरे प्रदेश को बिजली भेज दी जाती है।

मेरी मांग है दिवियापुर जिला औरया में एन.टी.पी.सी. का प्लांट लगा हुआ है उसी क्षेत्र में बिजली देना निश्चित करें जिससे कि वहां के लोगों को लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : सभापति महोदय, विद्युत मंत्रालय के लिए वर्ष 2009-10 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान में भाग लेने की अनुमति देने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

जो मैं कहना चाहता हूं उसे मैं दो भागों में विभक्त करना चाहता हूं। सर्वप्रथम, समायाभाव के कारण, मैं अपने राज्य जिसे उड़ीसा की केवल तीन मुख्य समस्याओं के बारे में बात करना चाहता हूं। श्री नवीन पटनायक जी के सक्षम नेतृत्व के तहत राज्य सरकार, जहां तक संभव हो कार्यकुशल तरीके से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, पारेषण वितरण करने का प्रयास कर रही है।

संघ सरकार के कहने पर उड़ीसा सरकार ने 1999 में, जो कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, ने ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना आरंभ की। इस प्रक्रिया में, दो राज्यों, उड़ीसा तथा दिल्ली निजीकरण की प्रक्रिया में आगे आए। परंतु अब दुर्भाग्यवश हमने पाया कि केन्द्र सरकार अब मुकर गई है तथा वह जिम्मेदारी लेने से बच रही है।

हर व्यक्ति कह रहा था कि निजीकरण एक नये युग का प्रादुर्भाव करेगा और यह एक ऐसा राज्य बनाने में मदद करेगा जहां बिजली की कोई कमी नहीं होगी। इस प्रक्रिया में, एक बड़ी कंपनी, हालांकि इसकी छवि इतनी अच्छी नहीं है, चार डिस्टकाम में से इसने उड़ीसा में तीन को अपने हाथ में लिया। उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा तथा दक्षिण उड़ीसा रिलांयस पावर के पास है और सेस्को राज्य सरकार के पास है जो उड़ीसा के अधिकांश तटीय भाग को नियंत्रित कर रहा है।

हमें केन्द्र सरकार से इस बहाने से वित्तपोषण से वंचित रखा गया है कि हम निजीकरण कर चुके हैं। राज्य सरकार तथा राज्य के अधीन निगमों को इन परिसम्पत्तियों का आधुनिकीकरण न कर पाने से पारेषण और वितरण का कार्य अवरुद्ध हुआ है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से उड़ीसा में न्यूनतम 2,000 मे.वा. की उत्पादन क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना स्थापित करने को कहा था । राज्य सरकार को पर्यावरण और वन मंत्रालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त की के वेदबहाल नामक स्थान पर विद्युत संयंत्र आरंभ करने के लिए सभी पूर्वापेक्षाओं को एकत्रित करने में सक्षम हुई है। राज्य सरकार ने ऐसी ही दो स्थलों का सुझाव दिया है। परंतु, दुर्भाग्यवश, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा तथा स्पष्टतया विद्युत मंत्रालय इस पहलू पर उड़ीसा की अनदेखी कर रहा है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो यहां घुटनों के बल गिर कर यह फरियाद करूंगा कि मेरा राज्य गरीब है कृपया मेरे राज्य की मदद कीजिये। हर व्यक्ति इसी लहजे में बात कर रहा है। परंतु मैं 'उड़ीसा' और औसत नौजवान उड़ीसा के उद्यमिता के गुण पर गर्व करता हूं तथा ईश्वर ने उड़ीसा राज्य को जो प्राकृतिक संसाधन प्रदान किए है उन पर गर्व करता हूं। इसलिए, हम एक गरीब राज्य नहीं हैं; हम गरीब लोग नहीं हैं; हम सक्षम हैं; और हम अपने स्वयं के निर्णय लेने में सक्षम हैं--चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक हो -- जैसा कि विगत कुछ वर्षों में हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी सिद्ध कर दिया है कि हम अपने पांव पर खड़े होने में सक्षम हैं। हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। परंतु रुकावटे मुख्यत: केन्द्र सरकार की ओर से हमें अपने तरीके से न चलने देने की वजह से आ रही है चूंकि इस देश का ढांचा संघीय है। इसलिए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीआई) जैसी एक आदर्श परियोजना, जिसमें आपकी वर्ष 2012 तक प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण करने की मंशा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री तथागत सत्पथी]

है, इसमें रुकावट यह है कि कार्य केन्द्रीय निगमों जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी या ऐसे ही संगठनों को सौंपा गया है। अब, यह संगठन राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन नहीं हैं।

विभिन्न राज्यों से आरजीजीवीवाई के बारे में अनेक शिकायतें सुनने में आ रही है। मैंने सभी भाषण सुने हैं परंतु दुर्भाग्यवश किसी ने भी इस तथ्य पर रोशनी नहीं डाली। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र ढेंकानाल, तालचेर एक ऐसा केन्द्र है। दक्षिण से मेरे एक मित्र ने उल्लेख किया कि एनटीपीसी ओर एनएचपीसी का पुनः नामकरण करके इसे 'अंतर भारतीय ताप विद्युत निगम' कर दिया जाए। मेरे विचार से हमें खुशी होगी यदि एनटीपीसी और एनएचपीसी जैसे निगम दक्षिण की ओर भी रुख करें।

महोदय, तालचेर में प्रत्येक वर्ष कई मिलियन टन फ्लाई ऐश पैदा होती है। हम नहीं जानते है कि इसका क्या करना है। केन्द्र सरकार आरंभ में बहुत ही सुंदर तस्वीर पेश की थी कि इससे कोई समस्या नहीं होगी, फ्लाईऐश की ईंटें बनाई जाएं। आप कितनी ईंटें बना सकते हैं? यदि आप बनाए भी तब भी ईंटों की परिवहन लागत इतनी अधिक होगी कि एक निश्चित सीमा से आगे, वे किफायती साबित नहीं होती हैं और उन्हें कोई खरीदना नहीं चाहता है। इसलिए अगुल और ढेंकानाल जिलों में राख के बड़े टीले बनते जा रहे हैं और इससे आम आदमी का जीवन अस्तव्यस्त होता जा रहा है। इसलिए, वास्तव में हम इन संगठनों से ऊब चुके है। एक दुर्भाग्य यह भी है कि पिछली सरकार में एनडीए के शासनकाल के दौरान, तालचेर में एक वृहदकाय एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया गया था और संपूर्ण परियोजना को चिन्हित किया गया था कि इससे पैदा होने वाली सारी बिजली कर्नाटक राज्य अर्थात् दक्षिण भारत को जाएगी। इसलिए हम इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, हम प्रदूषण, गंदगी, फ्लाई ऐश; गंदा पानी झेल रहे हैं परंतु बिजली दक्षिण भारत को जाती है।

अब, आरजीजीवीवाई के तहत भी आपने हमारे गांवों के विद्युतीकरण के दूभर कार्य को इन्हीं निगमों को सौंपा है। कोई भी इसका पर्यवेक्षण नहीं कर रहा है। केन्द्र सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं है और इन निगमों की उपलब्धि के बारे में जानने की चेष्ठा नहीं कर रही है। राज्य सरकार को किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण लेने का कोई अधिकार नहीं है और इससे हो यह रहा है कि पूरी ढिलाई से काम चल रहा है; पूरी तरह से अनदेखी हो रही है और कोई भी उपलब्धि नहीं है। महोदय, मेरे अपने दो जिलों ढेंकानाल तथा अंगुल तथा शेष उड़ीसा में हम पाते है कि प्रगति अत्यंत धीमी है और फिर भी कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उन्हें डांट-फटकार सके और उन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है।

दूसरा मुद्दा यह है कि त्वरित विद्युत विकास और पुनरुद्धार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) नामक कार्यक्रम चल रहा है। यह योजना मुख्यतः शहरी तथा ब्लाक मुख्यालय के तंत्र प्रबंधन के लिए बनाई गई है। इन परियोजनाओं पर भारी मात्रा में पैसा खर्च किया जा रहा है। अब, आपके पास आरएपीडीआरपी भी है। परंतु जिस बात का मैंने पहले उल्लेख किया था कि निजीकरण के माध्यम से उड़ीसा को दसवीं योजना में प्रारंभ में 74 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, परंतु, उसके बाद हमें एक बार ही वह धनराशि प्राप्त हुई है। अब, हमें और अधिक निधियों से वंचित रखा गया है क्योंकि आप उदाहरण दे रहे हैं कि: 'आप निजीकरण कर चुके हैं: आप निजीकरण आरंभ कर चुके हैं और अब आपको अपने लिए स्वयं इंतजाम करना होगा। निजी कंपनियां इन धनराशियों को बट्टे खाते में डालने की इच्छुक नहीं है इसलिए, उड़ीसा को इस क्षेत्र में और अधिक वित्तपोषण से वंचित किया जा रहा है। मैं ऐसा याचना के तौर पर नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे मिन्नत नहीं कर रहा हूं। मेरी संघीय सरकार से यह मांग है कि हमारे यहां भी ग्रिडको, उड़ीसा पावर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड और उड़ीसा हाइड्रो-पावर कारपोरेशन हैं जो अपने सिद्ध पिछले रिकार्ड के आधार पर सक्षम और प्रवीण हैं। इन संगठनों की सक्षमता सिद्ध हो चुकी है। आप इन संगठनों को वित्तपोषित कर सकते हैं क्योंकि प्रमुख तौर पर नहीं हो रहा है।

उदाहरणस्वरूप, यदि आप रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लें, जो उड़ीसा और दिल्ली को संभाल रहा है, वह दिल्ली में पारेषण और वितरण नेटवर्क विकसित करने में 38 बिलियन रु. खर्च कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजनैतिक रूप से और हर उस प्रकार से जो हम सोच सकते हैं, दिल्ली व्यापक स्तर पर अपनी सद्भावना के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, वह दिल्ली में निवेश कर रही है। किन्तु उसे पैसा कहां से मिलता है? जब बीएसईएस था, तो उसने उड़ीसा में निवेश किया। इस प्रकार, इस कंपनी का आरम्भिक निवेश, जिसके माध्यम से इसने दिल्ली में वितरण नेटवर्क शुरू किया, उड़ीसा से हुआ था। किन्तु इस कंपनी ने उड़ीसा में कोई निवेश नहीं किया है। एक ओर, आपके जोर देने पर हमने इसका निजीकरण किया। कंपनी अब निवेश नहीं कर रही है। दूसरी ओर, आप यह कहते हुए हमें दोष दे रहे हैं, "चूंकि आपने निजीकरण किया है, हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे।" तो आप राज्य का वित्त पोषण रोक रहे हैं। इसलिए, हम हारे हुए

साबित हो रहे हैं। उनके हठ और उनके हितों के कारण हमने इसका निजीकरण किया और फिर भी हमें हार मिली है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, मुझे आपसे दो मिनट और चाहिए। मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा। आप आश्चर्य करेंगे कि मैं कितना संक्षेप में बोलूंगा।

अपने भाषण में दूसरे भाग में, मैं राष्ट्र के थोड़े से व्यापक दायरे पर बोलना चाहूंगा। मुझे यह नोट करके दुख हुआ है कि पिछली लोक सभा में भी – मैं यहां था – एक विश्वास मत आया था। सरकार और उस दल, ने जो सरकार को नियंत्रित कर रहा था। जो अभी भी सरकार को नियंत्रित करता है, भारत-अमरीकी परमाणु संधि, जिस पर हमने हस्ताक्षर किए थे, के स्वार्थवादी मुद्दे पर संघीय सरकार को खतरे में डाल दिया। वे जीत गए। उन्होंने इसे सम्भाल लिया। उन्होंने जो कुछ भी किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन, मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि उस समय से लेकर अब तक भी, भारत सरकार ने इसका कोई अनुमान नहीं लगाया है कि 50 वर्षों में वर्ष 2050 तक देश में विद्युत की कितनी आवश्यकता होगी। अतः, क्या लक्ष्य है। जिसे इस देश में हम विद्युत उत्पादन के लिए पाने का प्रयास कर रहे हैं?

महोदय, यदि आप केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए 17वें विद्युत सर्वेक्षण पर गौर करें, तो इसने वर्ष 2008-09 के लिए 7,94,561 मिलियन यूनिट की मांग का पुर्वानुमान लगाया था, जिसमें अत्यधिक मांग के समय कमी 12 प्रतिशत थी। किन्तु यदि आप 01 अप्रैल, 2009 – 01 अप्रैल को उड़ीसा दिवस है – की स्थिति के अनुसार हमारी वर्तमान संस्थापित क्षमता पर ध्यान दें, तो यह 1,47,965.40 मे. वा. है। यह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की वेबसाइट के आधार पर है। इस प्रकार, हमारा घाटा बहुत अधिक है। आपकी क्या योजनाएं हैं। आप अपनी योजनाओं को समुचित रूप से परिलक्षित नहीं कर पाए हैं। आप राष्ट्र को और इस सभा को यह नहीं बता पाए हैं कि आप राष्ट्र के समक्ष आ रही कमी से किस प्रकार निपटने का विचार रखते हैं। जब आप यह दावा कर रहे हैं कि वर्ष 2012 तक सभी के लिए बिजली उपलब्ध हो जाएगी, तो आप किस प्रकार आशा करते हैं और किस प्रकार सोचते हैं कि आप उस समय तक अपेक्षित, सुनिश्चित गुणवत्तापूर्ण और वांछनीय ऊर्जा की आवश्यकता पूरी कर लेंगे?

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री तथागत सत्पथी : मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अब चूंकि आपने अनुदेश दिया है, मुझे अपनी बात समाप्त करनी चाहिए।

व्यक्तिगत तौर पर, मैं प्रधानमंत्री जी को उस एक अच्छी बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, जो उन्होंने पिछली लोकसभा और इस लोकसभा के दौरान इन पिछले पांच वर्षों में की है और वह यह है कि उन्होंने उन नौकरशाहों को चिंता में डालने के खतरे पर इस राष्ट्र की अधिकतम उत्सर्जन सीमा पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन्होंने उन बहुराष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों को अपनी आत्मा बेच दी है, जो भारत के भूभाग में अपनी सभी प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना करना चाहती हैं। इसलिए, मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। किन्तु विद्युत मंत्रालय को इस पर भी ध्यान देना होगा कि जब आप उत्सर्जन कानून की सुदृढ़ बना रहे हैं, तो आपको यह निर्णय भी करना चाहिए कि आप किस प्रकार के विद्युत क्षेत्र पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त करें। श्रीमती सुप्रिया सुले।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, क्या आप मुझे बात समाप्त करने के लिए कह रहे हैं?

सभापति महोदय : जी हां, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है।

श्री तथागत सत्पथी : अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि जल विद्युत, वह विद्युत है, जो पर्यावरणानुकूल और लागत-किफायती है। यदि आरम्भिक निवेश काफी अधिक भी हो तो – वास्तव में यह काफी अधिक ही होगी – किंतु 10 से 12 वर्षों में हमने भारत में जो भी जल विद्युत इकाई देखी है, वह अपने पूंजी निवेश की भरपाई करने में सक्षम रही है। अतः, जल विद्युत भारत में उपलब्ध सबसे सस्ती विद्युत है। हमारे यहां पूर्वोत्तर से लेकर मेरे उड़ीसा राज्य तक, जहां 11 बड़े नदी क्षेत्र हैं, इसकी अतिव्यापक क्षमताएं हैं। हम न केवल अपने आपको विद्युत उपलब्धता में परिपूर्ण कर सकते हैं बल्कि हम दक्षिण और उत्तर के अपने सहयोगियों को भी अधिकाधिक विद्युत उपलब्ध करा सकते हैं।

सभापति महोदय : अब, अपनी बात समाप्त करें।

श्री तथागत सत्पथी : किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि समय आ गया है कि हम इस पर ध्यान केन्द्रित करें कि हम किस प्रकार की विद्युत चाहते हैं। परमाणु ऊर्जा उन आवश्यकताओं का जवाब नहीं है, जो भारत में वर्ष 2050 तक उभर कर आएंगी।

[श्री तथागत सत्पथी]

भाषण समाप्त करने से पहले, मैं सरकार और मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्हें इस बारे में श्वेत पत्र लाना चाहिए कि उन्होंने वर्ष 2050 तक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता का अनुमान लगाया है, वे इस आवश्यकता को किस प्रकार पूरा करना चाहते हैं और ऐसी क्या योजनाएं हैं, जिनके तहत वे पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना इस आवश्यकता को पूरा कर सकें।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : सभापति महोदय, विद्युत जैसे गंभीर विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मेरा मानना है कि इस सम्मानीय सभा में सभी का यह विश्वास है कि यदि हम विकास करना चाहते हैं तो विद्युत के प्रभावी और कुशल संवितरण और उत्पादन के बिना यह संभव नहीं हो पाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्युत शक्ति ऊर्जा का एक द्वितीय स्वरूप है जो कि आर्थिक विकास का इंजन है। अन्य सभी ऊर्जाओं के उलट विद्युत ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है, जिसे संचित नहीं किया जा सकता। इसे उत्पादन करने के साथ ही पारेषित कर दिया जाता है। विद्युत की मांग भी लचीली होती है। जितनी ज्यादा दी जाती है इसका उतना ही ज्यादा उपयोग होता है और संभवत: हमारा देश उन कुछेक विकास देश देशों में से एक है जहां प्रति व्यक्ति उपभोग बेहद कम है। जैसा कि मेरे एक साथी ने अभी जिक्र किया है और उड़ीसा, बिहार तथा उत्तर प्रदेश से आने वाले साथी जिक्र कर चुके हैं कि यदि हमारे सभी राज्यों का औद्योगिक विकास करना है तो विद्युत क्षमता को बढ़ाने का कार्यक्रम राज्यों की उच्चतम वरीयता होनी चाहिए। मेरे साथी विद्युत की कमी के लगभग सभी कारणों की बात कर चुके हैं। मैं उन सब बिन्दुओं को दोहराकर सदन का समय व्यर्थ नहीं करना चाहती। मैं अपने उन सब बिन्दुओं का सभा पटल पर रखना चाहूंगी।

परंतु उससे पहले मैं बिहार के एक साथी जिन्होंने ''सिंगल फेजिंग'' के बारे में व्यापक रूप से बात की है, में हस्तक्षेप करना चाहूंगी। मैं समझती हूं कि ''सिंगल फेजिंग'', जैसाकि सभी जानते ही हैं, राज्य का विषय है। यह राज्यों का एक ऐसा विषय है, जो उन्हें मजबूरन अपनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे सभी राज्यों में विद्युत उत्पादन पर्याप्त नहीं है। महाराष्ट्र ने ये किया है। आज तक हम सिंगल फेजिंग पर 500 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। जैसाकि हम सभी जानते हैं और बिहार से आए साथी ने जिक्र भी किया है कि आज जब हम वापिस अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं, तो हमारे गांव के अधिकांश लोग हमें यह बतातें हैं कि हम सिंगल फेजिंग नहीं चाहते, हम 24 घंटे अंधेरे में रह लेंगे परन्तु कृपया हमें थ्री फेज बिजली ही दी जाए, चाहे दिन भर में यह 6 से 8 घंटे ही क्यों न आए, क्योंकि हमें बिजली की जरूरत अपने बच्चों की शिक्षा के अतिरिक्त अपने कृषि पंप चलाने के लिए भी पड़ती है। इसलिए मेरा मानना है कि यह बेहद चिंताजनक स्थिति है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक राज्य में विद्युत की कमी है फिर चाहे वह 2000 मेगावाट, 3000 मेगावाट या 5000 मेगावाट, चाहे किसी भी मेगावाट की बात हो। आज वास्तव में इमें इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने सभी कार्यक्रमों में तेजी लाएं और जहां तक संभव हो प्रत्येक गांव में अपने सभी घरों में बिजली उपलब्ध कराएं। हम कई योजनाओं की बात करते हैं। यहां तक कि मेरे साथी श्री तथागत सत्पथी ने इस बात का भी जिक्र किया कि 2009 सभी गांवों को विद्युतीकृत किए जाने और 2012 तक वन क्षेत्रों सहित सभी घरों तक बिजली पहुंचायी जानी है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार हमें इस बात के लिए कुछ मार्गदर्शन और स्पष्टीकरण दे कि विद्युत की इतनी कमी के चलते हम इस लक्ष्य को किस प्रकार पूरा कर पाएंगे?

इसके अतिरिक्त, असल समस्या लाइसेंस खत्म करने की है। हालांकि सरकार द्वारा कई अच्छे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका हम भी समर्थन करते हैं, परंतु पर्यावरण मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय इन कार्यक्रमों को शीघ्रता से मंजूरी प्रदान करें। मेरे राज्य में तीन या चार ऐसी परियोजनाएं है, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय की मंजूरी न मिलने के कारण लंबित पड़ी हुयी हैं। यहां तक कि लाइसेंस खत्म करने की बात 1991 से की जा रही है तथापि अधिकांश राज्यों में इसका कोई परिणाम देखने को नहीं मिला।

एक अन्य समस्या पारेषण में खुली पहुंच से जुड़ी हुयी है। जो कि एक बड़ी समस्या है। यह हो चुका है तथापि राज्य स्तरों पर ये समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं।

मेरे साथी श्री तथागत सत्पथी ने परमाणु विद्युत के बारे में बात की। मैं समझती हूं कि हम सभी ने समझौते का समर्थन किया और अभी भी समर्थन कर रहे हैं परंतु हमें विकास की कार्य योजना के बारे में जानने की जरूरत है। हमने 20,000 मेगावाट क्षमता की बात की थी। यदि माननीय मंत्री हमें परमाणु ऊर्जा की रूपरेखा के बारे में बता सके तो हमें इसी अच्छी तरह समझने में बहुत सहायता मिलेगी।

एक अन्य बिन्दु जो उत्तर प्रदेश के मेरे साथी ने उठाया वह भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। आज भूमि का अधिग्रहण करने की भारी

समस्या है। अधिकतर किसान एक बिजली का पोल लगाने अथवा पवन ऊर्जा मिल लगाने के लिए भी अपनी जमीन देना नहीं चाहते। जब तक हमारे पास भूमि अधिग्रहण के लिए कोई समुचित अधिनियम नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि तब तक हम अपनी विद्युत परियोजनाओं को पूरा कर पाएंगे।

मेरा अंतिम बिन्दु वितरण के निजीकरण से जुड़ा हुआ है। उत्पादन के अतिरिक्त आज हमारे देश के प्रत्येक राज्य में वितरण और पारेषण सबसे बड़ी समस्याएं बनी हुयी हैं। मैं समझती हूं कि यदि हम ''फ्रैंचाइज मॉडल, भिवडी मॉडल'' जिसकी इस देश में बहुधा चर्चा होती रही है, को अपनाएं तो यह स्थिति सभी के लिए लाभकारी होगी। यह निजीकण नहीं है। यदि हम इसे मॉडल के तहत प्रयोग करके देशभर में इसे क्रियान्वित करें तो मैं समझती हूं कि इससे सभी को लाभ मिलेगा।

विद्युत पारेषण और वितरण के बारे में काफी बात की गयी। मैं इनमें से किसी मुद्दे को दोहराने के लिए सभा का समय नहीं लेना चाहूंगी परन्तु कार्बन उत्सर्जन, पर्यावरण और हमारे प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसाकि हमने कोयला, जल विद्युत के बारे में बात की, मैं समझती हूं कि हमें वास्तव में पवन ऊर्जा मिल, सौर ऊर्जा के साथ-साथ गन्ना मिलों से मिलकर विद्युत का उत्पादन करने की जरूरत है। वे ऊर्जा का मुख्य स्रोत नहीं हो सकते परंतु हम जानना चाहते हैं कि उस सौर मिशन का क्या हुआ जिसके बारे में हमने सबने बात की थी।

सौर ऊर्जा का दोहन करने की आवश्यकता है और मैं समझती हूं कि आगे बस यही एक रास्ता बचा है। यदि हम गन्ना मिलों और सृजन की बात करें तो 25 मेगावाट की इकाई लगाने से तकरीबन 9000 कृषि पंप चलाए जा सकते हैं। मैं समझती हूं इन सब विभिन्न प्रकार के दखलो जिनका 'प्रयोग और परीक्षण किया गया है, उनकी लागत काफी ज्यादा है और हम सभी इस बात से सहमत हैं। परंतु मैं समझती हूं कि प्राकृतिक संसाधन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। हमें इन सब चीजों की लागत कम करने के तरीकों का पता लगाना होगा और केवल इसी प्रकार हम अपने लोगों को अंधेरे में डूबने से बचा सकते हैं।

मैंने यह वास्तव में यह महसूस किया कि पूरी परियोजना के लिए केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति ही जिम्मेदार नहीं है अपितु सुधारों की तकनीकी कमजोरियां और उन्हें लागू करने की अक्षमताएं सचमुच चिंता का विषय है। मैं समझती हूं कि अपने सभी राजनैतिक मतभेदों को दूर रखकर अपने देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए समयबद्ध परियोजना चलाना ही एकमात्र रास्ता है। मैं अपने सभी साथियों से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि आईए हम सब साथ मिलकर देश को अंधेरे से बचाएं।

श्री ए. सम्पत (अटिंगल) : महोदय, हम सभी जानते हैं कि विद्युत का उत्पादन स्वयं में एक उद्योग है। ऐसा कहा जाता है कि यदि हमारे पास पर्याप्त बिजली हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे दैनिक क्रियाकलाप विद्युत की आपूर्ति पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। हमारे देश की अवसंरचना के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के तौर पर इस पर और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसपर अधिक ध्यान दिया भी गया है। मुझे आश्चर्य है कि भारत संघ की राष्ट्रपति ने संसद को संबोधित करते हुए केवल 13,000 मेगावाट की क्षमता लक्ष्य का उल्लेख किया है, जबकि इससे पहले भारत सरकार ने दसवीं योजना अर्थात् 2007-2012 की अवधि में 90,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया था, जोकि स्वयं ही 18,000 मेगावाट की वार्षिक वृद्धि है।

देश के विभिन्न भागों में विद्युत की भारी कमी महसूस की जा रही है, जिससे हाल ही में ईंधन विशेषकर पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में तेजी से हुई वृद्धि के कारण लोगों की कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं, बल्कि कृषि, उद्योग और व्यापार पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस समस्या का पहला प्रमुख कारण है अपर्याप्त विद्युत उत्पादन, दूसरा अपर्याप्त पारेषण तथा तीसरा कारण है अपर्याप्त वितरण नेटवर्क। यद्यपि, अबाधित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत लाखों उपभोक्ताओं का सपना है, परंतु, भारत के लाखों लोगों तक बिजली पहुंचाना अभी शेष है। हमारा गणराज्य 2010 में अपने हीरक जयन्ती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। परंतु क्या हजारों गांवों के लिए प्रसिद्ध नाटक 'वेटिंग फॉर गोडोट' के समान ही होगा? महोदय, मुझे ऐसी आशंका है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें युद्धस्तर पर छोटी जल, पवन, बायोमास तथा अन्य ऊर्जाओं में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के आयोग को बढ़ावा देना होगा। हम देश के विभिन्न भागों में पवन, समुद्र की लहरों तथा सौर ऊर्जा के दोहन के लिए और अधिक उत्पादन इकाइयों की स्थापना क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी 7000 किलोमीटर से अधिक की तट रेखा है।

माननीय विद्युत मंत्री ने लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया कि इस समय हम अप्रैल-मई, 2009 के दौरान कुल मिलाकर क्रमशः 13609 मिलियन यूनिट अर्थात् 10% तथा 13,603

[श्री ए. सम्पत]

मेगावाट अर्थात 12.3% की कमी का सामना कर रहे हैं। परन्तु, मुझे लगता है कि यह पूरी तस्वीर नहीं है। विद्युत का कुल तकनीकी तथा वाणिज्यिक नुकसान, बिक्री के लिए उपलब्ध कुल ऊर्जा का एक तिहाई है, जोकि बहुत ही दुखद है। हमें महत्वपूर्ण आत्म-विश्लेषण करना होगा कि हम विद्युत के लक्षित आंकड़ों का उत्पादन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण में भी स्वीकार किया गया है कि ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों तथा अन्यों के बीच काफी विवाद, मतभेद रहे हैं। देश की श्रम शक्ति की ओर उंगली उठाने वाली एक भी घटना नहीं हे। निजी क्षेत्र के ठेकेदारों तथा उप-ठेकेदारों के लाभ के लक्ष्य के कारण ही कुछ परियोजनाओं में विलंब हो रहा है। यद्यपि स्थापन्न क्षमता 1,49,391,91 मेगावाट है, उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के चरण पर हम विफल रहते हैं। हमारा ताजा आर्थिक सर्वेक्षण दर्शाता है कि वर्ष 2008-09 के दौरान विद्युत कंपनियों के बिजली उत्पादन में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जोकि 9.1 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम है। मैं कहना चाहता हूं कि: "ऊर्जा की कमी में वृद्धि हुई है, क्योंकि आवश्यकता में वृद्धि (5.1 प्रतिशत) उपलब्धता (3.8 प्रतिशत) से अधिक है।" मैं कहना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी योजना में नहीं कुछ कमी है।

हाल ही में, कुछ राज्यों ने निजीकरण का समर्थन किया है। इससे पहले भारत सरकार भी ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण की पक्षधर रही है। दुर्भाग्यवश, उन राज्यों का क्या हुआ जिन्होंने निजीकरण को अपनाया अथवा उसे वरीयता दी? हमारे सामने उसका उदाहरण है। हमारे सामने एनरॉन कंपनी का उदाहरण है, जोकि बिल्कुल दीवालिया हो गई। इससे सरकारी क्षेत्र के हमारे उपक्रमों की स्थिति और खराब हुई है। यह भार हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा देश के राजकोष ने उठाया।

मैं आपका ध्यान एक और कारक की ओर दिलाना चाहता हूं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरनान 41,110 मेगावाट जोड़कर क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव था, परन्तु केवल 51 प्रतिशत से 52 प्रतिशत ही जोड़ा जा सका। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि निजी निवेश की अनुमति दिए जाने के बाद भी, हमारे देश को बहुत कम लाभ हुआ। इसलिए, मैं निजीकरण के विरुद्ध हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कोयला क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में भी निजीकरण के लिए क्यों कहा जा रहा है। सरकार की ऊर्जा नीति का विरोध करने के अतिरिक्त मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है।

पिछले वर्ष इस सभा में उत्तर में बताया गया था कि भारत ने "अपने सीमित और छोटे यूरेनियम तथा थोरियम के वृहत संसाधनों" के दृष्टतम उपयोग हेतु तीन चरण का एक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया है।

"झारखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में यूरेनियम के भंडार हैं। थोरियम का लगभग एक तिहाई वैश्विक भंडार भारत के केरल तथा तमिलनाडु में है। हमें इससे सावधान रहना चाहिए कि विदेशी विवशताएं, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे अनुसंधान एवं विकास को दिग्भ्रमिक न करें तथा इसे नुकसान न पहुंचाएं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि 10वीं लोक सभा के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग हेतु धनराशि के आवंटन में कटौती के पीछे क्या था और कौन था?

केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने हाल ही में रिपोर्ट दी है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में अन्य राज्यों की तुलना में विद्युत की अधिक कमी है। चूंकि नवम्बर, 2008 में केन्द्रीय पूल का हिस्सा घटाकर 500-600 मेगावाट कर दिया गया, इसलिए केरल राज्य को विद्युत संकट का सामना करना पड़ा। थालचर और रामागुन्डम ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में कमी इसका कारण बताया गया। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि हमारे सरकारी खेत्र के उपक्रमों को पर्याप्त कोयला तथा गैस नहीं मिलती जबकि निजी क्षेत्र को इसकी प्रचुर आपूर्ति मिलती होती है।

हम अपनी जल संभाव्यताओं का दोहन करने में क्यों संकोच करते हैं? यद्यपि, अनुमान लगाया गया है कि भारत में जलविद्युत स्रोतों से 1,55,481 मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता है, परन्तु अब तक केवल 20 प्रतिशत का ही दोहन किया जा सका है। ब्रह्मपुत्र बेसिन और गंगा बेसिन के माध्यम से हमारे पास 86,776 मेगावाट और बिजली उत्पादन की क्षमता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल विद्युत सबसे सस्ती तथा सबसे कम प्रदूषण वाली बिजली है। मुझे आशंका है कि हाल ही में तथाकथित पर्यावरणविदों, के एक वर्ग द्वारा किए गए विरोध का गैर-सरकारी संगठन और कुछ विदेशी एजेंसियां उनका वित्तपोषण कर रही हैं। इसपर बहुत सावधानी से नजर रखनी होगी। हाल ही में मेरे राज्य केरल में भी कुछ लोग अशिरापल्ली और पूदमकुट्टी के परियोजना प्रस्तावों के विरोध में खुलकर सामने आ गए। पारेषण लाइनें बिछाने के विरुद्ध भी कुछ सुनियोजित कार्रवाई नजर आ रही है। यह सही है कि प्रभावित परिवारों के लिए बेहतर राहत और पुनर्वास की

व्यवस्था की जानी चाहिए। परन्तु अराजकता के बीज बोए जाने को अत्यधिक सावधानी से देखा जाना चाहिए।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार को विद्युत उत्पादन तथा पारेषण के क्षेत्रों को सामरिक महत्व के क्षेत्र घोषित करना चाहिए तथा इसके लिए पर्याप्त विधान बनाया जाना चाहिए।

साथ ही मैं नव-उदारवादी नीतिओं तथा प्रमुख क्षेत्रों के निजीकरण का कड़ाई से विरोध करता हूं। यह विनिवेश समस्याओं के समाधान हेतु रामबाण नहीं है। विद्युत क्षेत्र की बाजार की शक्तियों की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। घरेलू उपभोक्ता अब भी संख्या तथा उपभोग वार सबसे बड़ा वर्ग है। इसलिए, पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को विनियंत्रित करने, कोयला खनन में निजी क्षेत्र के निवेश, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा तेल क्षेत्रों की बिक्री, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजीकरण आदि से आम लोगों को निश्चित रूप से बहुत नुकसान होगा। किसी भी बहाने से राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के निजीकरण को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

इसलिए, मैं ऊर्जा नीति का विरोध करता हूं। मैं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को और अधिक अनुदान तथा महत्व देने की मांग करता हूं।

श्री के. सुगुमार (पोल्लाची) : सभापति महोदय, अपनी पार्टी एआईएडीएमके की तरफ से विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर इस महान सभा में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मैं अपना प्रथम भाषण अपने गतिशील नेता डा. पुरातची थलैवी अम्मा को समर्पित करता हूं जिन्होंने मुझे इस सभा में आने का अवसर प्रदान किया तथा मैं पोल्लाची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का मुझे विशाल बहुमत से संसद सदस्य चुनने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

देश में विद्युत की कमी की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि केन्द्र सरकार त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत देश में विद्युत उत्पादन के लिए 2,080 करोड़ रुपये देगी। मैं माननीय वित्त मंत्री को देश में विद्युत की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में किए गए अच्छे कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं।

दक्षिण भारत में बहुत अधिक बिजली जल से मिलती है इसलिए मानसून पर निर्भर है। इसमें बदलाव केवल मानसून से ही नहीं आता है बल्कि इसके अन्य ज्ञात कारण हैं जो आपूर्ति में भारी बाधा डालते हैं। इस क्षेत्र में कृषि बिजली के पम्पसेट्स पर निर्भर करती है इसलिए इस संकट का प्रभाव खरीफ की फसल पर पड़ता है तथा उपभोक्ता की जीवन शैली में परिवर्तन आने एवं उद्योग का विस्तार होने के कारण विद्युत की मांग बढ़ती है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अप्रैल-जून 2008 के नमूने आंकड़ों से पता चलता है कि दक्षिण भारत की अधिकतम मांग 26,640 मेगावाट थी जिसमें से केवल 25,035 मेगावाट की आपूर्ति की जा सकी और इसमें 1,605 मेगावाट या 6 प्रतिशत की कमी रह गई। केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार दक्षिण के चार राज्यों में औसतन अधिकतम मांग की कमी 12 प्रतिशत से 13 प्रतिशत है। वे इस कमी के लिए मानसून की असफलता एवं मांग में आई अचानक वृद्धि को मानते हैं।

विद्युत की अत्यधिक कमी का प्रभाव तमिलनाडु के औद्योगिक उत्पादन पर पड़ा है। कंपनियों का कहना है कि उत्पादन 50 प्रतिशत तक कम हो सकता है। वस्त्र, चमड़ा एवं नमक जैसे क्षेत्र कृषि उद्योग जैसे ही हैं। एसोसिएशन्स को उत्पादन में करीब 10000 करोड़ रुपये की हानि हुई थी।

तमिलनाडु के पास 10,122 मेगावाट का उत्पादन करने की क्षमता है जबकि मांग 11,622 मेगावाट की है, जिसमें 1,500 मेगावाट की कमी रह जाती है। अत्यधिक मांग की अवधि में यह कमी 1700 मेगावाट तक हो जाती है। इस कमी के कारण राज्य सरकार को औद्योगिक इकाइयों एवं वाणिज्यिक संस्थापनाओं के लिए हाई टेंशन नेटवर्क पर 40 प्रतिशत एवं लो टेंशन कनेक्शन पर 20 प्रतिशत की कटौती लागू करना पड़ता है। तमिलनाडु में उत्पादन 20 से 30 प्रतिशत कम है। लघु एवं मध्यम प्रतिष्ठानों का उत्पादन 20 प्रतिशत तक गिरा है, उसने पहले ही अपने जनरेटर सेटों के लिए डीजल खरीदने हेतु 20 करोड़ रुपये से 30 करोड़ रुपये तक खर्च कर दिए हैं।

तमिलनाडु के कारखानों में अत्यधिक मांग की समयावधि में प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक विद्युत की कटौती होती है। मौजूदा ग्राहकों को विद्युत कटौती करने की बजाए राज्य सरकार अतिरिक्त विद्युत खरीदने के बारे में सोच सकती थी जो नेशनल ग्रिड पर 1.80 रुपये प्रति यूनिट की दर पर उपलब्ध थी, और उद्योग 3.30 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करने को तैयार हैं। इस प्रकार तमिलनाडु विद्युत बोर्ड न केवल कमी पर ध्यान देता बल्कि 4000 करोड़ रुपये अर्जित करता।

[श्री के. सुगुमार]

तमिलनाडु में बिजली की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है तथा इस खराब स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय सरकार कोई उयुक्त कार्रवाई नहीं कर रही है। तमिलनाडु विशेषकर कोयम्बटूर एवं तिरुप्पुर जैसे औद्योगिकी जिलों में लघु उद्योग जैसे वस्त्र, फाइबर यूनिटें एवं रुलिंग यूनिटें बंद होने की कगार पर है। तथा इन उद्योगों में कार्यरत लाखों कर्मचारी अपना रोजगार खो रहे हैं एवं गरीब हो रहे हैं। इससे निकट भविष्य में आत्महत्याएं हो सकती हैं।

जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है इस समय केवल उन्हें कनेक्शन मिल रहा है जिन्होंने वर्ष 1990 एवं 1991 में कृषि कार्य हेतु पम्प कनेक्शनों के लिए आवेदन किया था। तमिलनाडु में यही स्थिति है। तथापि तीसरे चरण में किसानों को दिये जाने वाले कनेक्शनों पर प्रतिदिन तीस से चार घंटे बिजली मिल रही है। ऐसी स्थिति में हम कृषि उत्पादन में वृद्धि की आशा कैसे कर सकते हैं?

पवनचक्की से पर्याप्त बिजली पैदा हो रही है एवं भारत की 70 प्रतिशत पवनचक्की तमिलनाडु में स्थिति हैं। वे प्राकृतिक अपरम्परागत ऊर्जा का प्रयोग करके पवन की तीव्र गति से विद्युत का उत्पादन करते हैं। मेरे पोल्लाची निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1000 से अधिक पवनचक्की हैं जो ऊदुमालपेट एवं नेगामाम के आस-पास स्थिति हैं। पवन गति के प्राकृतिक संसाधनों के कारण पूरे भारत के उद्योगपति तमिलनाडु में पवन-चक्की स्थापित करने को उत्सुक हैं। लेकिन स्थानीय तमिलनाडु सरकार और सत्तासीन दल के अवांछित प्रभाव के कारण उद्यमी अब उत्तर की ओर रुख कर रहे हैं। जो लोग तमिलनाडु में पवन चक्की स्थापित करना चाहते थे अनुकूल वातावरण एवं सरकारों के सहयोग के कारण उत्तर के राज्यों में जा रहे हैं। तमिलनाडु में उपलब्ध पवन ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को तमिलनाडु में पवन चक्की की स्थापना करनी चाहिए। उपर्युक्त कार्य के लिए राजसहायता स्वीकृति करने हेतु कदम उठाने पर विचार किया जाए।

अनामलाइयार एवं नल्लार परियोजना मेरे निर्वाचन क्षेत्र पोल्लाची के लोगों के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है। जल प्रवण क्षेत्र से लगभग 12 टीएमसी जल समुद्र में जा रहा है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के अतिरिक्त जल को कोयम्बटूर के मैदान की तरफ मोड़े जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए अपर नीरार से नल्लार एवं तीरुमूर्ति डैम तक एक सुंरग का निर्माण करना है। इस प्रकार हम 350 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। शोलियार, नीरार, मनामपल्ली एवं सरकार पथी के विद्युत स्टेशनों की मौजूदा क्षमता पूरे वर्ष के लिए बढ़ाई जाए। 12 टीएमसी अतिरिक्त जल की उपलब्धता होने से हम पोल्लाची, यूदूमालपेट, मदाथुकुलम, वलपराई, किनाथूकडावु, पल्लाडम, सुलूर, तिरुप्पुर एवं कंजीयाम निर्वाचन क्षेत्रों में पीएपी सिंचाई प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

मैं दुख के साथ यह बात कहता हूं कि तमिलनाडु में कतिपय प्रमुख अपने परिवार के लिए विद्युत उत्पादन की मांग पर ही ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं और तमिलनाडु में विद्युत वितरण को विनियमित करने के लिए तमिलनाडु हेतु कोई परियोजना प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

***श्री कौशलेन्द्र कुमार** (नालंदा) : सभी प्रदेशों के देहाती इलाकों में बिजली की दयनीय दशा है। मैं बिहार राज्य से आता हूं और मेरा संसदीय क्षेत्र नालन्दा है। एक समय था जब नालन्दा जिला के गांव का शतप्रतिशत विद्युतीकरण किया गया था उस समय केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी।

आज नालन्दा के 40 प्रतिशत गांव में भी बिजली नहीं है। कहीं तार है तो कहीं खम्भा है, लेकिन नदारद है। अगर बिजली है तो जितने भी पावर सब स्टेशन हैं उसमें कोई सामान नहीं है, बुनियादी सामान नहीं है। सब स्टेशन के पुराने सामान को बदला जाये और तार एवम् पोल, जोकि क्षतिग्रस्त हो गये हैं, उसको बदला जाये ताकि जितना गांव में विद्युतीकरण है, उतना गांव में सुचारू रूप से मिल सके।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एक बहुत अच्छी योजना है, इससे बीपीएल गरीबों को बिजली मिलेगी। लेकिन कहीं तार है तो कहीं ट्रांस्फार्मर नहीं लगाया गया है कहीं जोड़ा नहीं गया है। बिजली की शिकायत करने पर विद्युत विभाग के अधिकारी कुछ कर नहीं पाते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि नालन्दा जिले के सभी गांवों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से जोड़ा जाये जिससे किसानों एवम् गरीबों को फायदा हो सके।

आप पूरे बिहार में बिजली देना चाहते हैं तो मौजूदा राज्य सरकार की मदद करें वो आपकी पूरी मदद करेगी। विद्युतीकरण करने की मंशा अगर साफ है तो बिहार में बिजली के सभी सामानों की सप्लाई

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

करें राज्य सरकार आपको पूरा मदद करेगी। एनटीपीसी के बाढ़ के यूनिट को कब तक चालू करना है, यह स्पष्ट नहीं है।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस यूनिट को यथाशीघ्र शुरू किया जाये ताकि बिहार राज्य को और बिजली मिल सके।

[अनुवाद]

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा (बंगलौर उत्तर) : सभापति महोदय, मुझे ऊर्जा क्षेत्र पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं कर्नाटक से आता हूं, जोकि एक अग्रणी राज्य है, जिसने 1902 में शिवासमुद्रम में विद्युत का उत्पादन किया। मुझे लगता है कि भारत रत्न स्वर्गीय डॉ. सर ए. विश्वेश्वरैया के नेतृव में दक्षिण में शायद यह प्रथम परियोजना थी। परन्तु आज हम केन्द्र के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों से बिजली मांग रहे हैं, जैसा कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से मेरे मित्र भी उल्लेख कर चुके हैं।

सभापति महोदय, भारत, ऊर्जा खपत करने वाला छठा सबसे बड़ा देश है। जितने भी दस्तावेज मैंने देखे, चाहे वह राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, बिजली अधिनियम हो अथवा बिजली अधिनियम के अंतर्गत नीतिगत दस्तावेज हो। या फिर वर्ष 2008-2009 की वार्षिक रिपोर्ट, जो "सभी को बिजली" की बात करते हैं, वे एक ही बात कहते हैं कि...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे सदस्य के बोलते समय व्यवधान न डालें।

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा : हम ऐसा किस प्रकार करेंगे? इस दिशा में हम किस प्रकार आगे बढ़ेंगे? महोदय, सभा में प्रस्तुत इन सभी दस्तावेजों में इस बात का उल्लेख है कि वर्ष 2012 तक "सभी को बिजली" मिल जाएगी। परन्तु, सभी तक बिजली पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार की योजना क्या है? वर्ष 2008-2009 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 9.1 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में उत्पादन क्षमता मुश्किल से 2.7 प्रतिशत है। जल विद्युत उत्पादन में कमी का कारण खराब मानसून हो सकता है। कुल अंशदान में से कर्नाटक लगभग 37 प्रतिशत बिजली के लिए जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्भर करता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सभी स्रोतों से 78,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। परन्तु उत्पादन क्षमताओं के आंकड़े देखने से मुझे नहीं लगता कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इतना उच्च लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, जबकि मांग और आपूर्ति का अंतर आधे से कहीं अधिक है। देश के आर्थिक विकास का क्या होगा, जिसे कि आठ प्रतिशत देखा जा रहा था?

महोदय, विद्युत जो कि देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ कृषि का भी केन्द्र है, यदि 2012 तक "सभी के लिए बिजली" का लक्ष्य प्राप्त करना है तो इसके लिए आवश्यक है कि इस बारे में पुनर्विचार किया जाए तथा इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षों में केवल 15 प्रतिशत लक्ष्य ही प्राप्त किया है। वर्तमान पारेषण एवं वितरण में होने वाली हानि 30 प्रतिशत को पार कर चुकी है। कपंनियों द्वारा प्रस्तावित पारेषण एवं वितरण हानि में कटौती कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष 2011-2012 तक इन्हें घटाकर 22 प्रतिशत तक कर दिए जाने की संभावना है। मैं इस पारेषण एवं वितरण हानि को 'चोरी से हुआ नुकसान' कहूंगा। विद्युत उत्पादन केन्द्र से बंगलौर तक पारेषण 500 किलोमीटर से अधिक है। इस उत्पादन केन्द्र से खपत स्थल तक पारेषण में यह चोरी होती है, चाहे वह उद्योगपति करे, कृषक करे अथवा आम आदमी करे।

सिंगल फेज़िग के बारे में, जैसा कि मेरे **अनुभवी** मित्र पहले बोल चुके हैं, ने पूर्ण विद्युत की मांग की थी। परन्तु हमारे किसान तकनीकी पद्धतियों का प्रयोग कर इस सिंगल फेज़ की तीन फेज़ में बदलने में पूरी तरह सक्षम हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि उत्पादन के तीन प्रकार होते हैं; 75 प्रतिशत विद्युत के लिए हम ताप विद्युत उत्पादन पर निर्भर करते हैं।

निसंदेह, ताप ऊर्जा से 75 प्रतिशत विद्युत का उत्पादन किए जाने का लक्ष्य है, परन्तु ताप विद्युत उत्पादन में समस्या क्या है? कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के बीच कोई समन्वय नहीं है। ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित 90 प्रतिशत ऊर्जा राज्यों तथा केन्द्र द्वारा उत्पादित की जाती है, जबकि निजी कंपनियों द्वारा केवल 10 प्रतिशत विद्युत का ही उत्पादन किया जा रहा है। ई-आवंटन में, जिसे कि आप कोयला आवंटन की ब्लॉक प्रणाली कहते हैं, हम स्पर्धा नहीं कर सकते, राज्य निजी कंपनियों से स्पर्धा नहीं कर सकता। निजी कंपनियां जानती हैं कि रिश्वत, प्रभाव अथवा किसी अन्य साधन के माध्यम से ब्लॉक किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, परन्तु राज्य अथवा केन्द्र ऐसा नहीं कर सकते। यदि केन्द्र और उन तीनों मंत्रालयों के बीच, जिनका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, समन्वय हो जाए तो इन परियोजनाओं को कोयले की कठिनाई युक्त आपूर्ति की संभावना है। जहां तक कोयले के भंडारों का संबंध है, विश्व में भारत का चौथा स्थान है, परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि समन्वय न होने के कारण हम भारत से बाहर से कोयला प्राप्त कर रहे हैं। यह खेदजनक है। इसलिए, मैं

[श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा]

केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह विद्युत के इस भाग की ओर ध्यान दे।

दूसरे, 92 प्रतिशत विद्युत का उत्पादन परमाणु को छोड़कर अन्य स्रोतों से किया जाता है। यदि आप परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करें, पिछले 123 समझौते में वर्ष 2020 तक जिसके लगभग 20,000 मेगावाट उत्पादन का प्रस्ताव है, हम देख चुके हैं कि एनटॉन में क्या हुआ तथा **चेरजोबिल** के साथ अनुभव किस प्रकार का रहा। भारत एक विशाल देश है। इस जनसंख्या को कचरे से निपटान, लीकेज आदि जैसे खतरों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए, यह बहुचर्चित 123 समझौता सुरक्षित ऊर्जा की व्यवस्था नहीं करता। महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या परमाणु ऊर्जा उत्पादन की लागत तय कर ली गई है। मेरे हिसाब से, उत्पादन लागत 18 रुपए प्रति यूनिट से अधिक बैठेगी। यदि आप इसकी तुलना जल विद्युत उत्पादन से करें तो अंतर बहुत अधिक है। कर्नाटक में इस समय हमें 53 पैसे प्रति यूनिट की दर से जल विद्युत प्राप्त हो रही है। लागत में इतना भारी अंतर इस सभा और देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

मैं केवल यह कहना चाहता हूं, और पहले भी कह चुका हूं कि भारत सरकार इस परमाणु ऊर्जा के स्थान पर शेष 92 प्रतिशत पर ध्यान क्यों नही देती, जिसका कि लागत लाभ अनुपात मैंने 18 रुपए प्रति यूनिट बताया था। एनरॉन की डाभोल परियोजना बंद कर दी गई क्योंकि इसकी लागत हमारे अनुमान से कहीं अधिक बैठ रही थी। इसलिए, अपशिष्ट का निपटान एक और प्रश्न है। यद्यपि, इसे स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है, परमाणु ऊर्जा के अपशिष्ट का निपटान बहुत बड़ी समस्या बन चुका है।

इसलिए, मैं यूनियन कार्बाइड में क्षति की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसके कारण बहुत... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा : सभापति महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं और कर्नाटक की ओर से बोलने वाला मैं एकमात्र सदस्य हूं। मैं अपनी सीमाएं जानता हूं क्योंकि मैं विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा चुका हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा : कृपया, मुझे इस मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ और समय प्रदान करें...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : महोदय, यह उनका पहला भाषण है। कृपया उन्हें बोलने के लिए कुछ और समय दें।

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा : कुछ एनएसजी राष्ट्र, जिन्होंने 123-समझौते से सहमति जताई है, वे परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए ईंधन की आपूर्ति करने में हिचकिचा रहे हैं। आपने अमरीका और भारत के बीच 123-समझौते से क्या हासिल किया है?

हाल ही में और इसके पहले भी हमने देखा कि अमरीकी सरकार और भारत सरकार के बीच वार्ता चल रही है। क्या यह विषय भी चर्चा के लिए उठाए गए मुद्दों में से एक था? मैं सरकार और मंत्री जी से इस संबंध में जानना चाहता हूं। क्या आपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिससे आपने वर्ष 2020 तक 20,000 मे.वा. की विद्युत उत्पादित करने की परिकल्पना की है, की तर्ज पर कोई कार्यक्रम शुरू किया है। यदि आपने ऐसा कोई कार्यक्रम शुरू किया है, तो कृपया हमें उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं। इस सभा ने बड़े हर्सोल्लास और इस आशा के साथ दो राष्ट्रों के बीच 123 समझौता पारित किया किया था कि हमारे उत्पादन और उपभोग के बीच अंतराल में कमी आएगी। हमने सोचा कि यह पिछली सरकार की महानतम उपलब्धियों में से एक है। किन्तु, आज भारत सरकार पर यह एक साये की तरह लटक रहा है, चूंकि वह महसूस कर रही है कि उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके उन्होंने गलती की थी।

महोदय, मैं यहां कुछ और बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे कर्नाटक राज्य ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से 1543 मे.वा. से बढ़ाकर 2000 मे.वा. तक विद्युत आबंटित करें, चूंकि कर्नाटक में कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसके साथ दो चीजें जुड़ी हैं। एक तो अधिक विद्युत आबंटित करने से जुड़ा है अर्थात्, इसे 1543 मेगावाट से बढ़ाकर 2000 मेगावाट किया जाना और 50 मेगावाट अधिक विद्युत उपलब्ध कराना, जो कर्नाटक को केन्द्रीय ग्रिड से मिलना शेष है। और जिसे केन्द्र सरकार ने वापिस ले लिया

है। ऐसा सौतेला बर्ताव क्यों किया जा रहा है? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कृपया इस मामले पर विचार करें। हमारे विरोध करने के बावजूद भी 700 मेगावाट की आय दोगुना क्षमता जोड़ने वाले परमाणु संयंत्र – जो कि कैगा परियोजना है – को केन्द्र सरकार ने स्वीकृत नहीं किया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अगले वक्ता श्री के. बापीराजू हैं। माननीय सदस्य, कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आपने बहुत अच्छा बोला है।

...(व्यवधान)

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा : महोदय, मैं अपनी अंतिम बात कह रहा हूं। विद्युत वितरण के लिए 765 केवी स्टेशन की योजना पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ कर्नाटक द्वारा बनाई गई है। क्या आप इन सभी मुद्दों पर विचार करेंगे।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि कुछेक परियोजनाएं हैं, जो लंबित हैं। कर्नाटक विद्युत निगम लि. ने येरमारूस परियोजना; इडलापुर परियोजना; गोधना सुपर थर्मल पावर स्टेशन परियोजना; जेवारगी, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक लि. पावर कंपनी; और घाटप्रभा, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट परियोजना के प्रस्ताव भिजवाएं हैं। ये सभी परियोजनाएं केन्द्रीय स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं और केन्द्र से अभी तक हमें कोई स्वीकृति नहीं मिली है। आपके माध्यम से, हम संबंधित मंत्री जी से अपील करते हैं कि वे इन सभी बातों पर गौर करें।

इतना समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री के. बापीराजू (नरसापुरम) : मैं माननीय सभापति महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। माननीय मंत्री जी एक विनम्र मंत्री हैं और मेरे सुझाव एक सीमा तक निश्चित तौर पर लाभदायक सिद्ध होंगे।

विश्व के दो विकसित देश अर्थात् चीन और भारत अन्य सभी पहलुओं के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र के विकास में अत्यधिक सक्रियता से भाग ले रहे हैं। वस्तुतः, 10 वर्ष पहले तक, भारत और चीन ऊर्जा उत्पादन के मामले में समान स्तर पर थे।

अपराह्न 4.00 बजे

आज, हम 1,20,000 मे.वा. विद्युत का उत्पादन करते हैं, किन्तु दस वर्ष की इसी अवधि में चीन ने 6,00,000 मे.वा. विद्युत का उत्पादन आरम्भ कर दिया है। यह अंतर काफी बड़ा है। वास्तव में, सरकार की मंशा काफी अच्छी है और वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिस पर न तो कोई और न ही स्वयं मैं टिप्पणी करना चाहता हूं निश्चित तौर पर, हमारे सुझाव को सरकार इस्तेमाल में लाएगी।

ग्यारहवीं योजना में लक्ष्य लगभग 70,000 मे.वा. था। किन्तु हम 40,000 मे.वा. से अधिक हासिल नहीं कर सकते, जो हम हासिल करने की अपेक्षा कर रहे हैं। हम वह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे, जो हमने वर्ष 2012 तक प्राप्त करने का विचार किया है। चीन का लक्ष्य प्रति वर्ष 80,000 मे.वा. विद्युत का उत्पादन करने का था, किन्तु वह 1,00,000 मे.वा. विद्युत का उत्पादन कर रहा है। गत तीन वर्षों से वह 1,00,000 मे.वा. विद्युत का उत्पादन करता आ रहा है।

वास्तव में, हमारी विद्युत की मांग 3,15,000 मे.वा. में 3,35,000 मे.वा. के बीच है किन्तु हम उस मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। वर्ष 2017 तक सरकार 1,60,000 मे.वा. या 1,80,000 मे.वा. विद्युत का उत्पादन कर सकती है, किन्तु उससे अधिक नहीं। तथापि जैसा कि मैंने कहा, सरकार बहुत ही ईमानदार है और राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अतंर्गत, वह वर्ष 2012 तक 23 मिलियन परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना चाहती है। वे अपने इरादों के बहुत ही पक्के हैं। स्वाभाविक रूप से ग्रिड क्षमता में और अधिक वृद्धि की जानी चाहिए तथा उस लक्ष्य को पाने के लिए असाधारण प्रयास किए जाने चाहिएं।

भारत के लोगों ने न केवल सरकार बनाने बल्कि एक स्थिर सरकार बनाने के पक्ष में अपना फैसला दिया है, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। देश में या विश्व में कहीं और भी कोई राजनीतिज्ञ यह कल्पना नहीं कर पाया कि इस प्रकार की एक स्थिर सरकार बनेगी क्योंकि आज हमारे देश में अनेक दल मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में, जब हमने कल्पना भी नहीं की, इस देश के लोगों ने यह फैसला सुनाया है, जिसके लिए हमें खुद को साबित करना होगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, क्या आप कृपा करके बैठ सकते हैं? माननीय विदेश मंत्री को अभी एक वक्तव्य देना है। आप उसके पश्चात् अपनी बात जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 4.02 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश मंत्री श्रीमती हिलेरी क्लिंटन की हाल की भारत यात्रा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री एस.एम. कृष्णा संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश मंत्री श्रीमती हिलेरी क्लिंटन की हाल की भारत यात्रा के बारे में वक्तव्य देंगे।

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : महोदय, मैं सभा को अमरीकी विदेश मंत्री श्रीमती हिलैरी क्लिंटन की भारत यात्रा के संबंध में बताना चाहता हूं। विदेश मंत्री श्रीमती क्लिंटन ने मेरे साथ बातचीत की और उन्होंने कल प्रधान मंत्री तथा विपक्ष के नेता के साथ मुलाकात की।

यात्रा के दौरान हमने वैश्विक मुद्दों, इस क्षेत्र की स्थिति तथा द्विपक्षीय भागीदारी को संवर्धित करने पर उपयोगी और रचनात्मक चर्चा की।

हमारी सरकारों के बीच दो महत्वपूर्ण करार संपन्न किये गये हैं: (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विन्यास बोर्ड का सृजन करने के संबंध में करार और (ii) एक तकनीकी सुरक्षोपाय करार, जो भारतीय अंतरिक्ष यान पर अमरीकी उपकरणों वाले असैनिक या गैर-वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपित करने की अनुमति प्रदान करेगा।

हमारे बीच एण्ड यूज *मानीटिंरिग* व्यवस्था पर भी सहमति हुई है, जिसे अब अमरीकी रक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों की भारत द्वारा खरीद हेतु स्वीकृति के रूप में समझा जाएगा। इसके द्वारा पूर्व की सरकारों द्वारा अमरीका से रक्षा उपकरणों की खरीद की तदर्थ व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाया गया है।

हमने द्विपक्षीय वार्ता की नई रूपरेखा पर भी सहमति व्यक्त की है, जिसके अंतर्गत हम दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा जारी रखेंगें।

इस यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को घनिष्ठ और व्यापक बनाने तथा भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच भावी संबंधों की विषयवस्तु निर्धारित करने में सहायता मिली है।

हमारे विचार-विमर्श के पश्चात जारी संयुक्त वक्तव्य की प्रति सभा पटल पर रख दी गई है।

भारत अमरीका संयुक्त वक्तव्य

विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा और अमरीकी विदेश मंत्री श्रीमती हिलेरी क्लिंटन ने आज भारत और अमरीका के बीच एक संवर्धित सामरिक भागीदारी का निर्माण करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसमें हमारे समय की निर्णायक चुनौतियों का समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

उन्होंने अपने-अपने देशों की जनता, निजी क्षेत्रों और संस्थाओं के बीच आर्थिक एवं सामाजिक संपर्कों की सुदृढ़ आधारशिला पर भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच विद्यमान द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के तंत्रों को मजबूत बनाए जाने पर सहमति व्यक्त की। पिछले दो भारतीय और अमरीकी सरकारों के कार्यकाल के दौरान भारत-अमरीकी संबंधों में प्राप्त नई ऊचाइयों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संबंधों के तीसरे और ऐसे बदलाव के दौर को जारी रखने की वचनबद्धता व्यक्त की जिसके जरिए 21वीं सदी में वैश्विक समृद्धि और स्थिरता का संवर्धन किया जा सकेगा।

विदेश मंत्री श्री कृष्णा और अमरीकी विदेश मंत्री श्रीमती क्लिंटन ''भारत-अमरीका सामरिक वार्ता'' की अध्यक्षता करेंगी जिसकी एक बैठक प्रति वर्ष बारी-बारी से दोनों देशों की राजधानियों में होती है। क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं को जारी रखते हुए और भारतीय एवं अमरीकी विकास, सुरक्षा तथा आर्थिक हितों को संपूरित करने वाली आपसी लाभकारी पहल करते हुए इस वार्ता में साझे हित और चिंता के विभिन्न द्विपक्षीय, वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर बल दिया जाएगा।

विदेश मंत्री श्रीमती क्लिंटन को अगले वर्ष वाशिंगटन डीसी में आयोजित होने वाली सामरिक वार्ता के पहले दौरे के लिए विदेश मंत्री श्री कृष्णा की यात्रा की प्रतीक्षा रहेगी।

साझे सुरक्षा हितों को बढ़ावा

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण उत्पन्न खतरों के विरुद्ध पारस्परिक सुरक्षा को संवर्धित करने की साझी इच्छा को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्री श्री कृष्णा और विदेशी मंत्री श्रीमती क्लिंटन ने आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में हाल के संवर्धित समन्वय का लाभ उठाने की दोनों सरकारों की वचनबद्धता की पुष्टि की। विदेश मंत्री

श्रीमती क्लिंटन ने गृह मंत्री श्री चिदंबरम को निकट भविष्य में वाशिंगटन आने का न्यौता दिया। विदेश मंत्री श्री कृष्णा और विदेश मंत्री श्रीमती क्लिंटन ने वैश्विक सहयोग की रूपरेखा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र व्यापक अभिसमय को शीघ्र पारित करने की अपनी वचनबद्धता की पुष्टि की।

रक्षा सहयोग

वर्ष 2005 के रक्षा सहयोग करार की रूपरेखा के तहत रक्षा क्षेत्र में संवर्धित सहयोग पर गौर करते हुए विदेश मंत्री श्री कृष्णा और विदेश मंत्री श्रीमती क्लिंटन ने रक्षा क्षेत्र में आपसी लाभकारी सहयोग को आगे बढ़ाने की दोनों सरकारों की वचनबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री श्री कृष्णा ने घोषणा की कि दोनों पक्षों ने अमरीकी रक्षा उपकरणों के लिए अंतिम प्रयोग प्रबोधन करार पर सहमति व्यक्त की है।

नाभिकीय शस्त्र मुक्त विश्व की आवश्यकता

भारत और अमरीका दोनों एक ऐसे विश्व की परिकल्पना करते हैं जो नाभिकीय शस्त्रों से मुक्त हो। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्री श्री कृष्णा और अमरीकी विदेशी मंत्री श्रीमती क्लिंटन ने निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में निष्पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी एवं सत्यापनीय विखण्डनीय पदार्थ नियंत्रण संधि संपन्न करने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति व्यक्त की। भारत और अमरीका नाभिकीय आतंकवाद की रोकथाम करने और वैश्विक नाभिकीय प्रसार की चुनौती का मुकाबला करने में सहयोग भी करेंगे। इस मुद्दे पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक उच्चस्तरीय वार्ता क्षेत्र की स्थापना की जाएगी।

असैनिक नाभिकीय सहयोग

भारत-अमरीका असैनिक नाभिकीय पहल की सफलता का लाभ लेते हुए, 21 जुलाई को, भारत और अमरीका के बीच शांतिपूर्ण नाभिकीय सहयोग के लिए 123 करार के अनुच्छेद 6 (iii) के प्रावधान के अनुसार पुनर्प्रसंस्करण व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं पर विचार-विमर्श आरंभ करेंगे।

वैश्विक संस्थाएं

विदेश मंत्री श्रीमती क्लिंटन ने इस बात की पुष्टि की कि वैश्विक संस्थाओं एवं समूहों को 21वहीं सदी के विश्व को प्रतिबिम्बित करना चाहिए जिससे की इनकी दीर्घावधिक विश्वसनीयता, प्रासंगिकता एवं प्रभावित बनी रहे और साथ ही विदेश मंत्री श्री कृष्णा और अमरीकी विदेश श्रीमती क्लिंटन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जी-8 तथा जी-20 की गई संरचना पर विचार विनिमय करने में रुचि व्यक्त की।

सतत आर्थिक विकास एवं वृद्धि को बढ़ावा

जी-20 के सदस्यों के रूप में भारत और अमरीका के अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर मुक्त व्यापार एवं निवेश नीतियों के प्रति वचनबद्धता के जरिए स्थाई रूप से वैश्विक आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। विदेश मंत्री श्री कृष्णा और अमरीकी विदेश मंत्री श्रीमती क्लिंटन ने विश्व व्यापार संगठन के दोहा दौर की वार्ताओं में प्रगति को सुविधाजनक बनाने की दोनों सरकारों की वचनबद्धता व्यक्त की।

उन्होंने दोनों देशों के बीच वर्षों के दौरान पनपी आर्थिक समानताओं को न केवल सिर्फ बनाए रखने के लिए सहयोग करने बल्कि साथ-साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ाने और उसका विस्तार करने और व्यापार एवं निवेश प्रवाह को बढ़ाने की भी वचनबद्धता व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नोट किया कि द्विपक्षीय निवेश संधि अगस्त, 2009 में नई दिल्ली में संपन्न होगी। इन्होंने दोनों देशों के निजी क्षेत्रों की कार्यकुशलता और उद्यमशीलता के नवगठित सीईओ मंच, जिसकी बैठक इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में होगी, का उपयोग करने का भी संकल्प लिया।

शिक्षा

विदेश मंत्री श्री कृष्णा और अमरीकी विदेश मंत्री श्रीमती क्लिंटन ने आदान-प्रदान और सांस्थानिक सहयोग के माध्यम से शैक्षिक सहयोग को बढ़ाने की महत्ता की पुष्टि की और इस सहयोग को मजबूत बनाने में निजी क्षेत्रों की भूमिका को बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमत हुए।

अन्तरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं नवाचार

दोनों पक्षों ने भारत-अमरीकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग की अपार संभावना को स्वीकार करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विन्यास करार संपन्न किया और एक प्रौद्योगिकी सुरक्षोपाय करार पर हस्ताक्षर किए जो कि भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर अमरीकी उपकरणों वाले असैनिक या गैर-वाणिज्यिक उपग्रहों को प्रक्षेपण की अनुमति प्रदान करेगा। दोनों पक्षों ने पृथ्वी एवं महासागर गतिकी के प्रति समझबूझ को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का हल ढूंढने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय महासागर वेधन कार्यक्रम में भारत की भागीदारी और

[श्री एस.एम. कृष्णा]

प्रथम वाणिज्यिक आधार पर पूर्णत: अखंडित कार्बन प्रग्रहण एवं पृथक्करण परियोजना का निर्माण करने के लिए फ्यूचर जेन परियोजना में भारत की भागीदारी का स्वागत किया।

उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग

दोनों देशों की ज्ञान एवं नवाचार आधारित अर्थव्यवस्थाओं की संपूरकताओं के कारण विद्यमान अत्यधिक संभावना को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग वार्ता की कार्यसूची और पहलों को जारी रखने पर सहमति हुई ताकि भारत-अमरीकी संबंधों के वर्तमान सामरिक स्वरूप को दर्शाते हुए दोनों अर्थ-व्यवस्थाओं के बीच उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार सुविधाजनक हो सके।

यह भी सहमति हुई कि नैनो-प्रौद्योगिकी, असैनिक नाभिकीय प्रौद्योगिकी, नागर विमानन और रक्षा, सामरिक एवं असैनिक नाभिकीय व्यापार में लाइसेंस के मुद्दों पर साझे हित के नए क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कार्यदल गठित किया जाएगा।

ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

विदेश मंत्री श्री कृष्णा और अमरीका की विदेश मंत्री श्रीमती क्लिंटन ने ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग संवर्धन की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ये प्रयास भारत-अमरीका ऊर्जा वार्ता और वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ता के माध्यम से बढ़ती ऊर्जा प्रभाविता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर केन्द्रित होंगे।

सौर एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा, परिष्कृत कोयला एवं ऊर्जा प्रभाविता और अन्य संगत क्षेत्रों सहित आपसी रूचि के क्षेत्रों में परिवर्तनशील एवं नवाचारी प्रौद्योगिकियों का विकास, तैनाती एवं अंतरण में सहायता के लिए दोनों पक्ष द्विपक्षीय वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग की प्रक्रिया शुरू करने पर भी सहमत हुए।

दिसंबर, 2009 में कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित यूएनएफसीसीसी सम्मेलन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए भारत और अमरीका ने प्रमुख अर्थव्यवस्था मंचों सहित अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

वैश्विक मुद्दे

दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के सह-संस्थापक के रूप में लोकतांत्र को मजबूत बनाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं में क्षमता निर्माण करने जैसे साझे हित के वैश्विक मुद्दों पर दोनों सरकारों के बीच उपयोग तालमेल का भी उल्लेख किया।

दोनों पक्ष महिला सशक्तीकरण एवं विकास दर जानकारियों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने के लिए महिला सशक्तीकरण मंच (डब्ल्यूईएफ) को विकसित करने और इस क्षेत्र तथा उससे परे भी महिलाओं को सशक्त बनाने के तरीकों पर विचार करने पर सहमत हुए।

निष्कर्ष

विदेश मंत्री श्री कृष्णा और अमरीकी विदेश मंत्री श्रीमती क्लिंटन ने इस बात की पुष्टि की कि भारत और अमरीका के बीच अच्छे संबंधों का आधार भारतीय और अमरीकी जनता के बीच परस्पर संबंध, वाणिज्य एवं शैक्षिक संपर्क है।

अमरीकी विदेश मंत्री श्रीमती क्लिंटन ने सौहार्दपूर्ण स्वागत और आतिथ्य-सत्कार के लिए विदेश मंत्री और भारत के लोगों को धन्यवाद दिया।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 403/15/09]

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल) : एक प्रश्न का उत्तर देना अभी बाकी है...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग) : उन्होंने उनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जो मैंने सुबह उठाये थे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह वाद-विवाद नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : क्या आपने सभा को विश्वास में लिया है?...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : मैं कहना चाहता हूं कि यू.एस. के सैक्रेट्री ऑफ स्टेट अमरीकी विदेश मंत्री के दौरे के बारे में पूर्ण वक्तव्य नहीं मांगा था। आज सुबह मेरे साथी श्री यशवंत सिन्हा द्वारा एक मुद्दा उठाया गया था और लगभग पूरे विपक्ष ने उनकी बात का समर्थन किया था। हमने कहा कि हम इस मामले का स्पष्टीकरण आज ही करना चाहते हैं। अन्यथा हम भारत-पाक संयुक्त वक्तव्य सहित विदेश मामलों से जुड़े विविध मामलों पर व्यवस्थित वाद-विवाद चाहते हैं। हमें ऐसा करना पड़ेगा और यहां उद्धृत प्रश्नों सहित हमें कई और

सारे प्रश्न पूछने पड़ेंगे। परन्तु आज हमने यह उम्मीद की थी कि विदेश मंत्री उस बिन्दु का स्पष्टीकरण देंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि हम भी उस एन्ड यूज निगरानी व्यवस्था पर सहमत थे जिसे यहां अब के बाद अमरीकी रक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरण की भारतीय खरीद हेतु स्वीकृति पत्र का संदर्भ दिया गया था। इतना ही नहीं बल्कि, उन्होंने आगे यह भी कहा कि व्यक्तिगत रक्षा खरीद के लिए अमरीकी के साथ यह प्रणालीगत और तदर्थ व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गयी है, ताकि पूर्ववर्ती मामलों के संबंध में भी औपचारिक प्रणालीगत व्यवस्था के अंतर्गत ऐन्ड यूज व्यवस्था का उपयोग करने का प्रयास किया जा सके। यह बेहद परेशान करने वाली बात है। अतएवं; मैं उम्मीद करता हूं कि इस ओर के मेरे कई साथियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर विदेश मंत्री द्वारा दिए जाएं। इस वक्तव्य के मद्देनजर मेरा मानना है कि आप इस पर तत्काल वाद-विवाद करने की अनुमति दें, ताकि सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। यदि ऐसा होने वाला है तो मैं यही रुक जाऊंगा अन्यथा; चूंकि जैसे कि अन्य सभाओं में रिवाज है इस सभा में इस प्रकार से पूछने का प्रचलन नहीं है अतएवं मेरा मानना है आज विरोध स्वरूप मेरा दल सदन से बाहर जाना चाहेगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वक्तव्य देते समय मंत्री ने उनमें से किसी भी प्रश्न का स्पष्टीकरण नहीं दिया, जो आज हमने उठाये थे। हमें इस वक्तव्य की जरूरत नहीं है। हमने जो प्रश्न उठाये थे वे इसी संबंध में थे कि हमें वक्तव्य की क्या जरूरत है। इसी कारण से हमने वक्तव्य की मांग की। हमने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा भारत सरकार अमरीकी द्वारा ऐन्ड यूज निगरानी के लिए तैयार क्यों हो गयी? और वे इस प्रणाली को औपचारिक बनाना चाहते हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि अमरीका के आगे घुटने टेकने के समान है। इस प्रकार विदेश मंत्री ने पूरे विपक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्नों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया कोई वाद-विवाद न करें। मैं इस पर वाद-विवाद नहीं करना चाहता। श्री बापी राजू आप अपनी बात जारी रखें।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह सभा का अधिकार है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री के वक्तव्य के बाद नियम वाद-विवाद की अनुमति नहीं देते।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम इस प्रकार का वक्तव्य नहीं चाहते ...*(व्यवधान)* हम मंत्री से स्पष्टीकरण चाहते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, हम नियमों में बंधे हुए हैं। नियम वाद-विवाद की अनुमति नहीं देते। श्री बापी राजू आप अपनी बात जारी रखें। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आपको मेरी बात माननी होगी।

*...(व्यवधान)**

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, आपको हमारी रक्षा करनी होगी। आप हमारी बात सुनिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हमें नियमों का पालन करना ही होगा।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री ने इस सभा का कम सम्मान किया है। पूरा विपक्ष मांग कर रहा है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों नियम वाद-विवाद की अनुमति नहीं देते। माननीय विपक्ष के नेता ने यह वक्तव्य दिया है।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : अन्य माननीय सदस्य वहां पर हैं। कृपया उनकी बात भी सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : वक्तव्य में ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार को यह समझौता क्यों करना पड़ा। ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए गए?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाईए। वक्तव्य कौन देना चाहेगा? कृपया स्पष्टीकरण ही मांगें।

श्री गुरुदास दासगुप्त : माननीय सभापति महोदय, संपूर्ण विपक्ष ने अपनी इस आशंका को व्यक्त किया है कि अमरीका से ली जा रही प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार होगा। उसका ऐन्ड यूज अमरीकी संभवत: अमरीकी सैनिकों के निरीक्षण के अध्याधीन हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों में इनका उपयोग किया जाएगा वे अमरीकी व्यक्तियों के पर्यवेक्षण में रहेंगे। इससे हम असुरक्षित हो जाएंगे। इससे हम अमरीका के पूरी तरह से ताबेदार जो जाएंगे। यह हमारी संप्रभुता का आत्मसमर्पण है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुके हो।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, सुबह जब मैंने उपाध्यक्ष की अनुमति से यह मुद्दा उठाया था तो मैंने कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाये थे जो समाचार पत्र में कुछ अल्पवर्द्धित रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।

[हिन्दी]

सारी सूचना अखबारों के माध्यम से हमें नहीं मिली। हमें कुछ-कुछ सूचना मिली कि एंड यूज मॉनीटरिंग एग्रीमैंट, एंड यूज वैरिफिकेशन एग्रीमैंट ऐसा कुछ भारत सरकार और अमेरिका के बीच में तय हुआ है। चूंकि इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें भी है, उस मंत्रालय में मैंने भी सर्व किया है, इसलिए मेरे मन में कई प्रकार की शंकाएं पैदा हुईं, जिन्हें मैंने यहां रखा। मैंने कहा कि जैसे स्पेसिफिकली जो थर्ड कंट्री इम्पोर्ट्स होते हैं, उसमें अगर अमेरिकन इक्युपमैन्ट लगा है, अमेरिकन टैक्नोलोजी का इस्तेमाल हुआ है तो उस पर भी यह लागू होगा। यह एक सवाल था, जो मैंने पूछा कि खास तौर पर सरकार की तरफ से बताया जाए कि अमेरिका से जो खरीदेंगे, उस पर तो लगेगा ही लगेगा, तीसरे मुल्क से जो खरीदेंगे, उस पर भी लगेगा और मैं जानता हूं कि इस प्रकार की बात हैं इसीलिए मैं इस सदन में जिम्मेदारी के साथ इस बात को उठा रहा हूं। इसके बाद मैंने कहा कि सरकार की तरफ से यह बयान दिया गया है कि जो चल है, चल मतलब अचल से भिन्न चल, जो मूवेबल है, उसे हम लोग दिखा देंगे। प्रधान मंत्री के लिए एयरक्राफ्ट है, एक हाई सिक्युरिटी एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है, जिसमें कि बहुत विशेष तौर के रडार वगैरह लगाये जायेंगे, लिखा गया कि इसे हम किसी नॉन एयरफोर्स बेस पर लाकर दिखा देंगे। लेकिन मैंने सवाल किया जो अचल है, जो इम्मूवेबल है, उसमें वैरिफिकेशन कैसे होगा, उसे उठाकर कैसे लायेंगे? बंगलुरू में अगर कोई संयंत्र लगा, जिसमें इनकी टैक्नोलोजी या इनका इक्युपमैंट यूज किया गया तो उसे कैसे लायेंगे? इसलिए मुझे शक हुआ कि जनता को गुमराह करने के दृष्टिकोण से इस प्रकार का सलैक्टिवली मीडिया में किया जा रहा है, ताकि देश संतुष्ट रहे कि ऐसा कुछ नहीं है।

[अनुवाद]

इसी कारण से इस संबंध में मैंने यह कहा था कि इस सभा में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। यह इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है। हमें यह जानने का अधिकार है कि क्या सरकार विदेशी सरकार की बात से सहमत है। तब जैसाकि हमारे विपक्ष के नेता ने कहा यहां दो वाक्यों के दिए गए सौम्य वक्तव्य से कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। हमें उन प्रश्नों के उत्तर चाहिए जो हमने उठाये थे? वक्तव्य में ऐसा कुछ भी नहीं है महोदय। कुछ भी नहीं है। इसलिए, हम पूर्णतया असंतुष्ट हैं; जिस कागज पर यह वक्तव्य लिखा गया है उसका कोई महत्व नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : सभापति महोदय, अभी माननीय श्री यशवंत सिन्हा ने जो कुछ कहा, उसी आधार पर हम सभी विपक्ष के सभी लोगों ने अपनी राय और सहमति व्यक्त की है। जब हमने अपनी आचार-संहिता दी है कि जो टैक्नोलोजी देंगे, उस पर अपना उत्तर देंगे तो उसकी जांच करेंगे। जैसा कहा गया कि बंगलौर में या कई और जगह भी हैं, वहां पर जाकर इनका सारा का सारा सामान उठाकर ले जायेंगे या हम अपनी टैक्नोलोजी से या अपने तरीके से कर रहे हैं, क्या उनको भी अमरीका जाकर देखेगा? जो भी जांच करने वाले आयेंगे, वे अमरीका से आयेंगे और दूसरी तरफ और जगह से भी? यह सब से खतरनाक है कि अमरीका से दूसरे या तीसरे देश में टैक्नोलोजी गई, वहां भी हटा ली गई तो उसकी भी जांच होगी? क्या अमरीका हमारा मालिक है? हमारा अपना स्वतंत्र देश है, उसकी अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान है। हमारी अपनी नीति है। एक स्वतंत्र देश की नीति अपनाई गई। मुझे लगता है कि आप नेहरु जी को भूल गये? आप नेहरु जी को पढ़ लेना। उन्होंने कहा था कि हमारे देश की विदेश नीति या हमारे देश की सुरक्षा के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर हमारे देश की सुरक्षा के मामले में कोई हस्तक्षेप करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां तक कहा कि अगर दुनिया में कहीं इस तरह का अन्याय होगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। यह नेहरु जी की नीति रही है। हम तो आपको नेहरु जी के बारे में बतना चाहते हैं। हमें लगता है कि आप गांधी को भूले हैं, नेहरु जी को भी भूल गये हैं। इसलिये हम विदेश मंत्री जी के बयान से सहमत नहीं है। यह कोई गुड्डा-गुड़िया का खेल नहीं है कि ऐसे ही बात कर ली। यह देश की सुरक्षा का सवाल है, देश के स्वाभिमान का सवाल है। इसलिए मैं मंत्री जी के बयान से सहमत नहीं हूं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार के समर्थन में एनटायर लोग हैं, और हम सब लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, बहुत गम्भीरता से कहा...*(व्यवधान)* आप सब लोगों ने मामला उठाया, यह अच्छी बात है, आप परेशान क्यों हैं? मैं अच्छी बात उठा रहा हूं कि आप के समर्थन के बावजूद

भी मंत्री जी का बयान बिल्कुल निर्गुण है। विदेश मंत्री जी नये-नये बने हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह केवल एंड यूज़ वाला मामला नहीं है। जब जार्ज बुश साहब यहां आये थे तो अमरीका के कुत्ते गांधी जी की समाधि पर गये थे और आज देश के पूर्व राष्ट्रपति का फिज़िकल सर्च किया गया है। जूते से लेकर सारी चीज़ उतार कर सर्च किया गया। इसमें एक सवाल नहीं है, एक बात नहीं है। आप जिस तरह से अमरीका से बात कर रहे हैं जबकि हमारे देश की जनसंख्या उनसे चौगुनी-पांच गुनी है। हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान है, उसे आप लगातार कुचल रहे हैं। आप उनसे बातचीत कर रहे हैं और यहां बयान देने को तैयार हुये। इसलिये इसमें एक सवाल नहीं है, इसमें कई सवाल हैं। कई बार ऐसा हुआ है। अभी शर्म अल शेख में जो कुछ आपने किया, बलूचिस्तान का जिक्र देश की आजादी के 60 सालों में कभी नहीं हुआ है। इस बारे में कोई सवाल नहीं था जो आपने पिंडोरा बाक्स खोल दिया। अपने पूरी तरह से अमरीका को देख लिया है, उसके बाद भी उनसे बातचीत करके उसके साथ उनके अनुसार चलने का काम कर रहे हैं। इसलिये यह एक सवाल नहीं है, कई सवाल हैं जिनके चलते आप उसकी तरफ झुके हुये हैं और आपकी विदेश नीति अमरीका के पास गिरवी रखी हुई है। इसलिये मैं सरकार पर यह चार्ज लगाना चाहता हूं, यह नहीं होना चाहिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है; यह वाद-विवाद नहीं है; आप अपना विचार रख चुके हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, मैं यहां अपना रोष प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम लोगों ने सुबह वक्तव्य की मांग की थी पर यह वक्तव्य बजाए उन चीजों को उद्घटित करने के, जिसकी हमने मांग की थी, काफी चीजों को छुपाती है। हम यह जानना चाहते थे कि सरकार को इस प्रकार के द्विपक्षीय समझौते के लिए किसने तैयार किया। यहां जिस चीज का उल्लेख किया गया है, वह यह कि इस दौरे ने अमेरिका के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक विस्तृत और गहरा किया है, परन्तु क्या इस द्विपक्षीय संबंध को विस्तृत और गहरा संप्रभुता के मूल्य पर किया गया है? यही सवाल है। मुझे याद है 30 साल पहले जब रक्षा व्यवस्था और खरीद पर चार्च हो रही थी, विशेषकर, सचेतरूप से भारत सरकार ने छठे दशक के उत्तरार्द्ध में और सातवें दशक के पूर्वार्द्ध में यह निर्णय लिया था कि हम किसी भी सरकार को, चाहे वह कोई भी हो, कितनी भी समर्थ ही भारतीय रक्षा तंत्र में उन्हें शामिल या भागीदारी नहीं बनाएंगे, जहां हमें अपनी संप्रभुता का त्याग करना पड़े। यह निर्णय छठे दशक के उत्तरार्द्ध और सातवे दशक के पूर्वार्द्ध में लिया गया था और यह जारी रहा। पूरी सभा ने उस समय सचेत रूप से यह निर्णय लिया था कि वे इस निर्णय का पालन करेंगे। यही वह निर्णय था जिसे शीत युद्ध के दौरान लागू किया गया था। बिना किसी पार्टी संबद्धता को ध्यान में रखते हुए सभी ने इस निर्णय का समर्थन किया था। आज क्या हो गया है? शीत युद्ध समाप्त हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम किसी एक शक्ति को इस विश्व पर नियंत्रण नहीं करने देंगे। भारत लागतार आधिपत्य के खिलाफ रहा है। मैं एक बार फिर सभा के सभी सदस्यों से और इस सरकार से यह निवेदन करूंगा; कि यह वक्तव्य हमारे रोष का शमन नहीं करता है। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि सरकार के पास अब भी समय है कि वह इस समझौते से बेदाग निकल आए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहती हूं कि एंड यूज़ मॉनीटरिंग एग्रीमेंट का विरोध इस सदन में आज पहली बार नहीं हो रहा है। वर्ष 2008 में भी इसका विरोध इतने ही पुरजोर ढंग से इसी सदन में हुआ था। यह अलग बात है कि विदेश मंत्री जी उस समय इस सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन सरकार एक निरन्तरता का नाम है और उन्हें यह बात जरूर बतायी जा चुकी होगी कि देश की संसद इसके विरोध में थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि केवल सांसद ही नहीं आपके अपने ऑफिसियल स्टैब्लिशमेंट ने भी इसका विरोध किया है। ...* ने इस एग्रीमेंट को इन्ट्रयुसिव कहा है। उन्होंने कहा है कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम पैसा दे देते हैं, हमने पैसा दे दिया, टैक्नोलॉजी खरीद ली, अब उसके मास्टर हम हैं और अब उस पर कोई इंस्पैक्शन नहीं कर सकता है। इसके लिए उन्होंने इन्ट्रयुसिव शब्द का प्रयोग किया है। सीएजी की रिपोर्ट आयी है, इसमें भी विरोध किया गया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि संसद के विरोध को, अपने ऑफिसियल स्टैब्लिशमेंट के विरोध को, सीएजी के विरोध को एक तरफ देखते हुए आपने इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किये?

महोदय, मेरा दूसरा सवाल है कि हम भी अमेरिका के साथ अच्छे रिश्तों के पक्षधर रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी हम दोस्ती के स्तर पर रिश्ता चाहते हैं, दासता के स्तर पर नहीं। आपका यह समझौता दासता का प्रदर्शन कर रहा है इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। अभी शरद यादव जी ने कांटीनेंटल एयरलाइंस के व्यवहार पर

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

माननीय कलाम जी की बात कही। भारत की भूमि पर, भारत के पूर्व राष्ट्रपति के जूते, मौचे सुरक्षा के नाम पर उतरवा दिये जाएं, यह क्या है? इस एक घटना से पूरे देश के लोगों का स्वाभिमान हिल गया है। हर देशवासी आहत हुआ है, लेकिन शासकों का स्वाभिमान नहीं हिला, उनका स्वाभिमान आहत नहीं हुआ है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि दासता के स्तर पर अमेरिका के साथ मत जाइए। जो चीज हम खरीदते हैं, उसका वे आकर इंस्पैक्शन करेंगे, जैसा कि सिन्हा जी ने कहा कि अगर हम दूसरे देश से खरीदते हैं और अगर उसमें भी कोई डुएल यूज का पुर्जा अमेरिका का बना हुआ लगायें, तो वे आकर उसका भी इंस्पैक्शन करेंगे। ऐसा समझौता हमें कतई मंजूर नहीं है। यह लोकतंत्र का तकाजा है कि अगर आपने इस समझौते पर कल हस्ताक्षर कर दिये हैं तो यह संसद लोकप्रतिनिधित्व संस्था है और लोक का दबाव मानते हुए इस समझौते को समाप्त करें। इस समझौते को रद्द कर दें। यह मेरी आपसे मांग है।

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : प्रात:काल इस सभा के अधिकांश सदस्यों ने एक गंभीर मुद्दा उठाया था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बहस न करें। सभा के संचालन के लिए अध्यक्ष पीठ है।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : सभापति महोदय, महाशय प्रात:काल अधिकांश सदस्यों ने, विशेषकर विपक्ष ने, एक गंभीर मुद्दा उठाया तथा सरकार से यह कहा कि अमेरिका के साथ समझौते के संबंध में जो हुआ उस पर वक्तव्य देकर अपनी बात स्पष्ट करें। मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि "हम लोगों ने एंड यूज़ मॉनीटरिंग एग्रीमेंट पर भी समझौता कर लिया है। "इसका क्या मतलब है? अमेरिका किस प्रकार यहां आकर और सभी चीजों पर नियंत्रण करेगा? हमें अपनी संप्रभुता सुरक्षित रखनी होगी। जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी कहा है जब हम इन उपकरणों को खरीद रहे हैं, तो हमें इस बात का पूरा अधिकार है कि हम जो करना चाहे वह करें। श्रीमती सुषमा स्वराज ने अभी-अभी कहा है कि हमारे अच्छे संबंध हों, परंतु ऐसे संबंध नहीं, जहां शर्तों का निर्धारण वे करें, इस कारण हमलोग चिंतित हैं। मंत्री जी कहते हैं "हम लोग चर्चा जारी रखेंगे।" अब आप क्या चर्चा करेंगे? एक बार जब अपने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, तो सब कुछ संपन्न कर दिया। इसलिए अब आप क्या चर्चा करेंगे? क्या आप इस समझौते को वापस लेंगे? हम यही जानना चाहते हैं। सभी माननीय सदस्यों की गंभीर चिंता यही है कि हम लोग अपनी संप्रभुता किसी विदेशी के सामने नहीं रख सकते। अत: सबसे पहले आप इस समझौते को रद्द करें। हम सबकी आपसे यही आशा है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, अब हम अनुदान की मांगों पर चर्चा शुरू करें।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने अभी नहीं बोला है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप एक बार पहले बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं। यह वाद-विवाद नहीं है। कृपया बैठ जाइए। विपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, मुझे स्मरण है कि इसी प्रकार की स्थिति पहले भी खड़ी हुई थी जब 123 एग्रीमैंट की बात थी। तब हमें लगता था कि दुनिया के बहुत सारे देशों में – अमरीका उनमें से एक है – कि जहां पर अगर कोई सरकार कोई वैदेशिक समझौता करती है तो उसको पुष्टि के लिए वहां की कांग्रेस के पास आना पड़ता है। मुझे लगा कि अगर इस प्रकार के कोई भी समझौते होते हैं जिनका देश की सार्वभौमिकता पर प्रभाव पड़ता है, देश की एकता पर प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में संविधान में परिवर्तन करने की जरूरत पड़े तो भी करना चाहिए कि भारत का संविधान इस प्रकार के समझौतों में संसद की पुष्टि आवश्यक माने – कहीं पर भी सार्वभौमिकता पर प्रभाव पड़ेगा या देश की एकता पर प्रभाव पड़ेगा तो उसकी पुष्टि संसद करे। मुझे लगता है कि कल आपने जो समझौता किया है, वह हमारी उस आशंका को और मजबूत करता है और आवश्यक बनाता है कि इस प्रकार का संशोधन संविधान में किया जाए कि इस प्रकार के समझौते कोई न करे। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कोई यहां पर आकर मॉनीटरिंग करे। यहां तक कि 123 एग्रीमैंट के बारे में भी जब राज्य सभा में प्रधान मंत्री बोले थे, तब उन्होंने कहा था कि हम ऐसी स्थिति कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई विदेशी प्रतिनिधि यहां आकर मॉनीटर करे। आपने स्वयं मान लिया? न केवल कल की बात में माना है, बल्कि यदि पूर्व की

सरकार ने कोई समझौता किया है तो उसके लिए भी मान लिया है। ये सारी की सारी बातें ऐसी हैं कि जिनके साथ जैसे पिछले सप्ताह मैंने कहा, उस वक्त लगता ऐसा था कि जैसे सदन ही, विपक्ष ही सरकारी पक्ष से सहमत नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे बातें सामने आई हैं, वैसे लगता है कि जो इंडिया-पाकिस्तान जॉइंट स्टेटमैंट प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया है, उसके साथ न केवल विपक्ष, लेकिन सरकारी पक्ष के भी बहुत सारे लोग सहमत नहीं हैं। यहां तक कि सरकारी पक्ष के प्रवक्ता ने उसकी पुष्टि करने से इंकार किया है। यह तो पहली बार हिन्दुस्तान के राजनीतिक इतिहास में हुआ है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस मामले में सबक लेकर वैदेशिक मामलों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जो कुछ दृश्य आज दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि दो सप्ताह में लगातार दो बार आपने ऐसी बात की है जिसके कारण जो एक राष्ट्रीय सहमति बनी थी आतंकवाद के संदर्भ में, राष्ट्रीय सहमति बनी है कि विदेशी सरकारों के प्रभाव में आकर हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, उस सहमति को आपने तोड़ दिया है। एक बार पिछली बार और एक बार आज। हम इसका विरोध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम लोग इस प्रकार का वक्तव्य नहीं चाहते...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप पहले बोल चुके हैं। एक सदस्य दो बार नहीं बोल सकते। आप पहले बोल चुके हैं। श्री आचार्य, कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : वह पहले बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या मंत्रीजी कुछ कहना चाहेंगे?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हम इससे सहमत नहीं हैं हम वाकआउट करते हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 4.30 बजे

[अनुवाद]

(इस समय श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, चूंकि सरकार ने हमारे सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, इसके विरोध में हम सभा से वाकआउट कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.31 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : सभापति महोदय, दो संप्रभु राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय समझ के संबंध में जो व्याख्या मांगी गई है, उससे मैं आश्चर्यचकित हूं। जैसा कि मुझे भी एहसास है, कि मैं उस महान राष्ट्र का नागरिक हूं जिसकी सभ्यता की हम हमेशा ऊंची बातें करते हैं। अत: हमारी स्वतंत्रता का प्रश्न, हमारी संप्रभुता का प्रश्न इस स्थिति में नहीं उठता। यह दो संप्रभु राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय समझौता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ। जब कतिपय हाइ-एंड रक्षा उपकरणों की खरीद हो रही थी, उस समय प्रत्येक अवसर पर क्या किया जा रहा था, जबकि उस समझौते में एक खण्ड है जिसमें इसके अंत प्रयोग वाले खंड को समाविष्ट किया गया था। परंतु हमने यहां ऐसी कोशिश की है कि यहां के बाद सभी हाइ-एंड रक्षा उपकरणों की भारत और अमेरिका के साथ खरीद पर इसे सामान्य बनाने की कोशिश की है...*(व्यवधान)* हम प्रत्येक देश के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। अत: यहां पर कुछ भी असाधारण नहीं है। सब कुछ बहुत ही स्पष्ट है। हम लोग जो कर रहे हैं उसके प्रति सचेत हैं। ऐसा देश के व्यापक हित में किया गया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस पर अब और बहस नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मंत्री जी ने उत्तर दिया है। यह तो परम्परा बन गई है, जिस तरह से राज्य सभा में सवाल जवाब पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है। लेकिन इस सदन

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

में अभी तक यह परम्परा नहीं थी। इसीलिए मैं शुरू में रिस्पोन्स की आग्रह नहीं कर रहा था। लकिन मित्रों ने रिस्पोन्स का आग्रह किया, आपने रिस्पोन्स दिया, उससे हम पूरी तरह से असंतुष्ट हैं, क्योंकि एक भी बात इन्होंने हम को नहीं समझाई है, जो कि इसमें नहीं है। जो इसमें हैं, केवल उसी को कहा है। आप कह रहे हैं कि जो हमने किया है, सही है, कोई गलत नहीं है। मैं मानता हूं कि इससे पूरे देश को गलत संदेश गया है। ज्वाइंट स्टेटमेंट पर जब स्ट्रक्चर्ड डिबैट होगी, तब हम उस पर और विस्तार से कहेंगे। अभी हम बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 4.33 बजे

(इस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री शरद यादव और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री भर्तृहरि महताब : हम भी संतुष्ट नहीं हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 4.34 बजे

अनुदानों की मांगों (सामान्य), 2009-2010 — *जारी*

विद्युत मंत्रालय

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बापीराजू, आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री के. बापीराजू (नरसापुरम) : सभापति महोदय, अपना भाषण जारी रखते हुए सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह ने एक राजनेता की तरह इस समझौते की जांच करने का निर्णय लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सभी अलग-अलग राजनीतिक दलों से हैं लेकिन हमारे पास एक दृष्टिकोण है और प्रधानमंत्री ने अपने दृष्टिकोण से ही अमरीका के साथ परमाणु समझौता करने का निर्णय लिया है। वे एक बार इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के पद से भी त्यागपत्र देने के इच्छुक थे। संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने सरकार चले जाने की कीमत पर भी इस समझौते की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। श्री राहुल गांधी ने और प्रयास किया एवं लोगों को उस समझौते के बारे में स्पष्टीकरण दिया जिस पर इस देश ने अमरीका के हस्ताक्षर किया था। राजनेताओं की सोच ऐसी ही होती है।

सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने एक सौर संयंत्र का उद्घाटन किया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि सौर ऊर्जा से इस देश के भाग्य को बदलने में मदद मिल सकती है।

महोदय, सौर ऊर्जा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। हमारा देश उष्ण कटिबंधीय देश है एवं हमारे यहां सूरज अधिक समय तक चमकता है। इसी के साथ यहां गुरुत्वाकर्ष की सघनता अधिक है जिसका लाभ हम उठा सकते हैं। हमारे देश में जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से हमें मदद मिलेगी। शुरू में बुनियादी ढांचे पर लागत आएगी लेकिन तदन्तर हमें इससे लाभ होगा। सौर ऊर्जा के बारे में आपने सही योजना बताई है। सरकार विचार वर्ष 2020 तक 20,000 मेगावाट उत्पादन करने का है। वर्ष 2030 तक सरकार का विचार लगभग एक लाख मेगावाट का उत्पादक करने का हैं और वर्ष 2050 तक सरकार दो लाख मेगावाट उत्पादन करने के बारे में सोच रही है इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। हमारी मांग बहुत ज्यादा है और इसके साथ ही उत्पादन बहुत कम है जिसके लिए निश्चय रूप से हमें और उत्पादन करना होगा।

जब मैं संसदीय समिति का सदस्य था उस समय मैंने पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की बात उठाई थी। उस समय यह हानि 38 प्रतिशत थी तथा औसत हानि 34 प्रतिशत है। मुझे आंध्र प्रदेश के बारे में यह कहते हुए गर्व है कि मुख्य मंत्री ने किसानों को नि:शुल्क बिजली दी है। किसानों को लगभग 2.80,000 कनेक्शन दिए गए हैं। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। यह शत प्रतिशत राजसहायता प्राप्त है। अत: जहां चाह है वहां राह है। इसी इच्छा के कारण वह ऐसा करने में सक्षम हैं। वह इस लागत में भारत सरकर के साथ हिस्सेदारी नहीं करते हैं। वह जुलाई से सात से नौ घंटे देने में सक्षम हैं। इससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे देश के कृषकों को निशुल्क बिजली देने का तरीका निकालने का अनुरोध करता हूं। मैं आपकी ही तरह से शत प्रतिशत देने की सलाह

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं दे रहा हूं। इसमें 50 प्रतिशत राज्य की तरफ से और शेष 50 प्रतिशत का अंशदान आपकी तरफ से हो सकता है।

अपराह्न 4.37 बजे

[श्री अर्जुन चरण सेठी पीठासीन हुए]

पहले से ही आंध्र प्रदेश द्वारा इसमें शत प्रतिशत अंशदान किया जा रहा है।

जहां तक बुनियादी संरचना की बात है, योजनाओं को मंजूरी मिल जाने एवं विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमति देने के बाद भी छोटी मोटी सिविल याचिकाओं से बाधा जा जाती है। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर बांध हेतु 20 वर्ष पहले परमाणु ऊर्जा मंजूर की गई थी लेकिन कुछ आरोपों के कारण यह कार्य रोक दिया गया। विभाग छोटी मोटी याचिकाएं स्वीकार कर रहा हैं जो ठीक नहीं है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मानी जानी चाहिए क्योंकि इससे समय एवं करोड़ों रुपयों की बचत हो सकती है।

हमें आंध्र प्रदेश में शतप्रतिशत राजसहायता देने में समय हैं क्योंकि हमने विभाग को दुरुस्त कर लिया है। हम पारेषण एवं वितरण हानि को 38 प्रतिशत जो कि पूरे देश का औसत है से कम करके 18 प्रतिशत तक लाए हैं। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री के महती प्रयासों से संभव हुआ है जिन्होंने उनसे इस पहलू पर कार्य कराया है। अत:, मैं भारत सरकार से इस दिशा में सभी प्रकार के प्रयत्न करने का अनुरोध करता हूं। नन्दन रिपोर्ट में भी वाणिज्यिक एवं तकनीकी पहलुओं संबंधी हानियों को कम करने की बात कही गई है। हमें उस रिपोर्ट से लाभ होगा। निश्चय ही हानि का स्तर नीचे आएगा जिससे ऊर्जा की बचत हो सकती है एवं इससे किसानों को लाभ होगा।

मैं जल विद्युत के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। दार्जिलिंग में जल विद्युत डेढ़ शताब्दी पहले आ गई थी। यह भारत में नहीं एशिया में अपनी तरह का पहला कार्य है। यह एशिया की पहली इकाई है। लेकिन हम उतना उपयोग करने में सक्षम नहीं है जितना होना चाहिए। हमारे पास इसके लिए संभाव्यता हैं ईश्वर इतना दयालु है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत की संभाव्यता बहुत अधिक है। दस वर्ष पहले जब मैं सदस्य था मैंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा हो तो उन्होंने बताया कि कोई पारेषण लाइन नहीं है। आप पारेषण लाइन्स बन सकते हैं लेकिन उस कारण से आपको उत्पादन नहीं रोकना चाहिए। दोनों कार्य एक साथ किए जा सकते हैं।

मैं भारत और चीन के बीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा चाहता हूं। हमारे प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। मेरा अनुरोध है कि प्रधानमंत्री को तीन माह में एक बार मंत्रियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए एवं विद्युत की स्थिति की समीक्षा होनी चाहिए। जब तक विद्युत की स्थिति में सुधार नहीं होता है तब तक आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल एवं खाद्य तेलों के उत्पादन में सुधार नहीं आ सकता। अब आवश्यक वस्तु केवल विद्युत है। विद्युत नहीं हो तो हम किसी भी विदेशी से निवेश करने की आशा नहीं कर सकते। हमारा देश केवल ऊर्जा के माध्यम से ही विकास कर सकता है।

[हिन्दी]

***श्री वीरेन्द्र कुमार** (टीकमगढ़) : आज पूरे देश की विद्युत निर्माण की स्थिति काफी गंभीर संकट के दौरे से गुजर रही है यह राष्ट्रव्यापी समस्या बन गयी है तथा बिजली का निर्माण केवल राज्यों पर नहीं छोड़ा जा सकता तथा केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का कार्य अभी भी लक्ष्य से पीछे चल रहा है। मध्य प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में ऐसे गांवों की बहुत बड़ी संख्या है जहां आज भी बिजली नहीं पहुंच सकी है स्वतंत्रता के 62 वर्षों के उपरांत भी गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाना हामरे सामने बहुत बड़ी चुनौती है आज बिजली विकास का प्रतीक बन गई है अत: बिजली निर्माण में आ रही कठिनाइयों को दूर करने में केन्द्र राज्य सरकारों के साथ सहयोग करें।

मध्यप्रदेश में गत वर्ष बारिश कम होने से बिजली निर्माण काफी कम हो रहा है तथा कोयला आधारित विद्युतघरों को चलाने के लिए जितने कोयले की आवश्यकता है केंद्र सरकार इस संबंध में शीघ्र मध्य प्रदेश को आवश्यक कोयला उपलब्ध कराये तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा केन्द्र के समक्ष विद्युत उत्पादन की योजनाओं के लिए शीघ्र राशि आवंटित करें ताकि शीघ्र ही मध्य प्रदेश में वहां की जनता को पर्याप्त बिजली दिलाई जा सके तथा केन्द्र एवं राज्य मिलकर बड़ी विद्युत इकाइयां स्थापित करने की दिशा में शीघ्र कदम उठायें तथा निजी क्षेत्र में भी आवश्यक साधन उपलब्ध कराये जिससे निवेशक इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सके। देश के पहाड़ी क्षेत्रों से बहने वाली नदियों पर अधिक विद्युत उत्पादन इकाइयों को लगाने पर जोर देना चाहिए तथा बिजली की चोरी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए एवं फैक्टरी से लेकर आम आदमी तक सभी से एक सा व्यवहार करना चाहिए।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : महोदय, पंजाब के साथ जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत का हिस्सा इंडस जल संधि की शर्तों और सतलज, व्यास और रावी नदियों के जल में हिस्से के संबंध में उत्तरवर्ती करारों के अनुसार राजस्थान ने पंजाब की निम्नलिखित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में विद्युत हिस्सेदारी के संबंध में दावे दायर किये थे:–

परियोजना का नाम	अधिष्ठापित	राज्य द्वारा हिस्से की मांग	
	क्षमता	प्रतिशत	मेगावाट
आनन्दपुर साहिब जल विद्युत परियोजना	134	20.0	26.8
मुकेरियन जल विद्युत परियोजना	207	58.5	121.1
यू.बी.डी.सी. चरण-द्वितीय	45	52.6	23.67
थीन बांध परियोजना	600	52.6	315.6
शाहपुर कांडी जल विद्युत परियोजना	168	52.6	88.37
योग	1154		575.54

नांगल हाइडल चैनल से रोपड़ थर्मल स्टेशन के लिए जल लेने की अनुमति देने के समय दिनांक 10.5.1984 को ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार तथा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसमें निम्न निर्णय लिये गये:–

- भारत सरकार रावी और व्यास नदियों पर पंजाब द्वारा स्थापित थीन बांध, आनन्दपुर साहिब, मुकेरियां, यू.बी.डी.सी. चरण-द्वितीय और शाहपुर कांडी जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादित विद्युत के लिए राजस्थान और हरियाणा का दावा सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय हेतु भेजेगी तथा
- भारत सरकार राजस्थान और हरियाणा को केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों के अनावंटित हिस्से में से आवंटित किये गये हिस्सों से अतिरिक्त विद्युत आवंटन करने के दावों को भी ध्यान में रखेगी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उपरोक्त दोनों ही निर्णयों की अनुपालना नहीं की गई।

समय अवधि के दौरान, राज्य सरकार अपने हिस्से की विद्युत प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष हर स्तर पर जैसे कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक, मुख्य मंत्रियों की सम्मेल आदि में लगातार प्रयत्न कर रही है। लेकिन, सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय जानने हेतु दावा अभी तक नहीं भेजा गया है और ना ही राजस्थान को केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों के अनावंटित कोटे में से समझौते के अनुसार अतिरिक्त विद्युत आवंटित की गई है।

पंजाब ने आनन्दपुर साहिब, मुकेरियां, यू.बी.डी.सी. चरण-द्वितीय तथा थीन बांध जल विद्युत परियोजनाएं चालू कर उसकी विद्युत का उपयोग करना भी शुरू कर दिया।

इस मुद्दे पर चंडीगढ़ में उत्तर क्षेत्र के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों की दिनांक 16.9.1998 की बैठके में यह फैसला किया गया कि:–

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग उक्त विचार का पृष्ठभूमि विवरण बनायें और इसे सम्बन्धित राज्यों को टिप्पणी के लिए भेजेंगे,
- जिस पर उत्तर क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों की बैठक में विचार किया जायेगा, और
- तत्समय के लिए भारत सरकार केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से विद्युत के आवंटन के अलावा विशेष आवंटन स्वीकृत करेगी।

पंजाब की जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत में राज्यों का हिस्सा तय करने के लिए पृष्ठभूमि विवरण बनाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में फरवरी, 1999 में एक समिति का गठन किया गया था। राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सभी सम्बन्धित राज्यों के हित में यही होगा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा भारत सरकार के मध्य दिनांक 10.05.1984 को किये गये समझौते की अनुपालना की जावे। अभी तक इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

राजस्थान सरकार ने समय-समय पर समझौते की अनुपालना हेतु अनुरोध किया, लेकिन इस सम्बन्ध में भारत सरकार के स्तर पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय

ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 1984 के समझौते के तहत सभी साझेदार राज्यों को समझौते के सभी शर्तों का पालन करना चाहिए और इस हेतु केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिए।

ए.पी.डी.आर.पी. (एक्सीलरेटेड पावर डवलपमेंट रिफोर्म प्रोग्राम) के तहत वर्ष 2009-10 के बजट में 160 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, लेकिन पावर डिमाण्ड एवं सप्लाई के अन्तर को दूर करने के लिए कोई ठोस प्रोग्राम हाथ में लेने की घोषणा बजट में नहीं ली गई है। बिजली के उत्पादन की बढ़ोत्तरी में सौर ऊर्जा का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। वर्तमान में सौर ऊर्जा के उपकरण, जिसमें विशेष रूप से पैनल बोर्ड सम्मलित है, अत्यधिक महंगें होने के कारण जनता इनका उपयोग नहीं करती है। जबकि पूरे राजस्थान में सौर ऊर्जा की बाहुल्यता है। इसे उत्पादित करने के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करने की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा आधारित टेक्नोलोजी जहां भी उपलब्ध हो और प्राप्त की जानी चाहिए एवं वर्तमान बिजली की दरों के बराबर सौर ऊर्जा प्राप्त होने लग जाए तो जनता सौर ऊर्जा को स्वीकार कर सकती है। सौर ऊर्जा के उपकरणों के बारे में जनता को जानकारी भो कम है। अत: मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे सार्वजनिक स्थान जहां जनता का रोज आना-जाना रहता है उदाहरणार्ति कलेक्ट्रेट परिसर, कोर्ट परिसर आदि ऐसे स्थानों पर सौर ऊर्जा के उपकरण स्थापित किये जावें तथा उनका इन्हीं स्थानों पर नि:शुल्क प्रदर्शन किया जाए, जिससे जनता में जागरूकता आए तो सौर ऊर्जा की तरफ आकर्षित हो सके।

राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर एवं सीकर जिलों में पवन ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं, लेकिन और क्षेत्रों का भी इसमें सर्वे किया जाना चाहिए, मेरे जानकारी के अनुसार बीकानेर क्षेत्र भी इसके लिए उपयुक्त है। अत: भारत सरकार पवन ऊर्जा की वाईबलेटी हेतु सर्वेक्षण करावें एवं जो इकाईयां बीकानेर क्षेत्र में स्थापित हो सकती हैं, उनके लिए विशेष प्रोत्साहन देने की घोषणा करें, जिससे पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बिजली का उत्पादन बढ़ सके और जो बजट में मांग एवं पूर्ति के अंतर को कम करने का उद्देश्य तय किया गया है, उनकी भी पूर्ति संभव हो सके।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के तहत वर्ष 2009-10 के बजट में यद्यपि बढ़ोत्तरी की गयी है लेकिन मांग को देखते हुए यह बढ़ोत्तरी नाकाफी है। राजस्थान राज्य से राजीव गांधी विद्युत योजना के तहत भारत सरकार को स्वीकृति हेतु सप्लीमेंट्री स्कीम के माध्यम से प्रोजेक्ट प्रेषित किये गये थे, लेकिन उनकी स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है यथाशीघ्र उनकी स्वीकृति जारी की जानी चाहिए। जिससे राज्य के ए.पी.एल. तथा बी.पी.एल. लोगों को कनेक्शन जारी किये जा सके।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना में मोनिटरिंग ठीक नहीं होने के कारण योजना का क्रियान्वयन देरी से होता है। अत: इस सम्बन्ध में मोनिटरिंग सिस्टम को और पुख्ता किया जावें।

नवेली लिग्नाईट प्रोजेक्ट के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र बीकानेर में बरसिंगसर प्रोजेक्ट का कार्य लगभग पूर्ण है, लेकिन अभी भी उसके चालू होने का कोई प्रोग्राम तय नहीं किया गया है। प्रोजेक्ट के तहत 250 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन का भी प्लांट लगाने का प्रोग्राम था, लेकिन उसके बारे में भी कोई ठोस क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। अत: बरसिंगसर के लिए यथाशीघ्र प्रोग्राम तय किये जावे तथा रीडी, बीठनोक, हाड़ला एवं पलाना में प्लांट लगाने अथवा सर्वेक्षण कार्यक्रम पूर्ण करने का भी निर्धारित प्रोग्राम यथाशीघ्र तय किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

***श्री एन. कृष्टप्प** (हिन्दुपुर) : सभापति महोदय, धन्यवाद, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कृषि प्रयोजनों के लिए 26,90,000 विद्युत कनेक्शन हैं तथा लगभग 1,00,000 अनधिकृत पंप कनेक्शन हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने न्यूनतम 7 घंटे की विद्युत आपूर्ति का वादा किया था, लेकिन विगत 10 दिनों से वह पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है। अगर हम कई उप-स्टेशन अथवा ट्रांसफार्मर स्थापित भी कर देते हैं, तो भी हम पर्याप्त विद्युत उत्पादन नहीं कर सकने के कारण किसानों की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं होंगे। महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में अपर्याप्त वर्षा किसानों के लिए काफी प्रतिकूल है। अभी तक बुआई नहीं की गई हैं अधिकांश किसान पम्प सेटों पर निर्भर हैं। किसानों की स्थिति में तभी सुधार होगा जब पर्याप्त विद्युत उत्पादन तथा विद्युत की नियमित आपूर्ति होगी।

अगर हम अभी उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो हम अपने किसान समुदाय को कठिन एवं अनिश्चित भविष्य की ओर ले जाएंगे। 1993 में आंध्र प्रदेश में 5635 मेगावाट विद्युत का उतपादन होता था जो कि चन्द्रबाबू नायडू के टी.डी.पी. के शासनकाल के दौरान 2003 में बढ़कर 10,635 मेगावाट हो गया। विगत चार वर्षों में मात्र 800 मेगावाट की वृद्धि हुई है। अगर विद्युत का उत्पादन हमारी विद्युत

*मूलत: तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एन. कृष्टप्प]

आवश्यकताओं को पूरा करता, तो हमारे किसानों की स्थिति काफी अच्छी होती। उन्होनें 7 घंटे के स्थान पर 8 घंटे विद्युत आपूर्ति करने का वादा किया, लेकिन अपर्याप्त विद्युत उत्पादन के कारण वे अपने वादों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। जल विद्युत उत्पादन कम होता जा रहा है। अपर्याप्त वर्षा तथा बांधों में घटे हुए जल स्तर के कारण अब 2500 मेगावाट की उत्पादन क्षमता से मात्र 800 मेगावाट का ही उत्पादन हो रहा है।

इसके परिणामस्वरूप किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामलों में वृद्धि हो रही है। आत्महत्याओं को रोकने तथा कृषि पम्प सेटों के लिए उचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस सरकार को कदम उठाना चाहिए। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के लिए मात्र 2080 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की कालोनियों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा सका है। चीन हमसे कम विद्युत का उत्पादन करता था, लेकिन अब वह हमसे 4 से 5 गुणा विद्युत का उत्पादन करता है। हम कब उन स्तरों पर पहुंचेंगे? हम कब अपनी विद्युत आवश्यकताओं तथा मांगों को पूरा कर सकेंगे? मैं इस सरकार से एक वक्तव्य की मांग करता हूं जिसमें यह बताया जाए कि वे कब कृषि क्षेत्र, घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्र को पर्याप्त विद्युत प्रदान करेंगे? इन्हीं मांगों के साथ मैं यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री एन. चेलुवरया स्वामी (मांडया) : सभापति महोदय, मैं यहां पर विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

विद्युत, किसी भी देश के आर्थिक विकास का आवश्यक घटक है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार विद्युत क्षेत्र में एक करोड़ रुपए का निवेश करने से अर्थव्यवस्था में 20 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है। उपर्युक्त के आलोक में हमें विद्युत की भूमिका और इसके महत्व को समझना चाहिए और सरकार को विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए।

विद्युत न केवल आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपितु यह गरीबी उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे हमें, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन: शैक्षिक विकास में वृद्धि अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने, पर्याप्त पेय जलापूर्ति और सुशासन आदि में कुछ मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के थ्री फेस कनेक्शन साथ 12 घंटे विद्युत की आपूर्ति करती है और शेष अवधि के लिए एकल फेस से विद्युत की आपूर्ति करती है तो हमारा कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा; हमारे किसान एक खुशहाल जिंदगी जी सकते और हमारा देश विकास करेगा। मेरी यह राय है कि यदि हमारे देश का समग्र विकास करना है तो सरकार को हमारे देश के सभी लोगों को विद्युत प्रदान करनी चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो हमें राजसहायता देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसके साथ ही हमें सब्सिडाइज्ड दरों पर खाद्यान्न देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हमारे किसान आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि हमारा देश आत्मनिर्भर है। यदि सरकार सभी संसाधनों का उपयोग करके विद्युत उत्पादन के लिए दीर्घावधि रणनीति नहीं बनाती तो हम कृषि उद्योगों और अन्य क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित नहीं कर सकते। यदि हमारे किसान आत्मनिर्भर नहीं होते तो सरकार कब तक सब्सिडाइज्ड दरों पर लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगी? इसे लम्बे समय तक जारी रखना मुश्किल है। इसलिए सरकार को विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अतिसक्रिय ऊर्जा रणनीति बनानी चाहिए ताकि हम देश के प्रत्येक घर में विद्युत प्रदान कर सके। मैं सरकार से प्रत्येक घर में कम से कम न्यूनतम बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ शाम के सयम बिजली प्रदान करने के लिए प्रत्येक गांव में सिंगल फेस ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि कर्नाटक में बंगलौर, मैसूर, हुबली, धारवाड़ आदि जैसे शहरों में जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है। अत: विद्युत आपूर्ति की मांग में भी वृद्धि हुई है। अकेले बंगलौर शहर में 3500 सॉफ्टवेयर कंपनियां है। उद्योगों के साथ-साथ सॉफ्टवेयर कंपनियों के विकास के लिए, विद्युत प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि पर्याप्त विद्युत उपलब्ध न होने के कारण अनेक सॉफ्टवेयर कंपनियां बंगलौर से जा चुकी है। पिछले कई वर्षों में अनेक युवाओं तथा पढ़े-लिखे युवाओं विशेषकर इंजीनियरों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है।

महोदय, इस संबंध में दीर्घवधि योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ-साथ मैं गर्व के साथ यह भी कह सकता हूं कि मैसूर राज्य ने शिवसमुद्रम नामक स्थान पर पहली कड़ी जलविद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित करके एक अलग मुकाम हासिल किया था। उस समय वह प्रौद्योगिकी विकसित देशों में शैशवकाल में थी। 1902 में विश्व में सबसे ज्यादा वोल्टेज के साथ सबसे बड़ी पारेषण लाइन का निर्माण,

विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया था। इसलिए, मैं सरकार से मेरे राज्य कर्नाटक के साथ-साथ देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने की संभावना तलाशने के लिए आगे आना चाहिए। इसके लिए कर्नाटक में एक आदर्श स्थान है जिसका नाम मेकदतू है। कावेरी-बेसिन मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा केन्द्र और राज्य सरकारों को पवन, सौर, बायोमास, चीनी उद्योग में सह उत्पादन आदि जैसे अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन करने के लिए विभिन्न कदम उठाने हेतु साथ मिलकर काम करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एम. राजामोहन रेड्डी (नेल्लोर) : सभापति महोदय, मुझे विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

विद्युत किसी भी देश के विकास के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और अति आवश्यक अवसंरचना है। इसीलिए, स्वतंत्रता के पश्चात् से हमारे नियोजक सभी अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत क्षेत्र को प्राथमिकता देते आए हैं। स्वतंत्रता के समय, विद्युत का उत्पादन मात्र 1362 मे.वा. था। किंतु अब हम, 1,45,000 या 1,50,000 मे.वा. उत्पादन तक पहुंच सके हैं। वर्ष 2011-12 तक हमारी आवश्यकता 2,33,000 मे.वा. होगी ओर वर्ष 2021-22 तक यह 4,88,000 मे.वा. तक पहुंच जाएगी। हमारे पूर्वानुमान के अनुसार पुन: वर्ष 2030 तक यह 9,50,000 मे.वा. होगी।

किसी भी सरकार के लिए यह लक्ष्य हासिल करना एक अत्यन्त दुरुह कार्य के समान है। जब तक हम इसकी समुचित ढंग से योजना नहीं बनाएंगे, हम यह लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त जब तक हम जल विद्युत, ताप विद्युत, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे सभी क्षेत्रों में विद्युत का उत्पादन शुरू नहीं करते, हम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते।

भारत सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना... *(व्यवधान)*। भारत सरकार ने दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 25,275 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 551 परियोजनाओं को शामिल करते हुए देश के सभी ग्रामों का विद्युतीकरण करने के इस अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी स्तर पर लगभग 1,25,000 ग्रामों का विद्युतीकरण करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया जिसमें से अभी तक 61,818 ग्रामों में विद्युत उपलब्ध कराई कई है। इसके साथ ही देश भर में गरीबी रेखा से नीचे के 2.43 करोड़ परिवारों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने का भी कार्यक्रम तय किया गया था जिसमें से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 60.58 लाख परिवारों को ही सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

यदि मैं कहूं, आंध्र प्रदेश में भी 21,623 ग्रामों का विद्युतीकरण करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसमें से अभी तक 16,632 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, गरीबी, रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 21,14,317 परिवारों के लिए सेवाओं के लक्ष्य की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 18,67,309 परिवारों के लिए सेवाएं जारी की गई हैं। जैसा कि आप भली-भांति जानते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार 30 लाख पंपसेटों के लिए सात घंटे तक विद्युत की मुफ्त आपूर्ति कर रही है? अब आंध्र प्रदेश सरकार इसे सात घंटे से बढ़ाकर नौ घंटे करने जा रही है। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है, वर्ष 2030 तक विद्युत की मांग 9,50,000 मे.वा. हो जाएगी। वर्ष 2050 तक 9,50,000 मे.वा. में से 1,50,000 मे.वा. मांग की कमी रह जाएगी।

जल विद्युत, ताप विद्युत और सभी अन्य स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने की समस्त संभावनाओं की खोज करने के पश्चात् भी यह कमी बरकरार रहेगी। वर्ष 2050 तक हमें 4,12,000 मेगावाट की कमी का सामना करना होगा। अत:, हम इस अंतराल को कैसे पाट सकते हैं? यह केवल परमाणु ऊर्जा को विकसित करके किया जा सकता है। इसीलिए, मैं यूपीए सरकार, यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और डा. मनमोहन सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी अड़चनों के बावजूद भी अमरीका के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्भीक निर्णय लिया। इस समझौते के माध्यम से परमाणु ऊर्जा विकसित करके हम अपने घाटे को कम कर सकते हैं। वर्ष 2030 में 1,50,000 मे.वा. के घाटे को हम मात्र 50,000 मे.वा. तक ला सकते हैं और वर्ष 2050 में हम 4,12,000 मे.वा. के घाटे को कम करके मात्र 7,000 तक ला सकते हैं। अर्थात् हम 4,05,000 मे.वा. की कमी की भरपाई कर सकते हैं।

इस प्रकार, यह वास्तव में एक ऐतिहासिक समझौता है और संपूर्ण देश यह साहसी निर्णय लेने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी और डा. मनमोहन सिंह का धन्यवाद करेगा। भावी पीढ़ियां यूपीए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के लिए आभारी रहेंगी।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं बिहार से आता हूं। पूरे देश में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना काफी लोकप्रिय योजना के रूप में मानी जा रही है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस योजना की प्रशंसा की है और इसमें जो कमियां हैं, उन्हें भी इस सदन के सामने रखने की कोशिश की है। मेरा पहला निवेदन है कि इस योजना के अंतर्गत थ्री फेज बिजली का प्रावधान नहीं है। आपको इसमें सिर्फ तार बढ़ानी है और अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाना है। मेरे बगल में माननीय सांसद बैठे हैं जिन्होंने इस चर्चा को प्रारंभ किया था। मुझे इनके क्षेत्र में जाने का अवसर मिला। इन्होंने अपनी सांसद निधि से 100 केवीए का ट्रांसफार्मर खरीदा। उसकी कीमत और आपके ग्रिड द्वारा जो 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, दोनों की कीमत बराबर है। इसे नीचे तक देखने की जरूरत है। मैं यह बात सिर्फ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कीमतों में इतने भारी अंतर के पीछे कौन सी व्यवस्था काम कर रही है।

गांवों के विद्युतीकरण के बैंच मार्क प्रावधान को भी काफी कम कर दिया गया है। विद्युतीकृत गांवों के लिए मात्र 4 लाख रुपये और अविद्युतीकृत गांवों के लिए मात्र 13 लाख रुपये का प्रावधान है। हम बिहार से आते हैं और बिहार का जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। एक गांव में टोलों की संख्या भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा पहले मात्र प्रतिशत परिवारों को बिजली देनी थी, अब 100 प्रतिशत बीपीएल परिवारों को देनी है, जिससे ज्यादा लागत आ रही है। यह लोकहित में होगा कि बैंच मार्क के प्रावधान को बढ़ाया जाए और आवश्यकतानुसार हाई पावर कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर लगाया जाए। मेरी मांग होगी कि विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जो नॉर्म्स हैं, उन्हें उदार बनाया जाए और बिहार की विशेष आवश्यकता को देखते हुए उसे बढ़ाया जाए। राज्य सरकार की ओर से अलग से डीपीआर यहां भेज दी गई है। मैं पुन: आग्रह करूंगा कि आप उसे अनुमोदित करें। हम आभार व्यक्त करते हैं, हम बधाई देते हैं कि आपने बजट 40 हजार करोड़ रुपये से 53 हजार करोड़ रुपये बढ़ाया है। इसीलिए मैं पुन: विनती करूंगा कि हमारे राज्य से जो डीपीआर आया है, उसे निश्चित रूप से अनुमोदित किया जाए। आपकी जो योजना चल रही है, यहां हमने उसका जिक्र किया है।

अपराह्न 5.00 बजे

लेकिन आपने दसवीं पंचवर्षीय योजना में जो सैक्शन किया, पूरे देश के राज्यों का वर्णन करने में काफी समय लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ अपने जिले के बारे में बताना चाहूंगा। आज सुबह मैंने जिला प्रशासन से एक रिपोर्ट मंगवायी थी, जिसके तहत दसवीं पंचवर्षीय योजना, जो दो वर्ष पहले पूरी होनी थी, उसमें एचटी और एलटी लाइन 4480 किलोमीटर सैंक्शन्ड है, जबकि एडीशनल रिक्वायरमैंट 2500 किलोमीटर है। 25 केवीए और 16 केवीए के कुल 1129 ट्रांसफार्मर्स सैंक्शन्ड हैं, जबकि एडीशनल रिक्वायरमैंट 25 केवीए के 1800 हैं। ये आंकड़े दसवीं पंचवर्षीय योजना के हैं। आप समझ सकते हैं कि आवश्यकता से काफी कम ही सैंक्शन हुआ है, जबकि दो साल पहले ही दसवीं पंचवर्षीय योजना का समय पूरा हो गया है। वह काम अभी अधूरा है। मैं सिर्फ अपने जिले की बात कर रहा हूं।

मैं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में भी बात करना चाहता हूं। मेरे यहां कुल 1345 गांव हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना में मैंने 744 गावों को जिक्र किया है। दो वर्ष पहले उस योजना का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उसका आधा ही सामान गया है। शेष 535 गांवों के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एचटी और एलटी लाइन 926 किलोमीटर है और एडीशनल रिक्वायरमैंट 1020 किलोमीटर सैंक्शन्ड हैं इसी प्रकार से...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : राधा मोहन जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राधा मोहन सिंह : सभापति महोदय, मैंने अभी अपने क्षेत्र की ही बात कही है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सब लोग अपने-अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आप अपनी बात समाप्त करिये, क्योंकि समय की कमी है।

...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : मैंने अभी अपनी बात शुरू ही की है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं सब लोगों को इतना ही टाइम दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : मेरा निवेदन है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना की जो एडीशनल रिक्वायरमैंट है, उसे भेजा जाये और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का भी एडीशनल रिक्वायरमैंट यहां मंत्रालय में पड़ा हुआ है, उसे भेजा जाये। बिजली उत्पादन के विषय को भी मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष बिजली की उपलब्धता मात्र 75-80 यूनिट है जबकि देश का औसत 600-650 है। राष्ट्रीय

विद्युत नीति के अनुसार 2012 तक राष्ट्रीय औसत 1100 यूनिट प्रति व्यक्ति किया जाना है।...*(व्यवधान)*

महोदय, बिहार की यह स्थिति है। आप कह रहे हैं कि राज्य इसे करे, लेकिन हमारे यहां से पहले से जो आया हुआ है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : राधा मोहन जी, समय नहीं है इसलिए आप अपनी स्पीच ले कर दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : केन्द्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार प्रयत्न करे। हमारी सरकार ने 20 हजार से अधिक मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए कोयले की व्यवस्था के बारे में लिखा है, लेकिन अभी तक कोल लिंकेज नहीं दिये जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में स्थापित बरौनी थर्मल और मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार के लिए 27.06.06 में एक पत्र आया था। हमने उसके लिए पांच-पांच लाख रुपये की रकम प्रौसेसिंग शुल्क के रूप में कोयला मंत्रालय में जमा भी कर दी है, लेकिन यह मामला अभी तक ऊर्जा मंत्रालय में लंबित है। इसके अलावा अन्य जो परियोजनाएं हैं, उसके लिए भी हमने प्रौसेसिंग शुल्क जमा किया है। ऐसी दर्जनों योजनाएं हैं, जिनके लिए शुल्क जमा है, कोल लिंकेज के आवंटन का इंतजार हो रहा है। इस दिशा में मिशन मोड में चलने की जरूरत है जबकि उलटा हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से ध्यान में लाना चाहता हूं कि 13 जुलाई, 2009 को राज्य सभा में माननीय ऊर्जा मंत्री ने जवाब दिया था कि 6 जुलाई, 2009 तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश के 78 प्रतिशत कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में सिर्फ 7 दिनों का कोयला है जबकि 10 संयंत्रों की स्थिति बहुत खराब है, जहां सिर्फ चार दिनों का ही कोयला उपलब्ध है। आज पूरे देश में कोयले का स्टॉक 11 हजार मिलियन टन है जबकि सामान्य आवश्यकता 22 मिलियन टन की है।

महोदय, दुख के साथ कहना पड़ता है कि नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी की आठ इकाइयों में से एक इकाई जो एक सौ मेगावाट की है वह कोयले की कमी से बंद पड़ी है। नाल्को को प्रतिदिन 15000 टन कोयले की जरूरत है जबकि उसे सिर्फ 10,000 से 12000 टन मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश के एनटीपीसी ताप विद्युत गृह को भी उसकी क्षमता से कम सप्लाई हो रहा है। बिहार में यही स्थिति हमारे बरौनी और कांटी थर्मल पावर प्लांट्स की है। वहां इसकी आपूर्ति नहीं हो रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में जो असफलता है, निश्चित रूप से उन तथ्यों को दो मिनट में आपके सामने रखकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। स्थापित क्षमता के मामले में भारत की उपलब्धि केवल डेढ़ लाख मेगावाट है, जबकि...*(व्यवधान)* चीन ने आठ लाख मेगावाट स्थापित क्षमता प्राप्त कर ली है। जिस प्रकार से ऊर्जा उत्पादन में कमी और पीक-ऑवर में ऊर्जा उपलब्धता में कमी के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, वह देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है। 31 जनवरी, 2004 तक ऊर्जा उपलब्धता में सात प्रतिशत की कमी थी, अब यह अन्तर बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो गया है। पीक-ऑवर की उपलब्धता में जो कमी है, पीक-ऑवर में वर्ष 2003-04 में, 31 जनवरी, 2004 तक 10.7 प्रतिशत थी, अब यह 30 जुन, 2009 तक यह कमी बढ़कर 13.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है। दसवीं योजना के 41,000 मेगावाट उत्पादन लक्ष्य के विरुद्ध केवल 18,420 मेगावाट ही प्राप्त किया जा सका है। इस तरह लक्ष्य का सिर्फ 44 प्रतिशत प्राप्त किया जा सका है।

सभापति महोदय : ऑनरेबल मेम्बर, अब यह रिकॉर्ड नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप 15 मिनट समय ले चुके हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, मेरे पास 23 माननीय सदस्यों की सूची है, जिन्हें अनुदानों की मांगों पर अभी बोलना है। इसलिए, मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने भाषणों को मात्र पांच मिनट तक सीमित रखें।

#डा. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब) : सभापति महोदय, 'विद्युत' के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

#मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[डा. रतन सिंह अजनाला]

मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि विद्युत मंत्री बहुत ही अनुभवी, परिश्रमी हैं और वह हर प्रकार की पीड़ा/शिकायत को समझते हैं। परंतु पीड़ा इतनी अधिक है कि उनके लिए उसका समाधान करना बहुत कठिन होगा।

संपूर्ण भारत में बिजली की कमी है, इस कमी को किस प्रकार दूर किया जाए, इस बारे में विद्युत मंत्री मेहनत से कार्य कर रहे हैं। परंतु समस्या यह है कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया कि "मेरी सरकार प्रति वर्ष 13000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी"; परंतु सरकार का कहना है कि 13000 मेगावाट कम है और वह हर वर्ष 18000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे।

मुझे बहुत खुशी है कि विद्युत मंत्री का दृष्टिकोण बहुत अच्छा तथा उच्च है। वह उच्च आंकड़ों तथा आकांक्षाओं में विश्वास रखते हैं, परंतु ये पूरी नहीं हो रही है। वर्ष 2008-2009 में 3500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया; अंतर देखिए, एक ओर 18000 मेगावाट की बात हो रही है और वास्तव में 3500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। विद्युत मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि उनके पास केवल वही आंकड़े होने चाहिएं, जो प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें और मेहनत करनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं बिजली संकट विशेषकर 10800 गांवों को बिजली देने की विद्युत मंत्री की वचनबद्धता के बारे में बात करना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कितने गांवों को दायरे में लिया गया है, क्योंकि ऐसे बहुत से गांव हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची है। ये आंकड़े गलत हैं।

कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री ने वक्तव्य दिया था कि "यदि लोग रात 8 बजे से 12 बजे तक टी.वी. देखें तो जनसंख्या नियंत्रित की जा सकती है। जब बिजली होगी, तभी टी.वी. देखा जा सकता है, जब बिजली ही नहीं होगी तो वे टी.वी. किस प्रकार देखेंगे और जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रित किया जाएगा। मेरा अनुरोध है कि केवल सुझावों से ही नियंत्रण नहीं किया जा सकता, इसके लिए वास्तव में कुछ करना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री महोदय के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए रात 8 बजे से 12 बजे तक बिजली प्रदान की जानी चाहिए। हम रात 8 बजे से 12 बजे तक की बिजली नहीं दे रहे हैं।

यह पर्याप्त नहीं है, दीपक पारिख समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान मांग को पूरा करने तथा शेष को कवर करने के लिए बिजली उत्पादन हेतु 750000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कितने वर्षों में वह धनराशि की व्यवस्था कर पाएंगे। जब हमारे पास अपेक्षित धनराशि होगी, तभी हम बिजली का उत्पादन कर पाएंगे। यह बहुत आवश्यक है कि आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जाए।

सभापति महोदय, बिजली की कमी के कारण हमें वार्षिक 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यदि हमारे पास अपेक्षित बिजली होगी तो हम 40,000 करोड़ रुपए के इस वार्षिक नुकसान से बच सकते हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बताना चाहता हूं कि पारेषण घाटे के कारण वैश्विक स्तर पर विद्युत हानि लगभग 23% है, जबकि भारत में यह 32% है। जब तक हम पारेषण घाटे को कम नहीं करेंगे, बिजली का घाटा बढ़ता रहेगा। बिजली में तीन मुख्य केन्द्र होते हैं, उत्पादन, वितरण एवं पारेषण। भारत से पारेषण घाटा अधिकतम है। वितरण के संबंध में, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बिजली चोरी की राशि अपार है और इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, यद्यपि यह राज्य का विषय है। पारेषण लाइनें भी पुरानी हैं और उन्हें आज तक बदला नहीं गया है, जिसके कारण पारेषण प्रभावित हो रहा है।

सभापति महोदय, 2003 के केन्द्रीय विद्युत अधिनियम में सिफारिश की गई है कि राज्यों के बिजली बोर्डों को भंग कर दिया जाए; उत्पादन तथा पारेषण को दो भागों में बांटा जाना चाहिए। विद्युत मंत्री अच्छी तरह जानते हैं कि राज्यों के बिजली बोर्ड करोड़ों के घाटे में चल रहे हैं। कोई भी राज्य इन बोर्डों को भंग करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि प्रश्न यह है कि इस नुकसान की क्षतिपूर्ति कौन करेगा। यदि केन्द्र 2003 के इस अधिनियम को सभी राज्यों में क्रियान्वित करना चाहता है तो राज्यों को अधिकतम सहायता दी जानी चाहिए जिससे कि वे अपने-अपने बिजली बोर्डों की सहायता कर सकें।

सभापति महोदय, मैं अपने राज्य पंजाब के बारे में बोलना चाहता हूं। हमें लगभग 8170 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, परन्तु कम उत्पादन के कारण हम 300 मेगावाट की कमी का सामना कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पंजाब और हरियाणा के लिए 100 मेगावाट बिजली की स्वीकृति देने के लिए मैं विद्युत मंत्री का आभारी हूं जिनमें 50:50 बिजली दोनों राज्यों को दी जाएगी।

चूंकि बिजली की भारी कमी है, इसलिए धान की खेती नहीं की जा सकती क्योंकि ट्यूब वैल बिना बिजली के नहीं चलते। इसलिए

100 मेगावाट की इस सहायता को और बढ़ाया जाना चाहिए। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के नुकसान को समाप्त कर इसकी सहायता की जाए।

मैं बताना चाहता हूं कि बिजली की कमी को पूरा करने तथा किसानों की सहायता के लिए पंजाब सरकार ने तीन दिन तक उद्योग की बिजली की आपूर्ति बंद कर दी, स्कूलों/कार्यालय के समय भी घटा दिया। किसानों को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि देशवासियों को प्रतिदिन भोजन मिल सके। मेरा अनुरोध है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम सभी को मिलकर पूरी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम बिजली की कमी से संबंधित इस मामले का समाधान नहीं करते, तब तक भारत का विकास विकसित नहीं होगा।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट में विद्युत मंत्रालय के लिए 9,202 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय निर्धारित किया है। इस क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय में इस मंत्रालय के तहत कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधनों के 43,896 करोड़ रुपये सहित अनुमानत: 53,126 करोड़ रुपये है। यह देखने से अत्यंत प्रभावशाली लगता है परंतु यह क्षेत्र कमियों से लगातार जूझ रहा है जो इस क्षेत्र में अवरोधों में और बढ़ोत्तरी कर रहा है।

योजना पर आते हुए, एपीडीआरपी, यह विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। वित्त मंत्री महोदय का इस योजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर 2,080 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। यह वर्ष 2008-09 के बजट में किए गए आवंटन में 160% की अधिक वृद्धि है।

अब विद्युत क्षेत्र के निष्पादन पर आते हैं, हमने यह पाया कि पिछले कुछ वर्षों में यह अत्यंत असंतोषजनक रही है। विद्युत क्षमता जोड़ने में देरी के परिणामस्वरूप समय तथा लागत वृद्धि हुई हैं। अब विद्युत उत्पादन में हुए विकास पर आते हैं, यह भी बहुत धीमा रहा तथा इस अवधि के दौरान विद्युत की कमी बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर हम तीन वर्षों के आंकड़ो पर गौर करे तो ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि यहां भी स्थिति बहुत खराब है। पिछले वित्तीय वर्ष में विद्युत उत्पादन में विकास में काफी तेजी से गिरावट आई हैं। यह वृद्धि तीन वर्षों में न्यूनतम है। महोदय, 2008-09 के दौरान विद्युत उत्पादन में विकास 2.7 प्रतिशत रहा। यह लक्षित 9 प्रतिशत से काफी कम था। वर्ष 2007-08 में विकास 6.3 प्रतिशत रहा; तथा 2006-07 में विकास 7.3 प्रतिशत रहा। वर्ष 2008-09 में विद्युत की कमी बढ़ी क्योंकि मांग या आवश्यकता में 5.1 प्रतिशत विकास रहा जोकि 3.8 प्रतिशत की उपलब्धता से अधिक था विशेषरूप से पश्चिमी और उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कमी महसूस की गई। यहां तक कि देश में ताप विद्युत स्टेशनों में वर्ष 2008-09 के दौरान अनेक कारणों यथा कोयले तथा गैस की कमी के चलते पीएलएफ में कमी आई।

अब मैं क्षमतावर्धन पर आता हूं, क्षमतावर्धन में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में ही भारी कमी रही है। वर्ष 2008-09 के दौरान तीन वर्षों में क्षमतावर्धन न्यूनतम रहा था। वर्ष 2007-08 के 9323 मे.वा. तथा 2006-07 के 6.853 मे.वा. की तुलना में 2008-09 में केवल 3454 मे.वा. ही वृद्धि हुई।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 78720 मे.वा. का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। अब तक योजना अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान 12,717 मे.वा. क्षमता ही जोड़ी गई हैं। इसका अभिप्राय है कि अगले तीन वर्षों के दौरान 66,000 मे.वा. क्षमता जोड़ी जानी है अर्थात् 22,000 मे.वा. प्रति वर्ष, जो मेरे विचार से संभव नहीं है और सरकार का '2012 तक सभी को बिजली' का नारा एक स्वप्न बनकर रह जाएगा।

अब निजीकरण या विद्युत विभागों को विभक्त करने पर आते हैं; विद्युत क्षेत्र में सुधार आरंभ किए हुए दो दशक हो गए हैं तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादको को विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी गई थी परंतु मेरे विचार से हमें वांछित परिणाम हासिल नहीं हुए हैं न ही विद्युत क्षेत्र में विशेषरूप से आईपीपी द्वारा, क्षमतावर्धन में कोई विकास दिखाई देता है और समय तथा लागत वृद्धि से इस पर प्रभाव पड़ा है। इसलिए मेरे विचार से विद्युत क्षेत्र में, निजी क्षेत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। साथ ही, आईपीपी द्वारा खरीदी गई बिजली की लागत बहुत अधिक होती जा रही है जबकि केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र में यह बहुत सस्ती है।

जब हम ऊर्जा सुरक्षा की बात करते है तो मेरे विचार से, इस क्षेत्र तथा साथ ही संबंद्ध क्षेत्रों जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में निजी कम्पनियों के बढते कब्जे से सुरक्षित बनाया जाए। यह सही समय है, और मैं समझता हूं कि यह उचित समय है कि विद्युत क्षेत्र में तथा कथित सुधार के लागत तथा लाभों पर ध्यान दिया जाए, जिसने विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा व्यापार में निजी कम्पनियों को खुली कर दी है। निजी कम्पनियों को अनुशासित रहने की आवश्यकता

[श्री असादूद्दीन ओवेसी]

है ताकि उन्हें क्षमतावर्धन में कमी में किसी भी ढिलाई के लिए जवाबदेह बनाया जा सके।

महोदय, अंत में, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय तथा राज्य विद्युत उपयोगिताओं को उनकी क्षमताओं का बड़े पैमाने पर विस्तार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार को मेरा यही सुझाव है कि उसे 4000 अल्ट्रामेगावाट विद्युत परियोजनाओं को निजी कंपनियों को सौंपने के निर्णय पर पुर्नविचार करना चाहिए। केन्द्रीय क्षेत्र में इन परियोजनाओं को आरंभ करना उचित है चूंकि इसमें कोई भी समय तथा लागत वृद्धि नहीं होगी। वहनीय प्रशुल्क एक महत्वपूर्ण कारक है।

अंत में, मैं अपने राज्य पर आता हूं, एनटीपीसी ने 1000 मे.वा. की सिमाद्री विशाखापत्तनम इकाई के प्रथम चरण का निर्माण किया था। जब पिछली तेलगूदेशम पार्टी सरकार वहां सत्तारूढ़ थी तब तात्कालीन मुख्य मंत्री ने सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के लिए 1000 मे.वा. आवंटित की थी। दूसरे चरण में, 1000 मे.वा. की इकाई का निर्माण किया जा रहा है। एनटपीसी कह रहा है कि विद्युत का 40% आंध्र प्रदेश को दिया जाएगा। माननीय विद्युत मंत्री से मेरा अनुरोध है कि दूसरे चरण में 1000 मे.वा. आंध्र प्रदेश को केवल इस कारण दी जाएगी क्योंकि आंध्र प्रदेश से एक माननीय सदस्य ने अभी बताया कि हम किसानों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं।

मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। अंत में, मैं विद्युत संरक्षण अधिनियम, 2001 पर आता हूं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य विनियामक आयोग तथा विभिन्न राज्य सरकारें इस विद्युत संरक्षण अधिनियम, 2001 को पूर्ण रूप से और सुविधा के लिए भूल गए हैं। इसके अनुसार विद्युत लेखपरीक्षा की जानी चाहिए तथा रिपोर्ट आरईसी को भेजी जाएगी। इसके पश्चात् यह ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो को जाता है। इस विद्युत संरक्षण अधिनियम, 2001 में प्रस्तावित था कि ऐसा करने से इस प्रणाली में ऊर्जा प्रबलता कम हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप कम उत्पादन होता है जिससे अंततः कम कार्बन उत्सर्जन होता है। केन्द्रीय मंत्रालय को सभी राज्य विनियामक आयोगों के साथ तथा राज्य सरकारों के साथ बैठना होगा। अगर यह नहीं किया जाता है तो यह मुश्किल होगा। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 एक अच्छा माध्यम है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होगी।

[हिन्दी]

श्री निनोंग ईरींग (अरुणाचल पूर्व) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया है। बिजली की समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इसकी समस्या है। माननीय सदस्यों ने इस विषय में अपने-अपने विचार सदन के सामने रखे, फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ पंक्तियों में अरुणाचल प्रदेश के बारे कहना चाहूंगा। इससे पहले मैं ऊर्जा मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने 40 करोड़ रुपए का बजट रखा था, उसे वित्त मंत्री जी से बात करके बढ़ा कर 52 करोड़ रुपए किया है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। कल भी सदन में चर्चा हुई थी कि पंजाब, हरियाणा राज्य को सूखे के समय में 50 मेगावाट का उत्पादन दिया था। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि कोसी की बिहार में जल संशोधन के विषय में जो समस्या है, उसके बारे में आपने सुना होगा कि पाला साहब और बंसल साहब वहां गए थे, वहां चर्चा हुई और शायद कुछ समझौता हुआ है। यह शायद हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। एक्सलरेटेड पावर डवलपमेंट रिफार्म्स में 1614 करोड़ रुपये बजट में रखे थे, उसे इस साल में 2080 करोड़ रुपया दे कर गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उद्योगपतियों के लिए तथा आईटी टेक्नोलोजी के जो कोर्सेस हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। हमारे यहां भी एपीडीआरपी कई टाउंस में शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वहां प्रोपोजल्स दे चुके हैं और कोशिश कर रहे है कि पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा उसे शुरू करें। जब हम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के बारे में कहेंगे, यह एक और बहुत बड़ा कदम है। जो 5400 करोड़ का एक टार्गेट रखा है हमारे पूरे देश भर में जितने हमारे पिछड़े-वर्ग के लोग हैं, हमारे जो दूरदराज के लोग हैं, हमारे बीपीएल के जो लोग हैं, उनके लिए यह बहुत ही लाभदायक होगा। हमारे यहां पूरे देश में 2008-09 की रिक्वॉयरमेंट 109809 मेगावाट की थी लेकिन हमें 96785 मेगावाट उपलब्ध हुई यानी कि हमारे यहां शार्टफॉल 13024 मेगावाट की रही है। इस बार विद्युत मंत्री जी ने फ्यूल थर्मल में 69000 मेगावाट, कोयले से 78000 मेगावाट, गैस से 16000 मेगावाट, ऑयल से 1199 मेगावाट, हाइड्रो-इलैक्ट्रिक में 36900 मेगावाट और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से 13242 मेगावाट का टार्गेट रखा है जिसमें चटक, नथपा, टेहरी वगैरह अन्य छोटे-छोट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इन से जो विद्युत उत्पादन होता है, इसको लेकर हमारा 150000 मेगावाट का टार्गेट रखा गया है।

आप खुद भी सोच सकते हैं कि आजादी के समय हमारी क्षमता केवल 508 मेगावाट की थी लेकिन आज की तारीख में 36916 मेगावाट पन बिजली से हमें उत्पादन मिल रहा है।

सर, मैं दो मिनट और लूंगा क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश के विषय में कहना चाहूंगा क्योंकि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, वहीं आपके भविष्य की पावर समस्या का समाधान कर सकता है।

हमारे यहां इस बार जो ग्यारहवीं योजना है, इसमें 2600 मेगावाट और 400 मेगावाट की अभी हमारी आवश्यकता है और वे परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं। इन परियोजनाओं में एक परियोजना हमारे सुवनसिरी में है, एक तवांग में है और एक 2000 मेगावाट की परियोजना है, दूसरी परियोजना 600 मेगावाट की है। इससे आप सोच सकते हैं कि 11वीं योजना में हमारा लक्ष्य 2600 मेगावाट, 12वीं योजना में 20,000 मेगावाट और 13वीं योजना में 12,400 मेगावाट है। इसका अर्थ यह हुआ कि 35,000 मेगावाट विद्युत पहले से निर्माण की प्रक्रिया में है। हम उससे सहमत नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमें तीन प्राथमिकता लेनी चाहिए। इनमें से एक है, राज्य ग्रिड की संस्थापना यानी जितने हमारे पॉवर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको एक-दूसरे से कनैक्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, पूर्वोत्तर राज्यों से देश के शेष भागों तक पारेषण लाइन। रिक्वायरमेंट जो जरूरी होती है, जैसे कि पीजीसीएल से हमें बात करनी पड़ेगी और इसमें हमें केन्द्र सरकार की पूरी सहायता चाहिए होगी क्योंकि 2500 कि.मी. अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली आने की जो समस्या है, वह बहुत ही जरूरी है, अगर हम इसे कर पाएंगे तब तो वहां बिजली का उत्पादन होगा लेकिन उसको लाना बहुत मुश्किल है। परंतु जैसे ही आप चिकन नेक पर आएंगे, जिसे हम लोग मुर्गी की गर्दन कहते हैं, क्योंकि आप जब सिलीगुडी जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे कि जो वहां 18 कि.मी. है, उसी में हमारे सारे विकास के कार्यक्रम—जैसे रोड नेटवर्किंग होती है, हमारे रेल लाइनें जाती है। इसलिए इन सबको ध्यान में रखकर ही मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर विशेष ध्यान दें ताकि अरुणाचल प्रदेश की जो भविष्य की समस्या है, उसे आप अविलम्ब ठीक कर सकें। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं-

लूट के औरों का धन राज बनाया होगा।
महज रोटी के लिए सैकड़ों को मोहताज बनाया होगा।
वही शहंशाह ने वेहम में आकर
कब्र पर मुमताज के एक ताज बनाया होगा।

मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज बहुत लोग एक छोटे सी बात के लिए वॉक आऊट करते हैं, विरोध भी करते हैं। लेकिन आप सोचिए चीन के समीप लगे हमारे प्रोजेक्ट्स की इतनी क्षमता है, वहां हमारे इतने सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, हमें उनके लिए सोचना चाहिए। अगर मुझे चीन जाना है तो मुझे वीजा नहीं दिया जाता है और कहा जाता है- आप हमारा ही हिस्सा हैं। हम आपको वीजा कैसे दे सकते हैं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां अरुणाचल प्रदेश और चीन के इश्यू को खत्म करना चाहिए। हम इसे बार-बार क्यों उठाएं? अगर में चीन जाऊंगा तो वीजा लेकर जाऊंगा? यहां इतने कार्यक्रम बना रहे हैं ओर हमारे लिए सोचना चाहिए क्योंकि हम भी वहां से, इतनी दूर से आते हैं। परंतु हम सच्चे राष्ट्रवादी हैं। हम अपने महान राष्ट्र का अंग हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व है।

[हिन्दी]

आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री पी. लिंगम** (तेनकासी) : सभापति महोदय, व्यक्तियों के जीवन और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में विद्युत बहुत महत्वपूर्ण है। यह केन्द्रीय धुरी है। इसी तथ्य के मद्देनजर 1948 में विद्युत उत्पादन को सार्वजनिक क्षेत्र में रखने के लिए केन्द्रीय विद्युत अधिनियम पारित किया गया था। तत्पश्चात् राज्यों में विद्युत बोर्ड स्थापित किए गए। हमने सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में 1,47,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन को देख सकते हैं। जब विद्युत की मांग बढ़ गयी तो सरकार समान रूप से विद्युत का उत्पादन बढ़ाने में विफल हो गयी जिसके परिणामस्वरूप देश और व्यक्तियों को विद्युत कटौती का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की कटौती से जनता, कृषकों और औद्योगिक इकाइयों पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमें विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु अर्थोपाय विकसित करने की जरूरत है ताकि हम विभिन्न क्षेत्रों की मांग को पूरा कर सकें।

हमारे देश के पास कई तरीकों से विद्युत उत्पादन करने की प्रचुर और विपुल संभावनाएं हैं। यदि हम देश की मुख्य नदियों को जोड़ दें तो हमारी पनविद्युत क्षमता अत्यधिक बढ़ जाएगी। नदियों के जोड़ने संबंधी राष्ट्रीय प्राधिकरण देश की 30 प्रमुख नदियों को जोड़ने की व्यवहार्यता का पता लगाया है। इसलिए इन नदियों को जोड़ने की तत्काल आवश्यकता है और वर्द्धित पनविद्युत परियोजनाओं के जरिए अधिक विद्युत उत्पादन हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

मेरे संसदीय क्षेत्र में पाम्बा, अचनकोविल और वैयप्पर नदियों को जोड़ा जा सकता है और इस तरह विद्युत उत्पादन क्षमता को कई गुना

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी. लिंगम]

बढ़ाया जा सकता है। अत: इस परियोजना को आरंभ करने की आवश्यकता है। इस बीच हमें पवन ऊर्जा की क्षमता का उपयोग करना चाहिए और हम पवन चक्कियां स्थापित कर और अधिक विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। ये पवन चक्कियां भूमि और जल दोनों में स्थापित की जा सकती हैं। अत: पवन चक्कियों से विद्युत उत्पादन को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

गन्ने के सह उत्पाद के रूप में चीनी मिलों से उपलब्ध खोई का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। अत: हमें गन्ने के अपशिष्ट को लाभदायक विद्युत में बदलने की क्षमता का निश्चित रूप से उपयोग करना चाहिए।

हमारे पास नेवैली लिग्नाईट कारपोरेशन है और वहां ताप विद्युत स्टेशन है। हमारे पास राज्य में ऐसा कोई और विद्युत स्टेशन नहीं है इसलिए तमिलनाडु में विद्युत का काफी आभाव है। विद्युत उत्पादन अपर्याप्त है और विद्युत बहुत अधिक है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि एन.एल.सी. इकाई से तमिलनाडु को और अधिक विद्युत प्रदान की जाए ताकि बिजली की कमी को पूरा करने में हमें मदद मिल सके। सरकार ने घोषणा की है कि ठेका कामगारों को शीघ्र ही न्याय मिलेगा जो स्थायी हुए बिना यहां पर एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन्हें शीघ्र स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु में विद्युत के संकट को दूर करने के लिए एन.एल.सी. की चौथी इकाई स्थापित की जाए।

हम परमाणु ऊर्जा की बात कर रहे हैं जिससे हमारे देश की विद्युत आवश्यकता को बहुत सहायता मिल सकती है। हमारे पास परमाणु ऊर्जा पहले ही से उपलब्ध है। थोरियम हमारे मृदा में उपलब्ध है। हमारे पास परमाणु रिएक्टरों से विद्युत उत्पादन की प्रौद्योगिकी है। हम किसी अन्य देश की सहायता लिए बिना आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमें अमेरिका जैसे देश के पास अपनी संप्रभुता गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भारत अमेरिका असैनिक परमाणु सहयोग समझौते से हट जाए। हमें देश ही में विद्युत उत्पादन करने पर ही जोर देना चाहिए । हमारे पास परमाणु रिएक्टरों हेतु अपेक्षित हैवी वाटर उंत्पादन करने की क्षमता है। स्पिक (एस. पी.आई.सी.) हैवी वाटर का उत्पादन करने वाली इस प्रकार की एक औद्योगिक इकाई है। यह इकाई पहले सार्वजनिक क्षेत्र की थी ओर बाद में यह निजी इकाई बनकर अंतत: बंद हो गई है। इस इकाई की क्षमता बर्बाद नहीं जानी चाहिए। इसलिए राष्ट्र हित और विद्युत उत्पादन के लिए इस औद्योगिक इकाई का पुनरुद्धार करने का प्रयास करना चाहिए। यह इकाई देश में उर्वरक उत्पादन के माध्यम से हरित क्रांति में सहयोग दे सकती है और परमाणु रिएक्टरों में आवश्यक हैवी वाटर के उत्पादन द्वारा (गुरू जल) विद्युत उत्पादन में भी सहयोग दे सकती है। एसपीआईसी संगठन जो अपनी रजत जयन्ती मना चुका है आज बंद पड़ा हुआ है। 'स्पिक' को पुन: चालू कर और गुरू जल का उत्पादन कर हम कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना को गुरूजल की आपूर्ति कर सकते हैं। कूडनकुलम में विद्युत उत्पादन प्रारंभ होने से विद्युत की कमी से त्रस्त तमिलनाडु की बहुत बड़ी मदद हो सकती है।

आज विद्युत उत्पादन और वितरण करने वाली कंपनियों जो पहले विद्युत बोर्ड हुआ करते थे, में आज जनशक्ति की कमी है। पुराने ट्रांसफार्मर और केबिलों के कारण बार-बार बिजली कट जाती है और कर्मचारियों के आभाव में रख-रखाव के कार्यों में बाधा आती है। हमारे विद्युत बोर्डों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए जो ट्रांसफार्मरों और पारेषण हेतु केबलों के उचित रखरखाव की ओर ध्यान दे सकें। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तात्कालिक आधार पर हमारे समक्ष उपस्थित बिजली के संकट को दूर करने हेतु इस आवश्यकता की ओर ध्यान दें।

अधिक विद्युत उत्पादन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मैं सरकार से यह अनुरोध भी करता हूं कि जरूरतमंद गरीबों, किसानों और बुनकरों को बिजली मुफ्त प्रदान की जाए और इस संबंध में समुचित योजनाएं बनाई जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर) : सभापति महोदय, सदन में विद्युत मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर विमर्श हो रहा है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं अन्य बातों पर आने से पहले यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ष 790 बिलियन यूनिट्स पावर इस देश में पैदा होगी और इसी पर देश आधारित रहेगा। जबकि वर्ष 2008-2009 में 723 बिलियन यूनिट्स का प्रोडक्शन हमारे बिजली घरों में हुआ था। इसका नतीजा यह होगा कि हम पिछले वर्ष से और पीछे चले जायेंगे। यह हमारे देश का ऐसा बजट है, जो गत वर्ष से हमें और पीछे ले जायेगा, शायद गत वर्ष में ऑफ पीक ऑवर में पूरे देश के पैमाने पर 11 परसेन्ट की कमी मांग और आपूर्ति में रही है। वह इस वर्ष बढ़कर

11.9 परसेन्ट होगी और पीक ऑवर में 9.3 परसेन्ट से बढ़कर 12.6 परसेन्ट का मांग और आपूर्ति में अंतर होगा। इसलिए ऐसा बजट है जिसमें स्पष्ट चित्र दिख रहा हो कि मांग और आपूर्ति के मामले में यह देश गत वर्ष से पीछे जायेगा।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश के सिनेरियो में हमारे बिहार की क्या स्थिति है, जहां से हम लोग आते हैं। वहां की स्थिति बड़ी जटिल है। वह गरीब सूबा है, पर कैपिटा कंजम्पशन सबसे कम है और उसी का नतीजा है कि हर क्षेत्र में हम लोग पिछड़े हुए हैं। लेकिन ईस्टर्न ग्रिड जिसका पार्ट बिहार है, वह इस वर्ष मांग और आपूर्ति के पैमाने पर सरप्लस में जायेगा। वर्ष 2008-2009 में जहां डेफिसिट 4.5 परसेन्ट था, इस वर्ष 2009-2010 में यह 2.4 के सरप्लस में जायेगा। लेकिन बिहार के उसी ईस्टर्न-रीजन का हिस्सा हैं मगर हमारे माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि आखिर इस देश की समृद्धि और देश के उत्पादन में बिहार क्यों पिछड़ता चला जा रहा है? इस समय बिहार में ऑफ पीक ऑवर में 16.4 परसेन्ट मांग और आपूर्ति में अन्तर है।

पीक ऑवर में यह अन्तर 27.9 परसेंट इस वर्ष चला जाएगा, जबकि गत वर्ष 27.6 परसेंट की कमी पीक ऑवर में थी। जैसे-जैसे समय गुजरता जा रहा है, हमारी मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ता जा रहा है और यही हमारे पिछड़ेपन का कारण है। मैं इसकी चर्चा में जाना नहीं चाहता हूं कि अपने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति कैसे हो रही है। यह ठीक है कि 5 हजार से अधिक ट्रांसफॉर्मर जले हैं, यदि वह भी रहते तब भी हमारी मांग और बढ़ जाती, लेकिन मैं उसकी चर्चा यहां करना नहीं चाहता हूं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि इस वर्ष विद्युत के उत्पादन में ईस्टर्न ग्रिड सरप्लस में होने जा रहा है तो बिहार का एलोकेशन बढ़ना चाहिए और मांग और आपूर्ति का अंतर घटना चाहिए। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि ईस्टर्न ग्रिड से ढाई हजार मेगावाट पॉवर प्रतिदिन बाहर जाता है और बिहार अंधेरे में रहता है। बिहार बिजली खरीदता है, पैसा चुकाता है, हमारे किसान बिजली के लिए पैसा देने को तैयार हैं। यह बात अलग है कि हमारे राज्य में भी शहरी और गांव की बिजली की मांग और आपूर्ति में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन उसकी चर्चा के लिए यह स्थान नहीं है। ढाई हजार मेगावाट पॉवर ईस्टर्न ग्रिड से बाहर नॉदर्न ग्रिड, वेस्टर्न ग्रिड, साउथर्न ग्रिड जाती हैं हमारे सारे ग्रिड बैक टू बैक के सिस्टम पर बने हुए हैं, लेकिन मेरा पिछले 5-7 सालों का अनुभव है कि कभी भी एक दिन में एक घंटे के लिए भी ईस्टर्न ग्रिड को बाहर के ग्रिडों से बिजली नहीं मिली है और यहीं से लगातार पॉवर बाहर जाती है। आखिर यह अन्याय क्यों हो रहा है? यदि इस देश में यही नीति रहेगी तो शायद कभी भी बिहार जैसे राज्य बिजली के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे और हमारी बिजली की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी।

महोदय, मैं दो-तीन बातों की चर्चा कर देता हूं। मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए कमी के राष्ट्रीय औसत के बराबर सभी राज्यों को विद्युत की आपूर्ति की जाए। एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए कि मांग और आपूर्ति में कोई राज्य हमारे एवरेज डेफिसिट से आगे न जाए। दूसरी बात जैसे-जैसे नये उत्पादन केंद्र आ रहे हैं, उनका टैरिफ महंगा होता जा रहा है। हम पिछड़े राज्य हैं और जो नये बिजली घर बनेंगे, हमें उनसे महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। मेरा कहना है कि केन्द्रीय सरकार के पुराने और नये बिजली घरों से उत्पादित बिजली की कीमत बराबर रहे। इसे हम जनरल टैरिफ कहते हैं। यदि पिछड़े राज्यों को जनरल टैरिफ पर बिजली नहीं मिलेगी तो इससे पिछड़े राज्यों को और परेशानी बढ़ती जाएगी। आज बिजली खरीदने की क्षमता के आधार पर बिजली की कीमत तय हो रही है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी घट जाती है तो उस समय बिजली की कीमत प्रति यूनिट चार्ज 9 रुपए, 10 रुपए तक पहुंच जाती है और समृद्ध राज्य उसे समय बिजली खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब राज्य उस समय 9 रुपए, 10 रुपए प्रति यूनिट में बिजली नहीं खरीद सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर ऐसा बाजार न बनाया जाए कि पिछड़े राज्यों को और महंगी बिजली खरीदनी पड़े। मुझे लगता है कि यह बहुत संकट का विषय है। जैसे ही ग्रिड में फ्रीक्वेंसी घटती है, कीमत बढ़ने लगती है। तीसरी बात, इस देश के पैमाने पर जितना भी बिजली का उत्पादन हो रहा है। उसमें से आधी बिजली कृषि परिक्षेत्र को मिलनी चाहिए। चौथी बात, गांव मे ट्रांसफार्मर और लाइन लगाने का काम, जो पॉवर ग्रिड कर रहा है, चाहे बिहार में सम विकास योजना के माध्यम से या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से हो। जिस तरह पी.एम.एस.वाई. सड़कों का 5 वर्ष तक रख-रखाव, उसके एस्टीमेट का पार्ट होता है, उसी तरह ग्रामीण विद्युतीकरण का भी होना चाहिए, यह नहीं हुआ है। मैं आज बताना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण जो राजीव गांधी जी के नाम पर हुआ है, उसके आधे से अधिक ट्रांसफार्मर जले हैं, वे छोटे ट्रांसफार्मर्स हैं। उन जले ट्रांसफार्मरों को कौन बदलेगा? बिहार बिजली बोर्ड का कहना है कि उनके पास वन फेज, टू फेज कनेक्शन का ट्रांसफार्मर नहीं होता है, थ्री फेज का होता है। भारत सरकार की तरफ से आपूर्ति एक फेज और दो फेज की हो रही है। वहां ट्रांसफार्मर 16 या 25 केवीए का लग रहा है।

[श्री जगदानंद सिंह]

इसको माननीय मंत्री जी देखें कि इतनी बड़ी कीमत - इस वर्ष 7500 करोड़ रुपये देश के पैमाने पर खर्च होने जा रहे हैं लेकिन वे सारी चीजें व्यर्थ में चली जाएंगी। यह देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे गांव के लोगों को बिजली कब मिलेगी? मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि छोटे ट्रांसफॉर्मरों के स्थान पर थ्री फेज बड़े ट्रांसफॉर्मर आप लगवाएं। महोदय, बिहार की उन योजनाओं को, जो बिहार के लिए अपनी बिजली पैदा करने का साधन हैं, 450 मेगावाट का कदवन प्रोजैक्ट भारत सरकार के सामने लंबित है। उससे हमारे सोन के इलाके को पानी भी मिलेगा। एक भी बूंद पानी व्यर्थ नहीं जाएगी। कदवन जलाशय बाणसागर समझौते का हिस्सा हैं यदि बाणसागर समझौते को भारत सरकार लागू करना चाहती है तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को न्याय देना चाहती है एक समान स्तर पर, तो हमारे अपर रिपेरियन स्टेट्स को पानी रोकने से रोकना पड़ेगा। कदवन जलाशय बनना चाहिए। इससे 450 मेगावाट बिजली पीक आवर्स के लिए हमें भी मिलेगी और ईस्टर्न ग्रिड को आवश्यकता पड़ने पर हम दे सकते हैं जिससे देश को बिजली मिलेगी। 3500 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता कोसी हाई डैम की है। कोशी का पानी बाढ़ का कारण बना हुआ है। माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि इस पानी से बिजली बननी चाहिए। सबसे बड़ा खतरनाक निर्णय जो मैं देख रहा हूं, वह यह है कि कोयले की जहां उपलब्धता होगी, वहीं थर्मल पावर स्टेशन लगेंगे। उससे भी खतरनाक बात होने जा रही है।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। जिन राज्यों में निजी बिजलीघर बनने वाले हैं, वे राज्यों को ऑफर दे रहे हैं कि 50 फीसदी बिजली उन्हें ही दे दी जाएगी। माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि योजना आयोग आप पर भी दबाव डाल रहा है कि आप इस कंपीटीशन में आइए। जहां यह बिजली बनेगी, प्रचुर मात्रा में जहां कोयला होगा और फिर पचास फीसदी बिजली उन्हीं को मिल जाएगी। फिर बिहार जो पिछड़ा राज्य है, उसको बिजली कैसे मिलेगी। कैसे रीजनल इम्बेलैन्स दूर होगा। मैं एक उदाहरण देकर खत्म कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि 1990 में मैं बिहार का ऊर्जा मंत्री था। आप सब लोगों के सामने जब राष्ट्रीय पैमाने पर ऊर्जा मंत्रियों की बैठक होती है, उस समय मैंने लोगों से कहा था कि सबसे ज्यादा डिमांड और सप्लाई में अंतर बिहार में है तीस फीसदी और उस समय के केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी ने बिहार का एलोकेशन बढ़ा दिया था। आज हाइयैस्ट डिफरेन्ट है। बिहार को 1500 मेगावाट की जरूरत है और आप बिजली दे पाते हैं 1000 मेगावाट से भी कम।

अंत में मेरा एक ही सबमिशन है कि मंत्री जी आपको एक नीति बनानी चाहिए कि जिसके पास मांग और आपूर्ति का सबसे बड़ा अंतर है, उसकी बिजली की कटौती किसी भी हालत में नहीं होगी। अभी आपने यह निर्णय कर लिया कि हमें एलोकेटेड पावर मिलेगी, वरना 1500 मेगावाट की डिमांड पर हमें 1000 मेगावाट बिजली मिलेगी तो बिहार पिछड़ा रहेगा, गरीब रहेगा, वहां रोशनी नहीं मिलेगी, वहां खेती नहीं हो पाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे विद्युत मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय विद्युत मंत्री जी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि राजीव गांधी विद्युतीकरण में उन्होंने 40000 करोड़ रुपये को बढ़काकर 53000 करोड़ रुपये किया हैं इससे देश के गरीब, छोटे, मझले टोले, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के तमाम गांवों को बिजली पहुंच सकेगी। साथ-साथ आदरणीय मंत्री जी का ध्यान में इस तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं कि राजीव गांधी विद्युतीकरण में बहुत सारे राज्य अपनी स्वैच्छिकता अपना रहे हैं। जो आपकी मंशा है कि देश के गरीबों को, देश के मझले टोलों तक बिजली पहुंचे, वे आपसे अनुबंध करके तो यहां से पैसा लेकर जा रहे हैं, लेकिन उन राज्यों में काम नहीं हो रहा है। मैं अपने राज्य मध्य प्रदेश और अपने निर्वाचन क्षेत्र उज्जैन का उदाहरण देना चाहता हूं। उज्जैन जिले को 45 करोड़ रुपये सन् 2006 में दिया गया । दो साल के अंदर वहां के मझले टोलों का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए था, लेकिन आज हालत यह है कि तीन साल हो गए हैं, उन कंपनियों का अनुबंध भी खत्म हो गया और अनुबंध खत्म होने के बाद वे कंपनियां पैसा लेकर इधर-उधर चली गईं और उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ। साथ ही माननीय विद्युत मंत्री जी यह भी कहा कि 5 अगस्त, 2008 को यहां पर सभी सांसदों को उस कमेटी की मॉनीटरिंग के लिए अध्यक्ष या संयोजक बनाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने कहीं भी इसकी सूचना सांसदों को नहीं दी है।

इसकी मानिटरिंग का इंतजाम किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार का जो पैसा गरीबों और दलितों के लिए जा रहा है, उसका उपयोग ठीक तरह से होना चाहिए। यदि उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो इसके लिए उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए।

मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ी की जा रही है, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, वर्ष 2007-08 के मुकाबले वर्ष 2008-09 में 9 प्रतिशत अधिक बिजली का उत्पादन हुआ है, जिसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, बहुत से अनुबंध प्राइवेट कंपनियों के साथ किए गए हैं, जिनका अनुपालन नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां बिजली कंपनियों से बिजली के उत्पादन के लिए अनुबंध किए गए हैं, लेकिन वहां एक कील भी अभी तक नहीं गाढ़ी गई है, एक यूनिट भी बिजली अभी तक पैदा नहीं हो पायी है। लेकिन मध्य प्रदेश से हजारों टन कोयला दूसरे राज्यों को जा रहा है, जहां उसका उपयोग हो रहा है। वर्ष 2020 का जो बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, वह प्राइवेट कंपनियों द्वारा बिजली उत्पादन के आधार पर है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक यूनिट का भी उत्पादन नहीं हुआ है। लेकिन हजारों टन कोयले का खनन किया जा रहा है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री नरहरि महतो (पुरुलिया) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 2009-10 हेतु विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के संबंध में चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

माननीय सदस्यगण काफी समय से वर्ष 2009-10 हेतु विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं पश्चिम बंगाल के अविकसित और पिछड़े जिले पुरुलिया का रहने वाला हूं। इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं।

विद्युत की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण योजना है। अर्थव्यवस्था की 9 प्रतिशत से अधिक वार्षिक विकास दर के साथ भारत में ऊर्जा की आवश्यकता काफी बढ़ी है। अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए कम से कम अगले तीन दशकों में प्रत्येक दस वर्ष तक अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा। देश की बढ़ती हुई विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उच्च क्षमता वाली परियोजनाएं विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का शुभारंभ वर्ष 2005 में हुआ था। मेरे जिले में 30 प्रतिशत से अधिक गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। केवल मेरे ही जिले में नहीं अपितु मेरे राज्य में कूच बिहार जैसे कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो अनुसूचित जातियों के निवासियों से भरे पड़े हैं। यह भारत का पहला जिला है जहां 52 प्रतिशत अनुसूचित जाति समुदाय के लोग रहते हैं। परंतु अब तक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एक भी गांव में लागू नहीं की गई है। मेरा माननीय मंत्री जी से ये निवेदन है कि वे कृपया इस मामले पर ध्यान दें।

विद्युत मंत्रालय ने कोयला खानों के मुहाने और तटीय स्थानों दोनों में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के विकास की सुविधा के लिए एक अनोखी पहल की है। राष्ट्रीय विद्युत नीति का लक्ष्य 2012 तक ऊर्जा की कमी को पूरा करने का है। विद्युत मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के मध्य कोयला पूर्ति के साथ-साथ पर्यावरण और वन स्वीकृति हेतु समन्वय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट्स स्कीम के माध्यम से विद्युत का आबंटन विभिन्न राज्यों के परामर्श से किया जाना चाहिए। साथ ही अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट्स स्कीम की नियमित निगरानी की जाए ताकि इससे संबंधित चिंता के मुख्य मुद्दों को सुलझाया जा सके। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि विद्युत मंत्रालय अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट स्कीम की प्रगति की निगरानी करता रहे ताकि ये परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जा सकें। विद्युत मंत्रालय परियोजनाओं को आरंभ कराने में सक्रिय भूमिका निभाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र में संथालदीह थर्मल पॉवर स्टेशन हैं इस परियोजना की कार्य प्रगति संतोषजनक नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक जल विद्युत परियोजना जिसका नाम पुरुलिया पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है इसे जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। अयोध्या हिल्स के लोगों द्वारा इस परियोजना को लागू करने की मांग लगातार की जाती रही है।

महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के क्षेत्रों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुचारू रूप से लागू नहीं की गई है। बिजली की तारों समेत बिजली के खंभें लगा दिए गए हैं परंतु अब तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है जिसके परिणामस्वरूप लोगों को बिजली नहीं मिल रही और इस कारण ग्रामीण, कृषक और छात्रों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया आप एक मिनट के लिए अपनी सीट पर बैठ जाइए।

माननीय सदस्यगण, चूंकि अभी काफी सदस्य बोलने के लिए बाकी हैं, अगर सभा की इच्छा है तो हम लोग इस बहस के समाप्त होने तक सभा की कार्यवाही की समायावधि बढ़ा सकते हैं।

श्री महतो, आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री नरहरि महतो : महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वियन ठेकेदारों के माध्यम से किया जा रहा है और वे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। साइन बोर्ड तो लगा दिए गए हैं, लेकिन क्षेत्र में जिन घरों में बिजली पहुंचाना प्रस्तावित है उनका कहीं नामोल्लेख तक नहीं किया गया है। यहां तक कि इस संबंध में क्षेत्र के संसद सदस्य से भी सलाह-मशविरा नहीं किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से इन बातों पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : जैसे कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं इस वाद-विवाद पर अनेक सदस्यों को बोलना है अत: जो माननीय सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री के. सुधाकरण।

अपराह्न 5.59 बजे

[**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

श्री के. सुधाकरण (कन्नूर) : महोदय, मैं अत्यंत प्रसन्नता और हर्ष के साथ विद्युत मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। परंतु इस विषय पर विचार व्यक्त करने से पूर्व में इस वाद-विवाद पर बोलने का यह अवसर देने पर आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे इस सम्माननीय सभा में कन्नूर की जनता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं अपनी पार्टी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को भी ध्यान देना चाहूंगा। मैं भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को नमन करता हूं जिसकी सहायता से मैं यहां पहुंचने में सफल हुआ हूं और जो भारत को सर्वोच्च शक्ति का केंद्र है।

महोदय, आज भारत तेजी से विकास कर रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था का भी तेजी से विकास हुआ है और यदि हम इसी विकास दर को बनाए रख सके। तो भारत विश्व में आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा।

सायं 6.00 बजे

किसी भी अर्थव्यवस्था में तेजी लाने वाली प्रेरक शक्ति विद्युत होती है। हमारे उद्योग और हमारे धान के खेतों के पंपसेट विद्युत पर निर्भर हैं। पर्याप्त विद्युत के बिना हम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। इन सभी तथ्यों पर विचार करके हमारे वित्त मंत्री ने विद्युत क्षेत्र के लिए बजट आबंटन को बढ़ाकर 160 प्रतिशत कर दिया है।

आज, हमारे देश में विद्युत की कमी है। विद्युत के हमारे पंरपरागत स्रोत जल विद्युत और ताप विद्युत हैं। मैं ऐसे राज्य से हूं जो मुख्यत: जल विद्युत पर निर्भर है। हमारे जलविद्युत केंद्र अपनी अधिकतम क्षमता से उत्पादन कर रहे हैं परंतु मेरे राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु यह पर्याप्त नहीं है।

नई जल विद्युत परियोजनाओं हेतु किसी प्रस्ताव से बहुत सी पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वनस्पति और जीव-जंतु का काफी बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो सकता है और इससे सामाजिक एवं पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। केरल के कुछ जल विद्युत संयंत्रों को पूर्व महाराजाओं के समय में बनाया गया था। उनमें से कुछ को हाल ही में नवीकरण किया गया था। स्वीकृत परियोजनाओं में पल्लिवसल, चेगुंलम और पन्नियन मुख्य हैं। नवीकरण कार्य पूर्णत: असफल रहा। भारी धनराशि खर्च करने के बाद ही हमने महसूस किया कि विद्युत उत्पादन पहले से घट गया था। वास्तव में, यह एक घाटे का सौदा था।

इसके अतिरिक्त, केरल की जनता को कनाडा की कंपनी द्वारा बेवकूफ बनाया गया। कंपनी ने कुछ राजनेताओं की मिलीभगत से जनता को धोखा दिया केरल राज्य में चर्चित कुख्यात लावालिन मानक का भ्रष्टाचार और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मार्गदर्शन के अभाव का अनोखा मामला है।

मैं समझता हूं कि मौजूदा नियमों के अनुसार, 100 करोड़ रुपये से अधिक की किसी परियोजना के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अनुमति की आवश्यकता होती है। परंतु मैं जानता हूं कि इस मामले में केरल सरकार या बिजली बोर्ड दोनों में से किसी ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से कोई पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की. थी। पिछले सप्ताह में प्रश्न काल के दौरान माननीय सदस्य पी.सी. चाको ने इस मुद्दे से संबंधित एक प्रश्न वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी से पूछा था परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अत:, महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछता हूं कि क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच करके इस सौदे में हुई अनियमितताओं को प्रकाश में लाएगी। यदि उत्तर 'नहीं'

में है तो भारत की संघीय प्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लग जाएगा। यदि अन्य सभी राज्य केरल की तरह चलें तो केंद्र सरकार की क्या स्थिति होगी? क्या केंद्र सरकार की ऐसे सौदों को नियंत्रित करने में कोई भूमिका होगी?

हमारे राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वास्तव में हमें अधिक विद्युत का उत्पादन करना होगा। ताप विद्युत जिसका भारत में विद्युत उत्पादन में अधिकांश हिस्सा है वह ईंधन के रूप में कोयले पर निर्भर है। घटिया किस्म वाले भारतीय कोयले से भारी मात्रा में राख का उत्सर्जन हो रहा है जिसके कारण पर्यावरण और वातावरण प्रदूषित हो रहा है और वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। अत:, इस क्षेत्र में, हमारे विकल्प बहुत सीमित हैं। हमारे पास जलविद्युत में कोई विकल्प नहीं है और ताप विद्युत में भी कोई विकल्प नहीं हैं हमारे पास केवल एक विकल्प है और वह परमाणु विद्युत है। आज इस बात को पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता है कि परमाणु ऊर्जा विद्युत उत्पादन का सबसे स्वच्छ स्रोत हैं और मेरा विचार है कि भारत के बड़े पैमाने पर परमाणु विद्युत का उत्पादन करना चाहिए।

इस संदर्भ में, मैं भारत में विद्युत उत्पादन के इतिहास में बड़ी उपलब्धि भारत-अमरीका परमाणु संधि का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं जिसकी सहायता से भारत को 35 वर्षों से परमाणु ऊर्जा संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी से अलग-थलग रखने का अंत हुआ था...*(व्यवधान)* परंतु हमारे एक राजनीतिक वर्ग ने इसे सरकार को गिराने का मुद्दा बनाया। मुझे भाजपा की मिलीभगत से इस सभा में सीपीआई(एम) द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव याद है जो भारतीय संसद के इतिहास का हिस्सा है। चुनाव के समय इसी मुद्दे पर वाद-विवाद हुआ था महोदय, जनता स्पष्ट जनादेश देकर संप्रग को सत्ता में वापस लाई। इस चुनाव का जनादेश स्पष्ट है कि इस राष्ट्र को लोकतांत्रिक सरकार की आवश्यकता है। इस राष्ट्र को स्थायी सरकार की आवश्यकता है, इस राष्ट को धर्मनिरपेक्ष सरकार की आवश्यकता है और इस राष्ट्र को ऐसी सरकार की आवश्यकता है जिसके पास विकासात्मक कार्यकलाप और कार्यक्रम हों। अत: जनता ने संप्रग को वोट दिया है। इसी जनता ने एलडीएफ को सबक सिखाया है। चौदहवीं लोक सभा में इनके साठ से अधिक सदस्य थे। परंतु जनता ने इस सभा में केवल दो दर्जन सदस्यों को पुन: निर्वाचित करके भेजा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप पहले ही आठ मिनट का समय ले चुके हैं। आपके साथी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके दल के सदस्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्यथा, हम उन्हें अवसर नहीं दे सकते।

श्री के. सुधाकरण : मुझे केरल से संबंधित कुछ और मुद्दे उठाने हैं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री के. सुधाकरण : मैं केरल से संबंधित कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं।

आरजीजीवीवाई योजना के बारे में हमारे राज्य केरल ने चौदह जिलों के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। उनमें से छह प्रस्तावों को स्वीकृत किया जा चुका था। परंतु जब आबंटन हुआ था तो हमें केवल एक जिले के लिए आवंटन किया गया। 526 जिलों में से, केरल से केवल एक जिले का चयन किया गया। 25000 करोड रुपये में से केरल को केवल 19.75 करोड़ रुपये दिए गए थे।

हमें एनागुंडम, कैगा और एनएलसी से विद्युत का बड़ा हिस्सा मिला करता था। परंतु केरल के हिस्से में काफी कमी की गई है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि केरल हेतु कोटे में वृद्धि की जाए। कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र प्रस्तावित विस्तार की प्रतीक्षा कर रहा है। वर्ष 2005 में माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी थी। परंतु वादा केवल वादा ही रह गया। यह वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

कुट्टियाडी वृद्धि योजना के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सारी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बावजूद इसे स्वीकृति नहीं दी गई है। हम पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम गैर-वनभूमि सौंप चुके हैं। हम वनीकरण की क्षतिपूर्ति हेतु धनराशि दे चुके हैं। मैं मंत्रालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं।

मुझे कई और मुद्दों का उल्लेख करना है। परंतु समय के अभाव के कारण मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री अनुराग सिंह ठाकुर** (हमीरपुर) : महोदय, हिन्दुस्तान में आजादी के 62 वर्षों के बाद भी बिजली का अभाव है और मांग दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रहे है। देश की मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति में देश और प्रदेश की सरकारें विफल रही हैं। आज जहां हम थर्मल पॉवर

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री अनुराग सिंह ठाकुर]

के अलावा हाइड्रो पॉवर पर निर्भर हैं, वहां सोलर, बायोमास और विंड एनर्जी का भरपूर दोहन नहीं कर पाए हैं, जो हमारे देश में प्रचूर एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

महोदय बिजली की कमी के कारण जब हम बिजली का उत्पादन जनरेटर के माध्यम से करते हैं, तो लगभग 9 से 10 रुपए प्रति यूनिट खर्च होता है। अगर यही विद्युत हम सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी या बायोमास से पैदा करें, तो प्रति यूनिट कम खर्च आएगा। डीजल सैटों के माध्यम से जब विद्युत उत्पादित की जाती है, तो कार्बन एमीशन्स भी बहुत मात्रा में होता है, जिससे पर्यावरण भयंकर रूप से दूषित होता है और वह मानव, पशु, पक्षी एवं अन्य समस्त जीवों के लिए हानिकर होता है। हजारों करोड़ रुपए की भारत सरकार की सब्सिडी जो डीजल पर दी जा रही है, वह भी बच जाएगी अगर हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोमास एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए निवेश करें और ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे हमारे देश में ये तीनों प्रकार की ऊर्जा सस्ती दर पर उत्पादित की जा सकें। इसके लिए अनुसंधान एवं विकास हेतु भारत सरकार द्वारा भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता है। यदि ऐसा किया जाएगा, तो देश बिजली संकट से उबर सकता है और देश को क्लीन ऊर्जा मिल सकती है।

महोदय, हिमाचल प्रदेश में विद्युत की खपत कम है, लेकिन वह अपनी आवश्यकता से दुगुनी विद्युत का उत्पादन करता है, जिसका लाभ पूरे देश को मिलता है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री, प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने वर्ष 1998 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, हजारों मेगावाट की नई पनविद्युत परियोजनाओं की शुरुआत की। आज हिमाचल प्रदेश में 6500 मेगावाट का पनविद्युत उत्पादन हो रहा है, जो वर्ष 2012 तक बढ़कर 10,000 मेगावाट हो जाएगा लेकिन इन विद्युत उत्पादन को लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमीशन लाइनों की जरूरत है इन ट्रांसमीशन लाइनों को बनाने पर हजारों करोड़ रुपए व्यय होते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार 4500 करोड़ रुपए ट्रांसमीशन लाइनों पर व्यय कर रही है और 500 मेगावाट विद्युत की ट्रांसमीशन के लिए प्रदेश सरकार ने 2100 करोड़ रुपये विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार से आग्रह किया है। यदि केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के निवेदन पर ध्यान नहीं देती और प्रदेश को विदेशी सहायता उपलब्ध नहीं कराती है, तो देश में बिजली का संकट हमेशा बना रहेगा क्योंकि प्रदेश में जो उत्पादन हो रहा है, उसे ग्रिड तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमीशन लाइनों की जरूरत होती है औ जब वे ही नहीं बनेंगी, तो उत्पादित ऊर्जा को उपयोग के लिए लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकेगा।

महोदय, बिजली को कन्करेंट लिस्ट से स्टेट लिस्ट में लाने का एकमात्र तात्पर्य यही था कि केन्द्र सरकार विद्युत उत्पादन हेतु, ट्रांसमीशन लाइनों के निर्माण हेतु एवं इस क्षेत्र के विकास एवं विस्तार हेतु जितनी भी अधिक से अधिक सहायता प्रदेशों को देगी, उतना ही विद्युत का उत्पादन बढ़ेगा और इस क्षेत्र में जहां भी किसी प्रकार की गड़बड़ी और कमियां हैं, उन्हें दूर किया जा सकेगा, लेकिन केंद्र सरकार अपना दायित्व ठीक प्रकार से नहीं निभा रही है और हर कार्य के लिए प्रदेश सरकार पर जिम्मेदारी डाल देती है।

महोदय, आज भी देश के लाखों गांवों में बिजली नहीं है। बिना बिजली के वहां विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते हैं। देश के लाखों गांवों में बिजली के अभाव में यदि बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो इसका अंततोगत्वा प्रभाव देश पर ही पड़ेगा और देश बिना बिजली के किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकेगा। अत: मेरा आग्रह है कि तापी विद्युत, पनविद्युत के साथ-साथ सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी और बायोमास एनर्जी की तरफ विशेष ध्यान दे और इन क्षेत्रों में भारी निवेश करे।

महोदय, मेरे कुछ निम्नलिखित सुझाव हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन पर गंभीरता से विचार करें और इन्हें स्वीकार करें, ताकि देश के गांव-गांव में बिजली पहुंच सके। जब गांव रोशन होंगे, तो देश अपने आप रोशन होगा ओर विश्व में महानायक बनने का सपना पूरा होगा।

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : सभापति महोदय, 2009-10 की अनुदान मांगों पर सामान्य चर्चा करने के लिए आपने जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पाण्डेय कृपया तीन मिनट के भीतर समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय : बस तीन ही मिनट का समय है? मंत्री महोदय का मैं 2-3 विषयों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सरकारी आंकड़ों में देश के थर्मल पावर केन्द्रों, प्लांट फैक्टर, लोड फैक्टर, पी.एल.एफ. में पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष जो वृद्धि का आंकड़ा दिया जा रहा है, वर्ष 2007-08 में वह 78.06 परसेंट था, अब वह घटकर 77.2 परसेंट पर आ गया है। सबसे बड़ी बात है कि भूटान से जो बिजली ली जा रही है, उसको भी मंत्री महोदय ने उसमें जोड़ा है।

हमारे यहां झारखंड में थर्मल पावर प्लांट चन्द्रपुरा में है और बोकारो थर्मल पावर प्लांट है। मंत्री महोदय को जानकर ताज्जुब होगा कि यह चिराग तले अंधेरा वाली बात हो गई। हमारे यहां बिजली 24 घंटे में से 8 घंटे से ज्यादा नहीं रहती है, जबकि हमारे यहां से कोयला दिल्ली और हिन्दुस्तान के सारे प्रदेशों में जाता है। मंत्री महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि चन्द्रपुरा में नया पावर प्लांट बन रहा है। आप बीच में शायद वहां गये भी थे। आपने देखा होगा कि सरकार को प्लांट को पूर्ण रूप से समय पर पूरा करवाने के लिए इंटरेस्ट फ्री एमाउंट मिला, लेकिन आज वह प्लांट समय पर पूरा नहीं हुआ। भारत सरकार के अब पूरे पैसे पर इंटरेस्ट लगने जा रहा है। आपने देखा होगा कि वर्तमान में बोकारो थर्मल प्लांट में भी नया प्लांट बन रहा है, चन्द्रपुरा में काम पूरा होने जा रहा है, लेकिन भेल को जो काम मिला, उसने तीन लेयर पर काम को बांटने का कम किया।

आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि काम की क्वालिटी किस ढंग की होगी। हमारे यहां वर्ष 1954 में कुनाल डैम का निर्माण हुआ और इसके बाद दामोदर वैली कारपोरेशन ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए एचपीसीएल के द्वारा प्रस्ताव दिया। आज तक वह किस खाते में पड़ा हुआ है, यह हमारी समझ से बाहर का विषय है।

महोदय, हम जल से जो बिजली पैदा करते हैं, उसमें सबसे कम खर्च आता है। उसमें पांच मेगावाट का प्रपोजल शुरू से चला आ रहा है, लेकिन आज तक दामोदर वैली कारपोरेशन ने उस पर कोई काम नहीं किया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जिसके बारे में जगदा बाबू ने कहा, उन्होंने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की बात कही। हम उस बात से जोड़ते हुए यह कहना चाह रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि हम गरीब के घर में एक बल्ब जला देते हैं, लेकिन बाकी गांव में रहने वाले लोगों को अगर पम्पिंग सेट चलाना होगा, कुट्टी काटने की दुकान खोलनी होगी या और कोई भी काम करना होगा, तो कहां से उसके लिए ट्रांसफार्मर लगेगा? वह लोड ही नहीं लेगा। आप दो फेज का कनेक्शन दे रहे हैं।

महोदय, इससे बड़ी बात यह है कि संथाल परगना में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत एक भी आदिवासी गांव को नहीं लिया गया। आप समझ सकते हैं कि पूरे झारखंड में क्या स्थिति बनी हुई है? काम की क्वालिटी की स्थिति भी ठीक नहीं है। महोदय, कोई मानीटरिंग नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि वर्तमान में आपने पूरे हिंदुस्तान में नए पावर प्लांट के लिए करोड़ों रुपए देने का काम किया है, लेकिन झारखंड के लिए मात्र 8.9 प्रतिशत ही फंड का एलोकेशन हुआ है।

महोदय, मेरा आग्रह है कि हमारे राज्य में कोयला है, पानी है, सब चीज है, लेकिन वर्तमान में वहां जो स्थिति है, उस पर आपकी अगर नजर नहीं जाएगी, तो झारखंड को नहीं बचाया जा सकता है और इस कारण वहां के लोगों में काफी आक्रोश है।

महोदय, कुछ विषय बाकी हैं, मैं उनको सदन के पटल पर रख रहा हूं।

*विद्युत मंत्रालय के अनुदान मांगों (सामान्य) 2009-10 पर चर्चा के लिए इस गरिमामय सदन में झारखंड एवं देश की ऊर्जा समस्या पर मा. ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज गांवों के करोड़ों लोगों को नियमित बिजली उपलब्ध नहीं होती।

सरकारी आंकड़े में देश में थर्मल पावर केन्द्रों में प्लांट लोड फैक्टर पीएलएफ पिछले वर्षों के तुलना में वृद्धि का आंकड़ा दिया जा रहा है। जबकि 2007-08 में पीएलएफ 78.6 से घटकर 77.2 समग्र हो गया। आश्चर्य है कि इसमें भूटान से आयतित बिजली को भी पीएलएफ में जोड़ दिया गया है। इस प्रकार 2008-09 के दौरान व्यस्ततम मांग मेगावाट एवं ऊर्जा जरूरत मिलियन यूनिट में क्रमशः 11.9 और 11.1 की कमी दर्ज की गई है। इससे भी दुःखद बात यह है कि कई राज्यों खासकर झारखंड एवं बिहार में राज्य विद्युत बोर्डों का पीएलएफ क्रमशः 27.2 प्रतिशत के लक्ष्य के तुलना में उपलब्ध 8.3 प्रतिशत है और लक्ष्य 12.7 प्रतिशत की तुलना में उपलब्धि 0.8 प्रतिशत है।

देश में जब एनडीए की सरकार थी यानि 1998 से 2004 तक ऊर्जा की कमी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रमशः 5.9 प्रतिशत 6.2 प्रतिशत 7.8 प्रतिशत 7.5 प्रतिशत 8.8 प्रतिशत 7.1 प्रतिशत एवं 7.3 प्रतिशत रहा है जबकि यूपीए सरकार में 2005-09 के दौरान ऊर्जा आवश्यकता की कमी का ग्राफ बढ़ा है। 2008-09 के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता 777039 मिलियन यूनिट थी जिसमें कमी 86001 मिलियन यूनिट है।

2007-08 में क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य 16335.2 मेगावाट रखा गया, उपलब्धि मात्र 9293 मेगावाट थी। देश में परमाणु अप्रसार संधि हुई। कहा गया कि इस संधि से बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे, परंतु 2008-09 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं राज्य क्षेत्र में न्यूक्लियर बिजली उत्पादन शून्य है केन्द्रीय क्षेत्र में थर्मल से बिजली उत्पादन के लक्ष्य 1750 के विपरीत उपलब्धि 750 मेगावाट है। इसी प्रकार केन्द्र एवं निजी क्षेत्र में हाइड्रो का उत्पादन शून्य है। इससे

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय]

साबित होता है कि राष्ट्रीय विद्युत नीति में 2012 तक सभी को विद्युत उपलब्ध कराने का लक्ष्य 1000 यूनिट प्रतिवर्ष एवं 11वीं योजना में 78,700 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि का प्रस्ताव विफल एवं भ्रामक साबित होगा।

देश में कोयला उत्पादन में से करीब 74 प्रतिशत कोयले का इस्तेमाल विद्युत क्षेत्र में होता है और विद्युत उत्पादन का 66 प्रतिशत उत्पादन कोयला चालित तापीय यूनिटों में होता है। आयातित कोयले पर निर्भरता 2008-09 में करीब 16.00 मिलियन टन हो गया है जबकि हमारे क्षेत्र के सीसीएल एवं बीसीसीएल की बंद खदानों को पुन: चालू कर दिया जाए तो हम कोयले की मांग को पूरा करने में कामयाब होंगे।

2008-09 के दौरान 13,085 मे.वा. क्षमता वाली 40 पन-बिजली परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके बाद 162 परियोजनाओं में से 77 स्कीमों हेतु 33,951 मे.वा. की डीपीआर तैयार की जा रही है।

डीवीसी-के अंतर्गत हमारे क्षेत्र में 1954 में कोणार बांध चालू किया गया था। एनएचपीसी ने 3 मे.वा. क्षमता की एक पारम्परिक इकाई हेतु अनुशंसा की। अब डीवीसी इस कार्य के लिए मौन है। डीवीसी की 10वीं, 11वीं योजना के अंतर्गत विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत क्षमता विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत बीटीपीएस 'ए' सीटीपीएस हमारे निर्वाचन क्षेत्र में है। इन विद्युत केन्द्रों में समय पर परियोजना का काम पूरा नहीं हो पा रहा है इसके अलावा विस्तार कार्य में कई त्रुटियां हैं।

राजीव गांधी ग्रा.वि. परि.-हमारे क्षेत्र में यह कार्य डीवीसी द्वारा हो रहा है, परन्तु कार्य की गुणवत्ता खराब है। योजना के अंतर्गत गांवों में सारे ट्रांसफार्मर एवं एल.टी. लाइन 3 फेज 25 केवीए का होना चाहिए इसके विपरीत 16 केवीए 1 फेज का ट्रांसफार्मर दिया जा रहा है जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। बीपीएल को 40 वाट का एक बल्ब जलाने का प्रावधान है वह पर्याप्त नहीं है।

झारखंड में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स दिया गया है इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। आग्रह करता हूं इस योजना का लाभ शीघ्र लोगों को मिले।

देश में 2003 में बने विद्युत अधिनियम में संशोधन कर विद्युत संशोधन अधिनियम, 2007 से लागू किया गया है। इसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लेख है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ संयुक्त प्रयास करेगी कि ग्रामीण विद्युत आधारभूत ढांचे के जरिए ग्रामों और बस्तियों सभी क्षेत्रों को बिजली सुलभ करवाएं और घरों का विद्युतीकरण हो। इसके लिए विद्युत सुधार तथा त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम एपीडीआरपी भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम की संचालन समिति में केन्द्र सरकारों के कई शीर्ष विभाग एवं चयनीत राज्य सरकार शामिल हैं। समिति ने 13 राज्यों के लिए 1947.70 करोड़ रुपये की लागत से 599 परियोजना के अनुमोदन प्राप्त किये हैं जिसमें से झारखंड में कुल 5 परियोजनाओं का चयन किया गया है। जिसकी लागत राशि 8.82 करोड़ है जबकि अन्य राज्यों को कई सौ करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाएं तैयार की गई हैं इससे साबित होता है कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया और एपीडीआरपी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल है।

अत: केन्द्र सरकार देश में ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने एवं झारखंड में विद्युत परियोजनाओं को सरजमीन पर लागू कराने के लिए ईमानदारी से पहले करे।*

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। मैं ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा जिनके कार्यकाल में देश में ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। मैं विशेष तौर से आपका ध्यान उत्तराखंड की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जहां बड़ी मेजर जलविद्युत परियोजना में परेशानी आ रही है।

महोदय, उत्तरकाशी एक पिछड़ा और सीमान्त जनपद है। वहां लोहारी-नागपाला हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्ष 2004 में शुरू किया गया। आज तक करीब 5-6 सौ करोड़ रुपए उस जल-विद्युत योजना पर खर्च हो चुके हैं, जो 600 करोड़ रुपए की योजना है, लेकिन चुनाव की वजह से गंगा पर विवाद उठाया गया और उस पर काम बंद करा दिया। अब यह मामला केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, उसने कहा कि 16 क्यूसेक पानी आप छोड़ सकते हैं और इस तरह से गंगा का बहाव बना रहेगा। पर्यावरण की सारी क्लियरेंसेज गवर्नमेंट आफ इंडिया से थी, मिनिस्ट्री ऑफ फारेस्ट्री की क्लियरेंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थी, इसलिए पूरे जनपद में बड़ा असंतोष हैं करीब डेढ़ हजार लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से इस परियोजना से जुड़े हुए हैं। यह सीमांत जनपद है, इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जल्दी से इस विवाद को खत्म कराने के संबंध में केंद्र सरकार निर्णय ले।

दूसरा मेजर पावर प्रोजेक्ट टिहरी में टी.एच.डी.सी. के द्वारा चल रहा है। महोदय, पूरा टिहरी का नगर, डूबा झील के अंदर। यह खेद की बात है कि वर्षों बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कंपन्सैशन के मामले तय नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने सारा पैसा रिहैबिलिटेशन के लिए राज्य सरकार को दे दिया है, लेकिन प्रदेश सरकार की बिल्कुल नाकामी है, जिससे आज तक लोग परेशान हैं, बाजारों की छांव में लोग रह रहे हैं, उनको कंपन्सैशन नहीं मिला, रिहैबिलिटेशन का कंपन्सैशन उन्हें नहीं मिला। केंद्र सरकार कहती है कि हमने प्रदेश सरकार को पैसा दे दिया।

सभापति जी, वहां जो झील बनी है, वह बहुत बड़ी है। उसकी लंबाई 40 किलोमीटर और गहराई हजार फीट है। उस झील की वजह से कई क्षेत्र जनपद से दूर हो गए हैं। वहां दो पुल बनने हैं, एक डोबराचाटी में और दूसरा चिन्यासीसौड़ में। केंद्र सरकार कहत है कि हमने पैसा राज्य सरकार को दे दिया और अब राज्य सरकार उसे बनाएगी, लेकिन राज्य सरकार कोई काम नहीं कर रही है। सारी जनता अस्त-व्यस्त और बहुत परेशान है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह मुख्य मंत्री को बुलायें और टिहरी के जो ये दोनों बड़े मेजर ब्रिजेज हैं, जिन पर विवाद फंसा है, उनको तत्काल सुलझाएं।

मेरा तीसरा अनुरोध, माननीय मंत्री जी से यह है कि वहां जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनमें स्टैगनेशन हो रहा है। यह आपका बहुत मेजर कारपोरेशन है, इसलिए जो सर्विस रूल्स हैं, उन्हें आप स्वयं देखें। वहां स्टैगनेशन नहीं होना चाहिए, प्रमोशन्स के एवेन्यूज रहने चाहिए, ताकि लोगों के प्रमोशन रुक न सकें।

मेरा अनुरोध है कि जो सोशल रिस्पौंसीबिलिटी फंड है, जो टीएचडीसी और एनटीपीसी हर पब्लिक सैक्टर खर्च करती है, उस सोशल रिस्पौंसीबिलिटी फंड की मॉनीटरिंग के लिए उस क्षेत्र के एमपी को जरूर होना चाहिए, उनकी राय जरूर होनी चाहिए ताकि उस पैसे का सही इस्तेमाल हो। उत्तराखंड सरकार को बिजली पैदा होने से 12 प्रतिशत रॉयल्टी मिलती है, लेकिन खेद की बात है कि प्रदेश सरकार जनपद के विकास या विस्थापितों के लिए उस 12 प्रतिशत रॉयल्टी में से एक पैसा भी खर्च नहीं करती। केन्द्र सरकार को नीति बनानी चाहिए कि जो राज्य सरकारें 12 प्रतिशत रॉयल्टी पा रही हैं, सैंट्रल प्रोजैक्ट्स में से उस रॉयल्टी का हिस्सा उन्हें उस क्षेत्र के विकास के लिए लगाना चाहिए जो रिहैबीलिटेशन से परेशान हैं या जहां सड़कों, नहरों, अस्पतालों, स्कूलों का विकास ठप्प हो जाता है। यह बहुत मेजर सवाल है। पूरा टिहरी उत्तरकाशी जनपद परेशान है। वह पर्वतीय क्षेत्र है।

आप पावर जनरेशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो लाइन लॉसेज ड्यू टू पिलफरेज है, जिस तरह से यह बढ़ रहा है, अगर आप इसे नहीं रोकेंगे तो आपका जो प्रयास है कि ऊर्जा का लक्ष्य पूरा करें, वह पूरा नहीं होगा। लाइन लासेज बढ़ रहे हैं।

मैं मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वे समय-समय पर सांसदों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते हैं।...*(व्यवधान)* यह बहुत जरूरी है कि प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री को बुलाकर आप इन समस्याओं का समाधान करें।

मैं इस अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला) : सभापति महोदय, बिजली के बारे में जो बात हो रही है, मैं भाषण करने के बजाए मंत्री जी से जाति तौर पर गुजारिश करूंगा कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर से हूं, जहां अल्लाह ने पानी की बोहतात दी है। हमारे पास 20 हजार मेगावाट पावर पैदा करने का पानी है, लेकिन उस पान को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमने बगलिहार का 900 मेगावाट का एक पावर हाउस बनाया, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उस पर दस बार अड़चन डाली क्योंकि हमारे देश और पाकिस्तान के दरम्यान जो वाटर ट्रीटी हुई है, उसमें भारत सरकार ने उस वक्त कश्मीर के दरिया उन्हें दिए और पंजाब के दरिया अपने लिए रख लिए। उसका नतीजा है कि हम वहां काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत मुश्किल होती है। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे पावर की बहुत कमी है लेकिन पावर की गुंजाइश इतनी ज्यादा है कि हम सारे नार्थ इंडिया को, सारे देश को पावर दे सकते हैं जिससे सारे देश को फायदा हो सकता है। हम इस वक्त अपने देश से ही 2000 करोड़ रुपये में पावर खरीद रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसकी कमी है। मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वे इस बात पर गौर करें और कश्मीर के बारे में एक पॉलिसी बनाएं, हमें पैसे दे दें जिससे पावर पैदा हो ताकि हमें भी आराम मिले और देश के बाकी हिस्सों को भी आराम मिले।

सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की रियासत का ज्यादा दारोमदार टूरिस्ट आमद-व-रफ्त पर है और वहां जबरदस्त टूरिज्म चल रहा है। वहां हम बिजली के बगैर टूरिज्म को भी फरोग नहीं दे सकते।

हमारे पास कोई कारखाना नहीं है। वहां बेरोजगारी है। इसलिए बिजली की जरूरत है ताकि वहां इंडस्ट्री हो और लोगों को थोड़ा रोजगार मिले। हमारे पास जो बड़े-बड़े सनतयाफ्ता और तालीम याफ्ता लोग हैं, उन्हें सरकार रोजगार नहीं दे सकती, चाहे कोई भी सरकार

[श्री शरीफुद्दीन शारिक]

हो। इसलिए जरूरी है कि वहां कारखाने खुलें, सनत आ जाए और उसके लिए सबसे पहले बिजली की जरूरत है। मैं भारत सरकार और अपने पावरफुल मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वे इसकी तरफ ध्यान दें और मनसूबे बनाकर, हमारे पास गुंजाइश है, उसका फायदा उठाएं ताकि हमें रोजगार मिले और पावर मिले।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि समय कम है, इसलिए आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि 14वीं लोक सभा में, पिछली यूपीए सरकार को न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर लोक सभा में विजय हासिल करने के बाद 15वीं लोक सभा में जिस दृढ़ता का मैसेज मिला है, वह निश्चित रूप से इसलिए मिला है कि इन्होंने राष्ट्रीय विद्युत नीति बनाई थी जिसमें सन् 2012 तक प्रति व्यक्ति एक हजार यूनिट की परिकल्पना थी कि हम पूरे हिन्दुस्तान में हर हिन्दुस्तानी को विद्युत के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे।

संभवत: न्यूक्लियर डील के बाद अब न्यूक्लियर बिजली पर पूरे हिन्दुस्तान की निगाह है कि कब हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे। मैं अपने कुछ वाक्यों के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की समयबद्धता, गुणवत्ता तथा राज्य सरकारों में विसंगतियों के कारण आ रही अड़चनों से, सतर्कता कमेटियों के माध्यम से उस पर केन्द्र की मजबूत पकड़ होनी चाहिए, ताकि समय से कार्य पूरा हो सके और उसका लाभ आम जनता को मिल सके।

दूसरा, अभी सदन में छोटे-छोटे हाइड्रो प्रौजेक्ट्स की बात आई है। शिवालिक बैल्ट और नेपाल राष्ट्र से लगी हुई सीमा पर कोसी, राप्ती, घाघरा आदि तमाम ऐसे पहाड़ी नाले हैं, जो वहां से निकलकर हमारे हिन्दुस्तान में जल-पलवन कर बाढ़ की स्थिति से तबाही मचाते हैं। उन पर छोटे-छोटे बांध बनाकर 10, 15 और 25 मेगावाट के प्रौजेक्ट्स लगाये जा सकते हैं। इस तरफ भी ध्यान देकर हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं। इसी तरह सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सीडीएम टेक्नोलॉजी के तहत कार्बन क्रेडिट के माध्यम से विदेशी मुद्रा हम अपने देश में ला सकते हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में तमाम ऐसी गुंजाइशें हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी एनर्जी के लॉस को बचा सकते हैं और कार्बन क्रेडिट का लाभ इस देश को प्रदान कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा, मुझे भाषण देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार के एक पत्र की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, जो केन्द्र सरकार पर थोपा गया मिथ्या आरोप है। इस पत्र में मिथ्या जानकारी दी गई हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मांग ओर सप्लाई में एक हजार से लेकर तीन हजार रुपये तक का डेफीसिट है। उत्तर प्रदेश में केन्द्र के अलावा जो ऊर्जा दी जाती है, उसका दुरुपयोग किया जाता है। हमारी मांग है कि उस तरफ भी ध्यान दिया जाये, जिससे ऊर्जा आम जनता तक पहुंचे, सही जगह पहुंचे, यह आप सुनिश्चित करें। इसके साथ ही इस पत्र में दादरी प्रौजेक्ट का कहीं कोई नाम नहीं है। रिलायंस पावर प्रौजेक्ट के रूप में वहां ढाई हजार एकड़ फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड लेने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था। वर्ष 2005 में वह जमीन ली गई थी। उस एग्रीमेंट के तहत यदि उस जमीन पर तीन साल तक कार्य न हो, तो यूपी गवर्नमैंट द्वारा उस जमीन को अधिग्रहीत करके एनटीपीसी या अन्य माध्यम से कार्य करना चाहिए, लेकिन वहां अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई, शिलान्यास भी नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से, सर्वोच्च सदन के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि वहां किसानों की फर्टाइल जमीन भी ले ली गई, लेकिन वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2009 तक उस पर कोई कार्य भी नहीं हुआ। उस समय तत्कालीन सरकार द्वारा आत्मनिर्भरता का जो सपना दिखाया गया था, वह मिथ्या साबित हो रहा है। हमारी मांग है कि उस पर कार्रवाई करते हुए किसानों को कम से कम आप वह जमीन वापस दिला दें।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : वहां गैस ही नहीं दी गई। जब गैस ही नहीं देंगे, तब काम कैसे चालू हो जाएगा?

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : गैस देंगे, आप जाइये।...*(व्यवधान)* राष्ट्रीय नीतियों के तहत गैस मिलेगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डॉ. विनय कुमार पाण्डेय के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : उसकी प्रापर्टी यही है कि गैस राष्ट्रीय निधि है...*(व्यवधान)* वह सरकार की नीतियों के तहत आपको मिलेगी।

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज) : सभापति महोदय, हम सभी लोग जानते हैं कि बिजली की मांग और आपूर्ति में अन्तर है, लेकिन हम जो बिजली पैदा कर रहे हैं, उसका भी सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें 35 प्रतिशत की क्षति होती है, जबकि यूरोप में यह क्षति 5 प्रतिशत और पाकिस्तान जैसे देश में 20 प्रतिशत ही है। इसे हम रोक सकते हैं। हमारे यहां लगभग 25,000 करोड़ रुपए की बिजली चोरी होती है, इसे भी रोका जा सकता है। अगले पांच-दस साल बाद हमें सात-आठ लाख मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी। हमारी परमाणु विद्युत की जो क्षमता है, 30,000 मेगावाट उससे भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे गैर-परम्परागत ऊर्जा के स्रोत हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय और गैर-परम्परागत ऊर्जा मंत्रालय को मिलकर एक बृहद योजना बनानी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। जब बिजली की बात होती है तो हम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की तरफ देखते हैं और जब सड़क की बात आती है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ओर देखते हैं। हमारे पास जनता को संतुष्ट करने के लिए इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई, मैं मंत्री जी से मिलकर एक विस्तृत कंप्लेंट दूंगा, विशेषकर बलरामपुर, बहराइज सहित चार-पांच जिलों में खंभे नहीं गड़े हैं, तार खींचे नहीं गए हैं, ट्रांसफार्मर लगे नहीं हैं, उसके बाद भी वहां काम अधूरा है। इसकी जांच कराने की जरूरत है क्योंकि हमें इन दोनों योजनाओं से बड़ी उम्मीद है। इसमें घोर अनियमितता हुई, मैं समय आने पर, इस सत्र के बाद जल्द ही इसकी एक विस्तृत कंप्लेंट दूंगा, लेकिन यह जरूर चाहूंगा कि जब उसकी जांच के लिए कोई कमेटी वहां जाए, तो हम लोगों को भी विश्वास में लिया जाए, जिसके संसदीय क्षेत्र में कमेटी जाए, वहां के सांसद को उसमें लिया जाए, तब हम आपको दिखाएंगे कि इस योजना की असलियत क्या है।

मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की जो हालत है, वहां का जो विद्युत बोर्ड है, वहां का जो विद्युत विभाग है, उसके पास लाइनमैन तक नहीं हैं कि वे लाइन को ठीक कर सकें गांव के लोगों ने, कस्बे के लोगों ने निजी लाइनमैन रखकर लाइन ठीक कराने का काम शुरू किया है, जिसका नतीजा यह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक वर्ष के अंदर तीन लोग मर चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर विद्युत का सामान चोरी हो जाए, तार या ट्रांसफार्मर चोरी हो जाए, तो विद्युत विभाग तब तक उस पर काम नहीं करवाता है जब तक थाने में उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है और उत्तर प्रदेश सरकार अपराध का आंकड़ा कम करने के लिए विद्युत चोरी की एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। इस बात से उत्तर प्रदेश के सारे सांसद सहमत होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इन छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान दिया जाए। आपका जो सपना है कि वर्ष 2012 तक सभी को बिजली देने का, वह पूरा हो, गुणवत्ता कायम रहे, इन्हीं बातों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं अपना बाकी भाषण सदन के पटल पर रखता हूं।

*हम सभी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि किसी क्षेत्र या देश के विकास में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के 62 वर्षों बाद भी हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं। आज पूरा देश बिजली संकट से जूझ रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की है। बिजली संकट का सबसे बड़ा कारण मांग की अपेक्षा उत्पादन का कम होना है। विद्युत उत्पादन पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना हमारी सरकारों ने नहीं दिया। साथ ही सरकार द्वारा किये गये पूंजी निवेश का उपयोग जनता के हित में ठीक से नहीं किया गया। हमारे अधिकांश विद्युत उत्पादन संयंत्र पुराने और जर्जर हालत में हैं जिससे वे अपनी क्षमता से कम बिजली पैदा कर रहे हैं। नये संयंत्रों की स्थापना पर जितना जोर दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। देश में जो बिजली पैदा हो रही है उसका भी ठीक ढंग से सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके दो प्रमुख कारण हैं।

1. पारेषण हानि:- वर्ष 2008-09 की जो आर्थिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत की गयी है उसमें सरकार ने खुद माना है कि देश में 30 प्रतिशत से अधिक विद्युत हानि हो रही है। वास्तविकता यह है कि भारत में 35 फीसदी ज्यादा पारेषण हानि होती है जबकि आस्ट्रेलिया में 5 प्रतिशत तथा यूरोप के अधिकांश देशों में यह हानि केवल 10 से 15 प्रतिशत होती है। यहां तक कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी 20 से 25 फीसदी पारेषण हानि होती है। पारेषण

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री बृजभूषण शरण सिंह]

हानि का प्रमुख कारण पुराने तथा जर्जर विद्युत तारों और खंभों का होना एवं उनके रख-रखाव की कमी है।

2. बिजली की चोरी:- हमारे देश में हर साल लगभग 25 हजार करोड़ रुपये की बिजली चोरी होती है जिसमें विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत होती है। यदि सरकार पारेषण हानि और बिजली चोरी पर अंकुश लगा दे तो कुछ हद तक विद्युत संकट से निजात मिल जायेगा।

महोदय, यदि ऊर्जा क्षेत्र को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया तो आने वाले समय में देश को गंभीर विद्युत संकट का सामना करना पड़ेगा। ऐसा आकलन किया गया है कि वर्ष 2030 तक देश में लगभग 7 लाख मेगावाट से 8 लाख मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी। वर्ष 2030 के दौरान जल विद्युत अंशदान 1 लाख मेगावाट से अधिक नहीं हो सकता। देश में अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की उपलब्धता भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। धीरे-धीरे कोयले के आयात पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। वर्ष 2030 में परमाणु विद्युत 30 हजार मेगावाट से अधिक नहीं प्राप्त हो सकेगा। ऐसी स्थिति में जब तक नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास आधारित बिजली के बड़े पैमाने पर दोहन करने को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता तब तक विद्युत संकट का समाधान संभव नहीं होगा। भारत की सौर, पवन, बायोमास और जल ऊर्जा क्षमता सम्मिलित रूप से 6 लाख मेगावाट से अधिक है। पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों साधनों से एकीकृत विद्युत सृजन की धारणा को दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। सरकार चाहे तो विद्युत मंत्रालय और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को सम्मिलित करते हुए एक स्पष्ट ऊर्जा नीति बना सकती है।

महोदय, केन्द्र सरकार के अनेक लक्ष्यों में से एक लक्ष्य वर्ष 2010 तक देश के सभी घरों को विद्युत उपलब्ध कराना है लेकिन जिस रफ्तार से इस दिशा में काम चल रहा है हम अगले पांच वर्षों में भी इस लक्ष्य को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। इसका बहुत जोर-शोर से प्रचार किया जाता है लेकिन हकीकत कुछ और ही बयान करती हैं। एक तो इस योजना कार्य बहुत धीमा है तथा दूसरे भारी भ्रष्टाचार के चलते मानको की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। माननीय विद्युत मंत्री ने 19 दिसम्बर, 2008 को इसी सदन को सूचना दी थी कि 2005-06 से 2008-09 तक इस योजना के तहत 69 हजार गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया हैं इसके विपरीत वर्ष 2008-09 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि अभी तक 59 हजार 882 गांवों में बिजली पहुंचा कर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 53.78 परिवारों को 31 मार्च, 2009 तक कनेक्शन दे दिय गये हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की 235 चालू परियोजनायें 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निष्पादित की जानी है। इससे साफ जाहिर है कि इस योजना का कार्य धीमी गति से चल रहा है।

इस योजना के अंतर्गत जिन गांवों का विद्युतीकरण पूरा होना दिखाया गया है उनमें अधिकांश गांवों में यह कार्य अधूरा है। कुछ गांवों में बिजली के खंभे गाड़ दिये गये हैं लेकिन तार नहीं लगा है और जहां तार भी लगा दिये गये हैं वहां विद्युत प्रवाह ही नहीं है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में अभी प्रथम चरण का ही कार्य अधूरा पड़ा है क्योंकि राज्य के दो जनपदों को छोड़कर शेष जिलों में अभी तक दूसरी किश्त का पैसा ही नहीं भेजा गया जबकि माननीय विद्युत मंत्री कई बार सदन में आश्वासन दे चुके हैं। जहां तक मानकों का सवाल है, उसकी पूरी तरह अनदेखी की गई है। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने भारी कमीशन लेकर बड़े ठेकेदारों को काम करने का ठेका दे दिया जिन्होंने कम दर पर छोटे ठेकेदारों (पेटी कान्ट्रैक्टर) को फुटकर में वही काम सौंप दिया। इसका नतीजा यह निकला है कि बिजली के खंभों को गाड़ने के लिए निर्धारित मानक के अनुसार गड्ढे नहीं खोदे गये तथा खराब मसालों (ग्राडटिंग) का प्रयोग किया गया। कई जगहों पर सीमेंट और गिट्टी की जगह मिट्टी तथा ईंट के टुकड़ों से ही गड्ढों को भराई कर दी गई। इसके चलते लाइन चालू होने के पहले ही अनेक खंभे गिर गये फिर भी अधिकारियों ने उसे ठीक कराने की जगह पावों को हैंड ओवर कर दिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा, बलरामपुर तथा बहराइच आदि जनपदों में ग्राउटिंग की गड़बड़ी से सैंकड़ों खम्भे या तो गिरे पड़े हैं अथवा झुक गए हैं। इसी तरह घटिया किस्म के ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं जो आये दिन जल जाते हैं। 11 हजार के.वी.ए. की लाइन से जनहानि न हो, इसके लिए स्टे इंसुलेटर लगाना अनिवार्य है परंतु अधिकांश गांवों में इंसुलेटर नहीं लगाया गया है जिससे जन-धन के नुकसान का खतरा बना हुआ है।

अंत में, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कारगर और ईमानदार कोशिश करे, पारेषण हानि तथा बिजली चोरी रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करे, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की गति को तेज कराते हुए पहले चरण के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करावे, निर्धारित मानकों का उल्लंघन

करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करे तथा इस योजना में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करे।

इन शब्दों के साथ मैं विद्युत मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि एक भारतीय होने के नाते हमें इस बात का गर्व है कि विद्युत मंत्रालय के क्षेत्र में, चाहे थर्मल हो, हाइड्रो, न्युक्लियर या रिन्युएबल सोर्सेज, सभी को मिलाकर दुनिया में बिजली उत्पादन के मामले में हम पांचवें स्थान पर हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हमारा देश 6.6 मिलियन सर्किट किलोमीटर के साथ ट्रांसमीशन और वितरण की दृष्टि से दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। लेकिन फिर भी हमारे देश में बिजली की मांग है और हमारी मांग तथा सप्लाई में काफी बड़ा अंतर है। इस संदर्भ में देखा जाए तो हम काफी पीछे हैं। हमारे देश में बिजली की उत्पादन क्षमता लगभग 1,48,000 मेगावाट है। जैसा कि आपने बताया है कि सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में 78,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रहा है। मैं नहीं समझता कि आप कैसे इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का यह तीसरा साल चल रहा है और हम अभी तक मात्र 12,000 मेगावाट तक ही पहुंच पाए हैं यानि प्रतिवर्ष 6000 मेगावाट। यदि इस दर को मान लिया जाए तो हम इस पंचवर्षीय योजना में मुश्किल से 30,000 मेगावाट का ही बिजली उत्पादन कर पाएंगे और अपने लक्ष्य से काफी पीछे रहेंगे। इसलिए मैं विद्युत मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह बताएं कि कैसे आप निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे?

हम बिजली उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया में पांचवें स्थान पर जरूर हैं और ट्रांसमिशन तथा वितरण में इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से हमें तीसरा स्थाल भले ही हासिल हो, फिर भी हमारे यहां केवल 631 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। इस हिसाब से हम चीन से काफी पीछे हैं और दुनिया के विकसित देशों से तो हम 18 से 20 गुना पीछे हैं। इस संबंध में मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि किसी भी विकसित समाज में ठीक बात है कि बिजली की खपत ज्यादा होती है।

हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। बिना बिजली के न तो किसान का काम चलेगा, न मजदूर का काम चलेगा और न ही उद्योग चल सकते हैं। सभापति जी, अगर बिजली न रहे तो हमारी बात भी आप तक और मंत्री जी तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए बिजली आज के जमाने में आराम की चीज न होकर एक जरूरत हो गई है इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजली में जो नुकसान हम झेल रहे हैं, उसके आंकड़ों के हिसाब से ट्रांसमिशन और वितरण में 27 प्रतिशत का हमें लॉस है। इसी तरह सात प्रतिशत कलेक्शन लॉस होता है। इन दोनों को मिला दिया जाए और साथ ही व्यावसायिक नुकसान को भी जोड़ दिया जाए, तो हम तक पहुंचने वाली बिजली के लिए अतिरिक्त डेढ़ यूनिट का उत्पादन व्यय आता है। सिर्फ इसी सेक्टर में होने वाला नुकसान हमारी जीडीपी का लगभग चार प्रतिशत है। यह बहुत बड़ा गैप है। कंसोलिडेटिड फिस्कल डेफिसिट को मूल रूप से राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार की पावर आउटेज और वेस्टेज से वर्ष 2008-2009 में सरकार को पिछले वर्ष 44,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि हम इस लॉस को तो कम कर सकते हैं, उसके लिए क्या उपाय हमारे मंत्री जी ने सोचा है, वह इस बात का खुलासा अपने जवाब में करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

सभापति जी, मैं बिहार राज्य से चुनकर आया हूं इसलिए एक-दो मिनट में वहां की बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। वहां बिजली की स्थिति बहुत खराब है, वैसे तो पूरे देश में ही बिजली की कमी है, लेकिन बिहार में ज्यादा कमी है। हम यह चाहते हैं कि केन्द्र हमें इस संदर्भ में विशेष सहयोग दे, मजबूती प्रदान करे। बिहार में 1320 मेगावाट के चार थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाने का प्रपोजल है। जिसको कोल-लिंकेज के लिए, वहां की सरकार ने, बीएसीबी ने, 26.7.2006 एवं 3.9.2008 तारीख को प्रोसेसिंग फीस जमा कर दी है। पिरपेंटी 1320 मेगावाट, चौसा 1320 मेगावाट, लखीसराय 1320 मेगावाट और नबीनगर 1980 मेगावाट के लिए कोल-लिंकेजिज अभी तक अवेटेड है जबकि प्रोसेसिंग फीस जमा है। इसी तरह से नबीनगर में रेल और ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त उपक्रम के तहत 1 हजार मेगावाट का संयंत्र लगाने की स्वीकृति प्राप्त है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 अप्रैल, 2004 को बिहार के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आपको एनओसी दी और उसके चार वर्ष के बाद कैबिनेट की स्वीकृति मिली, कैबिनेट की एप्रूवल मिली। जो काम एक दिन का था, कैबिनेट में ले जाना था, उसको करने में चार साल लगे, तो मैं कैसे समझूं कि भारत सरकार बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बहुत गंभीर है और बिजली उत्पादन के मामले में देश को आत्म-निर्भर करना चाहती है।

[श्री सुशील कुमार सिंह]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की चर्चा सभी माननीय सदस्यों ने की है। हम कहना चाहते हैं कि जब किसी गांव का आप विद्युतीकरण करें, वहां बिजली पहुंचाएं तो उसमें कोई कास्टवाइज फैक्टर नहीं होना चाहिए। उसमें एपीएल, बीपीएल को कोई सवाल नहीं होना चाहिए। पूरे गांव में जो भी व्यक्ति बिजली का कनैक्शन लेना चाहे, उसे बिजली दी जानी चाहिए और तीन-फेस की बिजली दी जानी चाहिए। केवल बल्ब जलाने के लिए ही बिजली नहीं दी जानी चाहिए। वह सिंचाई का काम न कर सके, मोटर न चला सके।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप पहले ही सात मिनट का समय ले चुके हैं। अभी आपकी पार्टी से एक और सदस्य को बोलना है। कृपया समाप्त करें अन्यथा, मैं उन्हें बोलने का अवसर नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह : सर, मुझे एक मिनट का समय और दिया जए। बिहार में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का दूसरा चरण भी स्वीकृति के लिए लम्बित है। मैं चाहूंगा कि इस चरण की भी स्वीकृति दी जाए। एक बार और कहना चाहूंगा कि जो डीपीआर बना है, उसमें पहले मात्र दस घर को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य था और उसी के आधार पर डीपीआर बना है, उन दस घरों को विद्युतीकरण करके हम मान लेते हैं कि पूरे गांव को हमने बिजली दे दी। इसमें संशोधन करना चाहिए और जहां भी हम बिजली पहुंचाएं वहां पूरे गांव को बिजली दें।...*(व्यवधान)*

श्री सज्जन वर्मा (देवास) : सभापति महोदय, इतनी उदारता हम लोगों के साथ भी करना।

श्री सुशील कुमार सिंह : उसमें भी एक गलत एग्रीमेंट है, वह यह है कि बिहार को जहां से बिजली एलोकेटेड है, तलचर, फरक्का, कहलगांव, ताला और रंगेय और उनके यूनिट फिक्स हैं कि यूनिट नम्बर एक से बिहार को बिजली मिलेगी या दो से मिलेगी या तीन से मिलेगी। जब वे यूनिट मेंटेनेंस में जाता है, रिपेयर होता है तो बंद कर दिया जाता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री सज्जन वर्मा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सज्जन वर्मा के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं और इन्हें रिकॉर्डेड मान लिया जाएगा। यदि आप इस तरह बोलते रहे तो मैं सभा को कैसे चलाऊंगा। अब, आप आठ मिनट का समय ले चुके हैं।

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह : मैं अपना शेष भाषण सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

*महोदय, मैं विद्युत मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए इस सदन में उपस्थित हुआ हूं।

भारतीय होने के नाते हमें यह जानकर गर्व महसूस होता है कि हमारा देश विद्युत उत्पादन के भिन्न माध्यमों थर्मल, न्यूक्लियर तथा रिन्युएबल सोर्सेज को मिलाकर दुनिया के देशों में पांचवे स्थान पर है। हमें इस बात का भी गर्व है कि हमारा देश 6.6 मिलियन सर्किट किलोमीटर के साथ ट्रांसमिशन तथा वितरण की दृष्टि से दुनिया का तीसरा बड़ा देश है।

यद्यपि हम उत्पादन क्षमता के हिसाब से दुनिया में पांचवे तथा ट्रांसमिशन एवं वितरण की इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर हैं फिर भी 631 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष की खपत के हिसाब से चीन जैसे देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत से आधी से भी कम है। आज भी हमारे लगभग 20 प्रतिशत गांवों तक न सिर्फ बिजली नहीं पहुंच पाई है वरण 30 से 40 करोड़ देशवासी आज भी विद्युत आपूर्ति की सुविधा से महरूम हैं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

अगर हम विकसित देशों में अपने देश में विद्युत आपूर्ति की तुलना करें तो हम पायेंगे कि विकसित देशों में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 1000 यूनिट प्रतिवर्ष अथवा 12000 यूनिट प्रतिवर्ष है जो हमारे देश में 631 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष खपत से कई गुणा अधिक है तथा प्रति व्यक्ति खपत का सालाना अंतर लगभग 11300 यूनिट है अथवा यूं कहें कि विकसित देशों में हमारी प्रति व्यक्ति खपत से लगभग 15 से 18 गुना ज्यादा है।

हम जानते हैं कि तकनीकी रूप से विकसित सभी समाजों/देशों में प्रति व्यक्ति आय तथा ऊर्जा की खपत के बीच एक मजबूत गठबंध है। यानि ज्यादातर ऊर्जा की खपत, प्रति व्यक्ति आय अधिक होने का भी द्योतक है। अधिक ऊर्जा का उत्पादन विकास का द्योतक है। बिना ऊर्जा उत्पादन के विकास की प्रक्रिया बाधित होती है तथा हम विकसित देशों की तुलना में काफी पीछे छूट जाते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण है।

मैं महसूस करता हूं कि ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में रिफार्म की काफी आवश्यकता है और यह हमारे देश के अर्थतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। आज हमारे देश में करीब डेढ़ लाख मेगावाट का उत्पादन है। ऐसे में औसतन पॉवर कटौती 9-10 प्रतिशत तथा पीक ऑवर में यह 15-20 प्रतिशत रहती है। आंकड़े बताते हैं कि ट्रांसमिशन एवं वितरण में 27 प्रतिशत का नुकसान तथा इसी प्रकार 7 प्रतिशत का कलैक्शन नुकसान होता है। इस प्रकार से अगर ट्रांसमिशन तथा वितरण एवं व्यवसायिक नुकसान को एक साथ मिला दिया जाये तो हम तक पहुंचने वाली प्रति यूनिट बिजली के लिये अतिरिक्त डेढ़ यूनिट बिजली के लिए अतिरिक्त डेढ़ यूनिट का उत्पादन व्यय आता है। सिर्फ इसी सेक्टर में होने वाला नुकसान लगभग हमारी जीडीपी का चार प्रतिशत है।

यह नुकसान कंसेलिडेटेड फिस्कल डेफिसिट मानकर मूल रूप से राज्य द्वारा वहन किया जाता है और इस प्रकार की पॉवर आऊटेज/वेस्टेज के कारण मात्र वर्ष 2008-09 में ही सरकार को 44000 करोड़ का नुकसान हुआ।

सरकार ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को दुरूस्त करने के लिए कोई कदम उठा रही है या नहीं, पता नहीं। इसी प्रकार कलैक्शन लॉसेज को कैसे कम किया जाये, इस पर भी शीघ्र कुछ करना होगा। 2011-12 में समाप्त होने वाली ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने उत्पादन क्षमता में 78 हजार मेगावाट और बढ़ाने का प्रस्ताव है और 2012-2017 में 12वीं योजना में इसे एक लाख से एक लाख दस हजार मेगावाट तक उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। किंतु, 2007-08 तथा 2008-09 में कुल मिलाकर 12000 मेगावाट उत्पादन हुआ है। इस प्रकार हम ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य से काफी पीछे चल रहे हैं। समझ में नहीं आता कि सरकार लक्ष्य उत्पादन में 66000 मेगावाट की उत्पादन लक्ष्य आगामी दो वर्षों में कैसे प्राप्त करेंगी।

हम जानते हैं कि हमारे देश में कुल उत्पादन का लगभग 54 प्रतिशत थर्मल, करीब 25 प्रतिशत हाइड्रल, करीब 10 प्रतिशत गैस आधारित, करीब 40 प्रतिशत न्यूक्लियर एनर्जी और 8 प्रतिशत रिन्यूएबुल सोर्सेज से आता है लेकिन हम अभी भी अपनी उत्पादन क्षमता तथा आवश्यकता पूर्ति में काफी पीछे हैं। इसका कारण शायद यह भी है कि हम विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति के अन्यान्य स्रोतों पर ध्यान नहीं दे रहे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जियो थर्मल प्रोसेस (जमीन के अंदर उपलब्ध गैस भंडार) से विद्युत उत्पादन की तकनीक पर ध्यान देना चाहिये। इससे हम अरबों डालर के विदेशी विनिमय की बचत कर पायेंगे क्योंकि अपने थर्मल प्लांट्स हमें चलाने के लिए आस्ट्रेलिया इंडोनेशिया एवं मोजाम्बिक जैसे देशों से कोयला आयात पर व्यय नहीं करना होगा। मैं ऐसा कह रहा हूं, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मैं कोयले पर आधारित थर्मल पॉवर प्लांट्स के खिलाफ हूं लेकिन मेरा मतलब यह है कि हमें जियो थर्मल जैसे ऊर्जा उत्पादन के तमाम उपलब्ध घरेलू स्रोतों की खोज करने की आवश्यकता है।

ऊर्जा क्षेत्र में बिहार के साथ भेदभाव। बिहार में प्रस्तावित थर्मल पॉवर इकाई जो कोल लिंकेज के इंतजार में है।

पीर पैंती - 1320 मेगावाट, कोल लिंकेज के लिए 27.6.06 को 5 लाख रुपये प्रोसेसिंग फीस जमा है।

चौसा - 1320 मेगावाट, 3.09.08 को 5 लाख जमा किया गया।

लक्खीसराय - 1320 मेगावाट, 3.09.08 को 5 लाख जमा किया गया।

क. नवीनगर - 1980 मेगावाट, 5 लाख जमा लिंकेज नहीं मिला।

ख. नवीनगर में रेल और ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त उपक्रम के तहत 1000 मेगावाट का संयंत्र लगाने की स्वीकृति प्राप्त

[श्री सुशील कुमार सिंह]

है लेकिन असैनिक कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। 58 मेगावाट -42 मेगावाट, राज्य का हिस्सा 100 मेगावाट के बदले 58 मेगावाट। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 16.04.04 को एन ओ सी मिला, लेकिन लगभग चार वर्षों के बाद केन्द्रीय मंत्री परिषद से इसकी स्वीकृति मिली जो खेद का विषय है और ऊर्जा क्षेत्र में भारत सरकार की चिंता दर्शाती है।

इसके अतिरिक्त बीएसईबी की मुजफ्फरपुर एवं बरौनी विद्युत उत्पादन इकाइयों के आर एन एम के लिए 1045.9 करोड़ की आवश्यकता है जिसके विरुद्ध राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत 506.02 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 539 करोड़ रुपये और चाहिए जिसका प्रस्ताव भारत सरकार के योजना आयोग में लंबित है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार की दर्जनों पन बिजली परियोजनाओं का प्रस्ताव होने के बावजूद एक भी परियोजना की स्वीकृति बिहार में नहीं मिली।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना:-

1. एपीएल - बीपीएल - गांव-गांव में संघर्ष।
2. सिंगल फेज - थ्री फेज - कृषि एवं कुटीर उद्योग
3. द्वितीय चरण की स्वीकृति।
4. बिना विद्युतीकरण किए बोर्ड लगा दिया गया।
5. डी पी आर पेंडिंग।

केन्द्रीय पूल से बिहार को आबंटित बिजली 1580 मेगावाट है परंतु उपलब्धता मात्र 900 से 950 मेगावाट है। एम टी पी सी का बकाया नहीं जबकि पहले करोड़ों में बकाया था। त्रुटिपूर्ण इकरारनामा- तलचर, फरक्का कहलगांव ताला रंगित, परमाणु करार - थोरियम।*

श्री सज्जन वर्मा : माननीय सभापति महोदय, मुझे यूपीए की सरकार पर गर्व है, जिस सरकार ने सुशीलकुमार शिंदे जिसे बहुत ही कुशल प्रबंधक को देश के ऊर्जा विभाग को सौंपा। पिछली यूपीए सरकार में भी वे ऊर्जा मंत्री थे और इस सरकार में भी वे बड़ी दमदारी के साथ काम कर हैं। माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया गया कि जो परमाणु डील, हमारे देश ने अमरीका के साथ की, उसके कारण, हर वर्ष 13000 मेगावाट बिजली हम अपने देश में उत्पादित करेंगे। निश्चित रूप से पांच वर्षों में 70 हजार मेगावाट बिजली बनेगी, तो देश का किसान खुशहाल होगा और देश के उद्योगपति भी देश के विकास में अपना सहयोग दे सकेंगे। मैं आपको माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि वहां इतनी संभावनाएं हैं कि 60 हजार मेगावाट बिजली बन सकती है। हमें इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे देश में गैस के बड़े भंडार मिल रहे हैं। हम उन्हें क्यों प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं? हम क्यों नहीं उस गैस से बिजली बनाते हैं? मैं अपने प्रदेश की बात भी आपसे कहना चाहता हूं। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना इस देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यह योजना, उन राज्यों में, जहां यूपीए की सरकार नहीं है, वहां सही ढंग से लागू नहीं हो रही है। मैं अपने राज्य मध्य प्रदेश की बात आपसे कहना चाहता हूं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बहुत कमजोर स्थिति में है, क्योंकि यह योजना केंद्र सरकार की बनाई हुई है। अभी हमारे साथी ने कहा कि दो साल से उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में यह योजना चल रही है, लेकिन आज तक इस योजना का दस प्रतिशत काम भी नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आप हर प्रदेश में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएं। मैं जहां से लोक सभा का चुनाव लड़ता हूं देवास और साझापुर डिस्ट्रिक्ट यह राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित नहीं है। आप इन क्षेत्रों को इस योजना के तहत सम्मिलित करने की कृपा करें।

मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे प्रदेश में 80 हजार किसानों को, जो देश के अन्नदाता कहलाते हैं, प्रदेश की सरकार ने आपराधिक मुकदमे बना कर जेल भेजने की साजिश की। उन्हें विद्युत चोर कहा, मैं सदन में कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो ऊर्जा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा करने का हक भी नहीं है, जो इस देश के अन्नदाता को जेल में भेजने का षडयंत्र रचते हैं। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा हमारे पंजाब के साथी ने कहा कि बिजली बोर्डों को भंग कर देना चाहिए। हर प्रदेश में नियामक आयोग बने हैं। नियामक आयोग क्या सही काम कर रहे हैं, क्या प्रदेश सरकार पर नकेल लगा रहे हैं? इस बात की निश्चित रूप से मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, मुझे पता नहीं है कि यह अधिकार है या नहीं, लेकिन नियामक आयोग

प्रदेश के अंदर सिर्फ बिजली की दरें बढ़ाने का काम करते हैं। यह नहीं देखते हैं कि वह प्रदेश वास्तव में उन किसानों को, उद्योगपतियों को सही मात्रा में बिजली दे रहा है या नहीं। जब चाहते हैं साल भर में नियामक आयोग रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन कभी प्रदेश सरकारों पर दबाव नहीं बनाते हैं कि आप सही रूप से लोगों की बिजली दीजिए, अधिक बिजली दीजिए। मेरा निवेदन माननीय मंत्री जी से है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की सही ढंग से हर राज्य में मॉनिटरिंग कराएं। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बस्तियों के लिए है, जहां करीब लोग रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार वहां ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। यदि आप हम जैसे लोगों को मॉनिटरिंग कमेटी में रखेंगे, तो ऐसी सरकारों पर हम नकेल लगाएंगे।

[अनुवाद]

***श्री सी.एल. रुआला** (मिजोरम) : सभापति महोदय, हम कम्प्यूटर युग में रह रहे हैं। हमारे सारे कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से चल रहे हैं। जब तक विद्युत की आपूर्ति न हो हमारा कम्प्यूटर काम नहीं कर सकता। इस लिए विकास संबंधी कार्य शीघ्रता से करने के लिए बिजली अनिवार्य है। महोदय, आपका कार्यालय बिजली के बिना काम नहीं कर सकता। आपको यह देखना है कि आपके कार्यालय को लगातार विद्युत आपूर्ति होती रहे।

महोदय, मेरा चुनाव क्षेत्र, मिजोरम, देश में विद्युत की कमी वाला राज्य है। हमारे यहां बहुत सारी नदियां हैं, जिनसे हम सैकड़ों मेगावाट विद्युत का उत्पदन कर सकते हैं। लेकिन, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें अभी भी पूर्वोत्तर ग्रिड की विद्युत उपलब्धता पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे पूरे साल बिजली नहीं मिल पाती। यह बहुत हद तक मौसमी है।उत्पादन केन्द्रों में कम विद्युत उत्पादन के परिणामस्वरूप कम मांग के समय में हमारे जरूरत की केवल एक तिहाई की ही आपूर्ति की गई।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री को यह संदेश देना चाहता हूं कि 210 मेगावाट क्षमता की तुआईवाई पनबिजली परियोजना 2006 में आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित थी। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने परियोजना की बी.जी.एफ. की प्राप्ति के लिए फरवरी, 2007 में डी. ई.ए. को सिफारिश की थी। लेकिन, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यह मामला अभी भी लम्बित है।

महोदय, मिजोरम के माननीय मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणब जी को फरवरी, 2009 में तुआईवल एच.ई.पी. के लिए वी.जी. एफ. की 'सैद्धांतिक' अनुमति देने के लिए शीघ्र अनुकूल निर्णय लेने हेतु लिखा है लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई अनुकूल कार्यवाही नहीं की गई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे तुआइवल एच.ई.पी. के लिए वी. जी.एफ. पाने में हमारी मदद करें। योजना आयोग ने वार्षिक योजना (2009-2010) के दौरान मिजोरम की वार्षिक योजना 2009-2010 के लिए, तुआईवल एच.ई.पी. के कार्यान्वयन हेतु 80.00 करोड़ रुपये के आबंटन की सिफारिश की थी, बशर्ते कि परियोजना को व्यवहार्यता अंतर वितपोषण मिल जाए।

[हिन्दी]

***श्री भूदेव चौधरी** (जमुई) : महोदया, विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश में मच रहे हाहाकार पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज के परिवेश में बिजली आम लोगों का सबसे आवश्यक आवश्यकता हो गयी है। बिजली के बिना किसी भी क्षेत्र में विकास की परिकल्पना करना दिवा स्वप्न के अलावा कुछ नहीं हो सकता। पूरे देश में से बिहार की स्थिति विद्युत ऊर्जा के मामले में काफी दयनीय है।

महोदया, देश के कई राज्य ऐसे भी है जहां की गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। वहीं बिहार के आज भी 18,395 गांव विद्युतीकरण से वंचित है। केन्द्र सरकार राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलायी जा रही है, परन्तु लक्ष्य के अनुरूप कार्य न होना बिहार के लिये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण के दिशा में जो कार्य हो रहा है, धरातल पर इसकी सत्यता जानकर सदन को घोर आश्चर्य होगा। विद्युतीकरण के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। आधिसंख्य गांवों में एक फेज का लाईन और 10 के.वी. का ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है जो कि विद्युत सप्लाई के पश्चात् महीने भर में ही जल जाता है। अथवा किसी न किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान दिया जा रहा है कि विद्युतीकृत गांव में विद्युत का सप्लाई कहां से होगा। महोदय, बिहार में उद्योग का घोर अभाव है। यहां के अस्सी प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है। सरकार द्वारा डीजल का दाम बढ़ाने, उर्वरकों पर से सब्सिडी हटाने के बाद किसानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। सामने सुखाड़ की स्थिति साफ दिख रही है। ऐसी परिस्थिति में किसानों को सिर्फ बिजली उपलब्ध हो जाती

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री भूदेव चौधरी]

तो किसान हर दर्द को सहने में सक्षम हो जाता परन्तु विद्युतीकरण हो या अन्य जनोपयोगी योजना बिहार के साथ सदैव सौतेला व्यवहार होता रहा है, और सरकार द्वारा आंकड़ों के खेल में उलझाकर प्रदेश की निरीह जनता को अपने हाल पर रोने के लिए छोड़ दिया जाता है। आजादी के 62 वर्षों के बाद भी अगर बिहार हर क्षेत्र में विपछड़ा है तो इसका दोषी कौन है? देश और प्रदेश में अधिसंख्य वर्षों तक कांग्रेस या कांग्रेस की समर्थित सरकार ही रही, परंतु पूरे देश में से विद्युतीकरण के मामले में उड़ीसा और झारखंड के बाद बिहार की ही दयनीय स्थिति है।

महोदया, विगत सरकार के शासन काल में इसी सदन में परमाणु संधि को लेकर जो स्थिति बनी उसके लिए पूरा सदन शर्मसार हो गया था, फिर भी सरकार बची, संधि पर हस्ताक्षर भी हुआ, और सरकारी बयान सबसे ज्यादा ऊर्जा के क्षेत्र में देश की संपन्नता को लेकर इस संधि को महत्वपूर्ण बताने के परिप्रेक्ष्य में आता रहा। हम सदन के माध्यम से जानना चाहेगें कि देश विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में कब तक सुसंपन्न हो सकेगा? क्या बिहार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के विषय में सरकार अभिरुची रखती है? बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव है? अगर सिर्फ केन्द्र और राज्य सरकार के कार्यों पर आरोप-प्रत्यारोप ही होता रहा तो इस सदन की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न होना स्वभाविक होगा।

महोदया, बिहार विभाजन के बाद शेष बिहार को औसत आवश्यकता से अधिक विद्युत भी केन्द्र सरकार से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बिहार सरकार के माननीय मुख्य मंत्री नितीश कुमार विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के मामले में काफी गंभीर है। ये बिहार को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, किन्तु केन्द्र की उदारतापूर्वक मदद की आवश्यकता है। वर्तमान समय में बिहार की स्थिति काफी बदली है, कई निजी कंपनी बिहार में विद्युत संयंत्र लगाने को तैयार है। पर केन्द्र से इस दिशा में जो मदद मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। खास कर बिहार को कोल लींकेल न मिलना बिहार के लिये केन्द्र सरकार के मन में उपेक्षा की भावना को साफ परिलक्षित करता है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार में विद्युत उपलब्धता के लिये थर्मल पावर स्थापना की जाये। केन्द्र द्वारा बिजली का कोटा तत्काल बढ़ाया जाये। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत सभी गांवों में तीन फेज लाइन और उच्च शक्ति ट्रांसफार्मर लगाया जाये ताकि किसान सिचाई कार्यों के लिए विद्युत का उपयोग कर सके। बिहार में जो भी कंपनी बिजली घर लगाना चाहे उसे केन्द्र से आवश्यक सहयोग के साथ-साथ शीघ्र कोल लिंकेज दिया जाये।

महोदय, बिहार में पनबिजली उत्पादन की अपार संभावनाए है। कोसी नदी जो नेपाल से निकल कर हर वर्ष बिहार के उत्तरी इलाके में तबाही मचाती है, नेपाल सरकार से वार्ता कर उसे बांध कर एक तरफ सिचाई का साधन उपलब्ध कराया जा सकता है तो दूसरी ओर इससे प्रचुर मात्रा में बिजली उत्पादन भी होगा। जरूरत है, केन्द्र सरकार की सकारात्मक पहल और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने की प्रबल इच्छा शक्ति। अतएव, सरकार से बार-बार अनुरोध करना चाहूंगा कि अंकगणित के मकड़ जाल से निकल कर देश और बिहार प्रदेश की गरीब जनता के दर्द को समझ कर उसका समुचित प्रयास किया जाये।

महोदया, अन्य राज्यों की तरह अगर बिहार को और कुछ नहीं तो सिर्फ विद्युत ऊर्जा के मामले में सुसंपन्न कर दिया जाये, यहां के किसानों को 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध होती रहे, तो बिहार कृषि के बूते देश की आर्थिक विकास की दर के लक्ष्य तक पहुचाने में किसी राज्य से पीछे नहीं रहेगा। पूरा सदन इस बात से सहमत है कि बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ राज्य है, तो मैं समझता हूं बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये विशेष पैकेज देने में पूरा सदन बिहार की मांग का समर्थन करेगा। अतः, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर वहां की जनता को उचित हक प्रदान किया जाये।

मैं अपने लोक सभा क्षेत्र जमुई में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के हाल का एक छोटा सा नमूना पेश करना चाहूंगा। जमुई जिला में 1273 गांवों में विद्युतीकरण का लक्ष्य था जिसमें एक भी गांव में विद्युतीकरण नहीं हो सका इसी जिले में चार पावर सब-स्टेशन लगाने था जिसमें से एक भी अब तक बनकर तैयार नहीं हो सकता पावर ग्रिड के पदाधिकारी सिर्फ टालमटोल का रवैया अपना रह हैं।

महोदया, जमुई लोक सभा क्षेत्र में सभी संसाधन उपलब्ध है, यथा पानी के लिए भीम बांध जैसे बड़ा जलाशय, कोयला के लिये झारखंड का अत्यंत नजदीक होना, ढुलाई के लिये रेलवे लाइन उपलब्ध होना, थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिये प्रर्याप्त जमीन उपलब्ध होना। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से जुमुई में एक उच्च शक्ति थर्मल पावर प्लांट लगाने का निवेदन करता हूं। आशा है, माननीय मंत्री मेरे प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

दो बंद पड़े ताप विद्युत संयंत्रों ने अभी तक विद्युत उत्पादन करना शुरू नहीं किया है। बरौनी और कांटी ताप विद्युत संयंत्र का पुनरुद्धार

कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। उनकी पुरानी पड़ चुकी मशीनरी को बदलकर नए लगाए जाएं और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) और राज्य सरकार के बीच नबीनगर औरंगाबाद में 1980 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, पर यह कब पूरा होगा, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है, और क्या इतने भर से राज्य की बिजली की जरूरतें पूरी हो जाएंगी और अधिक बिजली उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किए जाएं, इसके लिए बिहार सरकार की मदद की जाए। अभी बिहार की कुल स्थापित क्षमता 584 मेगावाट की ही है जबकि जरूरत इससे काफी अधिक है। मुजफ्फरपुर बंद पड़ा है और बरौनी में केवल 30 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। राज्य को बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 60 किलोवाट प्रति वर्ष है जबकि राष्ट्रीय औसत 354.75 किलोवाट प्रतिवर्ष है। इतने भारी अंतर को पाटने के लिए केन्द्र सरकार बिहार को कितनी राशि की सहायता दे रही है।

बिहार राज्य बिजली बोर्ड को भारी वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इसकी स्थापना लागत 51.71 करोड़ रु. प्रति माह है जबकि इसका मासिक घाटा 107 करोड़ रु. का है। राजसहायता प्रदान कर बोर्ड के वित्तीय हाल को दुरूस्त किया जाए।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांवों का जो विद्युतीकरण किया जा रहा है उनमें बिहार 29.02.2008 की स्थिति के अनुसार 18395 गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई गई है।

बी.पी.एल. कनेक्शन के अंतर्गत अनुदान राशि को 1500 रु. से बढ़ाकर 2200 रु. किया गया, यह पर्याप्त नहीं है। इसे बढ़ाकर 3500 रु. किया जाए।

आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत गांवों में 10, 16 और 25 किलोवाट के ट्रांसफर्मर लगाए जा रहे हैं। ये पर्याप्त नहीं हैं। इनकी क्षमता बढ़ाई जाए ताकि कृषि कार्य में लोगों को सुविधा हो सके। सिर्फ बत्ती जलाना पर्याप्त नहीं होगा, किसानों को मदद भी मिलनी चाहिए।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में बीपीएल के साथ-साथ एपीएल के लोगों को भी शामिल किया जाए। बिहार में मंजूर लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार को बिहार को और अधिक मदद देनी चाहिए ताकि परियोजना को शीघ्रता से पूरा किया जा सके। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बिहार को मात्र 1619 करोड़ रुपये ही प्रदान किये गये। इस राशि को बढ़ा कर 3 हजार करोड़ रु. किया जाए और उचित बिजली वितरण की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

***श्री थोल तिरूमावलावन** (चिदम्बरम) : सभापति महोदय, विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका हार्दिक अभारी हूं। इस सम्माननीय सभा में अध्यक्षपीठ और अपने सम्मानित सहयोगियों और को अभिवादन करते हुए मैं अपनी पार्टी विदुथलाई चिरुथाईगल कार्ची, की ओर से अपने विचार रखता हूं।

विद्युत से विश्व को गति और प्रकाश मिलता है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आगे रहने वाले देश मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ-साथ औद्योगिक विकास में भी आगे रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा देश विद्युत उत्पादन के मामले में राष्ट्रमंडल में पिछे चल रहा है। यद्यपि हमारे पास बड़ी मात्रा में संसाधन है और विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं फिर भी हम उनके अधिकतम दोहन के तरीके विकसित नहीं कर पाये हैं। हमारे पास पर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं नहीं हैं। यही कारण है कि अभी भी विकास के क्षेत्र में हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था है। आज भी हमारे देश के दूर-दराज के हिस्सों में स्थित हजारों छोटी बसावटों और गांवों में लोगों ने बिजली देखी तक नहीं है और यही कारण है कि हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश का बड़ा भाग अभी भी अंधकार में है। यही कारण है कि पूर्ववर्ती शासकों, जो इंडिया शाइन्स का दावा करते थे, को जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया क्योंकि वे जरूरत मंदों को बिजली मुहैया कराने में असफल रहे।

बेंजामिन फ्रैंकलीन, माइकल फैराड़े और थॉमस अल्वा एडीसन ने विद्युत उत्पादन के तरीकों की खोज की और मानवता के कल्याण के लिए इसका उपयोग किया। उन महान वैज्ञानिको के निष्कर्ष उनकी खोज के 300 वर्षों के बाद भी हमारे भारत के अनेक गांवों तक नहीं पहुंच पाये हैं। चूंकि यह भारत सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है, अत: भारत सरकार हमारे दूर-दराज के हर छोटे गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम अपने हाथों मे ले। यही कारण है कि वर्तमान सरकार का लक्ष्य सभी के लिए बिजली है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के इस दूरदृष्टि युक्त दृष्टिकोण से प्रेरित होकर हम योजनाएं बना रहे हैं।

हर क्षेत्र तथा हर वर्ग के लोगों का विकास में हिस्सा होना चाहिए जिसे हम समावेशी और सम विकास की संज्ञा देते हैं। केन्द्र में संप्रग

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री थोल तिरूमावलावन]

सरकार की यह घोषित नीति है। इसके साथ ही हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे अनेक राज्य तथा अधिकांश गांव बिजली की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। भारत सरकार ने विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। पन बिजली परियोजना, ताप विद्युत परियोजना, पवन ऊर्जा परियोजना, सौर ऊर्जा परियोजना सभी पर विचार हो रहा है और कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है। तमिलनाडु में चेय्यूर और कुड्डलोर को इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए चुना गया है। लेकिन दुर्भाग्यवस इसे लम्बित रखा गया हैं।

उदाहरण के लिए, कुडनकुलम न्यूक्लियर परख प्रोजेक्ट की घोषणा हुए 10 साल बीत चुके है। इसे अभी भी असली जामा पहनाया जाना बाकी है। विद्युत उत्पादन अभी शुरू होना है। इसमें अभी भी समय लगेगा। यह परियोजना अभी पूरी की जानी है। हम जानते हैं कि रूस के साथ 8,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की परियोजना शुरू करने के लिए एक समझौता हुआ है। इसकी नियति के बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं है।

जयंकोंडम ताप विद्युत परियोजना की घोषणा की गई थी और उत्पादन शुरू किए जाने के लिए इसे अभी स्थापित किया जाना है। हम महसूस करते हैं कि केरल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों की उपेक्षा की जा रही है। कृष्णा-गोदावरी बेसिन में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक गैस उपलब्ध है। बम्बई हाई में उपलब्ध भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस की पाइप लाइन के माध्यम से देश के उत्तरी राज्यों को उनसे आपूर्ति की जाती है। उत्तरी राज्यों को उनसे आपूर्ति की जा रही है। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह देखे कि कृष्णा-गोदावरी बेसिन में उपलब्ध प्राकृतिक गैस देश के दक्षिण भाग में स्थित राज्यों को उपलब्ध करायी जाए। लेकिन मैंने पाया है कि रिलायंस, गुजरात पेट्रोलियम कम्पनी तथा ओ.एन.जी.सी. कृष्णा-गोदावरी बेसिन से प्राप्त प्राकृतिक गैस को उत्तरी राज्यों में ले जाने की योजना बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि रिलायंस प्राकृतिक गैस को वहां से गुजरात और अन्य उत्तरी राज्यों में ले जाने की अपनी योजना पर आगे बढ़ रही है और इसे उत्तरी राज्यों में ले जाने के लिए पूरे दक्षिणी राज्यों में पाइप लाइन बिछाई जा रही है। 2007 में यह सहमति हुई थी कि वहां उपलब्ध प्राकृतिक गैस आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को दी जाएगी। लेकिन इसे दर किनार कर दिया गया है। तमिलनाडु के हमारे मुख्यमंत्री डॉ. कलैगनार करुणानिधि ने इस मामले को प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के सामने उठाया। परंतु दुर्भाग्यवश मुझे सुलह कराने वाले उपाय जैसी कोई योजना नजर नहीं आती है। काकीनाड़ा, नेल्लोर और चेन्नई से होकर जाने वाली पाइपलाइन डालने की परियोजना को बंद कर दिया गया है।

हमारे प्रधान मंत्री समावेशी विकास पर जोर देते रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने भी इसे दोहराया है। परंतु मुझे ऐसी कोई योजना नहीं नजर आती जो इसके उत्साह को कार्य योजना में परिवर्तित कर सके। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि किसी क्षेत्र को छोड़ा नहीं जाना चाहिए अथवा किसी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। हमारे देश के सभी राज्यों को विकास करने को समान अवसर मिलना चाहिए। सभी राज्यों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा और उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समुचित योजनाएं बनाई जानी चाहिए।

जहां तक तमिलनाडु का संबंध है तो यहां पर नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के अलावा कोई अन्य सरकारी विद्युत उत्पादन संयंत्र नहीं है। एनटीपीसी है, एनएचपीसी है और मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई संगठन ऐसी कोई योजना ला रहा है। जिससे तमिलनाडु को लाभ हो। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह औद्योगिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों में विद्युत उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के उपक्रमों को योजनाएं और कार्यक्रम बनाने हेतु राजी करे। नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन (एनएलसी) द्वारा उत्पादित विद्युत के बड़े हिस्से की आपूर्ति तमिलनाडु को की जाए जो विद्युत की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है।

एनएलसी में लगभग 5000 ठेका श्रमिक हैं जो लम्बे समय से कार्यरत हैं परंतु उन्हें अभी तक 'इनकोसर्व' सोसाइटी में सम्मिलित नहीं किया गया है और नियमित भी नहीं किया गया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन कामगारों को स्थायी किया जाए। उन्हें सम्मानित समाज का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जब मैंने इस मामले को विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे के सामने उठाया तो उन्होंने कहा कि एनएलसी कोयला मंत्रालय के अधीन है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह विद्युत संयंत्र को विद्युत मंत्रालय के अधीन लाने के लिए कदम उठाए। विद्युत उत्पादन मुख्य मुद्दा है। अत: एनएलसी को विद्युत मंत्रालय के अधीन लाना एचित होगा। विद्युत की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने हेतु बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिए तमिलनाडु सहित सभी दक्षिणी राज्यों को लाभान्वित करने हेतु विद्युत परियोजनाओं की घोषणा की जानी चाहिए।

बोलने का यह अवसर देने पर अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) : माननीय सभापति महोदय, मैं ऊर्जा विभाग की अनुदान की मांगों के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं अपने उद्बोधन में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी और ऊर्जा मंत्री श्री शिंदे जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऊर्जा विभाग के लिए ज्यादा राशि देकर देश में ऊर्जा संकट को दूर किया है। हिन्दुस्तान में पिछले पांच-छः वर्षों से एनटीपीसी के माध्यम से बेहतर काम करने की कोशिश की गई है। मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का अभारी हूं कि उन्होंने अपने दौरे के समय मध्य प्रदेश के इन्दौर में नरसिंहपुर जिले में 42000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एनटीपीसी प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। मैं इसके लिए अपने उद्बोधन में आदरपूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मेरा माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध है कि एनटीपीसी प्रोजेक्ट का काम शीघ्र चालू करें जिससे मध्य प्रदेश में विद्युत संकट को शीघ्र दूर किया जा सके। राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना के बारे में सम्माननीय सांसद महोदय ने बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिले में यह योजना लागू की गई है। जैसा हमारे साथी ने जिक्र किया, चूंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस योजना का नाम स्वर्गीय नेता माननीय राजीव गांधी जी के नाम पर है इसलिए जिन जिलों में यह योजना लागू की गई है, वहां सुचारू रूप से इसका संचालन नहीं किया जा रहा है, क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। मेरा निवेदन हैं कि जिन जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू की गई है वहां केंद्र सीधे दखल देकर इस योजना का सुचारू रूप से संचालन करे। मैं मध्य प्रदेश की बात कहना चाहता हूं। वहां पिछले पांच सालों में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जहां हम एक तरफ गरीबों को एक बत्ती कनेक्शन देने की बात कहते हैं वहां दूसरी तरफ गरीबों का एक बत्ती कनेक्शन काटकर उन पर हजारों रुपये के हिसाब से बिल लाद दिए गए हैं। उन पर अपराध के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जहां हम किसानों को बिजली देने की बात करते हैं, वहां मध्य प्रदेश के हजारों किसानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपराध के मामले दर्ज कर दिये हैं और उन्हें जेल में डालने की कार्रवाई की जा रही है। मेरा सदन से निवेदन है कि ऐसी अनियमित कार्रवाइयों पर रोक लगाई जानी चाहिए। जिन किसानों ने अपने कनेक्शन पी.डी. करने का आवेदन किया है, जो किसान बिजली के बिल नहीं दे पा रहे हैं, उन्होंने निवेदन किया है कि हमारा कनेक्शन पी.डी. कर दिया जाए। लेकिन बजाय उनका कनेक्शन पी.डी. करने के उनके बिल लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और एक-एक किसान पर एक-एक लाख रुपये तक का बिल बकाया है। इस संबंध में केन्द्र सरकार को दखलंदाजी देकर प्रदेश सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाना चाहिए।

महोदय, मध्य प्रदेश में एक और विसंगति बहुत अधिक हो रही है। यह बहुत गम्भीर विषय है। देश में यदि कोई प्रदेश बिजली के सर्वाधिक संकट से जूझ रहा है तो वह मध्य प्रदेश जूझ रहा है लेकिन वहां जो किसान बिजली का बिल दे रहा है, उस किसान की लाइन भी काटी जा रही है और जो किसान बिजली का बिल नहीं दे रहा है, उसकी लाइन भी काटी जा रही है। इस बारे में केन्द्र सरकार से निर्देश जारी होना चाहिए कि जो किसान बिजली का बिल दे रहा है, जो मकान मालिक बिजली के बिल का नियमित भुगतान कर रहा है, उसे सुचारू रूप से बिजली प्रदान की जाए। मैं समझता हूं कि इस हेतु सदन से निर्देश जारी होना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे जिले में प्राइवेट सेक्टर में एक विद्युत संयंत्र की स्थापना की शुरूआत हो रही है। मेरी प्रार्थना है कि 10-10, 15-15 मेगावाट के छोटे संयंत्र अन्य जिलों में भी लगाए जाएं, जिससे कि हमारे क्षेत्र में बिजली का संकट दूर हो सके।

महोदय, कोयले के नाम पर मध्य प्रदेश में बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है। वहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें कोयला नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने जवाब में इस बात का उल्लेख जरूर करें कि जब एनडीए की सरकार थी तब मध्य प्रदेश को कितना कोयला मिलता था और हमारी यूपीए की सरकार में हम कोयले की मात्रा बढ़ाकर दे रहे हैं, इसकें बाद भी लगातार प्रदेश की सरकार कोयले के नाम पर अपना रोना रोकर पूरे प्रदेश में माहौल को खराब करने की कोशिश करती रहती है।

मैं सदन में पुनः अपनी ओर से माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश में बिजली के संकट को दूर करने के लिए अपनी ओर से बहुत बेहतर प्रयास किया है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : सभापति महोदय, मेरी पार्टी की तरफ से पहले भी कई वक्ता अपनी अपनी बातों को यहां रख चुके हैं। लेकिन बिहार में एनटीपीसी का एक ही थर्मल पावर प्लान्ट जो अभी चल रहा है, वह मेरे लोक सभा क्षेत्र भागलपुर के कहलगांव में है। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली सरकार में भी जब आप मंत्री थे तो आप कहलगांव गये थे। लेकिन वहां

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन]

जहां से बिजली बनती है, उसके चारों तरफ अंधेरा रहता है। वहां से बिजली बनकर दिल्ली और पंजाब जाती है। लेकिन बिहार में बिजली बनती है और जहां जरूरत है, वहां आप हमें जो बिजली दे रहे हैं, वह ताल से दे रहे हैं, तालचर से दे रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि जब बिहार में बिजली का संकट है और यदि आपने बिहार का कोटा बढ़ाना है तो जो बिजली बिहार के कहलगांव में बन रही है, वह बिजली आपको बिहार को देनी चाहिए।

दूसरी बात मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने भागलपुर में घोषणा की थी कि यहां पर एक हजार मेगावाट का एक बिजलीघर और लगायेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने जवाब में उसके बारे में जरूर जिक्र करें। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जहां पर बिजली बनती है, वहां उसका पॉल्यूशन बहुत फैलता है, आसपास लोग बिजली देखते हैं और चारों तरफ अंधेरा रहता है। आज भागलपुर में आपने बिजलीघर बना दिया, लेकिन जो लैंड लूजर्स हैं, उन्हें आज भी मुआवजा नहीं मिला। आज भी वे दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। नंदीग्राम का सबक देश देख चुका है। मेरा अनुरोध है कि लैंड लूजर्स को आपका जो रोजगार देने का वायदा है, वह पूरा करना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग बिहार के लोगों से ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि एनडीए ने वहां अच्छी सफलता प्राप्त की है। आपकों वहां पर दो सीटें ही मिली हैं। मंत्रिमंडल में तो अंधेरा है ही, क्योंकि बिहार का एक भी चिराग मंत्रिमंडल में नहीं जलता है और यह पहली ऐसी कैबिनेट है कि जिसमें कोई बिहारी बैठता नहीं है।...*(व्यवधान)*

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : अध्यक्ष महोदया बिहार की हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूं। खान साहब को भी मौका नहीं मिला। खान साहब आपका भी नाम नहीं है।...*(व्यवधान)* जो टोका-टोकी है, मैं तो सिर्फ याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं, सभापति जी, यह मेरा भाषण नहीं है, चूंकि मंत्री जी जवाब देंगे, इसलिए मैं इनका जवाब सुनने के लिए आया हूं और मैं इंतजार कर रहा हूं क्योंकि आप मैन आफ वर्ड्स माने जाते हैं।

सायं 7.00 बजे

आप कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। आप भागलपुर के कहलगांव के लैंड लॉस्टियों को न्याय देंगे। हमने मांग की थी कि 10 किलोमीटर की रेडियस में जो गांव हैं, उन्हें बिजली सुलभी करायें। यह हमारा आपसे अनुरोध है। हम एक लाइन में आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अभी चुनाव से पहले आपके मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है। कोई कितनी भी आलोचना करे, मैं आलोचना नहीं करूंगा। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना गांव-गांव में पहुंची है। बल्ब जले या न जले, लेकिन आपे बोर्ड बहुत अच्छे लगा दिये हैं, सब जगह राजीव गांधी जी की फोटो है और बोर्ड लगे हैं। आपने गांव में बल्ब नहीं जलाया है बल्कि बहुत कीमती लोहे का बोर्ड लगाया है, जो प्रिन्टिड है। आपके नेता की उस बोर्ड पर फोटो है, यह आपके नेता के नाम की योजना है। बिहार में सिर्फ बोर्ड लगा है, बल्ब नहीं जल रहा है। मुझे आशा है कि आप बिहार के लोगों के साथ न्याय करेंगे और बिहार को बिजली देंगे।

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरुन रशीद (थेनी) : मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं विद्युत मंत्रालय अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

इस समय हमारा देश विद्युत की अत्यंत कमी का सामना कर रहा है। प्रत्येक राज्य में विद्युत की अत्यधिक कमी है। तमिलनाडु इसका अपवाद नहीं है। तमिलनाडु के पास उपलब्ध कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 10,100 मे.वा. है जिसमें टीएनईबी 5597 मे.वा. सम्मिलित है।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर) : खान साहब, आपको भी मंत्री नहीं बनाया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

श्री जे.एम. आरुन रशीद : लगभग 5,597 मे.वा. विद्युत टीएनईबी के अपने विद्युत उत्पादन केंद्रों से और 1,154 मे.वा. निजी विद्युत संयंत्रों से है। लगभग 335 मे.वा. केंद्र सरकार के विद्युत उत्पादन केंद्रों की सहायता से हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत क्षेत्र में पवन चक्कियों से कुल 3,693 मे.वा. की क्षमता उपलब्ध है।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, इनकी स्पीच ले करा दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह एक मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री जे.एम. आरुन रशीद : पूरे देश में, तमिलनाडु पवनचक्कियों से अधिक विद्युत का उत्पादन कर रहे है। विद्युत की कमी को पूरा करने हेतु लगभग 451.6 मे.वा. विद्युत उत्पादन संयुक्त उत्पादन विद्युत संयंत्रों से और 104.85 मे.वा. बायोमास संयंत्रों से किया जाता है।

महोदया सोनिया गांधी और हमारे माननीय मंत्री श्री शिंदे के मार्गदर्शन में पिछले कार्यकाल में तमिलनाडु को आरंभ में 1000 मे.वा. और बाद में 500 मे.वा. विद्युत दिए जाने के लिए संप्रग सरकार को धन्यवाद, मैं उन्हें केंद्रीय ग्रिड से तमिलनाडु को इतनी विद्युत दिए जाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

गत वर्ष व्यस्ततम समय में विद्युत की मांग लगभग 9076 मे. वा. पहुंच गई है और ऊर्जा खपत में वृद्धि नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष होने की संभावना है। वर्ष 2008-09 में संभावित मांग 9500 मे.वा. होने का अनुमान है। प्रतिवर्ष विद्युत की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है।

विद्युत की भारी कमी से उबरने में हमें काफी मुश्किल आ रही है और विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार को विशेष कदम उठाने पड़ेगे। सरकार अन्य राज्यों से विद्युत खरीदकर तथा उद्योगों को रक्षित विद्युत के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करके इस कमी को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है।

सायं 7.04 बजे

[श्री पी.सी. चाको *पीठासीन* हुए]

गर्मी के महीनों में पवन विद्युत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी निजी विद्युत उत्पादक संगठनों को विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु तमिलनाडु के पास 7845 मेगावाट की स्थापित, क्षमता है। अधिकांश पवनचक्कियां कन्या कुमारी और थेनी जैसे खुले स्थान वाले दक्षिणी जिलों में तथा कोयम्बटूर के पहाडी जिलो और इसके सीमावर्ती जिलों में स्थापित है। कुछ वर्ष पूर्व तमिलनाडु में कुल पवन विद्युत की क्षमता 3,500 मेगावाट आंकी गई थी।

सभापति महोदय : आप भाषण के शेष भाग को सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री जे.एम. आरुन रशीद : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय : आप भाषण पढ़ रहे हैं इसलिए, इसे सभापटल पर भी रख सकते हैं। भाषण के लिए आपको धन्यवाद।

श्री जी.एम. आरुन रशीद : बस, एक मिनट

महोदय, तमिलनाडु में प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि के कारण विद्युत की खपत बढ़ी है। हर घर में मिम्सी, ग्राऩ्डर, फ्रिज और एयरकंडीशनर है। बच्चे पंखा चलाए बिना सो नहीं सकते। इसलिए, लोगों के लिए बिजली अति आवश्यक हो गयी है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें मत भड़काइए, नहीं तो वे और अधिक समय लेगें। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जे.एम. आरुन रशीद : महोदया, भारत की स्थापित क्षमता 8748 मेगावाट कह है और पवन विद्युत के क्षेत्र में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है जिसका कुल स्थापित क्षमता में 44 प्रतिशत योगदान है।

महोदय, मैं अपने भाषण का शेष भाग सभा पटल पर रखता हूं।

*राज्य क्षेत्र के पेरियार बाईगाई बराज परियोजना के अंतर्गत प्रथम चरण में (2+2 मेगावाट), 2(2+1.25 मे.वा.) के तथा चौथे चरण में (2+1.25 मे.वा.) कुल 9 मेगावाट क्षमता के 17 पावर हाउस शुरू किए जाएगें। केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कैगा परमाणु विद्युत केन्द्र की 220 मेगावाट क्षमता की दूसरी यूनिट, चरण-II तथा कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना चरण-1, की 1000 मेगावाट क्षमता की प्रथम यूनिट 2008-09 के दौरान शुरू की जाएगी। उपर्युक्त दोनों परियोजनाओं से टी.एन.ई.बी. को क्रमश: 53 मेगावाट और 463 मेगावाट विद्युत उपलब्ध करायी जाएगी।

तमिलनाडु सरकार मर्चेंट पावर प्लांट रूट के अंतर्गत तटीय ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है। कुल 17140 मेगावाट क्षमता के लिए मर्चेंट पावर प्लांट रूट के अंतर्गत विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु 10 फर्मों को सुविधा प्रदाता पत्र भेजा जा चुका है। इसके अलावा सरकार अतिरिक्त 15000 मेगावाट के लिए मर्चेंट पावर प्लांट की स्थापना हेतु के 10 से ज्यादा आवदेनों पर सक्रियता से विचार कर रही है। यदि केन्द्र और राज्य सरकारें परियोजना को शीघ्र शुरू

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री जे.एम. आरुन रशीद]

करने हेतु समय पर अपेक्षित अनुमति दे देती है तो तभी तमिलनाडु में विद्युत की कमी दूर होगी।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को 5 वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है जो निर्बाध रूप में विद्युत आपूर्ति कर सकती हैं जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। नई आवासीय कालोनियों की संख्या में वृद्धि भी विद्युत की कमी का मुख्य कारण है। सरकार ने पहले ही गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 1 लाइट यूनिट देने की कृपा की है; बुनकर समुदायों (हथकरघा और विद्युतकरघा बुनकर) को 500 यूनिट तक निःशुल्क विद्युत दी है। कृषि क्षेत्र के लिए नए कनेक्शनों हेतु कई हजार आवेदन पिछले कई सालों से लम्बित पड़े हैं।

यदि केन्द्र सरकार सेंट्रलग्रिड से तमिलनाडु सरकार को 2000 मेगावाट विद्युत दे सके तो इससे कृषि क्षेत्र को फायदा होगा। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) द्वारा उत्पादित बिजली निकटवर्ती राज्यों को दी जाती है। तमिलनाडु में विद्युत की भारी कमी के कारण एन.एल.सी. में उत्पादित विद्युत का कम से कम 80% केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु को दिया जाना चाहिए। कोयला के अभाव में तमिलनाडु स्थित विद्युत उत्पादन यूनिटें काफी प्रभावित होती है। केन्द्र सरकार को इन यूनिटों को कोयले की लगातार आपूर्ति के लिए एक नीति बनानी चाहिए। तमिलनाडु एक विस्तृत क्षेत्र है, कन्याकुमारी जिला विशेषकर पवन विद्युत उत्पादन के मामले में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करने वाला जिला, कन्याकुमारी से 1500 मेगावाट से अधिक पवन विद्युत उत्पादन किया जा सकता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अंडोपत्ती और बोदी में तेज हवाएं चलती है। हवाएं बहुत तेज चलती है और सरकार इन विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में पवन विद्युत उत्पादन यूनिट शुरू करने की संभावनाओं का पता लगा सकती है। सरकारी तथा निजी यूनिटो ने अंडीपत्ती में पवन विद्युत उत्पादन इकाइयां लगाई हैं। मैं बोडी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में भी पवन विद्युत उत्पादन इकाइयां लगाने का अनुरोध करता हूं।

माननीय मुख्यमंत्री डॉ. एम. करुणानिधि की अध्यक्षता में तमिलनाडु विद्युत की कमी पर नियंत्रण करने तथा इस कमी को न्यूनतम करने तथा गरीब परिवारों और किसानों की मदद करने की भरसक कोशिश कर रहा है। उन्हें एक दिन में एक से दो घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। इस पावर-कट से बचने के लिए केन्द्र सरकार ने पावर ग्रिड से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को अधिक विद्युत की आपूर्ति की है।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पेरियार बांध तथा अन्य बांधों (सुरुली और मनिमुथारू बांध) का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इनमें से अधिकांश इकाइयां खराब रख-रखाव के कारण अधिकांश समय बंद ही रहती है। और आधुनिक उपकरणों और पुर्जों की खरीद के लिए इन्हें अतिरिक्त वित्तपोषण की आवश्यकता है। लेयर कैंप पावर हाउस अपनी स्थापित क्षमता 140 मेगावाट अर्थात् 4x35 मेगावाट की जगह 98 मेगावाट का उत्पादन कर रहा है। एक यूनिट को रख-रखाव के लिए बंद कर दिया गया है।

केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह वास्तविक स्थिति का आकलन करने तथा जलविद्युत उत्पादन के लिए दिए जाने वाले समुचित वित्तपोषण का आकलन करने के लिए सक्षम अधिकारियों का एक दल भेजें ताकि विद्युत उत्पादन पुनः शुरू हो सके।

नेवेली एकक की सभी इकाइयां कार्य नहीं कर रही हैं, जिसके कारण वहां श्रमिकों संबंधी बड़ी समस्या चल रही है। 5000 कर्मचारी 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं और उन्हें नियमित नहीं किया गया है। पिछले कुछ महीनों में श्रमिक संघों ने आंदोलन करके अपना विरोध व्यक्त किया है और संबंधित अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक और अधिकारी उनके उचित अनुरोध पर विचार नहीं कर रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह श्रमिक संबंधी समस्याओं की जांच करें और कृपया उन्हें हल करें; इसके बारे में अधिकारियों और श्रमिक संघों के बीच वार्ता के समय कई बार आश्वासन दिए गए हैं, परंतु कुछ नहीं हुआ है।

मैं अनुरोध करता हूं कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और श्रमिक संबंधी मुद्दों का शांतिपूर्वक समाधान किया जाए ताकि विद्युत उत्पादन पूरी क्षमता से किया जा सके।

श्री सुशीलकुमार शिंदे के कुशल नेतृत्व और माननीया सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के उत्कृष्ट मार्गदर्शन में विद्युत मंत्रालय; एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड कंपनियां बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। टीएनईबी के साथ एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम का माननीय विद्युत मंत्री, श्री सुशीलकुमार शिंदे, तमिलनाडु के विद्युत मंत्री श्री आर्कोट वीरा द्वारा एन्नोर (2x500 मे.वा. के उत्पादन हेतु) उद्घाटन किया गया था जिसमें उपमुख्यमंत्री श्री एम.के. स्टालिन उपस्थित थे। परंतु कार्य अपेक्षित स्तर का होने की संभावना नहीं है। भेल के साथ संयुक्त उद्यम - उदानगुडी 2x800 मे.वा. विद्युत संयंत्र भी केवल कागजों

पर है। यह कब आरंभ होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि यह कार्य समय पर पूरा किया जाए और विद्युत उत्पादन तत्काल आरंभ किया जाए। इसी प्रकार कुंडागलम परियोजना और अनेक विद्युत उत्पादन कार्यक्रम केवल कागजों पर ही हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विद्युत उत्पादन आरंभ करने और कृषि इकाइयों तथा गरीब परिवारों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कदम उठाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं और हमारे विशाल देश के विद्युत उत्पादन की स्थिति सुधारने में माननीय मंत्रियों के कड़े कदमों का स्वागत करता हूं तथा विनम्रतापूर्वक निम्न सुझाव देता हूं:-

1. सरकार को खुले मुहाने वाले संयंत्रों को प्रोत्साहन देना चाहिए।
2. जलाशय क्षेत्र में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए।
3. अधिक पवन ऊर्जा हेतु संयंत्र को अधिक राजसहायता देकर और अधिक संख्या में 'विंड टरबाईन' स्थापित किए जाएं।
4. 50 मे.वा. से कम विद्युत उत्पादन करने वाले लघु विद्युत उत्पादकों को सस्ती दरों पर कोयला दिया जाना चाहिए।
5. कावेरी बेसिन में 20 मेगावाट से कम विद्युत का उत्पादन करने वाले लघु विद्युत उत्पादकों को गैस प्रदान की जाए।
6. विद्युत की चोरी और पारेषण क्षति से बचने के लिए इसके नियमन हेतु कोई तंत्र बनाया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यदि इन्हें बड़े पैमाने पर कार्यान्वित किया जाता है, तो हमारा देश विद्युत के पूर्ण उत्पादन, खुशहाली और औद्योगिक तथा कृषि विकास के साथ संपन्न देश बन जाएगा।*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : महोदय, विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद वर्ष 2009-2010 के लिए विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चल रहे वाद-विवाद और चर्चा में भाग लेते समय मैं अपने बोडोलैंड क्षेत्र की अति गंभीर और खेद जनक स्थिति तथा जनता के सामने आ रही समस्याओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी करना चाहता हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत उत्पादन के मामले में असम सरकार की चिंताजनक क्षमता की और माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

आज की स्थिति के अनुसार असम सरकार का उपक्रम, असम राज्य बिजली बोर्ड की विद्युत उत्पादन क्षमता केवल 200 मे.वा. है। इस का विद्युत संयंत्रों से 200 मे.वा. विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। एक लोकोवा गैस टबाईन आधिरित संयंत्र है जो केवल 80 मे.वा. विद्युत का उत्पादन करता है। दूसरा नामरूप गैस टर्बाइन आधारित संयंत्र है, जो केवल 70 मे.वा. विद्युत का उत्पादन करता है। तीसरा कारबी-लंगयी पन विद्युत संयंत्र है, जिससे केवल 50 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है कुल मिलाकर असम राज्य बिजली बोर्ड (एएसईबी) केवल 200 ते.वा. विद्युत का उत्पादन करता है। व्यस्ततम समय में पूरे असम राज्य के लिए कुल आवश्यकता 900 और 1000 मे.वा. के बीच है। विद्युत की अधिकांश मात्रा बाहर से खरीदनी पड़ती है। भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र और साथ ही भूटान में भी भारी मात्रा में विद्युत का उत्पादन कर रही है।

[हिन्दी]

वह पावर हमारे बोडोलैंड ऊपर से ही पश्चिम की तरफ आती है लेकिन हमें नहीं दी जाती है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार की तरफ से कम से कम हमारे बोडोलैंड एरिया में जितनी छोटी-बड़ी नद-नदियां हैं, उन पर मैगा हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्रोजैक्ट्स और मिनी पावर प्रोजैक्ट्स की स्थापना की जाए। इसके लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपये की धनराशि का आबंटन बहुत जरूरी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सालाकती नाम की एक जगह में एनटीपीसी 750 मैगावाट क्षमता का एक नया प्लांट लगाने जा रही है। उसको टाइम से कमीशन करने के लिए उचित कदम उठाने पड़ेगे।

मैं एक बहुत गंभीर मामले की ओर आपके जरिये मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे कोकराझार जिले के लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना कुछ साल पहले सैंक्शन हुई थी। उसका 2007 में दो बार टैंडर हो चुका था। पहला टैंडर 9 जुलाई, 2007 में हुआ। दूसरी बार 2007 के सितम्बर, महीने में हुआ। वह सारे जिले के लिए सिंगल पैकेज में था, लेकिन 30 मार्च, 2008 को उसे तीन पैकेज में बांटा गया। तीन में से बी पैकेज को किसी एक कम्पनी को दे दिया गया। 'ए' और 'बी' दो पैकेज के लिए 17 अप्रैल 2009 को पावर ग्रिड कार्पोरेशन के अंडर टेंडर हो चुका

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

है। लेकिन आज ही अचानक मुझे मालूम चला है कि उन दो पैकेजिस को असम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि:

[अनुवाद]

असम राज्य बिजली बोर्ड पहले से एक असफल सरकारी उपक्रम हैं यह मेरे बोडोलैंड क्षेत्र की जनता को कोई अच्छी सेवा प्रदान नहीं कर सकता। अत:, मैं माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि असम बिजली बोर्ड को यह पैकेज नहीं दिया जाना चाहिए। बल्कि यह पैकेज पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

वे लोग बहाना बना रहे हैं कि कोकराझार जिले में पावर ग्रिड कार्पोरेशन की तरफ से काम देखने के लिए कोई अफसर नहीं है। लेकिन कोकराझार जिले के अलावा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बैसीमुथियारीजी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपका समय समाप्त हो चुका है। यदि आप अपने भाषण के शेष भाग को सभा पटल पर रखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, मैं अपने भाषण का शेष भाग सभा पटल पर रख रहा हूं।

*माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2009-2010 के लिए विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चल रहे वाद-विवाद और चर्चा में भाग लेने का यह अवसर देने पर मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और इसके साथ ही मैं असम राज्य में विद्युत क्षेत्र की खेदजनक और गंभीर स्थिति से संबंधित कतिपय मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी करना चाहता हूं।

मैं, माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री का ध्यान असम राज्य विद्युत बोर्ड (एएसईबी) द्वारा लोगों को विद्युत आपूर्ति के संबंध में दयनीय स्थिति के कारण संपूर्ण असम राज्य, विशेषकर हमारे बोडोलैंड क्षेत्र के लोगों की अत्यधिक समस्याओं और कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाना अवलोकनार्थ चाहता हूं, ताकि वे संबंधित मामले पर ध्यान दें और उसके समाधान हेतु उपयुक्त कार्यवाही चाहता हूं।

आज की स्थिति अनुसार, एएसईबी वर्तमान 3 विद्युत ऊर्जा संयंत्रों से केवल 200 मेगावाट का उत्पादन कर सकता है। जबकि राज्य में व्यस्तम घंटे में ऊर्जा की मांग 900 मेगावाट और 1000 मेगावाट के बीच होती है। निम्नलिखित तालिका एएसईबी के अंतर्गत वर्तमान 3 विद्युत संयंत्रों की वर्तमान क्षमता को दर्शाती है, जोकि संपूर्ण असम राज्य के लिए काफी कम है।

1. लाकोवा गैस टरबाईन आधारित संयंत्र – 120 मेगावाट अनुमानित क्षमता में से 80 मेगावाट;
2. नामरूप गैस टरवाईन आधारित ऊर्जा संयंत्र – 120 मेगावाट अनुमानित क्षमता में से 70 मेगावाट; और
3. कार्बी-लांग्पी पन बिजली परियोजना – 100 मेगावाट अनुमानित क्षमता में से 50 मेगावाट

उपरिलिखित 3 विद्युत संयंत्रों के अतिरिक्त एएसईबी की दो और विद्युत परियोजनाएं अर्थात् बोगाईगांव ताप विद्युत केन्द्र। सलाक्टी (210 मेगावाट की बीटीपी) और चंद्रपुर ताप विद्युत परियोजना (30 मेगावाट)। ये दो विद्युत परियोजनाएं पिछले 10-12 वर्षों से बंद हैं। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आज एएसईबी बाहर बाजार से और 560 मेगावाट खरीद रहा है। 510 मेगावाट की खरीद नीपको (एनईईपीसीओ) से की जा रही है और 50 मेगावाट की खरीद पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीईसीआईएल) और एनटीपीसीएल से की जा रही है। यह स्थिति कि व्यस्ततम घंटे में विद्युत की मांग 900 मेगावाट होने पर 140 मेगावाट की कमी स्पष्ट रूप से दर्शाती है। महोदय, मुझे यह बताते हुए अत्यंत खेद है कि विद्युत आपूर्ति की बुरी स्थिति के कारण हमारे बोडोलैंड क्षेत्र में अभी भी अधिकतर गांव अंधेरे में हैं।

मैं माननीय विद्युत मंत्री से अनुरोध करता हूं कि बिना और विलंब के काफी समय से लंबित निम्नलिखित मांगों पर ध्यान दे।

कोकराझार जिल में बीटीएडी में साक्कोटी के 750 मेगावाट के एनटीपीसी विद्युत संयंत्र, को 2010 तक निर्धारित समय के अंदर प्रारंभ किया जाए।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

एनटीपीसी, सक्कोटी की कुल विद्युत उत्पादन में से कम से कम 500 मेगावाट ऊर्जा बोडोलैण्ड क्षेत्र के लिए आरक्षित रखी जानी चाहिए और एनटीपीसीएल द्वारा ही बोडोलैंड क्षेत्र में इस विद्युत के वितरण हेतु आवश्यक तंत्र का निर्माण करना चाहिए।

सरकार को बोडोलैंड क्षेत्र में कुछ अर्थक्षम नदियों के उपरिनद में बृहत और लघु ताप-विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

केन्द्र सरकार को हमारे पिछड़े-बोडो आदिवासी क्षेत्र अर्थात् बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट (बीटीएडी) के अंदर नई विद्युत परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम 50,000 करोड़ रुपये का अनुमोदन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

केन्द्र सरकार को बोडोलैंड क्षेत्र के किसानों को नि:शुल्क विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही संबंधी नीति निर्णय लेना चाहिए।

विद्युत मंत्रालय को पी.जी.सी.आई.एल., गुडगांव के संबंधित प्राधिकारियों को तत्काल निदेश देने चाहिए कि वे अपने निगरानी तंत्र के अंतर्गत बोडोलैंड क्षेत्र के भीतर कोकराझार जिले में आरजीजीवीवाई लागू करें। इस संबंधित परियोजना को लागू करने संबंधी कार्यों को करने के संबंध में एएसईबी द्वारा की गई मांगों से सहमत न होने का कारण यह है कि पीजीसीआईएल के कार्यों की गुणवत्ता और स्तर एएसईबी की तुलना में कहीं अच्छा है।

भारत सरकार को विशेषकर बोडोलैंड क्षेत्र के अंतर्गत आदिवासी गांवों में और असम के जिलों में भी निशुल्क ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

विद्युत मंत्रालय असम राज्य विद्युत बोर्ड (एएसईबी) के संबंधित प्राधिकारी को तुरंत निदेश करे कि असम में विभिन्न जिलों हेतु स्वीकृत आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में लागू किया जाए।

विद्युत मंत्रालय बोडोलैंड क्षेत्र के अंतर्गत शेष जनजाति आदिवासी गांवों में आरजीजीवीवाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 500 करोड़ रु. की आवश्यक निधि की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

केन्द्र को नार्थ ईस्टर्न पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना करनी चाहिए।*

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, देश में बिजली की अभूतपूर्व कमी है। सभी सांसदों ने बिजली की कमी के बारे में सदन में कहा है। अनेक सांसदों ने कहा है कि हमारी सरकार इतनी गंभीर स्थिति पर भी गंभीर नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछली बार इसी सरकार ने बिजली की कमी को देखते हुए अमरीका के साथ परमाणु समझौता किया था और यह कहा था कि हम जल्दी बिजली उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन परमाणु से बिजली आने में 10-15 साल लगेंगे। सरकार ने यह भी कहा था कि देश में अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। लेकिन अभी तक एक भी प्रोजेक्ट नहीं लगा है। सरकार ने अपनी वाह-वाही के लिए यह सब कहा था।

महोदय, मंत्री जी महाराष्ट्र से ही आते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में सबसे ज्यादा बिजली की कमी महाराष्ट्र में है। वहां 40 प्रतिशत बिजली की कमी है। 6500 मेगावाट बिजली की कमी होने के काराण महाराष्ट्र में रोजगार कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। किसानों को बिजली के कनैक्शन नहीं मिल रहे हैं। यदि मंत्री जी इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो मैं उनकी बात से सहमत हूं। राज्य सरकार द्वारा यदि बिजली नहीं दी जा रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि केन्द्र सरकार को मदद नहीं करनी चाहिए।

महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां एक पावर प्लांट है, जिसकी बिजली उत्पादन क्षमता 2340 मेगावाट की है, लेकिन वहां कभी भी 2340 मेगावाट बिजली नहीं बनी है। उसकी क्षमता के अनुसार कभी बिजली नही बनती है। इसका परिणाम यह है कि महाराष्ट्र के प्लांट की क्षमता यदि 13 हजार मेगावाट है, लेकिन बिजली का उत्पादन सात-आठ हजार मेगावाट ही होता है। देश के सभी पावर प्लांट्स में पूरी क्षमता से बिजली निर्माण हो, इसके लिए आपको मॉनिटरिंग करनी चाहिए। राज्य सरकार अथवा उनके बोर्डों पर निर्भर न रहे। देश में बिजली की कमी से पूरा देश त्रस्त है, परेशानी बढ़ रही है। अनेक कारखानों में तीन की जगह दो शिफ्टों में काम होने की वजह से लोगों को काम नहीं मिल रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है। यह एक गंभीर विषय है।

महोदय, यहां कोयला मंत्री नहीं हैं। देश के बिजली घरों को कोयला नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ट्रैडर्स को कोयला नीलाम किया जा रहा है। ऐसा कहीं नहीं होता है। इस मामले को ऊर्जा मंत्री जी

[श्री हंसराज गं. अहीर]

को गंभीरता से लेना चाहिए। कोयला बिजली घरों को पहले दिया जाना चाहिए। शरद यादव जी ने कहा कि जितने कोयले के ब्लॉक्स का आबंटन किया जा रहा है, उनमें से सिर्फ 20 प्रतिशत ही बिजली घरों के लिए दी गई। 80 प्रतिशत कोयला निजी लोगों को दिया गया। यह गंभीर विषय इसलिए है, क्योकि बिजली की इतनी कमी होने के बावजूद सरकार गंभीर नहीं है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और जितने भी राज्य सरकार के प्लांट हैं, उनके नियंत्रण के लिए. ..*(व्यवधान)* मैं कोयला मंत्रालय की एक बात बताना चाहता हूं।.. .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कोयले के बारे में नहीं, पावर के बारे में बोलिए।

श्री हंसराज गं. अहीर : सभापति महोदय, पावर प्रोजेक्ट को कोयला नहीं दिया जा रहा है। 90 प्रतिशत कोयला दिया जाता है और कहा जाता है कि दस प्रतिशत कोयला विदेश से आयात किया जाए। यह कौन सी नीति है, जब देश में पावर प्लांट टोप प्रायरटी पर चलता है तो बाहर से कोयला लाने के लिए क्यों कहा जाता है?

सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा एक ही मुद्दा है कि हमारे नागपुर में मोदा प्रोजेक्ट एक हजार मेगावाट का एनटीपीसी का बन रहा है, जिसके बनने के लिए आपने स्वीकार किया था। जब कि इन्होंने पहले कहा था कि दो हजार मेगावाट का बनेगा। इसके लिए मैं मांग करता हूं कि उसका विस्तार किया जाए, उसे दो हजार मेगावाट का बनाया जाए। देश में सबसे अधिक किसानों ने जहां आत्महत्या की है, वह यवतमाल जिला है, जो मेरे क्षेत्र में आता है। मैं मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि एनटीपीसी का एक हजार मेगावाट का प्लांट यवतमाल जिले में बनाया जाए। मेरे यहां निजी पावर प्लांट के उदघाटन में मंत्री जी आए थे।...*(व्यवधान)* वर्धा पावर प्लांट के लिए मंत्री जी ने मंच पर घोषणा की थी कि जिस जिले में बिजली का उत्पादन होता है, जहां पावर प्लांट है, उस जिले में लोड शेडिंग नहीं होगी। आपने वहां यह घोषणा की थी, मेरे पास उसकी सी.डी. भी है। मैं विनती करूंगा कि आप जब जवाब देंगे तो कहिए कि जिस जिले में बिजली बनती है, उस जिले में बिजली की कटौती नहीं होगी, इस बारे में आप घोषणा करें।

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जैसा कि विशेष सूत्रों से पता चला है कि देश में आगामी 25 साल के बाद कोयले के भंडारण में बड़े पैमाने पर कमी आने की संभावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पनबिजली एनएचपीसी योजना पर अभी से अगर विशेष ध्यान दिया जाएगा तो भविष्य में कोयले से उत्पन्न होने वाला जो संकट है, उससे हम निजात पा सकेंगे।

मैं आपका ध्यान टिहरी डेम की तरफ ले जाना चाहूंगा, जो लगभग 25 साल से बन रहा है। वहां 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन आज तक एक हजार मेगावाट तक ही लक्ष्य पहुंच पाया है। अगर बरसात की कमी ज्यादा हो गई तो भी उत्पादन में कमी हो जाती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो 1400 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य है, वह कब तक पूरा होगा और इसमें देरी क्यों हो रही है?

मैं पनबिजली के बारे में मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और भूटान के पास के क्षेत्र बहुत ही उपयुक्त हैं। जैसे कि बिहार के हमारे साथियों ने ध्यान दिलाया कि अगर वहां बिजली के संयंत्र लगा दिए जाएं तो बाढ़ से भी बचाव होगा और जब डेम बनेंगे तो उससे किसानों को बड़े पैमाने पर सिंचाई के साधन मिलेंगे। मैं आपका ध्यान भाखड़ा-नंगल बांध की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो लगभग तीन सौ करोड़ से बना था। आज उसका फायदा कई प्रांतों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 15 वर्षों में 1826 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मात्र 420 मेगावाट उत्पादन की क्षमता स्थापित हुई। मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश को पूरी बिजली मुहैया कराने के लिए उन्होंने दादरी में बहुत बड़ा प्लांट लगाने का कार्य किया और वह लग भी गया, लेकिन कतिपय कारणों से गैस कनैक्शन या गैस के रेट न तय हो पाने की वजह से या जो भी कोई पोलिटीकल मैटर रहा हो, उससे उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि उसमें जो भी बाधा हो, उसे अगर आप दूर करेंगे तो उत्तर प्रदेश के किसानों के हर खेत में पानी पहुंचेगा। हमने बिजली के लिए पूरे देश के किसानों को मुफ्त में बिजली मिले, जिससे देश का विकास हो, इसके लिए हमने आपको अविश्वास प्रस्ताव के समय साथ दिया था।

माननीय सभापति महोदय, शहर और गांव में बिजली देने में बहुत भेदभाव किया जाता है। शहरों में ही नहीं, गांवों में भी लोग रहते है। गांवों में बड़े पैमाने पर कटौती कर के शहरों में बिजली दी जाती है। वहां अगर एक दिन बिजली नहीं रहती है, तो हाहाकार मच जाता

है। गांवों में महीनों बिजली नहीं रहती है, लेकिल अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती।

महोदय, विद्युत उत्पादन का जो लक्ष्य प्रति वर्ष रखा जाता है, हमेशा देखा जाता है कि वह आधा भी पूरा नहीं होता है। मैं बिजली चोरी के संबंध में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी होती है। अगर इस पर आप रोक लगाएं, तो निश्चित तौर से रैवेन्यू की बढ़ोत्तरी होगी।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज भी उत्तर प्रदेश में डेढ़ लाख परिवारों के लोग ढिबरी की रोशनी में जीने का काम करते हैं। ढिबरी, यानी एक प्रकार का चिराग होता है, जिससे मिट्टी का तेल डालकर रोशनी की जाती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन डेढ़ लाख परिवारों को आप कब तक बिजली देने का काम करेंगे?

महोदय, अंत में, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो किसान निजी नलकूप लगाने का काम करते हैं, उन किसानों को तार और खम्बे का जो एस्टीमेट बनता है, उस पर सब्सिडी दीजिए, ताकि वे निजी नलकूपों के पाध्यम से अपने खेतों की सिंचाई कर सकें।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत अभारी हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मंत्री जी, आपके द्वारा हिन्दी में अपना भाषण शुरू करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर हमारे साथी श्री उदय सिंह जी ने अपना भाषण बिहार से शुरू किया और उसका आखिरी भाषण उत्तर प्रदेश के श्री तूफानी सरोज ने किया। इस प्रकार देखें, तो एक परिक्रमा पूरी हो गई। बिहार से प्रारम्भ होकर, उत्तर प्रदेश में, बिहार के नजदीक हम फिर आ पहुंचे और इन मांगों का अंतिम भाषण श्री तूफानी सरोज का हुआ। चूंकि यह राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है, यह कोई एक प्रान्त का विषय नहीं है, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों को पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, तीन साल पहले मैं इस विभाग में आया, प्रधान मंत्री जी ने मुझे बुलाया। मैं गवर्नर था वहां से मुझे आमंत्रित किया और फरवरी, 2006 में मैंने ऊर्जा मंत्री के रूप में चार्ज लिया। अब तक मुझे केवल तीन ही साल हुए हैं। जब 10वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति में लगभग एक वर्ष ही शेष था, तब मैं इस मंत्रालय में आया था जब 10वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, तब मैंने रिव्यू करना शुरू किया कि कहां हमारी गलती हुई, जिसके कारण हम विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए। किसी को तो यह देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी आप जैसा एक सदस्य हूं, चाहे इधर बैठूं या ऊधर। मैंने यह सब देखा, इसमें इंट्रोस्पैक्शन किया और कई चीजें इसमें पूछीं तथा जहां गलती थी, उसे करैक्ट करने का प्रयास किया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि आठवीं, नौवीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं, यानी पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे देश में बिजली उत्पादन की कैपेसिटी में कितना एडीशन हुआ। विगत 15 सालों में हमारे देश ने केवल 56 हजार मैगावाट कैपेसिटी निर्मित की। हमारे उदय सिंह जी और कई अन्य माननीय साथियों ने इस पर टीका-टिप्पणी की और कहा कि विद्युत को कन्करेंट लिस्ट में इसलिए लाया गया, ताकि केन्द्र सरकार इस बारे में कड़ाई से काम कर सके। इसीलिए मैंने 10वी पंचवर्षीय योजना के अंत में, देश के सभी विद्युत मंत्रियों, मुख्य मंत्रियों और अंत में प्रधान मंत्री को बुलाया और सबसे विनती की कि जब तक राज्य बिजली निर्माण नहीं करेंगे, तब तक बिजली निर्माण का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत सरकार तो इस संबंध में सप्लीमेंट्री काम करती है।

आज देश में पूरा काम देखा जाये तो आज बिजली की इतनी कमी है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि हम इसको पूरा करने के लिए कैसे प्रयास कर रहे हैं। हमने रिव्यू लिया, इंट्रोस्पैक्शन किया। यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में एक महत्वपूर्ण बात हमारे ख्याल में आ गई कि 41,110 मैगावाट टार्गेट किया, लेकिन 20 हजार के ही ऑर्डर्स हमने वहां बुक किये थे और बाकी बचे हुए 21 हजार मैगावाट की मशीनरी के ऑर्डर्स ही नहीं हो पाये थे। इसलिए जब हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे थे, तब सबसे पहला हमने काम किया कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के आखिरी साल में उसके ऑर्डर्स देना शुरू कर दिया और यह प्लान कर दिया कि 78,755 मैगावाट का हमने एक टार्गेट रखा है। आज इस घड़ी तक 11वीं योजना में काम के लिए 80 हजार मैगावाट के ऑर्डर्स दिये जा चुके हैं।

[श्री सुशीलकुमार शिंदे]

काम नहीं हुआ है, यह बात नहीं हुई है, क्योंकि यह हम सब की चिन्ता है, हमारी भी है।...*(व्यवधान)* मैं बताऊंगा, मैं सब बताता हूं। यू.पी. का तो पूरा बताऊंगा, ऐसे छोड़ूंगा नहीं। मैं सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, ताकि आपको पूरी बात पता चल सके और मेरे सभी साथी मुझे सहयोग दे सकें। जो आपने मुख्यमंत्री का बताया तो कई मुख्यमंत्रियों को मैंने लास्ट ईयर सर्कुलर भेजा कि ये सब हमारे जो सांसद हैं, एम.एल.ए. हैं, उनको आप मोनेटरिंग कमेटी में ले लें। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का इसी सदन में मैंने चार दिन पहले बोला था। इसको कई चीफ मिनिस्टर्स ने लिया है। महाराष्ट्र में लिया है, उत्तर प्रदेश में नहीं लिया है, बिहार का मुझे पता नहीं है कि बिहार में लिया है कि नहीं लिया है। लेकिन अभी मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप सब लोगों का यह कहना है तो मैं अगले हफ्ते में सभी चीफ मिनिस्टर्स को एक और चिट्ठी लिखूंगा कि हाउस में जो हमारे सब साथी हैं, उनको आप नहीं बुलाते हो, उनसे मालूमात भी नहीं करते हो। हमने कमेटी में मोनेटरिंग करने का काम उनको दिया है। मैं खुद उसमें चिट्ठी लिखूंगा। मैं आपसे जाते-जाते बस इतना ही कहूंगा।

मैं आपको यह बताऊंगा कि जब हम यह सब मोनेटरिंग कर रहे थे तो यह ख्याल में आ गया कि हमारे देश में एक ही बिजली की मशीनरी उत्पादन करने का कारखाना है, जो भेल है, जिसकी कैपेसिटी 6 हजार मैगावाट की है और हम हर साल बड़ी तादाद में 10-15 हजार मैगावाट बिजली क्षमता जोड़ने जा रहे हैं तो हम इसको कैसे कॉप-अप करेंगे। हमारी सरकार की यह फैक्टरी है। आज देखा जाये तो सभी ऑर्डर्स चाइना में जा रहे हैं, कहीं फ्रांस में जा रहे हैं, कहीं जर्मनी में जा रहे हैं, लेकिन इसमें यहां दिक्कतें आ रही थीं। हमने उनके साथ बैठकर भी तय किया कि यहां ज्यादा मशीनरी लगानी चाहिए। इसके लिए हम आपको जो भी मदद करनी है, ऑर्डर्स देने हैं तो ऑर्डर्स भी हम दे देंगे। यह बात हमने कर दी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि भेल का प्रोडक्शन 10 हजार मैगावाट तक जा रहा है और यह 11वीं पंचवर्षीय योजना में 15 हजार मैगावाट तक चला जायेगा।

यहीं हमने रोक नहीं लगाई, क्योंकि यह कम्पीटीशन का युग है। सन् 2003 में जो इलैक्ट्रिसिटी एक्ट की बात आप कह रहे हैं, जिसमें बिडिंग प्रोसीजर और कम्पीटीशन पर एक तो सस्ती बिजली देने का और अनइंट्रप्टिड बिजली देने का वचन हमने इस देश को दिया है। चाहे सरकार किसी की भी हो, सन् 2003 में तो हम नहीं थे, लेकिन इस देश को आश्वस्त किया है, हम कैरीफारवर्ड कर रहे हैं तो यह नहीं बोल रहे हैं कि वह सरकार बी.जे.पी. की थी और हम नहीं करेंगे। यह देश की, राष्ट्र की चिन्ता है। उसके लिए हम काम करेंगे और जब भेल में हमें और भी ज्यादा मदद चाहिए थी तो हमने यह विचार किया कि इंडीजिनस ट्रांसफर आफ टैक्नोलोजी क्यों न हम कर दें। बाहर के, परदेस के बहुत अच्छे लोग यहां आ रहे हैं, एल्सटॉम है, सीमेंस है, अन्साल्डो है, तोशीबा है तो हमने वह प्रयास भी किया और आज मुझे इस सदन को बताने में खुशी हो रही है कि आज 4-5 बाहर के कारखाने जोइंट सैक्टर में भारत में आ रहे हैं। एक कारखाना एम.एच.आई, का आ रहा है, वह जापान का है, लार्सन एंड टूब्रो के साथ उनका एग्रीमेंट हो गया है और उसका काम भी हमारे गुजरात में शुरू हो गया है। दूसरी फैक्ट्री आ रही है, जो एल्सटाम के साथ है, भारत फोर्ज हमारे देश की बड़ी कंपनी है, उसके साथ एग्रीमेंट हो गया है, तीसरा तोशीबा का जेएसडब्ल्यू के साथ एग्रीमेंट हो गया है, अंसाल्डो का मेरे ख्याल से जीबी इंजिनियरिंग के साथ एग्रीमेंट हो गया है और सीमेंस का भेल कंपनी से एग्रीमेंट हो गया है। इस तरह मशीनरी बनाने वाले जो कारखाने हैं, इसके लिए हमने यह भी प्रयास किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि बैलेंस आफ प्लांट की बड़ी तकलीफ होती है। कारखाना तैयार है, लेकिन ऐश हैंडलिंग प्लांट और एयरकंडीशन प्लांट, आदि नहीं होते हैं, कारखाना रेडी है, पर बैलेंस आफ प्लांट नहीं होता है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो पांच-छः कारखाने आ रहे हैं, उनमें से एक-दो कारखाने को बोल रहे हैं कि-

[अनुवाद]

केवल एक ही उत्पाद पर ध्यान दें ताकि सब उसकी मांग करे और उन्हें मांगों की पूर्ण सुरक्षा भी मिलेगी।

[हिन्दी]

यह युग सुपर क्रिटिकल का है। हमारे साथी ने यहां कहा था कि कार्बन बचाने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा और जब क्लाइमेंट चेंज की बात कर रहे हैं, कल ही अमेरिका के कई प्रमुख लोग और डाक्टर टॉड मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा कि भारत जरूर इस तरह की प्रगति कर रहा है कि सुपर क्रिटिकल 660, 800 और 1,000 मेगावाट यूनिटों की ओर जा रहा है। फिलहाल 250 मेगावाट यूनिट की हमारी जो मशीनरी बनाने की क्षमता थी, वह पांच सौ तक बढ़ी और पांच सौ से बढ़कर आज भेल 660 सुपर क्रिटिकल बनाने के काम में लगा है। हमें इस बात का गर्व है कि भारत इस तरह

की टेक्नालाजी ट्रांसफर करके, इस तरह की बड़ी-बड़ी मशीन्स बनाने जा रहा है। हमने सब तरफ से इसे इकट्ठा करने का प्रयास किया है।

मेरे भी दिल में भी यह आता था कि जब हम कर नहीं पाते तो इतना बड़ा टारगेट क्यों लेते हैं? 41,110 का टारगेट ले लिया, तो 21,180 ही किया, लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक हम बड़ा टारगेट नहीं रखते हैं, तब तक हम उस स्टेज पर नहीं जा पायेंगे, क्योंकि कई बार इसमें स्लिपेज होते हैं। स्लिपेज इसलिए होते हैं, कई बार गैस नहीं मिलती है, कई बार मशीनें नहीं मिलती है, कई बार जमीन और पानी मिलने में देर होती है। जब स्लिपेज होते हैं, तो एचीवमेंट में भी कमी आती है। ग्यारहवीं योजना के लिए 78,700 मेगावाट का हमने यहां टारगेट किया, 80,000 मेगावाट के हमने ऑर्डर्स बुक कर दिए, लेकिन आज भी हमारे दिल में यह डर है क्योंकि हम 78,000 तक नहीं पहुंच पायेंगे। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से हम मानिटरिंग कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि हमने एक ऐसा ग्रुप मानिटरिंग करने के लिए बनाया है, चाहे थर्मल हो, चाहे हाइड्रो हो, आजकल हम न्यूक्लियर पर नहीं जाते हैं, लेकिन हाइड्रो और थर्मल पर जाते हैं। कुछ सीनियर इंजीनियर्स हैं, चाहे प्राइवेट हों या गवर्नमेंट की यूनिट्स हों, वहां जाकर मानिटरिंग कर रहे हैं। ये ऐसे मानिटरिंग करते हैं कि वहां उनको पैसा मिला या नहीं, इस बैंकिंग से पैसा मिल रहा है या नहीं, क्या उससे काम रुका है, उनको कोल लिंकेज मिला है या नहीं, गैस मिली है या नहीं, जमीन मिली है या नहीं, कुछ दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव अड़चनें आ रही हैं या नहीं, इस तरह की मानिटरिंग करने के लिए हमने रिटायर्ड आफीसर्स की एक कमेटी बनायी है। डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी इसकी हर महीने बैठक करते हैं और मैं हर तीन महीने में उसकी बैठक लेता हूं। मानिटरिंग करते वक्त जब मैं खुद मानिटरिंग करता हूं, जब मुझे लगा कि थोड़ा सा स्लिपेज हो रहा है, तो मैंने यह सोचा कि जैसे किसी भी देश में वार चालू होता है, तो उस देश के रिटायर्ड जनरल्स को बुलाया जाता है। मेरे डिपार्टमेंट में पहले जो छः-सात पावर सेक्रेटरी थे, उन सभी को मैंने बुलाया और एडवाइजर टू मिनिस्टर कहकर उनका एप्वाइंटमेंट किया है, शायद आज ही उनके ऑर्डर्स निकले होंगे। वह चाहे शाही जी हो, राजदान हो, पंडित हो, अब्राहम हो, कुछ और भी हैं, एक कोल मिनिस्ट्री से सेक्रेटरी लिया है और फिक्की से भी लिया है।

सी.आई.आई. से भी एक लिया है कि वे हमें एडवाइस करें ताकि पता लगे कि हम कहां हैं। हम खुल्लम-खुल्ला चर्चा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि छुपाकर करना चाहते हैं। हम इसे देश की प्रगति के लिए करना चाहते हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में आज जो चिन्ता प्रकट कर रहे थे, मुझे इस बात की खुशी है। आपने उन्हें हम सबका नेता बोला। मैं आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि आप पावर मिनिस्टर रहे हैं। मैंने सिंह साहब का भाषण बहुत गौर से सुना। मैं बता रहा था कि एडवाइस करने के लिए मैंने एक कमेटी बनाई है, क्योंकि हमारी टास्क फोर्स से भी कभी चूक हो सकती है। जो सीनियर सैक्रेटरी थे, उन्होंने इस डिपार्टमैंट को चलाया है। उन्हें पता लगेगा कि वहां दिक्कतें हैं। वे एडवाइस करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जो रिव्यू लिया है, इस घड़ी हमारे पास एक लाख 50 हजार 612 मेगावाट कैपेसिटी है। 11वें प्लान में आज तक 15,325 मेगावाट कैपेसिटी एडिशन हो गया है। आपने डर जताया कि दो साल में इतना ही किया है और अभी तीन साल बाकी हैं, तो कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी देर लगती है। अभी यह शुरू हुआ है और काम झटपट हो जाएगा। बीच में क्यों कम हो जाएगा, वह एकाउंट भी मैं आपको दे दूंगा। अंडर कांस्ट्रक्शन प्रोजेक्टस में हाई डिग्री सर्टेनिटी 41 हजार 447 मेगावाट की है। यह सब मिलाकर 56 हजार 522 बनाना है।

[अनुवाद]

वे परियोजना जो अधिक प्रयास से सामने आ सकती है

[हिन्दी]

9 हजार 702 है, यानी, 66 हजार 224 मेगावाट, इतने प्रोजैक्ट आ ही जाएंगे। लेकिन इसमें जो 10 हजार कैपटिव है, उसे हमने अभी नहीं पकड़ा है। जो 12वें प्लान में आने वाले थे, मुझे आज सुबह ही कुछ लोगों ने कहा कि यदि हमें कोयला दे दिया गया तो हम 11वें प्लान में लाएंगे। मैंने इमीडिएटली फोन करवाया कि क्या वे कोयला दे सकते हैं। यह प्रयास भी हम कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में जब डीपीआर स्वीकार करते हैं, तो पहली कंडीशन होती है कि आपके राज्य को 6 से 8 घंटे अनइंटरप्टेड बिजली देनी चाहिए। जब उन्हें यह मान्य होगा तब सिगनेचर करके हम डीपीआर स्वीकार करते हैं। आपने बताया कि कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सिगनेचर किया, आधा काम हो गया लेकिन वे बिजली नहीं देते। मैं समझ सकता हूं कि कई जगह बिजली कम हो सकती है। हम इसे कर रहे हैं और हमने सन् 2009 का जो प्रौमिस किया है, उसी की वजह से वह 2010 हो सकता है। सन् 2012 तक हर घर में बिजली मिल जाएगी, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। जब यूपीए सरकार सत्ता में आई तो उसने इस देश को स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था। उन्होंने देश में पहला सबसे बड़ा काम यह किया था।

[श्री सुशीलकुमार शिंदे]

हमारे साथी अभी एनरॉन की बात कर रहे थे। एनरॉन में भी 10 हजार करोड़ रुपये देकर, श्री प्रणब मुखर्जी उसके चेयरमैन थे, जिससे ऐग्रीमैंट हो गया और वह कम्पनी बंद हो गई थी, यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद उसे चालू कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो लैंडर्स थे, उन परदेसी लोगों का पैसा भी दे दिया। जब तक कौन्फीडैंस नहीं आता कि भारत इस तरह का देश है कि यदि हमने वहां कुछ इन्वैस्टमैंट किया तो उसे ले सकते हैं, तब तक इन्वैस्टमैंट नहीं हो सकता। वह इन्वैस्टमैंट किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूएमपीपी के लिए आप जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रौजेक्ट की बात कर रहे थे, उसके रोड शो के लिए हम गये थे। वे नौ अल्ट्रा मेगा पावर प्रौजेक्ट्स थें। उस समय हमारे यहां अमेरिका के जो ऐम्बेस्डर वाइजनर थे, वे उस समय एनरॉन में इन्वाल्व थे। उन्होंने कम से कम 300 अमेरिकन्स के सामने भारत की तारीफ की और कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है, जो कमिट करता है, देता है। भारत के कालर टाइट होते हैं जब मिस्टर वाइजनर जैसे आदमी ऐसे कहते हैं। यह किसने किया? यूपीए सरकार में डा. मनमोहन सिंह जी ने यह काम किया, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो अच्छा काम हो गया, उसे हम बुरा कहें। इसलिए मैंने कहा कि वर्ष 2003 का हमारा जो एक्ट है, वह बहुत अच्छा है। अभी यहां उसकी चोरी के बारे में बताया गया है। ओपन एक्सेस के बारे में भी यहां जो कुछ कहा गया, उसे भी में बताऊंगा, लेकिन उसमें बहुत देर लगेगी। मैं यूएमपीपी के बारे में कहना चाहता हूं कि हमने नौ यूएमपीपी फ्लोट किये। एक अल्ट्रा मेगा पावर प्रौजेक्ट 16 हजार करोड़ रुपये यानी फोर बिलियल डॉलर्स का है। वह प्रौजेक्ट 4000 मेगावाट का है। मुझे इस सदन में बोलते हुए खुशी हो रही है कि हमने अभी तक तीन प्रौजेक्ट्स दे दिये हैं। मुन्द्रा, सासान, कृष्णापट्टनम को दे दिये हैं। तिलैय्या प्रौजेक्ट में फारेस्ट क्लीयरेंस मिलने में कुछ प्रौब्लम थी, अभी उसे भी हमने दे दिया है। ऐसे हमारे चार यूएमपीपी प्रौजेक्ट्स चले गये हैं। उनका इसमें कैलकुलेशन नहीं किया गया है। वे चार-चार हजार मेगावाट के हैं। अभी उड़ीसा के हमारे साथी कह रहे थे, उनका नाम इस समय मेरे दिमाग में नहीं है। उन्होंने वहां स्पॉट दिया है, हम करने के लिए तैयार हैं। अभी छत्तीसगढ़ में हमने एनटीपीसी के साथ चार हजार मेगावाट का, वह यूएमपीपी नहीं है, लेकिल वहां एनटीपीसी के साथ एग्रीमैंट हो गया है। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं। हम चीफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और कह रहे हैं।

मैं सदन को बताना चाहूंगा कि रिव्यू आफ कैपेसिटी एडशिन की मीटिंग भी मैंने जून, 2009 में ली थी। जैसे ही नयी सीकार बनी, वैसे ही मैंने उनके साथ तुरंत मीटिंग की थी। मैंने 23 जून, 2009 को दूसरी बार स्टेट पावर मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई। आप पहली मीटिंग में आये थे। अभी बिहार के हमारे पुराने साथी कांग्रेस के हैं। वे वहां जाते हैं। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वे काम करते हैं। 9 जुलाई, 2009 को रिव्यू आफ कैपेसिटी एडीशन की सैकिंड मीटिंग हुई। 14 जुलाई को हमने एक मीटिंग की थी। देश में प्राइवेट डेवलपर्स जो मशीन्स लगाने या बिजली निर्माण का काम करते हैं, उनकी हमने अभी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मैंने पूछा कि उनको क्या-क्या दिक्कतें हैं। उन्होंने मुझे अपनी दिक्कतें बतायी थीं। अभी मैंने मैनुफेक्चरिंग यूनिट के जिन पांच नये लोगों के बारे में बताया कि वे आ रहे हैं, उनसे भी मैंने 16 तारीख को मीटिंग की थी।

यह भी बताया गया था कि कई बार बैंक से लोन नहीं मिलता, तो हमारे यहां पावर फाइनेंस कार्पोरेशन और रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन है। पावर कार्पोरेशन से हमने अभी तक 1,98,749 करोड़ रुपये का लोन सैंक्शन किया है और डिसबर्समैंट अभी तक 72 हजार के ऊपर हो गया है। अभी यह काम चालू है। रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन का डिसबर्समैंट 42 हजार 883 रुपये का हुआ है। हमारे कार्पोरेशन इस तरह काम कर रहे हैं जिससे बिजली निर्माण का काम तेजी से हो। इसे भी हम मानिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। मेरे पास कई रिकाड्र्स हैं। हमारे जो एक्सीलेरिटेड पावर प्रोग्राम हैं, उसमें हम अभी नयी योजना लाये हैं। उनमें पहले जो एपीडीआरपी योजना थी, उसे बदल दिया गया है।

नयी योजना में और ज्यादा इनसेन्टिव्स स्टेट्स को मिलेंगे क्योंकि जो लोन अभी हम दे रहे हैं, वह ग्रांट में कनवर्ट हो जाएगा। आपने चिन्ता व्यक्त की है कि टी एंड डी लॉस है, पुरानी मशीनरी होने से बहुत नुकसान हो रहा है। ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, अब हम 400 केवी की लाइन पर जा रहे हैं ताकि बिजली की चोरी कम हो जाए। पिछले साल हमने बिजली चोरी को रोकने के लिए कानून पास किया है, बिजली चोरी के विरुद्ध पूरे देश में एक वातावरण पैदा हो गया है, आज हजारों केसेज दर्ज होने शुरू हो गए हैं। अभी माननीय सदस्य उदय प्रताप सिंह जी कह रह थे कि नरसिंहपुर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का काम नहीं हो रहा है। हमने मार्च, 2008 में इसे सैंक्शन कर दिया है और इसकी कॉस्ट 39.75 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

राज्य सरकार ने सरकार द्वारा स्वीकृति के 15 माह बीत जाने के बाद भी कार्य प्रदान नहीं किया है।

[हिन्दी]

हमने तो सैंक्शन कर दिया है, लेकिन वे नहीं देते हैं। उज्जैन का भी ऐसा ही मामला है। वह टेंथ प्लान का है, उसकी कॉस्ट 40.76 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

काफी धीमी गति से काम हो रहा है और 20 प्रतिशत

[हिन्दी]

काम वहां हो गया है। कायंकुलम थर्मल पावर स्टेशन के बारे में आपने कहा है। वहां 2x1,000 मेगावाट का प्रौजेक्ट है। लेकिन यह अभी प्रॉशेस में है, हम इसे देख लेते हैं क्योंकि एग्जैक्टली इसके फिगर्स हमारे पास नहीं हैं। कहलगांव के बारे में माननीय सदस्य ने कहा था, वह बहुत एक्टिव एविएशन मिनिस्टर रहे हैं, दो बार इस सदन में चुनकर आए हैं, जब मैं वहां गया था तो वहां थे और मैंने जो निर्णय लिए उससे वह बहुत खुश भी थे। उन्होंने मुझे वहां दुबारा नहीं बुलाया, शायद इसीलिए काम रुका होगा। कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन में स्टेज-वन में तो 840 मेगावाट एग्जिस्टिंग है और स्टेज-टू में

[अनुवाद]

एन.टी.पी.सी. द्वारा 1500 मेगावाट की स्थापना की गई है। 500 मेगावाट प्रत्येक की दो इकाइयां

[हिन्दी]

कॉमर्शियल आपरेशन में है। जो थर्ड यूनिट है, वह सिंक्रोनाइज हो गयी है, अगर आप बुलाएं तो शायद मैं फिर वहां आ सकता हूं। मैं जब विंध्याचल गया था, वहां मैंने देखा और एक-दो जगह मैंने देखा है कि जहां हमारी पावर यूनिट्स हैं, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाशघर है लेकिन उससे एक किलोमिटर आगे जाने पर अंधेरा ही अंधेरा मिलता है। मैंने विंध्याचल में भी और आपके यहां आपके सामने ही एनाउंस कर दिया था कि हमें इसके लिए कुछ करना होगा, कम से कम उसकी पेरीफरी में दस किलोमीटर तक करना होगा। मैं कुछ छिपाता नहीं हूं। हमने इसे सोच लिया था, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल डिफीकल्टीज हैं। आखिर हम बिजली देंगे, लेकिन कहां देंगे। यूजुअली हम इसे ग्रिड में ही देंगे, स्टेट को ही देना पड़ेगा। स्टेट को यह काम देखना होगा और बिल की वसूली करनी ही होगी क्योंकि वह बिल वहां जाता ही है। इसलिए हम यह देख रहे हैं कि कौन बिल लेगा, कैसे मेनेजमेंट होगा, उस पर ट्रांसफार्मर कौन लगाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से बहुत सी जगहों पर काम हो रहा है, इससे लोगों को सुविधा हो जाएगी, लेकिन मैं सभी राज्यों सभी मुख्यमंत्रियों को कहूंगा कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो कि

[अनुवाद]

सरकार ने निर्णय लिया है कि केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्र की 5 किमी की परिधि के अंदर गांवों के ग्रामीण घरों को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान को जाएगी।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : पहले तो आपने ज्यादा का अनाउंस किया था।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : लेकिन अभी पांच किलोमीटर से शुरूआत करेंगे। उसमें थोड़ी दिक्कत थी, पांच किलोमीटर भी स्केयर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए, तो बहुत बड़ा होता है। इस बारे में कुछ स्कीम्स फार्मूलेट करनी होंगी, क्योंकि यह अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। हम जब वहां जाते हैं तो रात में काफी प्रकाश देखते हैं, लेकिन बाहर जब निकल कर थोड़ा दूर जाते हैं तो अंधेरा नजर आता है। मैं काफी दिनों से यह बताना चाहता था, इच्छा किया आपने याद दिला दिया, मुझे इसकी खुशी है। इसमें कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है। हमारे साथी बैसिमुथियारी जी ने बोगाइगांव की बात कही। हम उनकी बात गौर से सुनते हैं। वहां 750 मेगावाट के प्लांट पर काम चल रहा है। आज ही मैंने वहां एनटीपीसी के चेयरमैन और अपने जाइंट सेक्रेटरी को भेजा है। यह राज्य हमारे प्रधान मंत्री जी का राज्य सभा का निर्वाचन क्षेत्र भी है इसलिए भी हम इस काम को जल्द से जल्द करना चाहते हैं।

इस मंत्रालय का कार्यभार संभाले हुए मुझे करीब तीन साल हो गए हैं, जो कि ज्यादा वक्त नहीं है। देश की दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में मैं इस मंत्रालय में आया था और 11वीं पंचवर्षीय योजना का यह तीसरा साल चल रहा है। मुझे पता नहीं था कि अब की बार भी मुझे यह मंत्रालय मिलेगा या नहीं, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे फिर इस मंत्रालय में काम करने का मौका दिया। आप सब जानते हैं कि मैं रात-दिन मेहनत करता हूं, रात के नौ बजे तक दफ्तर में बैठता हूं।

श्री राजीव रंजव सिंह उर्फ ललन सिंह : बाड़ में एनटीपीसी का क्या होगा।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : वह भी बताता हूं, थोड़ा सब्र करें। मेरे पास सब कुछ है। बाड़ में मशीनरी की प्राब्लम है। मैं भी वहां गया था। वह फाइनेलाइजेशन की स्थिति में है।

श्री राजीव रंजव सिंह उर्फ ललन सिंह : बहुत स्लो है।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : थोड़ा स्लो है, यह मैं मानता हूं लेकिन उसमें जिस देश से सहयोग लिया जा रहा है, उससे थोड़ा डिस्प्यूट है, मैं उस कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता। इस वजह से मशीनरी में थोड़ी दिक्कत आ रही है।

उदय सिंह जी ने कहा कि बिहार को अलग तरीके से हम देखते हैं। उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। नीतीश जी भी यहां मंत्री रहे हैं। हम भी उनसे कहते थे। मैं भी मंत्री होने के नाते यह कहना चाहता हूं कि जितना हो सकेगा, हम बिहार की मदद करेंगे। केवल बिहार की ही नहीं, अन्य राज्यों की भी मदद करेंगे। यही बात मैं मध्य प्रदेश के बारे में भी कहना चाहता हूं। लेकिन आप रिकार्ड देखिए, प्रस्तावों को स्वीकार किए हुए नौ-नौ महीने हो जाते हैं, लेकिन राज्यों की तरफ से अवार्ड नहीं आता है। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, लेकिन जिस दृष्टि से इसे देखा जाता है, उससे दिक्कत आ जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि फिर मैं क्या कर सकता हूं। आपने कहा कि बड़े-बड़े बोर्ड लगा दिए यह किसी पार्टी विशेष के बोर्ड नहीं थे। पहले तो बार्ड ही नहीं लगाने देते थे और कहते थे कि हमारी सरकार की योजना है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सही बात है।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : देखा, ये भी कह रहे हैं कि सही है। यह योजना राजीग गांधी जी की ही देन है। इसलिए बड़े-बड़े बोर्ड लगाए हैं। राजीव गांधी जी ने देश को उजाले में रखने का स्वप्न देखा था।...*(व्यवधान)* यह बात सही है कि सांसदों को भी मानिटरिंग कमेटी में रखा जाए, हमने रखा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियो को इस बाबत पत्र लिखूंगा और उसकी कापी सभी सांसदों को एक पत्र के साथ भेजूंगा।...*(व्यवधान)* ऐसा नहीं है कि इससे कुछ नहीं होगा, अगर आप लोग मानिटरिंग करेंगे तो जरूर कुछ होगा। हमारे उदय सिंह जी पूछ रहे थे,

[अनुवाद]

हमारे उदय सिंह जी पूर्णिया जिले के लिए आरजीजीवीआई परियोजना वर्ष 2005 में 52.35 करोड़ रुपये की लागत के साथ स्वीकृत की गई थी। यह स्वीकृत है। परियोजना का लक्ष्य 5083 बिजली रहित गांवों को बिजली प्रदान करना और 25,563 बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना था।

[हिन्दी]

श्री उदय सिंह : यही मैंने कहा था।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : मैं आपको बता रहा हूं कि *[अनुवाद]* पावर ग्रिड कार्पोरेशन वहां कार्यान्वयन एजेन्सी है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार, 1 जुलाई 2009 को 5025 गांवों को विद्युत प्रदान की गई है और 10,354 बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

[हिन्दी]

आपको तो मालूम है कि यहां 90 परसेंट हम सब्सिडी देते हैं, 10 परसेंट स्टेट को देना पड़ता है। यदि हम समाजवाद की बात करते हैं तो बीपीएल का गरीब आदमी कभी भी बिजली नहीं ले सकेगा, उसको हम कनैक्शन देने का काम करते हैं। उसका बिल बहुत आता है, उसके बारे में भी राज्यों को देखना पड़ेगा कि कहां उसको सब्सिडी देते हैं, वह काम भी करना पड़ेगा। सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे तो फिर राज्यों के पास रहा क्या? इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार 90 प्रतिशत सब्सिडी आपको दे रही है, कितना खर्चा हो रहा है। अभी 28 करोड़ रुपये आपने बताया और पिछली योजना में 5000 करोड़ रुपये मिले तथा 28 करोड़ रुपये और मिले और जो सैकिंड फेज में प्रोजैक्ट है, उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर के सामने बोलना नहीं चाहता, मैं भी कभी स्टेट में फाइनेंस मिनिस्टर था, लेकिन सरकार से हम सैकिंड फेज के लिए, जल्दी से जल्दी पैसे की मांग कर रहे हैं और 30,000 करोड़ रुपये चाहिए। इसी सदन में मैंने आपको आश्वासन दिया था कि 300 की संख्या के गांव के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपने 100 लोगों की संख्या से ऊपर के लिए करने को कहा और वह बात हमने मान ली, यह बताने में हमें खुशी होती है। जहां पहले विद्युतीकरण है और अभी उस गांव में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की बिजली पहुंचानी है, उसे इंटैंसिफाई करते हैं, तो उसका भी खर्चा बढ़ गया। यह योजना 16,000 करोड़ रुपये की थी जो अब 5,000 28,000 और 30,000 की हो गयी। यह हमारा वायदा है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के काम में हम आगे रहेंगे और पहले फेज में हमने निर्णय ले लिया है कि जो हमारे बोर्डर स्टेट्स हैं।...*(व्यवधान)* नार्थ-ईस्ट के जिले हमने

ले लिये हैं, नक्सलाइट्स प्रभावित जिले ले लिये हैं। इन सभी जिलों को हमने फर्स्ट फेज में लिया है, लेकिन जो थोड़े से जिले रह गये हैं उन्हें भी हम लेने का प्रयास करेंगे। बरौनी एक्सपेंशन, लखीसराय, चौसा, पिरपेंटी आदि में कोयले के लिए आपने बोला था। कहलगांव और नबीनगर के लिए हमने कोल-मिनिस्ट्री को रिक्मेंड किया है।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : कोल मिनस्ट्री से आप कोऑर्डिनेट करें ताकि स्टेट आत्म-निर्भर बने।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : वह हम कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही यही है कि हम कर रहे हैं।

श्री उदय सिंह : सर, आपने सभी चीजों का बहुत संतोषजनक ढंग से जवाब दिया है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में बहुत अच्छा चल रहा है और हम इस योजना की सराहना करते हैं लेकिन दिक्कत सोशल स्ट्राइफ की हो जाएगी। आपने जिस आंकड़े को कंफर्म किया, यही फिगर में सुबह कर रहा था।

रात्रि 8.00 बजे

महोदय, मेरे यहां 3,66,000 बीपीएल परिवार हैं। अगर उनमें से केवल 25 हजार लोगों को ही हम रोशनी देंगे या कनेक्शन देंगे, बाकी लोगों को नहीं देंगे, तो इतना तनाव हो जाएगा कि लेने के देने पड़ जाएंगे, आपके लिए भी और हमारे लिए भीं

श्री सुशीलकुमार शिंदे : मैंने अभी-अभी आपको बताया कि जिस प्रकार से खर्चा आ रहा है, जिसके पास बिजली नहीं है और जहां बहुत लोग दुखी हैं, उन्हें बिजली देने में दिक्कत है। इसमें 30 हजार करोड़ रुपए लगेंगे, कैसे इतना लोड ले सकेंगे। एक-एक करके काम करेंगे। उसे भी हम देख लेंगे कि क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ट्रांसफारमर की बात कही और नीतीश जी भी बार-बार कहते हैं, जब डीपीआर के प्रोजेक्ट्स आ गए।...*(व्यवधान)* अभी सभी लोग सैटिस्फाई नहीं हुए हैं। मैं दोपहर के दो बजे से यहां बैठा हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ा काम है। 90 प्रतिशत सब्सीडी मिल रही है, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। मैं इतने सालों से राजनीति में हूं, मेरे ख्याल में भी नहीं आया था कि देश में इस तरह काम हो जाएगा, क्योंकि देश में हमारी कुटीर योजना चल रही थी। यूपीए सरकार के आने से पहले कितने घर हो गए थे। आप जरा एनालिसिस कीजिए। आपने बहुत अच्छा कहा है, चाहे उत्तर प्रदेश के हमारे साथी हों, कांग्रेस के हों या अलग पार्टी के हों, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो बिजली की दिक्कत पीक आवर्स में डिमांड 11,080 मेगावाट की है। पीक आवर्स में सप्लाई केवल 8563 की है। पीक डेफिसिट 2517 मेगावाट की है और एनर्जी रिक्वायरमेंट 17,770 मिनियन यूनिट मेगावाट की है और एनर्जी एवेलिबिलिटी 14476 मिलियन यूनिट मेगावाट की है। वहां भी जो डेफिसिट है, वह 3294 मिलियन यूनिट मेगावाट की डेफिसिट है। हमें वहां भी 18.5 परसेंट की डेफिसिट है। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपने भी पीएलएफ के बारे में बताया तथा झारखंड में पतरातू यूनिट का उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश में टांडा यूनिट की बात कहीं, वहां का क्या पीएलएफ था, 20,15,14 लेकिन आज यही टांडा की यूनिट्स 85 पीएलएफ के ऊपर चल रही हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि जबसे एनटीपीसी ने इसे लिया, हम इससे बिजली ज्यादा दे रहे हैं। आज एग्रीमेट और टेक्नीकल लॉसिस 48 परसेंट हैं, लेकिन एपीडीआरपी योजना के बाद, मेरे पास सभी फिगर्स हैं, जो राज्य में काम किया है, वहां 15 परसेंट लास आ गया है, कहीं 20 परसेंट लास आ गया है लास कम हो रहा है और बिजली की कंजर्वेशन उसमें एवायडेड कैपेसिटी जनरेशन होती है, हमने तीन-चार स्कीम्स बहुत अच्छी शुरू की हैं, आपको मालूम होगा। वन स्टार, टू स्टार, थ्री स्टार, फोर स्टार, फाइव स्टार के फ्रिज, फैंस आदि पर स्टार लग कर मार्केट में मान आ रहा है, ताकि बिजली की कंजम्प्शन कम हो। बिल्डिंग कोड हमने लगाया है। बिल्डिंग बनाते समय बिजली कंजम्प्शन कम करने के लिए कोड बनाया है। हमने उसके लिए डैवलपर्स की बड़ी मीटिंग बुलाई इंजीनियर्स की भी मीटिंग बुलाई और उनको यह सब जानकारी दी। दूसरी बात, सीएलएफ से बल्ब्स चेंज करके दे दिये, उससे भी बिजली की बचत होती है। आपको बताने में मुझे इस बात की खुशी है कि अभी तक 1500 मेगावाट एवॉइडेड कैपेसिटी हमने बचाई है। यह कोई सादा बात नहीं है। यह एवॉइडेड कैपेसिटी जो है, एक तो हम हर साल बच्चों का कम्पीटीशन करवाते हैं, बच्चे पेंटिंग करते हैं, 7'-8 लाख बच्चे आते हैं और हम बच्चों को 50,000 का आवार्ड देते हैं और एक लाख का भी पिछले साल अवार्ड कर दिया था क्योंकि वे हमारे एम्बेसैडर के रूप में काम करना चाहते हैं। वे जो पेंटिंग निकालते हैं, उसी पेंटिंग के माध्यम से हम पब्लिसिटी करते हैं कि इस तरह से घर से बाहर जाते वक्त अपने बिजली के स्विच बंद करिए, ए.सी. बंद करिए। जहां आफिस है तो जब बारिश हो गई तो तुरंत ही ए.सी. बंद करिए। इस तरह के कम्पीटीशन हो रहे हैं और एवॉइडेड कैपेसिटी के अंदर है। यह सब काम करते समय हम देख रहे हैं कि जितना हो सके, उतना हम यह काम कर रहे हैं। राजीव गांधी विद्युतीकरण में अभी तक टोटल विलेजेस 1 लाख 18 हजार हैं, उसमें से 62,520 विलेजेज का विद्युतीकरण हो गया है और 62.5 लाख बीपीएल हाउसहोल्ड उसमें हो गये हैं।... *(व्यवधान)*

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) : सर, आप ट्रांसफार्मर के लिए कुछ कह रहे थे।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : वह ट्रांसफार्मर का जो डीपीआर आता है, उसी समय स्टेट के ट्रांसफार्मर का भी आता है तो उसके लिए हम सोच रहे हैं। बिहार के मुख्य मंत्री जी ने भी बताया है, उसमें कुछ करना पड़ेगा। जो भी नये डीपीआर्स बदल रहे हैं, उस वक्त हम भी यह कहेंगे कि बहुत लोगों की मांग हे लेकिन यह सोचिए कि इस देश में कई जगह बिजली नहीं थी, तो वहां बिजली तो अभी जा रही है।...*(व्यवधान)*

श्री जगदीशन शर्मा (जहानाबाद) : सभापति महोदय, आप अगर नहीं करेंगे तो आप उद्देश्य पूरा नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी मान नहीं रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुशीलकुमार शिंदे : जब आपने डीपीआर स्टेट में दिया था, तब क्या आपको मालूम नहीं था कि आपके पास बिजली कम है?...*(व्यवधान)* ऐसे नहीं कहिए। फिर मैं काउंटर एक्ट करूंगा। डीपीआर क्यों दे दिया?...*(व्यवधान)* उसी वक्त थ्री फेज का डीपीआर का देना था। आपने वन फेज का क्यों दे दिया? यह दिक्कत है। मैं आपको इरीटेट नहीं करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : अब कोई प्रश्न नहीं। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री नहीं मान रहे हैं। वे बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर) : मैं सिर्फ एक बिन्दु कहना चाहता हूं तो उसमें आपको क्या आपत्ति है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री जो बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री नहीं मान रहे हैं। कृपया इसे समझिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशीलकुमार शिंदे : अभी भूटान और नेपाल के बारे में आपने कह दिया था कि यहां पन-बिजली के बारे में प्रयास करना चाहिए। मैंने खुद नेपाल के मिनिस्टर से बात की है और भूटान के भी और ज्यादा प्रोजेक्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यह बात सही है कि नेपाल से जो पानी आता है, विशेषकर बिहार में उसका असर होता है, बिहार में दोनों जगह पूर्व और पश्चिम की तरफ समस्या होती है। इसके लिए हम भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। कई जगह उनका सर्वे हो गया था, कैनेडियन गवर्नमेंट का डीपीआर हो गया था, उनकी भी कुछ समस्याएं हैं। हम कह रहे हैं कि हम करेंगे। उन्होंने भी प्राइवेटाइजेशन में एक-दो परियोजनाएं दे दी हैं। इसलिए हम उनसे भी यह कह रहे हैं कि 2000-3000 मेगावाट के हम करना चाहते हैं और उसके लिए आज भी यदि नेपाल को हमारे से पावर जाना है तो आपके बिहार से व चिकन नैक से ही जाता है और उधर से भी आता है।

पिछले साल बाढ़ आ गई थी तो टावर गिर गए थे, चिकन नेक के बारे में बहुत अच्छी तरह से कहा गया कि सिलिगुड़ी से लाइन दे दी। आज हमारे साथी अरुणाचल प्रदेश गए हैं। वहां बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और हमें 50,000 मेगावाट की कैपिसिटी मिल

सकती है। अभी कामेंग, दिबांग आदि तीन-चार प्रोजेक्ट लिए गए हैं, इन प्रोजेक्ट्स से बिजली तैयार होगी। इसके लिए वहां से ट्रांसमिशन लाने के लिए भी प्रोग्राम बनाया गया है और इसके लिए भी काम कर रहे हैं। सिक्किम में जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वहां भी चिकन नेक सिलिगुड़ी में आकर मिलेगा और एक तरफ सिलिगुढ़ी से आएगा और एक तरफ असम से आएगा, अरुणाचल प्रदेश से आएगा। इस तरह इवेकुएशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 14,000 मेगावाट का पावर ग्रिड इंटर स्टेट में ट्रांसमिशन करता था अब यह 20,750 मेगावाट तक हो गया है। हमें यह विश्वास है कि 11वें प्लान तक 38,000 मेगावाट का पावर ग्रिड पूर्ण हो जाएगा।

महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है। हर बार ऐसा ही होता है। हम आई टी आई एडॉप्शन करने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हमने नई पालिसी बनाई है कि जहां एनटीपीसी और एनएचपीसी के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहां खुद का आईटीआई शुरू करें। यह काम बहुत जगह शुरू हो गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अभी तक हमारी आर्गेनाइजेशन ने एनएचपीसी ने 7, एनटीपीसी ने 16, एनएचडीसी ने 1, डीवीसी ने 8, टीएचडीसी ने 2, एसजेवीएनएल ने 2, नीपको ने 2 आईटीआई एडॉप्ट किए हैं और पीजीसीएल 4 करने वाला है। इस तरह से 38 आईटीआई एडाप्ट किए हैं और 13 एडाप्ट करने हैं, जिसमें से एनएचपीसी ने 1, एनटीपीसी ने 6, बीबीएमबी ने 2, पीजीसीआईएल ने 4 एडाप्ट करने हैं। अभी जितने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहां स्पेशल आईटीआई की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी यहां जम्मू-कश्मीर के साथी मौजूद नहीं हैं, कल ही वहां के चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे चर्चा की है कि वे एक अच्छे स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट आईटीआई, आईटीआई और आईआईटी के बीच का सैंटर, खोलना चाहते हैं। उन्होंने वहां के लोकल लोगों के बारे में बताया जिनकी जमीन जाती है और ऑस्ट्रिस का भी कारण बताया। वे हजारों साल से वहां रह रहे हैं जब उन लोगों की जमीन जाती है तो उन्हें थोड़ा सा पैसा मिलता है लेकिन वे कहां खर्च करते हैं यह मालूम नहीं है। इसलिए हमने सोचा उस फैमिली के बच्चों को ट्रेंड करें ताकि वही काम करें। जैसे ही इसकी फाउंडेशन होगी, जैसा कि हमने कहा है कि वहां एक साल के अंदर आईटीआई का काम शुरू करेंगे और बच्चों को ट्रेंड करेंगे, अफेक्टिड लोगों को पहले करेंगे और फिर इर्द-गिर्द के लोगों को काम पर लगाया जाएगा। लोकल लोगों को बहुत से प्रोजेक्ट में नहीं लिया जाता है, यह हमारे लिए दिक्कत की बात है।

महोदय, आज कल जमीन की बहुत दिक्कत हो रही है। हमने एनटीपीसी में अभी शुरू किया है। हमारे सम्मानित सदस्य चंद्रपुर के हैं, उनके यहां मौदा में हमने 6-7 लाख रुपये एकड़ के हिसाब से जगह ले ली है। इसके अलावा और भी कई जगहों पर हमने यह सूचना दी है कि अभी सैक्शन 4 और 8 लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। वह व्यक्ति वहां सैकड़ों सालों से रहता है और अपना घर छोड़कर चला जाता है। उसे थोड़ा पैसा जरूर मिलता है, लेकिन वह बाकी खर्च कैसे चलाता है और उसके बाद उसका सारा जीवन उजड़ जाता है। इसलिए हमने कहा कि यदि उसे निगोशिएशन में थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाए तो वह वहां से खुशी से चला जायेगा।

महोदय, अभी मैं एक प्रोजैक्ट की बात बताता हूं, जो मेरे शोलापुर में लगी है। हमने वहां निगोशिएशन के बाद तीन लाख रुपये एकड़ के हिसाब से जमीन ले ली है। लेकिन वहां पर काम करने वाला जो मजदूर है, वहा कहां जायेगा। मालिक की तो जमीन ले ली, लेकिन उस मजदूर को भी हमने पचास-पचास हजार रुपये फिक्स्ड डिपाजिट पर रखा है और ग्राम पंचायत का सर्टिफिकेट लेकर...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : कहलगांव में तो अभी नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री शाहनवाज, जब मंत्री महोदय अपना उत्तर पूरा कर लेंगे तब मैं आपको एक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। अभी नहीं।

[हिन्दी]

श्री सुशीलकुमार शिंदे : वहां का पहले हो गया।...*(व्यवधान)* यह पहले का है, परंतु अभी जो नया शुरू हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो पहले हो गया, उसका अभी कुछ नहीं करेंगे। जो हो गया है, उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन जो नया हो रहा है, उसका हमने कर दिया है।

[अनुवाद]

यह व्यक्ति और स्थान पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : पहले वालों का क्या होगा?

श्री सुशीलकुमार शिंदे : जो पहले वालों का है, वहां वहीं है, लेकिन अभी तो करना पड़ेगा। तब आप भी नहीं थे और मैं भी मिनिस्टर नहीं था। इसका क्या करें।

सभापति महोदय, आज यहां जो डिस्कशन हुआ है, इस पर कई सजैशंस मिले हैं। यहां बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। राजनीति की एक-दो टोका-टोकी छोड़ दीजिए, लेकिन जिस तरह के विचार यहां प्रकट हुए हैं, उनसे पता चलता है कि आप सभी लोग भी देश की चिंता को समझते हो। इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं।...*(व्यवधान)* आप मुझे बोलने तो दीजिए।...*(व्यवधान)* कांटी के बारे में चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई थी, उसके बारे में हम देख रहे हैं और जो देख रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलें।

महोदय, यहां बहुत अच्छे सुझाव दिये गये हैं, उनके लिए मैं आप सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा निवेदन है कि जो मेरी डिमांड्स हैं, उन्हें सदन मान्य कर दे और जो कट मोशंस हैं, उनके लिए मैं सम्माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि वे उन्हें विदड्रा कर लें।...*(व्यवधान)* अभी उसमें देर है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं तीन प्रश्नों की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, मुझे मंत्री जी से एक क्लेरिफिकेशन लेना है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप अध्यक्षपीठ की बात क्यों नहीं सुनते? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपसे आपका स्थान ग्रहण करने के लिए कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मंगनी लाल मंडल : आप चाहें तो मुझे सदन से निकाल दें...*(व्यवधान)* मैं अपना प्रश्न जरूर पूछूंगा।...*(व्यवधान)* मैंने पहले लिखकर दिया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं आपको स्पष्टीकरण प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इसे कार्यवही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा, लेकिन आप अध्यक्षपीठ की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इस प्रकार व्यवहार न करें। मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री मंडल, इस तरह से व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको सावधान कर रहा हूं। मुझे आपकी पूर्व सूचना मिली है और मैं आपको भी अनुमति दूंगा। लेकिन अब आप आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री शाहनवाज हुसैन जी कृपया अपनी बात जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : सभापति जी, मैंने अपनी बात रखते हुए मंत्री जी से जानना चाहा था कि जो लैंड लूजर्स हैं, उनका क्या कर रहे हैं? आज नंदीग्राम जैसी घटना सब जगह होने की संभावना हो रही है। क्योंकि बीस साल पहले आपने कहलगांव में एनटीपीसी बना लिया, वहां से बिजली का पैसा कमाया और कहलगांव में जिनकी जमीन चली गई हैं, उन्हें आपने नौकरी देने का वायदा किया था और यह कहा था कि जो स्किल्ड वर्कर होगा, उसे ट्रेनिंग देकर नौकरी देंगे। आज वहां के लोग बूढ़े हो गये हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। वहां एक आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से तीन लोगों को गोली लगी। जिसके कारण बिहार सरकार को बहुत संकट का सामना करना पड़ा। मैं सभापति जी के माध्यम से आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जिन भू विस्थापितों की जमीन गई है, उन्हें आंदोलन का रास्ता न अपनाना पड़े। इसलिए वहां के जनप्रतिनिधि के नाते में आपसे

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गुजारिश करता हूं कि आपने उन्हें जो नौकरी देने का वचन दिया है, उस वचन को आप पूरा करें।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : मैंने आपके सामने ही जनरल मैनेजर से बोल दिया है। देखिए जैसे-जैसे पास जगह होती है, वे ले लेते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने उनको अनुमति दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, बिहार के मामले में मैं माननीय मंत्री जी से क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। अभी बिहार के 18 हजार गांव शेष बचे हैं और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत जो गांव कवर्ड हुए हैं, आच्छादित हुए हैं, वे आंशिक रूप से ही हुए हैं। जितने भी माननीय सदस्यों ने दूसरे प्रदेशों की चर्चा की है, उन लोगों ने कहा है कि डीपीआर में गड़बड़ी हुई है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि डीपीआर आपने बनवाया, उसमें सचेष्ट नहीं थे। डीपीआर केंद्रीय सरकार के निर्देश के अनुसार तैयार किया गया है। पहले यह था कि बिहार में जितने गांव कवर्ड हुए हैं, उनमें आंशिक हुआ है, आधा हुआ है, एक तौला हुआ है या चला गया है। आपने पहले सीलिंग की थी, भौतिक उपलब्धि का लक्ष्य रखा था और अब आपने वित्तीय सीमा बांधी है।

सभापति महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही कि जितने भी राजस्व गांव हैं, वे चाहे छोटे हैं, मझोले, बड़े हैं, जनसंख्या में अलग-अलग हैं। उनकी जनसंख्या बड़ी है या छोटी है, लेकिन आपने पहले एक गांव का भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 9 लाख रुपए की वित्तीय सीमा बांधी थी। जब वह नहीं हुआ तो आपने उसका भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 14 लाख रुपए की सीमा बांधी है। इस सीमा से सभी गांवों को कवर्ड नहीं किया जा सकता है और इससे केवल गांव आंशिक रूप से ही कवर्ड होता है। क्या सरकार की ऐसी योजना है, अगर है तो यह योजना त्रुटिपूर्ण है और क्या सरकार इसका निराकरण करेगी?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभी प्रश्न पूछे जाने के पश्चात मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं। दो और माननीय सदस्य प्रश्न पूछने वाले हैं।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, आपके जरिये मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमने कोकराझार जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए चार साल से लगातार प्रयास किये और तब यह सैंशन हुआ। यह आदरणीय मंत्री जी ने सैंशन किया। वर्ष 2007 से वर्ष 2009 तक दो साल टेंडरिंग प्रोसेस में बीत गये, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया है। मुझे मालूम हुआ कि इस प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंट करने के लिए आसाम स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिया गया है। हमारी मांग है कि इसे भारत सरकार, पीजीसीआईएल को ही देना चाहिए। एसीबी पब्लिक अंडरटेकिंग है और यह टोटली फेल अंडरटेकिंग है और उससे कोई काम नहीं बनेगा।

[अनुवाद]

श्री के. बापीराजू (परसापुरम) : विद्युत परियोजनाओं संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद भी विलंब हो रहा है। लेकिन कुछ छोटी-छोटी याचिकाएं हैं। अत: शीघ्र मंजूरी के लिए कुछ समन्वय होना चाहिए ताकि ये परियोजनाएं जल्द आरंभ हो सकें। मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि चूंकि हमने आंध्र प्रदेश में कृषि सेवाएं निशुल्क दी है, इसी प्रकार ये पूरे देश में दी जा सकती हैं। लेकिन यदि राज्य सरकार 50 प्रतिशत के साथ आगे आए तो यह सरकार सहायता कर सकती है। सबसे निर्धन व्यक्ति को सरकार से सहायता की आवश्यकता है; कृपया उन्हें बताएं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने प्रश्न पूछे हैं और उन्होंने विस्तारपूर्वक उत्तर भी दिए हैं। कृपया सहयोग करें।

अब, माननीय मंत्री उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए; हमारे पास समय नहीं है। अब, माननीय मंत्री उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : नि:शुल्क विद्युत देना संबंधित राज्यों के ऊपर है। यदि उनके पास कोई विशेष योजना है, तो वे दे सकते

[श्री सुशीलकुमार शिंदे]

हैं; राज्य अपने बजट में प्रावधान कर सकते हैं और इसे बोर्डों को दे सकते हैं। जब मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था तो मैंने भी किसानों को नि:शुल्क विद्युत मुहैया कराई थी लेकिन मैंने बजट में प्रावधान किया था और इसे बोर्ड को दे दिया था। अत:, यह उन पर छोड़ा जाना है। उस समय, उस विशेष अवधि के दौरान कमी थी। अत: यदि राज्य चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। भारत सरकार इस समय ऐसा नहीं कर सकती।

[हिन्दी]

माननीय सदस्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में डीपीआर के बारे में कह रहे थे। अभी हमारी जो स्कीम है, हम उसके बाहर नही जा सकते हैं। अभी हमारी जो स्कीम है, हमें उसके मुताबिक ही काम करना होगा और जो कुछ बैसीमुथियारी जी ने बोला है, उसे मैं देख लूंगा,

[अनुवाद]

मैं इस पर विचार करूंगा।

सभापति महोदय : अब मैं विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[अनुवाद]

सभापति महोदय : 15 सदस्य ऐसे हैं जो अविलंबनीय लोक महत्व के विषय रखना चाहते हैं। यदि सदस्य एक मिनट में अपनी बात रख पाते हैं, तो मैं इसकी अनुमति दूंगा अन्यथा मैं सभा को स्थगित कर दूंगा। मैं यह मानता हूं कि सभी सदस्य एक-एक मिनट का समय लेंगे।

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह पटेल (बांदा) : सदन स्थगित कर दीजिए, अच्छा है। एक मिनट में क्या बोलेंगे? स्थगित कर दीजिए तो हम चलेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : माननीय सभापति जी, हमारे देश में बाल श्रम की स्थिति बहुत गंभीर है। हमने बाल श्रम अधिनियम तो बना दिया किन्तु हमारे देश के सभी राज्यों में बड़ी संख्या में 10 से 12 साल के जो बाल श्रमिक हैं, वे होटलों में ढाबों में और चाय के स्टालों पर बहुत बड़ी संख्या में कार्य करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ मेरठ के पीतल उद्योग में, अलीगढ़ के ताला उद्योग में, फिरोजाबाद के कांच उद्योग में जहां 700 डिग्री सैन्टीग्रेड से 800 डिग्री सैन्टीग्रेड की हीट में बच्चों को काम करना पड़ता है; शिवाकाशी का पटाखा उद्योग, शिवाकाशी का मुद्रण उद्योग और शिवाकाशी का माचिस उद्योग; इन सबमें बहुत बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम करते हैं। इन बाल श्रमिकों का शोषण किया जाता है। उनको कम पैसा देकर उनसे बहुत अधिक काम कराया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे देश का हर बच्चा इस आश्वासन के साथ सोकर नहीं उठता कि जब वह उठेगा तो उसे भरपेट भोजन मिलेगा, और वह भी अपनी उम्र के बच्चों के समान स्कूल जा सकेगा। यह हमारे लिए, हम और आप सभी के लिए बड़ी चिन्ता की बात है कि हमारे देश में हजारों की संख्या में जब बच्चे सुबह सोकर उठते हैं, जब हम सभी एसी और कूलर की हवा में सो रहे होते हैं, उस समय वे बच्चे एक बड़ा थैला उठाकर प्लास्टिक की पन्नी बीनने के लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं। हमारी स्वतंत्रता का तब तक कोई अर्थ नहीं रह जाता है जब तक हमारे देश की अगली पीढ़ी अपना बचपना खोकर चाय के स्टालों पर झूठे कप के बरतन धोने के लिए और सुबह से उठकर कूड़ा-करकट बीनने के लिए अभिशप्त है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह बाल श्रमिकों का शोषण रोके तथा उनके पुनर्वास के कार्यों को गति प्रदान करे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप केवल मुद्दा उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बैसीमुथियारी जी, इस विषय पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। इसलिए, आप सिर्फ एक मिनट का समय ले सकते हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार, का ध्यान एक बहुत ही अविलंबनीय लोक महत्व के एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं जो बहुत ही गंभीर और विनाशकारी बाढ़ की स्थिति तथा सूखे की स्थिति से संबंधित है, जो इस समय असम राज्य में, विशेषकर बोडालैंड क्षेत्र में व्याप्त है।

सभापति महोदय : आपने मुद्दा उठाया है। इस विषय पर चर्चा भी होगी। अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं भारत सरकार से बोडोलैंड क्षेत्र तथा असम राज्य के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति करने की अपील करता हूं जिससे कि सूखा तथा बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई तथा उनका पुनर्वास किया जा सके।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने विषय उठाया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री महाबली सिंह (काराकाट) : सभापति महोदय, केन्द्रीय विद्यालय के माध्यम से बेहतर शिक्षा की उम्मीद लोगों को होती है और केन्द्रीय विद्यालय स्तरीय शिक्षा के लिए सुविख्यात है। लेकिन खेद है कि बिकार में सासाराम, औरंगाबाद और कैमूर बरसों पहले जिले बनाए गए लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार की ओर से उपर्युक्त जिलों में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित नहीं किये गये। समाज के कमजोर और निर्धन तबकों को शिक्षा प्रदान करना सरकार के प्राथमिक लक्ष्यों में शामिल है। केन्द्रीय विद्यालय इस लक्ष्य को पूरा करने में सरकार की स्थापित नीतियों को लागू करते हैं क्योंकि समाज के जिन वंचित तबकों को स्तरीय शिक्षा धनाभाव में नहीं मिल पाती है, उनके बच्चे इन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये तीनों जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं, लोग शिक्षा अभाव के चलते नक्सली मूवमेंट से जुड़ते जा रहे हैं जो चिन्ता का विषय है। यह एक गंभीर मुद्दा है जो शिक्षा के मौलिक प्रश्न से जुड़ा है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि...*(व्यवधान)* बिहार के सासाराम, औरंगाबाद तथा कैमूर जिलों में यथाशीघ्र केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएं।...*(व्यवधान)*

श्री आर.के. सिंह पटेल : मान्यवर, विषय तो पूरा हो जाने दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : विषय को सभा के संज्ञान में लाया गया है। यही पर्याप्त है।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : महोदय, रेल बजट में दिल्ली से सादलपुर सप्ताह में तीन दिन गाड़ी चलाने की घोषणा की गई थी। मेरा निवेदन हे कि यह महत्वपूर्ण ट्रेन है, लोगों की कई दिनों से मांग है कि गाड़ी को तुरंत शुरू किया जाए। जब यह छोटी लाइन थी, उस समय 10-12 गाड़ियां चला करती थीं, अब जिस गाड़ी को सप्ताह में तीन दिन चलाने की घोषणा की गई है, उसे रोज चलाया जाए और इसे तुरंत शुरू किया जाए ताकि लोगों की मांग पूरी हो सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आर.के. सिंह पटेल, कांच फैक्ट्री से संबंधित यह मामला राज्य का विषय है और इसे यहां नहीं उठाया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री आर.के सिंह पटेल : महोदय, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने एक ग्लास फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बरगड़ इलाके में, जहां पर सिल्का सैंड मौजूद है, वहां उन्होंने अपने कार्यकाल में शिलान्यास किया था। करोड़ों रुपया भारत सरकार का उस फैक्ट्री के निर्माण में लगाया गया। वहां के किसानों के खेत भी एक्वायर किए गए थे। वह फैक्ट्री बनी हुई है। माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था कि उस फैक्ट्री से पिछड़े क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा और वह फैक्ट्री डेंवलप की गई। उनके वंशज और अनुयायी इस सदन में मौजूद हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस फैक्ट्री को तुरंत शुरू करवाया जाए। मशीनें आना बाकी हैं, जिन्हें लाकर, जो भी कमिया शेष हों, उन्हें दूर कर माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सपने को साकार किया जाए।

श्री प्रदीप माझी (नवरंगपुर) : महोदय, इस महीने की पांच तारीख को मध्य प्रदेश के संगरूली डिस्ट्रिक में राजस्थान एक्सपलोसिव और

[श्री प्रदीप माझी]

आईडियल एक्सपलोसिव में दो धामके हुए। यहां नार्दन कोल फील्ड के लिए बारूद बनता है। मैंने जब अखबार में पढ़ा तो स्वयं वहां जाकर जायजा लिया। धमाके के समय 21 लोग काम कर रहे थे, जिसमें से 19 लोगों की मृत्यु हो गई। केवल एक आदमी की ही लाश मिली, बाकी सभी के चिथड़े उड़ गए। छोटे से लैंड माइन के ब्लास्ट से ही बहुत से लोगों की जान चली जाती है। आप स्वयं सोच सकते हैं कि जब दो बड़ी फैक्ट्रियों में ब्लास्ट होगा तो कितना बड़ा धमाका हुआ होगा। राज्य सरकार और जिला प्रशासन इस बात को इसलिए छिपा रहे हैं, क्योंकि जब इन दोनो फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिया गया था, उसमें नियम के मुताबिक फैक्ट्री के आस-पास तीन किलोमीटर के एरिया में रेजीडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां से तीस मीटर की दूरी पर ही रेजीडेंशियल एरिया है। उस दिन रविवार था, इसलिए ज्यादा लोगों की जान नहीं गई। इसकी इनक्वायरी के लिए प्रिंसीपल सैक्रेटरी को नियुक्त किया गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसकी जांच किसी रिटायर्ड जज से करवायी जाए।

डॉ. भोला सिंह (नवादा) : सभापति महोदय, मैं आसन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य और राष्ट्र कवि दिनकर का बिहार, राष्ट्रीय विकास की कतार से बहुत पीछे छूट गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह अविलंबनीय लोक महत्व का विषय नहीं है। यह एक सामान्य विषय है। आपने चर्चा में भाग लिया है। इसलिए, आप एक मिनट में अपनी बात रखिए। कृपया संक्षेप में बोलिए।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह : महोदय, * मैं भी इस सदन का एक सम्मानित सदस्य हूं। मैं आसन से अपेक्षा करता हूं, *...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं अनुमति नहीं दूंगा। आपको अध्यक्षपीठ का आदर करना होगा। आपको अध्यक्ष पीठ से अनुमति लेनी होगी। यदि आपको कुछ कहना है, तो आपको एक मिनट में खत्म करना होगा। आपको अपवाद नहीं माना जा सकता। सभी सदस्य अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग कर रहे हैं। कृपया ऐसी भाषा का प्रयोग मत कीजिए।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह : महोदय, आपका जो भी आदेश है, मैं उसका पालन करता हूं।

सभापति महोदय, बिहार अंधकार में डूबा हुआ है। 56 हजार करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। बिहार की आर्थिक संरचना समाप्त हो गई है। बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ और सूखा आया करता है। इसलिए बिहार जिस गति से विकास कर रहा है, अगर इसी गति से विकास करेगा, तो उसे महाराष्ट्र और गुजरात की कतार में आने में 40 वर्ष लगेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार में जब तक 80 या 85 हजार करोड़ रुपए की योजना नहीं लाई जाएगी और 15 प्रतिशत की दर से अगर बिहार का विकास नहीं होगा, तो बिहार राष्ट्रीय विकास की दर में समान स्तर पर नहीं आ सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह बिहार को एक स्पेशल राज्य का दर्जा प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीकारा) : महोदय, आपने मुझे मेरे चुनाव क्षेत्र से संबंधित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को उठाने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में एक गंभीर समस्या है जिसके बारे में मीडिया में खबर आई है। अल्लेपी चिकित्सा महाविद्यालय के विकिरण विभाग के अनुसार कुट्टानाड तालुक, जो मेरे चुनाव क्षेत्र में है, से अस्पताल में बड़ी संख्या में कैंसर पीड़ित मरीज आ रहें हैं। वर्ष 2007 में कैंसर से पीड़ित मरीजों की संख्या 300 थी; 2008 में यह बढ़कर 355 हो गई और इस साल जून तक यह संख्या 455 है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 66 प्रतिशत ज्यादा है। अधिकांश मरीज जिगर, गले और अस्थि कैंसर से पीड़ित हैं। उस क्षेत्र से संसद सदस्य होने के नाते मुझे इन मरीजों की ओर प्रधानमंत्री राहत कोष से धन राशि प्रदान करने के लिए सैकड़ों अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इन परिस्थितियों में मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह कुट्टानाड तालुक में एक उच्च स्तरीय चिकित्सा दल इस क्षेत्र में कैंसर से पीड़ित मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए भेजें। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि उन अनेक लोगों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य पैकेज दिया और कुट्टानाड के लोगों के लिए एक सुपर स्पेशियासिटी हॉस्पीटल स्थापित किया जाए।

***डा रतन सिंह अजनाला** (खडूर साहिब) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिक्खों के बारे में एक बहुत ही करुण कहानी सुनना चाहता हूं। भारत की आजादी के बाद लगभग 130 गुरुदारे पाकिस्तान में रह गए। इन गुरुद्वारों की सम्पत्ति के प्रबंधन के लिए पाकिस्तान निस्काषिती न्यास परिसम्पत्ति बोर्ड का गठन किया गया था। यह बोर्ड गुरुद्वारों की सम्पत्ति की देख-रेख करता था। यह बोर्ड अब एक गुरुद्वारा की 734 एकड़ की सम्पत्ति बेचने वाला है, जो कानूनी रूप से सही नहीं है।

आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री से अनुरोध करता हूं कि गुरुद्वारे की भूमि की अवैध बिक्री को तत्काल रोका जाए और सिक्खों की सम्पत्ति के विरुद्ध किए जा रहे अन्याय को रोका जाए। इसे सरकार के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड़) : महोदय, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नीति शास्त्रों के पूर्ण उल्लंघन से संबंधित महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पेप्सी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे जिसके अनुसार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पेप्सी के कुछ उत्पादों का समर्थन करेगी जिनके लिए वह एक करोड़ रुपये लेती है। यह चिकित्सा संबंधी नीति शास्त्रों के विरुद्ध है और इस प्रकार समुचित कार्रवाई करना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नीतिशास्त्र समिति की जिम्मेदारी है। ऐसा प्रत्येक संगठन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संवीक्षा के अंतर्गत आता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने गत एक वर्ष में इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अत:, इस बात पर विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पुख्ता सबूतों के बावजूद इस समर्थन संबंधी मुद्दे पर अपने सभी संभव प्रयासों के आगे बढ़कर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सुरक्षा करने जा रहा है। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल इस मामले की जांच करे और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 30 के अंतर्गत जांच आयोग गठित करें।

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम) : महोदय, मेरा अनुरोध है कि विजयनगरम, आंध्र प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उपक्षेत्रीय कार्यालय खोला जाए। महोदय, उपक्षेत्रीय कार्यालय, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के तीन उत्तरी तटवर्ती जिलों अर्थात् विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 4.11 लाख से अधिक भविष्य निधि जमाकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के अंतर्गत पेंशनरों की संख्या में भी दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। विजाग स्थित कार्यालय विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में कार्यरत कर्मचारियों की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने में असमर्थ है। विजयनगरम में उपक्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना से दो जिलों विजयनगरम और श्रीकाकुलम के पेंशनरों तक को न केवल प्रभावी ढंग से ईपीएफओ की सेवाएं पहुंचेगी बल्कि शिकायतों के निवारण में होने वाले विलंब में भी कमी आएगी और अधिकारियों तक पहुंचने की दूरी भी घटेगी। इसके अतिरिक्त सेवाओं के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में अधिक ध्यान दिया जाएगा।

अत:, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री से आग्रह करता हूं कि विजयनगर में उपक्षेत्रीय कार्यालय को तत्काल स्वीकृति दी जाए।

डॉ. जी. विवेकानन्द (पेड्डापल्ली) : महोदय, मुझे बाबली के मुद्दे को उठाने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार महाराष्ट्र 60 टीएमसी पानी का उपयोग कर सकता है और शेष पानी का आंध्र प्रदेश द्वारा उपयोग किया जा सकता है। अत:, आंध्र प्रदेश ने पोचमपाद परियोजना का निर्माण किया है और अब महाराष्ट्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन करते हुए बैराज और गेट का निर्माण किया है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह महाराष्ट्र सरकार को उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने, 60 टीएमसी अधिक पानी का उपयोग न करने और गोदावरी नदी के पार बैराजों के निर्माण को रोकने का निदेश दे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही जलयागनम कार्यक्रम आरंभ कर चुके हैं और यदि अधिक पानी लिया जाता है तो आंध्र प्रदेश की 17 लाख एकड़ से अधिक भूमि प्रभावित होगी। तेलंगाना के छह जिलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जनता अभी से पेयजल के लिए परेशान हो रही है।

मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस संबंध में कार्रवाई करे।

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी : महोदय, मैं इस मुद्दे पर अपने आपको उनसे संबद्ध करना चाहूंगी।

सभापति महोदय : श्री सतपाल महाराज, आपका मुद्दा उत्तराखंड में कानून और व्यवस्था से संबंधित है। यह राज्य का विषय है, मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : ये तो देश की सीमाएं हैं। वहां चीन की और नेपाल की सीमा लगती है, इसलिए यह केन्द्र का विषय है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप जल्दी करिये।

श्री सतपाल महाराज : सभापति महोदय, मुझे आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना है कि उत्तराखंड प्रदेश के सीमान्त जनपदों की जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का भार राजस्व पुलिस पर निर्भर है, किन्तु राजस्व पुलिस द्वारा पुलिस कार्यों का लगभग एक वर्ष से बहिष्कार करने के फलस्वरूप प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और प्रदेश की जनता अपने आपको असुरक्षित अनुभव कर रही है। जैसा कि सदन के सम्मानित सदस्य भली प्रकार जानते हैं कि उत्तराखंड की सीमा चीन व नेपाल से मिली हुई है तथा इस राज्य के पर्वतीय जनपद सीमान्त जनपद हैं। यदि सीमान्त जनपदों की जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था ही ठप्प हो जायेगी तो कभी भी देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

मेरा निवेदन है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए राजस्व पुलिस की उचित मांगों को स्वीकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार को शीघ्र निर्देशित करने की कृपा कीजिए।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): सभापति महोदय, कॉमनवैल्थ गेम्स 2010 को देखते हुए जिस तरीके से मैट्रो की घटनाएं अभी 12 जुलाई को एस.एल.आर. जंक्शन पर हुई, मिसहैपनिंग हुई और उसके पहले घटनाएं होती रहीं, उनको देखते हुए एक स्थिति यह उत्पन्न हुई कि क्या उस समय तक यह प्रोजैक्ट पूरा हो पाएगा और हो पाएगा तो क्या सही दिशा में सही ढंग से हो पाएगा? ये जो घटनाएं घटी हैं, इनसे दर्शकों, को आगुन्तकों को, खिलाड़ियों को और जो पर्यटक आने वाले हैं तथा स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आकर खड़ा हुआ है।

यह जो कमेटी बनाई गई है, मैं सीधे अपने बिन्दु पर आता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जांच कमेटी बनाई गई है, उस जांच कमेटी में क्या डिजाइन और डिजाइन एप्रूवल के प्रोसेसिंग से होकर गुजरने वाले किसी सदस्य का नाम तो नहीं है कि जो जांच कर रहा है? अगर वे जांच कर रहे हैं तो उससे तो सही बात सामने नहीं आएगी। कम से कम इम्पार्सियल मैम्बर से, कमेटी से जांच कराई जाये, जिससे सही बात सामने आये और भविष्य में ऐसी घटना न घटे और नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा से खिलवाड़ न किया जा सके।

[अनुवाद]

प्राय: 50 और 60 वर्ष की आयु के पुरुष और महिलाएं हाइपर टेंशन और मधुमेह के कारण गुर्दे के रोगों से पीड़ित होते हैं, परंतु हमारे जिले में 20 और 35 वर्ष के बीच की आयु के व्यक्ति भी गुर्दे के रोग से पीड़ित है। यदि आप गत एक दशक में मृत्यु संबंधी आंकड़ों का अवलोकन करें तो आप देखेंगे कि सैंकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु इसी रोग के कारण हुई हैं।

जहां तक इस मुद्दे का संबंध है तो पूरे देश, आंध्र मेडिकल कालेज, विजाग चिकित्सा विज्ञान संस्थान और विश्व के नंबर एक संस्थान हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से डॉक्टर हमारे यहां आए हैं। उन्होंने रोगियों की जांच की है और उन्होंने इस क्षेत्र के इन रोगियों की खान-पान की आदतों का अध्ययन किया है। इन सब जांचों को करने के बाद हमारे सभी डॉक्टर साथी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भूजल में सिलिकॉन और स्ट्रोनरियम के अधिक नमूनों के कारण ये व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं।

इस संबंध में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह श्रीकाकुलम जिले में राजीव गांधी चिकित्सा संस्थान में गुर्दे के रोग का उपचार करने के लिए रेनल उपस्कर हेतु अनुदान दे। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि इन क्षेत्रों के व्यक्तियों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने हेतु जलशोधन यंत्र स्थापित करे।

अंत में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह श्रीकाकुलम जिले में व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करने हेतु कुछ जागरूकता उत्पन्न करने और कोई सुझाव देने के लिए विशेष दल भेजे।

सभापति महोदय : अब, श्री प्रेम दास बोलेंगे।

श्री प्रेम दास, आज हम विद्युत के मुद्दे पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अत: आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रेमदास (इटावा) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एनटीपीसी डिबियापुर में लगी हुई है, उसके लिए किसानों ने जमीन उपलब्ध करायी, एनटीपीसी लगाने में सहयोग किया। मेरी मांग है कि एनटीपीसी से उस क्षेत्र के लिए और औरैय्या जिले के लिए बिजली दी जाए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला शून्यकाल में उठाने की अनुमति चाहता हूं।

तुलसी रॉयल सुगंधित तम्बाकू, धर्मपाल सत्यपाल प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा स्वामित्व एवं धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड द्वारा निर्मित पाउच एवं डिब्बे पर महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का रामचरित मानस की रचना करते हुए फोटोग्राफ है, जो कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के नाम का व्यावसायिक इस्तेमाल है। महाकवि ने सत्य और अहिंसा की जीत पर आधारित रामचरित मानस की रचना की विनयपत्रिका की रचना की। उनके फोटोग्राफ का व्यावसायिक इस्तेमाल देश के करोड़ों नागरिकों की भावनाओं से खिलवाड़ करना है।

कई दशकों से ऐसा हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास की मर्यादा को जिस तरह से तम्बाकू बनाने वाली कंपनी कर रही है, यह जांच का विषय है। कौन-से सरकारी अधिकारी ने तुलसी के नाम के व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति दी, कैसे दी और हर बार इसका नवीकरण भी होता रहा, क्या किसी सरकारी अधिकारी ने इसकी जांच नहीं की?

इस सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाई जाए, ताकि देश के करोड़ों नागरिकों की भावनाओं को चोट न पहुंचे।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.47 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 22 जुलाई, 2009/ 31 आषाढ़, 1931 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा श्री घनश्याम अनुरागी	241
2.	श्री राकेश सिंह	242
3.	श्री प्रभातसिंह पी. चौहान	243
4.	श्री एल. राजगोपाल	244
5.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	245
6.	श्री जगदीश शर्मा श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	246
7.	श्री डी.वी. सदानन्द गौडा	247
8.	श्री वरुण गांधी श्री भर्तृहरि महताब	248
9.	श्री प्रह्लाद जोशी	249
10.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	250
11.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	251
12.	श्री निशिकांत दुबे	252
13.	श्री आनंदराव अडसुल	253
14.	श्री महेश जोशी	254
15.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	255
16.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	256
17.	श्री अशोक कुमार रावत	257
18.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	258
19.	श्री उदय सिंह श्री असादूद्दीन ओवेसी	259
20.	श्री दुष्यंत सिंह श्री जगदम्बिका पाल	260

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आदित्यनाथ, योगी	2243, 2298, 2335, 2353
2.	अडसुल, श्री आनंदराव	2275, 2323, 2347, 2366
3.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	2252, 2302, 2339, 2357, 2365
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2202, 2271, 2319, 2344
5.	अजमल, श्री बदरुद्दीन	2242
6.	एंटोनी, श्री एंटो	2209, 2280

1	2	3
7.	अनुरागी, श्री धनश्याम	2380
8.	आवले, श्री जयवंत गंगाराम	2248, 2364
9.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	2230
10.	बाबर, श्री गजानन ध.	2264, 2315, 2342
11.	बैस, श्री रमेश	2254, 2304
12.	बलराम, श्री पी.	2374
13.	बाउरी, श्रीमती सुस्मिता	2201
14.	भडाना, श्री अवतार सिंह	2251
15.	बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर	2235
16.	चौहान, श्री संजय सिंह	2257
17.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	2211
18.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2246
19.	चौधरी, श्री अधीर	2220, 2303
20.	दास, श्री भक्त चरण	2233, 2248
21.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	2295, 2335, 2382
22.	डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन	2389
23.	धनपालन, श्री के.पी.	2261
24.	दुबे, श्री निशिकांत	2381
25.	दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव	2335
26.	गद्दीगौदर, श्री पी.सी.	2236, 2245
27.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2222, 2285
28.	गांधी, श्रीमती मेनका	2225, 2373

1	2	3
29.	गांधी, श्री वरुण	2282, 2376
30.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	2281, 2325
31.	हक, शेख सैदुल	2228
32.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	2213, 2274, 2347
33.	जयाप्रदा, श्रीमती	2256, 2306, 2335, 2352, 2368
34.	झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	2258, 2308
35.	जोशी, श्री महेश	2283
36.	जोशी, श्री प्रहलाद	2336
37.	कलमाडी, श्री सुरेश	2222, 2312
38.	करुणाकरन, श्री पी.	2240
39.	कश्यप, श्री वीरेन्द्र	2265, 2345
40.	खैरे, श्री चंद्रकात	2253, 2285, 2311, 2332, 2382
41.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	2222
42.	लागुरी, श्री यशवंत	2213, 2324
43.	लंगम, श्री पी.	2382
44.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2207, 2270, 2318, 2343, 2362
45.	महतो, श्री नरहरि	2239
46.	महताब, श्री भर्तृहरि	2247, 2367, 2375
47.	माझी, श्री प्रदीप	2227, 2229, 2234, 2286, 2384
48.	मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार	2205, 2269, 2317, 2354
49.	मंडल, श्री मंगनी लाल	2249
50.	मणि, श्री जोस के.	2238, 2296

1	2	3
51.	मुंडा, श्री अर्जुन	2203, 2289, 2328, 2377
52.	मुत्तेमवार, श्री विलास	2336, 2295
53.	नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप	2388
54.	निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद	2360
55.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2299, 2385
56.	पाल, श्री जगदम्बिका	2279, 2337, 2338, 2356
57.	पांडा, श्री वैजयंत	2224, 2282, 2297, 2334, 2387
58.	पांडा, श्री प्रबोध	2237
59.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	2285, 2327
60.	पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार	2208, 2327, 2382
61.	पटेल, श्री देवजी एम.	2217
62.	पटेल, श्री आर.के. सिंह	2241
63.	पटेल, श्री बाल कुमार	2254, 2304
64.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2227, 2234, 2286, 2384
65.	पाठक, श्री हरिन	2250
66.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	2218, 2276
67.	राघवेन्द्र, श्री बी.वाई.	2231, 2287, 2325
68.	राजगोपाल, श्री एल.	2223, 2361, 2379
69.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	2212, 2272, 2305
70.	राव, डॉ. के.एस.	2330
71.	राव, श्री नामा नागेश्वर	2369, 2382
72.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2293, 2332, 2351, 2361, 2369

1	2	3
73.	राठवा, श्री रामसिंह	2195
74.	रावत, श्री अशोक कुमार	2277, 2322, 2349, 2359
75.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2223, 2335
76.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2216, 2301, 2337, 2355, 2363
77.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	2254
78.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	2205, 2340, 2354
79.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2200, 2263, 2300, 2302
80.	सत्पथी, श्री तथागत	2222, 2224
81.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	2370, 2371, 2372
82.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	2199, 2266, 2383
83.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	2260, 2309, 2368
84.	सिंह, डॉ. भोला	2255, 2305
85.	सिंह, श्री दुष्यंत	2291, 2330, 2358
86.	सिंह, श्री गणेण	2233, 2292, 2331
87.	सिंह, श्री जगदानंद	2245
88.	सिंह, श्री राधा मोहन	2221, 2254, 2278, 2304, 2336
89.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	2224, 2226, 2310
90.	सिंह, श्री राकेश	2268, 2316, 2346, 2382
91.	सिंह, श्री सुशील कुमार	2219, 2378
92.	सिंह, श्री उदय	2290, 2329, 2350, 2387
93.	सिंह, श्री यशवीर	2262
94.	सिंह, देव, श्री कालीकेश नारायण	2215, 2314, 2341, 2382

1	2	3
95.	सिन्हा, श्री यशवंत	2300
96.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2196, 2273
97.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	2204, 2294, 2333
98.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	2200, 2248, 2267, 2320, 2352
99.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	2206, 2288
100.	स्वराज, श्रीमती सुषमा	2248, 2307
101.	तकाम, श्री संजय	2210
102.	टन्डन, श्री लालजी	2336
103.	तिवारी, श्री मनीष	2386
104.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	2198, 2265, 2321, 2345
105.	थॉमस, श्री पी.टी.	2232
106.	तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह	2243
107.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2274, 2324, 2347, 2356
108.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	2197
109.	वर्मा, श्री सज्जन	2259, 2313
110.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	2284, 2326, 2348, 2383
111.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	2356
112.	यादव, श्री दिनेश चन्द्र	2255
113.	यादव, प्रो. रंजन प्रसाद	2214, 2255
114.	यादव, श्री हुक्मदेव नारायण	2335
115.	यास्खी, श्री मधु गौड	2222, 2285

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	244, 246, 248, 251, 255, 257, 258
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	253, 254, 259
गृह	:	245, 247, 252
सूचना और प्रसारण	:	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	
खान	:	241, 243
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	242, 249, 250, 256, 260
युवक कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	2199, 2200, 2202, 2206, 2211, 2212, 2215, 2226, 2229, 2231, 2232, 2237, 2238, 2240, 2241, 2244, 2246, 2251, 2257, 2259, 2264, 2268, 2270, 2271, 2274, 2276, 2278, 2289, 2290, 2296, 2297, 2301, 2302, 2309, 2310, 2315, 2316, 2319, 2321, 2325, 2339, 2344, 2345, 2346, 2347, 2349, 2362, 2364, 2367, 2371, 2373, 2375, 2376, 2377, 2378, 2380, 2389
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	2213, 2216, 2219, 2221, 2247, 2252, 2258, 2269, 2280, 2288, 2299, 2303, 2305, 2314, 2320, 2342, 2351, 2352, 2358, 2361, 2363
गृह	:	2196, 2201, 2205, 2208, 2220, 2224, 2227, 2228, 2235, 2239, 2254, 2256, 2262, 2263, 2272, 2275, 2282, 2285, 2294, 2298, 2304, 2306, 2308, 2324, 2327, 2332, 2335, 2336, 2350, 2353, 2360, 2366, 2368, 2379, 2382, 2384, 2386, 2387, 2388

सूचना और प्रसारण	:	2198, 2218, 2223, 2236, 2295, 2311, 2318, 2323, 2343, 2348, 2354
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	2197, 2203, 2207, 2209, 2214, 2248, 2266, 2267, 2277, 2279, 2286, 2293, 2322, 2329, 2334, 2337, 2355, 2365, 2385
खान	:	2225, 2253, 2284, 2291, 2312, 2326, 2330, 2372, 2374
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	2210
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	2195, 2204, 2217, 2222, 2233, 2234, 2242, 2243, 2249, 2250, 2255, 2260, 2261, 2265, 2273, 2281, 2287, 2292, 2328, 2331, 2333, 2338, 2340, 2341, 2359, 2369, 2370, 2383
युवक कार्यक्रम और खेल	:	2230, 2245, 2283, 2300, 2307, 2313, 2317, 2356, 2357, 2381

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

©2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।